



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2009/आश्विन 8, 1931

No. 188]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2009/ASVINA 8, 1931

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2009

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 1-सीए (5)/60/2009.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (5ख) के अनुसरण में, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् के 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखाओं और रिपोर्ट की एक प्रति जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

60वीं वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् “परिषद्” कहा गया है) को 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपनी 60वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

प्रारंभ में परिषद्, उस सम्मान के लिए सदस्यों और छात्रों की सराहना करती है, जिसके साथ आज के समाज में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की वृत्ति को देखा जा रहा है। यह उपलब्धि सदस्यों और छात्रों द्वारा एक साथ उपदर्शित उत्कृष्टता, स्वतंत्रता और अखंडता के कारण प्राप्त हो सकी है।

इस रिपोर्ट के माध्यम से, परिषद् और इसकी विभिन्न समितियों की वर्ष 2008-2009 की महत्वपूर्ण गतिविधियों और साथ ही भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के वर्ष 2008-2009 के लेखाओं की विशिष्टियों को उपदर्शित करने के साथ-साथ, परिषद् द्वारा इस अवसर पर इस रिपोर्ट में इस अवधि के दौरान और जुलाई, 2009 के प्रथम सप्ताह तक, विशेष रूप से अभिप्राप्त किए गए एक और मील के पत्थर के संदर्भ में, अर्थात् राष्ट्र की सेवा में 60 वर्ष पूरा करते हुए और 61वें वर्ष में प्रवेश करते हुए, सदस्यों और छात्रों से संबंधित की गई प्रमुख पहलों, महत्वपूर्ण घटनाओं, सांख्यिकीय रूपरेखाओं, आयोजित की गई मंगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के व्यौरों को भी समाविष्ट किया गया है। रिपोर्टधीन वर्ष एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है, जिसमें संस्थान ने 1 जुलाई, 2008 को अपने हीरक जयन्ती वर्ष में प्रवेश किया और उसने इस अवसर के अनुरूप कार्यक्रमों का आयोजन करके उसे पूर्ण शानो-शौकत से मनाया, चाहे ऐसे कार्यक्रम वृत्तिक रूप से समकालीन विषयों पर हों अथवा वृत्ति को समाज के समीप लाने के विचार से सामाजिक रूप से सुसंगत विषयों पर हों।

परिषद् इस अवसर पर यह संकल्प लेती है कि वह उत्कृष्टता और अखंडता की भावना के साथ अपने राष्ट्र और अन्य पणचारियों की सेवा करना जारी रखेगी।

संसद् के अधिनियम द्वारा 1 जुलाई, 1949 को आईसीएआई की स्थापना से, लेखांकन वृत्ति में सदस्यता और छात्र आधार के निबंधनों में अद्वितीय विकास हुआ है। संस्थान, जिसे केवल 1,700 सदस्यों के साथ स्थापित किया गया था, आज विकास के ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां इसके सदस्यों की संख्या 1,55,000 और छात्रों की संख्या 5,20,000 को पार कर चुकी है। इस महान विकास यात्रा के दौरान, भारत में लेखांकन वृत्ति ने पुनःसंरचना, समुन्नति, मूल्य परिवर्धनों, नाना क्रमकरण और वैश्विक एकीकरण के महत्वपूर्ण प्रक्रमों को पार किया है। अनेक वर्षों से, संस्थान ने वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और अखंडता के अभिरक्षक के रूप में और सर्वोत्तम लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों को तैयार करने के अपने मूल मिशन में सारवान प्रगति की है, क्योंकि यह सदैव परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों से संगत रूप में स्वयं को अनुकूल बनाने की आवश्यकता के साथ स्वयं को परिवर्तित करता रहा है। इस संदर्भ में, संस्थान सदैव यह सुनिश्चित करने में सतर्क रहा है कि एकाउंटेंटों का प्रशिक्षण विश्व में सर्वश्रेष्ठ के समतुल्य हो और इसके परिणामस्वरूप संस्थान के सदस्यों (सीए) को अधिकाधिक रूप से एक सकल कारबार समाधान प्रदान करने वालों के रूप में देखा जा रहा है। संस्थान, इसके सदस्यों की ब्रांड छवि की स्वीकार्यता, उनके सम्मान में वृद्धि करने के लिए और उन्हें वैश्विक चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के रूप में रूपांतरित करने में सहायता करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अपने 61 वर्ष के जीवन में, यह उल्लेख करना अत्यधिक उत्साहवर्धक है कि हमारे राष्ट्र के नेताओं ने सदैव राष्ट्र निर्माण के प्रति आईसीएआई की पहलों और सहयोग को अभिस्वीकार किया है।

आर्थिक परिस्थितियों में ऐसे परिवर्तनों के कारण, जिन्होंने वृत्ति के लिए और अधिक चुनौतियां और साथ ही समान रूप से अवसर भी उत्पन्न किए हैं, यह आवश्यक हो गया है कि लघु और मध्यम आकार की फर्मों की सक्षमता का निर्माण किया जाए, जिससे कि उन्हें सदैव बढ़ती प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करने और उनका फायदा प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके। इस प्रयोजन के लिए, प्रारंभ की गई पहलों में, सदस्यों के मस्तिष्क में सक्षमता निर्माण उपायों जैसे कि नेटवर्किंग, समामेलन और निगम रूपों में प्रबंध संबंधी परामर्शी सेवाओं के संबंध में जागरूकता का सृजन करना और संभावी आशंकाओं का समाधान करना और ऐसी सुदृढीकरण प्रक्रिया को अपनाते समय सदस्य के फायदों, अवसरों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करना सम्मिलित है। अन्य प्रारंभ की जाने वाली पहलों में सक्षमता निर्माण के और क्षेत्रों का पता लगाना है जैसे कि इक्विपमेंट, सस्ती दरों पर निधियों की उपलब्धता के लिए बैंकों के साथ करार, वर्चुअल पुस्तकालयों के सृजन के लिए पद्धतियां तैयार करना और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के एकत्रण को सुकर बनाना जिससे कि सदस्य वास्तव में एक छत के नीचे एकत्रित हो सकें।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, संस्थान ने स्वयं के लिए एक उत्तम छवि बनाई है और इसे पूरे विश्व में प्रमुख लेखाकरण निकायों में से एक के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप, संस्थान के सदस्यों की सेवाओं की विश्व भर में बड़ी मांग है। वैश्विक स्तर पर सदस्यों के लिए और अधिक अवसरों को सुनिश्चित करने के विचार से, संस्थान ने अन्य निकायों के साथ-साथ, इंग्लैंड और वेल्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएईडब्ल्यू) और आस्ट्रेलिया चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएए) के साथ रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परस्पर मान्यता करारों (एमआरए) पर हस्ताक्षर किए हैं। संस्थान के सदस्यों की अंतरराष्ट्रीय पहचान में और वृद्धि को सुकर बनाने के विचार से संस्थान ने न्यूयार्क में अपने चैप्टरों का सृजन किया और साथ ही सिंगापुर और डब्लिन में भी अपने चैप्टर स्थापित किए और इसके अतिरिक्त बहरीन में भी संस्थान के कार्यालय को स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है।

यह गर्व की बात है कि वर्तमान समयों में भी, जब आर्थिक मंदी एक वैश्विक सत्य है, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंटों के ज्ञान और कौशल का इस संबंध में सुझाव प्राप्त करने के लिए सहारा लिया जा रहा है कि पूरे विश्व के सामने आई इस मंदी की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी उपाय क्या हो सकते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी नवीकरणों का उपयोग करते हुए, वृत्ति में प्रवेश करने हेतु प्रवेश स्तरीय परीक्षा अर्थात् सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) का सफलतापूर्वक ऑन लाइन आयोजन किया गया है।

परिषद् का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी राष्ट्र की वित्तीय अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने और आर्थिक विकास के लिए अंतर्निहित जांच और सतुलनों के साथ एक सुदृढ़ लेखांकन वृत्ति सफलता की कुंजी है। इस उद्देश्य के लिए, आईसीएआई ने विश्व भर में विभिन्न लेखाकरण निकायों में प्रचलित सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों को सम्मिलित करते हुए सर्वश्रेष्ठ भारतीय लेखांकन, संपरीक्षा और आश्वासन मानकों को समाविष्ट करने वाले भारतीय लेखांकन मानकों को विकसित किया है और उनकी अधिसूचना को समर्थ बनाया है।

1. परिषद्

32 निर्वाचित सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित 8 सदस्यों वाली बीसवीं परिषद् का गठन 5 फरवरी, 2007 से नौन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। वर्ष 2008-2009 और वर्ष 2009-2010 के लिए परिषद् की संरचना पृथक-पृथक रूप से दर्शित की गई है।

2. परिषद् की समितियां

परिषद् ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित) की

धारा 17 और धारा 21घ, जो 17 नवंबर, 2006 से प्रवृत्त है, के निबंधनानुसार वृत्ति संबंधी विषयों के बारे में तीन स्थायी और विभिन्न अस्थायी समितियों का गठन 5 फरवरी, 2009 को किया। परिषद् ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की क्रमशः धारा 21क और धारा 21ख के उपबंधों के अनुसरण में एक अनुशासन बोर्ड और एक अनुशासन समिति का भी गठन किया है। इसके अतिरिक्त, एक अनुशासन समिति जो एक स्थायी समिति है, उक्त अधिनियम की धारा 21घ के अधीन गठित की गई थी। अस्थायी समितियों में गठित की गई नई समितियों में लघु और मध्यम व्यवसायों संबंधी समिति, अंतरराष्ट्रीय कराधान समिति, अवसंरचना समिति, मानव संसाधन और प्रशासन समिति तथा प्रतिनिधित्व समिति सम्मिलित हैं। 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान, परिषद् की विभिन्न समितियों की 214 बैठकें आयोजित की गईं, जबकि 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के दौरान 153 बैठकें आयोजित की गई थीं।

3. संपरीक्षक

सीए गुरमीत एस. ग्रेवाल, एफसीए और सीए प्रमोद जैन, एफसीए वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए आईसीएआई के संयुक्त संपरीक्षक थे। परिषद् उनकी सेवाओं की प्रशंसा करती है।

4. स्थायी समितियां

4.1 कार्यपालक - समिति

यह समिति छात्रों/सदस्यों/फर्मों से संबंधित विभिन्न रजिस्टर रखने, सदस्यों के प्रवेश, हटाए जाने और उनके पुनःस्थापन के कार्य की देख-रेख करती है, जिसमें व्यवसाय प्रमाण-पत्र को जारी करने समेत सदस्यों से संबंधित विषयों पर और छात्रों से संबंधित सब विषयों पर, जिनमें उन्हें अनुज्ञा देना, जहां अपेक्षित हो, छात्रों/सदस्यों/फर्मों की ओर से किए गए विलम्ब की माफी, भी शामिल है, शाखाओं से संबद्ध विषयों, जिनमें नई शाखाएं खोलना, नए चैप्टर खोलना और विदेशों में कार्यालय खोलना तथा कर्मचारियों से संबंधित विषयों आदि पर भी विचार करना सम्मिलित है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति द्वारा परिषद् को की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैं :

- न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर में आईसीएआई के एक चैप्टर की स्थापना।
- मध्य क्षेत्र में रांची में और पश्चिमी क्षेत्र में बसई में छात्र संघ की एक-एक शाखा स्थापित करना।
- सदस्यों के लिए, भूतलक्षी प्रभाव से सदस्यता के रजिस्ट्रीकरण के लिए साधारण क्षमा स्कीम।
- किसी कार्यवाही में उपयोग करने और संस्थान द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित) की धारा 22 के साथ पठित धारा 21 के अधीन आयोजित/की जाने वाली किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही में उपयोग करने के लिए आशयित दस्तावेजों के अनुवाद संबंधी नियम।
- उद्योग में कार्यरत सदस्यों के लिए समिति द्वारा 'कारपोरेट कम्यूनिकी' न्यूज लेटर का प्रकाशन पुनः प्रारंभ करने।
- ठाणे में विकेन्द्रीकृत कार्यालय खोलने।
- शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी नई स्कीम के अधीन फाइनल परीक्षा में उपसंजात होने के लिए सन्नियमों को शिथिल करने।
- प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं को भवन अनुदान के मान का पुनरीक्षण।
- वैकल्पिक विवाद समाधान प्रकोष्ठ की स्थापना।
- दो या अधिक फर्मों के समामेलन के पश्चात् फर्म की वरिष्ठता संबंधी प्रास्थिति पर स्पष्टीकरण।
- गेटवे टू इंटरनेशनल ट्रेड-व्यापार विधियों और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति की विज्ञप्ति।
- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 के कारण बहुअनुशासनात्मक भागीदारी, वित्त समिति आदि के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 में संशोधनों से संबंधित प्रारूप अधिसूचना।
- "चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स छात्र कल्याण निधि" नामक एक न्यास की स्थापना के लिए प्रारूप न्यास विलेख।
- विभिन्न प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करना।
- सीमित दायित्व भागीदारी विधेयक, 2006 के उपबंधों के कारण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 में किए जाने के लिए अपेक्षित परिवर्तनों के लिए प्रस्ताव।
- कर्नाटक के माननीय राज्यपाल सी.ए. रामेश्वर ठाकुर के सम्मान में बंगलोर स्थित संस्थान के प्रस्तावित उत्कृष्टता केन्द्र का नामकरण।
- मध्य क्षेत्र में ब्यावर में एक शाखा की स्थापना।
- छात्र संघ शुल्क के एक भाग को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स छात्र कल्याण निधि में जमा करना।

- सूचना प्रणाली संपरीक्षा पाठ्यक्रम में अर्हतापत्र अर्हता प्राप्त करने पर ' (आईसीए)' के स्थान पर ' (आईसीएआई)' शब्दों का प्रयोग करना ।
- विभिन्न परीक्षाओं के लिए परीक्षा फीस का पुनरीक्षण ।
- लेखाकरण तकनीशियन पाठ्यक्रम के संबंध में प्रारूप चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008 ।
- लेखाकरण तकनीशियन पाठ्यक्रम-पाठ्यचर्या, संपरिवर्ती उपबंध, पूर्व में उत्तीर्ण समूह के संबंध में छूट, फीस संरचना और उससे संबंधित अन्य अनुषंगी विषय ।
- आईसीएआई और आईसीएईडब्ल्यू के बीच परस्पर समझ ज्ञापन - आईसीएईडब्ल्यू के सदस्यों द्वारा उत्तीर्ण किए जाने वाले विषयों के लिए पाठ्यक्रम अंतर्वस्तु ।
- पीई-2 और फाइनल (पुरानी पाठ्यचर्या) परीक्षा के छात्रों के लिए प्रश्नपत्रों की अपेक्षाओं के विषय में विनियम 2005 के अधीन कठिनाइयों का निवारण ।
- विनियम 5(3) के निबंधनानुसार अध्येता सदस्य के रूप में किसी सहबद्ध सदस्य के प्रवेश के मामले पर विचार करना ।
- व्यवसायरत चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों को व्यवसाय से भिन्न किसी अन्य कारबार में संलिप्त होने के मामलों पर विचार करना ।
- प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं के कार्यकरण के संबंध में केन्द्रीय परिषद् के पुनरीक्षित निदेश - ऐसी विशिष्टियों/व्यौरों के संबंध में जो अंततः प्रबंध समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त का भाग बन सकेंगे ।
- फाइनल परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा ऐसी अवधि और ऐसी रीति में, जिसे समय-समय पर परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, पूरा किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम और आधुनिक आईटी प्रशिक्षण को प्रारंभ करने ।
- विनियम 40 के अधीन, ऐसे व्यक्तियों को, जो विनियम 37ग के उपविनियम (3) के परंतुक के अधीन उसके लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, जारी किए जाने वाले लेखाकरण तकनीशियन स्तर के प्रमाणपत्र का प्रारूप ।

रिपोर्टअधीन अवधि के दौरान समिति द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण विनिश्चय निम्नलिखित से संबंधित हैं :-

- छात्रों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए शिक्षा अधिकारी/काउंसलर उपलब्ध कराना ।
- संस्थान के पदधारियों के लिए ड्रेस कोड का पुनर्विलोकन ।
- शाखाओं, प्रादेशिक कार्यालयों और डीसीओ में पट्टिकाएं/पत्थर/स्लेब प्रतिष्ठापित करने और साथ ही इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अवसरों के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना ।
- प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं द्वारा आयोजित किन्हीं कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के दौरो के संबंध में अपनाए जाने वाला शिष्टाचार ।
- बीमा और पेंशन के क्षेत्र में प्रकाशनों के आधारिक प्रारूप तैयार करने वाले लेखकों को संदेय मानदेय का पुनरीक्षण ।
- संस्थान के प्रमुख प्रकाशनों का मानकीकरण और उनमें समरूपता बनाए रखना ।
- निगम कार्य मानकों का प्रारूप फ्रेमवर्क ।
- प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को, उनके अंतर्गत आने वाले सदस्यों के आधार पर संदेय राजस्व अनुदान (सदस्यता फीस) का पुनरीक्षण ।
- सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद् और प्रादेशिक परिषद् की सर्वश्रेष्ठ शाखा के चयन के लिए मानदंड का पुनर्विलोकन ।
- उद्योग में संस्थान के सदस्यों के लिए सर्वोत्तम सीएमडी/सीईओ/सीएफओ पुरस्कारों का आयोजन ।
- आईसीएआई की सीआईआरसी की मुरादाबाद शाखा द्वारा भवन निर्माण के लिए भूमि के क्रय हेतु प्रस्ताव ।
- उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना के लिए बंगलोर में भूमि का आबंटन ।
- मुंबई और कोलकाता में विद्यमान भवनों में संरचनात्मक ग्लेजिंग संकर्म द्वारा नवीकरण ।
- नए आए अधिकारियों से परस्पर क्रिया के अनुक्रम में हाल ही में किए गए/ प्राप्त सुझाव और संस्थान से बाहर निकायों/अस्तित्वों/गतिविधियों में मानद पद धारण करने वाले कर्मचारियों के संबंध में भी एक नीति तैयार करने की महसूस की गई आवश्यकता ।
- डब्ल्यूआईआरसी की पिंपरी-चिंचवड शाखा की अधिकारिता ।
- अध्ययन-बोर्ड अनुदान के लिए सीए छात्रों हेतु उप प्रादेशिक सम्मेलन को सम्मिलित करना ।

- प्रदेशों और शाखाओं की छात्र संबंधी गतिविधियों के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता का पुनर्विलोकन ।
- सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद्/शाखा पुरस्कार और साथ ही सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ/ छात्र संघ की शाखा पुरस्कार ।
- ऐसे छात्रों को, जो अखिल भारतीय वक्तृता और क्विज प्रतियोगिताओं, अखिल भारतीय सीए छात्र सम्मेलनों और सीए छात्रों के राष्ट्रीय अभिसमय में भाग ले रहे हैं, एसी 2टीयर किरायों की प्रतिपूर्ति ।
- वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए संपरीक्षा फीस का पुनरीक्षण ।
- जयपुर, राजस्थान स्थित संस्थान के उत्कृष्टता केन्द्रों के लिए भूमि का आबंटन ।
- संस्थान के लेखाकरण संग्रहालय की स्थापना ।
- पूरे विश्व में सार्वभौमिक उपयोग के लिए आईसीएआई द्वारा लेखाकरण सॉफ्टवेयर का विकास ।
- लोक संस्थाओं के सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग रूप में संस्थान को दिल्ली नगर निगम द्वारा सौंपे गए कार्यों के लिए मंजूरी ।
- संस्थान के सदस्यों को द्वितीय पहचानपत्र जारी करना ।
- उत्तीर्ण व्यक्तियों के लिए दीक्षांत समारोह ।
- छात्रों और सदस्यों के लिए ड्रेसकोड या लेपल पिन ।
- संस्थान के हीरक जयन्ती वर्ष में सद्भाव व्यवहार के भाग रूप में संस्थान के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संदेय पेंशन की दरों को, सेवानिवृत्ति की अवधि/तारीख पर ध्यान न देते हुए, सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के आधार पर समतुल्य बनाना ।
- ग्रेटर नोएडा में भूमि का उपापन ।
- सीआईआरसी की भिलाई शाखा को भिलाई इस्पात संयंत्र (सेल) के शहरी सेवा विकास द्वारा भूमि का आबंटन ।
- ऐसे छात्रों को, जो पहले ही वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (पीसीसी) के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं या जिन्होंने वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (पीसीसी) के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन किया है, वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा 2) में उपसंज्ञात होने की अनुमति प्रदान करना ।
- बिहार बाढ़ अनुतोष खाते में सहयोग करना ।
- साधारण प्रबंध, व्यक्तित्व विकास और संसूचना कौशलों संबंधी तीन मास के आदर्श कार्यक्रम के लिए जयपुर में कैम्पस किराए पर लेना ।
- भरथिआर विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर के साथ परस्पर समझ ज्ञापन ।
- सदस्यों को, इंग्लैंड और वेल्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएइडब्ल्यू) के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तम वृत्ति प्रमाणपत्र जारी करने का मामला ।
- एटीसी छात्रों को लेपल पिन उपलब्ध कराना ।
- रोहतक और फरीदाबाद में भूमि का आबंटन ।
- एसएपी वित्तीय लेखाकरण इआरपी 2005 (इसीसी 6.00) का शुभारंभ ।
- प्रबंध लेखाकरण इआरपी 2005 (इसीसी 6.00) ।
- आईएसए पीटी बैचों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए जलपान की बेहतर/उत्कृष्ट व्यवस्थाएं ।
- कर्मचारी कल्याण उपाय के रूप में अनुमोदित अस्पतालों/नर्सिंग होमों की सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए और अधिक अस्पतालों का नामांकन ।
- मुंबई स्थित संस्थान के भवन को पुनःडिजाइन करना /पुनः-सुसज्जित करना ।
- ऐसी फर्मों के मामले में, जिनका सम्मेलन अगस्त, 2008 से पूर्व हुआ था, वरिष्ठता की प्रभावी तारीख ।
- वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकृत छात्रों को एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना ।
- कारबार वित्त संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ करना ।
- समितियों के सचिवों को आवश्यकता आधार पर डेटा कार्ड वाले लैपटॉप उपलब्ध कराना ।

- सॉफ्ट कौशलों के विकास के लिए छात्रों को तीन मास का आवासी पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान (एनआईएफएम) के साथ परस्पर समझ ज्ञापन (एमओयू) ।
- नवगठित अस्थायी समिति के निर्देश निबंधनों के संबंध में परिषद् को सिफारिश करना ।
- प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं के पत्र शीर्षों/न्यूज लेटर आदि में एकसमानता ।
- सूचना प्रणाली संपरीक्षा निर्धारण परीक्षा के संचालन के लिए केन्द्र अधीक्षकों और अन्य परीक्षा कृत्यकारियों को संदेय मानदेय में वृद्धि ।
- परिषद् और प्रादेशिक परिषदों के निर्वाचन बायोमीट्रिक/इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों द्वारा कराना ।
- अखिल भारतीय आधार पर प्रादेशिक परिषदों के सदस्यों और शाखाओं की प्रबंध समिति के सदस्यों के बीच अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन ।
- ऐसे स्थानों पर, जहां सदस्यों की संख्या काफी अधिक है किन्तु किसी शाखा की स्थापना के प्रयोजन के लिए अपेक्षित न्यूनतम संख्या से थोड़ी कम है, शाखाओं के विस्तार पटल स्थापित करना ।
- विदेशों में स्थित संस्थान के चैप्टरों में परामर्शदाताओं के रूप में परिषद् के सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करना ।
- परिषद् को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि (सीएसबीएफ) स्थापित करने के संबंध में और यह सिफारिश करना कि आर्टिकल के रूप में छात्रों के रजिस्ट्रीकरण के समय 250 रुपए की राशि प्रभारित करना और छात्रों के लिए विभिन्न कल्याण स्कीमों को बनाए रखने के लिए सीएसबीएफ के खाते में जमा करना ।
- संस्थान के कर्मचारियों के लिए ट्रेस कोड को प्रादेशिक और शाखा स्तर पर विस्तारित करना ।
- आईसीएईडब्ल्यू के सदस्यों द्वारा विनिर्दिष्ट आईसीएआई परीक्षा हेतु रजिस्ट्रीकरण के लिए/ आईसीएआई की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आईसीएआई को, आईसीएआई और आईसीएईडब्ल्यू के बीच हस्ताक्षरित परस्पर समझ ज्ञापन के अधीन संदेय - रजिस्ट्रीकरण, परीक्षा, सदस्यता के लिए प्रवेश और वार्षिक सदस्यता - फीस के संबंध में परिषद् को सिफारिश करना ।
- शाखाओं को छात्र रजिस्ट्रीकरण प्रारूप प्राप्त करने और अध्ययन सामग्री जारी करने के लिए प्राधिकृत करना ।
- एक दिवसीय संगोष्ठियों के संबंध में शाखाओं को संदेय अनुदान को 10000 रुपए से बढ़ाकर 20000 रुपए करना ।
- प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं को वक्तृता प्रतियोगिताओं के लिए संदेय अनुदान को 5000 रुपए से बढ़ाकर 25000 रुपए करना ।
- प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं को क्विज प्रतियोगिताओं के लिए संदेय अनुदान को 5000 रुपए से बढ़ाकर 25000 रुपए करना ।
- प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं को छात्र क्रियाकलापों के लिए संदेय अनुदान को, शाखा में छात्रों की संख्या के प्रतिनिर्देश से विनिर्दिष्ट अधिकतम राशि के अधीन रहते हुए, 150 रुपए प्रति छात्र से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति छात्र करना ।
- सीए छात्रों के राष्ट्रीय अभिसमयों की संख्या को प्रति क्षेत्र 1 से बढ़ाकर 3 करना ।
- विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त संगोष्ठियों के संबंध में एकदिवसीय संगोष्ठी के लिए अनुदान को 25000 रुपए से बढ़ाकर 75000 रुपए तथा दो दिवसीय संगोष्ठी के लिए 40000 रुपए से बढ़ाकर 125000 रुपए करना ।
- आईटी प्रयोगशालाओं में क्वालिटी शिक्षा की मानीटरी, मार्गदर्शन करने और उसे सुनिश्चित करने तथा उससे संबंधित विषयों के समन्वयन के लिए अधिकारी तैनात करना ।
- दसवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर की वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना और उपरोक्त प्रतियोगिताओं में छात्रों के साथ आने वाले किसी एक माता/पिता को यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति करना तथा डीए का संदाय करना ।
- विद्यमान आईटी प्रयोगशालाओं के अलावा शाखाओं में और अधिक प्रयोगशालाओं की स्थापना करना और इस प्रयोजन के लिए आईसीएआई के अनुदान में 75% तक वृद्धि करना ।
- क्लोज्ड सीसीटीवी, स्मोक डिटेक्टर, सेंट्रल लॉकिंग प्रणाली, बीमा आदि के माध्यम से आईटी प्रयोगशालाओं को संरक्षा प्रदान करना और उन पर आने वाले व्ययों के 75% तक की आईसीएआई द्वारा प्रतिपूर्ति करना ।

- विश्वविद्यालयों में बी कॉम/एम कॉम उपाधि परीक्षाओं में स्वर्ण पदक विजेताओं को आईसीएआई द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोहों में आमंत्रित करना और उन्हें सम्मानित करना ।
- भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय और आईसीएआई के बीच किए गए परस्पर समझ ज्ञापन के निबंधनानुसार उस विश्वविद्यालय के पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए आईसीएआई के सदस्यों हेतु फीस तय करना ।
- परिषद् को ऐसे सदस्यों के लिए, जो व्यवसायगत सदस्यों से भिन्न हैं, सीपीई अध्ययन सर्किलों संबंधी सनियमों पर सिफारिश करना ।
- आईटी निदेशालय का सृजन करना ।
- सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद्/ सर्वश्रेष्ठ शाखा का चयन करते समय शाखाओं को, विभिन्न समितियों/बोर्डों द्वारा जारी उद्भासन प्रारूपों की प्रतिक्रिया में उनकी सक्रियता के लिए वरीयता प्रदान करना ।
- फर्मों के सम्मेलन के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे सदस्य को, जो अपने व्यक्ति नाम से व्यवसाय कर रहा है किसी फर्म के समतुल्य व्यवहार प्रदान करना ।
- आर्टिकलों के समापन/स्थानांतरण के लिए न्यायोचित परिस्थितियों के संबंध में परिषद् को सिफारिश करना ।
- परियोजना 'परिवर्तन' - उद्यम आईटी रणनीति का एक अध्ययन ।

4.2 वित्त समिति

परिषद् की यह स्थायी समिति चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 में किए गए संशोधनों के कारण अस्तित्व में आई । उक्त समिति, अन्य बातों के साथ, सत्य और सही लेखाओं को रखे जाने, वार्षिक बजट तैयार करने, निधियों के निवेश, निधियों से राजस्व और पूंजी, दोनों प्रकार के व्ययों के लिए आहरण करने से संबंधित और अनुषंगी गतिविधियों का नियंत्रण, कार्यान्वयन और अधीक्षण करती है ।

4.3 परीक्षा समिति

मई, 2008 में अबुधाबी, दुबई और काठमांडू में स्थित केंद्रों के अलावा 105 नगरों में स्थित क्रमशः 173 और 175 केंद्रों में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फाइनल और वृत्तिक शिक्षा-2 परीक्षाओं का आयोजन किया गया था । मई, 2008 में 129 केंद्रों पर वृत्तिक सक्षमता परीक्षा (पीसीई) का आयोजन किया गया था । जून, 2008 में, अबुधाबी और दुबई में स्थित केंद्रों के अलावा 11 नगरों के 207 केंद्रों पर सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) का आयोजन किया गया था । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स वृत्तिक शिक्षा-II, पीसीई और फाइनल (पुराना और नया पाठ्यक्रम) परीक्षाएं 1 से 16 नवंबर, 2008 के दौरान विदेशों के अतिरिक्त देश भर में क्रमशः 144, 166 और 167 केंद्रों में आयोजित की गईं ।

मई, 2008 में आयोजित फाइनल, वृत्तिक शिक्षा-2 और वृत्तिक सक्षमता परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्रमशः 25625, 33396 और 2713 थी । जून, 2008 में आयोजित सीपीटी में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 76026 थी । नवम्बर, 2008 में आयोजित पीई-2, पीसीई और फाइनल (पुराना और नया पाठ्यक्रम) परीक्षाएं देने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 27889, 32804 और 34796 थी ।

पूर्वोक्त छात्र परीक्षाओं के अलावा, वर्ष के दौरान जून, 2008 में सूचना प्रणाली संपरीक्षा - निर्धारण परीक्षा (आईएसए-एटी) में अर्होत्तर पाठ्यक्रम की निर्धारण परीक्षाओं का भी आयोजन किया गया था । इसके अतिरिक्त, प्रबंध लेखांकन पाठ्यक्रम (भाग-1), निगम प्रबंध पाठ्यक्रम (भाग-1) और कर प्रबंध पाठ्यक्रम (भाग-1) की परीक्षाओं का आयोजन मई, 2008 में छात्र परीक्षाओं के साथ किया गया था । मई, 2008 में बीमा और जोखिम प्रबंध तथा साथ ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विश्व व्यापार संगठन (आईटीएल और डब्ल्यूटीओ) में अर्होत्तर पाठ्यक्रम परीक्षाओं का आयोजन भी किया गया था ।

ऑन लाइन सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) का आयोजन 7 दिसम्बर, 2008 को 11 नगरों अर्थात् अहमदाबाद, बंगलोर, चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और पुणे में किया गया था, जिसके परीक्षा केन्द्र संस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण (आईटीटी) केन्द्रों में अवस्थित थे । इसके अतिरिक्त, पेपर -पेंसिल पद्धति सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) का आयोजन 14 दिसम्बर, 2008 को देशभर में और विदेशों में 111 शहरों में अवस्थित 221 परीक्षा केन्द्रों में किया गया था । 14 दिसम्बर, 2008 को आयोजित पेपर -पेंसिल पद्धति सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) में कुल 89026 अभ्यर्थी उपसंजात हुए थे । ऑन लाइन सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) का आयोजन 28 मार्च, 2009 को 8 नगरों अर्थात् अहमदाबाद, बंगलोर, चेन्नई, दिल्ली एनआरओ, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में किया गया था, जिसके परीक्षा केन्द्र संस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण (आईटीटी) केन्द्रों में अवस्थित थे । ऑन लाइन सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) का आयोजन 25 अप्रैल, 2009 को 15 नगरों अर्थात् अहमदाबाद, बंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली एनआरओ, गुंटूर, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पुणे, सूरत और विशाखापत्तनम में किया गया था, जिसके परीक्षा केन्द्र संस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण (आईटीटी) केन्द्रों में अवस्थित थे । ऑन लाइन सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) का आयोजन 23 मई, 2009 को 19 नगरों अर्थात् अहमदाबाद, बंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली एनआरओ, दिल्ली रोहिणी, गुंटूर,

हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे, रायपुर, सूरत, उदयपुर और विशाखापत्तनम में किया गया था, जिसके परीक्षा केन्द्र संस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण (आईटीटी) केन्द्रों में अवस्थित थे। 17 दिसम्बर, 2008, 28 मार्च, 2009, 25 अप्रैल, 2009 और तत्पश्चात् मई, 2009 में आयोजित ऑन लाइन सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) देने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 217, 106, 183 और 271 थी।

उपरोक्त छात्र परीक्षाओं के अलावा, वर्ष के दौरान 20 दिसम्बर, 2008 को देशभर में 21 नगरों (31 परीक्षा केन्द्रों में) में सूचना पद्धति संपरीक्षा - निर्धारण परीक्षण का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। साथ ही, प्रबंध लेखांकन पाठ्यक्रम (एमएसी)(भाग-I), बीमा जोखिम प्रबंध (आईआरएम) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और विश्व व्यापार संगठन (आईटीएल और डब्ल्यूटीओ) की परीक्षाओं का सफल आयोजन नवंबर, 2008 में किया गया था।

चूंकि अप्रैल और मई, 2009 के मासों में लोक सभा के साधारण निर्वाचन और अनेक राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन आयोजित किए जाने थे, इसलिए यह विनिश्चय किया गया था कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स पीई-2, पीसीई, फाइनल (पुराने और नए पाठ्यक्रम), आईआरएम, एमएसी (भाग 1), टीएमसी (भाग 1), सी.एम.सी. (भाग-1) आईटीएल और डब्ल्यूटीओ परीक्षाओं का आयोजन मई, 2009 के बजाय 1 से 15 जून, 2009 के दौरान किया जाए।

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए निम्नलिखित प्रसुविधाएं प्रदान की जाती रही हैं :

- जून, 2009 की सीए परीक्षाओं के लिए, ब्यावर, सोनीपत और पाली मारवाड़ (सोनीपत और पाली मारवाड़ केवल सीपीटी के लिए विद्यमान परीक्षा केन्द्र थे) में नए परीक्षा केन्द्र प्रारंभ किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 28 जून, 2009 को सीपीटी के लिए बिलासपुर, अलीगढ़ और बहरीन में नए परीक्षा केन्द्र खोले गए हैं।
- ओएमआर प्ररूप में परीक्षा आवेदन पत्रों को मई, 2008, नवंबर, 2008 और जून, 2009 में भी जारी रखा गया था और अभ्यर्थियों को, अभ्यर्थियों के स्केन किए गए फोटो और नमूना हस्ताक्षर से युक्त प्रवेश पत्र भी जारी किए गए थे। इससे अभ्यर्थियों को पृथक् रूप से पहचान पत्र जारी करने की आवश्यकता समाप्त हो गई थी।
- आईसीएआई के सभी प्रादेशिक कार्यालयों और प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं के अलावा दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के महानगरों में विभिन्न अवस्थानों पर परीक्षा आवेदन पत्र उपलब्ध कराना जारी रखा गया। अभ्यर्थियों को ओएमआर आवेदन पत्र में उनके द्वारा उपदर्शित व्यक्तिगत पहचान संख्यांक (पिन) का उपयोग करके वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रसुविधा प्रदान की गई थी।
- ऐसे स्थानों में, जहां आईसीएआई के प्रादेशिक/विकेन्द्रीकृत कार्यालय अवस्थित हैं, अर्थात् अहमदाबाद, बंगलौर, चैन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई और पुणे में निवास करने वाले छात्रों को विलंब शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तक संबंधित कार्यालयों में विलंब शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई थी।
- परिणाम और साथ ही अंक भी राष्ट्रीय सूचना केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए थे। परिणामों की घोषणा के साथ ही मैरिट सूची से संबंधित जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई थी।
- परिणामों की घोषणा के साथ ही आईसीएआई के प्रादेशिक कार्यालयों और प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं द्वारा परिणाम और साथ ही अंक डाउनलोड करने की प्रसुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी।
- घोषणा पर परिणाम अभिनिश्चित करने के लिए अग्रिम में अनुरोध रजिस्टर करने की प्रसुविधा को जारी रखा गया था और उसके लिए रजिस्टर करने वाले अभ्यर्थियों को, परिणामों की घोषणा के तुरंत पश्चात् ई-मेल से उनके परिणाम उपलब्ध कराए गए थे।
- मई, 2008, नवंबर, 2008 और जून, 2009 परीक्षाओं के लिए छात्रों को ई-मेल क्वैरी के माध्यम से प्रवेश-पत्र की सुविधा को जारी रखा गया था।
- मई, 2008, नवंबर, 2008 और जून, 2009 परीक्षाओं के परिणामों को एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराना जारी रखा गया था।

4.4 अनुशासन समिति

यह समिति संस्थान द्वारा प्रदत्त वृत्तिक अर्हता की प्राप्ति और स्तर बनाए रखने में परिषद् की सहायता करती है। ऐसे सदस्यों के, जिनके मामले परिषद् द्वारा समिति को 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 के दौरान प्रथम दृष्टया राय के लिए विनिर्दिष्ट किए गए थे, विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच करने के अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में समिति ने 20 अवसरों पर अपनी बैठकों की थीं जो कुल मिलाकर 32 दिन चली थी और ये बैठकें देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले स्थानों पर की गई थी। पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, समिति ने 84 मामलों में जांच की थी, जिनमें उसे पूर्व वर्षों में निर्दिष्ट मामले भी सम्मिलित थे।

5. तकनीकी और वृत्तिक विकास

5.1 लेखांकन मानक बोर्ड

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई), जो देश का एक प्रमुख लेखांकन निकाय है, देश में एक उत्तम, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। भारत में

विद्यमान विविध लेखांकन नीतियों और व्यवहारों में संगतता लाने के लिए आईसीएआई ने लेखांकन मानकों को तैयार करने के लिए वर्ष 1977 में लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) का गठन किया था। इसके गठन से ही, एएसबी नए लेखांकन मानकों को तैयार करके और साथ ही समय-समय पर विद्यमान लेखांकन मानकों को पुनरीक्षित करके इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय मानकों को, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएसबी) द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों (आईएस) और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के समरूप बनाना है। एएसबी लेखांकन मानकों के एक समान उपयोग और उनके कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर विभिन्न उद्घोषणाएं भी जारी करता है।

आईसीएआई द्वारा तैयार किए गए लेखांकन मानकों को, कंपनी अधिनियम, 1956 में धारा 211(3क), (3ख) और (3ग) अंतःस्थापित करके अक्टूबर, 1998 में विधिक मान्यता प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा 211(3ग) के अनुसार आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा लेखांकन मानक संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीएस) के परामर्श से विहित किया जा सकेगा। इस धारा के परंतुक के अनुसार, सरकार द्वारा लेखांकन मानकों की अधिसूचना जारी किए जाने तक, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों को कंपनियों द्वारा अपनाया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2006 में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत के राजपत्र में अपनी तारीख 7 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के अधीन लेखांकन मानक 1 से 7 और 9 से 29 को विहित किया था। ये मानक, इन लेखांकन मानकों के प्रकाशन की तारीख को (अर्थात् 7 दिसम्बर, 2002) या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों के संबंध में प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त, 7 मार्च, 2008 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2008 के अधीन लेखांकन मानक (एस 15) के सीमित पुनरीक्षण को अधिसूचित किया गया था। हाल ही में, केन्द्रीय सरकार द्वारा एनएसीएस के परामर्श से 27 मार्च, 2008 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2008 के अधीन लेखांकन मानक (एस 11) के संशोधन को अधिसूचित किया था।

वैश्वीकरण और उदारीकरण के साथ, पूंजी बाजार वैश्विक बन गए हैं। विदेशी पूंजी बाजारों तक पहुंच की वांछा करने वाली फर्मों को प्रायः लेखाओं के दो सेट तैयार करने होते हैं; एक घरेलू अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए और दूसरा ऐसे विदेशी बाजार के अनुसार, जहां से पूंजी प्राप्त की जानी है। बहुमानक पूंजी आबंटन की मात्रा और दक्षता पर दबाव डालते हैं क्योंकि निवेशक विभिन्न अधिकारिताओं में कंपनियों की वित्तीय जानकारी की सुगमता से तुलना नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार, वैश्विक रूप से स्वीकार्य और उच्च गुणवत्ता वाले लेखांकन मानकों के एकल सेट की आवश्यकता प्रायः महसूस की जाती रही है। आईएसबी द्वारा जारी किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को वैश्विक वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के रूप में अधिकाधिक मान्यता प्राप्त हो रही है। अनेक देशों ने विभिन्न अस्तित्वों के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए या तो आईएफआरएस को अपना लिया है अथवा अपनाए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। यद्यपि आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक मुख्यतः आईएस/आईएफआरएस पर आधारित हैं, फिर भी कतिपय मामलों में देश में विद्यमान आर्थिक परिस्थितियों के अलावा विधिक और विनियामक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लेखांकन मानकों में आईएस/आईएफआरएस से विचलन किया गया है।

हाल ही के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों से अभिसरन ने पूरे विश्व में जोर पकड़ा है। वर्तमान में 113 से अधिक देश आईएफआरएस के उपयोग की अपेक्षा करते हैं अथवा अनुमति देते हैं या उनसे अभिसरन की नीति को अपना रहे हैं। कतिपय अन्य देशों ने किसी भावी तारीख से आईएफआरएस अपनाने के अपने आशयों की घोषणाएं की हैं, उदाहरणार्थ ब्राजील और कनाडा क्रमशः 2010 और 2011 से इन्हें अपनाएंगे। यूएसए का वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड (एफएएसबी) और आईएसबी यूएस जीएपी और आईएफआरएस के अभिसरन के लिए कार्य कर रहे हैं। यूएसए का प्रतिभूति और विनियम आयोग (एसईसी) ने यह विनिश्चय किया है कि यूएस जीएपी और आईएफआरएस के बीच किसी समाधान विवरण को प्रस्तुत करने की अपेक्षा किए बिना आईएफआरएस से संगत वित्तीय विवरण फाइल करने की अनुमति प्रदान की जाए। इस परिदृश्य में, भारत जो एक महत्वपूर्ण उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था है, के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ने लोक हित अस्तित्वों के संबंध में 1 अप्रैल, 2011 से आईएफआरएस से अभिसरन का विनिश्चय किया है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने भी ऐसा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

यह अभिसरन, अन्य बातों के साथ, भारतीय अस्तित्वों को विदेशों से निम्न लागत की पूंजी प्राप्त करने में सहायता करेगा। यह चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भी, भारतीय वृत्तिकों के लिए विदेशों में बढ़ते हुए अवसरों का लाभ प्रदान करेगा।

आईएफआरएस के साथ अभिसरन के कार्यान्वयन के लिए और भारत को आईएफआरएस-संगत बनाने के लिए एएसबी ने आईएफआरएस के साथ अभिसरन की पद्धति का पता लगाने और ऐसे अभिसरन की प्राप्ति के लिए एक योजना अधिकथित करने की आज्ञा वाले एक कार्य बल को वर्ष 2006 में गठित किया था। इस कार्य बल ने एक अवधारणा पत्र तैयार किया था, जिसे एएसबी और आईसीएआई की परिषद् ने स्वीकार कर लिया था। इस अवधारणा पत्र की प्रमुख सिफारिश यह थी कि 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों के लिए बड़े आकार की कंपनियों और लोक

हित संगठनों जैसे कि सूचीबद्ध अस्तित्वों, बैंकों और बीमा अस्तित्वों आदि के आईएफआरएस के साथ अभिसरन की अनुमति प्रदान की जाए।

तथापि, परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अभिसरन के विनिश्चय के कार्यान्वयन में सम्मने आने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए उपयुक्त उपांतरणों के साथ इस योजना पर पुनः विचार किया जा रहा है।

आईएफआरएस के साथ अभिसरन के विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए, एसबी ने वर्ष 2011 से आईएफआरएस को सुगम रूप से लागू करने के लिए विभिन्न कृत्य करने हेतु एक समूह का गठन किया था। इस समूह ने (क) एसबी की कार्य योजना तैयार करने और आईएसबी के साथ परस्पर संपर्क करने के लिए ; (ख) सरकार और विनियामक प्राधिकारियों से बातचीत करने के लिए ; (ग) उद्योग संघ से परस्पर संपर्क करने के लिए, और (घ) आईएफआरएस पर शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए जिससे कि एकाउंटेंट अभिसरन के लिए तैयार हो सकें, आगे चार उपसमूहों का गठन किया था।

बोर्ड इस उद्देश्य के साथ कार्य कर रहा है कि ऐसे भारतीय - समतुल्य मानक जारी किए जाएं जो आईएसबी द्वारा जारी सभी आईएस/आईएफआरएस के तत्समान हों। सरकार और विनियामक प्राधिकारियों से बातचीत के लिए उपसमूह का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि वह आईएफआरएस के साथ अभिसरन के कारण उद्भूत होने वाले विरोधाभासी विधिक और विनियामक अपेक्षाओं की पहचान करे और जहां उचित हो विभिन्न विधियों और विनियमों में परिवर्तन करने के लिए सुसंगत प्राधिकारियों से बातचीत करे। इस उपसमूह ने कंपनी अधिनियम, सेबी नियमों और विनियमों के लिए आईएफआरएस को अपनाए जाने से संबंधित मुद्दों और इसके अतिरिक्त बीमा अस्तित्वों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित मुद्दों की पहचान करने के लिए एक कोर समूह का गठन किया था। कंपनी अधिनियम, 1956 तथा सेबी नियमों तथा विनियमों (परस्पर निधियों से भिन्न) में अपेक्षित परिवर्तनों संबंधी रिपोर्टों को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है। इन विधियों में आवश्यक संशोधन करने के लिए सुसंगत प्राधिकारियों से बातचीत की जा रही है। अन्य रिपोर्टों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

उद्योग संघों के साथ परस्पर संपर्क करने के लिए उपसमूह का गठन इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि वह आईएफआरएस के कार्यान्वयन के संबंध में उद्योग/विनिर्दिष्ट मत प्राप्त करने के पश्चात् आईएफआरएस अपनाए जाने के लिए उद्योग को तैयार करने में उनका सहयोग प्राप्त करेगा। इस संबंध में, इस समूह ने एसबी के सहयोग से विभिन्न उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों की हैं। सभी संघों ने आईएफआरएस के साथ अभिकरण का समर्थन किया है।

शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी उपसमूह का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि वह तैयार करने वालों, संपरीक्षकों और अन्य लेखांकन कृतिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकताओं पर विचार करे। इस संबंध में, मुंबई, दिल्ली, बंगलोर, पुणे, कोलकाता और हैदराबाद में आईएफआरएस संबंधी एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसमें 60 घंटों का ई-पठन और 30 घंटों का कक्षा अध्यापन सम्मिलित है। आईएफआरएस संबंधी एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए 29 मार्च, 2009 को एक परीक्षा का भी आयोजन किया गया था जिसमें 128 व्यक्ति उपसंजात हुए थे जिनमें से 116 को उत्तीर्ण घोषित किया गया था। महत्वपूर्ण रूप से, लगभग 700 सदस्यों ने इस पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण करवाया है। इसके अतिरिक्त, फिक्की, एसोकेम और सीआईआई से भी उद्योग के लिए आईएफआरएस जागरूकता कार्यक्रम आयोजन करने के लिए संपर्क किया गया है।

जहां तक सघु और मध्यम आकार के अस्तित्वों का संबंध है, आईएसबी ने एसएमई के लिए आईएफआरएस की अपेक्षाओं पर विचार करने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया है। यह समूह इस बात की समीक्षा करेगा कि क्या भारत में एसएमई के लिए समान सन्नियमों को अपनाया जा सकता है अथवा क्या विद्यमान मानक जारी रहने चाहिए।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लेखांकन मानक बोर्ड के अन्य क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

5.1.1 अंतरराष्ट्रीय लेखांकन बोर्ड (आईएसबी) के क्रियाकलापों में सहयोग और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर प्रतिक्रिया करना

बोर्ड विभिन्न स्तरों पर आईएसबी के साथ परस्पर क्रियाएं करता है जैसे कि :

- विश्व मानक - निर्धारकों (डब्ल्यूएसएस), राष्ट्रीय मानक - निर्धारकों (एनएसएस) और प्रादेशिक मानक - निर्धारकों (आरएसएस) की बैठकों में आईएसबी के साथ सक्रिय भागीदारी।

इस संबंध में, अध्यक्ष और सचिव, एसबी ने 10 सितम्बर, 2008 को पेरिस में आयोजित एनएसएस की बैठक में भाग लिया था, जहां उन्होंने अवधारणात्मक ढांचे, एसबी समेकित परियोजना और जटिल वित्तीय लिखतों के लिए लेखांकन सहित विभिन्न मुद्दों पर परिचर्चा में भाग लिया था। आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने विभिन्न सुझाव दिए थे, जिनमें से अनेक को स्वीकार कर लिया गया था। उन्होंने 11 सितम्बर, 2008 से लंदन में डब्ल्यूएसएस की एक दो दिवसीय बैठक में भाग लिया था, जहां अध्यक्ष, एसबी ने वर्ष 2011 से भारत में आईएफआरएस के साथ अभिसरन के लिए किए गए उपायों के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण दिया था।

- बोर्ड ने आईएसबी द्वारा जारी विभिन्न उद्भासन प्रारूपों/परिचर्चा पत्रों को परिचालित किया था और अपनी वेबसाइट पर भी रखा था और उनके संबंध में विभिन्न पणधारियों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। सुसंगत समझी गई टिप्पणियों को आईएसबी के समक्ष रखा गया था।

आईएफआरएस के साथ अभिसरन संबंधित रहने के दौरान और अधिक प्रभावपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बोर्ड, समय-समय पर ऐसे अध्ययन समूहों का गठन करता है जो आईएसबी द्वारा जारी परिचर्चा पत्रों या उद्भासन प्रारूपों का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण के पश्चात् ये समूह भारत-विनिर्दिष्ट आशंकाओं को सूचीबद्ध करते हुए अपनी टिप्पणियां भेजते हैं जिनका एसबी द्वारा उन्हें आईएसबी को भेजे जाने से पूर्व पुनर्विलोकन किया जाता है।

- आईएसबी के पद्धारियों, श्री वेन एस. उपटन, अंतरराष्ट्रीय क्रियाकलाप निदेशक और श्री प्रभाकर कालवाचेरला, पूर्णकालिक सदस्य, आईएसबी ने 12 मई, 2009 को आईसीआई का दौरा किया था, जहां बोर्ड ने उनके साथ आईएफआरएस के साथ अभिसरन में अंतर्कलित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था।

5.1.2 लेखांकन मानकों संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीएस) के साथ परस्पर क्रियाएनएसीएस ने आईसीआई द्वारा इस अवधि के दौरान विरचित पुनरीक्षित लेखांकन मानक (एस) 2, सूचियां, लेखांकन मानक (एस) 3, नकद प्रवाह विवरण पर विचार किया था। एसबी ने एनएसीएस द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया और एसबी के समाधानप्रद रूप में समुचित रीति से उनका समाधान किया। बोर्ड द्वारा तैयार किए गए लेखांकन मानक (एस) 12, सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटन को पहले ही एनएसीएस द्वारा अधिसूचना के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय को भेज दिया गया है।

5.1.3 विनियामक निकायों के साथ परस्पर क्रिया

प्रमुख लेखांकन निकाय होने के कारण, आईसीआई, एसबी के माध्यम से विभिन्न लेखांकन विषयों पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए समय-समय पर विभिन्न विनियामक निकायों से परस्पर क्रिया करता है। पूर्वोक्त के अतिरिक्त, विभिन्न लेखाकरण मुद्दों पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पद्धारियों के साथ नियमित बैठकें की गई थी।

5.1.4 अन्य परियोजनाएं

- प्रमाणित उत्सर्जन अधिकारों (सीआईआर) के लिए लेखांकन के महत्व को महसूस करने के पश्चात्, पिछले वर्ष उनसे संबंधित सभी सुसंगत मुद्दों का समाधान करने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया गया था। इस अध्ययन समूह ने स्व-जनित प्रमाणित उत्सर्जन कमियों (सीआईआर) के लिए लेखांकन संबंधी प्रारूप मार्गदर्शक टिप्पण तैयार किया था जिस पर एसबी ने विचार किया था और उसे जनता से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए उद्भासन प्रारूप के रूप में जारी किया गया था।
- कुछ समय पहले सेवा रियायत ठहरावों के संबंध में मार्गदर्शन जारी करने के उद्देश्य से एक अध्ययन समूह का गठन किया गया था। इस अध्ययन समूह ने सेवा रियायत करारों के लिए लेखांकन संबंधी प्रारूप मार्गदर्शक टिप्पण तैयार किया था जिस पर एसबी ने विचार किया था और उसे जनता से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए उद्भासन प्रारूप के रूप में जारी किया गया था।
- एस 11 अधिसूचना - कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2009, जिन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, के संबंध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए गए हैं।

5.1.5 नए विमोचन

नए लेखांकन मानकों का जारी किया जाना

- लेखांकन मानक (एस) 32, वित्तीय लिखतें : प्रकटन

- एस 11 अधिसूचना - कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2009, जिन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, के संबंध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए गए हैं।
- एसबी, परिषद् द्वारा अनुमोदित, एनएसीएस द्वारा अनुमति प्राप्त और एमसीए द्वारा अधिसूचना से जारी किए जाने के लिए तैयार लेखांकन मानक।

- लेखांकन मानक (एस) 2, सूचियों का मूल्यांकन

- लेखांकन मानक (एस) 3, नकद प्रवाह विवरण

- लेखांकन मानक (एस) 10, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

- लेखांकन मानक (एस) 12, सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटन

- जनता की टिप्पणियों के लिए जारी नए/पुनरांशित लेखांकन मानकों, मार्गदर्शक टिप्पणों का प्रारूप

- एस 16, उधार लागतें

- एस 1, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुती
- आईएफआरआईसी के समरूप सेवा रियायत ठहरावों के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण
- स्वजनित प्रमाणित उत्सर्जन कमियों के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण
- जनता की टिप्पणियों के लिए अंतिम रूप दिए जा रहे नए/पुनरीक्षित लेखांकन मानकों का प्रारूप
 - एस 7, संनिर्माण संविदाएं
- संस्थान की परिषद् के सदस्यों, विनिर्दिष्ट बाहरी निकायों और एनएसीएस के बीच प्रचालन के लिए नए/पुनरीक्षित लेखांकन मानकों का प्रारूप
 - एस 29, उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां
 - एस 25, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग
 - एस 33, शेयर आधारित संदाय
- संस्थान की परिषद् के सदस्यों, विनिर्दिष्ट बाहरी निकायों और एनएसीएस के लिए अंतिम रूप दिए जा रहे नए/पुनरीक्षित लेखांकन मानकों का प्रारूप
 - एस 4, रिपोर्टिंग तारीख के बाद की घटनाएं
 - एस 11, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव
 - एस 15, कर्मचारियों के फायदे
 - एस 17, प्रचालन खंड
 - एस 21, समेकित और पृथक वित्तीय विवरण
 - एस 23, सहबद्ध फर्मों में निवेश
 - एस 28, आस्तियों का हानिकरण
 - आईएस 29, अत्यधिक मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग, के तत्समान लेखांकन मानक
 - आईएफआरएस 6, खनिज संसाधनों की खोज और मूल्यांकन, के तत्समान लेखांकन मानक
- पुनरीक्षणाधीन लेखांकन मानक
 - आईएस 18, राजस्व के तत्समान लेखांकन मानक (एस) 9
 - आईएस 12, आयकर के तत्समान लेखांकन मानक (एस) 22
 - आईएस 38, अमूर्त आस्तियां के तत्समान लेखांकन मानक (एस) 26
 - आईएफआरएस 3, कारबार संयोजन के तत्समान लेखांकन मानक (एस) 14
 - आईएस 8, लेखांकन नीतियां, लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन और त्रुटियों के तत्समान लेखांकन मानक (एस) 5
- नए लेखांकन मानक तैयार करना
 - आईएस 26, सेवानिवृत्ति फायदा योजनाओं का लेखांकन और रिपोर्टिंग के तत्समान लेखांकन मानक
 - आईएस 40, निवेश संपत्ति के तत्समान लेखांकन मानक
 - आईएस 41, कृषि के तत्समान लेखांकन मानक
 - आईएफआरएस 1, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का पहली बार अपनाया जाना के तत्समान लेखांकन मानक
 - आईएफआरएस 4, बीमा संविदाएं के तत्समान लेखांकन मानक
- एसबी के विधाराधीन पुनरीक्षित लेखांकन मानकों का प्रारूप
 - लेखांकन मानक (एस) 19, पट्टे (आईएस के तत्समान पुनरीक्षणाधीन है)

- लेखांकन मानक (एस) 24, गैर चालू आस्तियाँ, जिन्हें विक्रय के लिए धारित किया गया है और बंद कर दिए गए प्रचालन (आईएस के तत्समान पुनरीक्षणाधीन हैं)।
- लेखांकन मानक (एस) 20, प्रति शेयर उपार्जन

अन्य परियोजनाएँ

- पुनरीक्षणाधीन लेखांकन मानकों के विवरणों का प्राक्कथन
- अवधारणा पत्र का पुनरीक्षण

5.2 स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन संबंधी समिति

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकाधिक स्थानीय निकाय लेखांकन के नकद आधार से प्रोदभवन आधार पर स्थानांतरित हो रहे हैं, स्थानीय निकायों के लिए उच्च क्वालिटी के वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के एक एकल सेट की आवश्यकता को मान्यता देते हुए, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की परिषद् ने मार्च, 2005 में स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों संबंधी एक स्वतंत्र समिति (सीएसएलबी) का गठन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रोदभवन आधार पर स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक तैयार करना था।

सीएसएलबी की संरचना काफी व्यापक है और यह मानक नियतन प्रक्रिया में सभी हितबद्ध समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। आईसीएआई की परिषद् के सदस्यों के अलावा सीएसएलबी में शहरी विकास मंत्रालय, भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेखा महानियंत्रक, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, पंचायती राज मंत्रालय, प्रमुख स्थानीय निकायों के निदेशालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभागों के निदेशालयों, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और आईसीएआई द्वारा सहयोजित अन्य सुविख्यात वृत्तिक सम्मिलित हैं।

स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक विरचित करने के अलावा, समिति स्थानीय निकायों की लेखांकन पद्धतियों और प्रणालियों में सुधार करने के लिए भी उपाय करती है और वह स्थानीय निकायों द्वारा प्रोदभवन लेखांकन अपनाने और स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों के प्राक्कथन में यथा अधिकथित लेखांकन मानकों को लागू करने में आने वाली समस्याओं के संबंध में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के मंच के रूप में कार्य करती है।

स्थानीय निकायों के लेखांकन मानक विरचित करते समय, सीएसएलबी अंतरराष्ट्रीय लेखांकन फ्रेमवर्क (आईएफएसी) के अंतरराष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड (आईपीएसएसबी) द्वारा तैयार किए गए अंतरराष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानकों पर सम्यक रूप से विचार करती है और वैश्विक संगतता को सुकर बनाने के विचार से उन्हें यथा संभव रूप से एकीकृत करने की चेष्ट करती है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समिति ने तीन प्रकाशनों अर्थात् स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक 3, 'विनियम संव्यवहारों से राजस्व' और स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक 4, 'उधार लेने संबंधी लागत' तथा "स्थानीय निकायों के लिए प्रोदभवन लेखांकन: निर्वाचित प्रतिनिधि और पणधारी" को जारी किया है। समिति ने प्रस्तावित राष्ट्रीय नगरपालिक आस्ति मूल्यांकन पद्धति मैनुअल, जिसे राष्ट्रीय शहरी कार्य द्वारा विकसित किया गया है, पर भी टिप्पणियाँ अग्रेषित की हैं।

'स्थानीय निकायों द्वारा वित्तीय रिपोर्टों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए ढांचे' के प्रारूप को, विनिर्दिष्ट बाहरी निकायों और आईसीएआई के परिषद् सदस्यों के बीच उसके सीमित परिचालन पर प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर लोक उद्भासन के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रारूप ढांचा ऐसी अवधारणाओं को अधिकथित करता है, जो वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने में आधारिक हैं और जो समिति के स्थानीय निकायों के लिए भावी लेखांकन मानकों के विकास में सहायता करेंगे। 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण' संबंधी स्थानीय निकायों के लिए प्रस्तावित लेखांकन मानक के प्रारूप को विनिर्दिष्ट बाहरी निकायों और परिषद् सदस्यों के बीच सीमित परिचालन के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएसएलबी ने अंतरराष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानकों के तत्समान स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों को तैयार करने के लिए अनेक अन्य परियोजनाएँ भी आरंभ की हैं।

समिति ने अंत उपयोगिताओं के फायदे के लिए, 15-17 जनवरी, 2009 के दौरान गोवा में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से 'स्थानीय निकायों में लेखांकन सुधारों का कार्यान्वयन : वर्तमान परिदृश्य और आगे की योजना' विषय पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया है। समिति इसी रूप रेखा पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 उत्तरपूर्व के राज्यों में अंत उपयोगिताओं के फायदे के लिए अन्य जागरूकता कार्यशालाओं को आयोजित करने का प्रस्ताव कर रही है। समिति चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए भी, उनके बीच स्थानीय निकायों द्वारा अपनाई जाने वाली सुधार प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप उभरने वाले अवसरों के संबंध में जागरूकता बनाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करने का प्रस्ताव कर रही है।

आईसीएआई, सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जीएसएबी) का सदस्य है और इसे जीएसएबी द्वारा समय-समय पर विरचित विभिन्न उप समितियों में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने वर्ष के दौरान आयोजित जीएसएबी की बैठकों में भाग लिया और बोर्ड की तकनीकी गतिविधियों में योगदान दिया। सीएसएलबी, जीएसएबी द्वारा तैयार विभिन्न प्रक्रमों के प्रारूपों पर टिप्पणियाँ तैयार करती है।

स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों संबंधी समिति के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

अध्ययन समूह से प्राप्त प्रारंभिक प्रारूप

- 'खंड रिपोर्टिंग' पर स्थानीय निकायों के लिए प्रस्तावित लेखांकन मानक (एएसएलबी)

लोक उदमसासन के लिए तैयार की जा रही उदघोषणाओं का प्रारूप

- स्थानीय निकायों द्वारा वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने और उनके प्रस्तुतीकरण के लिए ढांचा
- स्थानीय निकायों में लेखांकन सुधार और चार्टर्ड एकाउंटेंटों की भूमिका पर प्रास्थिति पत्र

संस्थान की परिषद् के सदस्यों, विनिर्दिष्ट बाहरी निकायों के लिए अंतिम रूप दी जा रही उदघोषणाओं का प्रारूप

- 'उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियों' पर स्थानीय निकायों के लिए प्रस्तावित लेखांकन मानक (एएसएलबी)
- 'संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर' पर स्थानीय निकायों के लिए प्रस्तावित लेखांकन मानक (एएसएलबी)
- 'रिपोर्टिंग तारीख के पश्चात् की घटनाओं' पर स्थानीय निकायों के लिए प्रस्तावित लेखांकन मानक (एएसएलबी)
- 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुती' पर स्थानीय निकायों के लिए प्रस्तावित लेखांकन मानक (एएसएलबी)
- 'गैर-विनिमय संव्यवहारों से राजस्व' पर स्थानीय निकायों के लिए प्रस्तावित लेखांकन मानक (एएसएलबी)
- 'संनिर्माण संविदाओं' पर स्थानीय निकायों के लिए प्रस्तावित लेखांकन मानक (एएसएलबी)

ऐसी अन्य परियोजनाएं, जिनके लिए विभिन्न अध्ययन समूह प्रारूप तैयार कर रहे हैं :

- स्थानीय निकायों के लिए प्रस्तावित लेखांकन मानकों का प्रारूप
 - नकद प्रवाह विवरण
 - लेखांकन नीतियां, लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन और त्रुटियां
 - सूचियां
 - विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव
- अन्य परियोजनाएं
 - प्रोदमवन लेखांकन के फायदों को दर्शित करने वाली पुस्तिका का विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद

5.3 संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड

वार्षिक रूप से तैयार और प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय विवरणों का उद्देश्य व्यापक उपयोक्ताओं की सामान्य जानकारी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। संपरीक्षा इन वित्तीय विवरणों को विश्वसनीयता प्रदान करती है। अतः संपरीक्षा आर्थिक विकास के रास्ते को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि संपरीक्षा उच्च गुणवत्ता की हो और उन्हें लोक हित के अंतर्निहित उद्देश्य से पूरा किया जाए। इस प्रकार लेखांकन वृत्ति, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत बैचमार्क के कतिपय सैट से युक्त है जिनके संदर्भ में किसी संपरीक्षक के कार्यपालन का मापतौल किया जा सकता है। लेखांकन मानकों में वृत्तिकों के लिए इस संबंध में मार्गदर्शन अंतर्विष्ट होते हैं कि उन्हें अपने वृत्तिक कार्य मूल सिद्धांतों के आधार पर करना चाहिए और उन मूल सिद्धांतों को लागू करने के लिए अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए जो निर्णय या व्यवहार से संबंधित होती हैं। लेखांकन मानकों की विरचना वृत्तिक कार्यों की इमानदारी, अखंडता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए की जाती है, जो कारबार उद्यमों द्वारा रिपोर्ट की जाने वाली वित्तीय जानकारी के प्रति समाज का भरोसा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।

भारत में संस्थान का संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड, संपरीक्षा, पुनर्विलोकन, अन्य आश्वासन, गुणवत्ता नियंत्रण और संबद्ध सेवाओं से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले मानक तैयार कर रहा है और जारी कर रहा है, जो देश में संपरीक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यवहारों के संहिताकरण का कार्य है और इसलिए आज्ञापक प्रकृति का है। बोर्ड द्वारा परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी मानकों को अंतरराष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा अंतरराष्ट्रीय संपरीक्षा मानकों (आईएसए) के साथ बैचमार्क किया जाता है। 2007 में एएसबी ने आईएएसबी के तत्समान कार्यक्रम के आधार पर अपनी स्पष्टीकारक परियोजना प्रारंभ की थी। उक्त परियोजना के अनुसरण में बोर्ड ने संपरीक्षा मानकों के पुनःसंख्यांकन और पुनःवर्गीकरण के अलावा उन तरीकों में भी आमूलचूल परिवर्तन किए हैं जिनमें उनको लिखा जाता है और समझा जाता है। बोर्ड ने 16 नए/पुनरीक्षित संपरीक्षा मानक जारी किए हैं और वर्ष 2010 के अंत तक पूर्ण/पुनरीक्षित संपरीक्षा मानकों का पूर्ण सैट सुस्थापित हो जाएगा।

मानकों के अलावा, बोर्ड परिषद् के प्राधिकार के अधीन मार्गदर्शन टिप्पणों की विरचना करता है और उन्हें जारी करता है। बोर्ड सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए अपने स्वयं के प्राधिकार के अधीन तकनीकी गाइडों, व्यवहार संबंधी मैन्युअलों, अध्ययनों और अन्य पत्रों की भी विरचना करता है। क्लैरिटी परियोजना के अधीन जारी संपरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड क्लैरिटी परियोजना के अधीन जारी मानकों से संबंधित एक कार्यान्वयन गाइड भी तैयार कर रहा है।

बोर्ड की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

➤ **नियोजन और क्वालिटी नियंत्रण मानक**

क्वालिटी नियंत्रण मानक

क्वालिटी नियंत्रण संबंधी मानक (एसक्यूसी) 1, “ऐसी फर्मों के लिए जो संपरीक्षा करती हैं क्वालिटी नियंत्रण और ऐतिहासिक वित्तीय सूचना का पुनर्विलोकन और अन्य आश्वासन तथा संबंधित सेवाओं का नियोजन”

नियोजन मानक

- संपरीक्षा संबंधी 33 मानक, जिनके अंतर्गत क्लैरिटी परियोजना के अधीन 22 मानक और 1 साधारण स्पष्टीकरण हैं (नीचे सूचीबद्ध किए गए अनुसार)
- पुनर्विलोकन नियोजन संबंधी एक मानक
- आश्वासन नियोजन संबंधी एक मानक
- संबंधित सेवाओं संबंधी 2 मानक

➤ **संपरीक्षा संबंधी विवरण और मार्गदर्शन टिप्पण**

- 2 विवरण (सूची अनुलग्नक 2 के अनुसार दी गई है)
- लेखापरीक्षा मुद्दों पर 31 मार्गदर्शन टिप्पण, जैसा कि संपरीक्षा उदघोषणाओं संबंधी पुस्तिका में दिए गए हैं, जो अनुलग्नक 3 के रूप में संलग्न है

➤ **उद्योग विनिर्दिष्ट मार्गदर्शन टिप्पण**

- बैंकों की संपरीक्षा (पुनरीक्षित 2009 संस्करण)
- स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों के लेखाओं की संपरीक्षा
- साधारण बीमा कारबार कर रही कंपनियों की संपरीक्षा
- जीवन बीमा कारबार कर रही कंपनियों की संपरीक्षा

➤ **अन्य प्रकाशन (गैर-आधिकारिक)**

- संपरीक्षा उदघोषणाओं की पुस्तिका (2008 संस्करण)
- संपरीक्षा और आश्वासन मानकों पर पृष्ठभूमि सामग्री
- टेलीकाम उद्योग में संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड - राजस्व, नियत आस्तियां और संबंधित प्रचालन लागतें
- ई-कॉमर्स संबंधी तकनीकी गाइड - वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए विचार
- बेसल 2 और जोखिम आधारित अधीक्षण पर एक अध्ययन
- एसक्यूसी 1 संबंधी कार्यान्वयन गाइड
- वित्तीय विवरणों की जोखिम आधारित संपरीक्षा संबंधी कार्यान्वयन गाइड

5.3.1 वर्ष 2008-09

वर्ष 2008-09 के दौरान लेखांकन और आश्वासन मानक बोर्ड की 7 बैठकें हुई थी, जिनमें कुल 11 दिन की पूर्ण बोर्ड परिचर्चाएं हुई थी। इस वर्ष के दौरान, बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय संपरीक्षा मानकों (आईएसए) के साथ अभिसरन की प्रक्रिया को त्वरित बनाया। बोर्ड ने “आईएएसबी के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ अभिसरन - प्रास्थिति पत्र और कार्य योजना” जारी किया था। इस पत्र में आईएएसबी द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ अभिकरण के संबंध में संस्थान की प्रास्थिति और नीति और इस दिशा में निरंतर कार्य करने की आवश्यकता को अधिकथित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पत्र में अभिसरन के क्षेत्र में एएसबी के समक्ष आवश्यक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया है। इस पत्र में आईएएसबी मानकों के साथ अभिसरन प्राप्त करने के संदर्भ में संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (एएसबी) की कार्ययोजना पर भी विचार-विमर्श किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस पत्र में आईएएसबी के साथ अभिसरन के संबंध में आईसीएआई के पहलों पर भी विचार-विमर्श किया गया है। इसके अतिरिक्त, आईएएसबी मानकों के साथ

अभिसरन की प्रक्रिया में बोर्ड ने इस वर्ष के दौरान, संपरीक्षा संबंधी बारह (12) मानकों (एसए) को क्लैरिटी परियोजना के अंतर्गत जारी किया है, जो निम्नानुसार हैं :

पुनरीक्षित एसए 230, “संपरीक्षा दस्तावेजीकरण”

एसए 230, संस्थान द्वारा वर्ष 1985 में जारी तत्कालीन संपरीक्षा और आश्वासन मानक (एएस) 3 ‘दस्तावेजीकरण’ का पुनरीक्षित पाठ है। यह नया मानक किन्हीं वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए संपरीक्षा दस्तावेजीकरण तैयार करने के संपरीक्षक के उत्तरदायित्व से संबंधित है। एसए 230 संपरीक्षा दस्तावेजीकरण, की गई संपरीक्षा प्रक्रियाओं दस्तावेजीकरण और अभिप्राप्त किए गए संपरीक्षा साक्ष्यों और अंतिम संपरीक्षा फाइनल को समय पर तैयार करने की अपेक्षाओं से भी संबंधित है। यह एसए 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 250, “किन्हीं वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा में विधियों और विनियमों को विचार में लेना”

एसए 250, संस्थान द्वारा वर्ष 2001 में जारी तत्कालीन संपरीक्षा और आश्वासन मानक (एएस) 21 ‘किन्हीं वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा में विधियों और विनियमों को विचार में लेना’ का पुनरीक्षित पाठ है। यह नया मानक संपरीक्षक के, वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा करते समय विधियों और विनियमों को ध्यान में रखने के उत्तरदायित्व से संबंधित है। एसए 250 विधियों और विनियमों के प्रभाव विधियों और विनियमों के अनुपालन के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व, संपरीक्षक के उत्तरदायित्व, संपरीक्षा प्रक्रियाओं और पहचान किए गए या संदिग्ध दस्तावेजों की अपेक्षाओं के अनुपालन की रिपोर्टिंग के संबंध में कथन करता है। यह एसए 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 260, “ऐसे व्यक्तियों के साथ संपर्क जिन्हें शासन का प्रभार सौंपा गया है”

एसए 260, संस्थान द्वारा वर्ष 2003 में जारी तत्कालीन संपरीक्षा और आश्वासन मानक (एएस) 27 ‘ऐसे व्यक्तियों के साथ संपरीक्षा मुद्दों पर संपर्क जिन्हें शासन का प्रभार सौंपा गया है’ का पुनरीक्षित पाठ है। यह नया मानक संपरीक्षक के, वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के साथ संपरीक्षा मुद्दों पर संपर्क करने, जिन्हें शासन का प्रभार सौंपा गया है, के उत्तरदायित्व से संबंधित है। एसए 260 शासन के प्रभारी व्यक्तियों से संबंधित अपेक्षाओं, उन्हें संसूचित किए जाने वाले विषयों और दस्तावेजों का भी वर्णन करता है। यह एसए 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 500, “संपरीक्षा साक्ष्य”

संपरीक्षा साक्ष्य किसी संपरीक्षा का मूल पहलू है जिस पर अंतिम संपरीक्षा राय और संपरीक्षा रिपोर्ट आधारित होती है। अतः किसी संपरीक्षा की गुणवत्ता और प्रभाविकता काफी हद तक संपरीक्षक की संपरीक्षा साक्ष्य एकत्रित करने और उनका मूल्यांकन करने की प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और उपयुक्तता से प्रभावित होती है। यद्यपि संस्थान की परिषद् ने मई, 1988 में संपरीक्षा साक्ष्य संबंधी एक मानक जारी किया है, फिर भी इस मानक के पुनरीक्षित पाठ में संपरीक्षकों के लिए संपरीक्षा साक्ष्य के महत्वपूर्ण पहलुओं पर वृहत मार्गदर्शन अंतर्विष्ट हैं, जैसे कि पर्याप्त, उपयुक्त संपरीक्षा साक्ष्य क्या है, संपरीक्षा साक्ष्य के रूप में कौन सी जानकारी का उपयोग किया जाए, परीक्षण के लिए मद्दों का चयन करते समय किन तथ्यों को ध्यान में रखा जाए, संपरीक्षा साक्ष्य की असंगतता या उसकी विश्वसनीयता में संदेह की दशा में किस प्रकार प्रतिक्रिया की जाए। अन्य शब्दों में, पुनरीक्षित मानक ऐसे सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है जिन्हें ऐसे संपरीक्षा साक्ष्य, जो संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों, अभिप्राप्त करने और उनके मूल्यांकन के लिए अपनाया जाए। पुनरीक्षित मानक 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए सभी वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 510, “प्रारंभिक संपरीक्षा नियोजन - प्रारंभिक अतिशेष”

एसए 510, संस्थान द्वारा जुलाई, 2001 में जारी तत्कालीन संपरीक्षा और आश्वासन मानक (एएस) 22 ‘प्रारंभिक संपरीक्षा नियोजन - प्रारंभिक अतिशेष’ का पुनरीक्षित पाठ है। यह नया मानक संपरीक्षक के, प्रारंभिक संपरीक्षा नियोजनों के संबंध में कार्यवाही करते समय प्रारंभिक अतिशेषों से संबंधित उत्तरदायित्व से संबंधित है। यह एसए 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 530, “संपरीक्षा का नमूना”

एसए 530, संस्थान द्वारा अप्रैल, 1998 में जारी तत्कालीन संपरीक्षा और आश्वासन मानक (एएस) 15 ‘संपरीक्षा का नमूना’ का पुनरीक्षित पाठ है। यह मानक संपरीक्षकों के लिए, उनके संपरीक्षा समनुदेशनों में नमूना लेने की तकनीकों का उपयोग करते समय एक मानक गाइड है और इसके अंतर्गत सांख्यिकीय और गैर सांख्यिकीय, दोनों प्रकार के नमूने आते हैं। यह

एसए 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 540, “लेखांकन प्राक्कलनो, उचित मूल्य लेखांकन प्राक्कलनों सहित की संपरीक्षा और अन्य संबद्ध प्रकटन”

एसए 540, संस्थान द्वारा अप्रैल, 2000 में जारी तत्कालीन संपरीक्षा और आश्वासन मानक (एएएस) 18 ‘लेखांकन प्राक्कलनो की संपरीक्षा’ का पुनरीक्षित पाठ है। यह मानक बाजारों की अनिश्चितता और नकद धन की कमी के वर्तमान समयों में उचित मूल्य और लेखांकन प्राक्कलनों की संपरीक्षा के संबंध में सम्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। लेखांकन प्राक्कलन, किसी मापमान के सटीक उपाय की अनुपस्थिति में धनीय राशियों का अनुमान है। इसमें सारवान मिथ्या कथनों का जोखिम काफी बढ़ जाता है क्योंकि लेखांकन प्राक्कलनो में प्रबंधन द्वारा निर्णय का उपयोग अंतर्वलित होता है। यह मानक ऐसी जटिल वित्तीय लिखतों के, जिनका सक्रिय रूप से तथा खुले बाजार में व्यापार नहीं किया जा रहा है और धनीय प्रतिफल के बिना विनिमय पक्षकारों को अंतर्वलित करने वाले संव्यवहारों के मूल्यांकन का सत्यापन करते समय संपरीक्षकों को विनिर्दिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह एसए 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 550, “संबंधित पक्षकार”

एसए 550, संस्थान द्वारा अप्रैल, 2001 में जारी तत्कालीन संपरीक्षा और आश्वासन मानक (एएएस) 23 ‘संबंधित पक्षकार’ का पुनरीक्षित पाठ है। इस मानक का उद्देश्य, संपरीक्षकों द्वारा संबंधित पक्षकार संबंधों को समझने की आवश्यकता पर और ऐसे सारवान मिथ्या कथनों की, जो उनके कारण उदभूत हो सकेंगे, पहचान करने के लिए संव्यवहारों पर बल देकर तथा संपरीक्षक को कपट के कारण होने वाले सारवान मिथ्या कथनों सहित ऐसे मिथ्या कथनों के निर्धारित जोखिम पर अपने कार्य प्रयासों को केन्द्रित करने का निदेश देकर इस क्षेत्र में वर्तमान संपरीक्षा व्यवहारों को मजबूत करना है। यह एसए 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 560, “पश्चातवर्ती घटनाएं”

एसए 560, संस्थान द्वारा अप्रैल, 2000 में जारी तत्कालीन संपरीक्षा और आश्वासन मानक (एएएस) 19 ‘पश्चातवर्ती घटनाएं’ का पुनरीक्षित पाठ है। यह नया मानक संपरीक्षक की किन्हीं वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा में पश्चातवर्ती घटनाओं से संबंधित उत्तरदायित्व से संबद्ध है। एसए 560 वित्तीय विवरणों की तारीख और संपरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बीच होने वाली घटनाओं, ऐसे तथ्यों, जो संपरीक्षक को संपरीक्षक की रिपोर्ट के पश्चात् किन्तु वित्तीय विवरण जारी करने से पूर्व ज्ञात होते हैं और ऐसे तथ्य, जो संपरीक्षक को वित्तीय विवरण जारी होने के पश्चात् ज्ञात होते हैं, से भी संबंधित है। यह एसए 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 570, “गोइंग कंसर्न”

एसए 570, संस्थान द्वारा अप्रैल, 1998 में जारी तत्कालीन संपरीक्षा और आश्वासन मानक (एएएस) 16 ‘गोइंग कंसर्न’ का पुनरीक्षित पाठ है। यह नया मानक प्रबंध द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनके प्रस्तुतीकरण में गोइंग कंसर्न अनुमान के उपयोग के संबंध में वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा में संपरीक्षक के उत्तरदायित्व के निबंधनानुसार ब्यौरे अंतर्विष्ट करता है। एसए 570 यह अपेक्षा करता है कि संपरीक्षक प्रबंध से इस बात की जांच करे कि क्या प्रबंध की निर्धारण अवधि से परे ऐसी कोई घटनाएं या परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं जो अस्तित्व के किसी गोइंग कंसर्न के रूप में बने रहने के सामर्थ्य पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती हैं। एसए 570 जोखिम निर्धारण प्रक्रियाओं और संबद्ध क्रियाकलापों, प्रबंध के निर्धारण का मूल्यांकन, अतिरिक्त प्रक्रियाओं, संपरीक्षा निष्कर्षों और रिपोर्टिंग, गोइंग कंसर्न अनुमान के उपयोग आदि की अपेक्षाओं का भी कथन करता है। यह एसए 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 580, “लिखित अभ्यावेदन”

एसए 580, संस्थान द्वारा अप्रैल, 1996 में जारी तत्कालीन संपरीक्षा और आश्वासन मानक (एएएस) 11 ‘प्रबंध द्वारा अभ्यावेदन’ का पुनरीक्षित पाठ है। यह नया मानक संपरीक्षक के, प्रबंध द्वारा इस अभिस्वीकृति के संबंध में कि वह वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनकी प्रस्तुती तथा आंतरिक नियंत्रणों, प्रबंध अभ्यावेदनों के विभिन्न प्रारूपों, ऐसी परिस्थितियों जहाँ प्रबंध के अभ्यावेदन अविश्वसनीय हैं या जहाँ प्रबंध अनुरोध किए गए अभ्यावेदन उपलब्ध कराने से इंकार करता है, के संबंध में कर्तव्यों और उद्देश्यों के ब्यौरे को अंतर्विष्ट करता है। यह एसए 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

एसए 720, “संपरीक्षित वित्तीय विवरणों को अंतर्विष्ट करने वाले दस्तावेजों में अन्य जानकारी के संबंध में संपरीक्षक का उत्तरदायित्व”

किन्हीं वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा में, किसी संपरीक्षक का उत्तरदायित्व यह है कि वह वित्तीय विवरणों की सत्यता और औचित्य पर अपनी राय व्यक्त करे, क्योंकि किसी संपरीक्षा का आधारिक उद्देश्य वित्तीय विवरणों को विश्वसनीयता प्रदान करना है। अनेक मामलों में, विशेषकर कंपनियों के मामलों में, ऐसी वार्षिक रिपोर्टें और अन्य ऐसे दस्तावेजों, जिनमें संपरीक्षित वित्तीय विवरण और उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट अंतर्विष्ट होती है, को पणधारियों को जारी किया जाता है, जिसमें काफी अन्य जानकारी सम्मिलित कर दी जाती है जो वित्तीय विवरणों से संबंधित नहीं होती। उदाहरण के लिए, प्रबंधकों/निदेशकों की रिपोर्टें, वित्तीय अनुपात आदि। यह मानक अपनी तरह का पहला ऐसा मानक है, जिसे संस्थान द्वारा जारी किया गया है और जो संपरीक्षक से यह अपेक्षा करता है कि वह संपरीक्षित वित्तीय विवरणों की तुलना में किन्हीं सारवान असंगतताओं की पहचान करने के लिए ऐसी अन्य जानकारी को पढ़े क्योंकि ये उन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट की विश्वसनीयता को कम कर सकते हैं। इस मानक में ऐसे मामलों में जहां ऐसी सारवान असंगतताओं का पता लगा है या जहां ऐसी अन्य जानकारी को पढ़ने की प्रक्रिया में, कोई स्पष्ट तथ्य संबंधी मिथ्या कथन संपरीक्षक की जानकारी में आया है, संपरीक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में ब्यौरेवार मार्गदर्शन अंतर्विष्ट है। यह मानक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, परिषद् ने मुंबई और एबीवैली सिटी में 18 से 20 जून, 2009 को हुई अपनी 288वीं बैठक में निम्नलिखित संपरीक्षा मानकों (एसए) को अनुमोदित किया और इन एसए को 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी बनाने का विनिश्चय किया।

पुनरीक्षित एसए 210, “संपरीक्षा नियोजनों के निबंधनों पर सहमति देना”

एसए 210, संस्थान द्वारा 2003 में जारी तत्कालीन संपरीक्षा और आश्वासन मानक (एएएस) 26 ‘संपरीक्षा नियोजनों के निबंधन’ का पुनरीक्षित पाठ है। यह नया मानक संपरीक्षक के प्रबंध और जहां उचित हो शासन के लिए प्रभारी व्यक्तियों, के साथ संपरीक्षा नियोजनों के निबंधनों पर सहमति देने, जिनके अंतर्गत यह स्थापित करना भी है कि किसी संपरीक्षा के लिए कतिपय पूर्व शर्तें, जिनके संबंध में उत्तरदायित्व प्रबंध में निहित होता है और जहां उचित हो शासन के लिए प्रभारी व्यक्ति उपस्थित हों के उत्तरदायित्व को अंतर्विष्ट करता है। यह एसए 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

एसए 265, “शासन और प्रबंध के लिए प्रभारी व्यक्तियों को आंतरिक नियंत्रण में कमियों की संसूचना देना”

संसूचना, किसी संपरीक्षक द्वारा, किसी संपरीक्षा के दौरान उसकी जानकारी में आई किन्हीं कमियों के संबंध में उसके विचारों और रायों को प्रबंध या शासन के लिए प्रभारी व्यक्तियों को बताने या उनका आदान-प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन है। यद्यपि, संपरीक्षा विषयों की संसूचना से संबंधित पहलुओं को पुनरीक्षित संपरीक्षा मानक (एसए) 260, शासन के लिए प्रभारी व्यक्तियों को संसूचना, के अंतर्गत रखा गया है फिर भी यह मानक संपरीक्षक के इस उत्तरदायित्व से विनिर्दिष्ट रूप से संबंधित है कि वह प्रबंध या शासन के लिए प्रभारी व्यक्तियों को आंतरिक नियंत्रण में ऐसी कमियों की उपयुक्त रूप से संसूचना दे, जो वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के दौरान उसकी जानकारी में आई हैं। यह मानक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 402, “किसी सेवा संगठन का उपयोग करने वाले किसी अस्तित्व से संबंधित संपरीक्षा के लिए प्रतिफल”

वर्तमान युग में, संगठनों के लिए यह सामान्य बात है कि वे अपने प्रचालनात्मक क्रियाकलापों में से कुछ को एक या अधिक सेवा संगठनों को आउटसोर्स कर दें जिससे कि वे अपने प्रमुख क्रियाकलापों पर अधिक ध्यान दे सकें तथा अपने उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर सकें। यद्यपि, संस्थान द्वारा अगस्त, 2002 में जारी तत्कालीन संपरीक्षा और आश्वासन मानक (एएएस) 24 ‘किसी सेवा संगठन का उपयोग करने वाले किसी अस्तित्व से संबंधित संपरीक्षा के लिए प्रतिफल’ में उपरोक्त पहलुओं को सम्मिलित किया गया था फिर भी पुनरीक्षित मानक इन पहलुओं पर और अधिक व्यापक तथा उपयोजन मार्गदर्शन प्रदान करता है यह मानक उपयोक्ता संपरीक्षक के इस उत्तरदायित्व से संबंधित है कि वह उस समय पर्याप्त उपयुक्त संपरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करे जब कोई उपयोक्ता अस्तित्व एक या अधिक सेवा संगठनों का उपयोग करता है। यह जोखिम आधारित संपरीक्षा मानकों अर्थात्, एसए 315, अस्तित्व और उसकी परिस्थितियों को भलीभांति समझकर सारवान मिथ्या कथनों के जोखिम का पता लगाना और निर्धारण करना तथा एसए 330, निर्धारित जोखिमों के संबंध में संपरीक्षक की प्रतिक्रियाएं से भी संबंध का उपबंध करता है। यह एसए 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 610, “आंतरिक संपरीक्षकों के कार्यों का उपयोग”

एसए 610 संस्थान द्वारा जनवरी, 1989 में जारी तत्कालीन संपरीक्षा और आश्वासन मानक (एएएस) 7 ‘आंतरिक संपरीक्षकों के कार्यों का सहारा लेना’ का पुनरीक्षित पाठ है। यह नया मानक बाह्य संपरीक्षक के आंतरिक संपरीक्षकों के कार्य के प्रति

ऐसे उत्तरदायित्व से संबंधित है, जब बाह्य संपरीक्षक ने एसए 315 के अनुसार यह अवधारित किया हो कि आंतरिक संपरीक्षा कृत्यों के संपरीक्षा के लिए सुसंगत होने की संभावना है। यह एसए 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 320, “किसी संपरीक्षा की योजना और उसके कार्यपालन में भौतिकता”

एसए 320 संस्थान द्वारा जनवरी, 1997 में जारी तत्कालीन संपरीक्षा और आश्वासन मानक (एएस) 13 ‘संपरीक्षा भौतिकता’ का पुनरीक्षित पाठ है। जहाँ तत्कालीन एएस 13 में संपरीक्षा भौतिकता, योजना के प्रक्रम पर और साथ ही संपरीक्षा प्रक्रियाओं के कार्यपालन के समय संपरीक्षा जोखिमों के साथ इसके संबंध और संपरीक्षा के दौरान पहचान किए गए मिथ्या कथनों के मूल्यांकन को अंतर्बलित करता था वहीं यह नया मानक संपरीक्षक के इस उत्तरदायित्व से संबंधित है कि वह किसी वित्तीय विवरण की संपरीक्षा की योजना और कार्यपालन में भौतिकता की अवधारणा का उपयोजन करे और संपरीक्षा के दौरान पहचान किए गए मिथ्या कथनों के मूल्यांकन के लिए पृथक एसए अर्थात् एसए 450 विद्यमान है। यह एसए 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 450, “किसी संपरीक्षा के दौरान पहचान किए गए मिथ्या कथनों का मूल्यांकन”

यद्यपि एसए 450, “किसी संपरीक्षा के दौरान पहचान किए गए मिथ्या कथनों का मूल्यांकन” के तत्कालीन कोई पृथक मानक नहीं है, फिर भी एसए 450 के कुछ पहलु संस्थान द्वारा जनवरी, 1997 में जारी तत्कालीन संपरीक्षा और आश्वासन मानक (एएस) 13 ‘संपरीक्षा भौतिकता’ में सम्मिलित थे। यह एसए संपरीक्षक के इस उत्तरदायित्व से संबंधित है कि वह संपरीक्षा के दौरान पहचान किए गए मिथ्या कथनों या ठीक न किए गए मिथ्या कथनों का मूल्यांकन करे और यह एसए 320 से संबद्ध है जो संपरीक्षक के इस उत्तरदायित्व से संबंधित है कि वह किसी वित्तीय विवरण की संपरीक्षा की योजना और कार्यपालन में भौतिकता की अवधारणा का उपयोजन करे। यह एसए 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

उदभासन प्रारूप

बोर्ड ने क्लैरिटी परियोजना के अधीन लोक टिप्पणियाँ हेतु निम्नलिखित संपरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के उदभासन प्रारूप भी जारी किए हैं।

- पुनरीक्षित एसए 700, “वित्तीय विवरणों पर राय बनाना और रिपोर्ट करना”
- एसए 705, “स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट में राय में उपांतरण”
- एसए 706, “स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट में विषय पैराओं और अन्य विषय पैराओं पर बल देना”

5.3.2 अन्य तकनीकी साहित्य

बोर्ड ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित अन्य तकनीकी साहित्य जारी किया था :

- **हैंडबुक ऑफ आडिटिंग प्रनाउंसमेंट (2008 संस्करण)**

○ दो जिल्दे - एक और दो

○ जिल्द 1 : 1 अप्रैल, 2008 को यथाप्रवृत्त सभी क्वालिटी नियंत्रण और नियोजन मानक।

■ इसमें 1 अप्रैल, 2008 तक एएसबी क्लैरिटी परियोजना के अधीन जारी सभी पुनरीक्षित/नए मानकों का पाठ भी सम्मिलित है।

■ आश्वासन नियोजनों के लिए पुनरीक्षित प्राक्कथन और ढांचे का पाठ।

■ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (1क) के अधीन रिपोर्टिंग संबंधी विवरण और सीएआरओ 2003 संबंधी विवरण का पाठ।

■ मानकों के साधारण स्पष्टीकरणों का पाठ।

○ जिल्द 2 : 1 अप्रैल, 2008 को यथाप्रवृत्त संपरीक्षा संबंधी 32 सभी सामान्य मार्गदर्शक टिप्पणों का पाठ।

○ संपूर्ण हैंडबुक की सीडी।

- **बैंकों की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण - पुनरीक्षित 2009 संस्करण।**

○ पूर्णरूपेण पुनरीक्षित, जिसमें आरबीआई द्वारा जारी सभी सुसंगत परिपत्रों के प्रभाव को समाविष्ट किया गया है।

○ दो जोखिम आधारित मानकों, अर्थात् एसए 315 और एसए 330 के प्रभाव को सम्मिलित करने के लिए पूर्ण रूप से पुनः लिखा गया।

- नए पूजी पर्याप्तता ढांचे अर्थात् बेसल - 2 पर ध्योरेवार मार्गदर्शन ।
- निम्नलिखित पर पृथक अध्याय :
 - बैंक के खजाना संबंधी प्रचालनों पर विशेष फीचर ।
 - विदेशी विनिमय और व्युत्पत्तियों में संव्यवहार ।
 - वित्तीय विवरणों में प्रकटन अपेक्षाएं ।
- आरबीआई के महत्वपूर्ण परिपत्रों की सीडी ।
- **एसक्यूसी 1 संबंधी कार्यान्वयन गाइड ।**
 - ऐसी व्यापक नीतियों का सैट, जिन्हें कोई संपरीक्षा फर्म उपांतरणों सहित या रहित अपना सकेगी ।
 - अनुलानक ज्ञापन प्ररूप, जांच सूचियां और टेम्पलेट उपलब्ध कराते हैं ।
- **वित्तीय विवरणों के जोखिम आधारित संपरीक्षा संबंधी कार्यान्वयन गाइड ।**
 - दो जोखिम आधारित मानकों एसए-315 और एसए-330 की आधारिक अपेक्षाओं का वर्णन करती है ।
 - एसए को स्पष्ट करने के लिए व्यवहारिक और मामला अध्ययन आधारित पद्धति ।
 - जोखिम आधारित संपरीक्षाएं करने संबंधी पुनरीक्षित एसए 240 "वित्तीय विवरणों की किसी संपरीक्षा में कपट के संबंध में संपरीक्षकों के उत्तरदायित्व" और पुनरीक्षित एसए 300, "वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा की योजना" की विवेक्षाओं पर भी विचार-विमर्श प्रस्तुत करती है ।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पृष्ठभूमि सामग्री**
 - संपरीक्षा मानकों पर व्यापक किन्तु साधारण पठन सामग्री अंतर्विष्ट करती है ।
 - पांच भागों में विभाजित है :
 - पहला भाग, प्रस्तावना, में पाठकों के लिए संपरीक्षा का इतिहास और प्रकृति, संपरीक्षा मानकों का महत्व, आश्वासन नियोजनों के लिए ढांचा आदि से संबंधित संक्षिप्त विवरण सम्मिलित है ।
 - दूसरा भाग, प्रस्तुतियों में संपरीक्षा और आश्वासन मानकों में अंतर्विष्ट मूल सिद्धांतों को कुछ टिप्पणों सहित समाविष्ट किया गया है ।
 - पृष्ठभूमि सामग्री के तीसरे भाग में विभिन्न एएएस से एकत्रित संभाव्य दस्तावेजी अपेक्षाएं अंतर्विष्ट हैं ।
 - पृष्ठभूमि सामग्री के चौथे भाग में मामला अध्ययन और तकनीकी प्रश्न अंतर्विष्ट हैं ।
 - पांचवें पाठ में संपरीक्षा संबंधी ऐसे नए मानकों का पाठ अंतर्विष्ट है जिन्हें इस वर्ष से प्रभावी किया गया है ।
- **बेसल-2 और जोखिम आधारित अधीक्षण पर एक अध्ययन ।**
 - ग्राफों, सारणियों और चित्रात्मक प्रस्तुतियों का उपयोग करते हुए बेसल-2 ढांचे के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्पष्ट करती है ।
 - पांच अध्यायों में विभाजित है :
 - एक पर्यावलोकन
 - दी श्री मीलर स्ट्रक्चर
 - प्रत्यय जोखिम
 - प्रचालनात्मक जोखिम
 - बेसल-2 का कार्यालय
 - एक दृष्टांत मानक ढांचे के माध्यम से सरलीकृत रीति में कार्यान्वयन पद्धति को स्पष्ट किया गया है ।
- **टेलीकॉम उद्योग के संरक्षित, नियत आस्तियां और संबंधित प्रचालन लागतों में संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड ।**
 - टेलीकॉम कंपनियों के लिए विनियामक ढांचा

- निम्नलिखित के लिए संपरीक्षा पद्धति और प्रक्रियाएं :
 - जोखिम निर्धारण
 - राजस्व और प्राप्य
 - नियत आस्तियां आदि
- पदों की व्यापक शब्दावली
- परिशिष्ट - विभिन्न टेलीकॉम सेवाओं के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन समायोजित सकल राजस्व परिगणना पत्र और संपरीक्षकों की रिपोर्ट का प्रारूप ।
- ई-कॉमर्स - वित्तीय विवरणों की परीक्षा के लिए प्रतिफल संबंधी तकनीकी गाइड ।
 - किसी पब्लिक नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट पर जुड़े कंप्यूटरों का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक क्रियाकलाप ।
 - वित्तीय विवरणों पर राय बनाने के प्रयोजन के लिए संपरीक्षक के जोखिम निर्धारण पर ई-कॉमर्स के प्रभाव का निर्धारण ।
 - विचारार्थ विनिर्दिष्ट मामले ।
 - ई-कॉमर्स परिस्थितियों में संपरीक्षा करते समय संपरीक्षा संबंधी सुसंगत मानकों (एसए) का उपयोग ।
 - परिशिष्ट - ई-कॉमर्स परिस्थितियों से संबंधित विशिष्ट पदों की शब्दावली और 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' का पाठ ।
- ऐसी परियोजनाएं, जिनपर कार्य चल रहा है ।

इनके अतिरिक्त बोर्ड ने, वर्ष के दौरान अनेक अन्य परियोजनाएं भी प्रारंभ की हैं और कुछ परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है ।

5.3.3 अन्य पहलें और विकास

विनियामक निकायों से परस्पर क्रिया

बोर्ड, आवधिक रूप से विनियामकों और अन्य सरकारी संस्थाओं जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) आदि से लेखांकन विषयों पर प्रतिक्रिया करता है ।

आईएएसबी की गतिविधियों में सहयोग और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना

चूंकि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) अंतरराष्ट्रीय एकाउंटेंट्स संघ (आईएफएसी) का संस्थापक सदस्य है, इसलिए एएसबी विभिन्न स्तरों पर आईएएसबी के साथ परस्पर क्रिया करता है । मई, 2009 में, आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने वैंकूवर में अंतरराष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएसबी), राष्ट्रीय मानक निर्धारकों (एनएसएस) के साथ बैठक में भाग लिया और अपने विचार प्रस्तुत किए । प्रतिनिधियों ने भारत में अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ समाभिरूपण के संबंध में हुई घटनाओं और इस प्रक्रिया के दौरान सामने आई चुनौतियों से अवगत कराया ।

जागरूकता सृजित करना और सक्षमता का निर्माण

वर्ष 2008-09 के दौरान सदस्यों के बीच संपरीक्षा मानकों के संबंध में जागरूकता का सृजन करना बोर्ड का प्रमुख लक्ष्य था । इस प्रक्रिया में बोर्ड ने नई दिल्ली, पुणे और कानपुर में संपरीक्षा वृत्तिकों की तीन सभाओं का आयोजन किया था । इन सभाओं में विचार किए गए विषयों में भारतीय संपरीक्षा और आश्वासन मानकों का अंतरराष्ट्रीय संपरीक्षा मानकों के साथ समाभिरूपण, जोखिम आधारित संपरीक्षाएँ - हाल ही की प्रवृत्तियाँ और क्वालिटी नियंत्रण संबंधी मानक (एसक्यूसी) 1 के फर्म के भीतर कार्यान्वयन सहित फर्मों की क्वालिटी में कैसे सुधार लाया जाए - जैसे विषय सम्मिलित थे । इसके अतिरिक्त, जागरूकता का सृजन करने के लिए, बोर्ड अपने 2 प्रकाशनों, अर्थात् "वाट इज ऐन ऑडिट - अंडरस्टैंडिंग ऐन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स" और "प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पृष्ठभूमि सामग्री" को भी पुनरीक्षित करने की भी योजना बना रहा है ।

भावी रणनीति और कार्यक्रम

चूंकि अंतरराष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएसबी) ने अपनी क्लैरिटी परियोजना को पहले ही मार्च, 2009 में पूरा कर लिया है, इसलिए बोर्ड भी अपनी अभिसरन प्रक्रिया को 1 अप्रैल, 2010 तक पूरा करने का प्रयास करेगा । इस प्रयोजन के लिए, बोर्ड ने पहले ही क्लैरिटी परियोजना के अधीन आईएएसबी द्वारा जारी ऐसे आईएसए के, जिन्हें बोर्ड द्वारा

अभी जारी किया जाना है, तत्समान संपरीक्षा मानकों के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने समय-सीमा के भीतर क्लैरिटी परियोजना को पूरा करने के लिए एक ब्यौरेवार सूची तैयार की है। आईएएसबी द्वारा जारी आईएसए और एएसबी द्वारा आज की तारीख तक जारी मानकों के बीच एक समाधान इस रिपोर्ट के अधीन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, अगले वर्ष के लिए अपना कार्यवृत्त तय करते हुए, बोर्ड भारत में सदस्यों के बीच संपरीक्षा मानकों के संबंध में जागरूकता बनाने के लिए रणनीति तैयार करेगा। इस प्रयोजन के लिए, बोर्ड ने क्लैरिटी परियोजना के अधीन जारी संपरीक्षा मानकों संबंधी कार्यान्वयन गाइड जारी करने का विनिश्चय किया है।

5.4 अनुसंधान

अनुसंधान समिति, संस्थान की सबसे पुरानी तकनीकी समितियों में से एक है। यह समिति साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन और/या संपरीक्षा सिद्धांतों और व्यवहारों पर, जिन्हें वृत्ति द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के मूल्यवर्धन के लिए तैयार किया गया है, मार्गदर्शक टिप्पणों, तकनीकी गाइडें, अध्ययनों, मानोग्राफों आदि का प्रकाशन करती है। यह संस्थान की किसी अन्य समिति के कृत्यों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान और सतत आधार पर अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाएं प्रारंभ करती है। अपनी उप समिति, शील्ड पैनल के माध्यम से अनुसंधान समिति वित्तीय विवरणों की प्रस्तुती में सुधार लाने के विचार से 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीआई पुरस्कार' के लिए गौरवान्वित वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन करती है।

5.4.1 समिति की उपलब्धियां

इस अवधि के दौरान समिति ने निम्नलिखित प्रकाशनों का विमोचन किया :

लघु वित्त संस्थाओं के लिए लेखांकन संबंधी तकनीकी गाइड

अनेक लघु वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के साथ देश में लघु वित्त का क्षेत्र एक फलता-फूलता उद्योग है। यह प्रकाशन मुख्यतः, एमएफआई के वित्तीय विवरणों में उनके कार्यों की स्थिति और क्रियाकलापों के प्रचालन परिणामों के सत्य और निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा उपलब्ध कराता है। यह प्रकाशन एमएफआई के लिए वित्तीय विवरणों और उनमें सुसंगत गैर-वित्तीय जानकारी के प्रकटनों के लिए प्रारूपों की भी सिफारिश करता है। एमएफआई के वित्तीय विवरणों को तैयार करने वालों और संपरीक्षकों के लिए यह प्रकाशन लघु वित्त क्षेत्र में अंतर्वर्तित लेखांकन मुद्दों के समाधान के लिए अतिउपयोगी सिद्ध होगा।

सॉफ्टवेयर के लिए राजस्व मान्यता संबंधी तकनीकी गाइड

यह तकनीकी गाइड उत्तम लेखांकन व्यवहारों को स्थापित करने के विचार से सॉफ्टवेयर की राजस्व मान्यता से संबंधित उद्योग विनिर्दिष्ट लेखांकन मुद्दों पर कार्यवाही करने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है। सॉफ्टवेयर उद्योग में आजकल की जाने वाली अनेक राजस्व उत्पन्न करने वाली संविदाएं अत्यंत जटिल हैं और उनमें अत्यधिक अनिश्चितता अंतर्वर्तित होती है। सॉफ्टवेयर उद्योग में अनेक प्रकार के राजस्व मान्यता सिद्धांत अपनाए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में काफी विवेक अपेक्षित है। सॉफ्टवेयर उद्योग में की जाने वाली विभिन्न किस्म की संविदाओं की राजस्व मान्यता के लिए एक समान और उत्तम लेखांकन व्यवहारों को स्थापित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समिति ने "सॉफ्टवेयर के लिए राजस्व मान्यता संबंधी तकनीकी गाइड" नामक इस प्रकाशन को निकाला है।

शेयर मूल्यांकन संबंधी तकनीकी गाइड

समिति ने अपने विद्यमान प्रकाशन 'स्टडी ऑन शेयर वैल्यूएशन' (दूसरा संस्करण 1994) को, उसके अंतिम संस्करण के पश्चात् होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित किया है पुनरीक्षित प्रकाशन का शीर्षक है 'टेकनीकल ऑन शेयर वैल्यूएशन'। यह प्रकाशन विधि, कानूनी दिशानिर्देशों और न्यायालयों के निर्णयों और साथ ही सुस्थापित मूल्यांकन व्यवहारों द्वारा यथाअधिकथित शेयर मूल्यांकन की पद्धतियों, नियमों और सिद्धांतों का वर्णन करता है। यह गाइड शेयरों के मूल्यांकनों के विशेषज्ञों द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करती है। इसका उद्देश्य शेयर मूल्यांकन में अंतर्वर्तित समकालीन मुद्दों पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।

एस 28 के प्रयोजनों के लिए भावी नकद प्रवाह के प्राक्कलन और बट्टा दरों, आस्तियों के हानिकरण संबंधी तकनीकी गाइड

इस तकनीकी गाइड में लेखांकन मानक (एस) 28, 'आस्तियों का हानिकरण' के सिद्धांतों का उपयोग करने के लिए व्यवहारिक कार्यान्वयन मार्गदर्शन अंतर्वर्षित है। यह मानक यह सुनिश्चित करता है कि किसी उद्यम की आस्तियों को, उनकी वसूलनीय रकम से अनधिक पर अग्रणीत किया जाए। किसी आस्ति की वसूलनीय रकम के अवधारण के लिए एस 28 के अधीन 'उपयोग में मूल्य' का मापमान अपेक्षित है। एस 28 'उपयोग में मूल्य' के मापमान के सिद्धांतों को अधिकथित करता है, जिसके लिए नकद प्रवाहों और समुचित बट्टा दरों का प्राक्कलन अपेक्षित है। यह महसूस किया गया था कि

‘उपयोग में मूल्य’ के मापमान के संबंध में अनेक पहलुओं पर मार्गदर्शन अपेक्षित है। अतः, संस्थान की अनुसंधान समिति ने ऐसे पहलुओं के संबंध में इस तकनीकी गाइड को तैयार किया।

5.4.2 प्रगति में महत्वपूर्ण परियोजनाएं

वर्ष के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं के अलावा, समिति की कतिपय अन्य परियोजनाओं पर भी कार्य चल रहा है। समिति ने उभरते क्षेत्रों जैसे कि एसइजेड विकास क्रियाकलापों के लिए लेखांकन, गैर लाभकारी संगठनों (एनपीओ)/गैर सरकार संगठनों में लेखांकन और दूर संचार कंपनियों के लिए राजस्व मान्यता आदि में मार्गदर्शन जारी करने का कार्य आरंभ किया है। तेल और गैस उद्योग में हुई हाल ही की घटनाओं और विधियों में संशोधनों के कारण, तेल और गैस उद्योग में लेखांकन संबंधी विद्यमान मार्गदर्शक टिप्पण को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, समिति ने इस मार्गदर्शक टिप्पण के पुनरीक्षण की परियोजना को भी आरंभ किया है। समिति ने संस्थान के सदस्यों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों को पुनर्विलोकन के दौरान पाए गए प्रमुख अननुपालन से अवगत कराने के विचार से, वित्तीय रिपोर्टों के मूल्यांकन में उसके द्वारा पाई गई सामान्य असंगतताओं को प्रकाशित करने और उन असंगतताओं को भी प्रकाशित करने, जो अध्ययन के रूप में हैं, का विनिश्चय किया है।

5.4.3 वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीआई पुरस्कार

आईसीआई, अपनी अनुसंधान समिति के माध्यम से “वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीआई पुरस्कार” के लिए वार्षिक प्रतिस्पर्धा का आयोजन करता रहा है। इस प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य, वृहत्तर जवाबदेही और सूचित निर्णय लेने के मिशन से वित्तीय जानकारी को तैयार करने और उसकी प्रस्तुती में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करना और बढ़ावा देना है। यह प्रतिस्पर्धा यह प्रसारित करती है कि वित्तीय रिपोर्टिंग, जवाबदेही, पारदर्शिता, एकरूपता, विश्वसनीयता, कालातीत तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। वर्ष 2007-08 में प्रतिस्पर्धा विभिन्न उद्योगों के कृत्यक प्रवर्गीकरण के आधार पर सात प्रवर्गों के अधीन आयोजित की गई थी।

वर्ष 2007-08 के लिए “वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीआई पुरस्कार” के लिए निर्णायकों के पैनल ने इन उद्योगों की वार्षिक रिपोर्टों और लेखाओं में अंतर्विष्ट वित्तीय और अन्य जानकारी पर बहुत बारीकी से विचार किया था। इस वर्ष पैनल ने एक नया पुरस्कार प्रारंभ किया है, अर्थात् हाल ऑफ फेम पुरस्कार। यह विनिश्चय किया गया था कि यह पुरस्कार किसी ऐसे अस्तित्व को प्रदान किया जाए जिसे पिछले पांच वर्ष के दौरान समान प्रवर्ग में निरंतर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। समारोह में कुल मिलाकर 30 पुरस्कार - 1 हाल ऑफ फेम, 7 स्वर्ण शील्डें, 8 रजत शील्डें और 14 पट्टिकाओं को नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार वितरित किया गया था :

प्रवर्ग	पुरस्कार	अस्तित्व का नाम	निम्नलिखित को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा
I	विनिर्माण और व्यापार उद्यम (जिसके अंतर्गत प्रसंस्करण, खनन, पौधा रोपण, तेल और गैस उद्यम भी हैं)	स्वर्ण शील्ड	डा. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड
		रजत शील्ड	टाटा बीपी सोलर इंडिया लिमिटेड
	उत्कृष्ट वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	1. केरन इंडिया लिमिटेड	31 दिसम्बर, 2007
		2. ग्लेक्सोस्मिथ क्लिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड	31 दिसम्बर, 2007
		आईटीसी लिमिटेड	31 मार्च, 2008
		3. इंडियन एंड फार्मर्स फर्टिलाइजर कोओपरेटिव लिमिटेड	31 मार्च, 2008
		4. स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	31 मार्च, 2008
II	बैंककारी और वित्तीय संस्थाएं (जिनके अंतर्गत एनबीएफसी, परस्पर निधियां, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, निवेश बैंकर, एचएफसी आदि हैं)	स्वर्ण शील्ड	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
		रजत शील्ड	1. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स
			2. श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस

			उत्कृष्ट वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	कंपनी लिमिटेड	
				1. कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	31 मार्च, 2008
				2. ग्रुह फाइनेंस लिमिटेड	31 मार्च, 2008
III	सेवा क्षेत्र (जिसके अंतर्गत होटल, परामर्श, परिवहन, स्टॉक एक्सचेंज, आरएंडडी, निजी अस्पताल हैं)	स्वर्ण शील्ड	उत्कृष्ट वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	3. युनियन बैंक ऑफ इंडिया	31 मार्च, 2008
				बांबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	31 मार्च, 2008
				किंग्स हेल्थकेयर मैनेजमेंट लिमिटेड	31 मार्च, 2008
IV	बीमा क्षेत्र	स्वर्ण शील्ड	उत्कृष्ट वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	आईसीआईसीआई पुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड	31 मार्च, 2008
				आईसीआईसीआई लोमबार्ड जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	31 मार्च, 2008
				रजत शील्ड	
V	सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और मनोरंजन उद्यम	हॉल ऑफ फेम	उत्कृष्ट वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	इंफोसिस टेक्नालाजिज लिमिटेड	31 मार्च, 2008
				स्वर्ण शील्ड	
				न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	31 मार्च, 2008
				रजत शील्ड	
				1. एमफैसिस लिमिटेड	31 मार्च, 2008
				2. ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड	31 मार्च, 2008
VI	अवसररचना और सन्निर्माण क्षेत्र (जिनके अंतर्गत विद्युत उत्पादन और प्रदाय, पत्तन न्यास, मैट्रो, मार्ग आदि हैं)	स्वर्ण शील्ड	उत्कृष्ट वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	1. पर्सिसटेंट सिस्टम्स लिमिटेड	31 मार्च, 2008
				2. श्री अष्टविनायक सिने विजन लिमिटेड	31 मार्च, 2008
				दी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	31 मार्च, 2008
				रजत शील्ड	
				एनटीपीसी लिमिटेड	31 मार्च, 2008
				1. लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	31 मार्च, 2008
VII	अन्य (धारा 25 की कंपनियां, शिक्षा संस्थाएं, एनजीओ, पुर्त अस्पताल और अन्य संगठन हैं)	स्वर्ण शील्ड	उत्कृष्ट वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	2. पुर्वाकारा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	31 मार्च, 2008
				विद्या डेयरी	31 मार्च, 2008
				स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट	31 मार्च, 2008
				फाइनेशियल मैनेजमेंट सर्विस फाउंडेशन	31 मार्च, 2008

वर्ष 2007-08 के लिए “वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार” प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेताओं को गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई में आयोजित ‘आईसीएआई पुरस्कार’ समारोह में सम्मानित किया गया था। माननीय श्री राम

नाइक, भूतपूर्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, इस समारोह के मुख्य अतिथि थे । इस समारोह में वरिष्ठ सरकारी पदधारियों, विख्यात व्यक्तियों, उद्योगपतियों, बड़े पब्लिक और प्राइवेट उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों ने भाग लिया था ।

5.4.4 अनुसंधान प्रस्तावों के लिए निमंत्रण

अनुसंधान समिति लेखांकन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों, उदाहरणार्थ चैन डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में लेखांकन विद्युत उत्पादन और वितरण कंपनियों के लिए लेखांकन, विमानन उद्योग में लेखांकन, पोत परिवहन कंपनियों के लिए लेखांकन, प्रबंध नियंत्रण प्रणालियाँ, भारतीय संदर्भ में सामाजिक लागत फायदा विश्लेषण पद्धतियाँ आदि के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से अनुसंधान परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित करती है ।

5.5 निगम विधियाँ समिति

5.5.1 अनुसूची 6 और लघु तथा मध्यम आकर की कंपनियों के लिए सरल अनुसूची 6 विहित करना

5.5.2 निम्नलिखित के संबंध में विचार और सुझाव :

- क) प्रबंधकीय पारिश्रमिक संबंधी सन्धियम,
- ख) एक विशिष्ट आकार से बड़ी कंपनियों में मुख्य वित्तीय अधिकारी की अनिवार्य नियुक्ति,
- ग) कंपनी अधिनियम की अनुसूची 14 का पुनरीक्षण,
- घ) कंपनी रजिस्ट्रार के पद संबंधी कृत्य, कंपनी विधि व्यवहारों के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन,
- ङ) मूल्यांकन पर पृष्ठभूमि सामग्री,
- च) कंपनी विधेयक, 2008,
- छ) पुनरीक्षित मूल्यांकन वृत्तिक विधेयक,
- ज) एलएलपी अवधारणा नियम

5.5.3 निम्नलिखित के संबंध में निगम कार्य मानक

- क) एमसीए 21 के अधीन स्पष्टीकरण
- ख) संपरीक्षकों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति और हटाया जाना
- ग) कारबार मूल्यांकन

5.5.4 मूल्यांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के पहले बैच का आयोजन

नए कंपनी विधेयक, 2008 के अधीन उपलब्ध अवसर के अनुसार और साथ ही भारतीय जीएएपी के आईएफआरएस के साथ प्रस्तावित अंगीकरण के साथ ही समिति ने वृत्तिकों के लिए तकनीकी सशक्तिकरण कार्यवाही के रूप में मूल्यांकन संबंधी एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का विनिश्चय किया । तदनुसार, समिति ने पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की अन्य पद्धतियों को तैयार किया और निम्नलिखित अवस्थानों पर पाठ्यक्रम का संचालन किया :

- क) दिल्ली
- ख) मुंबई
- ग) चेन्नई
- घ) कोलकाता

5.5.5 निम्नलिखित के संबंध में अनुमान

- (क) परिसमापन में लेखांकन संबंधी ज्ञान और प्रक्रियाओं को तैयार किया गया है और शासकीय परिसमापक कार्यालय, दिल्ली के कर्मचारिवृद्ध/पदधारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है ।
- (ख) विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय के पदधारियों के लिए मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- (ग) मुंबई और दिल्ली में मूल्यांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दूसरे बैच की कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं ।

5.5.6 मुंबई और दिल्ली में मूल्यांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दूसरे बैच की कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं

5.6 वित्तीय बाजार और निवेशकों का संरक्षण

हाल ही की आर्थिक मंदी, जिसका असर पूरे विश्व पर हुआ था, ने बाजारों और निवेशकों को अत्यधिक प्रभावित किया है । नीति निर्माता वित्तीय स्थायित्व को पुनःस्थापित करने और नव विकास के लिए आधारिक कार्य प्रारंभ करने के लिए रणनीतियाँ तैयार कर रहे हैं । वैश्विक मंदी के बावजूद, भारतीय पूंजी बाजार में इस समय सकारात्मक रुझान जगविदित है । हाल ही के निर्वाचनों के पश्चात् नई सरकार भी इस तथ्य के प्रति सचेत है कि आर्थिक तंत्र को पुनः बृहत विकास के मार्ग पर लाने के लिए सकल उपाय करना आवश्यक है जिसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है । एफआई और एफआईआई दिलचस्पी से ऐसे पैकेजों और सुधारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनका सरकार निगमों को प्रस्ताव करेगी और इस प्रकार देश में और अधिक

निवेश आगे की प्रबल संभावना है। दूसरी ओर, देश में हुए हाल ही के निगम कांडों के कारण निवेशकों की संरक्षा और उनके अधिकारों की विश्वसनीयता के संबंध में चिंताएं व्यक्त की गई हैं। एक ओर, बाजार उमर जा रहे हैं वहीं निवेशक यथाअपेक्षित रूप में आशावादी होकर उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार यह संपूर्ण बाजार के लिए एक उदाहरण और विरोधाभास की स्थिति है।

इस परिदृश्य के संबंध में आदर्श विचार लेते हुए, समिति ने पूंजी बाजारों के क्षेत्र में सदस्यों की भूमिका और उत्तरदायित्वों को दर्शित करते हुए सक्रिय उपायों की परिकल्पना करते हुए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इसके साथ ही संस्थान, राष्ट्र निर्माण में एक भागीदार के रूप में निवेशक शिक्षा और संरक्षण में सशक्तिकरण के लिए जन जागरूकता लाने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है जिसके लिए नई परियोजनाएं, कार्यक्रम और प्रकाशन तैयार किए गए थे।

परियोजनाएं

- इंट्रोस्पेक्शन ऑन मार्केट डिबेकल्स (2008 के प्रारंभ में) - एक प्रस्तुतिकरण - समिति ने यह प्रस्तुतिकरण कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा विचार किए जाने के लिए समस्या के स्रोत और कारणों और साथ ही ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों, जहां समस्या विद्यमान है, को स्पष्ट रूप से दर्शित करते हुए तैयार किया था।
- इन साइट्स ऑन इनिशियल ऑफरिंग्स (आईपीओ) - एक अनुसंधान अध्ययन - कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने संस्थान को यह आज्ञा दी थी कि वह वर्ष 2008 में बाजारों के इंडेक्स में भारी कमी के पश्चात् आईपीओ के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करे। इस प्रयोजन के लिए एक समूह का सृजन किया गया था और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार की गई थी।
- इनकलकेटिंग अवेयरनेस अमंग इनवेस्टर्स - अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना - समिति ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि के तत्वावधान में नवम्बर, दिसम्बर, 2008 और जनवरी, 2009 मासों के दौरान देश भर में 50 निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की व्यापक योजना तैयार की थी।
- इश्युज रिलेटेड टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन - एक 13/26 टीवी एपिसोड मास मीडिया निर्माण - निवेशक संरक्षा से संबंधित मुद्दों पर धारावाहिक का निर्माण करने संबंधी कार्य अभी भी परामर्शाधीन है।
- इन्टरनेस विद रेगुलेटरी आथरिटीज - सेबी और एमसीए - नीति/परामर्श पत्रों पर प्रस्तुतियां/सुझाव - समिति ने परस्पर निधि संबंधी सेबी सलहाकार समिति और मानक तथा प्रकटन संबंधी सेबी समिति की विभिन्न बैठकों में भाग लिया था।

कार्यक्रम

- हीरक जयंती सम्मेलन - संस्थान के हीरक जयंती समारोह के भागरूप में 16 जुलाई, 2008 को एर्नाकुलम में वित्तीय बाजारों संबंधी एक हीरक जयंती राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें 450 सदस्यों ने भाग लिया था।
- पूंजी बाजार संबंधी अखिल भारतीय सम्मेलन - आगे की कार्य योजना - कोलकाता - पूंजी बाजार संबंधी एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 19 जुलाई, 2008 को कोलकाता में किया गया था। इस बड़े सम्मेलन में लगभग 500 सदस्यों ने भाग लिया था तथा पूंजी बाजार के क्षेत्र के गणमान्य राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर इस सम्मेलन को संबोधित किया था।
- निजी सामग्री संबंधी कार्यशालाएं - पूंजी बाजारों में उभरते रुझानों और सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसरों को ध्यान में रखते हुए समिति ने 5 और 6 अप्रैल, 2008 को गुडगांव के समीप मानेसर में एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था जिसमें 50 सदस्यों ने भाग लिया था। ऐसा ही सम्मेलन 1 और 2 अगस्त, 2008 में मुंबई में आयोजित किया गया था, जो कि देश में आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन था जिसमें 450 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया था। 5, 6 सितम्बर, 2008 को चंडीगढ़ में एक अन्य कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें 70 व्यक्तियों ने भाग लिया था।
- अखिल भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में 13 सितम्बर, 2008 को पूंजी बाजार संबंधी एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में 100 सदस्यों ने भाग लिया था और पूंजी बाजार के क्षेत्र के विख्यात विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर संबोधन किया था।
- इस आयोजन को आईसीएआई की एनआईआरसी और भारतीय सदस्यों के राष्ट्रीय संघ (एएनएमआई) के सहयोग से आयोजित किया गया था।
- “संसेक्स नी संगठे” विषय पर आईसीएआई - ईटी संयुक्त कार्यक्रम - मुंबई में 23 अक्टूबर, 2008 को “संसेक्स नी संगठे” (संसेक्स के साथ सुर में) विषय पर एक संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में सदस्यों और पूंजी बाजार के क्षेत्र के विख्यात विशेषज्ञों ने भाग लिया था, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर संबोधन दिए थे। लगभग 800 सदस्य उपस्थित थे।

- मुद्रा वायदों पर श्रृंखला संगोष्ठियां - 29 अगस्त, 2008 से सेबी द्वारा मुद्रा वायदों में व्यापार की अनुमति दिए जाने से, एमसीएक्सएसएफ, आईसीएआई और एफडीडीआई ने देश के विभिन्न स्थानों में मुद्रा वायदों के माध्यम से व्यापार संबंधी अर्ध दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया था। इन कार्यक्रमों का आयोजन नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर, बंगलोर, हैदराबाद, कोयंबटूर, कोचीन और मुंबई में सितम्बर, 2008 मास के दौरान किया गया था।
- अखिल भारतीय निवेशक जागरूकता कार्यक्रम भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के तत्वावधान में, संस्थान ने वर्ष 2008-09 के दौरान 50 स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया था :
- प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम - फोरेक्स और खजाना प्रबंध तथा व्युत्पत्तियां - समिति ने पूर्वोक्त पाठ्यक्रम के पहले बैच का क्रमशः मुंबई और नई दिल्ली में संचालन किया। समिति अब आगे यह और प्रस्ताव कर रही है कि इन पाठ्यक्रमों को अन्य मेट्रो नगरों में भी प्रारंभ किया जाए और इन पाठ्यक्रमों के नए बैचों को शीघ्र ही प्रारंभ करने की संभावना है।
- पूंजी बाजार सुधारों पर सीपीई टेलीसम्मेलन - पूंजी बाजार और निवेशक संरक्षण संबंधी समिति ने सीपीई द्वारा 13 सितम्बर, 2008 को पूंजी बाजार सुधारों के विषय पर आयोजित टेली सम्मेलन में भाग लिया था।
- वित्तीय बाजारों के क्षेत्र में उभरते रुझानों पर सम्मेलन/कार्यशालाएं - 24 और 25 अप्रैल, 2009 को अमृतसर में एक दो दिवसीय संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी एनआईआरसी की अमृतसर शाखा द्वारा की गई थी। यह सम्मेलन पूंजी बाजार के क्षेत्र में वृत्तिक अवसरों के संबंध में और अधिक जानकारी प्रदान करने के निबंधानुसार सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन था।
- चेन्नई में पूंजी बाजार संबंध एक दिवसीय सीपीई कार्यक्रम - समिति ने 28 मई, 2009 को चेन्नई में पूंजी बाजार संबंध एक दिवसीय सीपीई कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में 850 सदस्यों ने भाग लिया था और इस सम्मेलन को पूंजी बाजार के क्षेत्र के विख्यात विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विषयों पर संबोधित किया गया था।

प्रकाशन

- निगम प्रशासन के प्रमाणन संबंधी विद्यमान मार्गदर्शक टिप्पण का पुनर्विलोकन (जैसा कि सूचीकरण करार के खंड 49 में अधिकथित है) - पुनरीक्षित मार्गदर्शक टिप्पण, 2009 का प्रकाशन किया गया था।
- साहित्य सामग्रियां - समिति ने निजी साम्पा और आईपीओ पर दो व्यापक साहित्यिक सामग्रियों को तैयार किया था और उन्हें आयोजित की गई विभिन्न संगोष्ठियों और सम्मेलनों में परिचालित किया गया था।
- समिति दर्शन - समिति ने वर्ष 2008-09 के लिए अपनी पीआर किट को निकाला। इसमें समिति की पूर्व, वर्तमान और भावी उपलब्धियां उपदर्शित हैं।

5.7 विशेषज्ञ राय

वित्तीय विवरणों का उद्देश्य रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के वित्तीय कार्यपालन और वित्तीय स्थिति के संबंध में सही जानकारी उपलब्ध कराना है, जो व्यापक प्रकार के उपयोक्ताओं के लिए अस्तित्व की प्रबंध दक्षता और आर्थिक निर्णय क्षमता को अभिनिश्चित करने के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय विवरणों को पारदर्शी सुसंगत, व्यापक, तुलनीय होना चाहिए और उन्हें अस्तित्व की अंतर्निहित आर्थिक वास्तविकता और उसके द्वारा किए जाने वाले संव्यवहारों को उपदर्शित करना चाहिए। विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी), संस्थान के सदस्यों के, वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करते समय और संपरीक्षकों, प्रबंध, विभिन्न पणधारियों और पदाधिकारियों के विचारों को सुमेलित करते समय साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के निर्वचन, कार्यान्वयन और उन्हें समझने में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का समाधान करके इस उद्देश्य के प्रति योगदान करती है।

समिति इस प्रयोजन के लिए विरचित सलाहकारी सेवा नियमों के अनुसार प्राप्त प्रश्नों का उत्तर देती है। नियमों के अनुसार, समिति लेखांकन और/या संपरीक्षा सिद्धांतों और संबंधित विषयों से संबंधित प्रश्नों के संबंध में कार्यवाही करती है और एक साधारण नियम के रूप में ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है जिनमें विभिन्न अधिनियमितियों का विधिक निर्वचन अंतर्बलित होता है और वृत्तिक कदाचार अंतर्बलित करने वाले विषयों को भी समिति स्वीकार नहीं करती है। सलाहकारी सेवा नियम संस्थान के वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं या उन्हें नई दिल्ली स्थित संस्थान के प्रधान कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि समिति को परिषद् द्वारा नियुक्त किया गया है, समिति द्वारा दी गई राय या अभिव्यक्त मत इसी के सदस्यों की राय या मत का प्रतिनिधित्व करते हैं और न कि वह संस्थान की समिति की शासकीय राय होते हैं।

1.4.2008 से 31.5.2009 की अवधि के दौरान, समिति ने बृहत रज वाले मुद्दों के संबंध में 60 रायों को अंतिम रूप दिया है जैसे कि आस्थगित करों के लिए लेखांकन, कार्यकारी फायदा स्कीमें, विदेशी विनियम अंतर, ऋण लागतें, अंतरण में सामग्री का

मूल्यांकन, सन्निर्माण अवधि के दौरान व्यय पर विचार आदि। समिति ने विनियामकों/सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त विभिन्न लेखांकन मुद्दों पर भी विचार किया था और 6 रायों को अंतिम रूप दिया था। इस अवधि के दौरान, विशेषज्ञ सलाहकार समिति और व्यापार विधियां तथा डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति द्वारा “लेखांकन वृत्तिकों के लिए उभरते प्रतिमानों पर हीरक जयंती राष्ट्रीय कार्यशाला” नामक एक संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी 24 अक्टूबर, 2008 को लखनऊ में आईसीएआई की सीईआरसी की लखनऊ शाखा द्वारा की गई थी। इस कार्यशाला का उद्घाटन माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा, अध्यक्ष, यूपी राज्य सलाहकार परिषद्, सदस्य, राज्य सभा द्वारा किया गया था और उन्होंने इस कार्यशाला को संबोधित भी किया था। माननीय श्री नरेश अग्रवाल, पूर्व मंत्री, यूपी सरकार ने भी उक्त कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस कार्यशाला में लगभग 450 सदस्यों ने भाग लिया था। उपरोक्त कार्यक्रम में समिति का एक जानकारी ब्राशर भी जारी किया गया था। इस ब्राशर को लगभग 14,500 उद्यमों को भेजा गया था जिनमें विनिर्माण, बैंकिंग और वित्त, पीएसयू, व्यापार, सेवा, आईटी कंपनियां, संचार, सन्निर्माण, विद्युत, बीमा, शैक्षिक संस्थाएं, एनजीओ, पतन न्यास और वाणिज्य तथा उद्योग के चैम्बर जैसे विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित थे।

किसी एक वर्ष के दौरान समिति द्वारा अंतिम रूप दी गई सभी रायों को, रायों के कंपेंडियम में प्रकाशित किया जाता है। अभी तक, कंपेंडियम की 25 जिल्दें, जिनमें समिति द्वारा जनवरी, 2006 तक अंतिम रूप दी गई रायें अंतर्विष्ट हैं, ईएसी द्वारा जारी की गई हैं। रायों के कंपेंडियम की सभी 25 जिल्दों में अंतर्विष्ट सभी रायों को अंतर्विष्ट करने वाली एक सीडी को जिसमें सुगम संदर्भ के लिए उपयोक्ता-मित्र विशिष्टियां हैं, इस अवधि के दौरान जारी किया गया था। यह विश्वास किया जाता है कि यह सीडी वृत्ति के लिए एक सुदृढ़ ज्ञान संसाधन होगा। श्रृंखला में कंपेंडियम की आगामी जिल्दें, जिनमें ईएसी द्वारा फरवरी, 2006 और जनवरी, 2009 के बीच दी गई रायें अंतर्विष्ट हैं, संकलनाधीन हैं और उन्हें शीघ्र ही जारी किया जाएगा। समिति द्वारा अंतिम रूप दी गई कुछ रायों को आईसीएआई के जर्नल ‘द चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट’ के प्रत्येक अंक में प्रकाशित किया जाता है। समिति की हाल ही की राय भी संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

5.8 सतत वृत्तिक शिक्षा

5.8.1 सामान्य अवलोकन

सीपीई वृत्तिकों के लिए, उनके ज्ञान, कौशल और सक्षमता के विकास और उसे बनाए रखने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। यह कहना अनावश्यक है कि आईसीएआई हमेशा अपने सदस्यों द्वारा दी गई वृत्तिक सेवाओं के मानक में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करता आया है और आईसीएआई की सीपीई समिति सदस्यों को यह स्तर बनाए रखने के लिए प्रत्येक संभव पहल कर रही है। समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं कि आईसीएआई के सदस्य विद्यमान और उभरते हुए विषयों और चार्टर्ड एकाउंटेंसी की वृत्ति से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबंधित विषय विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं के संबंध में निरंतर अद्यतन बने रहें और सदस्यों को आवश्यक कौशल प्रदान करने में सहायता की जा सके जिससे कि इस प्रकार अर्जित ज्ञान उनकी वृत्ति में उपदर्शित हो सके।

सभी सदस्यों को आशयित सक्षमता स्तर बनाए रखने के लिए समर्थ बनाने हेतु, जो उनकी वर्तमान भूमिका और ली जाने वाली नई भूमिकाओं में कार्यपालन में सुधार करने, वर्तमान नियोजन या वर्तमान वृत्ति में करियर संभावनाओं में सुधार करने और नए नियोजनों या भिन्न वृत्तियों में करियर अभिवृद्धि के समर्थन में, सीपीई क्रेडिट घंटों की अपेक्षाओं को आयु या पर्वग (अर्थात् सीओपी सहित/रहित) पर ध्यान न देते हुए सभी सदस्यों के लिए आज्ञापक बनाया गया है। कलेंडर वर्ष 2008 से आईसीएआई के सदस्यों के लिए सीपीई क्रेडिट अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

ऐसे सभी सदस्यों से, जो व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारित कर रहे हैं (ऐसे सदस्यों को छोड़कर जो विदेशों में निवास कर रहे हैं), जब तक कि उन्हें छूट प्रदान न की जाए, यह अपेक्षा की जाती है कि वे :

3 वर्ष की प्रत्येक रोलिंग अवधि में न्यूनतम 90 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें, जिनमें से 60 सीपीई क्रेडिट घंटे ढांचागत पठन के होंगे।

प्रत्येक वर्ष में ढांचागत पठन के न्यूनतम 20 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

ऐसे सभी सदस्यों से, जो व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारित नहीं कर रहे हैं या जो विदेशों में निवास कर रहे हैं (चाहे वे व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारित कर रहे हैं अथवा नहीं), जब तक कि उन्हें छूट प्रदान न की जाए, यह अपेक्षा की जाती है कि वे :

3 वर्ष की प्रत्येक रोलिंग अवधि में ढांचागत/गैरढांचागत पठन के न्यूनतम 45 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

प्रत्येक वर्ष में ढांचागत/गैरढांचागत पठन के न्यूनतम 10 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

ऐसे सभी सदस्यों से, (60 वर्ष से अधिक आयु के) जो व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारित कर रहे हैं जब तक कि उन्हें छूट प्रदान न की जाए, यह अपेक्षा की जाती है कि वे :

3 वर्ष की प्रत्येक रोलिंग अवधि में (ढांचागत/गैर ढांचागत) न्यूनतम 70 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

प्रथम वर्ष, अर्थात् 2008 में ढांचागत/गैर ढांचागत के न्यूनतम 10 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

दूसरे और तीसरे वर्ष, अर्थात् 2009 और 2010 में ढांचागत/गैर ढांचागत के न्यूनतम 20 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

ऐसे सभी सदस्यों से, (60 वर्ष से अधिक आयु के) जो व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारित नहीं कर रहे हैं जब तक कि उन्हें छूट प्रदान न की जाए, यह अपेक्षा की जाती है कि वे :

3 वर्ष की प्रत्येक रोलिंग अवधि में (ढांचागत/गैर ढांचागत) न्यूनतम 35 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

प्रथम वर्ष, अर्थात् 2008 में ढांचागत/गैर ढांचागत के न्यूनतम 5 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

दूसरे और तीसरे वर्ष, अर्थात् 2009 और 2010 में ढांचागत/गैर ढांचागत के न्यूनतम 10 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

किसी कलेण्डर वर्ष के दौरान गैर ढांचागत पठन क्रियाकलाप करने के लिए सीपीई घंटों का फायदा लेने के लिए सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आगामी वर्ष की 31 मई तक ऐसे संबंधित विकेन्द्रीकृत कार्यालय में स्वघोषणा प्रस्तुत करें जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत उनकी सदस्यता आती है।

5.8.2 टेली-कांफ्रेंसिंग कार्यक्रम

काफी लंबे समय से टेली-कांफ्रेंसिंग ज्ञान के प्रसार के लिए कम लागत की पद्धतियों में से एक है। वर्तमान समय में, समिति इंडिया गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), दिल्ली के सहयोग से चार्टर्ड एकाउंटेंसी वृत्ति से सुसंगत और संबंधित विषयों पर एक या दो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती है। अभी तक सम्मिलित किए गए विषयों में, लेखांकन और आश्वासन मानक, टीडीएस उपबंधों में हाल ही के परिवर्तन, कंपनी संपरीक्षा, आईएफआरएस के साथ भारतीय लेखांकन मानकों का अभिसरन, कर संपरीक्षा, पूंजी बाजारों में हाल ही की घटनाएं, सेवा कर के क्षेत्र में हाल ही की घटनाएं, सूचना प्रौद्योगिकी, पियर रिव्यू, बीमा और पेंशन, घन प्रबंध और निवेश रणनीतियां, कानूनी बैंक संपरीक्षा, निगम शासन, पूंजी अभिलाभ और सर्वेक्षण, तलाशी और अभिग्रहण, आयकर अधिनियम के अधीन हानियों का मुजरा और उन्हें अग्रणीत करना - व्यवहारिक मुद्दे और सीआईटी (अपील) तथा आईटीएटी के समक्ष अपील प्रक्रियाएं, आयकर अधिनियम और एफसीआर अधिनियम के विशेष प्रतिनिर्देश से गैर लाभकारी संगठनों से संबंधित मुद्दों का विधिक अनुपालन और सावधि ऋण तथा कार्यकारी पूंजी प्राप्त करने के प्रतिनिर्देश से परियोजना रिपोर्टें तैयार करने की कला।

सदस्यों से निरंतर प्राप्त होने वाली उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, सीपीई समिति ने टेली-कांफ्रेंसिंग कार्यक्रमों की सीडी बनाना प्रारंभ कर दिया है। सदस्य प्रति यूनिट 50 रुपये के संदाय पर इन सीडीयों को प्राप्त कर सकते हैं और इन्हें देखकर सदस्य दो घंटे (गैर ढांचागत) सीपीई क्रेडिट का दावा भी कर सकते हैं।

5.8.3 ई-लर्निंग पहलें

समिति ने ई-लर्निंग पद्धति से ज्ञान के प्रसार के क्षेत्र में कदम रखे हैं और इस वर्ष के दौरान दो परियोजनाएं प्रारंभ की गई थीं, अर्थात् सेवा कर और आईएफआरएस। सेवा कर संबंधी ई-लर्निंग पाठ्यक्रम को नवम्बर, 2008 में आरंभ किया गया था और अभी तक लगभग 50000 सदस्यों ने इस प्रसुविधा का लाभ लिया है। 1 अप्रैल, 2009 से सभी ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों का संचालन आईसीएआई की आईटी समिति द्वारा किया जा रहा है क्योंकि यह क्षेत्र उसके कार्यकरण पैटर्न के सन्निकट है।

5.8.4 घरेलू कार्यकारी विकास कार्यक्रम

यह समिति कारबार गृहों के पदधारियों के कौशलों में और वृद्धि करने तथा उनके हित के क्षेत्रों में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सस्ती लागत पर गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। समिति देश भर में विभिन्न संगठनों में, समकालीन सुसंगत विषयों और विशेषकर आईएफआरएस पर प्रत्येक मास ऐसे चार या पांच आयोजन करती है। इस वर्ष के दौरान 2000 से अधिक पदधारियों ने अपने ज्ञान को समुन्नत करने के लिए इन पाठ्यक्रमों का फायदा प्राप्त किया था।

5.8.5 सीपीई पोर्टल

इस समिति ने विद्यमान और किसी बाह्य अभिकरण द्वारा बनाए रखे जा रहे पोर्टल में सुधार करने के लिए पहल की थी। इस प्रणाली को और अधिक आकर्षक तथा उपयोक्ता - मित्र बनाने के लिए यह पोर्टल इस समय घरेलू पदधारियों द्वारा मानीटर तथा प्रबंधित किया जा रहा है तथा सदस्य सभी सहबद्ध ब्योरों के साथ अपने वार्षिक ढांचागत/गैरढांचागत क्रेडिट घंटों को देख सकते हैं और साथ ही न्यूनतम प्रयास से उसके प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं।

5.8.6 कार्यक्रम आयोजित करने वाले यूनिटों (पीओयू) के मानीटरी तंत्र को सशक्त बनाना

पीओयू के कार्यकरण पैटर्न को कारगर बनाने और साथ ही उनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले आयोजनों की समुचित मानीटरी और हाजिरी को समय पर अद्यतन करने के लिए मासिक जानकारी प्रणाली का एक व्यवहार आरंभ किया गया है, जो दी जाने वाली शिक्षा और विकसित की जारी पृष्ठभूमि सामग्री की गुणवत्ता में सुधार को सुकर बनाएगा।

5.8.7 गैर ढांचागत पठन क्रियाकलाप (यूएलए)

जैसा कि पहले कहीं कथन किया गया है, कतिपय प्रवर्ग के सदस्य यूएलए का भी फायदा प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रभाव की जारी सलाह में निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

- वेब आधारित पठन मोड्यूल (ई-लर्निंग)।

- ई-लर्निंग “ इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त या समर्थ अनुदेशात्मक अंतर्वस्तु या पठन अनुभव” है। इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण (सीबीटी) से कंपैक्ट डिस्क (सीडी), वेब आधारित उपयोजनों तक सभी कुछ सम्मिलित है।
- स्वतः पठन मोड्यूल और पाठ्यक्रम (ऑडियो टेपों, वीडियो टेपों का उपयोग, पत्राचार पाठ्यक्रम, कंप्यूटर आधारित पठन कार्यक्रम)
- पठन और व्यक्तिगत गृह अध्ययन।
- पठन और व्यक्तिगत गृह अध्ययन में संस्थान के जर्नल “ दि चार्टर्ड एकाउंटेंट” में लेखों को पढ़ना, तकनीकी, वृत्तिक, विज्ञानी या कारबार साहित्य को पढ़ना सम्मिलित है।
- तकनीकी मुद्दों पर समूह या द्विपक्षीय विचार-विमर्श।
- विभिन्न विश्वविद्यालयों/प्रबंध संस्थाओं/राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं में अतिथि संकाय या दौरा करने वाले संकाय के रूप में कृत्य करना।
- पीपीयू के अधीक्षण के बिना सीपीई टेली-कांफ्रेंसिंग कार्यक्रमों में भाग लेना।
- वेब/वृत्तिक जर्नलों में उपलब्ध प्रश्नावलियों/पहेलियों के समाधान उपलब्ध कराना।
- 7 वा अधिक भागीदारों वाली चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों द्वारा आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

कलेण्डर वर्ष 2008 में यूएलए पद्धति का लाभ लेने के लिए स्वतः-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख 31 मई, 2009 थी और इस संबंध में व्यक्तिक्रम से बचने के लिए सदस्यों की प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक थी।

5.8.8 सीपीई कलेण्डर

व्यवहार के विषय के रूप में, विभिन्न बोर्ड शीर्षों के अधीन उपदर्शी विषयों एक सूची प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर तैयार की जाती है और यह व्यवहार देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजन करते समय अंतर्वस्तु और सम्मिलित विषयों की एकसमानता बनाए रखने को सुकर बनाता है। तथापि, ये विषय आबद्धकर हैं और सूची बनाना सुसंगत रूप से सर्वांगपूर्ण है, फिर भी कतिपय वैकल्पिक विषयों को पृथक रूप से जोड़ा जाता है। वर्ष 2009-10 के लिए आबद्धकर विषयों में निम्नलिखित सम्मिलित है :-

लेखांकन तथा संपरीक्षा

1. आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक
2. आईसीएआई द्वारा जारी संपरीक्षा, आश्वासन तथा क्वालिटी मानक
3. विभिन्न सेक्टरों/उद्योगों (बैंककारी सेक्टर, भू संपदा सेक्टर, बीमा उद्योग आदि) में लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन : तकनीकी और प्रबंध संबंधी मुद्दे
4. लेखांकन मानकों में कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे, आशाएं और विभिन्न सेक्टरों/उद्योगों (बैंककारी, सेक्टर, भू संपदा सेक्टर, बीमा उद्योग आदि) में साधारण रूप में अपेक्षाओं का अनुपालन
5. लेखांकन और संपरीक्षा संबंधी आईसीएआई की उद्घोषणाएं तथा अन्य दस्तावेज
6. क्षेत्रवार/उद्योगवार व्यावहारिक प्रस्तुतीकरण के साथ लेखांकन दस्तावेज
7. यू.एस. और यू.के. जीएपी
8. आंतरिक संपरीक्षा मानक
9. पीयर रिव्यू - प्रेक्टिस यूनिट के लिए प्रणाली, प्रक्रिया तथा दस्तावेजीकरण
10. क्वालिटी पुनर्विलोकन के अधीन तकनीकी मानक
11. सर्वेन्स आक्सले अधिनियम
12. सर्वेन्स आक्सले अधिनियम की आंतरिक संपरीक्षा पर विवक्षाएं
13. शहरी स्थानीय निकायों का लेखांकन
14. सहकारी सोसाइटियों के लेखा
15. लघु अस्तित्वों की संपरीक्षा
16. न्यायालयिक लेखांकन तथा संपरीक्षा
17. आंतरिक संपरीक्षा - जोखिम आधारित आंतरिक संपरीक्षा सहित

18. आंतरिक संपरीक्षा और कपट संबंधी जोखिम
19. आंतरिक नियंत्रण - जोखिम आधारित परिप्रेक्ष्य सहित
20. आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में आश्वासन प्रदान करना
21. सेवा कर संपरीक्षा
22. वैट संपरीक्षा
23. गैर निगमित उद्यमों और उनके संपरीक्षकों से संबंधित मुद्दे
24. खंड 49 और आंतरिक संपरीक्षा की भूमिका
25. लेखांकन मानकों और अन्य रिपोर्टिंग तथा प्रकटन अपेक्षाओं के अनुपालन पहलू
26. वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन पहलू
27. आईसीएआई द्वारा जारी एएस और अन्य आज्ञापक मार्गदर्शनो के अनुपालन पहलू
28. आंतरिक संपरीक्षक का ऐसे व्यक्तियों के साथ संबंध, जिन्हें शासन का प्रभार सौंपा गया है
29. वृत्तिक आचार-संहिता और कारबार नैतिकता
30. संवहनीयता रिपोर्टिंग

लागत और वित्तीय प्रबंध

31. संतुलित स्कोर कार्ड
32. कारबार प्रक्रिया सुधार
33. वैश्विकृत कारबार माहौल में पूंजी संबंधी बजट तैयार करना
34. वित्तीय पूर्वानुमान
35. लागत प्रबंध
36. वित्तीय सम्यक् उद्यम
37. वित्तीय लिखतें
38. वित्तीय मॉडलिंग
39. सीमापार निवेशों से संबंधित मुद्दे
40. निगम वित्तीय रिपोर्टिंग
41. यूएस के जीएपी और आईएस के अधीन वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन

सूचना प्रौद्योगिकी

- 42.. निम्नलिखित पर व्यवहारिक कार्यशाला
 - क. बैंकों/बैंककारी उपयोजनों की आईएस संपरीक्षा
 - ख. सीएटीके/साधारण संपरीक्षा साफ्टवेयर का उपयोग
 - ग. स्टॉक ब्रोकर सीटीसीएल प्रसुविधा की आईएस संपरीक्षा
 - घ. एमएस-एक्सेल-संपरीक्षा के लिए उपकरण
 - ङ. नेटवर्क संरक्षा संपरीक्षा/पुनर्विलोकन
 - च. विंडोज एक्सपी संरक्षा पुनर्विलोकन
 - छ. विंडोज 2000/3003 संरक्षा पुनर्विलोकन
 - ज. एमएसएक्सेल - वित्तीय विश्लेषण/रिपोर्टिंग के लिए उपकरण
 - झ. वित्तीय प्रबंधन के लिए एमएस-एक्सेल
 - ञ. एमएस-एक्सेल की प्रोन्नत विशिष्टियां और सुविधाएं
 - ट. लेखांकन/वित्तीय अपेक्षाओं के लिए आंकड़ों का निष्कर्षण/विश्लेषण
 - ठ. एमएस-वर्ल्ड का उपयोग करते हुए रिपोर्टिंग/दस्तावेजीकरण
 - ड. कोर बैंकिंग उपयोजनों (सीवीए) की आईएस संपरीक्षा/पुनर्विलोकन

ड. सूचना प्रणाली संपरीक्षा

43. एक्सबीआरएल वित्तीय रिपोर्टिंग भाषा
44. आंतरिक नियंत्रणों का प्रमाणीकरण - खंड 49/सर्वेन्स आक्सले अधिनियम
45. लेखांकन सॉफ्टवेयर संरक्षा संपरीक्षा / पुनर्विलोकन और प्रोन्नत सुविधाएं/विशिष्टियां
46. अंकीय हस्ताक्षर और ई-फाइलिंग (आयकर/एससीए 21)
47. इआरपी को समझना (2 दिन)
48. इआरपी कार्यान्वयन/परीक्षण/अनुक्षण (8/21 दिन)
49. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
50. उभरती हुई सूचना प्रौद्योगिकी चुनौतियां और अवसर
51. वीपीओ/केपीओ सनराइज क्षेत्रों में बढ़ते अवसर
52. सूचना प्रौद्योगिकी सर्वोत्तम व्यवहार - एक पुनर्विलोकन
53. कंप्यूटर से सहायता प्राप्त कार्यपालन मूल्यांकन
54. ई-कॉमर्स/ई-शासन
55. प्रबंध सूचना प्रणालियां (एमआईएस)
56. प्रौद्योगिकी प्रबंध
57. सूचना प्रणालियां - सुरक्षा और नियंत्रण
58. आंतरिक संपरीक्षा - उभरते सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिमों से जूझना कराधान
59. आय-कर अधिनियम के अधीन संपरीक्षा - तैयारी, प्रस्तुतीकरण और दस्तावेजीकरण
60. अवक्षयण : लेखांकन, कराधान तथा कंपनी विधि के मुद्दे
61. कराधान की तुलना में लेखांकन मानक
62. अप्रत्यक्ष कराधान में उभरते हुए मुद्दे
63. व्यवसाय कराधान संबंधी मुद्दे
64. अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी मुद्दे (अनिवासी भारतीय कराधान, डीटीए, अंतरण मूल्य और विदेशों में कराधान सहित)
65. विदेशी संदाय - आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 195 के अधीन टीडीएस
66. राष्ट्रीय कर अधिकरण सहित कर अधिकरण - चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की भूमिका
67. प्रत्यक्ष कर विधियों संबंधी वर्तमान निर्णय
68. सेवा कर - विधि और व्यवहार
69. अनिवासी भारतीय का कराधान - हाल की घटनाएं
70. कर विधियों के अधीन स्थगन, कर वसूली तथा अन्य सहबद्ध उपबंध
71. अंतरण कीमत
72. निगमित कराधान
73. फ्रिज बेनिफिट कर (एफबीटी)
74. मूल्य वर्धित कर (वेट)
75. सर्वेक्षण, तलाशी तथा अभिग्रहण - हाल की घटनाएं
76. डेस्क पुनर्विलोकन
77. निर्यात आयात व्यापार/सीमाशुल्क मूल्यांकन विधि - नियम और अनुपालन
78. केन्द्रीय बिक्रय कर (सीएसटी)
79. ऐसे स्थान जहां करों में छूट दी गई है
80. धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा
81. निर्धारण प्रक्रियाएं

82. आय-कर निर्धारण
83. अपीलें तैयार करना और सीआईटी और आईटीएटी के समक्ष प्रस्तुत करना
84. जीएसटी के संदर्भ में भारतीय कर प्रणाली का सुधार
- कारबार प्रबंध
85. विरोध प्रबंध
86. उपभोक्ता और संगठनात्मक क्रय संबंधी व्यवहार
87. संविदा प्रबंध - व्यवहारिक मुद्दे
88. प्रतिस्पर्धात्मकता : अवधारणाएं और चुनौतियां
89. वाणिज्यिक सम्यक उद्यम
90. क्रेडिट विश्लेषण और क्रेडिट प्रबंध
91. प्रदाय नीतियों का मूल्यांकन ढांचा
92. परिवर्तन संबंधी प्रबंध
93. सृजन संबंधी प्रबंध
94. कर्मचारी अत्यधिकता संबंधी प्रबंध
95. विनिर्माण परिस्थितियों में एबीसी का कार्यान्वयन
96. औद्योगिक संबंध
97. मूल्य आधारित प्रबंध
98. सकल क्वालिटी प्रबंध
99. रणनीति संबंधी विनिश्चय - करना
100. संवहनीयता विकास
101. उत्साहवर्द्धक तकनीकें
102. संक्षिप्त रिपोर्टिंग
103. ज्ञान संबंधी प्रबंध
104. संकर्मों की योजना बनाना और नियंत्रण
105. सही समय पर कार्य करना (जेआईटी)
106. कार्यपालन संबंधी प्रबंध
107. प्रभावी समय प्रबंध
108. क्वालिटी संपरीक्षाएं
109. मूल्यवर्धित कारबार नियंत्रण - जोखिम प्रबंध का सही तरीका
110. प्रबंध संपरीक्षा
111. जोखिम और अनिश्चय की परिस्थितियों के अधीन विनिश्चय करना
112. लागत में कमी और लागत नियंत्रण
113. संसाधन जुटाने में लागत कम करने संबंधी तकनीकें
114. कारबार नैतिकता
115. निगम संसूचनाओं में सिद्धांत और विषय
116. कारबार प्रस्तुतीकरण और संपरीक्षा विश्लेषण
117. कारबार संवहनीयता
- निगम विधियां
118. अनुसूची 6
119. एमसीए 21 के अधीन ई-प्रारूप
120. माध्यस्थता अधिनियम, 1996

121. मूल्यांकन तकनीकें
122. विलयन और निर्विलयन
123. कंपनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ)
124. सीएआरओ कंपनी अधिनियम के अधीन संपरीक्षक की रिपोर्ट - सीएआरओ, दस्तावेजीकरण, रिपोर्टिंग और प्रकटन अपेक्षाओं संबंधी मुद्दे
125. एनसीएलटी विधि तथा व्यवहार
126. एमसीए 21 - वृत्ति के लिए चुनौतियां तथा अवसर
127. सीमित दायित्व भागीदारी
128. एक्जिन नीति और प्रक्रियाएं
129. अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006
130. प्रतिस्पर्धा अधिनियम और समामेलन तथा अर्जन आचार संहिता
131. आईसीएआई की नीतिगत संहिता और उभरते हुए सुसंगत मुद्दे वित्त तथा पूंजी बाजार
132. व्युत्पत्तियां : भावी तथा विकल्प
133. व्युत्पत्तियां : लेखांकन और कराधान
134. ओटीसी व्युत्पत्तियां - एक विधिक परिप्रेक्ष्य
135. निधियां जुटाने के स्रोत
136. वित्त तथा पूंजी बाजार का वर्तमान रुझान
137. अंतरराष्ट्रीय वित्त
138. अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थानों की भूमिका
139. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नियम
140. परियोजना रिपोर्ट तथा मूल्य निर्धारण
141. परियोजना वित्त पोषण
142. फौरेक्स प्रबंध
143. सूचीबद्ध करने संबंधी करार
- निगम शासन
144. संपरीक्षा समिति चार्टर
145. संपरीक्षा समिति तथा स्वतंत्र निदेशक
146. सीओएसओ, सीओबीआईटी और ईआरपी
147. व्हिसल ब्लोअर नीति - ढांचा
148. उद्यम शासन
149. वहनीय विकास और सार्वभौमिक रिपोर्टिंग सूचकांक (जीआरआई)
150. निगम शासन में सीए की भूमिका
151. निगम शासन की रेटिंग
152. निगम शासन की संपरीक्षा
153. ग्लोबल वार्मिंग/मौसम में परिवर्तन
154. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)
155. कार्बन क्रेडिट
156. सुशासन के माध्यम से बोर्ड की प्रभावकारिता में सुधार
157. सार्वभौमिक विकास में निगम शासन का प्रभाव

158. ग्रीन कार्बन व्यवहार

बीमा और जोखिम प्रबंध

159. बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण

160. पेंशन निधि में विकास

161. बीमा क्षेत्र में प्रति धनशोधन

162. जोखिम प्रबंध

163. बीमा कंपनियों का मूल्यांकन

164. तृतीय पक्षकार बीमा

165. एस-15 और बीमांकन विज्ञान

166. उत्पादों की कीमत तय करना

लोक वित्त

167. वित्त नीति और आर्थिक विकास

168. लोक वित्त और लोक नीति : सरकार के उत्तरदायित्व और परिसीमाएं

169. कराधान परिप्रेक्ष्य - एक लोकतांत्रिक पहुंच - भारत में लोक वित्त

170. लोक ऋण और भारत में आर्थिक योजनाएं

171. लोक निधि का प्रबंध - महत्वपूर्ण मुद्दे और दिवक्षाएं

172. भारत में लोक ऋण

173. बाह्य ऋण और विदेशी मुद्रा आरक्षितियां

174. बजट - भारत में प्रक्रिया - सहायता और अनुदान

175. लोक बजटिंग की राजनीति : प्राप्त करना और व्यय करना - ऋण और संतुलन

176. भारत में बजट और मतपत्र - राज्य से केंद्र तक भागीदारी बजटिंग

177. वित्तीय विवेक और चुनौतियां : केन्द्र और राज्य संबंधों का पुनर्विलोकन

178. लोक व्यय के प्रभाव

179. भारतीय फेडरल वित्त

180. कृषि क्षेत्र में कराधान

181. रेल संबंधी वित्त

182. कराधान का विस्तार और प्रभाव

183. कराधान उत्तरदायित्व और वसूली

184. भारत में पब्लिक सेक्टर उपक्रम - एक प्रतिमान अंतरण

185. अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थाएं: अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थाओं की भूमिका/ परिवर्तित भूमिका और उत्तरदायित्व

186. धनशोधन

187. ग्रामीण बैंकिंग बढ़ती हुई संगतता और मविष्य

188. उदारीकरण युग के पश्चात् आर्थिक विकास

189. डेलीवरीन टू डिबोलूसन - भारत में लोकवित्त का तुलनात्मक पुनर्विलोकन

190. कर शासन - एक मध्यम आयवर्गीय अभिकरण

191. भारत में राज्य का आर्थिक उदभव : सक्षमता और सहमति

192. धन प्रदाय में परिवर्तन : नीति की दिशा और वर्तमान युग में संगतता

सुगत दक्षताएं

193. व्यक्तित्व का विकास

194. ग्राहकों से संबंध का प्रबंध

195. आय-कर प्राधिकारियों के समक्ष प्रभावी प्रस्तुतीकरण

196. तनाव प्रबंध
197. प्रस्तुतीकरण और संवाद संबंधी दक्षताएं
198. अंतर्व्यक्ति दक्षताएं
199. श्रवण और पठन दक्षताएं
200. निजी वित्त
201. आर्थिक संदी और वित्तीय संकट
- अन्य
202. परामर्शी और सलाहकारी सेवाएं
203. कारबार सलाहकारी सेवाएं
204. सूचना का अधिकार अधिनियम
205. छह सिगमा
206. कपट अन्वेषण, रिपोर्टिंग और निवारण
207. न्यायशास्त्र, विधि का निर्वचन तथा साक्ष्य अधिनियम
208. धन शोधन, जोखिम और प्रबंध - निवारण सहित
209. सीए संशोधन अधिनियम, 2006
210. सीए फर्मों का विलय, अविलय और निर्विलयन तथा क्षमता निर्माण
211. हस्तांतरण विलेखों के प्रारूपण की कला

सीपीई समिति की अन्य पहलें

- कंपनियों को क्रमबद्ध रूप से आईएफआरएस कार्यान्वित करने और 1 अप्रैल, 2011 की अंतिम तारीख की रूप में इसे पूरा करने में सहायता करने के विचार से, प्रत्येक मास विशेषकर बड़े पीएसयू में आधा दर्जन घरेलू कार्यकारी विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
- लेखांकन मानक, संपरीक्षित विवरण, आचार-संहिता और वृत्तिक आचार के विशेष संदर्भ से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करना।
- सदस्यों की, आज्ञापक सीपीई घंटों के प्रयोजन और संभावनाओं को समझने में सहायता करना, एफएक्यू के रूप में एक व्यापक मैनुअल निकाला जाएगा।
- समकालीन विषयों पर कुछ एक समकालीन प्रकाशनों को भी सीपीईसी के तत्वावधान में निकाला जाएगा।
- टेली-कांफ्रेंसिंग के कार्यक्रमों की प्रभाविकता में सुधार करना, पढ़ाए गए विषयों पर सीडी को अब आईसीएआई के सभी पीओयू में वितरित किया जा रहा है।
- विद्यमान सीपीई विवरण को अंतरराष्ट्रीय रूप से तुलनीय बनाने के लिए, गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करके वास्तविक मूल्यवर्धन करने के लिए इसके कतिपय खंडों का पुनरीक्षण और संशोधन अनुष्ठात किया गया है।
- दूरस्थ स्थानों में निवास करने वाले सदस्यों की सहायता करने के लिए सीपीई चैप्टरों और अध्ययन समूहों जैसे विभिन्न किस्म के पीओयू के सृजन के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।
- देश के विभिन्न क्षेत्रों में सीपीई संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण देने वाले कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना।

5.9 वृत्तिक विकास समिति

प्रस्तावना :

वृत्तिक विकास समिति को भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा वर्ष 1962 में एक गैर-स्थायी समिति के रूप में स्थापित किया गया था। वृत्तिक विकास समिति आईसीएआई की सर्वाधिक सक्रिय समितियों में से एक है, जिसने सदस्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आईसीएआई के सदस्यों के लिए पर्याप्त अवसरों की खोज करने, उन्हें व्युत्पन्न करने, विकसित करने और उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास किए हैं। यह वृत्तिक विकास आवश्यकताओं को अवधारित करती है और वृत्ति को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों और मुद्दों की पहचान करती है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह समिति ऐसे नए और विद्यमान क्षेत्रों में खोजबीन/क्रियाएं करके जहां सदस्यों के वृत्तिक कौशल को और अधिक उत्पादक और फायदाप्रद रीति में उपयोग किया जा सकता है; संस्थान के सदस्यों के लिए और अधिक वृत्तिक अवसरों का सृजन करने के लिए प्रयास कर रही है। इस समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किए हैं कि वृत्ति के सभी सदस्यों को समान

अवसर उपलब्ध हों। वृत्तिक विकास में अभी तक जांचे परखे नहीं गए क्षेत्रों की पहचान करने के अलावा वृत्तिक विकास समिति समाज के विभिन्न तबकों में बहुप्रकार के उपयोक्ताओं के साथ संपर्क प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने और उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंटों की भूमिका के संबंध में शिक्षित करने के लिए प्रयास कर रही है। विद्यमान और नए क्षेत्रों में चार्टर्ड एकाउंटेंटों के कौशल में वृद्धि करने के विचार से, यह हित के समकालीन क्षेत्रों में संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का भी आयोजन करती है। अपने मिशन की पूर्ति के लिए, वृत्तिक विकास समिति ने वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पहलें की हैं जैसे कि विभिन्न सरकारी विभागों और विनियामक निकायों के विभिन्न पदधारियों से की गई बैठकें आदि। बैठकों के अलावा समिति ने सदस्यों के कौशल में सुधार लाने के उद्देश्य से, उन्हें ऐसे नए नियमों और विनियमों से अवगत कराने के लिए और इस प्रकार सदस्यों और विनियामकों को एक-दूसरे के करीब लाने के लिए संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया था।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान वृत्तिक विकास समिति की प्रमुख उपलब्धियां/प्रयास नीचे दिए गए हैं :

- वर्ष 2009-10 के लिए बहुप्रयोजन इम्पैनलमेंट आवेदन प्रारूप को वेबसाइट www.meficai.org पर, “कंपलेंट सेन्टर” लिंक के साथ रखने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई थी। इस वर्ष किसी भी अन्य वर्ष की तुलना में, अंतिम तारीख में कोई विस्तारण किए बिना इम्पैनलमेंट के लिए अधिकतम संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पदधारियों के साथ कानूनी संपरीक्षकों की नियुक्ति में प्रबंधकीय स्वायत्तता के मुद्दे पर बैठक की गई थी।
- वृत्तिक हित के विभिन्न मुद्दों, जिनके अंतर्गत बैंक शाखा संपरीक्षा (आबंटन और एलाटमेंट), एनबीएफसी से संबंधित मुद्दे आदि हैं, पर भारतीय रिजर्व बैंक के पदधारियों से चर्चाएं।
- वृत्तिक हित के विभिन्न मुद्दों, जैसे कि कानूनी संपरीक्षकों की संपरीक्षा फीस का पुनरीक्षण, संपरीक्षकों को प्रशिक्षण तथा क्वालिटी सेवा परिदान को सुकर बनाना आदि पर चर्चा करने के लिए नाबार्ड के पदाधिकारियों के साथ बैठक।
- वृत्तिक हित के विभिन्न मुद्दों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पदधारियों के साथ बैठक।
- आवास के क्षेत्र के हित का संवर्धन करने तथा उसमें सहयोग करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंटों हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आईसीएआई की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है।
- भारतीय बैंक एसोसिएशन (एबीए) और आईसीएआई की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है जो बैंकिंग क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न प्रकार की संपरीक्षा के विस्तार क्षेत्र, परिधि और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के विषय में विद्यमान स्थिति की समीक्षा करेगी।
- वृत्तिक विकास समिति का ज्ञान पोर्टल www.pdicai.org सदस्यों को निरंतर समय पर अपनी सेवाएं और व्यवसाय में होने वाली नई घटनाओं के संबंध में अनिवार्य सूचना तथा विभिन्न क्षेत्रों में नए वृत्तिक अवसरों के संबंध में आवश्यक जानकारी दे रहा है।
- ऐसे व्यक्तियों के साथ, जिनके विचार, उद्देश्य और भविष्य की रणनीति एक समान हैं और जो नेटवर्क में भाग लेने वालों की दृढ़ता को संपूरित करते हैं, नेटवर्क स्थापित करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंटों को एक मंच उपलब्ध कराने हेतु सीए नेटवर्किंग और सुदृढीकरण के लिए पोर्टल, जो www.canet.co.in लिंक पर उपलब्ध है, ने अपनी पहले जारी रखी।
- पूर्वोक्त के अलावा, और अधिक वृत्तिक अवसरों का सृजन करने और पूर्व में विद्यमान अवसरों के अनछुए क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित संगमों और प्राधिकरणों के साथ भी बैठकें की गई थी :
 - सीए के लिए नए डोमेन का पूर्वानुमान लगाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केबीआईसी) के वरिष्ठ पदधारियों।
 - केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वरिष्ठ पदधारी
 - बंबई स्टॉक एक्सचेंज के पदधारी
 - अग्रिम बाजार आयोग के पदधारी
 - कार्यकारी निदेशक, (वित्त और लेखा), भारतीय जीवन बीमा निगम
 - वित्तीय सतर्कता इकाई - भारत के वरिष्ठ पदधारी
 - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के सदस्य (वित्त) और वरिष्ठ पदधारी

- कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अन्वेषण और रजिस्ट्रीकरण अपर महानिदेशक
- प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न पदधारी
- भारतीय केन्द्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लिमिटेड के पदधारी
- भारतीय एकाधिकार और निर्बंधित व्यापार व्यवहार आयोग के पदधारी
- भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड के पदधारी
- वित्तीय आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पंजाब और सिंध बैंक
- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इलाहाबाद बैंक
- साम्यापूर्ण वृत्तिक अवसरों को सुनिश्चित करने और अधिकाधिक कार्य उपलब्ध कराने की वृहत मांग के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित प्राधिकरणों को चार्टर्ड एकाउंटेंटों/चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों के पैनल उपलब्ध कराए गए थे :
 - वेतन और लेखा कार्यालय, विकिरण और समस्थान प्रौद्योगिकी बोर्ड, मुंबई
 - रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, महाराष्ट्र सरकार
 - परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पुदुचेरी
 - सहायक महाप्रबंधक, भारतीय वित्त निगम, नई दिल्ली
 - राष्ट्रीय वस्तु और व्युत्पत्ती विनिमय लिमिटेड
 - शासकीय परिसमापक कनार्टक उच्च न्यायालय, बंगलोर
 - सहायक महाप्रबंधक, पंजाब और सिंध बैंक, नई दिल्ली
 - अध्यक्ष, पब्लिक सेक्टर पुनःसंरचना और आंतरिक संपरीक्षा बोर्ड, तिरुवनंतपुरम
 - परियोजना अधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, वारंगल
 - मुख्य कार्यपालक अधिकार, यूपीएसई सिक्वोरिटीज लिमिटेड, कानपुर
 - उप प्रबंधक, ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
 - पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुंबई
 - पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कोलकाता
 - आयकर मुख्य आयुक्त, कानपुर
- अपने रादर्यों के कौशल और योग्यता में सुधार करने के लिए विनिर्दिष्ट सहायता उपलब्ध कराने के मार्गों और उपायों पर विचार करने के अपने प्रयासों में, समिति ने इस अवधि के दौरान निम्नलिखित सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन किया :
 - समिति द्वारा 'गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)' के संपरीक्षकों के लिए हैदराबाद, त्रिचुर, कोलकाता और चंडीगढ़ में कार्यशाला श्रृंखला का आयोजन किया गया था।
 - डब्ल्यूआईआरसी द्वारा बैंकों के कानूनी संपरीक्षक, 2008 के लिए बेसल II विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 27 और 28 मई, 2008 को मुंबई में किया गया था।
 - 26 जुलाई, 2008 को मुंबई में आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी द्वारा जलवायु परिवर्तन, कमी करना जिसके अंतर्गत सीईआर प्रक्रिया चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए वृत्तिक अवसर पर एक कार्यशाला की मेजबानी की थी।
 - 22 अगस्त, 2008 को अहमदाबाद में उभरते वृत्तिक अवसर पर एक कार्यशाला।
 - 26 अगस्त, 2008 को नई दिल्ली में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की देखभाल करने वाले प्रायोजक बैंकों के महाप्रबंधकों और अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए रात्रि भोज बैठक।
 - 5 सितम्बर, 2008 को मुंबई में राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ संयुक्त रूप से गृह निर्माण वित्त पोषण कंपनियों (एचएफसी) के कानूनी संपरीक्षकों के लिए सक्षमता निर्माण कार्यक्रम 26 जुलाई, 2009 को मुंबई में आयोजित कार्यशाला के लिए तैयार की गई पृष्ठभूमि सामग्री में सुधार करने के लिए क्रमशः दिल्ली और मुंबई में 2

सितम्बर और 20 अक्टूबर, 2009 को कार्बन क्रेडिट और सीडीएम विशेषज्ञों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया था।

- संपरीक्षा मैन्युअल, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रुडेंशियल संनियमों और आरआरबी की कानूनी संपरीक्षा से संबंधित विभिन्न अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 11 सितम्बर, 2008 को आरआरबी के अध्यक्षों और संपरीक्षकों की बैठक।
- 24 सितम्बर, 2008 को नई दिल्ली में पब्लिक सेक्टर उद्यमों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए निदेशक, वित्त और पीएसयू के स्वतंत्र निदेशकों के बीच रात्रि भोज बैठक।
- 17 दिसम्बर, 2008 को नई दिल्ली में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(क) के अधीन पीएसयू की संपरीक्षा करने के लिए विद्यमान निदेशों पर विचार-विमर्श तथा उनका पुनर्विलोकन करने के लिए निदेशक, वित्त और पब्लिक सेक्टर उद्यमों के कानूनी संपरीक्षकों के बीच बैठक।
- मुंबई, बंगलोर, नई दिल्ली, कोलकाता में केन्द्रीय कानूनी संपरीक्षकों के लिए इंटरएक्टिव कार्यशालाओं की एक श्रृंखला।
- एर्नाकुलम, त्रिवेंद्रम, गाजियाबाद, नोएडा में बैंक संपरीक्षकों के लिए हीरक जयंती इंटरएक्टिव विचार-गोष्ठियों की एक श्रृंखला।
- कोलकाता, लखनऊ, भोपाल और पिंपरी चिंचवाड़ में नाबार्ड के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कानूनी संपरीक्षकों के लिए हीरक जयंती राष्ट्रीय विचार-गोष्ठियों की श्रृंखला।
- 15 फरवरी, 2009 को भिलाई में वृत्तिक उत्कृष्टता और समृद्धि विषय पर हीरक जयंती विचारगोष्ठी।
- 26 अप्रैल, 2009 को इलाहाबाद में वृत्तिक उत्कृष्टता और समृद्धि विषय पर हीरक जयंती विचारगोष्ठी।
- 1 और 2 अप्रैल, 2009 को सीएंडएजी कार्यालय में वरिष्ठ सीएंडएजी पदधारियों के लिए आईएफआरएस के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम।
- सीएंडएजी पदधारियों के लिए नए/पुनरीक्षित लेखांकन मानकों/संपरीक्षा और आश्वासन मानकों पर एक चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (13-16 अप्रैल, 2009) के लिए सीएजी कार्यालय को संकाय समर्थन उपलब्ध कराया गया था।
- दिल्ली, एर्नाकुलम, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और जयपुर में सीएंडएजी कार्यालय के साथ संयुक्त रूप से पीएसयू के कानूनी संपरीक्षकों के लिए कार्यशालाओं की एक श्रृंखला।
- 29-30 मई, 2009 को कोयम्बटूर में वृत्तिक विकास और समृद्धि विषय पर एक अखिल भारतीय सम्मेलन।

5.10 पियर रिव्यू बोर्ड

आईसीएआई द्वारा जो पियर रिव्यू के क्षेत्र में अग्रणी है, देश में प्रारंभ किया गया पियर रिव्यू तंत्र संस्थान का एक सफल प्रयास रहा है, जिसने काफी हद तक उन उद्देश्यों को पूरा किया है जिनके लिए उनकी स्थापना की थी।

वर्ष 2002 में आईसीएआई की परिषद् द्वारा गठित पियर रिव्यू बोर्ड, जिसमें कारपोरेट कार्य मंत्रालय, सीएंडएजी, सेबी, सीआईआई और फिक्की जैसे निकायों से प्रतिनिधि और परिषद् के सदस्य सम्मिलित हैं, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से अग्रसर हो रहा है कि पुनर्विलोकनों को बेहतर ग्लोबल प्रेक्टिस के अनुसार किया जाता है।

इस क्रम में कि पुनर्विलोकनकर्ताओं द्वारा सुसंगतता और एकरूपता के साथ पुनर्विलोकन किया जाता है, बोर्ड पुनर्विलोकनकर्ताओं को प्रेक्टिस यूनिटों को पुनर्विलोकन के लिए उनको समनुदेशित करने से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रशिक्षण माड्यूल जो “ट्रेनिंग माड्यूल फॉर पियर रिव्यूअर्स” नामक पुस्तक के रूप में इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है, पुनर्विलोकनकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है तथा प्रशिक्षण सुसाध्यक के लिए मार्गदर्शन भी देता है कि पुनर्विलोकनकर्ताओं का प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है।

पियर रिव्यू प्रक्रिया का उद्देश्य तीन चरणों में क्रमबद्ध रीति से चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की सभी फर्मों को सम्मिलित करना है। पीयू का चयन विशेष रूप से विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से रेन्डम आधार पर किया जाता है। चरण 1 में सम्मिलित पी.यू. का 5 क्रमबद्ध रीति से चयन किया गया है तथा जो अभी प्रक्रम 2 के अंतर्गत सम्मिलित है, उनका 5 चरणों के लिए चयन किया गया है। प्रक्रम 3 के अधीन पीयू का चयन उसके फेज 1 के अधीन भी किया गया है। चयनित पीयू के ब्यौरे, पूरा किया गया पुनर्विलोकन तथा पियर रिव्यू प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिए गए हैं।

आईसीएआई की परिषद् द्वारा सेबी की बह सिफारिशें स्वीकार करने का विनिश्चय लिए जाने के पश्चात् कि 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों के लिए सूचीबद्ध कंपनियों के संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए संपरीक्षा फर्मों/व्यवसायी यूनिटों के पास संस्थान के पियर रिव्यू बोर्ड से जारी एक प्रमाणपत्र होना चाहिए, बोर्ड ने यह विनिश्चय

किया था कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों की संपरीक्षा फर्मों को त्वरित आधार पर पियर रिव्यू के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाएगा। तदनुसार पियर रिव्यू कार्य के लिए 1240 फर्मों का चयन किया गया था और उन्हें पियर रिव्यू के संबंध में संसूचित किया गया था।

5.10.1 बोर्ड की पहलें

- बोर्ड ने पुनर्विलोककों के प्रशिक्षण के लिए एक ई-लर्निंग मोड्यूल तैयार करने का विनिश्चय किया है जो उन्हें अपनी सुविधानुसार इन मोड्यूलों का अध्ययन करने में समर्थ बनाएगा। सदस्य को या तो बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने या फिर ई-लर्निंग मोड्यूलों के माध्यम से अध्ययन करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। तत्पश्चात् सदस्यों के फायदे के लिए एक स्वनिर्धारण परीक्षा भी विकसित की जाएगी।
- बोर्ड दस्तावेजीकरण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए संपरीक्षा दस्तावेजीकरण के लिए एक मेन्यू चालित सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। यह व्यवसायी यूनिटों द्वारा यह सुनिश्चित करना सुकर बनाएगा कि उनके पास अपने ग्राहकों को दी जाने वाली अधिप्रमाणन सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।
- बोर्ड ने ऐसे पियर पुनर्विलोककों के लिए, जिन्हें पहले ही उनके लेखांकन और संपरीक्षा मानकों संबंधी ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के उद्देश्य से प्रशिक्षित किया गया है, पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।
- बोर्ड ने अपने प्रकाशनों के पुनरीक्षण को भी अंतिम रूप दे दिया है। बोर्ड के प्रकाशनों, अर्थात् पियर रिव्यू मैनुअल, ट्रेनिंग मोड्यूल फॉर पियर रिव्यूर्स और एफएक्यू को शीघ्र ही मुद्रित किया जाएगा।

5.11 उद्योग में सदस्यों के लिए समिति

5.11.1 अवलोकन

उद्योग में लगे सदस्यों के लिए समिति आईसीएआई तथा विभिन्न हैसियत से उद्योगों में कार्य कर रहे चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के बीच निकट संपर्क बढ़ाने में लगी हुई है जिससे कि सरकारी संगठनों तथा अभिकरणों के साथ गहन तथा व्यापक नातेदारी के विकास के माध्यम से ज्ञान, विशेषज्ञता, कौशल तथा व्यक्तिगत कैरियर विकास में सहायता दी जा सके ताकि उन्हें नियोजन के अधिकतम अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को साथ-साथ पूरा करते समय व्यापार, वाणिज्य, उद्योग जगत तथा शासन को हर संभव अधिकतम अपावरण प्रदान किया जा सके।

समिति, उद्योग में अवसरों का पता लगाने में संस्थान के सदस्यों को सहायता प्रदान करती है। इस संबंध में, समिति संस्थान के सदस्यों तथा छात्रों के निम्नलिखित तीन प्रवर्गों के संबंध में सेवाएं प्रदान करने में लगी है :

- (i) कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से नए अर्हित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट।
- (ii) अनुभवी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट - जो वर्तमान में उद्योग में सेवा कर रहे हैं।
- (iii) अर्धअर्हित लेखांकन वृत्तिक।

सभी उपरोक्त सेवाएं प्लेसमेंट पोर्टल www.cmii.icaai.org के माध्यम से प्रशासित की जा रही हैं। आईसीएआई प्लेसमेंट पोर्टल वृत्तिकों (अर्हित और साथ ही अर्धअर्हित, दोनों को) को अंतरराष्ट्रीय बेहतर पद्धति ओरिएंटेड वित्त तथा लेखांकन संस्कृति और भारतीय उद्योग के लिए क्षमता निर्माण के उद्देश्यों के साथ विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करता है।

5.11.2 कैम्पस साक्षात्कार

समिति ने मई, 2008 और नवम्बर, 2008 में आयोजित सीए फाइनल परीक्षा में अर्हित सदस्यों के नियोजन के लिए वर्ष 2008-09 और 2009-10 (2 जुलाई, 2009 तक) कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

वर्ष 2008-2009 के दौरान

अगस्त-सितम्बर, 2008 के दौरान आयोजित कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का कार्यपालक संक्षिप्त विवरण :

- कुल मिलाकर 3817 अभ्यर्थियों ने इस अवसर का लाभ उठाया था।
- इन वृत्तिकों के बायोडाटा को केन्द्रवार वर्गीकृत किया गया था और उन्हें 16 केन्द्रों में 77 संगठनों के 149 साक्षात्कार बोर्डों के समक्ष उपसंजात होने का अवसर दिया गया था।
- कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय पद के लिए 21 लाख रुपए प्रति वर्ष के उच्चतम वेतन का प्रस्ताव किया गया था।
- कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में घरेलू पद के लिए 10.61 लाख रुपए प्रति वर्ष के उच्चतम वेतन का प्रस्ताव किया गया था।
- कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को लगभग 1000 नौकरियों का प्रस्ताव दिया गया था।

- नए अर्हताप्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंटों को औसतन 6.11 लाख रुपए प्रति वर्ष के वेतन का प्रस्ताव किया गया था ।
- कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के दौरान 70 कंपनियों ने भाग लिया था ।
- कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के दौरान 149 साक्षात्कार पैनलों ने भाग लिया था ।
- सभी क्षेत्रों में से सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर ने सर्वाधिक संख्या में भर्ती की थी (16.16 %), किन्तु खनन (8.42 %), बैंककारी क्षेत्र (7.52 %), वित्तीय सेवाएं, (6.40%), तेल और गैस परिरक्षण (5.0%), जैसे क्षेत्र प्रमुख भर्तीकर्ता थे ।
- इस कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में 19 नए भर्तीकर्ता अस्तित्वों ने पहली बार भाग लिया था ।
- अभ्यर्थियों को उनके साक्षात्कारों के लिए उचित रूप से तैयारी करने में समर्थ बनाने के लिए समिति ने 'त्वरित पुनर्विलोकन प्रश्न' और 'साक्षात्कार बोर्ड का सम्मान कैसे करें' नामक प्रकाशन निकाले थे ।
- समिति ने अभ्यर्थियों के सॉफ्ट कौशल को तीक्ष्ण करने और उन्हें तकनीकी पक्ष में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अनुकूलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया था ।

विशेष कैम्पस नियोजन कार्यक्रम, जुलाई, 2008

ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने जुलाई, 2008 में एफआईएफएम, फरीदाबाद से वृत्तिक कौशल विकास संबंधी त्रैमासिक आवासीय कार्यक्रम पूरा किया था, विशेष कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ।

- इसमें 7 संगठनों ने भाग लिया था और 21 नौकरियों का प्रस्ताव किया गया था ।
- कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय पद के लिए 24 हजार अमरीकी डालर प्रति वर्ष के उच्चतम वेतन का प्रस्ताव किया गया था ।
- घरेलू पदों के लिए 4 अभ्यर्थियों को 11 लाख रुपए प्रति वर्ष का प्रस्ताव किया गया था ।

विशेष कैम्पस नियोजन कार्यक्रम, अक्टूबर, 2008

ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने अक्टूबर, 2008 में एफआईएफएम, फरीदाबाद से वृत्तिक कौशल विकास संबंधी त्रैमासिक आवासीय कार्यक्रम पूरा किया था, विशेष कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ।

- इसमें 5 संगठनों ने भाग लिया था और 14 नौकरियों का प्रस्ताव किया गया था ।
- कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय पद के लिए 24 हजार अमरीकी डालर प्रति वर्ष के उच्चतम वेतन का प्रस्ताव किया गया था ।
- घरेलू पदों के लिए 2 अभ्यर्थियों को 6.5 लाख रुपए प्रति वर्ष का प्रस्ताव किया गया था ।

वर्ष 2009-2010 (2 जुलाई, 2009 तक) के दौरान

मार्च-अप्रैल, 2009 के दौरान आयोजित कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का कार्यपालक संक्षिप्त विवरण :

- कुल मिलाकर 3842 अभ्यर्थियों ने इस अवसर का लाभ उठाया था ।
- इन वृत्तिकों के बायोडाटा को केन्द्रवार वर्गीकृत किया गया था और उन्हें 16 केन्द्रों में 54 संगठनों के 95 साक्षात्कार बोर्डों के समक्ष उपसंजात होने का अवसर दिया गया था ।
- कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय पद के लिए 23 लाख रुपए प्रति वर्ष के उच्चतम वेतन का प्रस्ताव किया गया था ।
- कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में घरेलू पद के लिए 9 लाख रुपए प्रति वर्ष के उच्चतम वेतन का प्रस्ताव किया गया था ।
- कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को लगभग 508 नौकरियों का प्रस्ताव दिया गया था ।
- अभ्यर्थियों को औसतन 6.06 लाख रुपए प्रति वर्ष के वेतन का प्रस्ताव किया गया था ।
- कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के दौरान 54 कंपनियों ने भाग लिया था ।
- कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के दौरान 94 साक्षात्कार पैनलों ने भाग लिया था ।
- सभी क्षेत्रों में से वित्तीय सेवाओं ने सर्वाधिक संख्या में भर्ती की थी (29.62%), किन्तु बैंककारी क्षेत्र (20.00%), तेल और गैस परिरक्षण (11.90%), इंजीनियरी उपापन और संनिर्माण (8.10%) जैसे क्षेत्र प्रमुख भर्तीकर्ता थे ।
- अभ्यर्थियों को उनके साक्षात्कारों के लिए उचित रूप से तैयारी करने में समर्थ बनाने के लिए समिति ने 'हैंडबुक फॉर न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड एकाउंटेंट्स' नामक प्रकाशन के दो संस्करण निकाले थे ।

- समिति ने अभ्यर्थियों के सॉफ्ट कौशल को तीक्ष्ण करने और उन्हें तकनीकी पक्ष में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अनुकूलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया था।

विशेष कैम्पस नियोजन कार्यक्रम, मई, 2009

ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने मई, 2009 में एफआईएफएम, फरीदाबाद और साथ ही श्री एल.एन. भित्तल सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर से वृत्तिक कौशल विकास संबंधी त्रैमासिक आवासीय कार्यक्रम पूरा किया था, विशेष कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

- इसमें 7 संगठनों ने भाग लिया था और 28 नौकरियों का प्रस्ताव किया गया था।

- 4 अभ्यर्थियों को 5.75 लाख रुपए प्रति वर्ष के अधिकतम वेतन का प्रस्ताव किया गया था।

एसएमई और एसएमबी के लिए अनन्य रूप से तैयार किया गया कैम्पस नियोजन कार्यक्रम

नवम्बर, 2008 और मई, 2009 की परीक्षाओं में अर्हित नए चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) तथा मध्यम आकार की चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों के लिए अनन्य रूप से तैयार किए गए एक कैम्पस नियोजन कार्यक्रम को देशभर के 13 केन्द्रों में जून मास के दौरान आयोजित किया गया था जिससे कि सीए के प्रत्येक संभव निरोजक तक कैम्पस नियोजन कार्यक्रम की पहुंच बनाई जा सके। कुल मिलाकर 69 संगठनों ने 133 अभ्यर्थियों को नौकरी संबंधी प्रस्ताव दिए थे।

उद्योग में कार्बरेट सभी सदस्यों के लिए प्रश्नोत्तर

संस्थान से उद्योग में लगे सदस्यों की अपेक्षाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने तथा उन्हें मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सीएमआईआई ने एक प्रश्नोत्तर तैयार किया है जो <http://www.cmii.icaai.org/imgs/question-email1.pdf> लिंक से प्लेसमेंट पोर्टल पर उपलब्ध है।

आयोजित किए गए कार्यक्रम / संगोष्ठियां / सम्मेलन :

समिति ने 2008-09 और 2009-10 (2 जुलाई, 2009 तक) उद्योग में लगे सदस्यों के फायदे के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन किया :

वर्ष 2008-09 के दौरान :

सीएफओ बैठक

क्रम सं.	स्थान	तारीख
1	मुंबई	22 अप्रैल, 2008
2	चेन्नई	28 दिसम्बर, 2008

निगम एकाउंटेंटों की बैठक

क्रम सं.	स्थान	तारीख
1.	मिलाई	22 जून, 2008
2.	कोयम्बटूर	18 अक्टूबर, 2008
3.	एरनाकुलम	31 अक्टूबर, 2008
4.	हैदराबाद	14 नवम्बर, 2008
5.	पुणे	26 दिसम्बर, 2008
6.	मुंबई	29 दिसम्बर, 2008
7.	बैंगलोर	9 जनवरी, 2009

मानव संसाधन बैठकें

क्रम सं.	स्थान	तारीख
1.	मुंबई	11 जुलाई, 2008
2.	नई दिल्ली	25 जुलाई, 2008
3.	मुंबई	24 दिसम्बर, 2008

उद्योग विनिर्दिष्ट कार्यक्रम

क्रम सं.	विषय	तारीख और स्थान
1.	आईएफआरएस पर संगोष्ठी	मुंबई में 5 से 7 जून, 2008
2.	निजी साम्या संबंधी कार्यशाला	मुंबई में 1 और 2 अगस्त, 2008
3.	हीरक जयंती आवासीय पुनश्चर्चा कार्यशाला	अलेप्पी में 22 से 24 अगस्त, 2008
4.	आईएफआरएस पर कार्यशाला	बड़ौदा में 29 और 30 अगस्त, 2008
5.	ज्ञान और अनुष्ण उत्कृष्टता में समृद्धि पर संगोष्ठी	नई दिल्ली में 17 अक्टूबर, 2008
6.	उद्योग में लगे सदस्यों के लिए सीपीई संगोष्ठी	हैदराबाद में 15 नवम्बर, 2008
7.	'परिवर्तन की ब्यार - वृत्ति को चुनौतियाँ', पर अखिल भारतीय सम्मेलन	कोलकाता में 16 से 17 दिसम्बर, 2008
8.	उद्योग में लगे सदस्यों का हीरक जयंती सम्मेलन	पुणे में 27 दिसम्बर, 2008
9.	भू-संपदा और संनिर्माण उद्योग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	चेन्नई में 28 दिसम्बर, 2008
10.	आईएफआरएस बनाम जीएएपी पर संगोष्ठी	मुंबई में 23 जनवरी, 2009
11.	प्रत्यक्ष कर संबंधी गोष्ठी	मुंबई में 24 जनवरी, 2009
12.	वित्तीय संसाधन जुटाने संबंधी संगोष्ठी	मुंबई में 25 जनवरी, 2009

निगम मंच

आईसीएआई के कारपोरेट मंच (23 से 25 जनवरी, 2009) का आयोजन मुंबई में किया गया था जिसमें निम्नलिखित तीन आयोजन किए गए थे :

- करियर एसेंट (23 से 24 जनवरी, 2009) - नई नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराके, एक या अधिक वर्षों का उद्योग संबंधी अनुभव रखने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए करियर विकास की संभवनाएं उपलब्ध कराने वाला आयोजन ।
- 3 कंपनियों अर्थात्, नेसले इंडिया लिमिटेड, आईबीएम वक्ष और ब्राफ शिपिंग एलएलसी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था और विभिन्न सदस्यों को नौकरियों के प्रस्ताव दिए थे ।
- निगम सभा (23 से 25 जनवरी, 2009)- समकालीन विषयों जैसे कि आईएफआरएस, प्रत्यक्ष कर और वित्तीय संसाधन जुटाना पर 3 (भिन्न-भिन्न) राष्ट्रीय सभाओं को सदस्यों के ज्ञान में वृद्धि करने और उनके कौशल को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था ।

इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रीकृत प्रतिनिधियों की संख्या निम्नलिखित थी :

आईएफआरएस बनाम भारतीय जीएएपी	375
प्रत्यक्ष कर	210
वित्तीय संसाधन जुटाना	165

- आईसीएआई पुरस्कार, 2008 (25 जनवरी, 2009) - ये पुरस्कार उद्योग में लगे ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंटों को जो उद्योग में उदाहरणात्मक आदर्श प्रस्तुत करते हुए अपनी वृत्तिक सेवाएं प्रस्तुत करने में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हैं और जिन्होंने समवहनीय आधार पर अपनी कंपनियों के पणधारियों के लिए प्रतिभा का सृजन किया है, मान्यता प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए थे । पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रस्तुत करने वाली ज्युरी में देश की विख्यात कंपनियों और निगमों के सीएमडी, अध्यक्ष, प्रधान, सीएफओ आदि की हैसियत के लगभग 2 दर्जन गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित थे ।
- ज्युरी की बैठक 17 जनवरी, 2009 को मुंबई में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता माननीय श्री सुरेश प्रभु, संघ के भूतपूर्व विद्युत, भारी उद्योग और उद्यम मंत्री तथा संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा की गई थी । आईसीएआई पुरस्कार, 2008 का आयोजन 25 जनवरी, 2009 को गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई में किया गया था, जिसका उद्घाटन माननीय श्री राम नाइक, संघ के भूतपूर्व पेट्रोलियम और तेल तथा प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा किया गया था । इस समारोह में निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए थे :

क्रम सं.	प्रबर्ग	पुरस्कार विजेता का नाम	पद	संगठन
1	सीए बिजनेस एचिवर - निगम	सीए अखिल गुप्ता	उप गुप सीईओ और प्रबंध	भारती ग्रुप

			निदेशक	
2	सीए बिजनेस एचिवर - वित्तीय सेवाएं	सीए मोतीलाल ओसवाल	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लि.
3	सीए बिजनेस एचिवर - एसएमई	सीए के. उल्लास कामथ	उप प्रबंध निदेशक	ज्योति लेबोरेट्रीज लिमिटेड
4	सीएफओ - विनिर्माण	सीए आदेश गुप्ता	पूर्णकालिक निदेशक और सीएफओ	आदित्य बिड़ला नूवो लिमिटेड
5	सीएफओ - वित्तीय क्षेत्र	सीए केकी मिस्त्री	उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	एचडीएफसी लि.
6	सीएफओ - पब्लिक सेक्टर	सीए ए.के. सिंघल	निदेशक (वित्त)	एनटीपीसी लि.
7	सीएफओ (सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया, संचार और मनोरंजन)	सीए वी. बालाकृष्णन	सीएफओ	इंफोसिस टेक्नोलॉजिस लि.
8	सीएफओ - महिला	सीए इरावती दानी	निदेशक (वित्त)	वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि.
9	सीए प्रोफेशनल एचिवर - वित्तीय क्षेत्र	सीए भारत बांका	प्रबंध निदेशक और सीईओ	आदित्य बिड़ला कैपिटल एडवाइजर्स, साथ ही अध्यक्ष और प्रधान, ग्रुप कारपोरेट फाइनेंस, आदित्य बिड़ला ग्रुप

वर्ष 2009-10 के दौरान

- 1 जून, 2009 को फरीदाबाद में वृत्तिकों के लिए व्यक्तित्व विकास और लक्ष्य साधना संबंधी संगोष्ठी।
- 5 जून, 2009 को होटल सिड्ढेला, सेवोक रोड, दूसरा मील, सिलीगुड़ी में उद्योग में कार्यरत सदस्य के लिए एक दिवसीय सीपीई सभा।
- 9 जून, 2009 को लुधियाना में हीरक जयंती संगोष्ठी।

समिति के प्रकाशन

वर्ष 2008-09 के दौरान

उद्योग में कार्यरत सदस्यों के फायदे के लिए निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए गए हैं। इन प्रकाशनों के अनुकूलन कार्यक्रम के दौरान नए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों को निःशुल्क रूप से वितरित किया गया था :

- साक्षात्कार बोर्ड का सामना कैसे करें
- त्वरित पुनर्विलोकन प्रश्न

वर्ष 2009-10 के दौरान

समिति ने नए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों के फायदे के लिए 'नए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए हैंडबुक' पुस्तक के 2 संस्करण निकाले हैं।

समिति द्वारा प्रकाशित की गई प्रकाशन - परियोजनाएं

- समिति अपने ई-न्यूज़लेटर 'कारपोरेट कम्यूनिकी' का प्रकाशन पुनः प्रारंभ करने के लिए कार्यवाही कर रही है।
- समिति नीचे दिए गए व्योसे के अनुसार परियोजनाओं का प्रकाशन आरंभ करने के लिए कार्यवाही कर रही है :

क्रम सं.	लेखक का नाम	प्रकाशन का विषय
1	सीए सज्जया के. अग्रवाल	समामेलन और अर्जन : अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
2	सीए रवि कुमार यादव	सीमाशुल्क मूल्यांकन
3	सीए मितेश साहू	मूल्यवर्धित कारबार नियंत्रण - जोखिम प्रबंध का सही तरीका

समिति निम्नलिखित नीतियों पर कार्य कर रही है :

- उद्योग में लगे सदस्यों के लिए सीपीई अध्ययन सर्कल विकसित करना ।
- भर्तीकर्ता अस्तित्वों के लिए आधुनिकतम फिल्टरिंग प्रसुविधाओं और ऑन लाइन संदाय सुविधा वाले संपूर्ण जॉब पोर्टल को तैयार करना ।
- युवा चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए राष्ट्रीय युवा सीए सेवारत प्रतियोगिता ।
- उद्योग विनिर्दिष्ट कार्यक्रम ।
- सीएफओ की बैठकें ।
- निगम एकाउंटेंट बैठकें ।
- आईसीएआई निगम मंच - वर्ष 2009 के लिए पुरस्कार समारोह ।
- उद्योग में लगे सदस्यों के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन दौरे ।
- सदस्यों के बीच भाईचारे का संवर्धन और प्रसार करने के लिए खेलकूद, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन ।

5.12 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति

5.12.1 पर्यावलोकन

वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी, पूर्व में कारबार समर्थकर्ता की अल्प भूमिका से परिवर्तित होकर चयनित कारबार प्रचालक के रूप में उभरी है । सूचना प्रौद्योगिकी ने आधुनिक कारबार संव्यवहार में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं क्योंकि उद्यम और सरकारें अपने प्रचालनों के बेहतर प्रबंध और अपने ग्राहकों/नागरिकों को ई-सेवाओं/ई-शासन पहलों - ई-बैंकिंग/ई-सेवा/ई-संदाय/ई-शासन/ई-आरक्षण/ई-उपापन/ई-निविदाएं जैसी मूल्यवर्धित सेवाओं का प्रस्ताव करने के लिए बड़ी मात्रा में सूचना प्रौद्योगिकी को अपना रही हैं ।

नए डब्ल्यूटीओ को देखते हुए और विश्व के एक वैश्विक गांव में परिवर्तन के साथ भारतीय कारबार परिदृश्य में अधिकाधिक आईटी समर्थ सेवाएं (आईटीईएस) सम्मिलित हो रही हैं, जैसे कि ईआरपी, कारबार प्रक्रिया बाहरी स्रोत (बी.पी.ओ)/सूचना प्रक्रिया बाहरी स्रोत (केपीओ) ।

संस्थान की परिषद् ने, नियमित रूप से सूचना प्रौद्योगिकी चुनौतियों का मूल्यांकन करने और उचित शिक्षा तथा विकासशील कार्यक्रमों जैसे कि अर्हतापश्च पाठ्यक्रमों/सम्मेलनों/ संगोष्ठियों/ व्यवहारिक कार्यशालाओं के माध्यम से उन्हें वृत्ति के लिए लाभप्रद वृत्तिक अवसरों के रूप में संपरिवर्तन करने और साथ ही अध्ययन गाईडों, संसाधनों, ई-लर्निंग/ कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण पद्धतियों को तैयार करने के लिए वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति का गठन किया था ।

समिति की प्रथम पहल, सीए को सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हतापश्च पाठ्यक्रम (पीक्यूसी) के माध्यम से आईएस संपरीक्षा/प्रणाली और प्रक्रिया संपरीक्षा आश्वासन (एसपीए) मूल्यवर्धित सेवाएं प्रस्तावित करने के लिए सुसज्जित करना था, जिनके लिए दिनोंदिन मांग बढ़ती जा रही है । सीए अधिकाधिक रूप से इन सेवाओं का प्रस्ताव अपने ग्राहकों, विशेषकर बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ स्टॉक ब्रोकरों आदि को कर रहे हैं, जहां यह कानूनी अपेक्षा है ।

मांग विशेषकर आईएस सदस्यों की मांग पर विचार करते हुए समिति ने संकर्मों की दक्षता और प्रभावकारिता में वृद्धि करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी व्यवहारिक कार्यशालाओं की प्रस्थापना करना प्रारंभ कर दिया है, जिससे कि सीए एक उपकरण के रूप में आईटी का उपयोग करके अपने ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवाओं का प्रस्ताव कर सकें । समिति कंप्यूटर से सहायता प्राप्त संपरीक्षा तकनीकों/साधारण संपरीक्षा सॉफ्टवेयर विषय पर त्वरित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सीएटी विषय पर सीपीई पाठ्यक्रम की प्रस्थापना भी करती है और साथ ही उसने सीएटी संसाधन सीडी भी जारी की है ।

समिति ने वृत्ति के विकास के लिए अग्रिम क्षेत्र के रूप में ईआरपी परामर्श की पहचान की है और इस क्षेत्र में उभरते अधिकाधिक वृत्तिक अवसरों को ध्यान में रखते हुए उसने एसएपी एफए और एसएपी एमए और माइक्रोसॉफ्ट डाइनेमिक्स एनएवी संबंधित पाठ्यक्रमों की प्रस्थापना करना आरंभ कर दिया है । समिति ने 12 जुलाई, 2008 को टैली ग्राहकों को दूरस्थ संपरीक्षा से संबंधित टैली कारबार आश्वासन व्यवहार (बीएपी) संबंधी कार्यशाला भी प्रारंभ कर दी है ।

समिति ने संस्थान की सतत् वृत्तिक शिक्षा समिति के साथ “ बैंक शाखा संपरीक्षा -एक पर्यावलोकन” विषय पर ई-लर्निंग/कंप्यूटर आधारित लर्निंग पद्धति प्रारंभ की है और “सीएटी/जीएस का उपयोग करना - एक प्रस्तावना” और “ एमएनएक्सएल का सीएटी/जीएस के उपकरण के रूप में उपयोग करना” विषय पर एक मोड्यूल जारी किया है । समिति ने सेवा कर और आईएफआरएस संबंधी ई-लर्निंग पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए थे । समिति सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीए की सक्षमताओं को विकसित करने और उनके लिए वृत्तिक अवसर तैयार करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है ।

समिति ने संस्थान की सतत् वृत्तिक शिक्षा समिति के सहयोग से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वृत्ति सूचना प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है, संस्थान की पहल के भाग रूप में वरिष्ठ सदस्यों के लिए कंप्यूटर मूल्यांकन पाठ्यक्रम भी आरंभ किया है । इस

पाठ्यक्रम के बैचों का आयोजन, आईसीएआई के 100 सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों में स्थापित आईटीटी केन्द्रों में किया जाता है।

समिति ने “सूचना प्रौद्योगिकी के समय में न्यायिक लेखांकन और कपट की पहचान करने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम” प्रारंभ किया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य कपटों की पहचान में लेखांकन, संपरीक्षा सिद्धांतों का उपयोग करके निगम/कारबार कपटों का पता लगाने, पारिणामिक हानि का लेखा-जोखा करने, मुकदमेंबाजी के लिए समर्थन/ बाहरी काउंसिलर उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित अन्वेषणात्मक कौशल विकसित करना है।

इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का पहला बैच 17 जनवरी, 2009 से मुंबई में प्रारंभ हुआ था। 25 अभ्यर्थियों ने इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था।

5.12.2 सूचना प्रौद्योगिकी समिति की पहलें

परियोजना परिवर्तन (आईसीएआई में ई-शासन का संवर्धन)

यह अध्यक्ष (आईसीएआई) सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल का स्वप्न है और इसको आदर्श रूप से इन्फोसिस टेक्नोलॉजिस की सहायता से साकार किया जा रहा है। समिति ने परियोजना ‘परिवर्तन’ की परिकल्पना इस विचार से की है कि यह आईसीएआई को कार्यकरण को एक नए गुणवान रास्ते पर ले जाएगा जो देश के विद्यमान चार्टर्ड एकाउंटेंट और चार्टर्ड एकाउंटेंट बनने के इच्छुक व्यक्तियों को एक सीए परिवार के रूप में एक साथ लाएगा। इसका उद्देश्य एक ऐसी एकल एकीकृत प्रणाली का सृजन करना है जो चार्टर्ड एकाउंटेंटों के भौगोलिक अवस्थानों पर ध्यान न देते हुए इन्टरनेट के माध्यम से उनके पूरे समुदाय की एकसाथ सेवा करे। परियोजना परिवर्तन का प्रारंभ 6 मई, 2009 को संस्थान के प्रधान कार्यालय में किया गया था, जहां अस्थाई समितियों के विभागाध्यक्षों/सचिवों ने इन्फोसिस के दल के साथ परस्पर क्रिया की थी। इस परियोजना के भागरूप में सभी 5 प्रादेशिक मुख्यालयों और साथ ही बंगलोर और जयपुर में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा जहां सदस्यों और छात्रों को इनमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

आईटी निदेशालय का सृजन

वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति ने सदस्यों और छात्रों से संबंधित विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए समन्वयन को समर्थ बनाने तथा संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए सभी आईटी क्रियाकलापों को एक छत्री के नीचे लाने के लिए एक संपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) निदेशालय की आवश्यकता पर विचार किया था। समिति को यह महसूस हुआ कि आईटी निदेशालय वीआईपी, ऑन लाइन परीक्षा और परिणामों संबंधी कार्यवाहियों, वेबसाइटों और पोर्टलों, सदस्यों और छात्रों के लिए ई-लर्निंग, आईटी शिक्षा और प्रशिक्षण, जिनके अंतर्गत अर्हता पश्च पाठ्यक्रम भी हैं जैसी सभी आईटी पहलों के संबंध में एक समान पद्धति बनाने के लिए प्रक्रियाओं का समन्वयन, मानकीकरण, अनुकूलन करेगा और उन्हें त्वरित बनाएगा। समिति ने कार्यपालक समिति (ईसी) को आईटी निदेशालय के सृजन की सिफारिश की थी और ईसी ने 6 अप्रैल, 2009 को आयोजित अपनी बैठक में आईटी निदेशालय के सृजन को अनुमोदित कर दिया था और यह विनिश्चय किया था कि इसे अप्रैल, 2009 से कार्यरत बनाया जाए।

17 अप्रैल, 2009 को वैश्विक आर्थिक मंदी - सीए की बदलती भूमिका विषय पर प्रथम राष्ट्रीय आईसीएआई वेबकास्ट

समिति ने शुक्रवार, 17 अप्रैल, 2009 को वैश्विक आर्थिक मंदी - सीए की बदलती भूमिका विषय पर ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रीय आईसीएआई वेबकास्ट का आयोजन किया था। ऑन लाइन शिक्षा का संवर्धन करने और कम-से-कम समय में अधिकाधिक शिक्षुओं तक पहुंच बनाने के लिए, सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल, संस्थान के अध्यक्ष ने वेबकास्टिंग आयोजन का उद्घाटन किया था। 4000 से अधिक सदस्यों ने इस वेबकास्ट के लिए स्वयं को रजिस्टर किया है, जिनमें से अनेक सदस्यों ने बहु अवसरों पर इसे देखा है। यह संस्थान के इतिहास का एक अन्य मील का पत्थर है। आईसीएआई ऐसा करने वाला पहला वृत्तिक संस्थान है और अब अनेक अन्य संस्थान उसका अनुपालन करेंगे। वेब का उपयोग करते हुए मांग पर पठन सामग्री की अवधारणा का भविष्य सुनहरी है और आईसीएआई शीघ्र ही ऐसे अनेक और आयोजन करेगा। आईसीएआई वृत्ति से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने सदस्यों के समाधान करने के लिए उद्योग के अग्रणियों को आमंत्रित करेगा। ऐसे आयोजन न केवल पारंपरिक स्थल प्रशिक्षण से सहबद्ध यात्रा समय और लागतों की बचत करेंगे अपितु यह शिक्षुओं के लिए एक अद्वितीय अनुभव भी होगा। इस प्रकार असंभव को संभव बना दिया गया है। इससे विदेशों में निवास करने वाले आईसीएआई के अनेक सदस्यों के लिए एक ऐसा मंच तैयार हुआ है जिससे वे संस्थान की ऐसी संगोष्ठियों को लाइव देख सकेंगे जिनमें वे भाग लेना चाहते हैं किन्तु अपने भौगोलिक अवस्थान के कारण ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं।

समिति के नए प्रकाशन

समिति ने अधिकाधिक सदस्यों तक पहुंच बनाने के लिए दो ब्राशर - आईटी पाठ्यक्रम और आईटी प्रकाशन जारी किए हैं। समिति द्वारा आईएसए पाठ्यक्रम के विपणन के लिए सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हता पश्च पाठ्यक्रम पर एक सूचना पुस्तिका का प्रकाशन भी किया गया है।

समिति ने सदस्यों के फायदे के लिए और इस क्षेत्र में वृत्ति के विकास के लिए तीन नए प्रकाशन भी जारी किए हैं। (क) “टेक्निकल गाइड ऑन सिस्टम्स ऑडिट ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स” (ख) “टेक्निकल गाइड ऑन इनफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट” और (ग) “डाटा एनालिसिस फॉर ऑडिटर्स - प्रैक्टिकल केस स्टडीज ऑन यूजिंग सीएएटी”।

आईएसए बैठकें

समिति ने क्रमशः 29 दिसम्बर, 2008, 5 जनवरी, 2009 और 29 अप्रैल, 2009 को कोयम्बटूर, बंगलौर और तिरुमति में 3 घंटों की अवधि की आईएसए बैठक का आयोजन किया था। इन आईएसए बैठकों में प्रौद्योगिकी रुझानों और सदस्यों से मत और सुझाव प्राप्त करने के अलावा स्वयं को चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए अंतर्मथन सत्र हेतु आईएसए सदस्य एकत्रित हुए थे। ये बैठकें, इनमें भाग लेने वाले सदस्यों को सीपीई घंटों भी उपलब्ध कराती हैं।

1 से 5 जून, 2009 के दौरान इंफोसिस परिसर, बंगलौर में फिनेकल (कोर बैंककारी प्रणाली) पर संपरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

समिति ने 1 से 5 जून, 2009 के दौरान इंफोसिस टेक्नोलॉजिज, बंगलौर की सहायता से फिनेकल कोर बैंककारी प्रणाली पर संपरीक्षकों के लिए गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य फिनेकल के आधारीक उपयोग पर और इसकी संपरीक्षा और नियंत्रण विशिष्टियों के उपयोग पर त्वरित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।

यह कार्यक्रम विशेष रूप से बैंक शाखा संपरीक्षकों और उनके ऐसे सदस्यों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, जिन्होंने सूचना प्रणाली संपरीक्षा (आईएसए) पर अर्हता पश्च पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त की है।

उद्योग में लगे सदस्यों के लिए आईटी प्रबंध पाठ्यक्रम

समिति ने उद्योग में लगे सदस्यों के लिए आईटी प्रबंध पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की पहल की है, जो उद्योग में लगे सदस्यों को आईटी के क्षेत्र में उचित रूप में सुसज्जित करेगा। आईएसए अर्हता पश्च पाठ्यक्रम व्यवसाय में लगे सदस्यों के लिए है क्योंकि वर्तमान में चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिकाधिक रूप से उद्यमों के आईटी विभागों का प्रबंध कर रहे हैं।

समिति ने 3 जून, 2009 को हुई अपनी बैठक में यह विनिश्चय किया था कि सदस्यों को, निगमों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में उत्तम आईटी शासन व्यवहारों और प्रक्रियाओं को अपनाने में सहयोग करने में समर्थ बनाने के लिए आईटी प्रबंध पाठ्यक्रम का प्रस्ताव किया जाए जो उद्योग में उनके वृत्तिक अवसरों में भी अभिवृद्धि करेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, 2009

समिति इस वर्ष दिल्ली, पुणे, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, एर्नाकुलम और बंगलौर में प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलनों की एक श्रृंखला का आयोजन कर रही है। यह शिखर सम्मेलन सदस्यों को सूचना प्रणाली संपरीक्षा और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में उनके लिए खुले विभिन्न अवसरों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं।

महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पहलें

आईसीएआई और श्रीलंका चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएएसएल) के बीच हस्ताक्षरित परस्पर समझ ज्ञापन श्रीलंका के नागरिकों द्वारा डीआईएसए (आईसीएआई) अर्हता अर्जित करने की सुविधा प्रदान करता है। इस वर्ष के दौरान, समिति ने इस पाठ्यक्रम का संचालन 11 मई, 2009 को श्रीलंका में किया था। समिति के सचिव ने उद्घाटन सत्र के लिए श्रीलंका का दौरा किया था और उन्होंने आईसीएएसएल के दल के साथ व्यापक परामर्श किए थे। आईसीएएसएल के दल ने उक्त परस्पर समझ ज्ञापन के परिधि क्षेत्र का, उसमें समिति द्वारा प्रस्थापित अन्य पाठ्यक्रम, व्यवहारक प्रशिक्षण और कार्यशालाओं को सम्मिलित करने के लिए विस्तारित करने में गहन दिलचस्पी उपदर्शित की थी। उन्होंने आईसीएआई द्वारा उसके छात्रों को प्रस्थापित सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संबंध में भी दिलचस्पी दिखलाई थी। आईसीएआई द्वारा प्रस्थापित लेखांकन तकनीशियन पाठ्यक्रम दोनों संस्थानों के बीच एक अन्य दिलचस्पी का क्षेत्र है।

अर्हता पश्च पाठ्यक्रम को आईसीएआई के सभी 22 विदेशी चैप्टरों में लोकप्रिय बनाया गया है। आईसीएआई के दुबई, आबुधाबी और न्यूयार्क चैप्टरों ने विदेशों में रहने वाले सदस्यों के फायदे के लिए आईएसए पाठ्यक्रमों के संचालन में गहरी दिलचस्पी व्यक्त की है।

आईएसए प्रश्न संग्रह

वर्ष के दौरान समिति ने ऑन लाइन अभ्यास परीक्षा के लिए आईएसए प्रश्न संग्रह में वृद्धि करने का विनिश्चय किया है और उसने प्रश्न संग्रह में नियमित अद्यतन को समर्थ बनाने और सदस्यों को नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सदस्यों को ऑन लाइन अध्ययन सामग्रियों में अनुसंधान किया है। तदनुसार सदस्यों से प्रश्न आमंत्रित करते हुए एक डी.आई.एस.ए. (आईसीएआई) प्रश्न संग्रह विकास गाइड को वेब पर रखा गया है। इस प्रभाव की एक घोषणा दि चार्टर्ड एकाउंटेंट के मई, 2009 अंक में भी सम्मिलित की गई है।

नवीन समिति पोर्टल

समिति ने अपने नए सीआईटी पोर्टल को आरंभ किया है जो अतिरिक्त विशिष्टियों के साथ और अधिक उपयोक्ता मित्र और दक्ष हैं। इसे विजुअल स्टुडियो 2008 में विकसित किया गया है और यह आरएसएस प्रसुविधा से सुसज्जित है, जिसका

उपयोग करके उपयोक्ता इस साइट पर नवीनतम अद्यतन प्राप्त कर सकते हैं ।

नए पोर्टल में आईएस संस्था, साइबर खतरों और पुनर्विलोकन संबंधी ऑन लाइन ई-लर्निंग मोड्यूल सम्मिलित है । सदस्य इस पोर्टल को <http://cit.icaai.org> पर देख सकते हैं ।

सेवा कर ई-लर्निंग मोड्यूल

सेवा कर संबंधी पहला ई-लर्निंग पाठ्यक्रम अत्यधिक सफल रहा है और पिछले चार मास के दौरान 4500 से अधिक सदस्यों ने इस ई-लर्निंग पाठ्यक्रम के लिए स्वयं को रजिस्ट्रीकृत किया है । रजिस्ट्रीकरण पर सदस्य को एक ई-लर्निंग किट उपलब्ध कराई जाती है जिसमें सेवा कर संबंधी एक पुस्तक, लेखक द्वारा वीडियो प्रस्तुतीकरण और एक रीट्रिनिंग संहिता सम्मिलित होती है ।

आईएफआरएस - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर ई-लर्निंग पाठ्यक्रम का शुभारंभ

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति ने 3 से 5 जुलाई, 2009 के दौरान आगरा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में, शुक्रवार, 3 जुलाई, 2009 को अध्यक्ष सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल की उपस्थिति में आईएफआरएस - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर ई-लर्निंग पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया था ।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) भविष्य के लेखांकन मानक हैं । इस समय 110 से अधिक देश इन आईएफआरएस का उपयोग कर रहे हैं । अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) निरंतर यह सुनिश्चित करने के लिए इन मानकों में संशोधन कर रहा है कि वैश्विक लेखांकन मानकों का एक सेट आदर्श सन्निध बन जाए और प्रत्येक व्यक्ति समान लेखांकन भाषा में बातचीत करे ।

एक्सबीआरएल का संवर्धन - वित्तीय रिपोर्टिंग भाषा

संस्थान देश में इस वित्तीय रिपोर्टिंग भाषा के वृहत उपयोग का संवर्धन करने के लिए एक्सबीआरएल संबंधी पहल कर रहा है । आईसीआईआई एक्सबीआरएल अंतरराष्ट्रीय के लिए भारतीय अधिकारिता है । भारत में एक्सबीआरएल का कार्यान्वयन आईसीआईआई के सदस्यों के लिए एक उत्तम वृत्तिक अवसर है । समिति ने वित्तीय विवरणों को एक्सबीआरएल संगत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपकरण विकसित करने का विनिश्चय किया । समिति ने भारत में एक्सबीआरएल का संवर्धन के लिए संगोष्ठियों और सम्मेलनों को आयोजित करने का विनिश्चय किया था ।

ज्ञान संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए ई-कक्षा अध्ययन समूह

इस वर्ष के दौरान समिति ने, सदस्यों के लिए एक ऐसी ई-कक्षा विकसित करने के लिए बंगलोर में ई-कक्षा अध्ययन समूह का गठन किया है, जो आईसीआईआई के सभी ज्ञान संसाधनों जैसे कि प्रकाशन, प्रस्तुतीकरण, संगोष्ठी सामग्रियों आदि तक एक पोर्टल के अधीन ऑन लाइन पहुंच को सुगम बनाएगा । यह समूह आईसीआईआई की विद्यमान ऑन लाइन सुविधाओं का पुनर्विलोकन करेगा और यथासंभव रूप में ई-अंतर्वस्तु को ऑन लाइन उपलब्ध कराने के लिए रणनीति पर विचार-विमर्श करेगा ।

आईएसएसीए अध्ययन समूह

वर्ष के दौरान, आईसीआईआई - आईएसएसीए एमओयू के अधीन इस समय हमें उपलब्ध आईएस संपरीक्षा मानकों, मार्गदर्शनों और प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए सूचना प्रणाली आश्वासन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आईएसए सदस्यों को शिक्षित और तैयार करने के लिए आईएसएसीए अध्ययन समूह का सृजन समिति की एक अन्य महत्वपूर्ण पहल है ।

5.12.3 सूचना प्रणाली संपरीक्षा पर पश्च अर्हता पाठ्यक्रम

सूचना प्रणाली संपरीक्षा (आईएसए) पर पश्च अर्हता पाठ्यक्रम सदस्यों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बना रहा । इस पाठ्यक्रम में देशभर के सदस्यों के लिए विकास और संवर्धन हेतु एक अद्वितीय केन्द्र उपलब्ध कराने की क्षमता है । रिपोर्ट की अवधि के दौरान समिति ने 57 केन्द्रों में आईएसए वृत्तिक प्रशिक्षण के 57 बैचों का आयोजन किया था और लगभग 150 केन्द्रों में आईएसए पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था । निम्नलिखित सारणी में संख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं :

विशिष्टियां	रजिस्ट्रीकरण	ईटीउत्तीर्ण
1 अप्रैल, 2008 को	26,943	19,137
वर्ष के दौरान	1,992	623
31 मार्च, 2009 को	28,935	19,760
1 अप्रैल, 2009 से 20 जुलाई, 2009 के दौरान	178	630
20 जुलाई, 2009 को	29,113	20,390

5.12.4 आईटी समिति द्वारा प्रस्तापित विभिन्न पाठ्यक्रमों के रजिस्ट्रीकरण संबंधी आंकड़े

सीएएटी, एसएपी ईआरपी पाठ्यक्रम, माइक्रोसॉफ्ट एनएवी डायनेमिक्स और न्यायिक लेखांकन तथा आईटी और सीएएटी का उपयोग करके कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में 20 जुलाई, 2009 को रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	20 जुलाई, 2009 को रजिस्ट्रीकरण
1.	सीएएटी	3,197
2.	एसएपी ईआरपी पाठ्यक्रम	302
3.	माइक्रोसॉफ्ट एनएवी डायनेमिक्स	74
4.	एफएएफडी	33

5.12.5 आईटी सम्मेलन, संगोष्ठियां, व्यवहारिक कार्यशालाएं

इस वर्ष समिति ने सदस्यों के फायदे के लिए जून, जुलाई और अगस्त, 2009 के दौरान “प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, 2009” विषय पर नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार आईटी शिखर सम्मेलनों और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला का आयोजन किया है :

क्रम सं.	नगर	विषय	क्षेत्र	तारीख
1	बंगलोर	प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, 2009	दक्षिण	26 - 27 जून, 2009
2	कोलकाता	प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, 2009	पूर्व	18 - 19 जुलाई, 2009
3	एर्नाकुलम	टेक्नोलॉजिकल कार्यशाला, 2009	दक्षिण	18 जुलाई, 2009
4	दिल्ली	प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, 2009	उत्तर	अगस्त, 2009

इनके अतिरिक्त, समिति ने आईसीएआई की डब्ल्यूईआरसी की संबंधित शाखाओं के सहयोग से निम्नलिखित सम्मेलनों का भी आयोजन किया :

क्रम सं.	नगर	विषय	क्षेत्र	तारीख
1	पिंपरी चिंचवाड	हीरक जयंती राष्ट्रीय आईटी सम्मेलन	पश्चिम	20 - 21 जून, 2009
2	बड़ौदा	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय हीरक जयंती अभिसमय	पश्चिम	16 मई, 2009

5.13 आरंभ की गई जनसंपर्क गतिविधियां

वर्ष 2008-09 में, जब आईसीएआई ने अपने हीरक जयंती वर्ष समारोह को प्रारंभ किया, जो घरेलू और वैश्विक, दोनों स्तरों पर वृत्ति के ब्रांड निर्माण के लिए समर्पित थे, जनसंपर्क गतिविधियों में एकाएक तेजी आई। इस ऐतिहासिक वर्ष में, मीडिया के साथ परस्पर क्रियाओं में काफी वृद्धि हुई। आईसीएआई के भीतर, इसके सदस्यों, शाखाओं और प्रादेशिक कार्यालयों के बीच परस्पर क्रियाओं में भी कई गुणा वृद्धि हुई। जनसंपर्क विभाग द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- नियमित परस्पर क्रिया द्वारा आमने-सामने साक्षात्कारों, मीडिया को पाठ्यचर्या, वृत्ति, नए पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने, सीए के लिए नए मार्गदर्शनों, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के दौरों, अन्य क्रियाकलापों और घटनाओं के संबंध में नवीनतम जानकारीयों से निरंतर अवगत कराने के माध्यम से मीडिया से परस्पर क्रियाओं में वृद्धि हुई थी।
- लेखों और साथ ही परस्पर क्रियाशील बैठकों/राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर पर प्रेस को जारी विज्ञापितियों और विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से, आज के सक्रिय संदर्भ में चार्टर्ड एकाउंटेंसी वृत्ति की संभावना और विस्तार का समर्थन किया।
- संस्थान और इसके कार्यालयों/संबंधित संगठनों के बीच संपर्क विकसित करने के विचार से संस्थान के भीतर विभिन्न विभागों, प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं को संभार तंत्र समर्थन प्रदान करना।
- जन संपर्क कार्य के भाग रूप में, संस्थान द्वारा, उसकी विभिन्न समितियों द्वारा आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों/कार्यक्रमों/ आयोजनों/आईसीएआई के पुस्तक विमोचनों को मुद्रण तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समुचित कवरेज प्रदान की गई थी।

- जन संपर्क, हीरक जयन्ती समारोह का अभिन्न भाग था और सृजन तथा मीडिया प्रचार से संबंधित कार्यों को इस अनुभाग को समनुदेशित किया गया था। एक हीरक जयन्ती लोगो तैयार किया गया था, जो समारोहों से संबंधित सभी प्रकार की संसूचनाओं का अभिन्न भाग था। इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट लेखन सामग्री तैयार की गई थी, जिसका उपयोग लोगों के साथ वर्ष भर किया जाएगा।
- हीरक जयन्ती समारोहों के लिए संपूर्ण संसूचनाओं - आमंत्रणों, ब्राशर, स्मृति चिन्हों, पोस्टरों, स्टिकरों, विज्ञापनों, न्यूजलेटर आवरण पृष्ठों आदि को तैयार किया गया था। उन्हें, संसूचना पत्रों में एक समानता बनाए रखने के लिए सभी शाखाओं/प्रादेशिक कार्यालयों को अग्रणीत किया गया था।
- हीरक जयन्ती समारोहों की समुचित कवरेज के लिए तीन इलेक्ट्रानिक चैनलों - सीएनबीसी, यूटीवीआई, जी, के साथ गठबंधन किया गया था। सभी तीन चैनलों ने इस अद्वितीय अवसर के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न क्रियाकलापों का व्यापक प्रचार प्रदान किया था।
- हीरक जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में एक स्मृति चिन्ह जारी करने का विनिश्चय किया गया था। राष्ट्रीय राजनैतिक नेताओं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अंतरराष्ट्रीय निकायों के अध्यक्षों जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संपर्क किया गया था और उन्हें इस अवसर पर संदेश भेजने का अनुरोध किया गया था। इन सभी संदेशों और साथ ही नैगम नेताओं से प्राप्त संदेशों का संकलन करते हुए एक विशेष स्मृति चिन्ह निकाला गया था।
- संस्थान द्वारा की गई अनेक पहलों के भागस्म में जयपुर में “लेखांकन वृत्ति - वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक मजबूत सेतू” नामक एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें आईसीएआई और आईसीएईडब्ल्यू यूके के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस सम्मेलन में 2400 प्रतिनिधियों, जिनमें 40 देशों के 250 प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे, ने भाग लिया था। इस पूर्ण आयोजन को मीडिया में व्यापक कवरेज प्रदान की गई थी।
- समाज को समर्थन प्रदान करने और समाज कल्याण में बिल्कुल निचले स्तर के प्रति सक्रिय रूप से योगदान करने की समय की मांग को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एनएसएस) प्रारंभ की गई थी। दिल्ली की माननीय मेयर, सुश्री आरती मेहरा ने इस परियोजना का शुभारंभ किया था, जिसमें जन साक्षरता, पर्यावरण की समृद्धि, स्वास्थ्य, कुटुंब कल्याण, बाल कल्याण, झुग्गी-झोपड़ी का विकास, शारीरिक रूप से भ्रष्ट व्यक्तियों का कल्याण, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, आपदा प्रबंध, एनजीओ की सहायता करने आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करना सम्मिलित होगा। मीडिया ने इस संपूर्ण आयोजन को विज्ञापित किया था।
- “ईयर बुक” नामक वार्षिक प्रकाशन जनसंपर्क प्रकोष्ठ द्वारा निकाला गया था, जिसमें समितियों की उपलब्धियों सहित संस्थान की सभी क्षेत्रों में उपलब्धियां अंतर्विष्ट थीं।
- संस्थान के 59वें वार्षिक समारोह में नए लेखांकन सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया गया था और इसके दौरान सीपीए ऑस्ट्रेलिया के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस आयोजन को मीडिया में सम्यक् कवरेज प्राप्त हुआ था।
- संस्थान ने योग ग्राम, हरिद्वार में एक 4 दिवसीय “राष्ट्रीय नेतृत्व और योग शिविर” का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। इस आयोजन को हरिद्वार में मीडिया द्वारा तथा जन-संपर्क प्रकोष्ठ द्वारा व्यापक प्रचार करके अन्य सभी क्षेत्रों में समुचित कवरेज प्रदान की गई थी।
- उपयुक्त रूप से रचित लेखों और साथ ही राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर प्रेस के साथ परस्पर क्रियाशील बैठकों के माध्यम से सीए पाठ्यचर्या का संवर्धन किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के बहु आयामी विकास के परिणामस्वरूप बड़े, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों में लेखांकन वृत्तिकों के दूसरे टियर के लिए मांग में काफी उछाल आया है। उद्योग की इस मांग के प्रत्युत्तर में संस्थान ने लेखांकन तकनीशियन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था। इस समारोह में 1500 से अधिक छात्रों और सदस्यों ने भाग लिया था और इसका उद्घाटन संघ के तत्कालीन रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद द्वारा किया गया था। संपूर्ण मीडिया-प्रिंट और इलेक्ट्रानिक ने इस समारोह को कवरेज प्रदान की थी। लेखांकन तकनीशियन पाठ्यक्रम का संवर्धन करने के लिए विभिन्न प्रकाशनों में विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। साथ ही यूटीवीआई को संस्थान द्वारा आयोजित किए जा रहे आयोजनों के लिए मीडिया भागीदार बनाया गया है। लेखांकन तकनीशियन पाठ्यक्रम के संवर्धन के लिए यूटीवीआई द्वारा तैयार किया गया एक विज्ञापन चैनलों पर दिखाया जा रहा है।
- जुलाई, 2009 में आगरा में हुआ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अत्यधिक सफल रहा था और इस सम्मेलन में 3 एमओयू/संयुक्त घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिन्हें सम्यक् रूप से मीडिया कवरेज प्राप्त हुई थी।

- प्रेस और मीडिया को निरंतर परस्पर क्रियाओं और विशेषकर प्रत्येक परिषद बैठक के पश्चात् वृत्ति में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत कराया जाता है।

5.14 व्यापार विधियाँ और विश्व व्यापार संगठन

व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन संबंधी समिति, व्यापार से संबंधित विधि, जिसमें विशिष्ट रूप से माल और सेवाओं में व्यापार सम्मिलित हैं, तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था, जिसमें साधारणतया राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों रूप से विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था भी सम्मिलित है, से संबंधित सभी विषयों में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की सुविज्ञता और प्राधिकार स्थापित करने और उसे सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की सदस्यता के बीच इन विषयों में ऐसे साधनों और युक्तियों के माध्यम से, जो अधिक प्रभावकारी साधन समझे जाते हों, विशेषज्ञता के आधार को सृजित करने और बढ़ाने के लिए गठित की गई थी जिससे कि इस संबंध में निश्चित और अनिश्चित राष्ट्रीय आकांक्षाओं, चिंता और आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

समिति की संरचना में, आईसीएआई की परिषद् के सदस्य, देश के विभिन्न भागों से समिति को सहयोजित सदस्य और समिति के विचार-विमर्शों में समय-समय पर आमंत्रित किए गए अन्व विशेषज्ञ सम्मिलित हैं।

व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन संबंधी समिति, वर्ष 2001 में अपने सृजन से अपना सारा समय डब्ल्यूटीओ के क्षेत्र में जागरूकता का सृजन करने, इस क्षेत्र में विशेष कौशल रखने वाले वृत्तिकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए आवश्यक शिक्षा प्रदान करने तथा आधारिक कार्य करने में समर्पित कर रही है, इस प्रक्रिया में वह भारत के आर्थिक विकास की प्रक्रिया के प्रति योगदान करने के लिए निरंतर अपनी पहलों का कार्यान्वयन भी कर रही है।

यह समिति नई विश्व व्यापार व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों का और उनके ऐसे परिणामों का मूल्यांकन कर रही है जो इस विशेष सेक्टर को प्रभावित करेंगे, ताकि संस्थान के सदस्यों को नई विश्व व्यापार व्यवस्था द्वारा सृजित अनेकों अवसरों का फायदा उठाने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार किया जा सके। समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय वृत्तिक परिवर्तन की उन हवाओं से अछूते न रह जाएं जो हमारे चहुँ ओर अप्रत्याशित तेजी से एकत्रित हो रही हैं, वर्तमान में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित विषयों पर अधिकाधिक जोर देने का विनिश्चय किया है:

- डब्ल्यूटीओ व्यवस्था में संस्थान के सदस्यों की सक्षमता में वृद्धि
- भारतीय वृत्तिकों की सेवाओं के निर्यात में बढ़ोत्तरी करने के लिए उपायों की पहचान करना और उनका पता लगाना।
- डब्ल्यूटीओ के अधीन वृत्तिक अवसरों का सृजन
- विभिन्न उपायों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार
- डब्ल्यूटीओ में समुचित स्तर प्राप्त करने के लिए सरकार को तकनीकी अंतर्निवेश उपलब्ध कराके डब्ल्यूटीओ व्यवस्था के अधीन भारतीय वृत्तिकों के लिए समान अवसर प्रदान करना

5.14.1 अनुसंधान क्रियाकलाप

व्यवसाय कर रहे और सेवारत चार्टर्ड एकाउंटेंटों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को, अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न क्षेत्रों और उसकी संगतता संबंधी मुद्दों की समझ प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के आधारिक उद्देश्य से, समिति ने इस अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए हैं :

- कनाडियन एडवांटेज - ए रिसर्च स्टडी ऑन कनाडियन बिजनेस ऑपरयुनीटिज
 - इन्ट्रोडक्सन टू डब्ल्यूटीओ एंड ऑपरयुनीटिज फॉर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड लॉज एंड डब्ल्यूटीओ
 - हैंडबुक ऑन फॉरेन ट्रेड पालिसी एंड गाइड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट स्टडी ऑन बेनिफिट्स ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन संबंधी समिति ने निम्नलिखित देशों के लिए देश विशिष्ट अनुसंधान अध्ययन भी प्रारंभ किए हैं। इन अनुसंधान अध्ययनों का प्राथमिक उद्देश्य चार्टर्ड एकाउंटेंटों और व्यापार विधि/नियमों में रुचि रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को मार्गदर्शन प्रदान करना है जो बड़े भागीदार के रूप में (क) इन देशों में अपना कारबार स्थापित करना चाहते हैं; और (ख) इन देशों में वृत्तिक लेखाकार के रूप में काम करना चाहते हैं :-

- यूनाइटेड अरब अमीरात
- आस्ट्रेलिया
- सिंगापुर
- फ्रांस
- इटली

5.14.2 सरकार को तकनीकी अंतर्निवेश

- विदेश व्यापार नीति 2004-09 के वार्षिक अनुपूरक 2008 का विश्लेषण किया।
- समिति ने उन डब्ल्यूटीओ सदस्यों की व्यापार नीतियों का विश्लेषण आरंभ किया है, जिनकी व्यापार नीतियों का पुनर्विलोकन वर्ष 2009 के दौरान डब्ल्यूटीओ स्तर पर किया जाना है अर्थात् न्यूजीलैंड, मोरक्को, गुआना, जाम्बिया, साउथ अफ्रीकी कस्टम्स युनियन, चिली, मालदीव, नाइजर/सेनेगल, अल सेल्वाडोर और जार्जिया और उसमें उन देशों के लिए लेखांकन सेवाओं के संबंध में चिंताओं का समाधान किया जिससे कि उन्हें सरकार को संसूचित किया जा सके ताकि सरकार उनका डब्ल्यूटीओ स्तर पर समाधान कर सके।

5.14.3 अंतरराष्ट्रीय अध्ययन दौर/संगोष्ठियां/सम्मेलन/जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान व्यापार विधियां और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति में निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया था :

- 17 मई, 2008 को मुंबई में आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों संबंधी विधियों के साथ संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधियां और विदेश व्यापार नीति विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी द्वारा की गई थी।
- आईसीएआई की सीआईआरसी की मिलाई शाखा के साथ संयुक्त रूप से 10-17 अगस्त, 2008 के दौरान थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर का आईसीएआई का अंतरराष्ट्रीय अध्ययन दौर। इस प्रतिनिधिमंडल में सभी क्षेत्रों के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए 54 प्रतिनिधि सम्मिलित थे।
- 6 सितम्बर, 2008 को कोलकाता में बीपीओ/केपीओ के विशेष संदर्भ से डब्ल्यूटीओ व्यवस्था के अधीन उभरते वृत्तिक अवसरों पर एक संगोष्ठी, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की ईआईआरसी द्वारा की गई थी।
- 10 सितम्बर, 2008 को आईसीएआई भवन, नई दिल्ली में आईसीएआई के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधियों और डब्ल्यूटीओ में अर्हता पत्र पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकृत सदस्यों के लिए परस्पर क्रियाशील कार्यशाला, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कानपुर स्थित आईसीएआई के प्रादेशिक कार्यालयों में प्रसारित किया गया था।
- 2 अक्टूबर, 2008 को आगरा में एकाउंटेंटों के लिए उभरते प्रतिमानों पर हीरक जयंती संगोष्ठी, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की आगरा शाखा द्वारा की गई थी।
- 24 अक्टूबर, 2008 को लखनऊ में विशेषज्ञ सलाहकार समिति के साथ संयुक्त रूप से लेखांकन वृत्तिकों के लिए उभरते प्रतिमानों पर हीरक जयंती राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की लखनऊ शाखा द्वारा की गई थी।
- 30 दिसम्बर, 2008 को कोयम्बटूर में एकाउंटेंटों के लिए उभरते प्रतिमानों पर हीरक जयंती सम्मेलन, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एसआईआरसी की कोयम्बटूर शाखा द्वारा की गई थी।
- 3 और 4 जनवरी, 2009 को वाराणसी में प्रत्यक्ष कर समिति के साथ संयुक्त रूप से डब्ल्यूटीओ और कराधान पर अखिल भारतीय सम्मेलन, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की वाराणसी शाखा द्वारा की गई थी।
- 18-21 जनवरी, 2009 के दौरान आईसीएआई प्रतिनिधिमंडल का हांगकांग दौर।
- 24 जनवरी, 2009 को मुंबई में डब्ल्यूटीओ व्यवस्था में सीमा पार एकीकरण पर बैठक।
- 30 और 31 जनवरी, 2009 को गोवा में अप्रत्यक्ष कर समिति और प्रत्यक्ष कर समिति के साथ संयुक्त रूप से कराधान और डब्ल्यूटीओ पर हीरक जयंती अखिल भारतीय सभा, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की गोवा शाखा द्वारा की गई थी।
- 15 फरवरी, 2009 को मुंबई में वृत्तिक विकास समिति के साथ संयुक्त रूप से वृत्तिक उत्कृष्टता और समृद्धि पर हीरक जयंती विचारसंगोष्ठी, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की मिलाई शाखा द्वारा की गई थी।
- 4 से 8 मई, 2009 के दौरान थाईलैंड में अंतरराष्ट्रीय आईआरसी, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की मिलाई शाखा द्वारा की गई थी।
- नई दिल्ली में 15 मई, 2009 को भारत में विभिन्न राजदूतों के व्यापार पदधारियों के साथ परस्पर क्रिया। इस परस्पर क्रिया में जर्मनी, अस्ट्रेलिया, बेलारूस, पश्चा, ट्यूनिशिया, मालावी, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान के दूतावासों/उच्चायोगों के पदधारियों ने भाग लिया था। इस पहल को जारी रखने के लिए 26 मई, 2009 को नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोगों के पदधारियों से भी बहसचीत की गई थी।
- 26 जून, 2009 को नई दिल्ली में “गेट्स पर एक परस्पर क्रिया कार्यशाला - लेखांकन के लिए मुद्दे”, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कानपुर स्थित आईसीएआई के प्रादेशिक कार्यालयों में प्रसारित

किया गया था।

समिति ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधियों और डब्ल्यूटीओ पर एक मानक पृष्ठभूमि सामग्री का एक प्रकाशन भी निकाला है।

5.14.4 अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन में अर्होत्तर पाठ्यक्रम

समिति ने चार्टर्ड एकाउंटेंटों में, उन्हें सक्रिय तथा चुनौतिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक वातावरण के प्रति अनुकूल बनाने तथा उनके निमित्त तैयार करने हेतु आवश्यक तथा वांछनीय सक्षमताएं विकसित करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन में अर्होत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था। इस पाठ्यक्रम को सदस्यों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

- नवंबर, 2004 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन (आईटीएल एंड डब्ल्यूटीओ) में अर्होत्तर पाठ्यक्रम में सफल प्रारंभ के पश्चात्, देश भर से 309 से अधिक सदस्यों ने पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण कराया है।
- आईटीएल और डब्ल्यूटीओ में अर्होत्तर पाठ्यक्रम के लिए 30 दिन के वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) के दो बैचों का सफल संचालन इस वर्ष के दौरान नई दिल्ली में किया गया। पहले बैच का आयोजन जुलाई-अगस्त, 2008 के दौरान किया गया था। दूसरे बैच का आयोजन दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2009 के दौरान नई दिल्ली में किया गया था और इसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कानपुर स्थित आईसीएआई के प्रादेशिक कार्यालयों में प्रसारित किया गया था। इसके अतिरिक्त, आईटीएल और डब्ल्यूटीओ में अर्होत्तर पाठ्यक्रम के लिए वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) के प्रथम चरण को भी 1 जुलाई, 2009 से 15 जुलाई, 2009 के दौरान नई दिल्ली में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षोपाय निदेशालय, विदेशी व्यापार निदेशालय, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड में वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संकाय, प्रमुख विधि फर्मों, व्यापार और उद्योग के लोगों, वृत्तिकों, परामर्शियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा डब्ल्यूटीओ क्षेत्र में अनुसंधान आधारित अन्य संगठनों से मिलकर बने संकाय ने पी.सी.पी. के दौरान प्रस्तुतियां दीं और व्याख्यान प्रस्तुत किए।
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन में अर्होत्तर पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम संरचना, अध्ययन सामग्री और ढांचे को, पाठ्यक्रम की सकल संरचना को एक संकेन्द्रित रूप प्रदान करने के विचार से पुनः संतुलित करने का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, यह स्कीम सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने के लिए लंबित है।
- समिति इस पाठ्यक्रम को देश भर में सदस्यों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए और साथ ही इस पाठ्यक्रम को उद्योग, सरकार और अन्य संभावित उपयोक्ता समूहों के बीच संबद्धित करने के लिए प्रयास कर रही है, जिससे कि इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन के क्षेत्र में प्रशिक्षित सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसरों का सृजन किया जा सके।
- पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ अर्होत्तर पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकृत सदस्यों के साथ विभिन्न शहरों में परस्पर क्रियाएं की गईं।
- 5 मई, 2008 को आईसीएआई, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन के क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञों से परस्पर क्रियाएं की गई थीं जिनमें इस क्षेत्र में चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए संभावित योजना पद्धतियों के संबंध में उनके विचार मांगे गए थे।

5.14.5 डब्ल्यूटीओ संबंधी वेब पोर्टल

समिति ने सदस्यों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डब्ल्यूटीओ संबंधी एक व्यापक वेब पोर्टल (<http://wto.icaai.org>) विकसित किया है। इस पोर्टल का आशय सदैव परिवर्तनशील वैश्विक व्यापार परिस्थितियों में सदस्यों को नवीनतम घटनाओं से अवगत कराना है।

5.14.6 ई-न्यूजलेटर

समिति ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए 'गेटवे टू इंटरनेशनल ट्रेड - ई-कम्यूनिकी ऑफ दि कमेटी ऑन दि ट्रेड लॉज एंड डब्ल्यूटीओ' शीर्षक वाला एक ई-न्यूजलेटर भी प्रारंभ किया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान उक्त ई-न्यूजलेटर के अक्टूबर, 2008, अप्रैल, 2009 और जुलाई, 2009 अंक निकाले गए हैं और उन्हें संस्थान की वेबसाइट पर रखा गया है।

5.14.7 डब्ल्यूटीओ संबंधी तकनीकी पटल

डब्ल्यूटीओ संबंधी तकनीकी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए डब्ल्यूटीओ संबंधी तकनीकी पटल को मजबूत किया गया है।

5.14.8 डब्ल्यूटीओ संबंधी समाचार

अंतरराष्ट्रीय व्यापार और डब्ल्यूटीओ के क्षेत्र में हो रही नवीनतम घटनाओं से सदस्यों को अवगत कराने के लिए, डब्ल्यूटीओ संबंधी सुसंगत समाचारों/समाचार कतरनों को नियमित रूप से सदस्यों की जानकारी के लिए वेबसाइट पर रखा जा रहा है।

5.14.9 अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन में अर्होत्तर पाठ्यक्रम

- नवम्बर, 2004 में यह पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पश्चात् इस पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण के लिए देश के सभी भागों से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। रजिस्ट्रीकरण के क्षेत्रवार ब्यारे निम्नानुसार है।

क्षेत्र	14.7.2009 तक रजिस्ट्रीकृत सदस्यों की संख्या
पश्चिमी	79
दक्षिणी	55
पूर्वी	31
मध्य	52
उत्तरी	92
योग	309

5.14.10 चल रही अन्य परियोजनाएं/पहलें

- व्यवसाय में लगे और सेवारत चार्टर्ड एकाउंटेंटों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ के विभिन्न क्षेत्रों और मुद्दों पर सुविज्ञ बनाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के आधारित उद्देश्य से समिति ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अनन्य अनुसंधान प्रकाशन निकालने के लिए अनुसंधान क्रियाकलाप भी प्रारंभ किए हैं :
 - अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थता
 - सीमापार समामेलन और अर्जन
 - विभिन्न देशों के लिए देश विनिर्दिष्ट अनुसंधान अध्ययन

5.15 बीमा और पेंशन संबंधी समिति**5.15.1 डीआईआरएम अर्हता वाले सीए के लिए वृत्तिक अवसरों का विकास करना**

- बीमा कंपनियों के कानूनी संपरीक्षकों के रूप में फर्मों की नियुक्ति करते समय डीआईआरएम अर्हता रखने वाले भागीदारों या संदाय पर चार्टर्ड एकाउंटेंट रखने वाली सीए फर्मों को वरियता देने के लिए बीमा कंपनियों के कानूनी संपरीक्षकों की नियुक्ति संबंधी आईआरडीए दिशानिर्देशों को संशोधित करने के अनुरोध के साथ आईआरडीए को प्रतिवेदन भेजा गया है।
- पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनियों के प्रभागीय संपरीक्षकों के रूप में फर्मों की नियुक्ति करते समय डीआईआरएम अर्हता रखने वाले भागीदारों या संदाय पर चार्टर्ड एकाउंटेंट रखने वाली सीए फर्मों को वरियता देने के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय को प्रतिवेदन भेजा गया है।
- डीआईआरएम अर्हता रखने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंटों का उपयोग करने का अनुरोध करते हुए विभिन्न बीमा कंपनियों, तृतीय पक्षकार प्रशासकों और एनसीआर में अवस्थित सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के सीएमडी को डीआईआरएम मार्केटिंग पत्र भेजे गए थे।
- पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनियों के नामनिर्देशित निदेशकों को इस संबंध में समुचित उपायों पर विचार करने के लिए पत्र भेजे गए थे, जिससे कि संस्थान के सदस्यों की जानकारी को ऐसे डीआईएम अर्हताप्राप्त सदस्यों की सेवाओं के संभाव्य उपयोगिताओं के बीच प्रसारित किया जा सके।

5.15.2 एक अर्होत्तर पाठ्यक्रम के माध्यम से सदस्यों को बीमा और पेंशन क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना तथा उन्हें तैयार करना

- ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने डीआईआरएम तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण की है क्रमशः 6 - 11 अक्टूबर, 2008, 16 - 21 मार्च, 2009 और 18 - 23 मई, 2009 को अहमदाबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में तीन अनुकूलन पाठ्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था।

5.15.3 डीआईआरएम तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले संस्थान के सदस्यों के लिए 18 - 23 मई, 2009 को नई दिल्ली में डीआईआरएम अनुकूलन पाठ्यक्रम

- डीआईआरएम पाठ्यक्रम कर रहे आईसीएआई सदस्यों के फायदे के लिए नवम्बर, 2008 तक आयोजित डीआईआरएम तकनीकी परीक्षाओं के सुझाए गए उत्तरों को संस्थान की वेबसाइट <http://www.icaai.org/post.html?post-id=2432> पर रखा गया है।

- सदस्यों के बीच डीआईआरएम पाठ्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए, समिति निरंतर प्रयास कर रही है और उपयुक्त उपाय भी कर रही है। इसके परिणामस्वरूप, 2 जुलाई, 2009 तक रजिस्ट्रीकरणों की संख्या 3520 तक पहुँच गई है। क्षेत्रवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्षेत्र	रजिस्ट्रीकरण
मध्य	718
पूर्वी	388
उत्तरी	525
दक्षिणी	1140
पश्चिमी	749

- डीआईआरएम अर्हताप्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंटों की सेवाओं के उपयोक्ताओं और साधारण सदस्यों तथा चार्टर्ड एकाउंटेंटों की पाठ्यक्रम के छात्रों को जागरूक बनाने के विचार से, समिति ने डीआईआरएम अर्हताप्राप्त सदस्यों को इस प्रश्न पर अपने अनुभव बताने के लिए आमंत्रित किया था कि किस प्रकार डीआईआरएम पाठ्यक्रम ने उन्हें बीमा और जोखिम प्रबंध के क्षेत्रों में अपनी डोमेन विशेषज्ञता विकसित करने में समर्थ बनाया। हमारे उपरोक्त अनुरोध के संबंध में सदस्यों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को संस्थान की वेबसाइट [http:// icai.org/post.html?post id=3396](http://icai.org/post.html?post id=3396) पर रखा गया है।
- अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में, भारतीय बीमा संस्थान ने लाइसेंसियेट, एसोसिएट और फेलोशिप पाठ्यक्रमों के निम्नलिखित प्रश्न पत्रों के संबंध में आईसीएआई के सदस्यों को छूट प्रदान की है :

1. प्रश्न पत्र संख्या 12 : बीमा कारबार परिस्थितियाँ
2. प्रश्न पत्र संख्या 21 : सूचना प्रौद्योगिकी
3. प्रश्न पत्र संख्या 26 : जीवन बीमा वित्त
4. प्रश्न पत्र संख्या 89 : प्रबंध लेखांकन
5. प्रश्न पत्र संख्या 99 : आस्ति प्रबंध

उपरोक्त के अलावा, डीआईआरएम अर्हताप्राप्त सदस्यों को पूर्वोक्त पाठ्यक्रमों के निम्नलिखित प्रश्नपत्रों से भी अतिरिक्त छूटें मंजूर की गई थीं :

1. प्रश्न पत्र संख्या 01 : बीमा सिद्धांत
2. प्रश्न पत्र संख्या 11 : साधारण बीमा का व्यवसाय
3. प्रश्न पत्र संख्या 82 : सांख्यिकीय

भारतीय बीमा संस्थान से यह अनुरोध भी किया गया है कि वह डीआईआरएम अर्हताप्राप्त सदस्यों को कुछ और छूटें प्रदान करे।

5.15.4 बीमा और पेंशन क्षेत्रों में अद्यतन जानकारी

समिति के पृथक वेब पोर्टल (<http://www.insuranceicai.org>) को, संस्थान के सदस्यों के बीच ज्ञान और जागरूकता के प्रसार के लिए दैनिक आधार पर (रविवार और छुट्टी के दिनों को छोड़कर) बीमा तथा पेंशन क्षेत्रों के संबंध में दैनिक अद्यतन जानकारी रखकर अद्यतन बनाया जा रहा है।

5.15.5 बीमा और जोखिम प्रबंध तथा पेंशन के क्षेत्रों में सीए के बीच डोमेन विशेषज्ञता विकसित करना

प्रकाशन

- 'निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और बीमा कंपनियों की प्रक्रियाओं के पुनर्विलोकन और प्रमाणन संबंधी तकनीकी गाइड' शीर्षक वाली एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक बीमा और जोखिम प्रबंध प्रणालियों और बीमा कंपनियों की प्रक्रियाओं के इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी दिशानेर्देशों की अपेक्षा के अनुसार संपरीक्षा करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है।
- डीआईआरएम पाठ्यक्रम कर रहे सदस्यों को अद्यतन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए डीआईआरएम पाठ्यक्रम के लिए पुनरीक्षित अध्ययन सामग्री को मुद्रित किया गया है और उसे संस्थान के वेबसाइट के हाइपरलिंक [http:// icai.org/post.html?post id=959&cid=51](http://icai.org/post.html?post id=959&cid=51) पर रखा गया है। डीआईआरएम पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री

को ऐसी रीति में पुनरीक्षित किया गया है जिससे कि इसका संदर्भ डीआरआरएम पाठ्यक्रम कर रहे सदस्यों के अलावा अन्य सदस्य भी ले सकें।

इन मॉड्यूलों को निम्नानुसार नामित किया गया है :

- जीवन बीमा सिद्धांत और व्यवहार
- साधारण बीमा सिद्धांत और व्यवहार
- जोखिम प्रबंध और पुनर्बीमा
- बीमा क्षेत्र में कार्रवार रणनीतिगत योजना और सूचना प्रौद्योगिकी

5.15.6 समिति द्वारा आयोजित बीमा और पेंशन क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रम

- 29 जुलाई, 2008 को नई दिल्ली में पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनियों के नाम निर्देशित निदेशकों के साथ एक बैठक।
- समिति ने 19-21 नवम्बर, 2008 के दौरान नई दिल्ली में आईसीएआई की आंतरिक संपरीक्षा समिति के साथ संयुक्त रूप से और लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय), भारत सरकार के सहयोग से पब्लिक सेक्टर में जोखिम प्रबंध पर एक 3 दिवसीय प्रबंधकीय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में 39 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
- 17 जनवरी, 2009 को मुंबई में बीमा और जोखिम प्रबंध संबंधी एक राष्ट्रीय विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया था। अध्यक्ष, आईआरडीए ने इसका उद्घाटन किया था।
- पूर्वोक्त कार्यक्रमों के अलावा, समिति ने प्रादेशिक परिषदों और उनकी 3 सबसे बड़ी शाखाओं को 50 हजार रुपए प्रतिवर्ष की और संस्थान की अन्य शाखाओं को 20 हजार रुपए प्रतिवर्ष की विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी। समिति के अनुरोध के प्रत्युत्तर में प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्नानुसार है :

क्रम सं.	संगठन इकाई का नाम	स्थान और तारीख	सम्मिलित किए गए विषय
1.	एआईआरसी की कालीकट शाखा	26 जुलाई, 2008 को कालीकट में	<ul style="list-style-type: none"> • जोखिम प्रबंध • बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण/ अभिलाभ की हानि बीमा कंपनियों की आंतरिक/प्रभागीय संपरीक्षा
2.	आईसीएआई की एसआईआरसी की हुबली शाखा	26 जुलाई, 2008 को हुबली में	<ul style="list-style-type: none"> • बीमा और जोखिम प्रबंध
3.	आईसीएआई की एनआईआरसी की एचपी शाखा	9 अगस्त, 2008 को शिमला में	<ul style="list-style-type: none"> • धन प्रतिशोधन • नई पेंशन स्कीम
4.	आईसीएआई की एसआईआरसी की वैल्लोर शाखा	9 अगस्त, 2008 को वैल्लोर में	<ul style="list-style-type: none"> • बीमा और पेंशन क्षेत्रों का रूपंतरण • बीमा और पेंशन में वृत्तिक अवसर • जोखिम प्रबंध - परिप्रेक्ष्य और मुद्दे • बीमा कंपनियों की आंतरिक संपरीक्षा • बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण
5.	सीआईआरसी की मुरादाबाद शाखा	30 अगस्त, 2008 को मुरादाबाद में	<ul style="list-style-type: none"> • बीमा क्षेत्र में धन प्रतिशोधन • बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण • अधिप्रमाणन और ईडीपी संपरीक्षा के दौरान ली जाने वाली सावधानियां
6.	एसआईआरसी की बेल्लारी शाखा	28 जून, 2008 को बेल्लारी में	जीवन बीमा में जोखिम प्रबंध
7.	सीआईआरसी की अलीगढ़ शाखा	6 दिसम्बर, 2008 को अलीगढ़ में	<ul style="list-style-type: none"> • पारिणामिक हानि निर्धारण और संगणना संबंधी पत्र

			<ul style="list-style-type: none"> • अभिलाष नीति की हानि की विशिष्टियाँ • भारत में पेंशन क्षेत्र का विकास • बीमा दलाली
8.	सीआईआरसी की बरेली शाखा	6 दिसम्बर, 2008 को बरेली में	<ul style="list-style-type: none"> • बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण • माध्यस्थता बीमा दलाली
9.	आईसीएआई की सीआईआरसी की जयपुर शाखा	3 और 4 जनवरी, 2009 को जयपुर में	<ul style="list-style-type: none"> • बीमा और पेंशन क्षेत्र में सीए के लिए नए वृत्तिक अवसर • बीमाकिक विज्ञानों पर अंतर्निवेशों सहित कर्मचारियों के फायदे के लिए एएस-15(पुनरीक्षित) • पणधारियों को मनाना - सही पद्धति (वृत्तिकों के लिए व्यक्तित्व विकास) • आयकर में हाल ही के संशोधन • भू संपदा निवेशों की कर विवक्षाएं • टीडीएस/हाल ही की घटनाएं • कर संपरीक्षा - हाल ही में • संशोधन
10.	आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की अहमदाबाद शाखा	30 दिसम्बर, 2008 को अहमदाबाद में	<ul style="list-style-type: none"> • “बीमा क्षेत्र में सुधार - आशाएं तथा चिंताएं” • “साधारण बीमा उद्योग में लेखांकन पहलू” • निर्यात और आयात संव्यवहारों से संबंधित बीमा • “साधारण बीमा में विधि परिप्रेक्ष्य”
11.	आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की औरंगाबाद शाखा	27 दिसम्बर, 2008 को औरंगाबाद में	<ul style="list-style-type: none"> • बीमा और पेंशन संबंधी विषय
12.	आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की मदुरै शाखा	31 जनवरी, 2009 को मदुरै में	<ul style="list-style-type: none"> • बीमा और पेंशन संबंधी विषय
13.	आईसीएआई की सूरत शाखा	21 दिसम्बर, 2008 को सूरत में	<ul style="list-style-type: none"> • पुनर्बीमा - चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए एक अवसर • बीमा क्षेत्र में चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए अवसर • बीमा में संपरीक्षा और लेखा • जोखिम प्रबंध
14.	आईसीएआई की बड़ौदा शाखा	20 दिसम्बर, 2008 को बड़ौदा में	<ul style="list-style-type: none"> • पुनर्बीमा - चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए एक अवसर • बीमा क्षेत्र में चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए अवसर • बीमा में संपरीक्षा और लेखा • जोखिम प्रबंध
15.	आईसीएआई की सीआईआरसी	31 मई, 2008 को कानपुर में	<ul style="list-style-type: none"> • बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण • बीमा दलाली • जोखिम प्रबंध - इसके अनिवार्य तथ्य और

			प्रक्रिया
			<ul style="list-style-type: none"> • तृतीय पक्षकार बीमा
16.	आईसीएआई की सीआईआरसी की सहारनपुर शाखा	28 मई, 2008 को सहारनपुर में	<ul style="list-style-type: none"> • बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण • बीमा दलाली • तृतीय पक्षकार बीमा • कर्मचारी फायदों संबंधी एएस 15
17.	आईसीएआई की सीआईआरसी की अलवर शाखा	1 जून, 2008 को अलवर में	<ul style="list-style-type: none"> • बीमा और पेंशन क्षेत्रों संबंधी विषय
18.	आईसीएआई की एनआईआरसी की फरीदाबाद शाखा	14 जून, 2008 को फरीदाबाद में	<ul style="list-style-type: none"> • कर्मचारी फायदों संबंधी एएस 15 (पुनरीक्षित) • बीमा क्षेत्र में चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए अवसर
19.	आईसीएआई की सीआईआरसी की भोपाल शाखा	31 मई, 2008 को भोपाल में	<ul style="list-style-type: none"> • बीमा और जोखिम प्रबंध क्षेत्रों संबंधी विषय
20.	आईसीएआई की सीआईआरसी की गोरखपुर शाखा	6 जुलाई, 2008 को गोरखपुर में	<ul style="list-style-type: none"> • कर्मचारी फायदों संबंधी एएस 15 (पुनरीक्षित) • जोखिम प्रबंध • धन प्रतिशोधन
21.	आईसीएआई की ईआईआरसी की आसनसोल शाखा	22 जून, 2008 को आसनसोल में	<ul style="list-style-type: none"> • जोखिम प्रबंध • बीमा कंपनियों की संपरीक्षा
22.	आईसीएआई की एसआईआरसी	29 मार्च, 2009 को चेन्नई में	<ul style="list-style-type: none"> • उभरते परिदृश्य में जोखिम प्रबंध और बीमा के प्रति सोच • बीमा कारबार में हाल ही की घटनाएं • बीमा कंपनियों की कानूनी, आंतरिक और संवर्ती संपरीक्षा • बीमा दलाली - भूमिका, प्रकृति, विधियां और विनियम तथा बीमा अभिकरण और बीमा दलाली में अंतर
23.	आईसीएआई की एसआईआरसी की गुड़गांव शाखा	16 मई, 2009 को गुड़गांव में	<ul style="list-style-type: none"> • बीमा माध्यस्थता • पेंशन क्षेत्र का विकास • बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण (अभिलाषा नीति की हानि) • उभरते बीमा बाजार और सीए के लिए अवसर

5.15.7 बीमांकिक विज्ञानों पर अंतर्निवेशों सहित कर्मचारियों के फायदे के लिए एएस-15(पुनरीक्षित)

परिषद् वर्ष 2008-09 के दौरान समिति ने संस्थान के सदस्यों के फायदे के लिए बीमांकिक विज्ञानों पर अंतर्निवेशों सहित कर्मचारियों के फायदे के लिए एएस-15(पुनरीक्षित) के संबंध में कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को 20 हजार रुपए की एकल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी। इस विशेष वित्तीय सहायता स्कीम के अधीन प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की प्रास्थिति रिपोर्ट निम्नानुसार है :

- 21 जून, 2008 को मुंबई में आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी
- 29 जुलाई, 2008 को कोयंबटूर में आईसीएआई की एसआईआरसी की कोयंबटूर शाखा
- 28 नवम्बर, 2008 को नई दिल्ली में आईसीएआई की एनआईआरसी
- 7 फरवरी, 2009 को हैदराबाद में आईसीएआई की एसआईआरसी की हैदराबाद शाखा

- 28 जनवरी, 2009 को बीमाकिक विज्ञानों पर अंतर्निवेशों सहित कर्मचारियों के फायदे के लिए एएस-15(पुनरीक्षित) पर एक सीपीई टेलीकांफ्रेंसिंग का आयोजन करने के लिए सीपीई समिति को संकाय समर्थन प्रदान किया गया था।

5.15.8 समिति के तकनीकी प्रयासों में बीमा उद्योग का सम्मिलित होना

विभिन्न बीमा कंपनियों के सीएमडी और सीईओ को यह अनुरोध करते हुए पत्र भेजे गए हैं कि वे अपने-अपने संगठनों में कार्य करने वाले ऐसे कुछ विशेषज्ञों को नामनिर्दिष्ट करें, जिनकी सेवाएं समिति द्वारा, समिति के प्रस्तावित प्रकाशनों के लेखकों/पुनर्विलोककों के रूप में उपयोग की जा सकती हैं। समिति के नवीनतम प्रकाशनों के सेट सीएमडी और सीईओ को उनके परिशीलन हेतु एवं प्रकाशनों को अपने-अपने संगठनों के पुस्तकालय में रखने के लिए भेजे गए थे।

5.15.9 लेखकों को संदेय मानदेय का पुनरीक्षण

समिति की पहल के परिणामस्वरूप, कार्यपालक समिति ने 12 मई, 2008 को अपनी 474वीं बैठक में, अन्य बातों के साथ समिति की ओर से प्रकाशनों का आधारीक प्रारूप तैयार करने वाले लेखकों को संदेय मानदेय और पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया।

5.15.10 बीमा और पेंशन के क्षेत्रों में अनुसंधान क्रियाकलाप

- बीमा कारबार में अंतर्वलित कशधान मुद्दों संबंधी अंतर्निवेश प्राप्त करने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और बीमा कंपनियों को पत्र भेजे गए हैं। इस प्रकार प्राप्त प्रश्नों को प्रत्यक्ष कर संबंधी समिति को उनके विचारार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित किया गया है।
- आईसीएआई के लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराके बीमा और जोखिम प्रबंध के क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में समिति ने अनुसंधानकर्ताओं के संभाव्य वर्गों को आईसीएआई के लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन की परियोजना सुविधाओं (अनुसंधान प्रस्तावों संबंधी दिशानिर्देश) के संबंध में पत्र भेजे हैं। इसके प्रत्युत्तर में एआरएफ के विशेषज्ञ समूह ने 2.25 लाख रुपये की पात्र लागत और कुल 12 मास की अवधि के अधीन रहते हुए बीमा क्षेत्र में सुधार शीर्षक वाली एक परियोजना का अनुमोदन किया है।

5.15.11 पीएफआरडीए के प्रयासों के लिए तकनीकी समर्थन

समिति, इस प्रयोजन के लिए समिति द्वारा गठित एक तकनीकी समूह की सहायता से पीएफआरडीए को निम्नलिखित क्षेत्रों में तकनीकी समर्थन उपलब्ध करा रही है :

- i. पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए लेखांकन सन्नियमों का प्रारूपण।
- ii. पेंशन निधि प्रबंधकों से जानकारी प्राप्त करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप तैयार करना।
- iii. निधि प्रबंधकों के क्रियाकलापों की संपरीक्षा और पीएफआरडीए/ एनपीएस न्यास द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और निदेशों के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट।

5.16 निगम शासन संबंधी समिति :

निगम शासन संबंधी समिति सितम्बर, 2005 में निगम शासन संबंधी ऐसे मुद्दों का समाधान करने के लिए, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर अस्तित्वों, चाहे सूचीबद्ध हों अथवा नहीं, दोनों के समक्ष आ रहे हैं गठित की गई थी। इसे स्थापित करने का आधारीक प्रयोजन यह था कि निगम शासन के समुचित स्तर को बढ़ावा दिया जाए, बेंचवार अधिकथित करने में सहायता उपलब्ध कराई जाए और वैश्विकरण को ध्यान में रखते हुए निगमों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों/समस्याओं के बारे में सक्रिय रूप से अनुसंधान किया जाए।

शासन मानकों के व्यवहार में वृत्तिकता को सर्वोपरि रखने के लिए समिति निगम शासन के विभिन्न संघटकों, जिनमें इनके व्यवहारिक पहलू, अनेकों विधिक और विनियामक अपेक्षाएं सम्मिलित हैं, में जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों/संगोष्ठियों का आयोजन करती रही है। निगम शासन संबंधी राष्ट्रीय फाउंडेशन (एनएफसीजी) जिसकी स्थापना कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है, ने बहुधा समिति के कार्यक्रमों को प्रायोजित किया है। एक अन्य प्रमुख पहल के भागरूप में समिति ने एनजीओ को बृहत्तर पारदर्शिता और बेहतर आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिए जनवरी, 2009 में “कोड ऑफ गवर्नंस फॉर एनजीओ” नामक एक प्रकाशन निकाला है।

5.16.1 आयोजित किए गए कार्यक्रम :

वर्ष के दौरान, समिति ने निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया था :

- जून, 2008 में ईआईआरसी, कोलकाता के साथ संयुक्त रूप से कोलकाता में “स्वतंत्र निदेशकों” से संबंधित 1 अधिष्ठापन कार्यक्रम का आयोजन किया था।

- राष्ट्रीय निगम शासन फाउंडेशन (एनएफसीजी) के साथ भागीदारी में अगस्त, 2008 में मुंबई में निगम शासन संबंधी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी डब्ल्यूआईआरसी, मुंबई ने की थी।
- राष्ट्रीय निगम शासन फाउंडेशन (एनएफसीजी) के साथ भागीदारी में सितम्बर, 2008 में कोलकाता में निगम शासन संबंधी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी ईआईआरसी, कोलकाता ने की थी।
- राष्ट्रीय निगम शासन फाउंडेशन (एनएफसीजी) के साथ भागीदारी में दिसम्बर, 2008 में कानपुर में निगम शासन संबंधी एक अर्धदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी सीआईआरसी, कानपुर ने की थी।
- राष्ट्रीय निगम शासन फाउंडेशन (एनएफसीजी) के साथ भागीदारी में दिसम्बर, 2008 में चेन्नई में निगम शासन संबंधी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी एसआईआरसी, चेन्नई ने की थी।
- राष्ट्रीय निगम शासन फाउंडेशन (एनएफसीजी) के साथ भागीदारी में मार्च, 2009 में हैदराबाद में निगम शासन संबंधी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी एसआईआरसी की हैदराबाद शाखा ने की थी।

5.16.2 चल रही पहलें/परियोजनाएं

- निगम शासन संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विनियामकों के साथ परस्पर क्रियाएं
- निगम शासन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ करना
- निगम शासन संबंधी आईसीएआई संहिता तैयार करने के लिए आईसीएआई विशेषज्ञ सलाहकार समूह का गठन जिसमें विख्यात विशेषज्ञ सम्मिलित हों
- अनुसंधान - भारतीय निगम जगत में निगम शासन की सफलता/असफलता संबंधी मामला अध्ययन
- स्वतंत्र निदेशकों और संपरीक्षा समिति की भूमिका और उत्तरदायित्वों पर प्रकाशन निकालना
- निगम शासन रेटिंग पर सॉफ्टवेयर विकसित करना
- निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना
- स्वतंत्र निदेशकों संबंधी कार्यशालाएं आयोजित करना
- एनएफसीजी के साथ भागीदारी में राष्ट्रीय संगोष्ठियों और एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करना
- संपरीक्षा समिति व्यवहारों के संबंध में किसी एक कुटुंब के स्वामित्व वाले उद्यमों में नमूना सर्वेक्षण करना
- बैंककारी और निगम क्षेत्र के लिए पृथक रूप से संपरीक्षा समिति संबंधी गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करना

5.17 सीए फर्मों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति

5.17.1 पर्यावलोकन

फरवरी, 2008 में स्थापित सीए फर्मों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति (सीसीबीसीएएफ) का उद्देश्य व्यवसाय में लगे चार्टर्ड एकाउंटेंटों की सक्षमता निर्माण उपायों संबंधी अवधारणात्मक और कार्यान्वयन मुद्दों का समाधान करना है। इस समिति का उद्देश्य लघु और मध्यम आकार की फर्मों के लिए उनके संसाधनों, अवसरचना और कौशल सेट में अभिवृद्धि करने को सुकर बनाना है, जिसके द्वारा उन्हें बड़े कार्य करने में समर्थ बनाया जा सके जिसके परिणामस्वरूप अभिलाषों और बाजार अंश में वृद्धि हो। इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, समिति नियमित रूप से संस्थान द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न सक्षमता निर्माण उपायों, अर्थात् नेटवर्किंग, समामेलन, वर्तमान नियमों और प्रक्रियाओं के संदर्भ में व्यवसाय का निगम रूप, की प्रगति का पुनर्विलोकन करती है।

5.17.2 समिति की उपलब्धियां (31 मई, 2009 तक)

- आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत 35 नेटवर्कों की, उन्हें स्थापित करने वाली 112 फर्मों को प्रतिक्रिया प्ररूप भेजकर स्थिति का पुनर्विलोकन किया था और उसके द्वारा उनके नेटवर्कों के कार्यकरण में उनके सामने आने वाली चुनौतियों/स्कावटों की पहचान की थी।
- दिलचस्पी लेने वाले व्यवसायगत सदस्यों के बीच एक सीए नेटवर्किंग पोर्टल www.caconnect.co.in के माध्यम से नेटवर्किंग, समामेलनों आदि के लिए पहचान और परस्पर क्रिया को सुकर बनाया था।
- अंत उपयोगकर्ताओं तक सुगम पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर भारत में रजिस्ट्रीकृत नेटवर्कों के अध्ययन व्यापक डाटा की उपलब्धता को सुनिश्चित किया था।
- 20 अप्रैल, 2009 को मुंबई में सीए फर्मों की सक्षमता निर्माण संबंधी एक परस्पर क्रिया कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस परस्पर क्रिया कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों से संस्थान के विभिन्न सक्षमता निर्माण उपायों के संबंध में सदस्यों

के मतों को मांगते हुए एक व्यापक प्रतिक्रिया प्राप्त की गई थी और समेकित रूप में लघु और मध्यम आकार के व्यवसायियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों/बाधाओं की पहचान करने के लिए एक पूर्ण विश्लेषण किया गया था।

- हैदराबाद शाखा के साथ संयुक्त रूप से, 22 मई, 2009 को हैदराबाद में, सीए फर्मों की सक्षमता निर्माण संबंधी एक परस्पर क्रिया कार्यक्रम का आयोजन किया था।
- विद्यमान मार्गदर्शनों ने बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए नेटवर्क, सम्मेलन - निर्विलयन और निगम वृत्ति प्रारूप संबंधी दिशानिर्देशों के पुनरीक्षण के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया था।

5.17.3 समिति की नीतिगत पहलें

- व्यवसायगत सदस्यों के बीच आईसीएआई की विभिन्न सक्षमता निर्माण पहलों के संबंध में जागरूकता के सृजन के लिए और लघु तथा मध्यम आकार के व्यवसायियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और बाधाओं की पहचान करने तथा उनका समाधान करने के लिए जून से अगस्त, 2009 के बीच पांच प्रमुख नगरों, अर्थात् कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में सक्षमता निर्माण संबंधी कार्यशाला/परस्पर क्रिया कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- 22 अगस्त, 2009 को मुंबई में एक राष्ट्रीय नेटवर्किंग और सक्षमता निर्माण शिखर सम्मेलन का आयोजन करना।
- नेटवर्क, सम्मेलन - निर्विलयन और निगम वृत्ति प्रारूप संबंधी दिशानिर्देशों का पुनरीक्षण करना।
- सीए नेटवर्किंग पोर्टल www.caconnect.co.in में अंतरराष्ट्रीय नेटवर्किंग साध्यता का पता लगाना और तदनुसार साइट में बदलाव करना।
- फर्म स्तर पर अवधारणात्मक और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए मॉड्यूल विकसित करना और समेकन तथा नेटवर्किंग के संबंध में क्या, कैसे और क्यों का उत्तर देने के लिए एक व्यापक गाइड विकसित करना।

5.18 आर्थिक और वाणिज्यिक विधि समिति

आर्थिक और वाणिज्यिक विधि समिति को फरवरी, 2008 में, आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों के क्षेत्र में उभरते हुए वृत्तिक अवसरों पर और अधिक स्पष्टता से ध्यान केन्द्रित करने के और आर्थिक तथा वाणिज्यिक विधियों को अधिकथित करने/उनमें संशोधन करने के क्षेत्र में विधायी प्रक्रिया को सुकर बनाने के विनिर्दिष्ट उद्देश्य से बनाया गया है।

समिति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां तथा उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार है :

माध्यस्थम संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति ने क्रमशः 1 से 6 दिसम्बर, 2008 के दौरान नई दिल्ली में और 17 जनवरी से 15 फरवरी, 2009 के दौरान माध्यस्थम संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के छठे और सातवें बैच का संचालन किया है।

समिति ने महानगरों और छोटे नगरों में माध्यस्थम संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को जारी रखने का विनिश्चय किया है। समिति पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर माध्यस्थम संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का संचालन कर रही है। अन्य क्षेत्रों/शाखाओं में भी इस पाठ्यक्रम का संचालन करने का प्रयास किए जा रहे हैं।

अग्रिम स्तर की कार्यशालाएं

प्रमुख रूप से ऐसे सदस्यों के लिए जिन्होंने पहले ही माध्यस्थम पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, माध्यस्थम संबंधी अग्रिम स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। ऐसे सदस्य, जिनके पास व्यवसाय में/अर्हतांतर 10 वर्ष का अनुभव है, इन कार्यशालाओं में प्रवेश लेने के पात्र होंगे।

माध्यस्थमों के आईसीएआई के पैनल का संवर्धन

- आईसीएआई के माध्यस्थमों के एक पैनल को संस्थान के वेबसाइट पर रखा गया है। इस संबंध में एक समुचित उदघोषणा को संस्थान के जर्नल में भी प्रकाशित किया गया था।
- आईसीएआई के माध्यस्थमों के पैनल के साथ पत्रों को देशभर के और विदेशी उपयोक्ता निकायों अर्थात् माननीय उच्च न्यायालय, चैम्बर्स ऑफ कामर्स, स्टॉक एक्सचेंज और माध्यस्थम संस्थाओं को भेजा गया था ताकि वे चार्टर्ड एकाउंटेंटों को माध्यस्थमों के रूप में नियुक्त करने के लिए पैनल का उपयोग कर सकें।
- समिति ने प्रारंभ में राष्ट्रीय स्तर पर और तत्पश्चात वैश्विक रूप से आईसीएआई के माध्यस्थमों के पैनल का संवर्धन करने के विचार से एक उपसमूह का सृजन किया था।
- ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट माध्यस्थम/सुलह/मध्यकता प्रक्रियाओं, विशेषकर वित्त, लेखांक और कराधान मामलों आदि के क्षेत्र में निभा सकते हैं, जागरूकता सृजित करने के लिए विभिन्न व्यापार निकायों और संघों के साथ संयुक्त रूप से संगोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा।

- संबंधित प्रादेशिक परिषद और उनकी शाखाओं के सदस्यों के साथ समिति और उपसमूह के अध्यक्ष/सदस्य राज्य सरकारों के विधि विभागों के सचिवों के साथ, उन्हें माध्यस्थता मामलों में चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका से अवगत कराने और इस विषय पर उनके साथ विचार-विमर्श करने के लिए बैठकें करेंगे।
- समिति सदस्यों के ज्ञान को अध्ययन बनाने के लिए माध्यस्थता मामलों (कानूनी अध्ययन, लेख और मामला विधियाँ) और अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों के संबंध में चार्टर्ड एकाउंटेंट जर्नल में नियमित रूप से 4 पृष्ठों का प्रकाशन करेगी।

प्रकाशन

- समिति 3 नए प्रकाशन निकालने और समिति के पूर्व प्रकाशनों को पुनरीक्षित करने के लिए उपाय कर रही है।
- विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 पर एक अध्ययन
- फेमा (विदेशी विनियम प्रबंध अधिनियम, 1999) पर एक संदर्भ निदेशिका

समिति के नए प्रकाशन

- धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 पर एक अध्ययन
 - आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों में वृत्तिक अवसरों संबंधी हैंडबुक
 - वाणिज्यिक और अन्य दस्तावेजों के प्रारूपण, प्रतिहस्तांतरण, उन्हें स्टांपित और रजिस्ट्रीकृत करने संबंधी एक अध्ययन
- पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करना**
- कार्यशालाओं में भाग लेने वाले व्यक्तियों के बीच समय पर परिचालन के लिए एसईजेड विधियों संबंधी कार्यशालाओं पर समुचित पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

विभिन्न सरकारी विभागों/मंत्रालयों के साथ परस्पर क्रिया

सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसरों की खोज करने के प्रयोजन से सरकारी विभागों/मंत्रालयों के पदधारियों के साथ निरंतर परस्पर क्रिया की गई है और समिति ने इस परस्पर क्रिया को आगे जारी रखने का विनिश्चय किया है।

विभिन्न आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों के संबंध में सुझाव/टीका टिप्पणियाँ

समिति ने राष्ट्रीय आवास बैंक को आवास वित्तपोषण कंपनियों/सेक्टर के संबंध में तथा वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति को धन शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008 के संबंध में अपने विचार/सुझाव प्रस्तुत किए हैं।

पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करना

निम्नलिखित विधियों पर पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं :

- विशेष आर्थिक जोन और सहबद्ध विधियाँ
- माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
- विदेशी विनियम प्रबंध अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
- विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 और न्यास-विधियाँ

आयोजित की गई कार्यशालाएं

समिति ने सदस्यों के फायदे के लिए निम्नलिखित कार्यशालाओं का आयोजन किया है :

- 12 और 13 सितम्बर, 2008 को मुंबई में “विदेशी विनियम विधियों में वृत्तिक अवसर” विषय पर एक कार्यशाला
- 3 और 4 अक्टूबर, 2008 को मुंबई में “वाणिज्यिक और अन्य दस्तावेजों के प्रारूपण, प्रतिहस्तांतरण, रजिस्ट्रीकरण और स्टांपिंग में वृत्तिक अवसर” विषय पर एक कार्यशाला
- 18 और 19 अक्टूबर, 2008 को अहमदाबाद में “आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों में वृत्तिक अवसर” विषय पर एक कार्यशाला
- समिति अब देशभर में एसईजेड और उनकी सहबद्ध विधियों के संबंध में कार्यशालाओं का आयोजन करने की व्यवस्था कर रही है।

5.19 शासकीय लेखांकन संबंधी समिति

- शासकीय लेखांकन संबंधी समिति को निम्नलिखित निर्देश निबंधनों के साथ वर्ष, 2008 में गठित किया गया था।
- वर्तमान शासकीय लेखांकन प्रणाली का पुनर्विलोकन करना और उसके आधार पर उसमें सुधारों का सुझाव देना।

- समाज में, विशिष्ट रूप से पणधारियों में जिनके अंतर्गत अन्य लोगों के साथ सरकारी कर्मचारी, सीएंडएजी के कर्मचारी, वृत्ति के सदस्य, मीडिया, एनजीओ और साधारण नागरिक भी हैं, शासकीय लेखांकन के प्रति जागरूकता सृजित करना।
- केन्द्र, राज्य, जिला स्तर पर सरकारी निकायों, स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
- आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के साथ समुचित अंतरापृष्ठ सुकर बनाना तथा ऐसी पद्धतियाँ विकसित करना जो लेखांकन सुधान प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का उपयोग समर्थ बनाएंगी।
- नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी), लेखा महानियंत्रक (सीजीए) और विभिन्न अन्य मंत्रालयों के साथ शासकीय लेखांकन प्रणाली के ढांचे में सुधारों को विकसित करने के लिए सहायता और समन्वय करना।
- केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को लोक सेवा प्रदाय तंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता की वृद्धि करने में सहायता करना।
- केन्द्रीय और राज्य सरकारों को ऐसे लेखांकन सुधारों का सुझाव देना, जो कर आधार को व्यापक बनाने तथा राजस्व संग्रहण के बेहतर प्रशसान और तैनाती तंत्र में सहायता करेंगे, परिणाम मापमान और समुन्नत एमआईएस, रिपोर्टिंग और बजट संबंधी नियंत्रण तंत्रों की प्रक्रिया में सहायता करेंगे।
- वृत्ति के भीतर शासकीय लेखांकन के संबंध में अध्ययन को बढ़ावा देना तथा उसके संबंध में जागरूकता तैयार करना और वृत्ति को, शासकीय लेखांकन सुधारों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सरकार को सहायता प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिए सक्षमता निर्माण उपाय करना तथा इस प्रयोजन के लिए अध्ययन करना, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना, पृष्ठभूमि सामग्री आदि का प्रकाशन करना।

5.19.1 1.4.2008 से 31.5.2009 के बीच किए गए क्रियाकलाप

- “सरकार में विद्यमान लेखांकन प्रणाली और सरकार में प्रोदभवन लेखांकन सुधार” विषय पर एक प्रास्थिति पत्र तैयार किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ “सरकारी लेखांकन सुधारों का वैश्विक अनुभव, भारतीय परिदृश्य, भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाला लेखांकन का नकद आधार, इसकी परिसीमाएं, प्रोदभवन लेखांकन, सरकार के लिए इसके फायदे, न्यूजीलैंड के अनुभव से सीखा गया पाठ, अंतर्वर्तित प्रमुख मुद्दे और प्रोदभवन लेखांकन सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए पूर्व शर्तें आदि” सम्मिलित हैं।
- वृत्ति में लगे सदस्यों की जानकारी के लिए श्री सत्यमूर्ति, पूर्व उप सीएंडएजी, जो समिति में संस्थान के जर्नल “दि चार्टर्ड एकाउंटेंट” में सरकारी लेखांकन पर एक लेख लिखने के लिए विशेष आमंत्रिती है, प्रकाशन के लिए उसे तैयार कर रहे हैं।
- लेखांकन सुधारों की प्रक्रिया को आरंभ करने के विचार से समिति के अध्यक्ष ने गोवा सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों से गोवा सरकार में लेखांकन सुधारों के संबंध में बैठक की और गोवा सरकार के लिए लेखांकन सुधारों की एक परियोजना प्रारंभ करने की इच्छा व्यक्त की। इससे काफी सकारात्मक निष्कर्ष प्राप्त हुए थे। तत्पश्चात, गोवा के माननीय मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत के साथ बैठक में समिति के अध्यक्ष ने लेखांकन सुधारों की परियोजना प्रारंभ करने के लिए आईसीएआई द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव पत्र उन्हें प्रस्तुत किया था। समिति इस संबंध में गोवा सरकार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है।
- श्री एस.एम. कुमार, अपर लेखा महानियंत्रक और सुश्री प्रवीण त्रिपाठी, भारत की उप नियंत्रक और लेखा परीक्षक से भी जारी लेखांकन सुधार प्रक्रिया के संबंध में बैठकों की गई थीं और लेखांकन सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय करने का करार किया गया था।

5.20 प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति

5.20.1 कारबार वित्त में मास्टर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति ने आईसीएआई के सदस्यों के लिए कारबार वित्त में मास्टर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था। इस पाठ्यक्रम में समकालीन सुसंगतता वाले विषयों जैसे कि खजाना और फोरेक्स, प्रबंधन, एमएंडए, निगम मूल्यांकन, निधि जुटाना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, वित्त प्रबंध सिद्धांत और व्यवहार पर बल देता है। पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या इसमें भाग लेने वालों से यह अपेक्षा करती है कि वे मामला अध्ययन तैयार करें और समूह परिचर्चाओं में भाग लें।

5.20.2 प्रबंध लेखांकन और कारबार वित्त (जर्नल)

समिति ने आज की कारबार परिस्थितियों में प्रबंध लेखांकन और वित्तीय प्रबंध से संबंधित सुसंगत मुद्दों पर ध्यान केन्द्रीत करते हुए अपने मासिक जर्नल “प्रबंध लेखांकन और कारबार वित्त” के प्रथम अंक का प्रकाशन किया था। इस जर्नल को विभिन्न बैंको, विश्वविद्यालयों, प्रमुख कारबार विद्यालयों, मंत्रालयों आदि में परिचालित किया गया था और उनमें से अधिकांश ने समिति की इस पहल की सराहना की थी।

5.20.3 सीएआरआर/सीएस की अंतिम रिपोर्ट

भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने विद्यमान लागत लेखा अभिलेख नियमों और लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट नियमों (सीएआरआर) का पुनर्विलोकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। विशेषज्ञ समूह की बैठकों के अनुक्रम में, लागत लेखा अभिलेख रखे जाने के संबंध में आईसीएआई के मत और पद्धतियां प्रस्तुत किए गए थे। इस बात पर बल दिया गया था कि लागत लेखा अभिलेखों को उत्तम लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर रखा जाना चाहिए और न कि नियमों के आधार पर।

आईसीएआई को आईसीडब्ल्यूआई की लागत लेखा मानक बोर्ड (सीएसबी) संबंधी प्रबंध लेखांकन समिति में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है। सीएसबी ने निम्नलिखित के संबंध में उद्भासन प्रारूप जारी किए हैं :

- सीएस - 9 : उपयोगिताओं की लागत संबंधी लागत लेखा मानक
- सीएस - 11 : प्रत्यक्ष व्यय संबंधी लागत लेखा मानक
- सीएस - 12 : पैकिंग सामग्री की लागत संबंधी लागत लेखा मानक

सीएसबी ने निम्नलिखित लागत लेखा मानकों के प्रथम प्रारूप पर भी विचार-विमर्श किया है :

- सीएस - 10 : प्रशासनिक उमरी शीशों संबंधी लागत लेखा मानक
- सीएस - 13 : मरम्मत और अनुरक्षण लागत संबंधी लागत लेखा मानक
- सीएस - 7 : सामग्री की लागत संबंधी लागत लेखा मानक
- सीएस - 8 : कर्मचारी लागत संबंधी लागत लेखा मानक

5.21 लोक वित्त संबंधी समिति

वर्ष 2008 में, आईसीएआई ने लोक वित्त के क्षेत्र में केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय शासनों को वृत्तिक विशेषज्ञता प्रदान करने के उद्देश्य से पहली बार लोक वित्त संबंधी समिति का गठन किया था। इसके गठन से ही समिति ने आईसीएआई के अतुलनीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

आज की तारीख तक, समिति ने 7 राज्यपालों, 14 मुख्यमंत्रियों, 7 वित्तमंत्रियों और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के 25 सचिवों/मंत्रियों/आयुक्तों से परस्पर क्रियाएं की हैं और उन्हें अर्थव्यवस्था और प्रशासन को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान की है।

भारत के सर्वोच्च योजना निकाय तक पहुंच बनाने के लिए, समिति ने आईसीएआई, दिल्ली में 4 दिसम्बर, 2008 को एक वार्ता सत्र का आयोजन किया था जिसमें प्रोफेसर अभिजीत सेन, सदस्य, योजना आयोग, भारत सरकार ने पूंजी व्यय और राजस्व व्यय, योजनागत और गैर योजनागत व्यय, नकद प्राप्तियों और राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के वित्तों पर विचार प्रस्तुत किए थे।

आस्ति प्रबंध के विषय पर केरल सरकार के पदाधिकारियों के बीच जागरूकता का सृजन करने और अतिरिक्त राजस्व संसाधनों की खोज करने के लिए, समिति ने कराधान अध्ययन केन्द्र, केरल सरकार के साथ संयुक्त रूप से एर्नाकुलम, केरल में 27 दिसम्बर, 2008 को “लोक वित्त संबंधी मुद्दे” विषय पर एक राज्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। समिति के कार्य की सराहना करते हुए, केएसआईडी ने अपनी आस्तियों, दायित्वों, कंप्यूटरीकरण और संपूर्ण विभाग की लेखांकन प्रणाली को दोहरी प्रविष्टि वाली प्रोदभवन आधारित लेखांकन प्रणाली में संपरिवर्तित करने संबंधी रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव दिया है।

समिति ने लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से 28 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में आईएफआरएस पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 50 सीईओ, सीएफओ, पीएसयू और सरकारी उद्यमों के वित्त विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया था।

समिति ने 2 और 3 फरवरी, 2009 के दौरान नई दिल्ली में व्यापार और कर विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए बैठ से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया था और साथ ही अगरतला में 15 और 16 मई, 2009 के दौरान अगरतला नगर परिषद् के पदाधिकारियों के लिए आउटकम बजट और प्रोदभवन आधारित लेखांकन प्रणाली पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। समिति ने मेघालय सरकार के लिए संसाधनों के अभिसरन और राजस्व वृद्धि संबंधी एक रिपोर्ट भी तैयार की थी।

गुजरात सरकार ने समिति को, विभिन्न लेखांकन पैकेजों में उनके जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया है जो उन्हें बेहतर नियोजन प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा।

समिति ने अपनी बैठकों में प्रमुख व्यक्तियों और मंत्रियों को, उनके विचार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया था। सीए के. रहमान खान, माननीय उप सभापति, राज्य सभा, माननीय श्री यशवंत सिंह, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भारत सरकार, श्री रूपचंद पाल, माननीय अध्यक्ष, लोक उपक्रमों संबंधी समिति और सदस्य, भारत की वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति, स्व० श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, भूतपूर्व राज्यपाल, पुद्दुचेरी सरकार, डॉ० सतीश सी. झा, सदस्य, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्, प्र०० अतुल शर्मा, सदस्य, 13वां वित्त आयोग, ने समिति की बैठकों में भाग लिया था।

26 मई, 2009 को समिति ने आईसीएआई, नई दिल्ली में अपनी 7वीं बैठक का आयोजन किया था। दिल्ली सरकार के माननीय वित्त मंत्री, डॉ० ए.के. वालिया ने मुख्य अतिथि के रूप में इस बैठक को संबोधित किया था और देश के आर्थिक विकास में चार्टर्ड एकाउंटेंटों की भूमिका की सराहना की थी। उन्होंने चार्टर्ड एकाउंटेंटों को दिल्ली सरकार के राजस्व संसाधनों में वृद्धि करने के संबंध में योगदान करने का निमंत्रण दिया था।

18 जून, 2009 को, मुंबई में श्री अशोक चव्हाण, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री के साथ आयोजित एक बैठक में, उपाध्यक्ष, आईसीएआई और समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और राज्य में लोक वित्त से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था।

समिति का यह प्रयास है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों, पीएसयू, सीपीएसई, स्थानीय निकायों और एनजीओ की बेहूनी के लिए उनमें लोक वित्त के प्रभावी उपयोग, अतिरिक्त राजस्व के सृजन के संबंध में जागरूकता बनाई जाए और उन्हें तकनीकी अंतर्निवेश उपलब्ध कराए जाएं।

5.22 प्रत्यक्ष कर समिति

वर्ष 2008-09 के दौरान, तत्कालीन वित्त विधि समिति के स्थान पर दो नई समितियों, अर्थात् प्रत्यक्ष कर समिति और अप्रत्यक्ष कर समिति का सृजन किया गया था। 1.4.2008 से 31.5.2009 की अवधि के दौरान समिति ने विभिन्न क्रियाकलाप आरंभ किए जैसे कि सरकार को प्रतिवेदन, सीबीडीटी पदाधिकारियों के साथ परस्पर क्रियाएं, अंतरराष्ट्रीय कराधान पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ करना, वित्त विधि समिति के विद्यमान प्रकाशनों को पुनरीक्षित करना, संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन करना और इसी प्रकार के अन्य कार्य।

5.22.1 प्रतिवेदन/सुझाव

समिति ने सरकार को निम्नलिखित प्रतिवेदन किए हैं :

- इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से करों के संवाय के लिए समय के विस्तारण के लिए अनुरोध।
- केन्द्रीय कर विधेयक, 2007 पर विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के संबंध में सुझाव और संसदीय स्थायी समिति द्वारा वांछ किए जाने पर संस्थान के विचारों को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया था।
- “धन शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008” पर सुझाव।
- इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रतिवेदन कि क्या टीडीएस के संबंध में भेजी जाने वाली रकम को पुराने चालान 281 का उपयोग करते हुए भेजा जा सकता है क्योंकि नए प्ररूप सं. 17 को मंत्रालय की वेबसाइट पर संदाय गेटवे पर अपलोड नहीं किया गया था।
- प्रतिदाय के मामलों में संवीक्षा निर्धारण को समय पर पूरा करने के लिए शीघ्रताशीघ्र समुचित उपाय करने, अधिमानी रूप से ऐसे निर्धारणों को पूरा करने के लिए अंतिम तारीख नियत करते हुए, के लिए सीबीडीटी को अनुरोध। विकल्प के रूप में यह सुझाव दिया गया था कि इस शर्त को हटा दिया जाए कि प्रतिदाय ऐसे निर्धारण के पूरा होने के पश्चात् ही मंजूर किया जाएगा।
- सरकार को बजट पूर्व ज्ञापन - 2009 प्रस्तुत किया गया था।
- कर संपरीक्षा के क्षेत्र में कपटपूर्ण व्यवहारों को रोकने के लिए आईसीएआई द्वारा किए जाने वाले उपायों से संबंधित एक ब्यौरेवार उत्तर कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। सीबीडीटी परिपत्र सं. 03/2009, तारीख 21.5.2009 में दिए गए निदेशों, आईटीआर 5 को प्रस्तुत करने के विशिष्ट प्रतिनिर्देश से, के संबंध में निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए आयकर विवरणियां फाइल करने में सामने आने वाली मुश्किलों और व्यवहारिक कठिनाइयों पर विचार करने के लिए प्रतिवेदन।
- स्रोत पर निम्न कटौती या कटौती न करने के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सामने आने वाली मुश्किलों और व्यवहारिक कठिनाइयों पर विचार करने के लिए प्रतिवेदन।

5.22.2 सीबीडीटी पदाधिकारियों से परस्पर क्रिया

प्रत्यक्ष कर समिति ने एनआईआरएस के साथ श्री. आर.एस. मथौरा, तत्कालीन अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के लिए एक सत्रि भोज बैठक का आयोजन किया था। श्री मथौरा ने यह कथन करते हुए कि चार्टर्ड एकाउंटेंट वृत्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, यह आशा व्यक्त की थी कि वह भविष्य में और अधिक सक्रिय रूप से ऐसा करती रहेगी। इसके प्रत्युत्तर में आईसीएआई के माननीय अध्यक्ष ने यह कथन किया था कि आईसीएआई “राष्ट्र निर्माण में भागीदार” के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और वह ऐसा करना जारी रखेगा। उन्होंने ऐसी विनिर्दिष्ट घटनाओं का उल्लेख किया जब आईसीएआई ने बेहतर राजस्व संग्रहणों और उनमें होने वाली कमियों पर रोक लगाने के लिए उपायों का सुझाव दिया था।

5.22.3 अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति ने अहमदाबाद और दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आयोजन किया था। इस पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु की सदस्यों द्वारा सराहना की गई थी। 5 फरवरी, 2009 से अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी पृथक समिति के सुपुन के साथ ही यह प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उसे अंतरित कर दिया गया है।

5.22.4 प्रकाशन

समिति ने वित्तीय विधि समिति के निम्नलिखित विद्यमान प्रकाशनों को पुनरीक्षित करने के लिए देशभर में विभिन्न अध्ययन ग्रुप बनाए थे :

1. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण।
2. पूर्त न्यासों और संस्थाओं का कराधान - एक अध्ययन।
3. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115अख के अधीन रिपोर्ट संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण।

5.22.5 संगोष्ठियां और सम्मेलन

समिति ने उक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन किया था :

- 5 से 7 जून, 2008 के दौरान रामनगर में अप्रत्यक्ष कर समिति के साथ संयुक्त रूप से कराधान संबंधी एक आवासीय पाठ्यक्रम का संचालन किया था।
- 18 और 19 जुलाई, 2008 को हैदराबाद में हीरक जयंती सम्मेलन।
- 23 और 24 अक्टूबर, 2008 को विशाखापत्तनम में अखिल भारतीय सम्मेलन।
- 15 और 16 अक्टूबर, 2008 को चिंचवाड़गांव (पुणे) में कराधान संबंधी राष्ट्रीय हीरक जयंती सम्मेलन।
- 7 दिसम्बर, 2008 को कानपुर में कराधान संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी।
- 3 और 4 जनवरी, 2009 को वाराणसी में डब्ल्यूटीओ और कराधान संबंधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन।
- 30 और 31 जनवरी, 2009 को गोवा में हीरक जयंती अखिल भारतीय कर और डब्ल्यूटीओ अभिसमय।
- 25 अप्रैल, 2009 को इंदौर में प्रत्यक्ष कर संबंधी एक कार्यशाला।
- 17 और 18 मई, 2009 को त्रिचूर में प्रत्यक्ष कर और आईएफआरएस संबंधी आवासीय कार्यशाला।
- 16 मई, 2009 को बिलासपुर में प्रत्यक्ष कर संबंधी एक कार्यशाला।
- 30 अप्रैल, 2009 को कानपुर में प्रत्यक्ष कर संबंधी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी।
- 27 जून, 2009 को रायपुर में प्रत्यक्ष कर संबंधी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी।
- 27 जून, 2009 को सलेम में प्रत्यक्ष कर संबंधी एक पूर्ण दिवसीय कार्यशाला।

5.23 अप्रत्यक्ष कर समिति**5.23.1 केन्द्रीय कर विधेयक, 2007 पर अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के संबंध में संसदीय स्थायी समिति को प्रस्तुतीकरण**

वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने संस्थान से केन्द्रीय कर विधेयक, 2007 पर अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के संबंध में सुझाव आमंत्रित किए थे। आईसीएआई के विचारों को अंतर्विष्ट करने वाला एक ज्ञापन वित्त संबंधी स्थायी समिति को प्रस्तुत कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, संस्थान से यह अनुरोध किया गया था कि वह वित्त संबंधी स्थायी समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने विचार प्रस्तुत करे। तदनुसार, प्रधान, अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति और सचिव, आईसीएआई 19 जून, 2008 को समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे और उन्होंने संस्थान के विचारों को प्रस्तुत किया था। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते समय यह सुझाव दिया गया था कि निवासी निर्धारिणी को भी प्रतिनिर्देश करने की अनुज्ञा प्रदान करके अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने वाले मामलों के विस्तार क्षेत्र में वृद्धि की जाए। प्रतिनिर्देशों की कुल संख्या को विनियमित करने के विचार से ऐसे मुद्दों के, जिन्हें निर्दिष्ट किया जा सकता है, प्रकार के संबंध में और धनीय सीमा, प्रतिनिर्देश के लिए कार्यवाही फीस आदि जैसी कतिपय परिस्थिति लागू की जा सकती हैं। यह भी सुझाव दिया गया था कि कतिपय वर्षों का अनुभव रखने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट और अधिवक्ता जैसे वृत्तिकों को अग्रिम विनिर्णय संबंधी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में वृत्ति के लिए पात्र माना जाना चाहिए।

5.23.2 सरकार को प्रतिवेदन

समिति ने सरकार को निम्नलिखित दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे :

(क) सीबीसी को प्रतिवेदन

अप्रत्यक्ष कर समिति ने संस्थान की प्रतिनिधित्व समिति के साथ अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि वह उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 14क और धारा 14कक के अधीन विशेष संपरीक्षा करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंटों को सम्मिलित करे।

(ख) महाराष्ट्र सरकार को प्रतिवेदन

विक्रय कर आयुक्त, महाराष्ट्र ने नवम्बर, 2008 में एक परिपत्र जारी किया था जिसमें प्रारम्भ सं. 704 में प्रस्तुत संपरीक्षा रिपोर्ट का संशोधन करते हुए उसे वित्तीय वर्ष 2007-08 में जारी संपरीक्षाओं को लागू बनाया गया था। नई प्रारंभ की गई संपरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में कतिपय मुद्दे थे। इस विषय में डब्ल्यूईआरसी की प्रादेशिक अप्रत्यक्ष कर समिति ने महाराष्ट्र सरकार वेट और सीएसटी को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और साथ ही विक्रय कर विभाग के साथ बैठकें भी की थीं। प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने और बैठकें किए जाने के पश्चात् आयकर विभाग इस बात के लिए सहमत हो गया था कि वह व्यापारी और संबंधित और संपरीक्षक के विकल्प पर पुराने प्रारम्भ में संपरीक्षा रिपोर्टें स्वीकार करना जारी रखेगा।

5.23.3 ओईसीडी द्वारा जारी तकनीकी पत्र पर सुझाव

सेवाओं और अमूर्त वस्तुओं के सीमा पार व्यापार को वेट/जीएसटी लागू करने के संबंध में तकनीकी पत्र पर ओईसीडी ने टिप्पणियां/अंतर्निवेश आमंत्रित किए थे। इस पत्र में सेवाओं के सीमापार प्रदाय और कारबार से कारबार संदर्भ में अमूर्त वस्तुओं के सीमापार प्रदायों को मूल्यवर्धित कर लागू करने के लिए मूलभूत पद्धतियों को अधिकथित किया गया है। समिति ने कांफ्रेंस कॉलों के माध्यम से तकनीकी पत्र पर विचार-विमर्श किया था और उक्त तकनीकी पत्र पर अपने सुझावों को ओईसीडी को प्रस्तुत किया था।

5.23.4 सरकारी पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2008-09 के दौरान समिति ने सरकारी पदाधिकारियों के लिए 3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लेखांकन अवधारणाओं, लेखा बहियों और अन्य संबंधित विवरणों की संवीक्षा, संपरीक्षा तकनीकों, वित्तीय अभिलेखों को अप्रत्यक्ष कर अभिलेखों से संगत बनाना, वित्तीय अभिलेखों से सुराग ढूंढना आदि विषय सम्मिलित थे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों ने इन कार्यक्रमों की सराहना की थी और ये अत्यधिक सफल रहे थे।

(क) भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) समूह “क” परीक्षाधीन अधिकारियों के 59वें बैच के लिए “अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में वित्तीय और लेखांकन उपकरणों का उपयोग” विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 16 से 27 जून, 2008 के दौरान राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक अकादमी (एनएसीईएन), फरीदाबाद में किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सीए अमरजीत चोपड़ा, परिषद् के सदस्य द्वारा किया गया था और स्वागत भाषण सुश्री शशि मिज, अपर महानिदेशक, एनएसीईएन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विदाई भाषण अध्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस पाठ्यक्रम की सभी आईआरएस परीक्षार्थियों द्वारा सराहना की गई थी और उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की थी कि ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम एक मास होनी चाहिए।

(ख) समिति ने आईआरएस परीक्षार्थियों के 59वें बैच के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन करने के पश्चात् एनएसीईएन, नई दिल्ली में 18 से 22 अगस्त, 2008 के दौरान समिति ने “अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में वित्तीय और लेखांकन उपकरणों का उपयोग” विषय पर (वैसे ही जैसे इसका संचालन आईआरएस परीक्षार्थियों के लिए किया गया था) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था।

(ग) एसआईआरसी की प्रादेशिक अप्रत्यक्ष कर समिति ने सितम्बर, 2008 में वाणिज्यिक कर विभाग, तमिलनाडु के अधिकारियों के लिए लेखांकन समिति प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन श्री तिरु एस.एन.एम.उबेदुल्लाह, वाणिज्यिक कर मंत्री, तमिलनाडु सरकार द्वारा आईसीएआई भवन, चेन्नई में किया गया था।

5.23.5 बजटपूर्व ज्ञापन, 2009

समिति ने सदस्यों से प्राप्त सुझाव के आधार पर सरकार को बजटपूर्व ज्ञापन, 2009 प्रस्तुत किया था।

5.23.6 जीएसटी/वेट पर अनुसंधान परियोजन

भारत से बाहर रहने वाले ऐसे सदस्यों को, जो अनुसंधान परियोजनाओं से जुड़ने को इच्छुक थे, जीएसटी/वेट के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान प्रारंभ करने में अपनी दिलचस्पी व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया गया था। जीएसटी/वेट के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले विभिन्न देशों के 14 सदस्यों का एक समूह स्थापित किया गया था। इन 14 सदस्यों में से 2 सदस्यों ने अपने देश विनिर्दिष्ट पत्र तैयार किए थे और शेष सदस्यों ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी।

यह परियोजन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत 2 पत्रों और यूके, कनाडा, आस्ट्रेलिया और ब्राजील देशों को सम्मिलित करने वाली 16 जनवरी, 2008 को हुई अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में अन्य अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत पत्रों को सम्मिलित करते हुए एक पुस्तक के प्रकाशन के साथ पूरी हो गई थी।

5.23.7 कराधान संबंधी आवासीय पाठ्यक्रम

समिति ने 5 से 7 जून, 2008 के दौरान रामनगर (उत्तराखंड) में प्रत्यक्ष कर समिति के साथ संयुक्त रूप से कराधान संबंधी एक तीन दिवसीय आवासीय पाठ्यक्रम का आयोजन किया था। इस पाठ्यक्रम में खुदरा विक्रय, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, आतिथ्य, मीडिया और मनोरंजन आदि जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के व्यावहारिक मुद्दों से संबंधित विषय सम्मिलित थे। इस पाठ्यक्रम में उद्योग में लगे सदस्यों और गैर सदस्यों ने भाग लिया था और यह अत्यधिक सफल रहा था।

5.23.8 सेवा कर संबंधी तीन दिवसीय आधारिक स्तर पाठ्यक्रम

चूंकि अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में अविश्वसनीय गति से विस्तार हो रहा था, इसलिए अप्रत्यक्ष कर समिति ने यह विचार किया कि सदस्यों को अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में व्यवसाय करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए यह समय अतिउत्तम है। सदस्यों को अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में व्यवसाय करने हेतु प्रोत्साहित करने की दिशा में पहले कदम के रूप में समिति ने देश भर में सेवा कर संबंधी तीन दिवसीय आधारिक स्तर पाठ्यक्रम आयोजित करने का विनिश्चय किया था।

सेवा कर संबंधी पहले तीन दिवसीय आधारिक स्तर पाठ्यक्रम का आयोजन 29 से 31 अगस्त, 2008 के दौरान सिलीगुड़ी में किया गया था जिसका उद्घाटन अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क, सिलीगुड़ी ने किया था। उद्घाटन सत्र के दौरान सहायक आयुक्त, सिलीगुड़ी प्रभाग और सहायक आयुक्त जलपाइगुड़ी भी उपस्थित थे। इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के संकाय का यह मत था कि भाग लेने वाले व्यक्तियों में विषय के प्रति अत्यधिक दिलचस्पी थी और वे विषय के पठन के प्रति अत्यधिक उत्सुक थे। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी व्यक्ति इस बात से प्रसन्न थे कि यह एक निरंतर तीन दिवसीय पाठ्यक्रम था और वे इस विषय पर अपना ध्यान केन्द्रीत कर सकते थे। उन्होंने यह उल्लिखित किया था कि इस पाठ्यक्रम ने उनके ज्ञान में महत्वपूर्ण संवर्धन किया है और यह उन्हें व्यवसाय के क्षेत्र में अवसरों की पहचान करने और कार्य प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा। यह पाठ्यक्रम अत्यधिक सफल रहेगा।

तत्पश्चात्, सेवा कर संबंधी तीन दिवसीय आधारिक स्तर पाठ्यक्रम के दूसरे बैच का आयोजन सीआईआरसी की रायपुर शाखा द्वारा अक्टूबर, 2008 में किया गया था। यह कार्यक्रम भी अत्यधिक सफल रहा था।

5.23.9 मुंबई में अप्रत्यक्ष कर संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन

समिति ने 26 और 27 नवम्बर, 2008 को मुंबई में अप्रत्यक्ष कर संबंधी दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूईआरसी द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन में लगभग 600 सदस्यों ने भाग लिया था और यह अत्यधिक सफल रहा था।

इस सम्मेलन का आधरिक उद्देश्य ऐसी विभिन्न अप्रत्यक्ष कर विधियों, जो व्यापार और उद्योग/कारबार, संबंधी विनिश्चयों को प्रभावित करती हैं, के अधीन अतिमहत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यावहारिक रूप से ध्यान केन्द्रीत करते हुए विस्तृत परिचर्चा और विचार-विमर्श करना था और साथ ही देश में प्रस्तावित जीएसटी व्यवस्था पर एक सोच प्रक्रिया प्रारंभ करना था।

5.23.10 “संघीय प्रणाली में जीएसटी संरचना (भारत में जीएसटी के प्रस्तावित प्रारंभ के विशेष प्रतिनिर्देश से)” विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी

समिति ने 16 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में “संघीय प्रणाली में जीएसटी संरचना (भारत में जीएसटी के प्रस्तावित प्रारंभ के विशेष प्रतिनिर्देश से)” विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम की मेजबानी आईसीएआई की एनआईआरसी ने की थी।

यह एक कराधान नीति संबंधी कार्यक्रम था, जिसमें इस क्षेत्र में संस्थान के नेतृत्व को उपदर्शित किया गया था। इस संगोष्ठी में नीति निर्माताओं, राज्य सरकारों के वेट विभागों के पदाधिकारियों, एसोचेम, फिक्की, पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स और इंडियन मर्चेन्ट चैम्बर्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

डॉ. शोम, जो एचएमआरसी, यूके के प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं और जो उससे पहले वित्त मंत्री के सलाहकार थे, को विशेष रूप से इस संगोष्ठी के लिए आमंत्रित किया गया था।

श्री पी.सी.आ, अध्यक्ष, सीबीईसी उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे, इस संगोष्ठी का उद्घाटन अध्यक्ष, आईसीएआई द्वारा किया गया था और आईसीएआई के उपाध्यक्ष ने इस कार्यक्रम में विशेष संबोधन प्रस्तुत किया था। भाग लेने वाले व्यक्तियों ने इस संगोष्ठी की अत्यधिक सराहना की थी और यह एक सफल आयोजन था।

5.23.11 प्रकाशन

“ए गाइड टू सेनबेट क्रेडिट्स” का प्रकाशन किया गया है। यह आशा की जाती है कि यह काफी सीमा तक अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले सदस्यों की सहायता करेगी।

5.23.12 आईडीटी नेट

अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में व्यवसायरत या कार्यरत सदस्यों के लिए एक नेटवर्किंग पोर्टल, आईडीटी नेट का सृजन किया गया था और उसे संस्थान की वेबसाइट के साथ अपलिक किया गया था। अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले अधिकाधिक

सदस्य आईडीटी नेट पर रजिस्टर हो रहे हैं।

5.24 परिप्रेक्ष्य योजना समिति

परिप्रेक्ष्य योजना समिति आईसीएआई की एक अस्थायी समिति है, जिसे भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गठित किया गया है ताकि तेजी से बदलती विश्व व्यापार परिस्थिति में एक दृढ़ और सकारात्मक उद्योग को प्रस्तुत करने में समर्थ हो सके। भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिससे कि तेजी से बदलती विश्व व्यापार परिस्थिति में एक दृढ़ और सकारात्मक उद्योग को प्रस्तुत करने में समर्थ हो सके, परिप्रेक्ष्य योजना समिति ऐसी सभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर विचार करती है, जो वृद्धि के लिए अभिनिश्चित विनियमित क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं और वह इसके अतिरिक्त ऐसे नए मुद्दों को प्रस्तुत करके, जिनपर वृत्ति द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, अविनियमित क्षेत्र में चार्टर्ड एकाउंटेंसी वृत्ति की भूमिका का संवर्धन करने के लिए पद्धतियों और उपायों का सुझाव देती है। समिति को 'वह व्यक्ति जो आज तैयार नहीं है, कल बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा' मुहाबरे में यथापरिकल्पित उद्देश्य के साथ गठित किया गया था।

परिप्रेक्ष्य योजना समिति को, ऐसी उभरती हुई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं, जो वृत्ति के लिए बनाए गए विनियमित क्षेत्रों पर प्रभाव डाल सकती हैं, पर विचार करने के लिए और गैर-विनियमित क्षेत्रों में चार्टर्ड एकाउंटेंसी वृत्ति की भूमिका का संवर्धन करने के लिए मार्गों और उपायों का सुझाव देकर उसे और संपूरित करने संबंधी एक सक्रिय उपाय के रूप में सृजित किया गया था।

5.24.1 समिति द्वारा यथापरिकल्पित कार्ययोजना में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- वृत्ति की सक्षमता में वृद्धि करना और वृत्ति को वैश्विक अनिवार्यताओं के साथ अधिकाधिक रूप से एकीकृत करना।
- गुणवत्ता को बनाए रखते हुए वृत्ति के विकास के लिए योजना बनाना।
- राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी भूमिका में संस्थान और वृत्ति को तैयार करना।
- अनुसंधान क्रियाकलापों पर जोर देना।
- समर्थनकारी संस्थागत और संगठनात्मक ढांचा तैयार करना।

समिति के कार्यक्षेत्र सतत प्रकृति का है और इसके लिए हाल की घटनाओं पर विचार करना और उन्हें परिचर्चा और वाद-विवाद के लिए समिति की सूचना में लाना आवश्यक है। समिति मामला दर मामला आधार पर घटनाओं का निर्धारण करती है और सभी परिषद् सहयोगियों और साधारण सदस्यों से सहबद्ध होने और सहयोग करने का अनुरोध करती है जिससे कि ऐसी घटनाओं, जिनका वृत्ति के आयामों पर नकारात्मक प्रभाव है, को समुचित संसूचना/संपर्क कार्य से अकृत किया जा सके और साथ ही विद्यमान रूप से उपलब्ध विनियामक प्रोफाइल का संवर्धन किया जा सके।

समिति मुख्यतः एक अनुसंधान और विश्लेषण खंड के रूप में कार्य करती है और वह परिषद् तथा वृत्ति के मस्तिष्क, आंखों - कानों की भूमिका निभाती है।

विश्वभर में होने वाली घटनाओं से लेखांकन वृत्ति को अध्ययन बनाने के लिए और पूरे विश्व में एकाउंटेंटों के लिए एक परस्पर क्रिया मंच उपलब्ध कराने के लिए समिति ने दिसम्बर मास में निम्नलिखित विषयों पर दो अखिल भारतीय हीरक जयंती सम्मेलनों का आयोजन किया था :

- “आईसीएआई@ 60 - चुनौतियाँ और अवसर” इसका आयोजन 13 और 14 दिसम्बर, 2008 को आईसीएआई की ईआईआरसी की गुवाहाटी शाखा द्वारा किया गया था। इसमें उद्योग और विनियामकों के गणमान्य वक्ताओं ने भाग लिया था और उन्होंने अपने ज्ञान की लेखांकन बिरादरी के साथ साझेदारी की थी। लगभग 540 सदस्यों, जिसमें 95 छात्र भी सम्मिलित थे, ने इस सम्मेलन में भाग लिया था।
- “लेखांकन वृत्ति के उभरते प्रतिमान” इसका आयोजन 13 और 14 दिसम्बर, 2008 को आईसीएआई की एसआईआरसी की हैदराबाद शाखा द्वारा आईसीएआई के हीरक जयंती वर्ष समारोह के भाग रूप में किया गया था। यह सम्मेलन अत्यधिक सफल रहा था और इसमें 1800 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जिसमें वृत्ति के सदस्य और अन्य पणघारी सम्मिलित थे।

समिति ने, लेखांकन वृत्ति में हो रहे बहु आयामी परिवर्तनों, चाहे वे वृत्ति में हों या व्यवसाय में, का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण कार्यों का आयोजन किया था, जिसके लिए उसने: “लेखांकन वृत्तियों के लिए सक्षमता का पता लगाना” और “सदस्य फर्मों के संदर्भ में वृत्ति का बदलता प्रोफाइल” पर दो प्रश्नोत्तर जारी किए थे। इन सर्वेक्षणों का आशय दक्षता/कौशल के ऐसे सेट, जिसे किसी नए सीए के पास होना चाहिए, के निर्बंधानुसार विशेष आवश्यकताओं पर व्यवसायियों और उद्योग परिप्रेक्ष्य की पहचान करना और वृत्ति में लगे चार्टर्ड एकाउंटेंटों पर क्रमशः उन्हें सौंपे गए कार्यों के संबंध में उनकी सक्षमता निर्माण और सीए वृत्ति की ब्रांड छवि का संवर्धन करने के संबंध में ध्यान केन्द्रित करना है। समिति को इन प्रश्नोत्तरों पर उत्साहजनक प्रत्युत्तर प्राप्त हुए थे जिनकी संख्या लगभग 10000 हजार थी। समिति ने उक्त विषयों के संबंध में अपनी दो सर्वेक्षण रिपोर्टें जारी की हैं जिन्होंने अन्य बातों के साथ परिषद् को अपनी भावी कार्य योजना बनाने में सहायता की थी।

5.24.2 समिति ने अभी तक निम्नलिखित क्षेत्रों में आईसीएआई की विभिन्न समितियों को अपनी बैठकों से उदभूत होने वाली 30 घटनाएं निर्दिष्ट की हैं :

- उद्योग के लिए कार्यशाला मॉड्यूल/कार्यक्रम तैयार करना ।
- अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रमुख संस्थानों के साथ सहब्रांडिंग करने के लिए समझौते करना ।
- बाजार वास्तविकताओं से संगत अर्हतापत्र पाठ्यक्रम ।
- अत्यावधि के अपने स्वयं के प्रमाणन कार्यक्रम विकसित करना ।
- लागत लेखा मानकों को पुनरीक्षित करने के लिए पैनल ।
- राष्ट्रीय कर अपील अधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण की स्थापना ।
- आईपीओ लाने के समय व्युत्पत्ति हानियों का प्रकटन और सेंसेक्स में गिरावट ।
- आईसीडब्ल्यूआई लेखांकन तकनीशियन पाठ्यक्रम ।
- संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनियम को “वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार” विषय पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट ।
- निगम शासन के संबंध में ईयू पद्धति पर रिपोर्ट ।
- “सतत वृत्तिक विकास (सीपीडी) मापमान के संबंध में पद्धति” पर आईएफएसी सूचना पत्र (जून, 2008) ।
- कृषि - सीए के लिए एक नया क्षेत्र ।
- सीईएसआर बाजार की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने के लिए उपाय करता है ।
- तीन देशों के लेखांकन मानक निर्धारकों की पांचवीं बैठक का एमओयू ।
- आईएफएसी अंतरराष्ट्रीय आचार मानक बोर्ड द्वारा एकाउंटेंटों के लिए जारी नीतिगत और प्रचालनात्मक योजना ।
- एसीए के सर्वेक्षण एफडी की भूमिका के मर्मस्थल पर नेतृत्व और वाणिज्यिक कौशलों को प्रकट करते हैं ।
- संपरीक्षा फर्म शासन कार्यकारी समूह के संबंध में आईसीआईडब्ल्यू की उदघोषणा ।
- यूके के एफआरआरपी द्वारा निगम रिपोर्टिंग की चुनौतियों के संबंध में गतिविधि रिपोर्ट ।
- पिरोन शिक्षा और आईसीएफएआई द्वारा सीपीए कार्यक्रम का प्रारंभ ।
- न्यायिक संपरीक्षा का एक वृत्तिक क्षेत्र के रूप में उभरना ।
- आईटी विभाग, मुंबई द्वारा तीन मास में किए गए 1000 सर्वेक्षणों पर प्रेस विज्ञप्ति ।
- चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए समूह पेंशन स्कीम ।
- आर्थिक मंदी के अल्प/मध्यम/दीर्घकालिक प्रभाव पर जी-20 शिखर सम्मेलन की रिपोर्ट ।
- उपांतरित प्रमाणन पाठ्यक्रम के माध्यम से सीए सदस्यों के लिए वर्टिकल आधारित विशेषज्ञता ।
- वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर डॉ० राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट का प्रभाव ।
- वित्तीय क्षेत्र के निर्धारण पर योजना आयोग की रिपोर्ट का प्रभाव ।
- तृतीय देश संपरीक्षकों के संबंध में यूरोपीय आयोग का विनिश्चय ।
- विदेश में प्रशिक्षित आर्टिकलसीप का शिथिलीकरण ।
- उत्तम विनियमन और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने संबंधी जी-20 कार्यकारी समूह की रिपोर्ट ।

6. अंतरराष्ट्रीय कार्य समिति

6.1 अन्य लेखांकन निकायों द्वारा भारतीय अर्हता को मान्यता

चयनित विदेशी लेखांकन निकायों द्वारा संस्थान की अर्हताओं के मूल्यांकन के लिए उनके साथ निरंतर संवाद की प्रक्रिया का तेजी से चलते रहना ताकि विदेशी निकायों की अर्हता का भाग बनने वाले प्रशिक्षण और परीक्षा से संस्थान के सदस्यों को छूट प्राप्त हो जाए । लंबी प्रक्रिया होने के कारण, जिसमें अर्हता, प्रशिक्षण, सतत वृत्तिक शिक्षा और अनुशासनात्मक अपेक्षाओं का मूल्यांकन और देशीय संवेदनशीलताएं भी अंतर्बलित हैं, प्रक्रिया के परिणाम धीमे हैं, फिर भी संस्थान अपने प्रयासों से इसे शीघ्र ही समाप्त करने के लिए सक्रिय है । संस्थान ने इंग्लैंड और वेल्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान और जीबूटी विश्वविद्यालय के साथ परस्पर समझ ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे । सीपीए, आस्ट्रेलिया के साथ परस्पर मान्यता कशर (एमआरए) पर

भी हस्ताक्षर किए गए हैं। अर्हता मान्यता की प्रक्रिया कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, आयरलैंड आदि के लेखांकन निकायों के साथ चर्चा के विभिन्न प्रक्रमों पर है।

6.2 अंतरराष्ट्रीय मंचों में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व

आईसीएआई द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण उसके अंतरराष्ट्रीय लेखांकन निकायों अर्थात् इंटरनेशनल फेडरेशन आफ एकाउन्टेन्ट्स (आईएफएसी), कन्फडरेशन ऑफ एशियन एंड पैसिफिक एकाउन्टेन्ट्स (सीएपीए) और साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ एकाउन्टेन्ट्स (एसएएफए) की विभिन्न कृत्यकारी समितियों के अलावा उनके शासन बोर्डों में नामनिर्देशन से मिलता है। इस समय आईसीएआई का प्रतिनिधि एसएएफए के अध्यक्ष का पद धारित किए हुए है। निम्नलिखित में इसके नामनिर्देशित प्रतिनिधित्व करते हैं :-

आईएफएसी की समितियां

- बोर्ड सदस्य के रूप में
- लघु और मध्यम प्रेक्टीशनर समिति
- विकासशील राष्ट्र समिति
- आईएफएसी अनुपालन सलाहकार पैनल

सीएपीए

- अध्यक्ष के रूप में
- बोर्ड सदस्य के रूप में

एसएएफए

- बोर्ड सदस्य के रूप में
- शिक्षा, प्रशिक्षण और सीपीडी संबंधी समिति
- लेखांकन और लेखांकन मानकों संबंधी समिति
- वृत्तिक आचार संहिता और स्वतंत्रता संबंधी समिति
- पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन में सुधार संबंधी समिति
- कारबार में वृत्तिक एकाउन्टेन्टों संबंधी समिति
- क्वालिटी नियंत्रण संबंधी समिति
- लघु और मध्यम व्यवसायियों संबंधी समिति
- वित्तीय और टैरिफ व्यवस्था के सुव्यवस्थीकरण संबंधी समिति
- एसएएफए संविधान के पुनर्विलोकन के लिए कार्यबल
- अध्यक्ष, आईसीएआई, बोर्ड सदस्य के रूप में
- सचिव, स्थायी सचिव के रूप में

6.3 एमओयू/एमआरए

आईसीएआई ने 18-19 मई, 2009 के दौरान मुंबई में अफ्रीका दिवस समारोह के उपलक्ष्य में 18 मई, 2009 को जिबूटी विश्वविद्यालय, जिबूटी गणराज्य के साथ परस्पर समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस एमओयू पर जिबूटी राष्ट्रीकों को लेखांकन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने और जिबूटी में लेखांकन निकाय को संस्थागत बनाने के लिए परस्पर सहयोग से कार्य करने हेतु हस्ताक्षर किए गए थे।

आईसीएआई ने 3 फरवरी, 2009 को प्रमाणित लोक एकाउन्टेन्ट्स, आस्ट्रेलिया के साथ परस्पर मान्यता करार पर हस्ताक्षर किए थे जिससे कि एक दूसरे की अर्हता, प्रशिक्षण को मान्यता प्रदान की जा सके और एक सेतू तंत्र विहित करके अच्छी छवि वाले सदस्यों को प्रवेश दिया जा सके और साथ ही दोनों ओर से वृत्तिकों के आदान-प्रदान में वृद्धि की जा सके।

संस्थान ने इंग्लैंड और वेल्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान के साथ 20 नवम्बर, 2008 को एक परस्पर समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे ताकि दो निकायों के बीच कार्यकारी संबंधों को मजबूत किया जा सके। इस एमओयू में विश्व के दो सबसे बड़े संस्थानों के सदस्यों के लिए परस्पर मान्यता और परीक्षा व्यवस्थाओं के लिए उपबंध किया गया था।

6.4 विदेशों में चैप्टर प्रारंभ करना

आईसीएआई ने अपना 20वां चैप्टर न्यूयार्क, यूएसए में 24 जुलाई, 2008 को खोला।

आईसीएआई ने सिंगापुर में अपने 21वें चैप्टर को खोलने के लिए अनुमति प्रदान की थी, इसे शीघ्र ही कार्यरत बनाए जाने की संभावना है।

आईसीएआई आयरलैंड और थाईलैंड में अने चैप्टर खोलने के लिए वार्ताएं कर रही है।

6.5 भारत आने वाले प्रतिनिधिमंडल

2 अप्रैल, 2008 को एएमएफ फ्रांस से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

श्री हर्बर्ट रेनियर, प्रबंध निदेशक, विनियामक नीति और अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रभार, एएमएफ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने श्री पेट्रिस एग्विसी, अध्यक्ष, वित्तीय प्रकरणों और कारपोरेट वित्त पोषण का विनियमन, एएमएफ और श्री पेट्रिक पेरेंट, उपाध्यक्ष, कारपोरेट लेखांकन और संपरीक्षा प्रभाग एएमएफ के साथ, भारत में लेखांकन मानकों और संपरीक्षा निरीक्षणों के प्रवर्तन पर परस्पर विचार करने के लिए 2 अप्रैल, 2008 को आईसीएआई का दौरा किया। उनके साथ श्री जितेश खोसला, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, सुश्री नीलम भारद्वाज, महाप्रबंधक, इश्युज और लिस्टिंग प्रभाग, सेबी और श्री नितेश भाटी, प्रबंधक, इश्युज और लिस्टिंग प्रभाग, सेबी ने भी इस बैठक में भाग लिया था। बेहतर सहयोग और उचित तथा पारदर्शी बाजार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फरवरी, 2008 में एएमएफ और सेबी के बीच हस्ताक्षरित किए जाने वाले निर्देश निबंधनों के संबंध में सूचना मांगी गई थी। इस बैठक में दोनों अर्थव्यवस्थाओं की आईएफआरएस और आईएस के साथ समतुलना करने की प्रक्रिया के संबंध में एक समान समझ पर बल दिया गया था।

3 और 4 अप्रैल, 2008 को आईएफआरएस प्रशिक्षण के लिए मंगोलियन एकाउंटेंटों का दौरा

आईसीएआई और सीपीए, मंगोलिया ने, दोनों संस्थानों के बीच परस्पर हित और सहयोग का संवर्धन करने के लिए 11 सितम्बर, 2006 को द्विपक्षीय सहयोग पर परिचर्चा ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तब से, सीपीए - मंगोलिया अपने एकाउंटेंटों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (कार्यक्रमों) का आयोजन करने के लिए आईसीएआई साथ सम्पर्क में है। सीपीए, मंगोलिया के अनुरोध पर, 3 और 4 अप्रैल, 2008 को आईसीएआई द्वारा उनके 10 प्रतिनिधियों के लिए आईएफआरएस में प्रशिक्षण के दूसरे सत्र का आयोजन किया गया था।

20-21 अप्रैल, 2008 के दौरान लॉर्ड मेयर का दौरा

श्री एल्डरमैन डेविड लुईस एमए, लंदन नगर के माननीय सेवानिवृत्त मेयर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने इयान लुडर, लंदन नगर के शेरिफ, श्री मार्टिन हेगन, उपाध्यक्ष आईसीएआईडब्ल्यू, सुश्री जेन ओदन, निदेशक, यूके व्यापार और निवेश, श्री जेफ ग्लेकिन, उपाध्यक्ष, मुम्बई मिशन और श्री ग्राहम वार्ड, अध्यक्ष, इंडो-यूके लेखांकन कार्यबल में यूके पक्ष के साथ 21 अप्रैल, 2008 को आईसीएआई का दौरा किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत और यूके लेखांकन वृत्ति के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना था। प्रतिनिधियों ने "सीमित दायित्व भागीदारी विधेयक", एलएलपी का कराधान, क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की भूमिका और भारतीय संदर्भ में संपरीक्षकों के चक्रानुक्रम की प्रारिथिति पर जानकारी मांगी थी। आईसीएआई ने प्रतिनिधिमंडल को उपरोक्त मुद्दों के संदर्भ में भारतीय परिस्थितियों से अवगत कराया था। इसके अतिरिक्त, आईसीएआई और आईसीएआईडब्ल्यू के बीच एमआरए के लिए जारी वार्तालाप की अद्यतन स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया था।

2 मई, 2008 को समारा क्षेत्र, रूस से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एकाउंटेंट्स, समारा रिजन (एसआईपीए), रूस से एक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें श्री दमित्री याकोवेंको, अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एकाउंटेंट्स, समारा रिजन, श्री यूरी बोडरोव, बोर्ड के सदस्य और श्री एलेक्जेंडर शेस्टकोव, अध्यक्ष के सहायक ने 22 मई, 2008 को आईसीएआई का दौरा किया था। अध्यक्ष, एसआईपीए ने अपने संस्थान की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त व्यौरा प्रस्तुत किया था और उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की थी कि दोनों देशों को एक साथ आने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने यह सूचित किया था कि उन्हें आईएफआरएस पर वृत्तिक प्रमाणन एकाउंटेंट पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए यूके, अजरबैजान जैसे विभिन्न देशों से सहायता प्राप्त हुई थी। आईसीएआई के अध्यक्ष ने भी विनियामक ढांचे, लेखांकन मानकों आदि पर बल देते हुए भारत में लेखांकन वृत्ति का साधारण पर्यावलोकन प्रस्तुत किया था।

एसआईपीए ने जोखिम प्रबंध और बीमा के क्षेत्रों में आईसीएआई के सहयोग की वांछा की थी, जिसके प्रत्युत्तर में आईसीएआई ने यह कथन किया था कि उसने इन विषयों में विशेषज्ञता विकसित की है और आईसीएआई के पास इस विषय पर एक पृथक समिति है और एक अन्य अर्हतापत्र पाठ्यक्रम है।

वृत्तिक अर्हताओं को परस्पर मान्यता देने संबंधी करार की संभाव्यता के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई थी, जिसमें आईसीएआई ने इस बात को अनिवार्य रूप से रखा था कि उन्हें भी वैसा व्यवहार दिया जाए जो सीपीए, अमेरिका को दिया जा रहा है।

25 जुलाई, 2008 को यूरोपीय प्रतिभूति विनियामकों की समिति से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

यूरोपीय प्रतिभूति विनियामकों की समिति से श्री ली दिल्लर और सुश्री मेरियन बूगेल ने संस्थान और आईसीएआई का दौरा किया था। इस दौरा का मुख्य उद्देश्य भारत में लेखांकन मानकों को समझना और भारत में आईएफआरएस के साथ अभिसरन

के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था।

7 अक्टूबर, 2008 को कीनिया राष्ट्रीय लेखाकार और सचिव परीक्षा बोर्ड (केएएसएनईबी) द्वारा परामर्शों दौरा

कीनिया राष्ट्रीय लेखाकार और सचिव परीक्षा बोर्ड (केएएसएनईबी) के लेन्वा जेरेमिया एम, परीक्षा अधिकारी और सेजमेरी के.ए. बरासा, वरिष्ठ अधिकारी, मानव संसाधन प्रबंध और प्रशासन ने आईसीएआई और ऐसे अन्य संस्थानों की पाठ्यचर्या के अपने पुनर्विलोकन में सम्मिलित किए जाने वाले परीक्षा विषयों पर परामर्श करने के लिए आईसीएआई का दौरा किया था। इस पुनर्विलोकन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा पाठ्यचर्याएं बाजार मांगों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनी रहें।

7 नवम्बर, 2008 को यूके की विसीय स्पोर्टिंग परिषद् के प्रतिनिधिमंडल का दौरा

श्री पॉल बोएल, मुख्य कार्यपालक, यूके केएफआरसी ने आईसीएआई का दौरा किया था और एफआरसी द्वारा लेखांकन वृत्ति के विनियमन में निभाई जा रही भूमिका पर विचार-विमर्श किया था।

नवम्बर, 2008 से जनवरी, 2009 के दौरान आईएफआरएस और इंगलिश प्रशिक्षण के लिए मंगोलियाई लेखाकारों का दौरा

अप्रैल, 2008 में सीपीए के मंगोलियाई संस्थान से मंगोलियाई प्रतिनिधिमंडल के दौरे के पश्चात् आईसीएआई ने 6 नवम्बर, 2008 से तीन मास के लिए मंगोलियाई लेखाकारों को इंगलिश और आईएफआरएस में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया था, जिसके लिए मंगोलिया में स्थित भारत के राजदूत ने आईसीएआई को अनुरोध किया था।

13 अप्रैल, 2009 को श्री लेले हैंडफील्ड, कनाडा का प्रमाणित साधारण लेखाकार संघ का दौरा

श्री लेले हैंडफील्ड, उपाध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय और कारपोरेट कार्य और श्री बलदेव, उपाध्यक्ष, वित्त और प्रशासन, कनाडा का प्रमाणित साधारण लेखाकार संघ ने परस्पर मान्यता करार करने के लिए आईसीएआई और सीजीए कनाडा के बीच द्विपक्षीय बातचीत पर विचार-विमर्श करने के लिए आईसीएआई का दौरा किया था।

8 जून से 10 जून, 2009 के दौरान कनाडियाई चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

सीए जिलन खलील, निदेशक सीए अर्हता की अगुवाई में कनाडियाई चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान से एक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें सीए पाले मेसीकोट, प्रधानाचार्य, सीए अर्हता भी सम्मिलित थे, दोनों संस्थानों के बीच वृत्तिक अर्हता के आपसी मान्यता करार की संभावनाओं पर गहन विचार-विमर्श करने के लिए आईसीएआई का दौरा किया था।

30 जून, 2009 को अमरीकी सीपीए संस्थान से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

श्री अर्नी एलमोंट, अध्यक्ष, एआईसीपीए ने, आगरा में आईसीएआई के हीरक जयंती अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रमुख भाषण देने के लिए 30 जून, 2009 से 04 जुलाई, 2009 के दौरान भारत का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान, उन्होंने सीएडएजी, सीजीए, वित्त मंत्रालय और कारपोरेट कार्य मंत्रालय से भी बैठकें की थी।

अफ्रीका दिवस समारोह

आईसीएआई और भारतीय-अफ्रीकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 18-19 मई, 2009 के दौरान मुंबई में अफ्रीका दिवस मनाया था। अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों के राजनयिक अफ्रीका के विकास के लिए कार्य रणनीति तैयार करने के लिए एकत्रित हुए थे। राजयिकों ने अफ्रीका महाद्वीप के विकास के लिए भारत के प्रयासों की प्रशंसा की थी और यह विश्वास अभिव्यक्त किया था कि भारत और अफ्रीका के बीच यह प्रगतिशील संबंध नई उंचाईयां छुएंगे।

इन संबंधों के संवर्धन के उपलक्ष्य में, आईसीएआई और जीबूटी विश्वविद्यालय के बीच, जीबूटी राष्ट्रियों को लेखांकन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने और जीबूटी में लेखांकन त्रिकाय के संस्थाकरण हेतु एक साथ कार्य करने के लिए एक परस्पर समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। माननीय श्री एस.सी.जमीर, राज्यपाल, महाराष्ट्र, माननीय श्री मुसलिया मुदावाडी, केन्या के उप प्रधानमंत्री और श्री जयंतराव पाटिल, गृह मंत्री, महाराष्ट्र सरकार ने इस समारोह की शोभा बढ़ाई थी।

एक अंतरराष्ट्रीय लेखांकन तकनीशियन फेडरेशन (आईएफएसी की तर्ज पर) की स्थापना

आईसीएआई पूरे विश्व में लेखांकन तकनीशियन की वृत्ति का संवर्धन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय लेखाकार फेडरेशन (आईएफएसी) की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय लेखांकन तकनीशियन फेडरेशन (आईएफएसी) की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। आईएफएसी का उद्देश्य क्वालिटी लेखांकन शिक्षा, प्रशिक्षण, नैतिक अपेक्षाओं, सीपीएडी, अनुशासनात्मक अपेक्षाओं और वृत्ति को दूर तक ले जाने संबंधी ऐसे क्रियाकलापों के माध्यमों से, जो पूरे विश्व के सभी मण्डलियों की आवश्यकताओं को पूरा करे, एक अर्द्ध-कौशल प्रमाणन के रूप में लेखांकन वृत्ति को विकसित करने और मजबूत बनाने के लिए उचित उपलब्ध कराना है।

भारत सरकार द्वारा गठित विशेष समूहों को योगदान

आईसीएआई सक्रिय रूप से क्रमशः वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के संस्वावधान में गठित विशेष कार्य बलों, अर्थात्, भारतीय-यूके लेखांकन कार्यबल और कारपोरेट कार्य संबंधी भारतीय-यूके कार्यबल के क्रियाकलापों में भाग लेता है और योगदान करता है।

6.6 सम्मेलन**बीआरआईसी सम्मेलन में भाग लेना**

अध्यक्ष, आईसीएआई ने आईसीएआई के उपाध्यक्ष और सचिव के साथ 19 मई, 2008 को न्यूयार्क में बीआरआईसी मंच (संगोष्ठी) को संबोधित किया था, जिसमें 20 से अधिक वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों और लेखांकन वृत्ति और विनियामक निकायों के नेताओं ने आईएफएसी के अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाने की प्रक्रिया में हुई घटनाओं और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए भाग लिया था। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय से श्री शंकर नारायण, प्रधान महालेखाकार ने भी इस बड़े मंच में भाग लिया था।

02-03, जुलाई, 2008 के दौरान “ चार्टर्ड एकाउंटेंसी इन रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट” विषय पर हीरक जयंती अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

हीरक जयंती समारोहों के उपलक्ष्य में 2 और 3 जुलाई, 2008 के दौरान “ चार्टर्ड एकाउंटेंसी इन रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट” विषय पर एक दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट समुदाय के 1000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें साफा देशों से 50 सदस्य, विनियामक और बहुपक्षीय अभिकरणों, अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारक निकायों और सार्क क्षेत्र के लेखांकन निकायों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। आईसीएआई ने साफा बैठकों की मेजबानी की थी। हीरक जयंती समारोहों का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के शुभ हाथों से हुआ था। भारत के माननीय वित्त मंत्री, श्री पी. चिदंबरम ने भी हीरक जयंती समारोहों में भाग लिया था। माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री पी.सी. गुप्ता और राज्य सभा के उपसभापति श्री रहमान खान ने की। जुलाई, 2008 को श्रोताओं को संबोधित किया था। मुख्य महा पोस्टमास्टर ने इस अतिस्मरणीय अवसर पर एक विशेष लिफाफा भी जारी किया था।

20-22 नवम्बर, 2008 के दौरान जयपुर में “ लेखांकन वृत्ति-वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक रौशन सेतू” विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान ने 20-22 नवम्बर, 2008 के दौरान जयपुर में “ लेखांकन वृत्ति-वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक रौशन सेतू” विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इस तीन दिवसीय आयोजन में, विख्यात लेखांकन विशेषज्ञों, वित्त के क्षेत्र में बड़े नामों और बड़े उद्योगपतियों के बीच, विश्वभर के 2400 से अधिक सीए प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक अद्वितीय मंच उपलब्ध कराया था। इस आयोजन में, अंतरराष्ट्रीय लेखाकार फेडरेशन (आईएफएसी), एशियाई और प्रशांत लेखाकार कंफेडरेशन (कापा), अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएसबी) और व्यापार तथा उद्योग के नेताओं सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों से लेखांकन, संपरीक्षा और प्रबंध के क्षेत्र के विख्यात विशेषज्ञ एक साथ आए थे और उन्होंने सम्मेलन को गौरवान्वित किया था। मुख्य अतिथि संघ के माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री श्री प्रेम चंद गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया था। आईसीएआई ने कापा और साफा बैठकों की मेजबानी की थी।

7. अन्य गतिविधियां**7.1 मानव संसाधन विकास**

किसी संगठन का विकास के नए दौर में स्थापित करने के लिए, उस संगठन के लिए यह आवश्यक है कि उसके पास ईमानदार, समर्पित और सक्षम मानव संसाधन हों। इस मद्दे परियुक्त ने न केवल अपना ध्यान अपने उच्च कार्यनिष्पादन करने वाले कार्य बल को अपने पास बनाए रखने पर केन्द्रित करना जारी रखा, अपितु इस क्षेत्र के सर्वोत्तम और सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को संगठन में लाने के लिए उपाय प्रारंभ किए। इस तथ्य को मान्यता प्रदान करते हुए भी प्रशिक्षण, सक्षमता के स्तर में वृद्धि और व्यक्तित्व के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है, आईसीएआई के परिसरों के भीतर और बाहर आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में भागीदारी करने पर जोर देना जारी रखा।

कौशल और ज्ञान में और अधिक वृद्धि करने तथा सदस्यों, छात्रों तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों को क्वालिटी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संस्थान में व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए संस्थान के दिल्ली स्थित मुख्यालय और अन्य प्रादेशिक कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर ढांचागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

रिपोर्ट की अवधि के अंतिम छह मास के दौरान क्षेत्र की सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संकाय/शिक्षण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए समयबद्ध भर्ती कार्यक्रम चलाए गए थे। इस प्रकार की गई पहलों से वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं और 131 से अधिक मानव संसाधनों को नियोजित किया गया है, जो आईसीएआई के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी/शैक्षणिक पदों के लिए हैं।

शिकायत समाधान, समय पर परामर्शी सेवाओं, विकसित प्रसुविधा प्रबंध आदि के उद्देश्य से रिपोर्ट की अवधि के दौरान की गई और मानव संसाधन पहलों में बेहतर और क्वालिटी संकर्म वातावरण, साप्ताहिक विभागीय बैठकें, आवधिक कर्मचारी परामर्शी सेवा, शिकायत समाधान तथा कठिनाइयों को दूर करने वाले उपायों के साथ नए मास की शुरुआत करना सम्मिलित है।

7.1.1 मानव संसाधन और प्रशासनिक समिति का गठन

परियुक्त की प्रत्येक समिति, कार्यालयों और विभागों में सही संख्या और सही प्रकार के कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए और

संस्थान की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए फरवरी, 2009 में पहली बार मानव संसाधन और प्रशासनिक समिति का गठन किया गया था। मानव संसाधन और प्रशासनिक समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :

1. परिषद की सभी समितियों और विभिन्न अवस्थानों पर अवस्थित संस्थान के कार्यालयों, प्रादेशिक कार्यालय, विकेन्द्रीकृत कार्यालयों और शाखाओं में पर्याप्त और गुणवान जनशक्ति सुनिश्चित करना।
2. कार्यभार के आधार पर सभी स्तरों (केन्द्रीय, प्रादेशिक और शाखा स्तर) पर जनशक्ति की अपेक्षा का निरंतर विश्लेषण करना और कार्मिकों की भर्ती और उन्हें एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उपाय करना।
3. संस्थान के मानव संसाधन और प्रशासनिक कृत्यों को शासित करना तथा उनकी मानीटरी करना।
4. संस्थान के साधारण प्रशासन और कार्मिक प्रवर्ग में सुधार करना।

मानव संसाधन और प्रशासनिक समिति की पहली बैठक 25 फरवरी, 2009 को की गई थी और समिति ने पहले ही अनेक पहलों की हैं।

7.1.2 मानव संसाधन और प्रशासनिक समिति का उपसमूह

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों से उद्भूत होने वाले/संबंधित विषयों को संस्थान के कर्मचारियों तक विस्तारित करने और अंतर्बलित-वर्तमान और पूर्वानुमान लगाई गई भावी वित्तीय विवक्षाओं के संबंध में आदर्श मत बनाने के विचार से 15 अप्रैल, 2009 को मानव संसाधन और प्रशासनिक समिति के उपसमूह का गठन किया गया था।

मानव संसाधन और प्रशासनिक समिति के उपसमूह की पहली बैठक 10 मई, 2009 को हुई थी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम - अप्रैल, 2008 से आगे

क्रम सं.	कार्यक्रम तारीख	अवधि (दिन/घंटें)	शीर्षक	भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या	मानव घंटों की संख्या= (भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या x प्रशिक्षण दिवसों की संख्या x प्रत्येक दिवस में घंटों की संख्या)
प्रधान कार्यालय					
01.	28.04.08 से 02.05.08	5 दिन	प्रवेश करने वाले नए प्रबंध प्रशिक्षुओं के लिए अनुकूलन कार्यक्रम	50	50x5x8= 2000
कोलकाता कार्यालय					
01.	07.05.08 से 09.05.08 और 12.05.08 से 16.5.08	8 दिन	विभिन्न विभागों के साथ अनुकूलन और व्यक्तित्व विकास	8	8x8x8= 512
कानपुर कार्यालय					
01.	04.04.08	2 घंटे	विभिन्न विभागों के विभिन्न अधिकारियों द्वारा अध्यक्ष, सीआईआरसी	सभी कर्मचारिवृंद	
02.	17.04.08	2 1/2 घंटे	बाहरी सकांय द्वारा स्वअंतर्गमन के माध्यम से व्यक्तिगत विकास	सभी कर्मचारिवृंद	
03.	19.04.08 से 12.04.08, 21.04.08 से 25.04.08 और 30.04.08 से 12.05.08	15 दिन	प्रवेश करने वाले नए प्रबंध प्रशिक्षुओं और डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए अनुकूलन कार्यक्रम	7	15x7x8= 840

04.	07.06.08	2 घंटे	विभिन्न विभागों पर कार्यक्रम: विभिन्न भूमिकाएँ (एफएक्यू- सीपीटी-पीसीसी)	सभी कर्मचारिवृंद	
-----	----------	--------	---	------------------	--

7.1.3 मानव संसाधन और प्रशासनिक समिति की उपलब्धियाँ

अद्वितीय और अपनी तरह की प्रथम मानव संसाधन और प्रशासनिक समिति का सृजन

मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में संस्थान की विनिर्दिष्ट और विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन और प्रशासनिक समिति नामक एक नई समिति का गठन करके वर्ष 2009 में एक अद्वितीय और अपनी तरह की प्रथम पहल की गई थी। इसके प्रारंभ से ही समिति ने विभिन्न पहलों की थी और उपलब्धियाँ दर्ज की थीं। उदाहरण के लिए उसके महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में से कुछ नीचे प्रस्तुत हैं :

संगठनात्मक पुनःसंरचना

आधुनिक प्रबंध अवधारणाओं के अनुरूप एक अद्वितीय, साहसी, नवीन विचार को मानवीय इंजीनियरी के रूप में परिवर्तित किया गया, लागू किया गया था जिसके कार्यान्वयन द्वारा संस्थान के विभाग आधारित कार्यकरण को प्रतिस्थापित करके उसे एक सक्रिय, समिति आधारित जीवंत संगठन बनाया गया था। परिणाम अत्यंत उत्साहवर्धक रहे हैं और अतिमहत्वपूर्ण रूप से मूर्त तथा माये जाने योग्य रहे हैं। संगठनात्मक पुनःसंरचना ने संस्थान के कार्यकरण में सक्रियता, परिणाम - उन्मुख होने, आशावाद और जीवन्तता की एक नई भावना फूंक दी है।

अतिरिक्त समितियों का सृजन

आज की अति सक्रिय वैश्वीकरण परिस्थितियों में वृत्ति की विकासशील आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उभरते क्षेत्रों की पहचान की गई है और सदस्यों के हितों की संरक्षा करने तथा नए अवसरों की पहचान करने के लिए नई समितियों का सृजन किया गया था, अर्थात् :

1. प्रतिनिधित्व समिति
2. मानव संसाधन और प्रशासनिक समिति
3. अंतरराष्ट्रीय करारनाम संबंधी समिति
4. लघु और मध्यम आकार के व्यवस्थापियों संबंधी समिति
5. अवसंरचना समिति

इन अतिरिक्त समितियों को अतिरिक्त मानव संसाधनों को भर्ती किए बगैर सृजित किया गया था और यह तथ्य अध्यक्ष के अद्वितीय और प्रातिष्ठान नेतृत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

कार्यपालकों का सशक्तिकरण

नई प्रतिभाओं को हैगार और विकसित करने तथा उनमें नई प्रेरणा और नए-नए विचार अंतर्निहित करने और साथ ही नेतृत्व की दूसरी पंक्ति तैयार करने के लिए उन्हें अनुभवप्राप्त सर्वोच्च प्रबंध के साथ सुमेलित करने के लिए एक नई, साहसी पहल की गई थी जिसके द्वारा युवा चार्टर्ड एमएलईए को विभिन्न समितियों के सचिवों के रूप में तैनात किया गया था, इस पहल के अविश्वसनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं।

जनशक्ति का विकास

विभिन्न विभागों और समितियों की विभिन्न विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को विचार में लेते हुए जनशक्ति योजना के लिए एक अद्वितीय कार्यक्रम आरंभ किया गया था और सदस्यों के अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्यपालकों को हैगार की गई है।

अतिरिक्त जनशक्ति की पहचान, प्रशिक्षण और नियुक्ति करना

उपलब्ध जनशक्ति में से कार्य और अतिरिक्त जनशक्ति को पहचान करने पर विशेष बल दिया गया था और ऐसी जनशक्ति को विशिष्ट रूप से प्रशिक्षण और सशक्तिकरण के संस्थान के माध्यम से कार्यपालकों के लिए फायदाप्रद रूप से पुनःनियोजित किया गया है।

घटक और निष्कर्ष

विभिन्न निष्कर्षों और समितियों के लिए अतिरिक्त जनशक्ति अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए गए थे।

जनशक्ति का सही प्रबंधन

बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए लागू निबंधन के द्वारा रूप में मानव संसाधन में अनावश्यक नियंत्रणों की पहचान करके और उन्हें समाप्त करके लघु प्रबंध अवधारणाओं को कार्य योजना में परिवर्तित किया जाता है।

कार्य जीवन की बेहतर गुणवत्ता

पदाधिकारियों को, नियोजन में उनकी दिलचस्पी के कृत्यकारी क्षेत्रों में तैनात करके उनके उत्साह में वृद्धि की गई है तथा उनमें नियोजन संबंधी संतुष्टि की भावना लाने के लिए पहल की गई है।

प्रशिक्षण और विकास

दूसरी त्रैमासिक अवधि के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनेक पहलें की गई थीं और प्रशिक्षण कलेण्डर के साथ एक कार्य योजना को निष्पादन हेतु तैयार किया गया है।

बेहतर महसूस करना और अपनत्व की भावना

बेहतर महसूस करने के अलावा अपनत्व की भावना का सृजन करने के लिए आधुनिक निगम सेक्टर की रूपरेखा पर संस्थान के पदाधिकारियों के लिए ड्रेस कोड प्रारंभ करने की एक नई पहल की गई है।

लेखांकन तकनीशियन पाठ्यक्रम के लिए नया विभाग

सृजनशील जनसंपर्क के माध्यम से लेखांकन तकनीशियन पाठ्यक्रम की छवि बनाने और उसका विपणन करने के लिए एक नए विभाग का सृजन किया गया है।

सुगम निगम संसूचना

पारंपरिक पैटर्नों के बंधनों को तोड़ते हुए, अध्यक्ष ने “सीधे संपर्क में रहें” - नामक एक नई, सृजनात्मक अवधारणा प्रारंभ की थी जिससे संस्थान के सभी पदाधिकारी किसी दिन किसी भी समय 24x7 सीधे अध्यक्ष से संपर्क, संसूचित करने और योजनाओं को कार्यान्वित करने में समर्थ हो सकें। इस अवधारणा के परिणामस्वरूप अनुमोदनों की प्राप्ति में शीघ्रता आई है, शीघ्र निर्णय सुकर बने हैं और परिणामोन्मुख “दक्ष, प्रभावी, उद्यमशील नेतृत्व” स्थापित हुआ है।

7.1.4 प्रशासन संबंधी क्षेत्र**आईटीटी प्रयोगशालाओं/शाखाओं के लिए डीजल जेनरेटर सेट का उपापन**

संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार, आ की तारीख तक शाखाओं द्वारा स्थापित भिन्न-भिन्न आईटीटी प्रयोगशालाओं के लिए अपेक्षा के अनुसार विभिन्न क्षमता के 68 डीजी सेटों के लिए आदेश दिए गए हैं, जिनमें उत्कृष्टता केन्द्र, हैदराबाद में अबाधित विद्युत प्राय के लिए 500 केवीए का डीजी सेट सम्मिलित है। अधिकांश स्थानों पर प्रतिष्ठापन और कार्य प्रारंभ करने संबंधी कार्य पूरा हो गया है और डीजी सेटों का उपयोग आरंभ कर दिया गया है। शेष स्थानों में यह कार्य जुलाई, 2009 के अंत तक प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, संस्थान के सीपीई चैप्टरों में स्थापित की रही/स्थापित की जाने वाली आईटीटी प्रयोगशालाओं में डीजी सेट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है और वह प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के विचाराधीन है।

जयपुर में उत्कृष्टता केन्द्र की आधारशिला रखने का समारोह

11.09.08 को जयपुर में संस्थान के उत्कृष्टता केन्द्र की आधारशिला संघ के तत्कालीन कारपोरेट कार्य मंत्री द्वारा मुख्य अतिथि, राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रखी गई थी। प्रस्तावित कैम्पस आवासीय किस्म का होगा और वह 25 एकड़ की भूमि में फैला होगा। वस्तुविद का अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है और संविदाकर के चयन के लिए प्रक्रिया की जा रही है।

आईसीएआई राष्ट्रीय सेवा स्कीम का चयन

27.01.2009 को आईसीएआई की राष्ट्रीय सेवा स्कीम को सुश्री आरती मेहरा, दिल्ली नगर निगम की मेयर की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया था जिसका उद्घाटन गांधी दर्शन के सामने जवाहर मार्ग पर पौधा रोपण करके/ फूलों की चादर बिछाकर किया गया था।

उत्कृष्टता केन्द्र, हैदराबाद का उद्घाटन

31.01.2009 को हैदराबाद में उत्कृष्टता केन्द्र (संस्थानिक ब्लॉक) का उद्घाटन किया गया था और इसके आवासीय खंड का उद्घाटन 2.7.2009 को किया गया था। यह कैम्पस 2.82 एकड़ के एक भूखंड पर निर्मित किया गया है।

संस्थान के कर्मचारियों के लिए एक समान ड्रेस कोड का कार्यान्वयन

संस्थान के प्रधान कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं के कर्मचारियों के लिए एक समान ड्रेस कोड के उपयोग को कार्यान्वित किया गया है।

लेखांकन संग्रहालय का उद्घाटन

प्राचीनतम तुलन पत्र जैसी दुर्लभ और ऐतिहासिक चित्रों तथा लेखांकन के विकास के दस्तावेजी साक्ष्यों से युक्त लेखांकन संग्रहालय का, जो संस्थान के सी-1, सेक्टर-1, नोएडा स्थित परिसर में अवस्थित है, 2.02.2009 को उद्घाटन किया गया था। भारतीय लेखांकन बोर्ड के कार्यवृत्त, परिषद् की पहली वार्षिक रिपोर्ट, संस्थान का अपना पहला तुलन पत्र आदि जैसी मूल्यों को प्रदर्शन के लिए रखा गया है। संग्रहालय का दौरा करने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। संग्रहालय के लिए

भारतीय लेखांकन संग्रहालय के नाम का उपयोग करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, खाद्य और लोक वितरण, भारत सरकार के तारीख 30.04.2009 के पत्र द्वारा मान्यता/अनुमति प्रदान की गई है।

पहुंच नियंत्रण प्रणालियों का प्रतिष्ठापन

प्रधान कार्यालय में पहुंच नियंत्रण प्रणालियों का प्रतिष्ठापन किया गया है और इसे कार्यरत बनाया गया है। शीघ्र ही ऐसी प्रसुविधाओं को प्रादेशिक कार्यालयों में कार्यान्वित किया जाएगा।

भांडागार मदों के उपभोग के लेखांकन संबंधी नीति का शुभारंभ

विभागों/अनुभागों द्वारा एचओ/अन्य भांडागारों से प्राप्त या किसी अन्य विभाग/अनुभाग से सीधे प्राप्त प्राप्त भांडागार मदों के उपभोग के समुचित लेखांकन के लिए दिशानिर्देश अधिकथित करने के विचार से, भांडागार मदों के उपभोग के लेखांकन संबंधी नीति को स्थापित किया गया था। इस नीति से प्राधिकारियों को यह आश्वासन प्रदान करना अपेक्षित है कि मदों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए और संगठन के व्यापक उद्देश्यों के अनुसार किया गया था, जिनके लिए उन्हें उपाप्त किया गया था। यह नीति आगे और यह सुनिश्चित करेगी कि संगठन को खर्ची जा रही निधियों से सर्वोत्तम आउटपुट प्राप्त हो।

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स दिवस समारोह

इस शुभ अवसर पर अध्यक्ष ने संस्थान के प्रधान कार्यालय में संस्थान का झंडा फहराया था और अध्यक्ष ने स्वर्गीय जी.पी.कापडिया, संस्थान के पहले अध्यक्ष की मूर्ति को माला पहनाई थी।

प्लॉट सं. ए-29, सेक्टर 62, नोएडा में आईसीएआई काम्पलेक्स के प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन

सीए दिवस के समारोहों के अवसर पर, अध्यक्ष ने 1 जुलाई, 2009 को प्लॉट सं. ए-29, सेक्टर 62, नोएडा में आईसीएआई काम्पलेक्स के प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन किया था, इस अवसर पर श्री अर्नेस्ट ए. एलमोंट, अध्यक्ष, अमरीकी प्रमाणित लोक लेखाकार संस्थान (एआईसीपीए) और उपाध्यक्ष, आईसीएआई उपस्थित थे।

..... और विकास जारी है

यह ऐसा समय नहीं है कि हम संतुष्ट हो कर बैठ जाएं, अपितु यह समय पहले से निर्धारित प्रत्येक मानक से आगे बढ़कर भविष्य की ओर देखने तथा आगे और विकास करने का है। हम यह विश्वास करते हैं कि सफलता और उत्कृष्टता हमारे जीवन की कोई घटना न होकर हमारी जीवन शैली है। इस दिशा में, मानव संसाधन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, कार्य जीवन की बेहतर क्वालिटी को प्राप्त करने और एक आदर्श ज्ञान प्रबंध वातावरण का सृजन करने के लिए मुद्दों पर विचार किया जाएगा :

- सेवा नियम
- भर्ती नियम
- स्थानांतरण नीति
- क्रय नीति
- निपटान/व्ययन करने संबंधी नीति

..... “अपेक्षाओं से आगे बढ़कर” - मानव संसाधन - प्रशासन समिति

7.2 संपरीक्षा समिति

7.2.1 महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- ♦ मुख्यालय, प्रादेशिक कार्यालयों और विकेन्द्रीकृत कार्यालयों के कानूनी और आंतरिक संपरीक्षकों की नियुक्ति और उनकी संपरीक्षा फीस का पुनरीक्षण।
- ♦ विभिन्न शाखाओं, प्रादेशिक कार्यालयों, विकेन्द्रीकृत कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में कानूनी और आंतरिक संपरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में पुनरीक्षित मानदंडों का कार्यान्वयन।
- ♦ संपरीक्षकों को संदाय करने संबंधी प्रक्रिया, जिसे अब लेखा विभाग के माध्यम से किए जाने की बजाय सीधे परीक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।
- ♦ प्रधान कार्यालय में नियत अस्ति रजिस्टर को अद्यतन बनाने के लिए और इसकी संगतता के लिए अनुवर्ती कार्रवाई।
- ♦ आईसीएआई जर्नल के मुद्रक के लेखाओं की संपरीक्षा और शोध रकमों की वसूली।
- ♦ प्रधान कार्यालय के लेखाओं को प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं के लेखाओं से सुमेलित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई।
- ♦ 31 मार्च, 2008 और 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्षों के लिए शाखा लेखाओं और संपरीक्षा रिपोर्टों का विश्लेषण।

- ◆ विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों और आंतरिक संपरीक्षकों के संप्रेषणों का पुनर्विलोकन और संपरीक्षा समिति के लिए संक्षिप्त वर्णन तैयार करना ।
- ◆ विभिन्न विभागों/गैर-स्थायी समितियों के लिए आंतरिक संपरीक्षकों के कार्य के विस्तार और उनकी रिपोर्टिंग संरचना का पुनर्विलोकन, जिसे आंतरिक नियंत्रण तंत्र की पूर्णता और एक समान व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है ।
- ◆ क्षेत्रीय परिषदों और बीसीओ के ऐसे बैंक खातों को बंद करना, जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा था ।
- ◆ क्षेत्रीय परिषदों के पुराने पुस्तकालय निक्षेपों का अपलेखन ।
- ◆ निधियों के निवेश का विनियमन और संस्थान के लिए निवेश संबंधी दिशानिर्देशों का पुनर्विलोकन ।
- ◆ प्रादेशिक संपरीक्षा समिति की एक बैठक प्रत्येक तीन मास में बुलाने के लिए अनुवर्ती कार्यवाई ।
- ◆ पुराने चेकों का विश्लेषण और उनका अपलेखन ।
- ◆ शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी दस्तावेजों के लिए प्रक्रियाएं ।
- ◆ लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व कानूनी और आंतरिक संपरीक्षकों के साथ चर्चा की गई ।
- ◆ विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों का पुनर्विलोकन और आंतरिक संपरीक्षकों के संप्रेषणों को आईसीएआई की अधिकथित नीतियों के पालन के लिए नोट किया गया ।
- ◆ आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना ।
- ◆ आधुनिक आईटी परिस्थितियों के संदर्भ में आईटी प्रणाली संरक्षा को और मजबूत करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

7.2.2 पहले

- ◆ शाखाओं और ऐसे डीसीओ के लिए, जिनके सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक है, आंतरिक संपरीक्षकों की नियुक्ति ।
- ◆ संपरीक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और संपरीक्षकों का पैनल तैयार करके और बनाए रखते हुए उसे और अधिक पारदर्शी बनाना ।
- ◆ आईसीएआई के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को और सरल तथा कारगर बनाने तथा उसे मजबूत करने के लिए एक प्रारूप आंतरिक नियंत्रण दस्तावेज तैयार किया गया था और उसे सभी उपयोग्यता विभागों/गैर-स्थायी समितियों, प्रादेशिक कार्यालयों और विकेन्द्रीकृत कार्यालयों को, उनकी टिप्पणियों/विचार जानने के लिए परिचालित किया गया था ।
- ◆ शाखाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण मॉड्यूल के संबंध में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए पहल की गई है ।
- ◆ नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है ।
- ◆ प्राधिकार के समुचित प्रत्यायोजन के प्रयोजन के लिए प्रमुख विभागों की पहचान करने की कार्यवाही की जा रही है ।
- ◆ सभी प्रादेशिक परिषदों की संपरीक्षा के विस्तार क्षेत्र के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

7.3 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड

देश में वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों में सुधार करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, आईसीएआई ने वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड (एफआरआरबी) की स्थापना की है । एफआरआरबी स्वप्रेरणा से या किसी विनियामक निकाय (निकायों) द्वारा उसे प्रतिनिर्देश दिए जाने पर या किए जाने पर या मीडिया रिपोर्टों द्वारा गंभीर लेखाकरण अनियमितताएं सामने आई हैं, कतिपय उद्यमों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्टों का यथासंभव रूप में निम्नलिखित का अवधारण करने के विचार से पुनर्विलोकन करता है :

- (क) वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन ;
- (ख) विनियामक निकायों द्वारा विहित प्रकटन अपेक्षाओं, कानूनों, नियमों और उद्यम के लिए सुसंगत विनियमों का अनुपालन ; और
- (ग) संपरीक्षकों की रिपोर्टिंग बाध्यता का अनुपालन ।

एफआरआरबी की प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करते समय तकनीकी पुनर्विलोकक और वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूह बोर्ड की सहायता करते हैं । पुनर्विलोकन के लिए चयन किए गए साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्टों का प्रारंभिक पुनर्विलोकन, बोर्ड द्वारा रखे गए पैनल में से चयन किए गए तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा किया जाता है । साधारण प्रयोजन

वित्तीय विवरणों का और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्टों के तकनीकी पुनर्विलोकनों द्वारा दी गई प्रारंभिक पुनर्विलोकन रिपोर्टों पर, बोर्ड द्वारा उनकी अंतिम रूप से समीक्षा किए जाने से पूर्व वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूहों द्वारा विचार किया जाता है और उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है।

7.3.1 साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उनपर संपरीक्षकों की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन स्वप्रेरणा से

- बोर्ड ने, परिषद् वर्ष 2009-10 के दौरान पुनर्विलोकन के लिए 100 कंपनियों के वित्तीय वर्ष 2007-08 से संबंधित साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्टों का चयन किया है तथा उनके पुनर्विलोकन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है।
- बोर्ड ने, परिषद् वर्ष 2008-09 के दौरान पुनर्विलोकन के लिए 54 कंपनियों के वित्तीय वर्ष 2006-07 से संबंधित साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्टों का चयन किया है तथा उनमें से बोर्ड ने 26 रिपोर्टों पर विचार किया है।
- बोर्ड ने, परिषद् वर्ष 2007-08 के दौरान पुनर्विलोकन के लिए 61 कंपनियों के वित्तीय वर्ष 2005-06 से संबंधित साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्टों का चयन किया है तथा उनमें से बोर्ड ने 50 रिपोर्टों पर विचार किया है।
- बोर्ड ने, परिषद् वर्ष 2006-07 के दौरान पुनर्विलोकन के लिए 53 कंपनियों के वित्तीय वर्ष 2004-05 से संबंधित साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्टों का चयन किया है तथा उनमें से बोर्ड ने 42 रिपोर्टों पर विचार किया है।

वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 से संबंधित साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरण, आज के संदर्भ से काफी पुराने हो गए हैं और इसलिए बोर्ड ने यह विनिश्चय किया था कि इन पुराने वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन बंद कर दिया जाए। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 से संबंधित शेष 50 कंपनियों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन बंद कर दिया गया था, जिसे या तो वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूहों द्वारा विचार में लिया जाना था अथवा जो तकनीकी पुनर्विलोकनों के पास लंबित थे और जिनके संबंध में उस तारीख तक रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई थी।

7.3.2 विशेष मामले

सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड

सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के लेखाओं में घोर अनियमितताओं का प्रकटन किया गया था और यह प्रकटन जनवरी, 2009 में स्वयं कंपनी के अध्यक्ष द्वारा किया गया था। अतः वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उनपर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का एक विशेष मामले के रूप में पुनर्विलोकन आरंभ किया था।

मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई थीं :

- साधारणतया बोर्ड किसी उद्यम के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन किसी एकल वर्ष के लिए करता है। तथापि, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, एफआरआरई ने वित्तीय वर्ष 2003-04 से वित्तीय वर्ष 2007-08 तक के पांच वित्तीय वर्षों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उनपर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन करने का विनिश्चय किया था।
- सामान्यतया ऐसा पुनर्विलोकन किसी ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जाता है जो एफआरआरबी के साथ नामांकित है, तथापि, उच्च स्तर के प्रभावी पुनर्विलोकन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे तीन पुनर्विलोककों का पैनल नियुक्त करने का विनिश्चय किया था, जो संस्थान के वरिष्ठ, अनुभवप्राप्त और गणमान्य सदस्य हों।

तदनुसार, पुनर्विलोककों के पैनल को नियुक्त किया गया है और उन्होंने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के 5 वर्षों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन पूरा कर दिया है। उनके द्वारा शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

अन्य विशेष मामले

- चूंकि मीडिया द्वारा मेटास इन्फ्रा लिमिटेड के वित्तीय विवरणों में गंभीर लेखांकन अनियमितताओं की रिपोर्ट किया गया है, इसलिए बोर्ड ने मेटास इन्फ्रा लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन भी प्रारंभ किया है।
- एक सक्रिय उपाय के रूप में, यूसी 50 ऐसे उद्यमों का चयन किया गया है, जिनमें सत्यम कांड के पश्चात् स्वतंत्र निवेशकों ने त्यागपत्र दे दिया है, जिनका पुनर्विलोकन किया जाएगा। इस संबंध में पुनर्विलोकन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

7.3.3 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूहों का गठन

बोर्ड ने क्रमशः वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए 16 और 9 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूहों का गठन किया था, जो संबंधित वर्षों में साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उनपर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर तकनीकी पुनर्विलोकनों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक पुनर्विलोकन रिपोर्टों पर विचार करेंगे तथा उन्हें अंतिम रूप देंगे।

7.3.4 प्रकाशन

आईसीएआई के सदस्यों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों को पुनर्विलोकन के दौरान पाए गए प्रमुख अननुपालनों से अवगत कराने के लिए, बोर्ड समय-समय पर ऐसे अननुपालनों का संकलन करता है और उन्हें आईसीएआई के जर्नल में प्रकाशित करता है। इसी व्यवहार को जारी रखते हुए, ऐसे अननुपालनों से संबंधित एक टिप्पण का संकलन किया जा रहा है और उसे सीए जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा। 'एनहांसिंग ऑडिट क्वालिटी' शीर्षक के अधीन अननुपालन संबंधी लेखों को संस्थान के जर्नल 'दि चार्टर्ड एकाउंटेंट' के दिसम्बर, 2008, जनवरी, फरवरी, जून और जुलाई, 2009 अंकों में प्रकाशित किया गया था।

वित्तीय विवरण तैयार करने वाले व्यक्तियों और संपरीक्षकों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बोर्ड ने 'ए स्टडी ऑन कंप्लायंस ऑफ फाइनेशियल रिपोर्टिंग रिकवायरमेंट्स' को प्रकाशित करने का विनिश्चय किया है, जिसमें लागू लेखांकन/संपरीक्षा मानकों तथा मार्गदर्शक टिप्पणों और साथ ही सुसंगत विधियों और कानूनों के संदर्भ में विभिन्न वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुपालन पहलुओं पर बोर्ड द्वारा किए गए अनिवार्य संप्रेक्षण अंतर्विष्ट होंगे। इस अध्ययन में बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2006-07 से संबंधित साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन के दौरान किए गए संप्रेक्षण सम्मिलित हैं।

7.3.5 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का संचालन

बोर्ड के पास नामांकित तकनीकी पुनर्विलोककों की संख्या में वृद्धि करने और सदस्यों के सकल वित्तीय-रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन कौशल में सुधार करने और उन्हें प्रमुख अननुपालन से अवगत कराने के उद्देश्य से, बोर्ड नियमित आधार पर एक दिवसीय संगोष्ठियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। 18 अक्टूबर, 2008 को कोयम्बटूर में नियम प्रकटन विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। 5 सितम्बर, 2008 को कोलकाता में और 13 जून, 2009 को चेन्नई में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वर्तमान में 170 सदस्य बोर्ड के पास तकनीकी पुनर्विलोककों के रूप में नामांकित हैं।

7.4 आंतरिक संपरीक्षा संबंधी समिति

पारंपरिक आंतरिक संपरीक्षा संव्यवहार आधारित और लागत-चालित रही है। आज के युग में, आंतरिक संपरीक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं और वह एक प्रतिक्रियाशील, ऐतिहासिक रूप से केन्द्रीत कृत्य की अपनी छवि को तोड़कर एक ऐसा सक्रिय समूह बन रही है जो जोखिम आधारित फोकस रखता है। आंतरिक संपरीक्षा कृत्य को अधिकाधिक रूप से एक ऐसे कृत्य के रूप में देखा जा रहा है जो नीतिगत जोखिमों के निर्धारण और प्रबंध में अग्रणी भूमिका अपनाएगा, संगठन का मूल्यवर्धन करेगा और प्रचालनात्मक सुधार अवसरों की पहचान करेगा।

चार्टर्ड एकाउंटेंटों ने बहु अनुशासनात्मक आंतरिक संपरीक्षा दलों में कार्य करने के बावजूद भी अपने लिए एक सुभिन्न स्थान सृजित किया है। इस स्थान को बनाए रखने के लिए, चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे आवधिक रूप से अपनी जानकारी और कौशल का निर्धारण करें और उन्हें नियमित रूप से अद्यतन बनाएं। अतः, संस्थान वृत्ति का संवर्धन करने और साथ ही किसी संगठन की सफलता में इसकी भूमिका में अभिवृद्धि करने के विचार से आंतरिक संपरीक्षा के वृत्ति से संबंधित संसाधन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता है। तदनुसार आईसीएआई ने 5 फरवरी, 2004 को आंतरिक संपरीक्षा संबंधी एक अस्थायी समिति का गठन किया था। समिति को नवम्बर, 2008 में "आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड" के रूप में पुनर्नामित किया गया था। इस बोर्ड का उद्देश्य भारत में विद्यमान आंतरिक संपरीक्षा व्यवहारों का पुनर्विलोकन करना तथा आंतरिक परीक्षा संबंधी मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणों का विकास करना तथा आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना है।

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक

अवधि के दौरान, आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यवहारों को संहिताबद्ध करते हुए आंतरिक संपरीक्षा के संबंध में 13 मानक जारी किए हैं और साथ ही आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों के लिए ढांचा भी जारी किया है जो निम्नानुसार है :

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों के लिए ढांचा

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों के लिए ढांचा, संस्थान द्वारा जारी किए जा रहे आंतरिक संपरीक्षा मानकों के लिए निर्देश ढांचा उपलब्ध करता है। इस ढांचे का उद्देश्य आंतरिक संपरीक्षा क्रियाकलापों में वृत्तिकता का संवर्धन करना है। इस ढांचे में 4 संघटक अंतर्विष्ट हैं, अर्थात्, आचार संहिता, सक्षमता ढांचा, मानक की संरचना और तकनीकी मार्गदर्शन।

“रिपोर्टिंग”

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 4, रिपोर्टिंग का प्रयोजन प्रणालियों, प्रक्रियाओं, नियंत्रणों, जिनके अंतर्गत किसी अस्तित्व के वित्तीय विवरणों की मदें भी हैं, की किसी आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा की गई संपरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी आंतरिक संपरीक्षक की रिपोर्ट के प्रारूप और अंतर्वस्तु के संबंध में मानक स्थापित करना है।

एसआईए 5, “नमूने लेना”

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 5, नमूना लेना, किसी संपरीक्षा नमूने के डिजाइन और चयन के संबंध में और साथ ही आंतरिक संपरीक्षा नियोजनों में संपरीक्षा नमूनों के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। यह एसआईए नमूने के परिणामों के मूल्यांकन से भी संबंध रखता है।

एसआईए 6 “विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं”

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 6 “विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं”, आंतरिक संपरीक्षा के दौरान विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है।

एसआईए 7 “आंतरिक संपरीक्षा में क्वालिटी आश्वासन”

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 7 “आंतरिक संपरीक्षा में क्वालिटी आश्वासन” आंतरिक संपरीक्षा में क्वालिटी आश्वासन के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। यह मानक आंतरिक क्वालिटी पुनर्विलोकनों, बाह्य क्वालिटी पुनर्विलोकनों और उनके परिणामों की संसूचना के संबंध में भी व्यापक जानकारी उपलब्ध कराता है।

एसआईए 8 “आंतरिक संपरीक्षा नियोजनों के निबंधन”

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 8 “आंतरिक संपरीक्षा नियोजनों के निबंधन” आंतरिक संपरीक्षा क्रियाकलापों, चाहे उन्हें घरेलू संपरीक्षकों द्वारा किया गया हो अथवा किसी बाह्य अभिकरण द्वारा, के नियोजन के निबंधनों के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। यह मानक नियोजन के निबंधन के तत्वों का वर्णन करता है, अर्थात्, विस्तार, उत्तरदायित्व, प्राधिकार, गोपनीयता, परिसीमाएं, रिपोर्टिंग, प्रतिकर और मानकों का अनुपालन।

एसआईए 9 “प्रबंधन के साथ परस्पर संपर्क”

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 9 “प्रबंधन के साथ परस्पर संपर्क” प्रबंधन के साथ आंतरिक संपरीक्षक के परस्पर संपर्क के लिए ढांचे का उपबंध करता है। यह ऐसे विनिर्दिष्ट विषयों की पहचान करता है, जिन्हें नियोजन के निबंधनों में वर्णित किए गए अनुसार प्रबंधन को संसूचित किया जाना है।

एसआईए 10 “आंतरिक संपरीक्षा साक्ष्य”

यह मानक पर्याप्त समुचित आंतरिक संपरीक्षा साक्ष्यों की अवधारणा, आंतरिक संपरीक्षा साक्ष्य को अभिप्राप्त करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाओं, अर्थात् निरीक्षण, संप्रेक्षण, जांच और पुष्टिकरण, संगणना और विश्लेषणात्मक पुनर्विलोकन को स्पष्ट करता है।

एसआईए 11 “किसी आंतरिक संपरीक्षा में कपट पर विचार”

यह मानक किसी अस्तित्व में आंतरिक नियंत्रणों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है, जो कपटों के जोखिम का निर्धारण करने के लिए आंतरिक संपरीक्षा में भी सहायक सिद्ध होंगे। यह मानक कपट निवारण और उनका पता लगाने के संबंध में आंतरिक संपरीक्षक के उत्तरदायित्व को भी स्थापित करता है।

एसआईए 12 “आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन”

यह मानक आंतरिक नियंत्रणों, नियंत्रण वातावरण, जोखिम निर्धारण, नियंत्रण के परीक्षण और कमियों की संसूचना के अर्थ और उनमें अंतर्निहित परिसीमाओं जैसे पहलुओं से संबंधित है। यह एसआईए आंतरिक नियंत्रणों के मूल्यांकन में किसी आंतरिक संपरीक्षक की भूमिका को भी वर्णित करता है।

एसआईए 13 “उद्यम जोखिम प्रबंध”

यह मानक उद्यम जोखिम प्रबंध की प्रक्रिया और आंतरिक संपरीक्षक की भूमिका को स्थापित करता है। यह मानक आंतरिक संपरीक्षा योजना और ऐसी जानकारी के, जिसे आंतरिक संपरीक्षा को अपनी रिपोर्ट में उपलब्ध कराना चाहिए, संबंध में भी मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है।

एसआईए 14 “सूचना प्रौद्योगिकी के युग में आंतरिक संपरीक्षा”

यह मानक किसी सूचना प्रौद्योगिकी परिस्थितियों में आंतरिक संपरीक्षा करने के लिए आंतरिक संपरीक्षक के लिए आवश्यक कौशलों और सक्षमता, ऐसी कोई आंतरिक परीक्षा करने की योजना बनाते समय विचार में रखे जाने वाले तथ्यों, ऐसे विषयों,

जो आईटी परिस्थितियों में संपरीक्षा को प्रभावित कर सकते हैं, जोखिम का निर्धारण, संपरीक्षा प्रक्रियाओं, आईटी परिस्थितियों का पुनर्विलोकन और दस्तावेजीकरण को उपवर्णित करता है।

एसआईए 15 “अस्तित्वों और उसकी परिस्थितियों का ज्ञान”

यह मानक भी किसी आंतरिक संपरीक्षक द्वारा अस्तित्व के ज्ञान के उपयोग, उसे उपयोग करने तथा दस्तावेजीकरण के संबंध में दिशानिर्देश विहित करता है।

एसआईए 16 “किसी विशेषज्ञ के कार्य का उपयोग करना”

यह मानक ऐसी परिस्थितियों को स्पष्ट करता है जिनमें किसी विशेषज्ञ के कार्य के उपयोग के लिए आवश्यकता उद्भूत हो सकती है, इस प्रश्न का विनिश्चय करते समय विचार में लिए जाने वाले तथ्य की क्या किसी विशेषज्ञ के कार्य का उपयोग किया जाए अथवा नहीं, किसी विशेषज्ञ के कौशल और सक्षमता तथा उसकी वस्तुनिष्ठता के मूल्यांकन, किसी विशेषज्ञ के कार्य के मूल्यांकन के लिए प्रक्रियाओं, आंतरिक संपरीक्षक की रिपोर्ट में किसी विशेषज्ञ के प्रतिनिर्देशों को भी स्पष्ट करता है।

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों का सार-संग्रह (3 फरवरी, 2009 को यथाविद्यमान)

- आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों के रूप में आंतरिक संपरीक्षा के लिए सर्वोत्तम व्यवहारों को संहिताबद्ध किया है। सुगम निर्देश उपलब्ध कराने के लिए तथा आज तक जारी सभी मानकों की उपलब्धता और साथ ही एक स्थान पर प्राक्कथन को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों का सार-संग्रह जारी किया है।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा के प्रस्तावित मानक, किसी आंतरिक संपरीक्षा में विधियों और विनियमों को विचार में लेना, के उद्भासन प्रारूप को भी जारी किया है। बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक, प्रगति की मानीटरी करना को तैयार करने संबंधी परियोजना भी आरंभ की है।

7.4.1 तकनीकी मार्गदर्शन

मानक निकाले जाने के अलावा, बोर्ड आंतरिक संपरीक्षा संबंधी उद्योग विनिर्दिष्ट मार्गदर्शनों का सूत्रीकरण करने के लिए भी तेजी से कार्य कर रही है।

अवधि के दौरान आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड द्वारा निम्नलिखित तकनीकी मार्गदर्शन जारी किए गए हैं :

दूरसंचार उद्योग में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन

इस मार्गदर्शन को दूरसंचार उद्योग में कारबार संस्कृति, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की गहन समझ उपलब्ध कराने के लिए जारी किया गया है। यह पाठकों को किसी दूरसंचार कंपनी में आंतरिक संपरीक्षा के दौरान उद्भूत होने वाली विभिन्न तकनीकी बातों को समझने में सहायता करेगी।

स्टॉक ब्रोकरों की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन

बोर्ड द्वारा इस मार्गदर्शन को किसी स्टॉक ब्रोकिंग अस्तित्व की जटिलताओं को समझने में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के प्रयोजन से जारी किया गया है। यह किसी आंतरिक संपरीक्षक को अपने उत्तरदायित्वों को अत्यधिक दक्षता से निभाने में समर्थ बनाएगी।

अमूर्त आस्तियों की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन

यह मार्गदर्शन आंतरिक संपरीक्षा कृत्य द्वारा निभाई जाने वाली ऐसी भूमिका को प्रमुख रूप से उपदर्शित करता है, जिसे वह अमूर्त आस्तियों के प्रभावी और दक्ष प्रबंधन में निभा सकती है। इसके अंतर्गत अमूर्त आस्तियों की आंतरिक संपरीक्षा से सुसंगत सभी पहलुओं के ब्यौरे सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त, बोर्ड ने निम्नलिखित उद्योगों/क्षेत्रों की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन तैयार करने से संबंधित परियोजनाएं आरंभ की हैं :

1. गैर लाभकारी संगठन
2. बैंकों में खजाना संबंधी कृत्य
3. अवसंरचना
4. नगर निगम और स्थानीय निकाय
5. शैक्षणिक संस्थाएं
6. आईटी बीपीओ
7. सॉफ्टवेयर विकास
8. पेट्रो रसायन
9. खनन और निष्कर्षण - कोयला, लौह, इस्पात और एल्यूमीनियम उद्योग

10. किसी अस्तित्व की जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, आदि

7.4.2 साधारण मार्गदर्शन

वर्ष के दौरान बोर्ड ने किसी संगठन में ईआरएम प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए अनिवार्यताओं पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए उद्यम जोखिम प्रबंध कार्यान्वयन संबंधी मार्गदर्शन जारी किया है। यह मार्गदर्शन एक साधारण रीति में ईआरएम ढांचे के कार्यान्वयन के संबंध में कदम-दर-कदम पद्धति उपलब्ध कराती है और साथ ही ऐसे मुद्दों का भी समाधान करती है जो इस कार्यान्वयन के दौरान सामने आ सकते हैं। बोर्ड ने मैन्युअल ऑन कंकरेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स भी जारी किया है जो बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा में अंतर्बलित अधिकांश महत्वपूर्ण पहलुओं को उपवर्णित करता है।

आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड ने अपनी तरह का पहला मैन्युअल ऑन इंटरनल ऑडिट भी जारी किया है, जिसमें रिपोर्टिंग की नियुक्ति से प्रारंभ करते हुए आंतरिक संपरीक्षा करने संबंधी कदम-दर-कदम पद्धति अंतर्विष्ट है। यह आंतरिक संपरीक्षा की अवधारणात्मक और साथ ही व्यवहारिक पद्धतियों को भी उपवर्णित करता है।

आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में सदस्यों के ज्ञान आधार में विस्तार करने के लिए बोर्ड ने ट्रेनिंग मेटिरियल ऑन इंटरनल ऑडिट भी निकाला है। यह प्रशिक्षण सामग्री एक स्रोत सामग्री के रूप में प्रयोजन सिद्ध करेगी जिसका उपयोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा।

बोर्ड की अन्य चालू परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

- (क) एसआईए 7, आंतरिक संपरीक्षा में क्वालिटी आश्वासन संबंधी कार्यान्वयन मार्गदर्शन
- (ख) एसआईए 4, रिपोर्टिंग संबंधी कार्यान्वयन मार्गदर्शन
- (ग) बेजल 2 अनुपालन प्राप्त करने में आंतरिक संपरीक्षा की भूमिका संबंधी अध्ययन
- (घ) त्रैमासिक वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रकटन और प्रबंधन प्रमाणों में आंतरिक संपरीक्षा की भूमिका संबंधी अध्ययन
- (ङ) किसी अस्तित्व की जोखिम प्रबंध प्रक्रिया में आंतरिक संपरीक्षा की भूमिका संबंधी अध्ययन
- (च) संपरीक्षा समिति के साथ किसी आंतरिक संपरीक्षक के संबंधों पर अध्ययन

7.4.3 सम्मेलन और अन्य कार्यक्रम

आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं के संबंध में जागरूकता बनाने के विचार से, बोर्ड ने प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं के सहयोग से निम्नलिखित संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया है :

- (क) नई दिल्ली में पब्लिक सेक्टर में जोखिम प्रबंध संबंधी प्रबंधन विकास कार्यक्रम
- (ख) नई दिल्ली में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी सभा
- (ग) नई दिल्ली में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी अखिल भारतीय सम्मेलन
- (घ) पुणे में आंतरिक संपरीक्षा, आर्थिक चुनौतियों के समय में आंतरिक संपरीक्षा की भूमिका पर राष्ट्रीय हीरक जयंती सम्मेलन
- (ङ) कोलकाता में, परिवर्तन की हवाएं - वृत्ति को चुनौतियां, विषय पर हीरक जयंती अखिल भारतीय सम्मेलन
- (च) बंगलोर में आईएफआरएस और आंतरिक संपरीक्षा संबंधी सभा
- (छ) मुंबई में स्टॉक ब्रोकरों की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी संगोष्ठी
- (ज) हैदराबाद में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी संगोष्ठी
- (झ) पटना में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी

7.4.4 पाठ्यक्रम

बोर्ड ने 6 जून, 2009 को नई दिल्ली में उद्यम जोखिम प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया है। इस पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने के उद्देश्यों में संस्थान के सदस्यों को आवश्यक तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता प्रदान करना और उनके कौशल का निर्माण करना और इस प्रकार उद्यम जोखिम प्रबंध के विभिन्न पहलुओं में उन्हें अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार करना और इस क्षेत्र को एक अंतर्निहित क्षमता वाले क्षेत्र के रूप में विकसित करना सम्मिलित है। इस पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्ति आंतरिक संपरीक्षा, उद्यम जोखिम प्रबंध और अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के निगम शासन से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की वृत्तिक और ओर व्यक्तिगत पूर्व व्यस्तताओं को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह एक कक्षा अध्यापन, ई-लर्निंग और साथ ही स्वअध्ययन का एक संतुलित मिश्रण है। कक्षा अध्यापन को छह सप्ताह के कक्षा समय ढांचे के अंतर्गत पूरा किया जाएगा जिसमें छह शनिवारों को कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।

सम्यक अनुक्रम में, आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड यह पाठ्यक्रम मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में भी अप्रारंभ करेगा।

7.4.5 अन्य

बोर्ड ने आधुनिक संगठनों की विकास संबंधी आवश्यकताओं और आंतरिक संपरीक्षा कृत्य की परिवर्तनशील भूमिका को मुख्य रूप से उपदर्शित करते हुए “आंतरिक संपरीक्षा क्या है” शीर्षक वाला एक ब्राशर जारी करने का विनिश्चय किया था।

7.5 अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति

अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति को पहली बार 5 फरवरी, 2009 को सृजित किया गया था।

7.5.1 टिप्पण/विषय/क्रियाकलाप

1. आईसीएआई अंतरराष्ट्रीय वित्त संगम का निगम सदस्य बन गया है।
2. अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी सुझावों को सरकार को 26 मई, 2009 को प्रस्तुत बजट पूर्व ज्ञापन, 2009 में सम्मिलित किया गया था।
3. समिति द्वारा अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के पहले बैच का आयोजन मुंबई में किया गया था।
4. अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दूसरे बैच का आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है।
5. समिति अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई अध्ययन सामग्री को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं कर रही हैं।
6. महानगरों से भिन्न क्षेत्रों में अवस्थित सदस्यों के फायदे के लिए एक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

7.6 आचार मानक बोर्ड

आचार किसी भी सभ्य समाज का आधार होता है और यह एक ऐसी आरंभिक अपेक्षा है जिसकी कोई भी सभ्य व्यक्ति किसी अन्य सभ्य व्यक्ति से अपेक्षा करता है। निगम जगत में हुई हाल ही की निरंतर घटनाओं ने कारबार और वृत्ति में आचार की महत्ता को प्रमुख रूप से दर्शित किया है। ऐसा कारबार या वृत्ति, जिसमें आचारों का पालन नहीं किया जाता है, कमी-न-कमी अवश्य ही असफल होगा।

इसलिए प्रत्येक संस्थान के पास, चाहे वह राजनीतिक हो, कारबार या वृत्तिक हो, उस सीमा तक आचार मानकों के अनुपालन के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए, जो आम जनता को स्वीकार्य हो, तदनुसार, किसी भी वृत्ति के सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे आचारों का अक्षरशः पालन करें।

इस दूरदर्शिता के साथ, संस्थान के आचार मानक बोर्ड का सृजन किया गया था, जिसे यह प्रमुख उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह अपने सदस्यों के लिए ऐसे आचार संबंधी सिद्धांत तैयार करे जो पर्याप्त रूप से इतने कड़े हों कि जनता में उनके प्रति विश्वसनीयता को प्रत्याभू करें। बोर्ड का उद्देश्य, सदस्यों की ‘उत्कृष्टता, स्वतंत्रता, अखंडता’ के लंबे समय से संपोषित आदर्शों और साथ ही उनकी गरिमा और हितों की संरक्षा को प्रतिधारित करते हुए, सदस्यों के लिए एक सक्रिय और समकालीन आचार-संहिता और उनके नैतिक व्यवहार संबंधी संहिता तैयार करने के प्रति कार्य करना है।

सदस्यों के लिए आचार संबंधी सिद्धांत तैयार करने के अलावा, बोर्ड उसे निर्दिष्ट आचार संबंधी मुद्दों की परीक्षा भी करता है और उनपर सलाह प्रदान करता है। यह समय-समय पर सदस्यों के लिए ‘आचार-संहिता’ का पुनर्विलोकन करता है और उसके पुनरीक्षित संस्करणों का प्रकाशन करता है। बोर्ड के अन्य प्रकाशनों, अर्थात् ‘आचार संबंधी मुद्दों पर एफएफएफ्यू’, ‘संपरीक्षकों की स्वतंत्रता संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण’ और ‘संपरीक्षा रिपोर्ट के पुनरीक्षण संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण’ का भी समय-समय पर पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण किया जाता है। बोर्ड सदस्यों की अखंडता, वस्तुनिष्ठता और वृत्तिकता के संबंध में जन जागरूकता और विश्वास का संवर्धन भी करता है। यह सदस्यों की, उन्हें किसी अस्तित्व के संपरीक्षक के पद से अनुचित रूप से हटाए जाने के विरुद्ध शिकायतों की तैयार की गई प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा करता है और कार्यवाही करके अपने सदस्यों के हितों की संरक्षा के लिए आवश्यक कदम भी उठाता है।

7.6.1 विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण विनिश्चय

- 4 फरवरी, 2009 को आचार-संहिता- 2009 का विमोचन किया गया था। पुनरीक्षित आचार-संहिता में पहली बार वृत्तिक लेखाकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय लेखाकार फेडरेशन (आईएफएसी) की आचार-संहिता को, उसे भारतीय विधियों के अनुरूप बनाने के लिए जहां कहीं अपेक्षित था, परिवर्तनों के साथ अंतर्विष्ट किया गया है।
- वृत्ति में लगे सदस्यों को किसी लेख के माध्यम से निर्बंधित रूप से विज्ञापन देने की अनुमति प्रदान करने के लिए 14 मई, 2008 को विज्ञापन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
- विभिन्न मुद्दों, उदाहरण के लिए लेखा बहियों का रखा जाना, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर संपरीक्षा समनुदेशन, संपरीक्षा समनुदेशनों की विनिर्दिष्ट संख्या आदि पर 8 अगस्त, 2008 को परिषद् के साधारण दिशानिर्देश, 2008 जारी किए गए थे।

- वृत्ति में लगे सदस्यों को चार्टर्ड एकाउंटेंट विनियम, 1988 के परिशिष्ट (9) के अधीन साधारण अनुज्ञाओं के अंतर्गत कृषि भूमि का स्वामित्व अर्जित करने और कृषि संबंधी क्रियाकलाप करने की अनुमति प्रदान की गई है।
- परिषद् के सदस्य, परिषद् की समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रादेशिक परिषदों के सदस्य और शाखाओं की प्रबंध समितियों के सदस्य अपने विजिटिंग कार्डों के पृष्ठ पर फर्म के नाम का उल्लेख किए बिना अपने आवासीय पते या कार्यालय पतों को टेलीफोन/फैक्स नंबर सहित मुद्रित कर सकेंगे।
- वृत्ति में लगे चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा बनाई गई प्रबंध परामर्शी कंपनियां, किसी नियोजक से, अभ्यर्थियों की भर्ती या नियोजन संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराते समय, ऐसे अभ्यर्थियों की वार्षिक सीटीसी के प्रतिशत के आधार पर पारिश्रमिक प्राप्त कर सकती हैं क्योंकि ऐसी कंपनियों को पहली अनुसूची के भाग 1 के केवल खंड (6) और (7) ही लागू हैं। व्यक्ति रूप से व्यवसाय करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट या उनकी फर्मों को सीए अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 1 के केवल खंड (10) के उपबंधों के अनुसार उसके लिए अनुमति प्राप्त नहीं है।
- ऐसे सदस्य, जो वृत्ति कर रहे हैं, अपने रोटरी विजिटिंग कार्ड में 'चार्टर्ड एकाउंटेंट' शब्दों के साथ 'जिला गवर्नर' के पद नाम का उपयोग नहीं कर सकते हैं (अधिनियम की धारा 7 और अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 1 के केवल खंड (7) को देखते हुए)।
- आईसीआई के किसी ऐसे सदस्य को, जो अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा है, अपनी वृत्तिक लेखन सामग्री पर सीए लोगो का उपयोग करना अनुज्ञात नहीं है क्योंकि सीए लोगो को भारत में सीए वृत्तिक के चिन्ह के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह चार्टर्ड एकाउंटेंटों की वृत्ति के ब्रांड का संवर्धन करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- नैतिक मत के आधार पर किसी कंपनी के सीए निदेशक को बोर्ड बैठकों में भाग नहीं लेना चाहिए और बोर्ड द्वारा उसके किसी ग्राहक (ग्राहकों) से संबंधित मद पर विचार करते समय, उससे स्वयं को हटा लेना चाहिए।
- उद्योग में लगे और साथ ही वृत्ति में लगे सदस्य एएमएफआई (भारत में परस्पर निधियों का संगम) पाठ्यक्रम में भाग ले सकते हैं। तथापि, जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि क्या कोई व्यक्ति, किसी वित्तीय मध्यवर्ती वृत्ति भूमिका निभाने के लिए उसके साथ रजिस्ट्रीकृत हो सकता है, बोर्ड ने यह विनिश्चय किया था कि उद्योग में लगे सदस्य/ वृत्ति में लगे सदस्यों से भिन्न सदस्य किसी परस्पर निधि/संगम के साथ रजिस्ट्रीकृत होकर उनकी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, जब कि वृत्ति में लगे सदस्य ऐसा नहीं कर सकते हैं, चाहे वे पूर्णकालिक सीओपी या अंशकालिक सीओपी धारण कर रहे हों।
- वृत्ति में लगे किसी सदस्य द्वारा शेयरों के क्रय और विक्रय के कारबार में नियोजन पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (11) के अर्थान्तर्गत 'किसी कारबार' में नियोजन के समतुल्य हैं और इसलिए इस हेतु परिषद् की पूर्व अनुमति अपेक्षित है। किसी ग्राहक की आंतरिक परीक्षा संबंधी समनुदेशन और लेखांकन के लिए संव्यवहार की प्रविष्टि संबंधी समनुदेशन को एक साथ लेना निषिद्ध है, क्योंकि यह 'संपरीक्षकों की स्वतंत्रता संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण' के उपबंधों का उल्लंघन करता है।
- किसी एक अस्तित्व की समवर्ती संपरीक्षा और त्रैमासिक पुनर्विलोकन समनुदेशन एक साथ आरंभ नहीं किया जा सकता क्योंकि समवर्ती संपरीक्षा एक प्रकार की आंतरिक संपरीक्षा है और त्रैमासिक पुनर्विलोकन एक प्रकार की कानूनी संपरीक्षा है और दोनों को एक साथ प्रारंभ करना 'संपरीक्षकों की स्वतंत्रता संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण' के उपबंधों के अधीन प्रतिषिद्ध है।
- किसी फर्म द्वारा ऐसी पुस्तक का प्रकाशन, जिसमें उसका इतिहास अंतर्विष्ट हो और जो ग्राहकों, सहबद्ध व्यक्तियों, मित्रों और शुभचिंतकों के बीच वितरित करने के लिए हो तथा किसी फर्म के विशेष पत्र शीर्षों और लिफाफों पर 'वृत्ति में 75 गौरवान्वित वर्ष' शब्दों का मुद्रण वृत्तिक कार्य को मांगने के समतुल्य है और इसलिए यह चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (6) और (7) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है।
- सदस्य के लिए यह अनुज्ञात नहीं है कि वह साधारण जनता को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपनी फर्म के नाम और पते को अंतर्विष्ट करने वाले अपने पत्र शीर्षों का उपयोग करे क्योंकि इसमें एक संवर्धनात्मक तत्व अंतर्विलित है और यह वृत्तिक कार्य को मांगने के समतुल्य है।

7.6.2 बोर्ड की महत्वपूर्ण पहलें

- सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के उपबंधों के कारण चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में किए जाने के लिए अपेक्षित परिवर्तनों की समीक्षा।
- चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में संशोधनों के कारण बहुअनुशासनात्मक भागीदारियों (एमडीपी) संबंधी दिशानिर्देशों/पद्धतियों को अंतिम रूप देना।

- सदस्यों के बीच आचार संबंधी जागरूकता बनाना।
- “आचार संबंधी मुद्दों पर एफएक्यू” का पुनरीक्षण।
- ‘संपरीक्षकों की स्वतंत्रता संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण’ का पुनरीक्षण।

7.7 विजन समिति

आईसीएआई की विजन समिति में, जिसे वर्ष 2007 में स्थापित किया गया था, अपना पहला मील का पत्थर पार कर लिया है और उसने संपूर्ण वृत्ति, सेवारत सदस्यों, वृत्ति में लगे सदस्यों, छात्रों और संस्थान के लिए विजन तय करते हुए अग्रणी विजन दस्तावेज - 2021 जारी किया था। दस्तावेज में कार्ययोजना तैयार करने के लिए 3-5 वर्ष की कम समयसीमा में कार्य करने संबंधी सिफारिश का अनुपालन करते हुए समिति अब इसके अगले चरण पर है जहां उसमें परिषद् की कार्य अवधि के अनुसार तीन वर्ष की कम और सुसंगत रूप से पूर्व अनुमान लगाए जाने योग्य अवधि के लिए विजन विवरण तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया है। इससे अंततः और अधिक समकालीन तथा वास्तविक लक्ष्य निर्धारित होंगे और उनमें तेजी से परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य के आधार पर योजना के कार्यान्वयन के अनुक्रम के दौरान सुधार करने का विकल्प मौजूद होगा जिससे अंततः वर्ष 2021 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति संभव हो सकेगी। परिषद् द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् यह विजन विवरण परिषद् के नेताओं, परिषद्, इसकी समितियों और कर्मचारिवृंद सहित इसके सभी अंगों के लिए एक निदेशात्मक दस्तावेज बन जाएगा।

वर्ष 2008-09 में समिति ने :

1. एक अनुसंधान अभिकरण को नियोजित किया और इस सहस्राब्दि के तीसरे दशक में नेतृत्व और सफलता के लिए प्रमुख सफलता कारकों की पहचान करने के लिए गहन अनुसंधान अध्ययन किया था और अंततः ‘विजन विवरण- 2021’ तैयार किया गया था, जिसे परिषद् ने फरवरी, 2008 में हुई अपनी 276वीं बैठक में अनुमोदित कर दिया था।
2. विजन दस्तावेज के लिए समिति की कारबार योजना तैयार करने के लिए समिति हेतु अवधारणात्मक परामर्श प्रारूप तैयार किया था।
3. समिति की दिसम्बर, 2008 में हुई 283वीं बैठक में पुनःसंरचनात्मक ढांचे के साथ अग्रणी विजन दस्तावेज प्रस्तुत किया था जिसे परिषद् ने अनुमोदित कर दिया है।

वर्ष 2009-10 में, समिति ने अपना कार्य प्रादेशिक और शाखा कार्यालयों के पदधारियों के साथ एक विचार-विमर्श सत्र से प्रारंभ किया था और उमर कथित अनुसंधान अभिकरण के निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात् तैयार की गई प्रश्नावली पर उनकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त की गई थीं। समिति द्वारा पहचाने गए अगले कदम के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में विजन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना है। इनके लिए एक केन्द्रीय समूह परिचर्चा सत्रों के रूप में योजना तैयार की गई है जिसमें विनिर्दिष्ट विषय विचार-विमर्श का केन्द्र होंगे जैसे कि वे संभावित क्षेत्र जहां निकट भविष्य में सीए की सेवाएं अपेक्षित होंगी, सदस्यों से क्या अपेक्षाएं की जा सकती हैं, सक्षमता क्षेत्र आदि। इनमें भाग लेने वाले व्यक्तियों में अध्यक्ष, भूतपूर्व केन्द्रीय परिषद् सदस्य, भूतपूर्व प्रादेशिक परिषद् सदस्य तथा कारबार में वरिष्ठ पदों पर सेवारत सदस्य या ऐसे सदस्य सम्मिलित हैं जिन्होंने अपने कारबार स्थापित कर लिए हैं। भारत की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए, इनका उद्देश्य, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और विकास के विभिन्न स्तरों से आने वाले व्यक्तियों के मत तथा परिप्रेक्ष्य प्राप्त करना है।

अभी तक 3 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है तथा 3 और कार्यशालाओं के आयोजन की योजना बनाई गई है।

7.8 लघु और मध्यम व्यवसायियों संबंधी समिति

देश में लघु और मध्यम व्यवसायियों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2009-10 में पहली बार लघु और मध्यम व्यवसायियों संबंधी समिति का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यवसायियों के व्यवसाय प्रोफाइल में सुधार करने और उन्हें अपने ग्राहकों को बेहतर और दक्ष रीति में सेवा उपलब्ध कराने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और अवसरचना उपलब्ध कराना है। इस समिति के निर्देश निबंधन निम्नानुसार हैं :

“लघु और मध्यम व्यवसायियों संबंधी समिति का प्रमुख उद्देश्य, लघु और मध्यम व्यवसायियों को सशक्त करने के लिए एक कार्यान्मुख ढांचे का कार्यान्वयन करना है जिससे कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की अन्य समितियों द्वारा तैयार किए गए और परिकल्पित किए गए तकनीकी साहित्य, पद्धतियों और सक्षमता निर्माण आदर्शों को वास्तविक जीवन की कार्य परिस्थितियों में सम्मिलित किया जा सके और लागू किया जा सके। इस समिति के निर्देश निबंधन निम्नानुसार हैं :

- लघु और मध्यम व्यवसायियों को, दक्षतापूर्ण रीति में अपने व्यवसाय के प्रबंध में सहायता करने के लिए मार्ग और उपाय विकसित करना।
- लघु और मध्यम व्यवसायियों के व्यवसाय पोर्टफोलियो को पुनरुज्जीवित करने के लिए नेटवर्किंग नियमों को मजबूत बनाना।
- लघु और मध्यम व्यवसायियों की, वृत्ति के नए और अनन्य क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करना।

- लघु और मध्यम व्यवसायियों के व्यवसाय क्षेत्रों से सुसंगत मार्गदर्शन तैयार तथा जारी करना ।
- लघु और मध्यम व्यवसायियों को, दक्षतापूर्ण रीति में तकनीकी मानक उपयोजित करने में सशक्त बनाना ।
- लघु और मध्यम व्यवसायियों की, चैम्बर्स ऑफ कामर्स के सहयोग से कार्यक्रमों का आयोजन करके कारबार समुदाय में उनकी अनुपस्थिति में सुधार करने में सहायता करना ।
- लघु और मध्यम व्यवसायियों में कार्यशालाओं, विचार गोष्ठियों आदि के माध्यम से लेखांकन, संपरीक्षा और अचार मानकों के संबंध में जागरूकता बनाना ।
- परिषद् की अनुमति से अन्य कोई विषय ।

समिति, एसएमपी की आवश्यकताओं की पहचान करने और वृत्तिक व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त समर्थन उपलब्ध कराने के लिए मार्ग और उपाय तैयार करने के लिए एसएमपी का गहन सर्वेक्षण आरंभ करने का आशय रखती है । समिति यह आशय रखती है कि प्रमाणन, मूल्यांकन, न्यायिक आदि से संबंधित गैर-कंपनी विधि जैसे नए विशेषज्ञता के क्षेत्रों को विकसित करके एसएमपी के व्यवसाय पोर्टफोलियो को मजबूत बनाया जाए । समिति नए उभरते क्षेत्रों में एसएमपी को शिक्षित करने के लिए शाखा स्तर पर क्रैश पाठ्यक्रम संचालन करने की भी योजना बना रही है ।

7.9 प्रतिनिधित्व समिति

प्रतिनिधित्व समिति को एक अस्थायी समिति के रूप में पहली बार 5 फरवरी, 2009 को स्थापित किया गया था । बहुधा हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न समितियों के सदस्य, विभिन्न सरकारों, प्राधिकरणों और विनियामकों के समक्ष विभिन्न मुद्दों पर संस्थान का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं । इसका परिणाम यह होता है कि समान प्राधिकारी/विनियामक को आईसीएआई के सदस्यों के भिन्न-भिन्न सैटों द्वारा भिन्न-भिन्न अवसरों पर और अनेकों बार समान मुद्दों पर संपर्क किया जाता है । इस मुद्दे का समाधान करने के लिए अध्यक्ष ने प्रतिनिधित्व समिति का गठन किया था जिससे कि वह ऐसे किसी मुद्दे को हाथ में ले सके, जिसे किसी प्राधिकारी/विनियामक के समक्ष प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए उसका ध्यान आकृष्ट किया जाता है । समिति ने ऐसे सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किया है और संस्थान की ओर से संपर्क का एक केन्द्र उपलब्ध कराया है ।

समिति के सृजन से अब तक निम्नलिखित प्रतिनिधित्व किए गए हैं :

- भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई, संपरीक्षक नियुक्त करने के लिए बैंकों को दी गई स्वायत्तता का विरोध करते हुए ।
- भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई, आईसीएआई के सदस्यों के लिए लाइसेंसिएट, एसोसिएटशिप और फेलोशिप प्रश्न पत्रों के लिए छूट मांगने हेतु ।
- वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2008 और अधिनियम के अधीन वैट संपरीक्षा उपबंधों के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए और साथ ही 30 जून, 2009 तक संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने और प्रस्तुत करने के लिए साधारण समय विस्तार का अनुरोध करने के लिए ।
- पूर्त आयुक्त (महाराष्ट्र राज्य), मुंबई, चार्टर्ड एकाउंटेंटों को सोसाइटियों और न्यासों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित मामलों में उपसंजात होने की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध ।
- गोवा के मुख्यमंत्री, गोवा सरकार के लिए दोहरी प्रविष्टि और प्रोदमवन आधारित लेखांकन प्रणाली आरंभ करने के लिए ।
- प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, प्रमाणन प्राधिकारियों की अवसंरचना की संपरीक्षा के लिए संपरीक्षकों के नामांकन के लिए ।
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नए प्रारूप सं. 17 के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए ।
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, निर्धारण वर्ष 2007-08 के संबंध में संवीक्षा मामलों में प्रतिदाय में विलंब के मद्दे निर्धारिती के सामने आई असम्यक कठिनाइयों के संबंध में ।
- अंदमान और निकोबार द्वीप समूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, उनसे बजट संबंधी संसाधन लेखा और कंसोर्टियम बैंक प्रत्यय लेखा को तैयार करने, पुनः तैयार करने और संपरीक्षा के लिए उनकी निविदा सूचना में संशोधन करने का अनुरोध करते हुए और उन्हें आचार-संहिता के अनुरूप बनाने के लिए ।
- वित्त मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और विक्रय कर आयुक्त (महाराष्ट्र राज्य) मुंबई, महाराष्ट्र में व्योहारियों के वैट और सीएसटी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के विषय में उत्लंघनों के संबंध में ।
- सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार, दृष्टिहीन चार्टर्ड एकाउंटेंटों के, वित्त और लेखा क्षेत्रों में सरकारी सेक्टर में उनके नियोजन को आज्ञापक बनाकर सशक्तिकरण के लिए ।
- सभी मुख्यमंत्रियों को, दोहरी प्रविष्टि दोहरी प्रविष्टि और प्रोदमवन आधारित लेखांकन प्रणाली आरंभ करने के लिए ।

- भारतीय रिजर्व बैंक, उन्हें बैंक शाखा संपरीक्षक पैनल के लिए आईसीएआई को अद्यतन जिला सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए ।
- विधि और न्यायपालिका विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, आम माफी स्कीम प्रारंभ करने और फर्म रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र, मुंबई के कार्यालय से दस्तावेजों के अनुपालन/रजिस्ट्रीकरण के लिए ऑन लाइन प्रणाली आरंभ करने का सुझाव देने के लिए ।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, उन्हें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 14क और 14कक के अधीन विशेष संपरीक्षा के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंटों के नामांकन का प्रस्ताव करते हुए ।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भिन्न-भिन्न संपरीक्षा फीस के संबंध में ।
- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय, भारत सरकार, उनसे एसटीपीआई को वार्षिक कार्यपालन रिपोर्ट (एपीआर) प्रस्तुत करने के लिए समय विस्तारण का अनुरोध करते हुए ।
- मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के अधीन स्कीम की संपरीक्षा के संबंध में ।
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को स्रोत पर निम्न कटौती या अकटौती के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आने वाली वास्तविक दिक्कतों और व्यवहारिक कठिनाइयों के संबंध में ।
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सीबीडीटी परिपत्र सं. 03/2009 तारीख 21 मार्च, 2009 में दिए गए निदेशों के संबंध में निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए आयकर विवरणियां फाइल करने में आने वाली वास्तविक दिक्कतों और व्यवहारिक कठिनाइयों के संबंध में ।
- भारतीय रिजर्व बैंक को, बैंकों की संवर्ती संपरीक्षा के लिए पारिश्रमिक के संबंध में ।

7.10 अवसंरचना समिति

अवसंरचना समिति एक नव गठित समिति है, जिसे परिषद् ने 7 मार्च, 2009 को हुई अपनी 286वीं बैठक में अनुमोदन प्रदान किया था । समिति के निर्देश निबंधन निम्नानुसार हैं :

1. संस्थान, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं तथा विदेशों में चैप्टरों की विद्यमान भूमि और संस्थान भवनों का अनुसंधान ।
2. उत्कृष्टता केन्द्रों/प्रादेशिक परिषदों / देश भर में फैली शाखाओं और विदेशों में स्थित चैप्टरों के लिए भूमि और भवनों का अर्जन ।
3. नई भूमि और संस्थागत भवनों का अर्जन करने वाली प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं/चैप्टरों के लिए न्यूनतम अवसंरचना प्रसुविधाओं संबंधी नीति दिशानिर्देशों का अधिकथन ।
4. विद्यमान संस्थागत भवनों को समुन्नत करके और अतिरिक्त अवसंरचना प्रसुविधाएं उपलब्ध कराकर उनका मूल्यवर्धन करना ।
5. लागू कानूनों के अधीन भूमि और संस्थागत भवनों के संबंध में मूल दस्तावेजों का प्रशासन और बनाए रखना ।
6. संस्थान, प्रादेशिक परिषदों, उनकी शाखाओं, उत्कृष्टता केन्द्रों और विदेशों में स्थित चैप्टरों के लिए सभी पूंजी आस्तियों की पर्याप्तता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना ।
7. पूंजी आस्ति संबंधी अपेक्षाओं का विश्लेषण और आवश्यक उपाय करना ।
8. संस्थान के भवनों की एक समानता और मानकीकरण सुनिश्चित करना ।
9. ऐसे अन्य कार्य /कृत्य, जो परिषद्/ अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाए ।

अवसंरचना समिति ने 25 फरवरी, 2009 और 1 मई, 2009 को नई दिल्ली में अपनी दो बैठकों की थी और संस्थान / प्रादेशिक परिषद् और देश भर में फैली उनकी शाखाओं/चैप्टरों के अवसंरचना विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार किया ।

7.10.1 समिति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

क. उत्कृष्टता केन्द्र

संस्थान ने उत्कृष्टता केन्द्र के लिए निम्नलिखित शहरों में भूमि का अर्जन किया है :

1- जयपुर 2-बंगलोर 3-हैदराबाद

ख. संस्थान के भवन

संस्था के भवनों में चार भवन सम्मिलित हैं, अर्थात् सभागार ब्लॉक, अनुसंधान ब्लॉक, छात्रावास ब्लॉक और प्रशासनिक ब्लॉक ।

प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और उसका उद्घाटन 1 जुलाई, 2009 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। अन्य तीन भवनों का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है।

ग. संस्थान ने पुने शाखा के लिए भवन अर्जित किया है :

घ. संस्थान ने निम्नलिखित शाखाओं के लिए भूमि का अर्जन किया है :

1-कोटा 2-हुबली 3-सांगली 4-अहमदनगर 5-जलगांव 6-मथुरा 7-रोहतक 8-फरीदाबाद 9-बिलासपुर

ङ. संस्थान ने निम्नलिखित शाखाओं के भवनों के लिए संनिर्माण कार्य प्रारंभ किया है :

1-बदोदरा 2-नासिक 3-दुर्गापुर 4-विजयवाड़ा

च. शाखाओं के लिए भूमि के अर्जन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव विचाराधीन है :

1-भीलवाड़ा 2-कोट्टायम 3-सोलापुर 4-कोल्हापुर 5-पिम्परी चिंचवाड 6-बेल्लारी

छ. निम्नलिखित शाखाओं में पहले ही भूमि अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है :

1-वाराणसी 2-मेरठ 3-बरेली 4-इलाहाबाद 5-मुरादाबाद 6-मटिडा

- समिति ने शाखाओं को भवन अनुदान संबंधी मार्गदर्शनों को पुनरीक्षित किया है और उन्हें कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- समिति ने भवन अनुदान संबंधी प्रस्ताव की सिफारिश के संबंध में मार्गदर्शनों में संशोधन की सिफारिश की है और यह कार्यपालक समिति के विचाराधीन है।
- संस्थान के विद्यमान भवन 'आईसीएआई भवन', 27, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई का पुनःसुसज्जीकरण/नवीकरण कार्य चल रहा है।
- ई-29, सेक्टर 62, नोएडा स्थित संस्थान का भवन पूर्ण होने के निकट है और यह आशा की जाती है कि वह जुलाई, 09 से कार्यरत हो जाएगा। ऐसी शाखाओं, जिनके पास स्वयं की भूमि/भवन नहीं है, के लिए भवन समिति को भूमि/भवन अर्जित करने की सलाह दी गई थी।
- ऐसी शाखाओं को, जिन्होंने भूमि/भवन का अर्जन नहीं किया है, भूमि अर्जन की प्रक्रिया आरंभ करने की सलाह दी गई थी।
- समिति का यह स्वप्न है कि संस्थान की सभी शाखाओं के लिए सर्वोत्तम संस्थागत भवन अवसंरचना का सृजन किया जाए, सदस्यों और छात्रों को, आईटी, मामला अध्ययनों और अनुसंधान, साधारण प्रबंध और संसूचना कौशल के संबंध में गुणवाचक व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्कृष्टता केन्द्र का विकास किया जाए।

7.11 हीरक जयन्ती समिति

1 जुलाई, 2008 को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंसी वृत्ति ने अपनी विद्यमानता के 60वें वर्ष में प्रवेश किया और इस उपलक्ष्य में, 1 जुलाई, 2008 से प्रारंभ होने वाली अवधि को हीरक जयन्ती वर्ष समारोह के रूप में मनाया गया। 1 जुलाई ऐसा दिन है, जो इस वृत्ति के लिए विशेष मील का पत्थर है क्योंकि इस दिन वर्ष 1949 में भारतीय संसद ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम को प्रवृत्त किया था।

- 60वें वर्ष और हीरक जयन्ती समारोह के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में निम्नलिखित समारोह आयोजित किए गए थे -

29 जून, 2008 को श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने 'सेव दी इन्वायरन्मेंट मैराथन' को झंडा दिखाकर खाना किया था।

29 जून, 2008 को 'शर्मा बहनों द्वारा भजन संध्या' और स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा 'योग और ध्यान का उपयोग करते हुए जीवन शैली प्रबंध'

30 जून, 2008 को 'स्वास्थ्य जांच शिविर' और 'रक्त दान शिविर'

30 जून, 2008 को सीए छात्रों के फायदे के लिए श्री शिव खेड़ा द्वारा 'उत्प्रेरणा : सफलता की कूँजी' - नामक एक कार्यशाला

- संस्थान का 60वां स्थापना दिवस - 1 जुलाई, 2008 को प्रातः 7.30 बजे संस्थान के परिसर "आईसीएआई भवन" में ध्वजारोहण के साथ हीरक जयन्ती समारोह प्रारंभ हुए।

- 1 जुलाई, 2008 को नई दिल्ली में 60वें वर्ष और हीरक जयन्ती समारोह के प्रारंभ का औपचारिक उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था।

समारोह में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों में अन्य व्यक्तियों के साथ निम्नलिखित सम्मिलित थे :

श्री प्रेम चंद गुप्ता, संघ के माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री, सीए के. रहमान खान, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य सभा ।

- तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री श्री पी.चिदम्बरम ने 1 जुलाई, 2008 को हीरक जयन्ती के अवसर पर डाक विभाग द्वारा जारी विशेष आवरण पत्र का विमोचन किया था ।
- संस्थान की पहल - 'वातावरण बचाव' को प्रोत्साहित करने के लिए, 1 जुलाई, 2008 को श्रीमती आरती मेहरा, मेयर, दिल्ली नगर निगम ने नई दिल्ली स्थित संस्थान के परिसर में पौधारोपण किया था ।
- 1 जुलाई, 2008 को पद्मश्री सुश्री हेमा मालिनी द्वारा - भगवान शिव और मां दुर्गा (शक्ति) को समर्पित एक लाइव कला प्रदर्शन किया गया था ।
- 2 और 3 जुलाई, 2008 को "चार्टर्ड एकाउंटेंसी वृत्ति भूतकाल में और भविष्य में" विषय पर हीरक जयन्ती सम्मेलन ।
- उपरोक्त सम्मेलन में अन्य व्यक्तियों के साथ श्री मोंटेकसिंह अहलुवालिया, माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग, श्री विनोद राय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सीए सी. रामचन्द्रैया, संसद् सदस्य, श्री वी.के.ढल, कार्यकारी अध्यक्ष, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, श्री अनुराग गोयल, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और श्री दिलीप पदगांवकर, विख्यात पत्रकार ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया था ।
- उपरोक्त सम्मेलन में श्री मोंटेकसिंह अहलुवालिया ने "दी एकाउंटेंसी प्रोफेशन एंड इकनोमिक डेवलपमेंट इन इंडिया" नामक एक पुस्तक का विमोचन किया था ।
- 2 जुलाई, 2008 की संध्या में सुश्री श्रेया घोषाल, श्री तोषी सावरी और अन्यो द्वारा लाइव कला प्रदर्शन ।
- चार्टर्ड एकाउंटेंट के जुलाई, 2008 अंक को विशेष अंक के रूप में निकाया गया । इस अवसर पर प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं ने भी न्यूज लेटर के विशेष अंक निकाले ।
- प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं ने भी संस्थान की हीरक जयन्ती के अवसर पर सम्मेलनों और कार्यक्रमों का आयोजन किया । ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों में सीए रामेश्वर ठाकुर, कर्नाटक के माननीय राज्यपाल, डा. ए.आर.किदवई, हरियाणा के राज्यपाल, श्री एस. जयपाल रेडडी, संघ के शहरी विकास मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री और श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, संघ के गृह राज्य मंत्री सम्मिलित थे ।

2 और 3 जुलाई, 2008 को हीरक जयन्ती सम्मेलन का आयोजन

2 और 3 जुलाई, 2008 को "चार्टर्ड एकाउंटेंसी वृत्ति भूतकाल में और भविष्य में" विषय पर हीरक जयन्ती सम्मेलन का आयोजन कन्वेंशन हॉल, दी अशोक, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में किया गया था ।

इसमें 1 जुलाई, 2008 से हीरक जयन्ती समारोह के प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में आईसीएआई ने 2 और 3 जुलाई, 2008 को "चार्टर्ड एकाउंटेंसी वृत्ति भूतकाल में और भविष्य में" विषय पर हीरक जयन्ती सम्मेलन का आयोजन किया गया था । इस सम्मेलन में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट समुदाय के 1500 सदस्यों ने भाग लिया था जिसमें साफा देशों के 50 सदस्य भी सम्मिलित थे । इस सम्मेलन को व्यापार और उद्योग, विनियामकों के दिग्गजों, बहुपार्श्विक अभिकरणों, अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारक निकायों और सार्क क्षेत्र के लेखाकरण निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा संबोधित किया गया था ।

आईसीएआई द्वारा 13 से 16 मार्च, 2009 के दौरान हरिद्वार में राष्ट्रीय नेतृत्व और योग शिविर, अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने सभी उटीयर - केन्द्रीय परिषद्, प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 13 से 16 मार्च, 2009 के दौरान योगिक क्रियाओं पर विख्यात योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज और आचार्य श्री बालकिशन जी, आध्यत्मवादी और आयुर्वेद विद्वान द्वारा एक चार-दिवसीय 'राष्ट्रीय नेतृत्व और योग शिविर' का सफलतापूर्वक आयोजन किया था, जिसमें स्वस्थ, रोग मुक्त काया और शांत तथा चौकन्ने मस्तिष्क के फायदे बताए गए थे । इस योग सत्र, जो स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा योगिक जीवन पर व्याख्यान से प्रारंभ हुआ था, में पूरे भारत से सीए बिरादरी के 600 से अधिक नेताओं ने भाग लिया था । योग क्रियाओं के अलावा, इस शिविर में वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञों का अनुष्ठान भी किया गया था जिसमें सभी क्षेत्रों से चार्टर्ड एकाउंटेंटों के नेताओं ने भाग लिया था । योगिक सत्रों के बाद राष्ट्रीय ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गान तथा वंदे मातरम का गायन किया गया था ।

सभी प्रदेशों, अर्थात् पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों के शाखा अनुकूलन कार्यक्रमों में विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था, जिनमें से मुख्य मुद्दे थे, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, संस्थान के रणनीति संबंधी विनिश्चयों और नीति बनाने की प्रक्रिया में शाखाओं का योगदान, सतत वृत्तिक विकास, न्यायिक लेखाकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक आदि । इन बैठकों में संस्थान के वरिष्ठ कृत्यकारियों ने व्यापक रूप से भाग लिया था और उन्होंने इन बैठकों को संबोधित किया था । यह उल्लेखनीय है कि आईसीएआई की 118 शाखाओं के 600 से अधिक नेता इस अद्वितीय सत्र का भाग हैं । स्वामी रामदेव जी महाराज ने प्रत्येक बैठक को संबोधित किया था ।

इस शिविर में, वृत्तिक विकास कार्यक्रम के भाग रूप में ऋषिकेश और हरिद्वार दर्शन के लिए एक ट्रेन भी सम्मिलित था, जिससे चार्टर्ड एकाउंटेंटों के नेताओं ने यह सीखा कि किस प्रकार योग क्रियाओं के साथ अध्यात्मवाद जीवन को तनाव मुक्त बना सकता है और दिन-प्रतिदिन की सामान्य गतिविधियों के साथ वृत्तिक जीवन में दक्षता और प्रभाविकता में वृद्धि कर सकता है।

योग शिविर के अंतिम दिन, स्वामी रामदेव जी महाराज ने सीए वृत्ति की और उसके द्वारा आम जनता में विश्वास के संवर्धन की अत्यधिक प्रशंसा की। उनका विचार यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए कि योग क्रियाएं, साधारण जीवन और उच्च विचार ऐसा मार्ग है जो ईश्वर और मानव के बीच सेतु का कार्य करता है। उन्होंने चार्टर्ड एकाउंटेंटों से यह अनुरोध किया कि वे भारत स्वाभिमान आंदोलन के प्रयासों में सहयोग दें, जिससे कि दोनों मिलकर शङ्खसन के सामाजिक पहलुओं को नई दिशा प्रदान कर सकें।

इस अवसर पर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य क्षेत्रों से सीए बिरादरी के प्रतिनिधियों ने स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन की भूमि-भूमि प्रशंसा की और भारत स्वाभिमान आंदोलन की प्रादेशिक स्तर की गतिविधियों में पूर्ण सहयोग का प्रस्ताव किया।

शनिवार 4 अप्रैल, 2009 को फिरोजशाह कोटला मैदान, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली में टीम आईसीएआई और टीम आईआरएस (आय-कर) के बीच अखिल भारतीय हीरक जयंती टी 20 क्रिकेट मैच

हीरक जयंती समिति के तत्वावधान में 4 अप्रैल, 2009 को फिरोजशाह कोटला में एक टी-20 दिन-रात हीरक जयंती क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। एक कड़े संघर्ष के बाद टीम आईआरएस आय-कर को हराकर टीम आईसीएआई ने मैच अपने नाम किया था। इससे पूर्व आईसीएआई परिषद् सदस्यों और सीबीडीटी कृत्यकारियों के बीच एक प्रदर्शन मैच हुआ था। इन आयोजनों का डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव प्रसारण किया गया था, जिसे बड़ी संख्या में जनता ने देखा था।

आगरा में 3-5 जुलाई, 2009 के दौरान “चुनौतिपूर्ण परिस्थितियाँ-लेखाकरण वृत्ति के लिए वैश्विक रणनीतियाँ” विषय पर आईसीएआई हीरक जयंती अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

इस तीन दिवसीय सम्मेलन में उभरते और समकालीन महत्व के मुद्दों पर विचार किया गया था, अर्थात् अंतरराष्ट्रीय मानकों से संगतता, वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, प्रत्याशाओं में कमी को पूरा करना, वित्तीय बाजार और उनसे परे। सम्मेलन के कारण, आगरा में, जहाँ सदस्यों की संख्या लगभग 500 है, आईसीएआई के लगभग संपूर्ण सदस्य एकत्रित हुए, इस सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नब्बे प्रतिशत से अधिक व्यक्ति देश के अन्य भागों से आए थे और साथ ही इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और अधिकांश विकसित देशों में से लगभग 25 देशों से 200 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था।

इस सम्मेलन में सर डेविड स्पीडी, अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड, डा. आरनोल्ड शिल्डर, अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड, श्री इरनी एल्मोट, सीपीए अध्यक्ष, अमरीकी प्रमाणित लोक एकाउंटेंट्स संस्थान, सुश्री लिव वाटसन, उपाध्यक्ष, एक्सबीआरएल जैसे सुविख्यात व्यक्तियों ने भाग लिया था।

3 जुलाई की संध्या में भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की धीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें सुश्री सुरभि सिंह - कृष्णा धीम पर कथक नृतिका, श्री सुरेन्द्र हर्मा (विख्यात हस्त्य कवि), श्री नीतिन चोपड़ा - शिव नृत्य, उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति (होली/रासलीला/मयूर नृत्य), राजस्थान की लोक संस्कृति (कालबेलिया/धूमर), पंजाबी लोक-संस्कृति (गिद्धा और भांगड़ा) के कला-प्रदर्शन सम्मिलित थे।

4 जुलाई, की संध्या में बालीवुड सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री उदित नारायण, मोनिका ठाकुर और दल सम्मिलित हुए थे। 5 जुलाई, 2009 को, अर्थात् अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन, आगरा गो ग्रीन दौड़ का आयोजन किया था, जो चार्टर्ड एकाउंटेंटों और छात्रों को जीवन के सभी क्षेत्रों से आने वाले ऐसे व्यक्तियों, जो पर्यावरण की संरक्षा के प्रति चिंतित हैं, के साथ लाने के लिए एक बड़ी पहल थी। इस दौड़ में राहुल बोस जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भाग लिया था। इस दौड़ में 3000 से अधिक छात्रों और सदस्यों तथा उनके परिवारों ने भाग लिया था।

“व्यवसायिकता - आर्थिक विकास का एक उपकरण” विषय पर आईसीएआई हीरक जयंती सम्मेलन

अपने साठ वर्ष के ऐतिहासिक जीवन और इस वर्ष को आईसीएआई के हीरक जयंती वर्ष के रूप में मनाते हतुए, आईसीएआई ने 11 जुलाई, 2009 को दरबार हॉल, होटल ताज पैलेस, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली में अपने सदस्यों के लिए “व्यवसायिकता - आर्थिक विकास का एक उपकरण” विषय पर आईसीएआई हीरक जयंती सम्मेलन का आयोजन किया था।

इस सम्मेलन का उद्घाटन श्री के. रहमान खान, राज्य सभा के माननीय उप सभापति ने किया था। सीए अखिल गुप्ता, अध्यक्ष और उप सीईओ, भारतीय एंडसाइज और केपीएमजी की सीए अर्चना भूटानी ने अपने-अपने प्रस्तुतिकरण किए थे।

“हीरक जयंती समारोह” पर एक पृथक वेबपृष्ठ www.icaai.org पर उपलब्ध है। यह वेबपृष्ठ, अन्य बातों के साथ, आईसीएआई का निगमों और अन्यो को आईसीएआई हीरक जयंती समिति की विभिन्न पहलों से सहबद्ध होने के अनुरोध का भी वर्णन करता है।

यद्यपि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को हम सीए दिवस के रूप में मनाते हैं, किन्तु इस वर्ष के महत्व को देखते हुए, जो हीरक जयंती का महत्वपूर्ण वर्ष है, यह विनिश्चय किया गया है कि आईसीएआई के योगदान को दर्शित करने वाले आयोजनों का आयोजन करके/में सहयोग करके विभिन्न समकालीन और उमस्ते क्षेत्रों में आईसीएआई की भूमिका को स्थापित किया जाए। जुलाई, 2009 से जून, 2010 के बीच की अवधि को विभिन्न क्रियाकलापों के लिए मास-वार समर्पित किया जाए। प्रारंभिक रूप में, समिति ने पहले छह मास के लिए निम्नलिखित विषयवस्तुओं को तय किया है:

गतिविधि	मास
गो ग्रीन	जुलाई, 2009
शिक्षा पहल और आईटी प्रशिक्षण	अगस्त, 2009
करियर परामर्श	सितम्बर, 2009
सशक्तिकरण	अक्टूबर, 2009
कृषि	नवम्बर, 2009
जन जागरूकता	दिसम्बर, 2009
खेल-कूद और युवा समारोह	जनवरी, 2010

8. अन्य मामले

8.1 आईसीएआई का वार्षिक समारोह

आईसीएआई का 59वां वार्षिक समारोह 4 फरवरी, 2009 को नई दिल्ली में हुआ था। श्री प्रेम चंद गुप्ता, संघ के माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री मुख्य अतिथि थे। समारोह में वर्ष 2007-08 के लिए 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार', आईसीएआई द्वारा संचालित परीक्षाओं में मेधावी छात्रों को पुरस्कार तथा मेडल और आईसीएआई की उत्कृष्ट प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को शील्ड तथा प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए थे। समारोह में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, सदस्यों, छात्रों, आईसीएआई के अधिकारियों तथा कर्मचारियों सहित बहुत बड़ी संख्या में आमंत्रितियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स वृत्ति पर प्रशंसा की बौछार लगा दी।

8.2 चार्टर्ड एकाउंटेंट विनियम, 1988 में संशोधन

(i) वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने चार्टर्ड एकाउंटेंट विनियम, 1988 के निम्नलिखित विनियमों में संशोधनों को अपना अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है :-

विनियम 3क	सदस्यों की सूची	भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 3, खंड 4 तारीख 25 सितम्बर, 2008 में अधिसूचना सं. 1सीए(7)/116/2008, तारीख 25 सितम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित
विनियम 5(1)	सदस्यता के लिए आवेदन	
विनियम 6	फीस	
विनियम 10	किसी वृत्ति प्रमाणपत्र का रद्दकरण	
विनियम 11	किसी वृत्ति प्रमाणपत्र को पुनःप्रवृत्त करना	
विनियम 12, 13, 14, 15, 16 और 17	परिवर्धन केवल संबंधित विनियमों के शीर्षों के पश्चात्	
विनियम 17क	निदेशक (अनुशासन), अनुशासन निदेशालय द्वारा किसी शिकायत या सूचना के अन्वेषण के लिए ली जाने वाली फीस और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा अनुशासन समिति द्वारा जांच की प्रक्रिया - 17.11.2006 को या उसके पश्चात् प्राप्त होने वाली शिकायत या सूचना को लागू।	
विनियम 19	पुनःसदस्यता प्रदान करना	
विनियम 53क	अन्य वृत्तिक निकाय	
विनियम 53ख	भागीदारी के लिए वृत्तिक निकायों की सदस्यता	
विनियम 82 से 126	अध्याय VI -निर्वाचन -हटाए जाने के लिए	
विनियम 137(9)	पदधारी और समितियां	
विनियम 174क	परिषद् की समितियां	

विनियम 175	कार्यकारी समिति	भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 3, खंड 4 तारीख 3 दिसम्बर, 2008 में अधिसूचना सं. 1सीए(7)/123/2008, तारीख 3 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित
विनियम 176क	वित्त समिति	
विनियम 194	लेखाओं का रखा जाना	
विनियम 197	बजट संबंधी वास्तविक आंकड़ों की बजट प्राक्कलनों से तुलना	
विनियम 28घ	एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम के लिए नामांकन और फीस	
विनियम 28ङ	एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम में प्रवेश, परीक्षा, फीस और पाठ्यचर्या	
विनियम 29ग	फाइनल परीक्षा में प्रवेश	
विनियम 31 (iii)	एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम में नामांकन प्रारंभ होने के पश्चात् परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट पाठ्यचर्या के अनुसार - परिवर्धन के लिए	
विनियम 37ग	एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षाएं	
विनियम 38ग	फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षाएं	
विनियम 40	परीक्षा प्रमाणपत्र	
विनियम 45	आर्टिकलशिप में प्रवेश	
विनियम 50	परंतु यह भी कि एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम के लिए नामांकित कोई अभ्यर्थी, उसके द्वारा ग्रुप एक स्तर या एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम परीक्षा का लेखाकरण तकनीशियन स्तर उत्तीर्ण किए जाने पर 3 वर्ष की आर्टिकलशिप के लिए पात्र होगा - परिवर्धन के लिए	

8.3 केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय

केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व से जुड़ा है, पूर्णतया कंप्यूटरीकृत और क्रियाशील है। पुस्तकों, पत्रिकाओं और लेखों के डाटाबेस सहित पुस्तकालय सामग्री की खोज, विषय, लेखक, शीर्षक, प्रसंग, प्रमुख-शब्द और प्रकाशक-वार की जा सकती है अभिलेख इंटरनेट ऑन लाइन सेवा www.icai.org पर “नो युअर इंस्टीट्यूट-सेंट्रल काउंसिल लाइब्रेरी” के अधीन उपलब्ध है। निर्देश सेवा विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं और विद्वानों को तथा विशेष मामले के रूप में आईसीएआई का सीपीटी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है। आईसीएआई के प्रत्येक निदेशालय को दिए गए केन्द्र पुस्तकालय के साथ, संस्थान के नोएडा कार्यालय और विश्वास नगर छात्र पुस्तकालय को भी केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय www.icai.org पर “नो युअर इंस्टीट्यूट-सेंट्रल काउंसिल लाइब्रेरी” के माध्यम से विभिन्न पुस्तकालय सेवाएं उपलब्ध कराती है। ये सेवाएं स्व-स्पष्टीकारक हैं। इनमें से कुछ लिक जैसे कि ऑन लाइन जर्नलों की सूची, ई-पुस्तकें, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स जर्नलों से लेख और पुस्तकें, जर्नलों का ऑन लाइन डाटाबेस तथा पुस्तकालय में लेख पूर्वोक्त ऑन लाइन डाटाबेस में आगे और सर्च उपलब्ध कराते हैं। “सजेस्ट बुक्स/जर्नल कॉलम्स” के अधीन कोई भी व्यक्ति संस्थान को नई पुस्तकों/जर्नलों का सुझाव दे सकता है। यह उल्लेखनीय है कि “दि एकाउंटेंट्स ब्राउज़र” पिछले 10 वर्षों के संग्रह के साथ महत्वपूर्ण/वृत्तिक लेखों की अनुक्रमणिका है।

पूर्वोक्त के अतिरिक्त, पुस्तकालय ने केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय परिसरों और विभिन्न विभागों में, छात्रों, सदस्यों, संकाय सदस्यों और अनुसंधान विद्वानों द्वारा अपेक्षित सामग्री के लिए सर्च को सुकर बनाने के लिए अनेक आईसीएआई डाटाबेस प्रतिष्ठापित किए हैं। केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय के डाटाबेस को सभी प्रादेशिक पुस्तकालय डाटाबेस के साथ जोड़ने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर - लिबर्टी अर्जित किया गया है। केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय, सभी समितियों के लिए प्रकाशनों/पुस्तकों का उपबंध सम्मिलित करते हुए आईसीएआई द्वारा प्रस्थापित निम्नलिखित विद्यमान पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक प्रकाशन/पुस्तकों का भी उपापन कर रहा है।

- उद्यम जोखिम प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

- मास्टर इन बिजनेस फाइनेंस संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- निगम शासन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- आईटी और सीएएटी का उपयोग करते हुए न्यायिक लेखाकरण और कपट पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- फॉरेंस और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- व्युत्पत्तियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- मूल्यांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- माध्यस्थ्य संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

वेबसेवाएं :

www.icai.org पर उपलब्ध वेब सेवाएं निम्नलिखित हैं :-

- ऑन लाईन जर्नलों की सूची
- ई-बुक लिंक्स
- चार्टर्ड एकाउंटेंट जर्नल (1951-2000) से लेख
- चार्टर्ड एकाउंटेंट जर्नल (2001-2007) से लेख
- केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय - केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय में पुस्तकों, जर्नलों और लेखों के डाटाबेस के लिए एक पूर्ण ऑनलाईन सर्च
- केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय में डब्ल्यूटीओ विषय पर उपलब्ध पुस्तकों की सूची
- एकाउंटेंट्स ब्राउज़र, पिछले 10 वर्षों के वृत्ति संबंधी लेखों का संग्रह
- केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय - नई दिल्ली - सम्मेलन/संगोष्ठी
- पुस्तकालय में उपलब्ध सीडी
- चार्टर्ड एकाउंटेंट अनुक्रमणिका जुलाई, 2002 - जून, 2007
- सिफारिश की गई पुस्तकों की सूची
- पुस्तकालय प्रतिभूति निक्षेप नियम
- पुस्तकालय समाचार और मत
- केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय द्वारा मंगाए जाने वाले जर्नलों की सूची
- पुस्तकालय सेवा - सदस्यों से सदस्यता
- पुस्तकालय सेवा - छात्रों से सदस्यता
- पुस्तकालय में उपलब्ध फोटोग्राफ
- हाल ही में हुई परिवृद्धियां - केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय में क्रय की गई पुस्तकों
- पुस्तकालय में उपलब्ध एसएएफए पुस्तकें/प्रकाशन
- सुझाई गई पुस्तकें/जर्नल

पुस्तकालय में प्रतिष्ठापित ऑन लाईन डाटाबेस निम्नानुसार हैं :-

- पुस्तकालय साफ्टवेयर - लिबर्टी
- आईबीएफडी की इलेक्ट्रानिक सदस्यता
- प्रोवेस (सीएमआईई)
- सीटीआर ऑनलाईन
- आईटीआर ऑनलाईन
- मनुपत्रालो डाट काम
- एक्सकस ऑनलाईन
- ई-ज्यूरिक्स

- इंडस्ट्री डाट काम
- डेटनेट
- इंडियास्टेट डाट काम
- टेक्समैन

8.4 संपादकीय बोर्ड

आज के तेजी से बढ़ते हुए सार्वभौमिक युग में, विभिन्न विषयों, नए-नए उभरते क्षेत्रों, वृत्ति के पहलुओं और चुनौतियों से आईसीएआई के सदस्यों और चार्टर्ड एकाउंटेंट पत्रिका के अन्य पाठकों को अद्यतन बनाए रखने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए संपादकीय मंडल ने इस रिपोर्ट की अवधि (1.4.2008 और 31.5.2009 के बीच की) के दौरान अनेकों महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं।

यह आईसीएआई का ब्रांड अम्बेसेडर है और सदस्यों, छात्रों तथा बाह्य श्रोताओं के लिए संस्थान के प्रोफाइल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आज चार्टर्ड एकाउंटेंट विश्व की ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं से टक्कर ले रहा है चाहे वह अंतर्वस्तु की गुणवत्ता हो, गहन द्रष्टिकृत कवरेज, परस्पर क्रियात्मक फीचर, अंतरराष्ट्रीय मानक ले आउट/डिजाइनिंग, पेपर क्वालिटी, बाहरी आवरण या समय से लोगों तक पहुंच हो, सबसे अधिक विश्वसनीय और पाठक मैत्रिक के रूप में इसकी मान्यता लगातार बढ़ती जा रही है। यदि हमारे पाठकों की प्रतिक्रिया से यह सब उपदर्शित होता है तो यह न केवल सदस्यों के लिए बल्कि सहयुक्त वृत्तियों, संस्थाओं और भारत तथा विदेशों में आर्थिक जगत के हर वर्ग में अद्यतन वृत्तिक ज्ञान का उपकरण बन गया है।

इसकी व्यापक पहुंच और पाठन आधार की दृष्टि से इस पत्रिका का कुल परिचालन, आज 1,91,000 से अधिक हो गया है।

अंतर्वस्तु और ई-जर्नल :

- 1.4.2008 और 31.5.2009 के दौरान, विभिन्न विषयों पर कुल 160 लेखों का मुद्रण किया गया था।
- समाज में व्यापक रूप से वृत्ति की छवि का संवर्धन करने के लिए यह विनिश्चय किया गया था कि वृत्तिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आईसीएआई के सदस्यों की सफलता संबंधी असाधारण चयनित कहानियों को प्रकाशित किया जाए और जर्नल में नौ नए फीचर - 'इंडस्ट्री स्पेसिफिक', 'इंटरनेशनल टैक्सेसन', 'ग्लोबल पर्सपेक्टिव', 'करियर', 'मैनेजमेंट', 'आउटसोर्सिंग', 'वास्तुशास्त्र', 'नो युवर फ्यूचर', 'हेल्थ' प्रारंभ किए गए थे। 'नेशनल अपडेट', 'इंटरनेशनल अपडेट' और 'लीगल अपडेट' को, सदस्यों को बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समृद्ध बनाया गया था।

आईसीएआई के हीरक जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में एक अद्वितीय 218 पृष्ठ का जुलाई, 2008 अंक निकाला गया था और उसमें आईसीएआई के इतिहास के दुर्लभ गर्वपूर्ण क्षणों को व्यापक रूप से समाविष्ट किया गया था।

- न्यूनतम 1000 करोड़ की आवर्त वाली कंपनियों के सीईओ/सीएफओ को और 500 सबसे बड़ी कंपनियों के अध्यक्षों, सीईओ, महानिदेशकों और सीएफओ को जर्नल के लेखों में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया था जिससे कि जर्नल के आधार को व्यापक बनाया जा सके और उसमें सुधार किए जा सकें।
- ऑनलाइन जर्नल, जिसे एक अद्वितीय यूआरएल, www.ejournal.icai.org, के साथ आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था, उसे किसी उपलब्ध विनिर्दिष्ट सॉफ्टवेयर की अपेक्षा के बिना तीव्र और सुगम ब्राउज़िंग और सर्च सुविधा के साथ और अधिक सक्रिय तथा प्रयोक्तामित्र बनाने के लिए और समुन्नत तथा नवीकृत किया गया था। ई-जर्नल के प्रत्येक अंक को, समय से ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया था। आईसीएआई वेबसाइट पर जर्नल पृष्ठ और संपादकीय बोर्ड पृष्ठ को व्यापक रूप से समुन्नत और अद्यतन किया गया था।

ले आउट और डिजाइन :

- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार संपूर्ण जर्नल के ले आउट और डिजाइन तथा फोंट टाइप फ़ेस को और अधिक समुन्नत किया गया था।
- आवरण पृष्ठ के मास्ट हेड और आधारिक टेम्पलेट में और सुधार किया गया था।

अन्य पहलें

- आईसीएआई के ब्रांड निर्माण के लिए पहलों के भागरूप में में प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं के न्यूज लेटरों के, उनके आवरण पृष्ठ, मास्ट हेड, रंगक संयोजन, प्रस्तुतीकरण स्टाइल और अंतर्वस्तु के निबंधानुसार 'प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा प्रकाशित न्यूज लेटरों संबंधी सलाह' (कार्यपालक समिति द्वारा

यथाअनुमोदित रूप में) और संपादकीय बोर्ड द्वारा लिए गए विनिश्चयों की रूपरेखा का कड़ाई से पालन करते हुए मानकीकरण के लिए प्रयास किए गए थे।

- नोएडा में एक अद्वितीय भारतीय लेखाकरण संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अन्य वस्तुओं के साथ, संग्रहालय भारत में लेखाकरण के विकास की दुर्लभ और ऐतिहासिक छवियों (मानव सभ्यता में सबसे पुराने तुलन पत्र का साक्ष्य) और दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रस्तुत करता है।
- सीए छात्रों के बृहत्तर फायदे के लिए यह विनिश्चय किया गया था कि उनकी फीस संरचना में जर्नल प्रचारों को सम्मिलित करते हुए उन्हें जर्नल का अनिवार्य रूप से प्रदाय किया जाए।
- बोर्ड ने प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों के ऑन लाइन पाठ के अनुसार जर्नल के अनन्य ऑन लाइन पाठ की अभिकल्पना की थी। जर्नल के एक चल पाठ की भी परिकल्पना की गई है।
- जर्नल की सकल गुणवत्ता में और सुधार करने के लिए एक पाठक सर्वेक्षण किया गया था जिसके परिणामस्वरूप पाठकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।
- जर्नल के पठन में अतिरिक्त सुगमता प्रदान करने के लिए, सदस्यों को, यदि वे वांछ करते हैं तो उनके आवास के पते पर उनकी जर्नल की प्रति प्राप्त करने का विकल्प दिया गया था।
- वृत्तिक संपादकों के पैनल में विस्तार किया गया था जिससे कि वृत्तिक भाषा संपादन के पश्चात् आईसीएआई प्रकाशनों के शीघ्र जारी होने को सुकर बनाया जा सके।

8.5 उच्च स्तरीय समिति

मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा कंपनी के अनेक वर्षों के वित्तीय विवरणों में गंभीर अनियमितताओं और मिथ्या कथनों के बारे में प्रकटन के साथ एक बहुत बड़ी रकम को अंतर्विष्ट करने वाला निगम कपट सामने आया था। तत्कालीन अध्यक्ष ने 7 जनवरी, 2009 को दिए अपने स्वीकारोक्ति ब्यान में लेखाओं में गड़बड़ करने और अनेक वर्षों तक अधिक लाभ दर्शित करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया था।

इस पूरे कांड से वित्तीय विवरणों और रिपोर्टिंग, निगम शासन, संपरीक्षा की प्रक्रिया, सम्यक ध्यान संबंधी कार्यवाही और संपरीक्षकों की भूमिका की प्रभाविकता और विश्वसनीयता तथा शेयरधारकों/निवेशकों की अतिसंवेदनशीलता के संबंध में गंभीर आशंकाएं उत्पन्न हुई हैं। इस वित्तीय कपट से, जिसके न केवल भारतीय निगम क्षेत्र अपितु भारतीय निगम में शासन प्रणाली पर भी गंभीर रूप से दुष्प्रभाव पड़े हैं, गंभीर रूप से विवर्तित आईसीएआई की परिषद् ने साधारण जनता में लेखांकन और लेखा परीक्षा वृत्ति के प्रति विश्वास पुनःस्थापित करने की आवश्यकता को महसूस किया और इसलिए उसने सत्यम कांड की संपूर्ण रूप रेखा की जांच करने, जिसके अंतर्गत विभिन्न अभिकरणों द्वारा किए जा रहे अन्वेषणों में सहायता/सहयोग करना, समस्या की जड़ तक जाना, विद्यमान प्रणाली की प्रभाविकता, प्रणाली संबंधी मुद्दे, इसमें संलिप्त/सहबद्ध व्यक्तियों सहित मूल कारणों की पहचान करना और जहां कहीं अपेक्षित हो केन्द्रीय सरकार, सेबी और अन्य विनियामकों को उपयुक्त सिफारिशें करने के प्रयोजन के लिए परिवर्तनों का सुझाव देना है, नई दिल्ली में 12 और 13 जनवरी, 2009 को हुई अपनी 284वीं बैठक में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।

इस समिति का कार्य प्रगति पर है।

9. सदस्य

9.1 सदस्यता

31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान आईसीएआई द्वारा 8,395 नए सदस्यों को दर्ज किया गया था जिससे 1 अप्रैल, 2009 को आईसीएआई की कुल सदस्यता संख्या 153600 हो गई, जिसके अंतर्गत साधारण क्षमा स्कीम (जो 31 मार्च, 2009 को समाप्त हो गई) के अधीन ऐसे 2131 सदस्य भी हैं, जिनकी सदस्यता वापस की गई है।

पूर्व वर्ष में 2936 की संख्या की तुलना में 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 3,101 सहयोजित सदस्य अध्येता के रूप में प्रविष्ट किए गए।

1.4.2009 को सदस्यों की कुल संख्या

सदस्यों का प्रवर्ग	अध्येता (1)	सहयोजित (2)	स्तंभों का योग (1) और (2)
पूर्णकालिक व्यवसाय में	51298	19064	70362
अंशकालिक व्यवसाय में	3081	5230	8311

जो व्यवसाय में नहीं हैं	9539	65388	74927
	63918	89682	153600

9.2 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कल्याण निधि

दिसम्बर, 1962 में स्थापित चार्टर्ड एकाउंटेंट कल्याण निधि ऐसे जरूरतमंद लोगों, जो संस्थान के सदस्य हैं या रहे हैं और उनके आश्रितों को उनके भरण-पोषण तथा शिक्षा और चिकित्सा आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। निधि की वित्तीय विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :-

सदस्यता के ब्यारे

1.	31.03.2008 को कुल आजीवन सदस्य	= 87,029
2.	31.03.2009 को कुल आजीवन सदस्य	= 94,480
3.	नए आजीवन सदस्यों में कुल वृद्धि (31.03.2009 तक)	= 7,451
4.	31.03.2009 तक दी गई कुल वित्तीय सहायता	= 79

वित्तीय विशिष्टियों के ब्यारे

	31.3.2008 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.3.2009 को समाप्त वर्ष के दौरान
1.	दी गई कुल वित्तीय सहायता	1,64,16,000.00
2.	प्रशासनिक खर्च	11,235.00
3.	निधि में अधिशेष (कमी)	(72,46,236.00)
4.	निधि का अतिशेष	1,66,91,180.00
5.	कोरपस का अतिशेष	7,35,97,300.00
		57,00,000.00
		14,438.00
		32,17,810.00
		1,99,08,990.00
		8,06,82,800.00

9.3 एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान, 500 रुपए प्रतिमास के मूल्य की 60 छात्रवृत्तियां, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को दी जानी है। निधि की आजीवन सदस्यता 31 मार्च, 2008 को 1527 के मुकाबले 31 मार्च, 2009 को बढ़कर 1775 हो गई थी। निधि के पास जमा शेष 31 मार्च, 2008 को 10,29,295/- रुपए के मुकाबले 31 मार्च, 2009 को 9,57,181/- रुपए था।

9.4 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि (सीएसबीएफ)

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स पाठ्यक्रम के छात्रों को वित्तीय और अन्य अनुषंगी प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य और उद्देश्यों से अगस्त, 2008 में इस निधि की स्थापना की गई थी। प्रारंभ में, सीएसबीएफ लगभग 100 छात्रों को एक वर्ष के लिए 1000 रुपए प्रति मास मूल्य की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। 31 मार्च, 2009 को जनरल निधि के पास 21,44,658/- रुपए का अतिशेष जमा था।

10. छात्र

10.1 छात्रों के आंकड़े

एकीकृत वृत्तिक राक्षमता पाठ्यक्रम और लेखाकरण तकनीशियन पाठ्यक्रम नामक शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी एक नई योजना 1 दिसम्बर, 2008 से आरंभ की गई थी और उक्त पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रीकरण 10 दिसम्बर, 2008 से प्रारंभ हुआ था। 2004-2005 से 2008-2009 के पिछले पांच वर्षों और 1 अप्रैल, 2009 से 31 मई, 2009 तक के दौरान रजिस्ट्रीकृत छात्रों के संबंध में ब्यारे नीचे उपदर्शित हैं :

वर्ष	फाइनल (पुराने और नए)	सीपीटी	पीसीसी	आईपीसीसी	एटीसी (अनन्य रूप से रजिस्ट्रीकृत)
2004-2005	11,061	-	-	-	-

2005-2006	13,010	-	-	-	-
2006-2007	11,838	1,29,110 (13.9.2006 से आगे)	24,041 (13.9.2006 से आगे)	-	-
2007-2008	19,558	1,42,612	61,186	-	-
2008-2009	11,562	1,39,140	33,764	18,318 (10.12.2008 से आगे)	8 (10.12.2008 से आगे)
1 अप्रैल, 2009 से 2 जुलाई, 2009	1,123	34,720	642	754	-
योग	68,152	4,45,582	1,19,633	19,072	8

1 अप्रैल, 2009 से 2 जुलाई, 2009 की अवधि के दौरान वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम 1) के 5 छात्रों ने सामान्य प्रवीणता परीक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने का विकल्प लिया था (2008-2009 में यह संख्या 747 थी) । वर्ष 2008-09 के दौरान वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम 2) के 268 छात्रों ने और 1 अप्रैल, 2009 से 2 जुलाई, 2009 की अवधि के दौरान 4 छात्रों ने सामान्य प्रवीणता परीक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने का विकल्प लिया था । वर्ष 2008-09 के दौरान वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम 2) के 104 छात्रों ने और 1 अप्रैल, 2009 से 2 जुलाई, 2009 की अवधि के दौरान 20 छात्रों ने नए प्रारंभ किए गए शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अर्थात् एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने का विकल्प लिया था ।

10.2 प्रत्यायन स्कीम

31 मार्च, 2009 के दौरान सीपीटी मौखिक कोचिंग कक्षाएं संचालित करने के लिए प्रत्यायित संस्थाओं की सूची में 3 और संस्थाओं के नामों को सम्मिलित किया गया था, इस प्रकार उनकी कुल संख्या 131 (128 +3) हो गई है तथा 1 और को पीसीसी मौखिक कोचिंग कक्षाओं के संचालन के लिए सम्मिलित किया गया था, इस प्रकार उनकी कुल संख्या 74 (73+1) हो गई है । पीई (पाठ्यक्रम - 2) के लिए प्रत्यायित संस्थाओं की कुल संख्या वही बनी रही, जो कि 96 है और साथ ही फाइनल पाठ्यक्रम के लिए विद्यमान 10 संस्थाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

10.3 नए पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री

10 दिसम्बर, 2008 को, शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी एक नई स्कीम प्रारंभ करने के पश्चात्, एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (आईपीसीसी) और लेखाकरण तकनीशियन पाठ्यक्रम (एटीसी) के लिए अंग्रेजी अध्ययन सामग्री जारी की गई थी । हिन्दी की अध्ययन सामग्री तैयार की जा रही है और योजना के अनुसार उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए हिन्दी अध्ययन सामग्री जारी कर दी गई है ।

10.4 सुझाए गए उत्तर

मई, 2008 और नवंबर, 2008 में कराई गई निम्नलिखित परीक्षाओं के लिए सुझाए गए उत्तरों को मुद्रित किया गया था और उन्हें प्रदेशों और शाखाओं में नवंबर, 2008 और जून, 2009 की परीक्षाओं से तीन मास पूर्व वितरित किया गया था ।

वृत्तिक शिक्षा परीक्षा - 2 (पीईई-2)

समूह - 1

समूह - 2

वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (पीसीसी)

समूह - 1

समूह - 2

फाइनल (पुराना)

समूह - 1

समूह - 2

फाइनल (नया)

समूह - 1

समूह - 2

छात्रों को परीक्षाएं देने के लिए बेहतर तैयारी करने में सक्षम बनाने और उनके मार्गदर्शन के लिए अध्ययन बोर्ड ने आईसीएआई की वेबसाइट पर सुझाए गए उत्तरों को रखा था जिसमें उन्हें निःशुल्क डाउनलोड करने का विकल्प उपलब्ध था।

10.5 पुनरीक्षण परीक्षा पत्र (आरटीपी)

पीई-2, पीसीसी और फाइनल के लिए पुनरीक्षण परीक्षा पत्रों (आरटीपी) को समय से प्रदेशों और शाखाओं को भेजा गया था जिससे कि छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

पुनरीक्षण परीक्षा पत्रों (आरटीपी) और सुझाए गए उत्तरों का डिजाइन, गुणवत्ता और अंतर्वस्तु को छात्रों के फायदे के लिए पूर्णरूप से पुनःडिजाइन किया गया है और सुधारा गया है।

छात्रों को परीक्षाएं देने के लिए बेहतर तैयारी करने में सक्षम बनाने और उनके मार्गदर्शन के लिए अध्ययन बोर्ड ने आईसीएआई की वेबसाइट पर पुनरीक्षण परीक्षा पत्रों को रखा था जिसमें उन्हें निःशुल्क डाउनलोड करने का विकल्प उपलब्ध था।

पुनरीक्षण परीक्षा पत्रों को निम्नलिखित परीक्षा के संबंध में प्रकाशित किया गया है :

- वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-2) (समूह - 1 और 2)
- वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (समूह - 1 और 2)
- फाइनल (समूह - 1 और 2)
- फाइनल (नया) (समूह - 1 और 2)

10.6 अध्ययन सामग्री का पुनरीक्षण

वार्षिक आधार पर छात्रों की जानकारी को अद्यतन करने की सतत प्रक्रिया के भागरूप में विभिन्न अध्ययन सामग्रियों की अंतर्वस्तु को अद्यतन किया गया है और समुचित परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया गया है।

10.7 चयनित मामलों का संकलन

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में चयनित मामलों के संकलन, 2008, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विधियों से संबंधित चयनित मामले अंतर्विष्ट हैं, प्रकाशित किया गया है।

10.8 कराधान विषयों में अनुपूरक अध्ययन सामग्री

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में अनुपूरक अध्ययन सामग्री एक वार्षिक प्रकाशन है जिसमें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों में वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा किए गए संशोधन अंतर्विष्ट हैं। उसका प्रकाशन किया गया है और छात्रों के बीच वितरण के लिए उसे प्रदेशों और शाखाओं को अग्रेषित किया गया है।

10.9 अध्ययन बोर्ड के प्रकाशन

अध्ययन बोर्ड द्वारा निकाले गए प्रकाशनों में सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी), वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम 2), वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (पीसीसी), एकिकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (आईपीसीसी), लेखाकरण तकनीशियन पाठ्यक्रम (एटीसी) और फाइनल परीक्षाओं के संबंध में अध्ययन सामग्री सम्मिलित थी। बोर्ड ने सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के संबंध में पाठ्यक्रम सामग्री, वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम 2), वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (पीसीसी) और फाइनल परीक्षाओं के लिए सुझाए गए उत्तर और साथ ही वृत्तिक परीक्षा (पाठ्यक्रम 2) और फाइनल परीक्षाओं के संबंध में सुझाए गए उत्तरों का संकलन, पीसीसी, आईपीसीसी, एटीसी, फाइनल पाठ्यक्रम से संबंधित अध्ययन सामग्री की सीडी और साथ ही स्वनिर्धारण (सीपीटी) को जारी किया था।

10.10 100 घंटे का सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण

वर्तमान में 131 सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र पूर्णतया कार्यरत हैं और अन्य प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस रिपोर्ट की तारीख तक छात्रों के फायदे के लिए इन कंप्यूटर प्रयोगशालाओं में 3,741 कंप्यूटर प्रतिष्ठापित किए गए थे। इन कंप्यूटर प्रयोगशालाओं के पास प्रतिवर्ष 1,25,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने की क्षमता है।

पूर्णतया कार्यरत कंप्यूटर प्रयोगशालाएं	131
ऐसी प्रयोगशालाएं जिनकी स्थापना के लिए कार्यवाही की जा रही है	7
प्रतिष्ठापित कंप्यूटरों की संख्या	3741
आईसीएआई की कंप्यूटर प्रयोगशालाओं में फरवरी, 2008 से मई, 2009 तक प्रशिक्षित किए गए छात्रों की संख्या	68,909
आईसीएआई प्रयोगशालाओं में छात्रों को प्रशिक्षित करने की वार्षिक क्षमता	1,25,000

100 घंटे की सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संबंधी अध्ययन सामग्री को पूर्णतः पुनरीक्षित और अध्ययन किया गया है।

10.11 साधारण प्रबंध और संसूचना कौशल पाठ्यक्रम - 54 केन्द्र, 2008-09 के दौरान 265 बैच और 10870 छात्रों को प्रशिक्षण

1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 की अवधि के दौरान, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा देश भर में (दुबई केन्द्र सहित) 54 केन्द्रों पर साधारण प्रबंध और संचार कौशल पर 15 दिवसीय पाठ्यक्रमों के 265 बैचों का आयोजन किया गया था और इन कार्यक्रमों में 10870 छात्रों ने भाग लिया था (2007-2008 में 7851 छात्रों ने भाग लिया था)।

1.4.2009 से 31.5.2009 की अवधि के दौरान, 10 बैचों के लिए साधारण प्रबंध और संचार कौशल पर 15 दिवसीय पाठ्यक्रम प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा 5 केन्द्रों पर आयोजित किया गया था और इस अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों में 426 छात्रों ने भाग लिया था।

10.12 एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (आईपीसीसी) और लेखाकरण तकनीशियन पाठ्यक्रम (एटीसी) के लिए अनुकूलन कार्यक्रम

ऐसे छात्रों को, जिन्होंने एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (आईपीसीसी) और लेखाकरण तकनीशियन पाठ्यक्रम (एटीसी) के लिए रजिस्ट्रीकरण किया है, अनिवार्य रूप से 35 घंटे का 7 दिवसीय अनिवार्य अनुकूलन कार्यक्रम में भाग लेना होता है। इस अनुकूलन कार्यक्रम का उद्देश्य नए अर्हित सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) के छात्रों को संसूचना कौशल, प्रस्तुती कौशल, कार्यलय प्रक्रियाएं और साधारण वाणिज्यिक ज्ञान जैसे क्षेत्रों की सामान्य जानकारी प्रदान करना है। अनुकूलन कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम अंतर्वस्तु को समाविष्ट करने वाली व्यापक अध्ययन सामग्री तैयार की गई है और ऐसे पाठ्यक्रम के संचालन के लिए प्रदेशों और शाखाओं को वितरित की गई है।

10.13 वर्ष 2008-09 के दौरान छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि - कुल छात्रवृत्तियों की संख्या 220

गुणता छात्रवृत्तियों की संख्या को 12 से बढ़ाकर 60 किया गया है, गुणता एवं आवश्यकता आधृत छात्रवृत्तियों की संख्या को 12 से बढ़ाकर 60 किया गया है और आवश्यकता आधृत छात्रवृत्तियों की संख्या को 20 से बढ़ाकर 100 किया गया है।

10.14 लेखाकरण तकनीशियन पाठ्यक्रम सहित एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम का दिसम्बर, 2008 से प्रारंभ

आईसीएआई ने एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (आईपीसीसी) प्रारंभ किया जिसमें लेखाकरण तकनीशियन पाठ्यक्रम (एटीसी) भी सम्मिलित है। अन्य शब्दों में, छात्र या तो आईपीसीसी के माध्यम से पूर्णरूपेण चार्टर्ड एकाउंटेंटसी पाठ्यक्रम कर सकते हैं या फिर विकल्प के रूप में वे लेखाकरण तकनीशियन पाठ्यक्रम पूरा करके आईसीएआई से मध्यम स्तर की लेखाकरण अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।

10.15 छात्रों का संवादपत्र (स्टूडेंट्स न्यूजलेटर)

एक मासिक सीए छात्र संवादपत्र - 'दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टूडेन्ट' जिसमें छात्रों से सुसंगत विषयों पर उपयोगी लेख, शैक्षणिक अद्यतन, आलेख और अन्य सुसंगत उद्घोषणाएं हैं, छात्रों और साथ ही संस्थान के सदस्यों में लोकप्रिय और उनके लिए उपयोगी बना हुआ है।

10.16 सर्वश्रेष्ठ लेख के लिए पुरस्कार

सर्वोत्तम लेख के लिए 2000 रुपए का प्रथम पुरस्कार श्री राहुल कुमार बजाज को सितम्बर, 2007 के छात्र संवाद पत्र के अंक में प्रकाशित उनके लेख "कंसर्न फार - गोईंग कंसर्न" के लिए दिया गया था तथा द्वितीय पुरस्कार श्री गुरुराज एस. को जुलाई, 2007 के छात्र संवाद पत्र - दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टूडेंट के अंक में प्रकाशित उनके लेख "टुवर्ड्स ग्रीनर टुमोरो - अंडरस्टैंडिंग कार्बन क्रेडिट" के लिए दिया गया था।

10.17 छात्र आदान-प्रदान स्कीम - 4 देशों से 25 छात्र

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आईसीएएन) के 6 छात्रों, श्रीलंका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आईसीएएसएल) के 9 छात्रों, पाकिस्तान के एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छात्र और बंगलादेश के 9 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छात्रों ने भारत का दौरा किया और 10-11 जुलाई, 2008 को नागपुर में एमएएफए छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लिया।

10.18 सीए पाठ्यक्रम को पीएच.डी कार्यक्रम के लिए मान्यता

विभिन्न विश्वविद्यालयों से निरंतर संपर्क करने के बाद शिक्षा बोर्ड पीएचडी/फेलो कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए 4 भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अलावा 80 विश्वविद्यालयों से सीए पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त करने में सफल रहा है।

10.19 एकदिवसीय संगोष्ठियां

वर्ष के दौरान, 20 शाखाओं द्वारा 33 एकदिवसीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था।

10.20 वक्तृता प्रतियोगिता - 60 कार्यक्रम

5 प्रादेशिक परिषदों, जिन्होंने शाखा स्तरीय वक्तृता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था, सहित 54 शाखाओं द्वारा शाखा स्तरीय वक्तृता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इन 5 प्रादेशिक स्तरीय प्रतियोगिताओं के अलावा एक अखिल भारतीय वक्तृता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

अंतिम वक्तृता प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में 5 जनवरी, 2009 को किया गया था।

10.21 वि्वज प्रतियोगिताएं - 60 कार्यक्रम

5 प्रादेशिक परिषदों, जिन्होंने शाखा स्तरीय वि्वज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था, सहित 54 शाखाओं द्वारा शाखा स्तरीय वि्वज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इन 5 प्रादेशिक स्तरीय प्रतियोगिताओं के अलावा एक अखिल भारतीय वि्वज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

अंतिम वि्वज प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में 5 जनवरी, 2009 को किया गया था।

10.22 प्रादेशिक/राज्य स्तरीय व्याख्यान बैठकें - 21 बैठकें

1 अप्रैल, 2008 से 31 मई, 2009 की अवधि के दौरान 15 शाखाओं में 21 व्याख्यान बैठकों/अर्धदिवसीय संगोष्ठियों को आयोजन किया गया था और एक शाखा में एक क्रेश पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था।

10.23 अखिल भारतीय सीए छात्र सम्मेलन - अखिल भारतीय सम्मेलन

21वें अखिल भारतीय सीए छात्र सम्मेलन का आयोजन 10 और 11 जुलाई, 2008 को नागपुर में किया गया था।

10.24 सीए छात्रों के राष्ट्रीय अभिसमय - 5 राष्ट्रीय अभिसमय

वर्ष के दौरान 5 राष्ट्रीय अभिसमयों का आयोजन किया गया था। पांचवें राष्ट्रीय अभिसमय का आयोजन 9 और 10 जून, 2008 को जयपुर में किया गया था। छठे राष्ट्रीय अभिसमय का आयोजन 23 और 24 अगस्त, 2008 को कोलकाता में किया गया था। सातवें राष्ट्रीय अभिसमय का आयोजन 1 और 2 दिसम्बर, 2008 को नई दिल्ली में किया गया था। आठवें राष्ट्रीय अभिसमय का आयोजन 5 और 6 दिसम्बर, 2008 को एर्नाकुलम में किया गया था और नवें राष्ट्रीय अभिसमय का आयोजन 1 और 2 जनवरी, 2009 को राजकोट में किया गया था।

10.25 प्रादेशिक/उप प्रादेशिक/राज्य स्तरीय सम्मेलन - 7 सम्मेलन

दो दिवसीय प्रादेशिक/उप प्रादेशिक/राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन 6 और 7 जून, 2008 को बड़ौदा में, 11 और 12 जुलाई, 2008 को वसई में, 13 और 14 दिसम्बर, 2008 को सुरत में, 17 और 18 दिसम्बर, 2008 को चैन्नई में, 3 और 4 जनवरी, 2009 को बंगलोर में, 9 और 10 जनवरी, 2009 को भुवनेश्वर में तथा 10 और 11 जनवरी, 2009 को कोयम्बटूर में किया गया था।

10.26 विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त संगोष्ठियां - 3 संयुक्त संगोष्ठी

वर्ष के दौरान, अनेक विश्वविद्यालयों के समन्वयन से 3 संयुक्त संगोष्ठियां आयोजित की गई थी।

10.27 करियर काउंसेलिंग कार्यक्रम - 80 कार्यक्रम

पाठ्यविवरणों के बहुत से विषयों में अनेक विद्या संबंधी शंकाओं को स्पष्ट करने के लिए छात्रों की सहायता हेतु और सीए पाठ्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रादेशिक मुख्यालयों और शाखाओं में करियर काउंसेलिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 की अवधि के दौरान देश भर में विभिन्न अवस्थानों पर 80 करियर काउंसेलिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। 1 अप्रैल, 2009 से 31 मई, 2009 की अवधि के दौरान छात्र समुदाय के साथ परस्पर संवाद के लिए भारत में विभिन्न शाखाओं में 16 करियर काउंसेलिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

10.28 वृत्तिक कौशल विकास संबंधी त्रैमासिक (12 सप्ताह) आवासी कार्यक्रम - 7 बैच

आईसीएआई ने सीए के छात्रों और नए अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंटों के फायदे के लिए वृत्तिक कौशल विकास (साधारण प्रबंध, व्यक्तित्व का विकास और संसूचना कौशल) संबंधी त्रैमासिक (12 सप्ताह) आवासी कार्यक्रम आरंभ किया गया है। यह कार्यक्रम सीए के छात्रों और नए अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंटों की, कारबार संगठनों और वृत्ति में प्रभावी कार्यक्रम के लिए अपेक्षित वृत्तिक कौशल प्राप्त करने में सहायता कर रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजित विभिन्न बैच निम्नानुसार हैं :

- पहला बैच राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद (एनआईएफएम) में 28 अप्रैल, 2008 से 18 जुलाई, 2008 - इस कार्यक्रम में 55 छात्रों ने भाग लिया था।
- दूसरा बैच राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद (एनआईएफएम) में 11 अगस्त, 2008 से 31 अक्टूबर, 2008 - इस कार्यक्रम में 52 छात्रों ने भाग लिया था।
- तीसरा और चौथा बैच एल.एन. मितल सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर में 2 दिसम्बर, 2008 से 1 मार्च, 2009 - इस कार्यक्रम में 100 छात्रों ने भाग लिया था।

- पांचवाँ बैठक राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद (एनआईएफएम) में 4 फरवरी, 2009 से 28 अप्रैल, 2009 - इस कार्यक्रम में 50 छात्रों ने भाग लिया था।
- छठा बैठक भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर - 13 अप्रैल, 2009 से प्रारंभ हुआ और 14 जुलाई, 2009 को समाप्त हुआ- इस कार्यक्रम में 60 छात्रों ने भाग लिया था।
- सातवाँ बैठक राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद (एनआईएफएम) - 6 जुलाई, 2009 से प्रारंभ हुआ - इस कार्यक्रम में 53 छात्रों ने भाग लिया था।

10.29 सीपीटी, पीसीसी और फाइनल के छात्रों के लिए ज्ञान दर्शन कार्यक्रम - कुल 190 व्याख्यान

सामान्य प्रवीणता परीक्षा, वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले और फाइनल के छात्रों के फायदे के लिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सहयोग से ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से वर्ष के दौरान विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान परिदत्त किए गए थे। आयोजित किए गए ऐसे व्याख्यानों की संख्या नीचे दी गई है :

- सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) व्याख्यान : 110
- वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (पीसीसी) व्याख्यान : 40
- फाइनल व्याख्यान : 40

देश के विभिन्न भागों के छात्रों ने आईएसआरओ द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रणाली के माध्यम से संकाय के साथ परस्पर संवाद किया था। इन व्याख्यानों का आयोजन वर्ष के दौरान और 1 मई, 2009 तक किया गया था।

10.30 भरथिआर विश्वविद्यालय के साथ परस्पर समझ ज्ञापन

भरथिआर विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर और आईसीएआई के बीच एक परस्पर समझ के ज्ञापन पर 4 दिसम्बर, 2008 को कोयम्बटूर में हस्ताक्षर किए गए हैं।

एमओयू के अनुसार, सीए छात्र और साथ ही अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों को भरथिआर विश्वविद्यालय से बीकाम, एमकाम, बीबीए और एमबीए उपाधियां प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे।

उन्हें सीए पाठ्यचर्या के अंतर्गत आने वाले प्रश्न पत्रों के संबंध में छूट प्रदान की जाएगी और उन्हें ये उपाधियां प्राप्त करने के लिए केवल कुछ प्रश्न पत्रों की परीक्षा देनी होगी और उन्हें उत्तीर्ण करना होगा।

चार्टर्ड एकाउंटेंटों को पीएचडी उपाधि अर्जित करने में समर्थ बनाने के लिए भी एमओयू में उपबंध किया गया है।

10.31 भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान और गुरु जाम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार के बीच परस्पर समझ ज्ञापन

आईसीएआई ने गुरु जाम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार के साथ परस्पर समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके द्वारा सीए छात्र और साथ ही अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंट, एमओयू की शर्तों के अधीन रहते हुए बीबीए, एमबीए और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त करने में समर्थ होंगे।

10.32 छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निःशुल्क फोन नम्बर

अध्ययन बोर्ड, नोएडा में एक निःशुल्क टेलीफोन नम्बर 1800-200-2501 प्रतिष्ठापित किया गया है। इस नम्बर पर समर्पित अधिकारी छात्रों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। शिक्षा संबंधी प्रश्नों का उत्तर संकाय सदस्यों द्वारा दिया जा रहा है।

10.33 छात्र परामर्शी

दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चैन्नई और जयपुर स्थित संस्थान के कार्यालयों में छात्र परामर्शियों को नियुक्त किया गया है। वे चार्टर्ड एकाउंटेंटों के पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सीए छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

10.34 एमएंडएस अनुभाग के सहयोग से दीक्षांत समारोह

क्रम सं.	तारीख	दीक्षांत समारोह का स्थान
1.	9 नवम्बर, 2008	मुंबई
2.	16 नवम्बर, 2008	दिल्ली
3.	30 नवम्बर, 2008	चैन्नई
4.	7 दिसम्बर, 2008	कोलकाता
5.	28 दिसम्बर, 2008	जयपुर
6.	31 मई, 2009	मुंबई
7.	7 जून, 2009	नई दिल्ली

8.	21 जून, 2009	चेन्नई
9.	28 जून, 2009	कोलकाता

प्रस्तावित दीक्षांत समारोह :

1	2 जुलाई, 2009	हैदराबाद
2	11 जुलाई, 2009	जयपुर
3	2 अगस्त, 2009	बंगलोर

10.35 संकाय विकास कार्यक्रम - अलेप्पी, केरल

अलेप्पी, केरल में एक संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चार्टर्ड एकाउंटेंसी के छात्रों को वृत्तिक शिक्षा प्रदान करने वाले संकाय के सदस्यों की अध्यापन पद्धति में सुधार करना था। प्रस्तुतिकरण और संसूचना कौशलों तथा अध्यापन पद्धतियों में सुविख्यात विशेषज्ञों ने इस कार्यक्रम में संसाधन व्यक्तियों की भूमिका निभाई थी, इस समारोह में देश भर के 50 से अधिक संकाय सदस्यों ने भाग लिया था।

10.36 आईटी छात्रों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण

सूचना प्रौद्योगिकी के संकाय सदस्यों को, जो सीए के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, सुसज्जित करने के लिए अध्ययन बोर्ड ने एक प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के सुविख्यात विशेषज्ञों ने आईटी संकाय को प्रशिक्षण प्रदान किया था।

10.37 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता

संस्थान के हीरक जयंती वर्ष समारोह को मनाने के लिए शाखा (25 शाखाएं) और प्रादेशिक स्तरों (5 प्रदेश) पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रादेशिक स्तर पर 100 से अधिक छात्रों का चयन किया गया था। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 2009 के अंतिम भाग में किया जाएगा।

10.38 युवा समारोह

संस्थान की हीरक जयंती वर्ष समारोह प्रतियोगिताओं के भाग रूप में विभिन्न युवा समारोहों का आयोजन किया गया था जिनमें 25 शाखाओं द्वारा कराए गए विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन जैसे कि सुगम संगीत, गायन, युगल गीत - गायन, वाद्य संगीत, मोनो एक्टिंग, अंताक्षरी और हास्य कार्यक्रम का आयोजन सम्मिलित था।

10.39 राष्ट्रीय विद्यालय स्तर वाद-विवाद प्रतियोगिता

हीरक जयंती समारोह के भाग रूप में राष्ट्रीय विद्यालय स्तर वाद-विवाद प्रतियोगिता प्रारंभ की गई थी। ये प्रतियोगिताएं शाखा और प्रदेश स्तर पर आयोजित की गई थीं। 65 शाखाओं ने देश के विभिन्न भागों में अवस्थित विद्यालयों के सहयोग से इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था जिनमें 12,330 छात्रों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 2009 के अंत में कराया जाना प्रस्तावित है।

10.40 अध्यापक दिवस समारोह

5 सितम्बर, 2008 को अध्ययन बोर्ड, नोएडा में अध्यापक दिवस समारोह का विशाल उत्सव किया गया था। संकाय सदस्यों को आईसीएआई के अध्यक्ष द्वारा उपहार और एक विशेष प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था।

10.41 100 घंटे का आईटी प्रशिक्षण और जीएमसीएस का पर्यावलोकन

क. 100 घंटे का आईटी प्रशिक्षण

पूर्णतया कार्यरत कंप्यूटर प्रयोगशालाएं	131
ऐसी प्रयोगशालाएं जिनकी स्थापना के लिए कार्यवाही की जा रही है	7
प्रतिष्ठापित कंप्यूटरों की संख्या	3741
आईसीएआई की कंप्यूटर प्रयोगशालाओं में फरवरी, 2008 से मई, 2009 तक प्रशिक्षित किए गए छात्रों की संख्या	68,909
आईसीएआई प्रयोगशालाओं में छात्रों को प्रशिक्षित करने की वार्षिक क्षमता	1,25,000

ख. जीएससीएस शाखाएं

केंद्रों की संख्या	बैचों की संख्या	प्रशिक्षित छात्रों की संख्या
54	265	10,870

11. प्रादेशिक परिषदें और उनकी शाखाएं**11.1 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र संघों की शाखाएं**

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स पाठ्यक्रम के छात्रों को बंधुत्व की भावना के विकास और सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और बौद्धिक विकास आदि के संवर्धन में सक्रिय रूप से सम्मिलित करने के विचार से संस्थान की परिषद् सदैव छात्रों को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र संघों की शाखाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती रही है, अभी तक छात्र संघों की 42 शाखाओं की स्थापना की जा चुकी है।

11.2 प्रादेशिक परिषद् और उनकी शाखाएं

संस्थान की पांच प्रादेशिक परिषदें हैं अर्थात् पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद्, दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद्, पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् और उत्तर भारत प्रादेशिक परिषद् जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में हैं।

11.3 प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं की कुल संख्या 119 है।

11.4 इस समय, भारत के बाहर संस्थान के चेप्टरों की कुल संख्या 21 है।

11.5 इस समय, पूरे भारत में संदर्भ पुस्तकालयों की कुल संख्या 30 है।

11.6 शाखाओं के लिए भवन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्रादेशिक परिषदों की अनेक शाखाएं अपने निजी परिसर बनाने में रुचि दिखाती रही हैं। कुल मिलाकर 64 शाखाओं के अपने भवन हैं।

11.7 चल शील्ड

संस्थान सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद् को हर वर्ष चल शील्ड प्रदान करता है। पुरस्कार सम्पूर्ण कार्यों को देखकर दिया जाता है। इसी प्रकार हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ शाखा को एक पृथक चल शील्ड प्रदान की जाती है। पुरस्कार स्थापित शिक्षाओं के आधार पर दिया जाता है। अखिल भारतीय आधार पर सर्वश्रेष्ठ सीए छात्र संघ को और प्रादेशिक आधार पर छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा को चल शील्ड प्रदान करने की योजना वर्ष 1999 से चलाई गई है। 2008 के लिए ये शील्डें 4 फरवरी, 2009 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को दी गई थी :-

- सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद्
वर्ष 2008 के लिए उत्कृष्ट और प्रसंजनीय कार्य के लिए शील्ड
वर्ष 2008 के लिए प्रशंसा प्रमाणपत्र
प्रादेशिक परिषद् की सर्वश्रेष्ठ शाखा
- लघु आकार शाखा प्रवर्ग
 - मध्यम आकार शाखा प्रवर्ग
 - बड़ी शाखा प्रवर्ग

छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा :

पश्चिमी क्षेत्र
दक्षिण क्षेत्र

पूर्वी क्षेत्र
मध्य क्षेत्र

उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद्।

पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् और दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् (संयुक्त रूप से)।

पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद् और मध्य भारत प्रादेशिक परिषद्।

पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् की पिंपरी चिंचवड शाखा

उडुपट्टीआईआरसी की वसई शाखा

एसआईआईआरसी की एर्नाकुलम शाखा और उडुपट्टीआईआरसी की नागपुर शाखा (संयुक्त रूप से)

उडुपट्टीआईसीएएस की नागपुर और मुक्त शाखा (संयुक्त रूप से)
एसआईसीएएस की एर्नाकुलम और त्रिवेंद्रम शाखा (संयुक्त रूप से)

ईआईसीएएस की गुवाहाटी शाखा

सीआईसीएएस की इंदौर शाखा और जबपुर शाखा (संयुक्त रूप से)

उत्तम कार्य प्रदर्शन को देखते हुए निम्नलिखित शाखाओं को अलग से प्रशंसनीय कार्य के लिए शील्ड प्रदान की गई :-

लघु आकार शाखा प्रवर्ग :

सीआईआरसी की भिलाई शाखा
एसआईआरसी की तूतीकोरिन शाखा
एसआईआरसी की हुबली शाखा
ईआईआरसी की सिलीगुड़ी शाखा

➤ मध्यम आकार शाखा प्रवर्ग :

एसआईआरसी की सलेम शाखा
डब्ल्यूआईआरसी की औरंगाबाद शाखा

➤ बड़ी शाखा प्रवर्ग :

एसआईआरसी की कोयम्बटूर शाखा और सीआईआरसी की
इंदौर शाखा (संयुक्त रूप से)

➤ उत्तम कार्य प्रदर्शन को देखते हुए निम्नलिखित शाखाओं को अलग से प्रशंसनीय कार्य के लिए प्रमाणपत्र प्रदान किए गए थे :-

लघु आकार शाखा - एसआईआरसी की तिरुपुर शाखा और डब्ल्यूआईआरसी की जामनगर शाखा (संयुक्त रूप से)

मध्यम आकार शाखा - ईआईआरसी की गुवाहाटी शाखा और डब्ल्यूआईआरसी की गोवा शाखा (संयुक्त रूप से)

सचिव, डब्ल्यूआईआरसी को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए शील्ड प्रदान की गई थी ।

11.8 नए विकेन्द्रीकृत कार्यालय

तुरंत तथा व्यक्तिपरक सेवा के महत्व को मानते हुए, जो विकेन्द्रीकरण के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं, संस्थान की परिषद् मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में पहले से कार्यरत विकेन्द्रीकृत कार्यालयों के अलावा, दक्षिणी क्षेत्र में बंगलौर और हैदराबाद में, पश्चिमी क्षेत्र में अहमदाबाद और पुणे में और मध्य क्षेत्र में जयपुर में पांच और विकेन्द्रीकृत कार्यालय पहले ही स्थापित कर चुकी है । प्रादेशिक स्तर पर कार्य/गतिविधियों की मात्रा में वृद्धि पर विचार करते हुए, नागपुर, सूरत, वदोदरा और ठाणे (पश्चिमी क्षेत्र), एर्नाकुलम और कोयम्बटूर (दक्षिणी क्षेत्र), इन्दौर (मध्य क्षेत्र) और चंडीगढ़ (उत्तरी क्षेत्र) में आठ और विकेन्द्रीकृत कार्यालय स्थापित किए गए हैं ।

12. वित्त और लेखा

31 मार्च, 2009 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा जो परिषद् द्वारा अनुमोदित है, संलग्न है ।

13. प्रशंसा

13.1 परिषद् व्यवसाय के उन सदस्यों की आभारी है, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 2006 के अधीन गठित संस्थान के बोर्ड/समितियों में सहयोजित सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए थे और उस रूप में कार्य किया था और उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती है, जो व्यवसाय के सदस्य नहीं हैं लेकिन जिन्होंने परिषद् के शैक्षिक, तकनीकी, अन्य विकास क्रियाकलापों में और उसकी परीक्षाओं के संचालन में वर्ष 2008-2009 के दौरान परिषद् की सहायता की ।

13.2 परिषद् की हार्दिक कामना है कि वर्ष 2008-2009 में केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन की प्रशंसा अभिलेख पर अंकित की जाए ।

13.3 परिषद् डा. मनमोहन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री, सीए के. रहमान खान, राज्यसभा के माननीय उपाध्यक्ष, सीए रामेश्वर ठाकुर, कर्नाटक के माननीय राज्यपाल, श्री पी. चिदम्बरम, (तत्कालीन) संघ के माननीय वित्तमंत्री, श्री लालू प्रसाद, (तत्कालीन) संघ के माननीय रेलमंत्री, श्री प्रेम चंद गुप्ता, (तत्कालीन) संघ के माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री, श्रीमती शीला दीक्षित, दिल्ली की मुख्यमंत्री, श्री जयप्रकाश जायसवाल, माननीय गृह राज्यमंत्री, डा. मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, श्री विनोद राय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सुश्री आरती मेहरा, मेयर, दिल्ली नगर निगम, श्री अनुराग गोयल, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, स्वामी रामदेव और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का, जिन्होंने आईसीएआई द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर उन्हें गौरवान्वित किया, दिल से आभार व्यक्त करती है । परिषद् राज्य स्तर पर विभिन्न कृत्यकारियों की भी, जिन्होंने जिन्होंने आईसीएआई के विभिन्न अंगों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर उन्हें गौरवान्वित किया, सराहना करती है ।

13.4 परिषद् आईसीएआई द्वारा की गई अनेक गतिविधियों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई गहन रुचि और की गई पहल के अनुसरण में उनके द्वारा पहले ही उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है।

13.5 संस्थान के सभी अधिकारी और कर्मचारी वर्ष 2008-2009 के दौरान अपने निष्ठापूर्ण और अनथक प्रयासों के लिए परिषद् द्वारा प्रशंसनीय है।

सदस्य

(1 अप्रैल, 1999 से)

सारणी - 1

वर्ष (को यथाविद्यमान)		पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	योग
1 अप्रैल, 1999	सहयुक्त	17935	12515	5562	4875	8001	48888
	अध्येता	12038	9942	4779	5345	9374	41478
	योग	29968	22457	10341	10220	17375	90366
1 अप्रैल, 2000	सहयुक्त	17771	13023	5807	5057	8411	50069
	अध्येता	12200	10369	4941	5617	9784	42911
	योग	29971	23392	10748	10674	18195	92980
1 अप्रैल, 2001	सहयुक्त	19243	12915	5732	5215	8498	51603
	अध्येता	12868	10749	5077	5995	10100	44789
	योग	32111	23664	10809	11210	18598	96392
1 अप्रैल, 2002	सहयुक्त	20771	13456	5872	5493	9074	54666
	अध्येता	13540	11248	5296	6400	10580	47064
	योग	34311	24704	11168	11893	19654	101730
1 अप्रैल, 2003	सहयुक्त	23194	14446	6374	6318	10287	60619
	अध्येता	14279	11742	5572	6909	11135	49637
	योग	37473	26188	11946	13227	21422	110256
1 अप्रैल, 2004	सहयुक्त	24515	14943	6515	6714	10697	63384
	अध्येता	15091	12377	5836	7557	11846	52707
	योग	39606	27320	12351	14271	22543	116091
1 अप्रैल, 2005	सहयुक्त	26351	15724	6785	7552	11640	68052
	अध्येता	15834	12969	6146	8207	12338	55494
	योग	42185	28693	12931	15759	23978	123546
1 अप्रैल, 2006	सहयुक्त	28528	16,700	7172	8480	12898	73778
	अध्येता	16385	13358	6313	8539	12573	57168
	योग	44913	30058	13485	17019	25471	130946
1 अप्रैल, 2007	सहयुक्त	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	अध्येता	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	योग	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1 अप्रैल, 2008	सहयुक्त	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	अध्येता	17646	14034	6738	9472	13398	61288
	योग	50010	33237	14677	19517	28040	145481
1 अप्रैल, 2009	सहयुक्त	34294	20666	8193	10578	15951	89682
	अध्येता	18442	14516	7002	10007	13951	63918
	योग	52736	35182	15195	20585	29902	153600

सदस्य
(1 अप्रैल, 1950 से)
सारणी 2

		सहयुक्त	अध्येता	योग
1 अप्रैल, 1950	को	1,120	569	1,689
1 अप्रैल, 1951	को	1,285	672	1,957
1 अप्रैल, 1961	को	4,059	1,590	5,649
1 अप्रैल, 1971	को	7,901	3,326	11,227
1 अप्रैल, 1981	को	16,796	8,642	25,438
1 अप्रैल, 1991	को	36,862	22,136	58,998
1 अप्रैल, 2001	को	51,603	44,769	96,392
1 अप्रैल, 2002	को	54,666	47,064	1,01,730
1 अप्रैल, 2003	को	60,619	49,637	1,10,256
1 अप्रैल, 2004	को	63,384	52,707	1,16,091
1 अप्रैल, 2005	को	68,052	55,494	1,23,546
1 अप्रैल, 2006	को	73,778	57,168	1,30,946
1 अप्रैल, 2007	को	81,049	58,792	1,39,841
1 अप्रैल, 2008	को	84,193	61,288	1,45,481
1 अप्रैल, 2009	को	89,682	63,918	1,53,600

छात्र रजिस्ट्रीकरण प्रगति चार्ट
(31 मार्च, 1997 से)

	फाउंडेशन/ पीई (पाठ्यक्रम-I)	इंटरमीडिएट/ पीई (पाठ्यक्रम-II)	फाइनल	सीपीटी#	पीसीसी##	आईपीसीसी	एटीसी	योग
वर्ष 1996-97 के दौरान	28,209	21,354	9,275	-	-	-	-	58,838
वर्ष 1997-98 के दौरान	37,052	24,652	9,394	-	-	-	-	71,098
वर्ष 1998-99 के दौरान	43,809	28,253	12,227	-	-	-	-	84,289
वर्ष 1999- 2000 के दौरान	44,180	27,508	10,787	-	-	-	-	82,475
वर्ष 2000-01 के दौरान	38,405	33,405	9,026	-	-	-	-	68,430
वर्ष 2001-02 के दौरान	34,215*	30,403**	11,524	-	-	-	-	75,142
वर्ष 2002-03 के दौरान	35,324	33,283	11,102	-	-	-	-	79,909
वर्ष 2003-04 के दौरान	38,188	34,232	11,390	-	-	-	-	83,810

वर्ष 2004-05 के दौरान	39,000	34,190	11,061	-	-	-	-	84,251
वर्ष 2005-06 के दौरान	38,901	39,467	13,010	-	-	-	-	91,378
वर्ष 2006-07 के दौरान	45,617	32,339	11,838	1,29,110	24,041	-	-	2,42,945
वर्ष 2007-08 के दौरान	-	-	19,558	1,42,612	61,186	-	-	2,23,356
वर्ष 2008-09 के दौरान	-	-	11,562	1,39,140	33,764	18,318***	8***	2,02,792

* इसमें 1.10.2001 से 31.3.2002 तक पीई (पाठ्यक्रम-I) में रजिस्ट्रीकृत छात्र सम्मिलित हैं : 5006

** इसमें 1.10.2001 से 31.3.2002 तक पीई (पाठ्यक्रम-II) में रजिस्ट्रीकृत छात्र सम्मिलित हैं : 11848

*** इसमें 10 दिसम्बर, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक के छात्र सम्मिलित हैं :

13 सितम्बर, 2006 से सीपीटी

13 सितम्बर, 2006 से पीसीसी

बीसवीं परिषद् (2009-10) की संरचना

अध्यक्ष	:	सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल
उपाध्यक्ष	:	सीए अमरजीत चोपड़ा
अवधि	:	5 फरवरी, 2009 से आगे
सचिव	:	श्री टी. कार्तिकेयन

बीसवीं परिषद् (2009-10) के सदस्य

निर्वाचित सदस्य

सीए अभिजीत बंधोपाध्याय
सीए अक्षय कुमार गुप्ता
सीए अमरजीत चोपड़ा
सीए अनुज गोयल
सीए अतुल चुन्नीलाल भेड़ा
सीए भावना दोशी
सीए चरणजोत सिंह नन्दा
सीए जी रामास्वामी
सीए हरिन्दरजीत सिंह
सीए जे. वेंकटेश्वरलू
सीए जयंत गोखले
सीए जयदीप नरेन्द्र शाह
सीए के रघु
सीए के.पी. खण्डेलवाल
सीए महेश पी. शारदा
सीए मनोज फड़नीस
सीए पंकज इन्द्रचंद जैन
सीए प्रीति प्रदीप महात्मे
सीए राजकुमार एस. अदुकिया

कोलकाता
कानपुर
नई दिल्ली
गाजियाबाद
मुम्बई
मुम्बई
नई दिल्ली
कोयम्बटूर
नई दिल्ली
हैदराबाद
मुम्बई
नागपुर
बंगलोर
कोलकाता
जामनगर
इन्दौर
मुम्बई
गोवा
मुम्बई

सीए एस. गोपालाकृष्णन्	हैदराबाद
सीए एस संथानाकृष्णन्	चैन्नई
सीए संजीव महेश्वरी	मुम्बई
सीए शांति लाल डागा	हैदराबाद
सीए सुबोध कुमार अग्रवाल	कोलकाता
सीए सुनील एच. तलाटी	अहमदाबाद
सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल	मुम्बई
सीए वी. मुरली	चैन्नई
सीए वी. सी. जेम्स	कोच्ची
सीए वेद जैन	नई दिल्ली
सीए विजय गर्ग	जयपुर
सीए विजय कुमार गुप्ता	फरीदाबाद
सीए विनोद जैन	नई दिल्ली
नामनिर्दिष्ट सदस्य	
श्री अनिल कुमार अग्रवाल	नई दिल्ली
श्री के.पी. शशिधरन	नई दिल्ली
श्री के.आर. महेश्वरी	जयपुर
सीए कृष्णा कान्त	नई दिल्ली
सीए मनोज के. सरकार	कोलकाता
श्री ओ.पी. वैश	नई दिल्ली
श्री आर शेखर	गुड़गांव
श्रीमती रेणुका कुमार	नई दिल्ली

लेखा परीक्षक

सीए गुरमीत एस. ग्रेवाल
सीए प्रमोद जैन

बीसवीं परिषद् (2008-09) की संरचना

अध्यक्ष	:	सीए वेद जैन
उपाध्यक्ष	:	सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल
अवधि	:	4 फरवरी, 2009 तक
सचिव	:	डॉ. अशोक हल्दिया (12 अगस्त, 2008 तक) श्री टी. कार्तिकेयन (12 अगस्त, 2008 से आगे)

बीसवीं परिषद् (2008-09) के सदस्य**निर्वाचित सदस्य**

सीए अभिजीत बंधोपाध्याय	कोलकाता
सीए अक्षय कुमार गुप्ता	कानपुर
सीए अमरजीत चोपड़ा	नई दिल्ली
सीए अनुज गोयल	गाजियाबाद
सीए अतुल चुन्नीलाल भेड़ा	मुम्बई
सीए भावना दोशी	मुम्बई
सीए चरणजोत सिंह नन्दा	नई दिल्ली

सीए जी रामास्वामी	कोयम्बदूर
सीए हरिन्दरजीत सिंह	नई दिल्ली
सीए जे. वेंकटेश्वरलू	हैदराबाद
सीए जयंत गोखले	मुम्बई
सीए जयदीप नरेन्द्र शाह	नागपुर
सीए के रघु	बंगलोर
सीए के.पी. खण्डेलवाल	कोलकाता
सीए महेश पी. शारदा	जामनगर
सीए मनोज फड़नीस	इन्दौर
सीए पंकज इन्द्रचंद जैन	मुम्बई
सीए प्रीति प्रदीप महात्मे	गोवा
सीए राजकुमार एस. अदुकिया	मुम्बई
सीए एस. गोपालाकृष्णन्	हैदराबाद
सीए एस संधानाकृष्णन्	चेन्नई
सीए संजीव महेश्वरी	मुम्बई
सीए शांति लाल डागा	हैदराबाद
सीए सुबोध कुमार अग्रवाल	कोलकाता
सीए सुनील एच. तलाटी	अहमदाबाद
सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल	मुम्बई
सीए वी. मुरली	चेन्नई
सीए वी. सी. जेम्स	कोच्ची
सीए वेद जैन	नई दिल्ली
सीए विजय गर्ग	जयपुर
सीए विजय कुमार गुप्ता	फरीदाबाद
सीए विनोद जैन	नई दिल्ली

नामनिर्दिष्ट सदस्य

श्री ए.के. अवस्थी	नई दिल्ली
श्री अनिल कुमार अग्रवाल	नई दिल्ली
श्री जितेश खोसला	नई दिल्ली
श्री के.आर. महेश्वरी	जयपुर
श्री मनोज के. सरकार	कोलकाता
श्री ओ.पी. वैश	नई दिल्ली
डा. प्रीतम सिंह	गुड़गांव
श्री आर शेखर	नई दिल्ली

लेखा परीक्षक

सीए गुरमीत एस. ग्रेवाल
सीए प्रमोद जैन

संपरीक्षक की परिषद् को रिपोर्ट

1. हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के 31 मार्च, 2009 को यथा विद्यमान संलग्न तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संलग्न आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण की संपरीक्षा की है। इसमें अन्य संपरीक्षकों द्वारा संपरीक्षित संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केन्द्रों, क्षेत्रीय परिषदों और उनकी शाखाओं के लेखाओं को सम्मिलित किया गया है एवं हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय उनकी रिपोर्टों पर सम्यक्तः विचार किया गया है। ये वित्तीय विवरण, संस्थान के प्रबंध मंडल का दायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी संपरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. हमने भारत में साधारणतया स्वीकृत संपरीक्षा मानकों के अनुसार संपरीक्षा की है। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि हम इस बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए संपरीक्षा की योजना बनाएं और उसके अनुसार संपरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण किसी तात्त्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं। किसी संपरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में रकमों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की परीक्षण आधारित जांच करना सम्मिलित है। संपरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का निर्धारण और प्रबंध मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन तथा संपूर्ण वित्तीय विवरण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमारा यह विश्वास है कि हमारी संपरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।
3. हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि :-
 - (क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;
 - (ख) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और नकद प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुसार हैं ;
 - (ग) हमारी राय में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की अपेक्षाओं के अनुपालन में समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं ;
 - (घ) हमारी राय में तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण सुसंगत लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं ;
 - (ङ) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखाकरण सिद्धांतों के साथ पठित संलग्न अनुसूचियां और साथ ही लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पण भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुपालन में, निम्नलिखित के संबंध में एक सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं :
 - (i) तुलन पत्र की दशा में, 31 मार्च, 2009 को संस्थान के मामलों की स्थिति ;
 - (ii) आय और व्यय लेखा की दशा में, उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अधिशेष ; और
 - (iii) नकद प्रवाह विवरण की दशा में उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण।

ह/-
सीए प्रमोद जैन
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-90358

ह/-
सीए गुरमीत एस. ग्रेवाल
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-82918

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 27/9/2009

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31 मार्च, 2009 को यथाविद्यमान तुलन पत्र

	अनुसूची	31.3.2009 को रकम	लाख रु. में 31.3.2008 को रकम
निधियों के स्रोत :			
आरक्षितियां और अधिशेष	I	24896.60	17650.62
उद्दिष्ट निधियां	II	9152.98	6968.39
योग		34049.58	24619.01
निधियों का उपयोग :			
नियत आस्तियां :			
सकल ब्लॉक	III	15747.23	12325.29
घटाएं : अवक्षयण और परिशोधन		5275.28	4247.17
शुद्ध ब्लॉक		10471.95	8078.12
चालू पूंजी संकर्म (पूँजी अग्रिमों सहित)		4324.02	1888.06
निवेश :			
उद्दिष्ट निधि निवेश	IV	9152.98	6968.39
कर्मचारी फायदाप्रद निवेश		2206.13	1631.58
अन्य निवेश		10290.74	9322.86
योग		21649.85	17922.83
चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम :			
वस्तु-सूचियां	V	679.84	718.52
नकद और बैंक अतिशेष	VI	4072.47	1387.13
ऋण और अग्रिम	VII	2507.16	1647.58
निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज		2719.41	2113.91
योग		9978.88	5867.14
घटाएं : चालू दायित्व और प्रावधान			
चालू दायित्व	VIII	10102.19	7422.03
कर्मचारियों के फायदों के लिए प्रावधान		2272.93	1715.11
योग		12375.12	9137.14
शुद्ध चालू आस्तियां (दायित्व)		(2396.24)	(3270.00)
योग		34049.58	24619.01
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण			
लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पण	XII		
ऊपर निर्दिष्ट अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं।	XIII		

ह/-
सीए रवि प्रकाश मित्तल
सहायक सचिव

ह/-
टी. कार्तिकेयन
सचिव

ह/-
सीए अमरजीत चोपड़ा
उपाध्यक्ष

ह/-
सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल
अध्यक्ष

हमारी संलग्न सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
सीए प्रमोद जैन
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-90358

ह/-
सीए गुरमीत एस. ग्रेवाल
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-82918

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 29/9/2009

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31.3.2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय और व्यय लेखा

	अनुसूची	रकम 31.3.2009 को समाप्त वर्ष	रकम 31.3.2008 को समाप्त वर्ष
आय :			
फीस	IX	20770.19	13943.23
संगोष्ठियां		2454.68	1634.12
अन्य आय	X	2485.32	2880.37
पूर्व अवधि की आय		25.16	9.88
योग		25735.35	18467.60
व्यय :			
वेतन और भत्ते		3490.27	2201.45
मुद्रण और लेखन सामग्री		3041.53	2777.57
संगोष्ठी संबंधी व्यय		2528.17	1684.78
अन्य प्रचालन व्यय	XI	7502.56	5728.55
अवकाश और परिशोधन		1057.91	706.81
पूर्व अवधि के व्यय		59.87	24.00
योग		17680.31	13123.16
शुद्ध आधिक्य		8055.04	5344.44
निधियों/आरक्षितियों को विनियोग :			
शिक्षा निधि [पॉलिसी सं.3 (ग)]	XII	2711.67	1738.50
कर्मचारी कल्याण निधि [पॉलिसी सं.3(घ)]	XII	21.69	10.83
साधारण आरक्षित		5321.68	3595.11
योग		8055.04	5344.44
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण	XII		
लेखाओं का माग बनने वाले टिप्पण	XIII		
ऊपर निर्दिष्ट अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं।			

ह/-
सीए रवि प्रकाश मित्तल
सहायक सचिव

ह/-
टी. कार्तिकेयन
सचिव

ह/-
सीए अमरजीत चोपड़ा
उपाध्यक्ष

ह/-
सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल
अध्यक्ष

हमारी संलग्न सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
सीए प्रमोद जैन
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-90358

ह/-
सीए गुरमीत एस. ग्रेवाल
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-82918

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 29/9/2009

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण				
	(रकम लाख रुपए में)			
	2008-2009		2007-2008	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह				
शुद्ध अधिशेष		8055.04		5344.44
निम्न के लिए समायोजन :				
अवक्षयण और परिशोधन	1057.91		706.81	
निवेशों पर ब्याज	(1216.82)		(1085.69)	
		(158.91)		(378.88)
कार्य पूंजी के परिवर्तन के पूर्व प्रचालन अधिशेष		7896.13		4965.56
वस्तु सूची में (वृद्धि)/कमी	38.68		(333.04)	
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज में (वृद्धि)/कमी	(605.50)		(864.56)	
ऋण और अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(859.58)		(237.51)	
चालू दायित्वों में वृद्धि/(कमी)	2680.17		2248.94	
उपदान निधि के उपबंध में वृद्धि/(कमी)	557.82		(116.06)	
		1811.59		697.77
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद		9707.72		5663.33
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
चालू पूंजी संकर्म सहित नियत आस्तियों का अर्जन (शुद्ध)	(5887.70)		(3136.06)	
निवेशों का अर्जन	(3727.02)		(4291.75)	
निवेशों पर ब्याज	1216.82		1085.69	
उद्दिष्ट निधियों के निवेशों से आय (संदायों का शुद्ध)	547.89		466.11	
संक्रमणकालीन प्रावधान	0.00		(295.13)	
पूंजी प्राप्ति	827.63		381.57	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद		(7022.38)		(5789.57)
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी		2685.34		(126.24)
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य		1387.13		1513.37
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य - अनुसूची सं. VI का संदर्भ लें		4072.47		1387.13

टिप्पण :

- उपरोक्त नकद प्रवाह विवरण को आईसीएआई द्वारा जारी एएस-3 में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है।
- संलग्न अनुसूची I से XIII नकद प्रवाह विवरण का अभिन्न भाग है।

ह/-
सीए रवि प्रकाश मित्तल
सहायक सचिव

ह/-
टी. कार्तिकेयन
सचिव

ह/-
सीए अमरजीत चोपड़ा
उपाध्यक्ष

ह/-
सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल
अध्यक्ष

हमारी संलग्न सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
सीए प्रमोद जैन
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-90358

ह/-
सीए गुरमीत एस. ग्रेवाल
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-82918

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 29/7/2009

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची I
आरक्षितियां और अधिशेष

	शिक्षा		अवसंरचना		साधारण		अन्य *		लाख रुपए में योग	
	निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम	
	31.03.2009	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2008
प्रारंभिक अधिशेष	6,353.52	5529.35	1,663.84	1465.90	9,435.47	6275.81	197.79	156.43	17,650.62	13427.49
आय और व्यय लेखा से विनियोग	-	-	-	-	5,321.68	3595.11	-	-	5,321.68	3595.11
संक्रमणकालीन प्राक्धान	-	-	-	-	-	(295.13)	-	-	-	(295.13)
साधारण आरक्षितियों, अवसंरचना आरक्षितियों और अन्य आरक्षितियों से/(को) अंतरण	-	-	83.91	35.49	(147.37)	(71.55)	63.46	36.06	0.00	-
उद्दिष्ट निधियों से/(को) अंतरण	1,710.97	824.17	9.89	30.39	(192.87)	(68.77)	(13.92)	(0.06)	1,514.07	785.73
दाखिला फीस और आबंटित प्रवेश फीस	-	-	103.49	21.18	-	-	-	-	103.49	21.18
भवनों के लिए प्राप्त संदान	-	-	299.98	110.88	-	-	-	-	299.98	110.88
शुद्ध (कमी)/परिवृद्धियां	-	-	-	-	-	-	6.78	5.36	6.76	5.36
योग	8,064.49	6353.52	2,161.11	1663.84	14,416.91	9435.47	254.09	197.79	24,896.60	17650.62

*टिप्पण : अन्य आरक्षितियां ऐसी आरक्षितियां हैं जैसे कि पुस्तकालय आरक्षितियां और शिक्षण कक्षाएं आरक्षितियां, जैसी कि वे क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं की बहियों में विद्यमान हैं।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची II
उद्दिष्ट निधियाँ

लाख रुपए में

	प्रारम्भिक अतिरिक्त		आय और खर्च लेखा से		अवधियों और		वर्ष के दौरान प्राप्त असाधारण/		वर्ष के दौरान आय		वर्ष के दौरान संचय		समायोजन		योग	
	निम्नलिखित तारीख को रुकम	निम्नलिखित तारीख को रुकम	विनियोग	निम्नलिखित तारीख को रुकम	से/(को) अंतरण	अवधियों और	निम्नलिखित तारीख को रुकम	वर्ष के दौरान प्राप्त असाधारण/	निम्नलिखित तारीख को रुकम	वर्ष के दौरान आय	निम्नलिखित तारीख को रुकम	निम्नलिखित तारीख को रुकम	निम्नलिखित तारीख को रुकम	निम्नलिखित तारीख को रुकम	निम्नलिखित तारीख को रुकम	निम्नलिखित तारीख को रुकम
	01.04.2008	01.04.2007	2008-09	2007-08	2008-09	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
अनुसंधान निधियाँ	981.31	738.99	-	-	-	-	-	81.23	177.86	97.90	72.66	-	-	-	1,148.44	981.31
लेखांकन अनुसंधान भवन निधि	358.26	325.77	-	-	-	-	-	-	-	38.51	32.49	-	-	-	394.77	358.26
शिक्षा निधि	4,868.82	3413.78	2,711.87	1738.50	(1,710.97)	(824.17)	-	-	-	475.73	348.51	-	-	-	8,145.05	4868.82
मेडल और पुरस्कार निधि	137.07	126.64	-	-	-	-	-	8.13	5.40	9.64	11.03	(3.74)	(5.75)	(0.25)	151.18	137.07
छात्रों की छात्रवृत्ति निधि	41.91	38.46	-	-	-	-	-	27.95	0.55	4.27	3.84	(8.85)	(0.94)	-	73.28	41.91
कर्मचारी कल्याण निधि	120.45	108.82	21.69	10.83	-	-	-	-	-	12.27	18.65	(1.29)	(7.85)	-	153.12	120.45
अन्य निधियाँ (क्षेत्रीय परिषद और शाखाएँ)	860.77	552.07	-	-	-	-	-	320.11	60.54	40.31	22.04	(122.87)	(12.32)	-	1,095.22	860.77
योग	8,968.39	5294.53	2,733.38	1749.33	(1,514.07)	(785.73)	417.42	244.15	676.83	493.22	(26.86)	(128.75)	(8.25)	9,152.98	6968.39	

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची III
नियत आस्तियां

आस्तियां	सकल ब्लॉक				अवकाश और परिशोधन				लाख रुपए में	
	1.4.2008 लागत	को वर्ष के परिवृद्धियां	समयोजन/ अंतरण/ विक्रय	31.3.2009 को लागत	1.4.2008 तक	वर्ष के लिए	समयोजन/ अंतरण/ विक्रय	31.3.2009 तक	31.3.2009 को उत्पन्न की. बी.	31.3.2008 को उत्पन्न की. बी.
क. मूल आस्तियां										
1. भूमि - पूर्ण स्वामित्व	689.94			1,318.38	-	-	-	-	1,318.38	689.94
2. भूमि - पट्टाभूत स्वामित्व	3181.81			3,252.31	138.80	40.23	-	179.83	3,873.28	3043.01
3. मदन	2830.07			3,883.82	688.44	102.91	-	791.35	3,691.87	2141.63
4. विद्युतीय संस्थापन और फिटिंग	366.83			518.48	150.76	28.86	(0.27)	179.35	337.11	216.07
5. कंप्यूटर	2060.73			2,760.95	1469.34	548.32	(16.15)	2,801.51	758.54	581.39
8. वाहनकुलन	472.66			543.05	210.47	45.29	(0.07)	255.69	287.36	262.19
7. फर्नीचर और फिक्सचर्स	1106.22			1,404.94	385.87	87.89	(8.69)	485.07	939.87	720.35
8. लिफ्टे	108.40			113.42	49.50	6.17	-	55.67	57.75	58.90
9. कार्यालय उपकरण	554.32			848.89	277.21	55.97	(4.62)	328.56	520.33	277.11
10. बाइन	45.80			66.89	28.02	4.28	-	32.38	34.59	17.78
11. पुस्तकालय पुस्तकें	441.57			501.54	441.57	59.97	-	501.54	-	-
ख. अमूल आस्तियां										
सोफ्टवेयर	466.94			538.28	407.19	78.02	-	485.21	53.87	59.75
योग	12325.29			15,747.23	4247.17	1,057.91	(29.80)	5,275.28	10,471.95	8078.12
पूर्व वर्ष के आकड़े	10676.96			12,325.29	3554.08	706.81	(13.72)	4,247.17	8,078.12	

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान**अनुसूची IV**
निवेश

लाख रुपए में

		रकम	रकम
		31-03-2009 को	31-03-2008 को
क. दीर्घकालीन निवेश (लागत पर)			
बंधपत्र			
(i) भारत सरकार - 8% (कराधेय) बॉण्ड - 2003		4750.00	4750.00
अन्य			
(ii) अनुसूचित बैंकों में सावधि निक्षेप		3800.00	4991.37
ख. चालू निवेश			
अन्य			
अनुसूचित बैंकों में सावधि निक्षेप		13099.85	8181.46
	कुल निवेश	21649.85	17922.83
निम्नलिखित को आबंटित :			
उद्दिष्ट निधि निवेश		9152.98	6968.39
कर्मचारी कल्याण निवेश		2206.13	1631.58
अन्य निवेश		10290.74	9322.86
	योग	21649.85	17922.83

अनुसूची V
वस्तु सूचियां

लाख रुपए में

		रकम	रकम
		31.03.2009 को	31.03.2008 को
प्रकाशन और अध्ययन सामग्री		647.03	689.14
अध्ययन सामग्री और प्रकाशन के लिए कागज		0.96	2.34
उपभोज्य भंडार		31.85	27.04
	योग	679.84	718.52

अनुसूची VI
नकद और बैंक अतिशेष

लाख रुपए में

		रकम	रकम
		31.03.2009 को	31.03.2008 को
हाथ में नकदी		25.38	9.64
बैंक में नकदी		4047.09	1377.49
	योग	4072.47	1387.13

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची VII
ऋण और अग्रिम (जिन्हें सुरक्षित माना गया है)

लाख रुपए में

	रकम	रकम
	31.03.2009 को	31.03.2008 को
ऋण और अग्रिम - कर्मचारिवृद्ध	612.76	251.51
कर्मचारिवृद्ध ऋण से वसूलनीय ब्याज	111.25	105.47
प्रतिभूति जमा	340.65	64.16
आईसीएआई लेखांकन अनुसंधान प्रतिष्ठान	210.50	565.20
प्राप्य लेखे	394.77	231.26
अन्य - अग्रिम और पूर्व भुगतान	837.23	429.98
योग	2507.16	1647.58

अनुसूची VIII
चालू दायित्व

लाख रुपए में

	रकम	रकम
	31.03.2009 को	31.03.2008 को
अग्रिम में प्राप्त फीस		
परीक्षा फीस	701.81	870.54
पत्रिका अभिदाय	59.39	73.80
सदस्यता फीस	513.78	422.93
दूरस्थ-शिक्षा फीस	5013.33	3887.95
सूचना प्रणाली संपरीक्षा पाठ्यक्रम फीस	110.15	98.92
बीमा और जोखिम प्रबंध पाठ्यक्रम	17.50	4.80
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियां और डब्ल्यू टी ओ पाठ्यक्रम	730.02	4.56
संगोष्ठी फीस और अन्य संग्रहण (सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण सहित)	7136.98	656.12
खर्चों के लिए क्रेडिटर्स	2,180.97	929.11
अन्य दायित्व	784.24	473.30
योग	10102.19	7422.03

अनुसूची IX

लाख रुपए में

फीस	रकम	रकम
	31/3/2009 को समाप्त वर्ष	31/3/2008 को समाप्त वर्ष
शिक्षा	13747.17	8030.82
परीक्षा	2942.93	3317.35
सदस्यता	3001.48	1480.78
छात्र पंजीकरण	270.88	427.76
प्रवेश	28.52	7.65
छात्र संघ	250.89	372.10
अर्हतापत्र पाठ्यक्रम (पीक्यूसी)	176.11	194.60
प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	352.21	112.17
योग	20770.19	13943.23

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थानअनुसूची X
अन्य आय

	रकम	रकम
	31/3/2009 को समाप्त वर्ष	31/3/2008 को समाप्त वर्ष
प्रकाशन	533.14	554.15
निवेशों पर ब्याज	1,216.82	1,085.69
छात्र-न्यूजलेटर	10.51	11.94
पत्रिका से आय-अभिदाय	151.30	159.53
न्यूजलेटर्स	68.32	66.53
कैम्पस साक्षात्कार	307.54	529.11
विशेषज्ञ सलाहकार फीस	12.65	9.59
कर्मचारिवृद्ध ऋण पर ब्याज	15.84	16.43
अनापेक्षित प्रावधान प्रतिलिखित	2.23	18.13
आधिक्य पेंशन निधि प्रावधान प्रतिलिखित	0.00	288.46
अन्य	166.97	140.81
योग	2485.32	2880.37

अनुसूची XI
अन्य प्रचालन व्यय

	रकम	रकम
	3/31/2009 को समाप्त वर्ष	3/31/2008 को समाप्त वर्ष
झाक, टेलीफोन और तार	960.49	672.63
किराया दर और कर	665.60	455.13
यात्रा और वाहन - अंतर्देशीय	983.76	669.66
विदेशी संबंध		
- यात्रा	104.20	122.04
- विदेशी वृत्तिक निकायों की सदस्यता फीस	57.36	57.31
- अन्य व्यय	4.72	11.06
मरम्मत और अनुसूक्षण	547.61	508.66
प्रकाशन	243.80	206.98
परीक्षकों, परामर्शियों और अन्यो को फीस और व्यय	1893.76	1616.67
कक्षा प्रशिक्षण व्यय	1185.35	480.26
विज्ञापन और जनसंपर्क	386.89	298.33
कार्यालय बैठक व्यय	90.57	82.93
योग्यता छात्रवृत्ति	21.42	15.00
संपरीक्षा फीस		
- प्रधान कार्यालय	3.31	3.37
- अन्य कार्यालय	10.98	9.07
अन्य व्यय	342.74	317.45
योग	7502.56	5728.55

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान**अनुसूची XII****महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों पर विवरण****I. लेखाकरण कन्वेंशन**

लेखा ऐतिहासिक लागत आधार पर बनाए गए हैं और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा जब तक अन्यथा कथित न हो प्रोद्भवन आधार पर हैं।

II. राजस्व मान्यता**क. सदस्यता फीस :-**

(i) प्रवेश फीस, किसी व्यक्ति के सदस्य के रूप में प्रवेश के समय प्राप्त की जाती है और उसके एक तिहाई को आय के रूप में मान्यता दी गई है।

(ii) वार्षिक सदस्यता तथा व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस को, जब वे देय हो जाएं, उसी वर्ष में मान्यता दी जाती है।

- ख. दूरस्थ-शिक्षा और अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम फीस को पाठ्यक्रम की अवधि में मान्यता दी जाती है।
- ग. परीक्षा फीस को परीक्षा संचालन के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- घ. जर्नल के लिए अभिदाय को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है, जब वह देय हो जाए।
- ङ. प्रकाशन के विक्रय से राजस्व को, विक्रय बिल तैयार किए जाने के समय मान्यता दी जाती है अर्थात् जब संपत्ति माल के रूप में और साथ ही महत्वपूर्ण जोखिम और संपत्ति के फायदे क्रेता को अंतरित होते हैं।

च. निवेशों से आय-

(i) यूनिटों में निवेश पर लाभांश को प्राप्त करने की हकदारी के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) ब्याज धारित प्रतिभूतियों और सावधि जमा में ब्याज से आय को समय अनुपात आधार पर बाकी रकम और लागू दर को ध्यान में रखते हुए मान्यता दी जाती है।

III. आरक्षिती और अधिशेष तथा उद्दिष्ट निधि को आबंटन/अंतरण

- क. अध्येता सदस्यों से दाखिला फीस और सदस्यों के रूप में प्रविष्ट व्यक्तियों से प्रवेश शुल्क का 2/3 भाग सीधे अवसंरचना आरक्षिती में चला जाता है।
- ख. भवनों और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त संदान सीधे अपने-अपने आरक्षिती लेखा में संगणित किए जाते हैं।
- ग. दूरस्थ-शिक्षा फीस का 25%, जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50% से अधिक न हो, शिक्षा निधि में अंतरित किया जाता है।
- घ. वर्ष के दौरान सदस्यों से प्राप्त सदस्यता फीस का 0.75% (सहबद्ध और अध्येता तथा व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस) कर्मचारी कल्याणकारी निधि को आबंटित किया जाता है।
- ङ. निम्नलिखित उद्दिष्ट निधियों से शिक्षा आरक्षिती को अंतरण
- लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से लेखांकन अनुसंधान भवन से संबंधित भवन में परिवर्धन की लागत (शुद्ध कटौतियाँ) का 100%
 - शिक्षा निधि से अन्य नियत आस्तियों की परिवृद्धि (कटौतियों के शुद्ध) का 50%।

- च. उद्दिष्ट निधियों के निवेशों से आय, भारित औसत पद्धति के आधार पर उद्दिष्ट निधियों को संबंधित उद्दिष्ट निधियों के आरंभिक अतिशेष पर आबंटित की जाती है ।

IV. स्थिर आस्तियां/अवक्षयण और परिशोधन

- क. भूमि को छोड़कर नियत आस्तियां, अवक्षयण घटाकर ऐतिहासिक लागत पर वर्णित की जाती हैं ।
- ख. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि लागत पर वर्णित की जाती है । पट्टाधृत भूमि, पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए संदत्त प्रीमियम की रकम पर कथित होती है । इस प्रकार संदत्त प्रीमियम का परिशोधन पट्टे की अवधि में किया जाता है ।
- ग. अवक्षयण, संबंधित आस्तियों के उपयोग जीवन के आधार पर परिषद द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित दरों से अवलिखित मूल्य पर प्रदान किया जाता है :-

भवन	5%
वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर	15%
लिफ्ट, विद्युतीय संस्थापन, फर्नीचर और फिक्सचर	10%
वाहन	20%
कंप्यूटर	60%

- घ. अभिवृद्धियों पर अवक्षयण मासिक यथानुपात आधार पर दिया जाता है ।
- ङ. पुस्तकालय पुस्तकों पर क्रय वर्ष में अवक्षयण 100% की दर पर होता है ।
- च. अमूर्त आस्तियां (साफ्टवेयर) तीन वर्षों में समान रूप से परिशोधित की जाती हैं ।

V. निवेश

- क. दीर्घकालिक निवेश, लागत पर अवधारित किए जाते हैं और अस्थायी से भिन्न मूल्यों में कमी का प्रावधान किया जाता है ।
- ख. चालू निवेश लागत या उचित मूल्य के निम्नतर पर वहन होते हैं ।

VI. वस्तु-सूचियां

कागज, उपभोग्य सामग्री, प्रकाशन और अध्ययन सामग्री की वस्तु-सूचियां लागत या शुद्ध वसूलनीय मूल्य के निम्नतर पर मूल्यांकित होती हैं । लागत का अवधारण फीफो रीति से होता है ।

VII. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- क. विदेशी मुद्रा संव्यवहार, संव्यवहार की तारीख को प्रचलित विनमय दर की रकम पर विदेशी मुद्रा उपयोजित करके रिपोर्टिंग मुद्रा में आरंभिक मान्यता पर अभिलिखित किए जाते हैं ।
- ख. सभी आय और व्यय औसत दर पर निष्पादित होते हैं । सभी धनीय आस्तियां वर्षांत दरों पर निष्पादित होती हैं जबकि गैर-धनीय आस्तियां संव्यवहार की तारीख वाली दर पर निष्पादित होती हैं ।
- ग. विनिमय दर अंतर के कारण किसी आय या व्यय को आय और व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है ।

VIII. कर्मचारियों को फायदे

- क. अल्पकालिक कर्मचारी फायदों को वर्ष में बट्टा रहित रकम पर प्रभारित किया जाता है ।
- ख. नियोजन पश्च और दीर्घकालिक कर्मचारी फायदों को उस वर्ष में प्रभारित किया जाता है, जिसमें कर्मचारी ने अपनी सेवा प्रदान की है । प्रभारित रकम को, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अवधारित संदेय रकमों के वर्तमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है । बीमांकिक मूल्यांकन प्रक्षेपित यूनिट प्रत्यय पद्धति के अनुसार किया जाता है । नियोजन पश्च और अन्य

दीर्घकालिक फायदों के संबंध में बीमाकिक अभिताम और हानियों को आय और व्यय लेखा में प्रभावित किया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है।

ग. भविष्य निधि न्यास के रूप में सेवानिवृत्ति फायदे एक परिभाषित अभिदाय स्कीम है और भविष्य निधि न्यास को किए गए अभिदाय को, उस अवधि के लिए जब संबंधित निधि में अभिदाय शोध हो जाता है, आय और व्यय लेखा में प्रभावित किया जाता है।

IX. आस्तियों का हानिकरण

क. यदि आंतरिक/ बाह्य कारकों के आधार पर किसी हानिकरण का कोई संकेत प्राप्त होता है तो आस्तियों की अग्रणीत रकमों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को पुनर्विलोकित किया जाता है। किसी हानिकरण हानि को वहां मान्यता दी जाती है, जहां किसी आस्ति की अग्रणीत रकम उसकी वसूलनीय रकम से अधिक हो जाती है। आस्ति की वसूलनीय रकम उसकी शुद्ध विक्रय कीमत और उपयोग में मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य का निर्धारण करते समय, प्राक्कलित भावी नकद प्रवाह को पूंजी की भारित लागत पर उसके वर्तमान मूल्य में पट्टा प्रदान किया जाता है।

ख. हानिकरण के पश्चात्, आस्तियों को, उसके शेष बचे उपयोगी जीवन के लिए, पुनरीक्षित अग्रणीत रकम पर अवक्षयण प्रदान किया जाता है।

X. प्रावधान

किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है जब किसी पूर्व घटना के कारण उद्यम के पास कोई विद्यमान बाध्यता है; यह संभावना है कि उस बाध्यता के समाधान के लिए संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है। प्रावधानों को, उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टा नहीं दिया जाता है और उनके संबंध में तुलनपत्र की तारीख को बाध्यताओं के समाधान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम प्राक्कलनों के आधार पर अवधारण किया जाता है। इनको प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को पुनर्विलोकन किया जाता है और वर्तमान सर्वोत्तम प्राक्कलनों को उपदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची XIII

लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पण

1. आकस्मिक दायित्व

1.1 धारा 143(3) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2006-07 के बीच निर्धारण आदेश पारित किया गया है, जिसमें उसने 1496.59 लाख रुपए के कर दायित्व को अवधारित किया है। संस्थान ने इसके विरुद्ध सीआईटी (अपील), नई दिल्ली में अपील फाइल की है जिसका न्यायनिर्णयन लंबित है।

1.2 निर्धारण वर्ष 2006-07 से आय-कर अधिनियम की धारा 10(23ग) (iv) के अधीन संस्थान को छूट प्रदान नहीं की गई है और निर्धारण वर्ष 2009-10 से आगे छूट प्रदान किए जाने के आवेदन को विभाग द्वारा 20 मई, 2009 को नार्मजूर कर दिया गया था, अतः इस संबंध में अनिश्चितता के आधार पर संस्थान के लिए आय-कर संदाय करने संबंधी एक आकस्मिक दायित्व विद्यमान है। आकस्मिक दायित्व की रकम निश्चित न होने के कारण, उपलब्ध नहीं कराई गई है।

1.3 संस्थान द्वारा 286.75 लाख रुपए की दावे की रकम (पूर्व वर्ष 84.44 लाख रुपए) को अभिस्वीकृत नहीं किया गया है।

2. अन्य टिप्पण

2.1 पूंजी वचनबद्धता (अग्रिमों का शुद्ध) की प्राक्कलित रकम 7136.32 लाख रुपए है। (पूर्व वर्ष - 4985.31 लाख रुपए)।

2.2 पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में भूमि और विकास प्राधिकरण से नई दिल्ली में क्रय और अर्जित भूमि से संबंधित 6.17 लाख रुपए (पूर्व वर्ष - 6.17 लाख रुपए) जिसका रजिस्ट्रीकरण अभी कराया जाना है, सम्मिलित है।

2.3 ऋण और अग्रिमों में, आईसीएआई लेखांकन अनुसंधान प्रतिष्ठान को दिया गया 210.50 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 565.20 लाख रु.) का ब्याज मुक्त अग्रिम सम्मिलित है।

2.4 भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी "कर्मचारियों के फायदे" संबंधी लेखांकन मानक - 15 (पुनरीक्षित) के अधीन अपेक्षित प्रकटन नीचे दिए गए हैं :-

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान को मान्यता दी जाती है अर्थात् भविष्य निधि में नियोजक के अंशदान को वर्ष के लिए प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित कल्याण योजना

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित कर्मचारी उपदान निधि एक परिभाषित फायदा योजना है। बाध्यता के वर्तमान मूल्य को, अंतिम बाध्यता संगणित करने के लिए प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमाकिक मूल्यांकन पर अवधारित किया जाता है। छुट्टी नकदीकरण और पेंशन की बाध्यता को भी उसी आधार पर मान्यता दी जाती है, जो आधार उपदान के लिए है।

परिभाषित कल्याण योजना की प्राप्ति

पुनरीक्षित लेखांकन मानक-15 द्वारा अपेक्षा किए गए अनुसार परिभाषित फायदा योजना की स्थिति निम्नानुसार है :

लाख रुपए में

	उपदान (निधि पोषित)		छुट्टी - नकदीकरण (गैर निधि पोषित)		पेंशन (गैर निधि पोषित)	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
परिभाषित फायदा बाध्यता के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान						
वर्ष के आरंभ में	643.03		704.13		851.81	
परिभाषित फायदा बाध्यता		600.58		754.81		1,224.62
चालू सेवा लागत	70.45	51.52	165.87	79.86		
ब्याज लागत	47.07	46.40	50.64	58.66	63.83	97.83
बीमाकिक (अभिलाभ/हानि)	12.19	(14.32)	74.28	(146.04)	310.54	(467.24)
संदत फायदे	(30.6)	(41.15)	(57.98)	(43.16)	(1.42)	(3.40)
वर्ष के अंत में परिभाषित फायदे बाध्यता	742.15	643.03	936.14	704.13	1224.76	851.81
योजना आस्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान						
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	559.49	453.71	-	-	-	-
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	54.93	44.66	-	-	-	-
बीमाकिक (अभिलाभ/हानि)	(1.39)	3.04	-	-	-	-
नियोजक का अंशदान	95.25	82.39	-	-	-	-
संदत फायदे	(32.93)	(24.31)	(57.98)	(43.15)	-	-
वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	675.35	559.49	-	-	-	-
आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का समाधान			-	-	-	-

31 मार्च, 2008 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	675.35	559.49	-	-	-	-
31 मार्च, 2008 को बाध्यताओं का विद्यमान मूल्य-दीर्घकालिक	742.15	643.03	936.14	704.13	1224.76	851.81
31 मार्च, 2008 को बाध्यताओं का विद्यमान मूल्य-अल्पकालिक	-	-	45.23	75.64	-	-
31 मार्च, 2008 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई रकम	66.8	83.54	981.37	779.77	1224.76	851.81
वर्ष के दौरान माने गए व्यय						
चालू सेवा लागत	70.45	51.52	165.07	79.86	-	-
ब्याज लागत	47.08	46.40	50.63	58.86	63.83	97.63
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	(54.93)	(44.66)	-	-	-	-
बीमाकिक (अभिलाम)/हानि	13.59	(17.36)	74.28	(146.04)	310.54	(467.24)
अल्पकालिक दायित्व	-	-	45.22	75.64	-	-
वृद्धि लागत	76.19	35.90	335.21	68.12	374.37	(369.41)
बीमाकिक पूर्वानुमान						
नस्वरता सारणी	एलआईसी 1994-96 अंतोगत्वा	एलआईसी 1994-96 अंतोगत्वा	एलआईसी 1994-96 अंतोगत्वा	एलआईसी 1994-96 अंतोगत्वा	एलआईसी 1994-96 अंतोगत्वा	एलआईसी 1994-96 अंतोगत्वा
संनिघर्षण दर	05.00% वार्षिक	05.00% वार्षिक	05.00% वार्षिक	05.00% वार्षिक	05.00% वार्षिक	05.00% वार्षिक
अधिरूपित ब्याज की दर	07.50% वार्षिक	08.00% वार्षिक	07.50% वार्षिक	08.00% वार्षिक	07.50% वार्षिक	08.00% वार्षिक
वेतन में वृद्धि	मूल: 03.00% वार्षिक और म.म.: 06.00% वार्षिक	मूल: 03.00% वार्षिक और म.म.: 08.00% वार्षिक	मूल: 03.00% वार्षिक और म.म.: 06.00% वार्षिक	मूल: 03.00% वार्षिक और म.म.: 08.00% वार्षिक	मूल: 03.00% वार्षिक और म.म.: 06.00% वार्षिक	मूल: 03.00% वार्षिक और म.म.: 06.00% वार्षिक
योजना आस्तियों से आय	09.30% वार्षिक	09.25% वार्षिक				
शेष बची कार्याविधि	18.23 वर्ष	17.46 वर्ष	18.23 वर्ष	17.46 वर्ष	18.23 वर्ष	17.46 वर्ष
निवेश के ब्यारे	100% निवेश एलआईसी में	100% निवेश एलआईसी में	981.37 *	779.77 *	1224.76*	851.81*

* निवेश संस्थान द्वारा किए जाते हैं।

2.5 आय-कर के संबंध में छूट, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(iv) के अधीन निर्धारण वर्ष 2005-06 तक प्रदान की गई है। निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक इस छूट के नवीकरण का आवेदन पत्र विचारणीय है। वर्तमान में निर्धारण वर्ष 2009-10 से आगे छूट प्रदान करने संबंधी आवेदन को 20 मई, 2009 को आयकर प्राधिकारी द्वारा नामंजूर कर दिया गया था। संस्थान का यह दृढ़ विश्वास है कि उसे उक्त छूट प्रदान की जाएगी।

2.6 प्रकाशन और संगोष्ठी की गतिविधियों के केवल प्रत्यक्ष रूप से लक्षणीय खर्चों को क्रमशः इन व्यय शीर्षों पर प्रभावित किया गया है और इन गतिविधियों पर अप्रत्यक्ष व्यय, व्यय के कृत्यकारी शीर्षों पर प्रभावित किए गए हैं।

2.7 पूर्व अवधि आय में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

	2008-09 लाख रुपयों में	2007-08 लाख रुपयों में
अन्य	25.16	9.88
पूर्व अवधि खर्चों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-		
मुद्रण और लेखन सामग्री	0.40	---
लेखा परीक्षा फीस	0.25	---
प्रकाशन व्यय	0.30
परीक्षा फीस	0.96	2.59
मसमत और अनुज्ञा	0.63	2.44
यात्रा और वाहन	6.21	1.23
केतन और मत्ते	2.45	1.03
पत्रमाली फीस	0.17
अन्य	48.80	16.41
योग	59.87	24.00

2.8 संस्थान मुख्यतः भारत में और एक कारबार खंड में प्रचालन करता है, अर्थात् चार्टर्ड एकाउंटेंसी की वृत्ति को बढ़ावा देने ।

2.9 जहां कहीं, पूर्व वर्ष के ऑफिज़ों की तुलना चालू वर्ष के प्रस्तुतिकरण से करना आवश्यक समझा गया, इन्हें पुनः समूहबद्ध और पुनः वर्गीकृत किया गया है ।

टी. कार्तिकेयन, सचिव

[सं. विज्ञापन-III/4/असा.104/2009]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2009

(Chartered Accountants)

No. 1-CA(5)/60/2009.— In pursuance of sub-section (5B) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the Audited Accounts and Report of the Council of the Institute of Chartered Accountants of India for the year ended 31st March, 2009 is hereby published for general information.

60th Annual Report

The Council of the Institute of Chartered Accountants of India (hereinafter referred to as the "Council") has immense pleasure in presenting its 60th Annual Report for the year ended 31st March, 2009.

The Council, at the outset, commends the members and students for the respect which the Chartered Accountancy Profession commands today in the Society. This has been achieved by *excellence, independence and integrity* displayed by the members and students all along.

While highlighting through this Report, the important activities of the Council and its various Committees for the year 2008-2009, besides the accounts of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for the year 2008-2009, the Council also takes this opportunity to cover in this Report major initiatives, important events, statistical profile relating to members, students, details of seminars, conferences, workshops and training programmes organised during the period upto the first week of July, 2009 especially in the context of one more milestone reached i.e. accomplishing six decades of its services to the nation and entering into its 61st year of existence. The year under report has been a historic one, in that, the Institute entered into its Diamond Jubilee Year on 1st July, 2008 and celebrated the same wholeheartedly by conducting programmes befitting the occasion, be it on professional contemporary topics or those on socially relevant areas with a view to bringing the profession closer to the society. The Council resolved on this occasion to continue serving our nation and other stakeholders in the spirit of excellence and integrity.

Since 1st July, 1949, when the Institute was set up by an Act of Parliament, the accountancy profession has grown by leaps and bounds in terms of membership and student base. Founded with just about 1,700 members, the Institute has grown to cross the mark of 1,55,000 members and 5,20,000 students as of now. During its glorious journey, the accountancy profession in India has passed through many crucial phases of restructuring, upgradation, value addition, diversification and global integration. Over the years, the Institute has made considerable progress in its core mission as custodian of transparency and integrity in financial reporting and evolution of highest accounting and auditing standards as it always engaged in change, coupled with a need to adapting consistently to changing economic environment. It is in this context that the Institute has all through been vigilant in ensuring that the training of accountants matches the best in the world, and consequently, a member of the Institute (CA) is increasingly seen as a total business solution provider. The Institute is poised to go a long way in boosting the acceptability, stature and brand image of its members and help them transform them into Global Chartered Accountant. In the 61st year of its existence, it is a matter of encouragement in the journey ahead to note that the leaders of our nation have consistently acknowledged all along the ICAI's initiatives and contributions towards the cause of nation building.

With the changes in the economic environment that have thrown open more challenges, and opportunities alike, for the profession, it is imperative to build capacities of small and medium firms in order to facilitate them face and take advantage of the challenges in an ever increasing competitive environment. For the purpose, the initiatives undertaken include creating awareness and to address possible apprehensions in the members' mind regarding capacity building measures like networking, mergers and management consultancy services in corporate form, to identify the benefits, advantages, challenges faced by members while resorting to such consolidation process. The other initiatives underway include exploring further areas of capacity building like venture capital, tie-ups with banks for availability of funds at cheaper rates, working out the modalities for creation of virtual library and facilitating pooling of infrastructure facilities so that members can actually come together under one roof.

On the international front, the Institute has carved a niche for itself and is widely recognized as one of the premier accounting bodies across the globe. As a result, the services of members of the Institute are sought all over the world. With a view to ensuring more opportunities for members in the global arena, the Institute has signed Mutual Recognition Agreements (MRAs), among others, with the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) and the Institute of Chartered Accountants in Australia (ICAA), during the year under report. With a view to facilitating increased international presence of members of the Institute, the Institute also formed its chapter at New York, and setting up of such Chapters at Singapore and Dublin, as also setting up of an office of the Institute at Bahrain are underway.

It is a matter of pride that even in these times when there is a global talk of economic recession, efforts are being put in place to display the knowledge and skills of the Indian Chartered Accountant to suggest effective measures in tackling the crisis sweeping across the world. By making use of advanced technological innovatives, the entry level test for entering into the profession viz. Common Proficiency Test (CPT) have been held Online successfully.

The Council firmly believes that having a strong and robust accounting profession with all its inbuilt checks and balances therein would act as a catalyst in preserving the sound financial health as economic wealth of the nation. Towards this, the ICAI has developed and enabled notification of Indian accounting standards incorporating the best Indian accounting, auditing and assurance standards incorporating the best international practices prevalent in various accounting bodies of the globe.

1. THE COUNCIL

The Twentieth Council composed of 32 elected members and 8 members nominated by the Central Government, was constituted on 5th February, 2007 for a period of three years. The composition of the Council for the year 2008-2009 and the same for the year 2009-2010 are shown separately.

2. COMMITTEES OF THE COUNCIL

The Council, in terms of Section 17 and Section 21D of the Chartered Accountants Act, 1949, constituted on 5th February, 2009 three Standing, and various Non-Standing Committees/Boards to deal with matters concerning the profession. The Council also constituted a Board of Discipline and a Disciplinary Committee in pursuance to the provisions of Section 21A and 21B of the Chartered Accountants Act, 1949 respectively. Further, a Disciplinary Committee, a standing Committee, was also constituted under Section 21D of the said Act. Of the Non-Standing Committees, new Committees constituted included Small & Medium Practitioners Committee, International Taxation Committee, Infrastructure Committee, HR & Admin. Committee and the Representation Committee. During the year ended 31st March, 2009, 214 meetings were held of various Committees of the Council as compared to 153 meetings held during the year ended 31st March, 2008.

3. AUDITORS

CA. Gurmeet S. Grewal, FCA and CA. Pramod Jain, FCA were the Joint Auditors of the ICAI for the financial year 2008-2009. The Council wishes to place on record its appreciation of the services rendered by them.

4. STANDING COMMITTEES

4.1 Executive Committee

This Committee is responsible for the maintenance of various registers pertaining to students/members/firms, admission, removal and restoration of members, matters relating to members including issue of certificate of practice, matters relating to students including according permission, wherever required, condonation of delay on the part of students/members/firms, matters connected with Branches including opening of new Branches, opening of new Chapters and overseas offices and those connected with employees etc.

Some of the important recommendations made by the Committee during the period under Report to the Council are on matters relating to:

- Setting up of a Chapter of the ICAI in New York, United States of America and in Singapore.
- Setting up of a Branch of Students' Association at Ranchi in Central Region and at Vasai in Western Region.
- Open-ended General Amnesty Scheme for the Members for retrospective registration of membership.
- Rules on translation of documents intended to be used in any proceeding and to be followed by the Institute in any disciplinary proceeding held/dealt with under Section 21 read with Section 22 of the Chartered Accountants Act, 1949.
- Revival of publishing the newsletter 'Corporate Communiqué by the Committee for Members in Industry.
- Opening of Decentralised Office at Thane
- Relaxation in norms for appearance in Final Examination under new scheme of education and training.
- Revision in scale of building grant to branches of Regional Councils.
- Setting up of Alternate Dispute Resolution Cell.
- Clarification on the Seniority position of the firm after the merger of two or more firms.
- GATEWAY to International Trade – Communiqué of the Committee on Trade Laws & WTO.
- Draft Notification pertaining to amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988 arising out of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 relating to multi-disciplinary partnership, Finance Committee, etc.
- Draft Trust Deed for setting up a Trust viz., "The Chartered Accountants Students Benevolent Fund".
- Introduction of various post qualification certificate courses.
- Proposal for changes required to be made in the Chartered Accountant Act, 1949 due to provisions of Limited Liability Partnership Bill 2006.

- Naming of the proposed Centre of Excellence of the Institute at Bangalore in honour of Hon'ble Governor of Karnataka CA. Rameshwar Thakur.
- Setting up of a branch at Beawar in Central Region.
- Remitting a portion of Students Association Fee to the Chartered Accountants Students Benevolent Fund.
- Change in use of letters to 'ICAI' form 'ICA' on qualifying Post Qualification Course on Information Systems Audit.
- Revision of Examination Fee for different Examinations.
- Draft Chartered Accountants (Second Amendment), Regulations, 2008 relating to Accounting Technician Course.
- Accounting Technician Course – Syllabus, Transitional Provisions, Exemption in respect of Group passed earlier, fee structure and other incidental matters related thereto.
- Memorandum of Understanding between ICAI and ICAEW – Course contents for the subjects to be passed by ICAEW members.
- Removal of difficulties, under Regulation 205, in the matter of requirements of test papers for students of PE-II and Final (old syllabus) Examination.
- Admission of Associate Member as Fellow Member in terms of Regulation 5(3).
- Permitting Chartered Accountants in Practice to engage in any other business or occupation.
- Revised Directions of the Central Council regarding Function of the Branches of Regional Councils – relating to particulars/details that might invariably form part of minutes of each meeting of the Managing Committee.
- Introduction of a Study Course and Advanced IT Training to be completed by candidates for Final Examination with such period and in such manner, as may be specified by the Council, from time to time.
- Form of Accounting Technician Level Certificate to be issued under Regulation 40 to those who qualify for the same under proviso to sub-regulation (3) of Regulation 37C.

Some of the important decisions taken by the Committee during the period under Report pertain to:

- Providing Education Officer(s)/Counsellor(s) for rendering counselling services to students.
- Review of Dress Code for the officials of the Institute.
- Formulation of guidelines for installation of plaques/stones/slabs in the Branches, Regional Offices and DCOs vis-à-vis the occasion to be specified for the purpose.
- Protocol to be followed by Regional Councils/Branches in relation to visit of the President / Vice-President to any programme organized by them.
- Revision of honorarium payable to authors who are preparing the basic drafts of publications in the area of insurance and pensions.
- Standardisation and maintaining uniformity of the Institute's priced publications.
- Draft Framework of the Corporate Affairs Standards.
- Revision of Revenue Grant (Membership Fee) payable to Regional Councils and Branches on the basis of members covered by them.
- Review of criteria for selection of Best Regional Council and the Best Branch of the Regional Council.
- Organizing Best CMD/CEO/CFO Awards for the members of the Institute in Industry.
- Proposal for purchase of land for construction of building by Moradabad Branch of CIRC of ICAI.
- Allotment of land in Bangalore for setting up of a Centre of Excellence.
- Face lifting by structural glazing work in existing buildings at Mumbai and Kolkata.
- Suggestions made/received in the course of interaction with officers joined recently and the need felt for putting in place also a policy on employees occupying honorary position(s) in bodies/entities/activities outside the Institute.
- Jurisdiction of Pimpri Chinchwad Branch of WIRC.
- Covering Sub-Regional Conference for CA Students for Board of Studies grant.
- Review of annual financial assistance for students' activities to Regions and Branches.
- Best Regional Council/Branch Awards as well as Best Students' Association/Best Branch of Students' Association Awards.
- Re-imbursement of AC 2 tier fare to students participating in All India Elocution and Quiz

Contests, All India CA Students' Conference and National Convention for CA Students.

- Revision in audit fees for the financial year 2008-09.
- Allotment of land for proposed Centre of Excellence at Jaipur, Rajasthan,
- Setting up of the Accounting Museum of the Institute.
- Development of accounting software by the ICAI for universal application across the globe.
- Sanction for tasks that may be assigned by Municipal Corporation of Delhi to the Institute as part of social responsibility of public institutions.
- Issue of duplicate Identity Card to the members.
- Convocation for the Pass outs.
- Dress code or lapel pins for students and members.
- As a part of goodwill gesture in the Diamond Jubilee Year of the Institute, the rates of pension payable to retired employees of the Institute, brought on par, on the basis of position held at the time of retirement, irrespective of period/date of retirement.
- Procurement of land at Greater Noida.
- Allotment of land to Bhilai Branch of CIRC by Town Services Development of Bhilai Steel Plant (SAIL)
- Grant of permission to appear in Professional Education (Examination-II) by the students who have already been registered for Professional Competence Course (PCC) or who have applied for registration for Professional Competence Course (PCC).
- Contribution to Bihar Flood Relief Account.
- Hiring of campus at Jaipur for 3-months Modular Programme on General Management, Personality Development and Communication Skills.
- Memorandum of Understanding with Bharathiyar University, Coimbatore.
- Certificate of Goodstanding to the Members for registration with the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).
- Providing Lapel Pin for ATC Students.
- Allotment of land at Rohtak and Faridabad.
- Launch of SAP Financial Accounting ERP 2005 (ECC 6.00)
- Management Accounting ERP 2005 (ECC 6.00)
- Improved/Enhanced arrangements for refreshment to participants in the ISA PT batches
- Empanelment of more hospitals and their inclusion in the list of approved hospitals/nursing homes as employees welfare measure
- Re-designing/Re-furbishment of the Institute's building at Mumbai
- Effective date of seniority in case of firms where merger took place prior to August 2008
- Conversion of students registered under Professional Competence Course to Integrated Professional Competence Course
- Introduction of Certificate Course on Business Finance
- Need based providing of laptop with data card to the Secretaries to Committees
- Memorandum of Understanding (MoU) with National Institute of Financial Management (NIFM) for providing 3-months Residential Course to the students for development of soft skills
- Recommendation to the Council on the Terms of Reference of the newly constituted non-standing committees
- Uniformity in letter-heads/newsletters etc. of the Regional Councils and their branches
- Increase in the honorarium payable to Centre Superintendents and other examination functionaries for the conduct of Information Systems Audit Assessment Test
- Conduct of election to the Council and the Regional Councils through the Biometric/Electronic Voting Machines
- Conduct of Orientation Programme between the members of the Regional Councils and the members of Managing Committee of Branches on all India basis
- Setting up of Extension Counters of Branches at places where the number of members though sizeable but fell short of minimum required for the purpose of setting up of a branch
- Nominating members of the Council as mentors on the Institute's Chapters abroad
- Setting up of the Chartered Accountants Students' Benevolent Fund (CASBF) and that a sum of Rs.250 be charged from the students registering at the time of their articles for crediting to the account of CASBF for maintaining various welfare schemes for the students

- Extension of Dress Code for the employees of the Institute at Regional and branch level
- Fee – registration, examination, admission to membership and annual membership – payable to ICAI by members of ICAEW for registration to specified ICAI examination/attaining membership of the ICAI under the Memorandum of Understanding signed between ICAI and the ICAEW
- Authorising the branches to receive students' registration forms and issue study material
- Increase in the grant payable to branches in respect of one day seminars from Rs.10,000 to Rs.20,000
- Increase in the grant payable to Regional Councils and their branches in respect of Elocution Contests from Rs.5,000 to Rs.25,000
- Increase in the grant payable to Regional Councils and their branches in respect of Quiz Contests from Rs.5,000 to Rs.25,000
- Increase in the grant payable to Regional Councils and their Branches for students' activities from Rs.150 per student to Rs.250 per student, subject to maximum specified with reference to strength of the branch
- Increase in the number of National Conventions of CA Students from one to three per region
- Increase in grant for joint seminars with universities from Rs.25,000 to Rs.75,000 for one day seminar and from Rs.40,000 to Rs.1,25,000 for two days seminar
- Deployment of officers at IT labs to monitor, guide, ensure quality education and coordination of matters related thereto
- Holding of Regional and National level Debate Competition for the students of 10th to 12th class and reimbursement of traveling expenses and payment of DA to one parent accompanying the student to the above Competitions
- Establishment of more IT labs, in addition to the existing ones, at branches and the grant by the ICAI to the extent of 75% for the purpose
- Providing security at the IT labs by way of closed CCTV, smoke detector, central locking system, insurance etc. and reimbursement of the expenses thereon by the ICAI to the extent of 75%
- Inviting awardees of Gold Medals by the universities in the B.Com./M.Com. degree examinations to the Convocations organized by the ICAI and honoring them
- Fixation of fee by the members of the ICAI for undertaking Ph. D. Programmes of the Bharathiar University in terms of the Memorandum of Understanding entered into between that University and the ICAI
- Norms for CPE Study Circles for Members otherwise than in practice
- Formation of IT Directorate
- Weightage to branches for their proactiveness in responding to the exposure drafts issued by various committees/boards while selecting Best Regional Council/Best Branch
- Treating a member practicing in his individual name at par with a firm for the purpose of merger of firms
- Justified circumstances for termination/transfer of articles
- Project 'PARIVARTAN' – A Study of Enterprise IT Strategy

4.2 Finance Committee

The Finance Committee – one of the Standing Committees of the Council – came into existence consequent to the amendments to the Chartered Accountants Act, 1949 by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006. The said Committee controls, implements and supervises the activities related with and incidental, inter alia, to maintenance of true and correct accounts, formulation of annual budget, investment of the funds, and disbursements from the funds for expenditure – both revenue and capital.

4.3 Examination Committee

The Chartered Accountants Final and Professional Education-II examinations were held in 173 and 175 centres respectively spread over 105 cities in addition to those at Abu Dhabi, Dubai and Kathmandu in May, 2008. The Professional Competence examination (PCE) was held in 129 centres

in May, 2008. The Common Proficiency Test (CPT) was held in June, 2008 at 207 centres in 111 cities in addition to those at Abu Dhabi and Dubai. The Chartered Accountants PE-II, PCE and Final (Old and New Course), examinations were smoothly conducted all over the country and abroad in 144, 166 and 167 centres respectively from 1st to 16th November, 2008.

The total number of candidates who appeared in the Final, Professional Education –II and Professional Competence Examination held in May, 2008 were 25625, 33395 and 2713 respectively. The total number of candidates who appeared in CPT held in June, 2008 were 76026. The total number of candidates who appeared in the PE-II, PCE and Final (Old and New Course) examinations held in November, 2008 were 27889, 32804 and 34796 respectively.

Besides the aforesaid students' examinations, during the year, Assessment Tests of the Post Qualification Course in Information Systems Audit – Assessment Test (ISA-AT) was also held in June, 2008. Further, Examinations of Management Accountancy Course (Part-I), Corporate Management Course (Part I) and Tax Management Course (Part I) were also conducted alongwith the students' examinations in May, 2008. The Post Qualification Course examinations in Insurance and Risk Management and also in International Trade Laws and World Trade Organisation (ITL & WTO) were successfully conducted in May, 2008.

The Online Common Proficiency Test [CPT] was successfully conducted on December 7, 2008 in 11 cities viz. Ahmedabad, Bangalore, Chennai, New Delhi, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Mumbai, Nagpur and Pune with the examination centres located in the Information Technology Training (ITT) centres of the Institute. Further to the same, the Paper-Pencil mode Common Proficiency Test [CPT] was held successfully on December 14, 2008 across the country and abroad at 221 examination centres located in 111 cities. The total number of candidates who appeared in the Paper-Pencil mode Common Proficiency Test [CPT] held on December 14, 2008 was 89026. The Online Common Proficiency Test [CPT] was successfully conducted on 28th March, 2009 in 8 cities viz. Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi NRO, Hyderabad, Kolkata, Mumbai and Pune with the examination centres located in the Information Technology Training (ITT) centres of the Institute. The Online Common Proficiency Test [CPT] was successfully conducted on 25th April, 2009 in 15 cities viz. Ahmedabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Delhi NRO, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Mumbai, Nagpur, Pune, Surat and Visakhapatnam with the examination centres located in the Information Technology Training (ITT) centres of the Institute. The Online Common Proficiency Test [CPT] was successfully conducted on 23rd May, 2009 in 19 cities viz. Ahmedabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Delhi NRO, Delhi Rohini, Guntur, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Pune, Raipur, Surat, Udaipur and Visakhapatnam with the examination centres located in the Information Technology Training (ITT) centres of the Institute. The total number of candidates who appeared in the Online Common Proficiency Test [CPT] held on December 7, 2008, March 28, 2009, April 25, 2009 and subsequently on 23rd May 2009 were 217, 106, 183 and 271 respectively.

Besides the aforesaid students' examinations, during the year, Information Systems Audit – Assessment Test was held successfully on December 20, 2008 all over the country in twenty nine cities [thirty one examination centres]. Further, examinations of Management Accountancy Course (MAC) (Part-I), Insurance and Risk Management (IRM) and International Trade Laws and World Trade Organization (ITL & WTO) were conducted in November, 2008.

Since the Elections to the Lok Sabha and Legislative Assemblies of some States were scheduled to be held in the months of April and May 2009, it was decided to hold the Chartered Accountants PE-II, PCE, Final (Old and New Course), IRM, MAC (Part-I), TMC (Part-I), CMC (Part-I), ITL & WTO Examinations from 1st to 15th June, 2009 instead of May 2009. During the year under report, for the convenience of candidates, the following facilities are continued to be provided:

- For the June, 2009 CA examinations, new examination centres have been opened at Beawar, Sonapat and Pali Marwar (Sonapat and Pali Marwar were existing examination centres for CPT only). Further, new examination centres have been opened at Bilaspur, Aligarh and Bahrain for the CPT held on 28th June, 2009.

- Examination application forms in the OMR format were continued for May, 2008, November, 2008 and June, 2009 examinations also and the admit cards bearing the candidate's scanned photograph and specimen signature were issued to the candidates. This obviated the necessity of issuance of the identity card to the candidates separately.
- Examination application forms were continued to be made available, besides at all the Regional offices of the ICAI and branches of the Regional Councils at different locations in the metropolis of Delhi, Kolkata and Mumbai. Candidates were extended the facility of downloading the admit card from the website by using the Personal Identification Number (PIN) indicated by them in the OMR application form.
- Students residing in places where the Regional/decentralized offices of the ICAI are situated i.e., Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Mumbai and Pune were offered the facility of submitting their application forms with late fee at the respective offices up to the last date of submission of application form with late fee.
- The results as well as the marks were also made available on the National Informatics Centre's website. Information pertaining to Merit List was also made available on the website simultaneously with declaration of results.
- Facility of downloading of the results as well as marks by the Regional Offices of the ICAI and branches of Regional Councils was made available simultaneously with the declaration of results.
- Facility of registering requests in advance for ascertaining results on declaration was continued and candidates registering for the same were provided with their results by e-mail immediately after declaration of results.
- Admit card through e-mail query was continued to be extended to the students for May, 2008, November, 2008 and June, 2009 examinations.
- Results of May, 2008, November, 2008 and June, 2009 examinations were continued to be made available on SMS mode.

4.4 Disciplinary Committee

This Committee assists the Council in the maintenance of the status and standards of professional qualification awarded by the Institute. In discharging its avowed responsibility of conducting disciplinary inquiries against members whose cases have been referred to it by the Council upon *prima facie* opinion, during the year 1st April, 2008 to 31st March, 2009, the Committee held sittings on 20 occasions for a period spanning 32 days and at venues covering the various regions of the country. During the year under review, the Committee concluded its enquiry in 84 cases, which included cases, referred to it in previous years.

5. TECHNICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

5.1 Accounting Standards Board

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), being a premier accounting body in the country, has been relentlessly working to provide a sound, reliable and high-quality accounting and financial reporting system in the country. For harmonising the diverse accounting policies and practices in India, the ICAI had set up the Accounting Standards Board (ASB) in 1977 for formulating the Accounting Standards. Since its inception, ASB has been working in this direction by formulating new Accounting Standards as well as revising the existing Accounting Standards from time to time. The objective is to bring the Indian Standards in line with the International Accounting Standards (IAS) and International Financial Reporting Standards (IFRS), as issued by the International Accounting Standards Board (IASB). The ASB also issues various announcements from time to time to provide guidance on matters pertaining to uniform application of the Accounting Standards and their implementation. The legal recognition to the Accounting Standards formulated by the ICAI was granted in October 1998 with insertion of Section 211(3A), (3B), and (3C) in the Companies Act, 1956. As per Section

211(3C) of the Act, Accounting Standards issued by the ICAI may be prescribed by the Central Government in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS). As per the proviso in the section, till the notification of the Accounting Standards by the Government, the Accounting Standards issued by the ICAI are required to be followed by companies.

In the year 2006, Accounting Standards 1 to 7 and 9 to 29 were prescribed by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 vide its notification dated December 7, 2006 in the Gazette of India. These are to be effective in respect of accounting periods commencing on or after the publication of these Accounting Standards (that is, December 7, 2006). Further, Limited Revision to Accounting Standard (AS) 15 was notified under Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2008 vide its notification dated March 27, 2008. Recently, amendment to the Accounting Standard (AS) 11 has been notified under Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2009 vide notification dated March 31, 2009, by the Central Government in consultation with NACAS.

With globalisation and liberalisation, capital markets have gone global. Firms seeking to tap foreign capital markets often have to prepare two sets of accounts; one to adhere to the home requirements and the other to conform to the foreign market in which capital is raised. Multiple standards constrain the volume and efficiency of capital allocation since the investors cannot easily compare financial information of companies in different jurisdictions. Thus, a need for a single set of globally accepted and high-quality Accounting Standards has often been felt. The International Financial Reporting Standards being issued by the IASB are increasingly being recognised as the global financial reporting standards. Many countries have either adopted or have permitted adoption of IFRS for preparing financial statements of various entities. Though the Accounting Standards issued by ICAI are primarily based on IAS/IFRS, in certain cases, the Accounting Standards have departed from IAS/IFRS in view of legal and regulatory requirements apart from the economic conditions prevailing in the country.

Convergence with International Financial Reporting Standards has gained worldwide momentum in recent years. More than 113 countries currently require or permit the use of or have a policy of convergence with IFRS. Certain other countries have announced their intention to adopt IFRS from a future date, for example, Brazil and Canada from the year 2010 and 2011 respectively. Financial Accounting Standards Board (FASB) of USA and IASB are also working towards convergence of US GAAP and IFRS. The Securities and Exchange Commission (SEC) of USA has decided to permit filing of IFRS-compliant financial statements without requiring presentation of a reconciliation statement between the US GAAP and IFRS. In this scenario, with India being an important emerging global economy, the Institute of Chartered Accountants of India has decided to converge with IFRS from 1st April 2011 in respect of public interest entities. The Ministry of Corporate Affairs has also agreed to do so. Convergence, among other things, would help Indian entities raise capital from abroad at a low cost. It will also benefit the chartered accountants with opening of increased opportunities abroad for the Indian professionals.

To implement the decision on convergence with IFRS and making India IFRS-compliant, ASB had constituted a Task Force in the year 2006 with a mandate to explore the approach for convergence with IFRS and lay down a road map for achieving such convergence. The Task Force prepared a Concept Paper, which was accepted by the ASB and the Council of the ICAI. The principal recommendation in the Concept Paper was convergence with IFRS by large-sized companies and public interest organisations such as listed entities, banks and insurance entities from accounting periods beginning on or after 1st April 2011. However, keeping in view the changed circumstances and to address issues being faced in implementation of the decision of convergence, the road map is being reconsidered for suitable modifications.

For implementation of the decision on convergence with IFRS, the ASB constituted a Group to carry out various functions for a smooth transition to IFRS from 2011. This Group further constituted four

Sub-Groups for (a) preparing the work plan of ASB and liaising with the IASB; (b) approaching the government and regulatory authorities; (c) liaising with the industry associations; and (d) providing education and training on IFRS so that the accountants are ready for convergence.

The Board is having the target of issuing the Indian-equivalent standards that correspond to all the IAS/IFRS issued by the IASB. The Sub-Group for Approaching the Government and Regulatory Authorities was constituted with the objective of identifying the conflicting legal and regulatory requirements arising out of convergence with IFRS and approaching the relevant authorities to change various laws and regulations, where appropriate. This Sub-Group further constituted Core Groups for identifying the issues relating to adoption of IFRS for Companies Act, SEBI Rules and Regulations; apart from the issues concerning insurance entities, banks and other financial institutions. Reports on changes required in the Companies Act, 1956, and SEBI Rules and Regulations (other than Mutual Funds) have already been finalised. They are being taken up with the relevant authorities for necessary amendments in the laws. Other reports are also being finalised.

The Sub-Group for Liaising with Industry Associations was constituted with the objective of seeking their co-operation in making the industry ready for adoption of IFRS after obtaining industry-specific views on implementation of IFRS. In this regard, the Sub-Group has held meetings with representatives of various industries associations in association with the ASB. All associations are supporting the convergence with IFRS.

The Sub-Group on Education and Training was constituted with the objective of looking into the requirements for providing training to preparers, auditors and other accounting professionals. In this regard, a Certificate Course on IFRS has been launched at Mumbai, Delhi, Bangalore, Pune, Kolkata and Hyderabad, which includes 60 hours e-learning and 30 hours classroom teaching. An examination for the Certificate Course on IFRS was also conducted on March 29, 2009, in which, out of 128 participants, 116 were declared pass. Significantly, around 700 members have registered themselves for the course. Further, FICCI, ASSOCHAM, and CII have also been approached to organise IFRS awareness programmes for the industry.

As far as Small and Medium-Sized Entities are concerned, the IASB has constituted a Study Group to look into the requirements of IFRS for SMEs. The group will examine whether the same norms can be adopted for SMEs in India or whether the existing standards should continue.

A brief overview of other activities of the Accounting Standards Board during the period under report is as follows:

5.1.1 Contribution to the Activities of the International Accounting Standards Board (IASB) and Participation in Other International Developments

The Board interacts with the IASB at various levels, such as:

- Active participation with the IASB in meetings of the World Standard-Setters (WSS), National Standard-Setters (NSS) and Regional Standard-Setters (RSS)

In this regard, the Chairman and Secretary, ASB, attended the meeting of NSS held on September 10, 2008 at Paris, where they participated in discussions on various issues that included Conceptual Framework, ASB Consolidated Project, and Accounting for Complex Financial Instruments. The representatives of the ICAI gave various suggestions, many of which were accepted. They attended the two-day meeting of WSS from September 11, 2008 at London, where Chairman, ASB, made a presentation on the steps taken in India for convergence with IFRS from 2011.

- The Board circulated and hosted on the website various Exposure Drafts/Discussion Papers issued by the IASB, inviting comments by various stakeholders. Comments considered relevant were submitted to the IASB.

To play a more influential role pending convergence with the IFRS, the Board constitutes from time to time Study Groups to analyse discussion papers or exposure drafts issued by the IASB. After analysis, the Groups send their comments listing the India-specific concerns, which are reviewed by the ASB prior to its submission to the IASB.

- IASB official, Mr. Wayne S. Upton, Director of International Activities, and Mr. Prabhakar Kalavacherla, full-time Member, IASB, visited the ICAI on May 12, 2009, where the Board discussed with them various issues involved in convergence with IFRS.

5.1.2 Interaction with National Advisory Committee on Accounting Standards

The NACAS considered the revised Accounting Standard (AS) 2, *Inventories*, and Accounting Standard (AS) 3, *Statement of Cash Flows*, formulated by the ICAI during the period under report. Suggestions made by the NACAS were considered by the Board and addressed in an appropriate manner to the satisfaction of the Board. Accounting Standard (AS) 12, *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance* prepared by the Board has already been sent by NACAS to the Ministry of Corporate Affairs for notification.

5.1.3 Interaction with Regulatory Bodies

Being the premier accounting body, the ICAI, through ASB, interacts with various regulatory bodies from time to time and expresses its views on various accounting matters.

In addition to the above, regular meetings are held with MCA on various accounting issues.

5.1.4 Other Projects

- After realising the importance of Accounting for Certified Emission Rights (CERs), a study group was constituted last year to address all the relevant issues. The study group prepared the draft of Guidance Note on Accounting for Self-generated Certified Emission Reductions (CERs), which was considered by the ASB and the same was issued as Exposure Draft for comments from the public.
- A study group with the objective of issuing guidelines on Service Concession Arrangements was constituted earlier. The study group prepared the draft of Guidance Note on Accounting for Service Concession Arrangements, which was considered by the ASB and the same was issued as Exposure Draft for comments from the public.
- Frequently Asked Questions (FAQs) on AS 11 notification – Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2009 issued by the Ministry of Corporate Affairs, have been issued.

5.1.5 New Releases

Issuance of New Accounting Standards

- Accounting Standard (AS) 32, *Financial Instruments: Disclosures*
- Frequently Asked Questions (FAQs) on AS 11 notification – Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2009 issued by the Ministry of Corporate Affairs
- Accounting Standards Approved by ASB, Council, Cleared by NACAS, Ready for Issuance Upon Notification by MCA
- Accounting Standard (AS) 2, *Valuation of Inventories*
- Accounting Standard (AS) 3, *Statement of Cash Flows*
- Accounting Standard (AS) 10, *Property, Plant and Equipment*
- Accounting Standard (AS) 12, *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance*

- **Drafts of New/Revised Accounting Standards, Guidance Note Issued for Public Exposure**
 - AS 16, *Borrowing Costs*
 - AS 1, *Presentation of Financial Statements*
 - Guidance Note on Accounting for Service Concession Arrangements on the lines of IFRIC 12
 - Guidance Note on Accounting for Self-generated Certified Emission Reductions
- **Drafts of New/Revised Accounting Standards Being Finalised for Public Exposure**
 - AS 7, *Construction Contracts*
- **Drafts of New/Revised Accounting Standards Circulated among the Institute's Council Members, Specified Outside Bodies and NACAS**
 - AS 29, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*
 - AS 25, *Interim Financial Reporting*
 - AS 33, *Share-based Payment*
- **Drafts of New/Revised Accounting Standards Being Finalised for Circulation among the Institute's Council Members, Specified Outside Bodies and NACAS**
 - AS 4, *Events After the Reporting Date*
 - AS 11, *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*
 - AS 15, *Employee Benefits*
 - AS 17, *Operating Segments*
 - AS 21, *Consolidated and Separate Financial Statements*
 - AS 23, *Investments in Associates*
 - AS 28, *Impairment of Assets*
 - Accounting Standard corresponding to IAS 29, *Financial Reporting in Hyperinflationary Economies*
 - Accounting Standard corresponding to IFRS 6, *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources*
- **Accounting Standards Under Revision**
 - Accounting Standard (AS) 9 corresponding to IAS 18, *Revenue*
 - Accounting Standard (AS) 22 corresponding to IAS 12, *Income Taxes*
 - Accounting Standard (AS) 26 corresponding to IAS 38, *Intangible Assets*
 - Accounting Standard (AS) 14 corresponding to IFRS 3, *Business Combinations*
 - Accounting Standard (AS) 5 corresponding to IAS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*
- **Preparation of New Accounting Standards**
 - Accounting Standard corresponding to IAS 26, *Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans*
 - Accounting Standard corresponding to IAS 40, *Investment Property*
 - Accounting Standard corresponding to IAS 41, *Agriculture*
 - Accounting Standard corresponding IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*
 - Accounting Standard corresponding IFRS 4, *Insurance Contracts*
- **Drafts of Revised Accounting Standards Under Consideration of ASB**
 - Accounting Standard (AS) 19, *Leases* (Corresponding IAS is under revision)
 - Accounting Standard (AS) 24, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations* (Corresponding IFRS is under revision)

- Accounting Standard (AS) 20, *Earnings Per Share*

Other Projects

- Preface to the Statements of Accounting Standards Under Revision
- Revision of Concept Paper

5.2 Committee on Accounting Standards for Local Bodies

Recognising the need for a single set of high quality financial reporting standards for Local Bodies in view of more and more local bodies shifting from cash basis to accrual basis of accounting, the Council of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), constituted an independent Committee on Accounting Standards for Local Bodies (CASLB) in March 2005 with the main objective of formulating Accounting Standards for Local Bodies on accrual basis.

The composition of the CASLB is fairly broad-based and ensures participation of all interest-groups in the standard-setting process. Apart from the members of the Council of the ICAI, the CASLB comprises the representatives of the Ministry of Urban Development, Comptroller and Auditor General of India, Controller General of Accounts, National Institute of Urban Affairs, Ministry of Panchayati Raj, Directorates of major Local Bodies, Directorates of Local Fund Audit Departments, Academic Institutions and other eminent professionals co-opted by the ICAI.

Apart from formulation of Accounting Standards for Local Bodies, the Committee also takes steps in facilitating improvement in accounting methodology and systems of local bodies, and acts as a forum to receive feedback from Local Bodies regarding problems faced by them in the adoption of accrual accounting and in application of the Accounting Standards as set out in its Preface to the Accounting Standards for Local Bodies.

While formulating Accounting Standards for Local Bodies, the CASLB gives due consideration to the International Public Sector Accounting Standards (IPSASs) prepared by the International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) of the International Federation of Accountants (IFAC) and tries to integrate them, to the extent possible, with a view to facilitate global harmonization.

During the period under Report, the Committee has issued 3 publications namely, Accounting Standard for Local Bodies 3, '*Revenue from Exchange Transactions*', Accounting Standard for Local Bodies 4, '*Borrowing Costs*' and Booklet on '*Accrual Accounting for Local Bodies: Elected Representatives & Stakeholders*'. The Committee has also forwarded the comments on proposed National Municipal Assets Valuation Methodology Manual developed by the National Institute of Urban Affairs.

The draft 'Framework for the Preparation and Presentation of Financial Reports by Local Bodies' is being finalised for its public exposure on the basis of the comments received on its limited circulation among the specified outside bodies and the Council members of the Institute. The draft Framework sets out the concepts that underlie the preparation and presentation of financial statements and would assist the Committee in the development of future Accounting Standards for Local Bodies. The draft of the proposed Accounting Standard for Local Bodies on 'Presentation of Financial Statements' is being finalized for its limited circulation among specified outside bodies and the Council members. The CASLB has also undertaken many other projects for preparation of Accounting Standards for Local Bodies corresponding to International Public Sector Accounting Standards.

The Committee has organised an Awareness Workshop on '*Implementation of Accounting Reforms in Local Bodies: Current Scenario and a Way Forward*' jointly with the Ministry of Urban Development, Government of India on January 15-17, 2009 at Goa for the benefits of end users. The Committee is proposing to hold another Awareness Workshop on the same lines in the Northern-

Eastern region covering the 8 North-East States for the benefits of end users. The Committee is also proposing to hold the workshops for Chartered Accountants for creating awareness among them on the opportunities as a result of the reforms process being followed by Local Bodies.

The ICAI is a member of the Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB) and is also represented on its various Sub-Committees formulated from time to time by GASAB. The representatives of the ICAI participated in the meetings of GASAB held during the year and contributed to the technical activities of the Board. The CASLB prepares comments on drafts at various stages prepared by GASAB.

Given below is the resume of the important activities of the Committee on Accounting Standards for Local Bodies:

Preliminary Draft received from Study Group

- ◆ Proposed Accounting Standard for local Bodies (ASLB) on '*Segment Reporting*'

Draft of pronouncement being prepared for Public Exposure:

- ◆ Framework for the Preparation and Presentation of Financial Reports by Local Bodies
- ◆ Status paper on Accounting Reforms in Local Bodies and Role of Chartered Accountants

Drafts of Pronouncements being prepared for circulation among the Institute's Council Members and Specified Outside Bodies for comments:

- ◆ Proposed Accounting Standard for Local Bodies (ASLB) on '*Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*'
- ◆ Proposed Accounting Standard for Local Bodies on '*Property, Plant and Equipment*'
- ◆ Proposed Accounting Standard for Local Bodies (ASLB) on '*Events After the Reporting Date*'
- ◆ Proposed Accounting Standard for Local Bodies on '*Presentation of Financial Statements*'
- ◆ Proposed Accounting Standard for Local Bodies on '*Revenue from Non-Exchange Transactions*'
- ◆ Proposed Accounting Standard for Local Bodies on '*Construction Contracts*'

Other projects the drafts of which are under preparation by various Study Groups:

- ◆ *Drafts of Proposed Accounting Standards for Local Bodies*
 - Cash Flow Statements
 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
 - Inventories
 - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
- ◆ *Other Project*
 - Translation of the Booklet Highlighting the Benefits of Accrual Accounting into various regional languages

5.3 Auditing and Assurance Standards Board

The financial statements, prepared and presented annually, are directed towards the common information needs of a wide range of users. Audit adds credibility to those financial statements. Auditing therefore has a critical role in lubricating the wheels of economic development. It is therefore essential that the audits performed are of high quality and undertaken with the underlying objective of serving the public interest. The auditing profession, therefore, does have certain set of universally accepted benchmarks, called Auditing Standards, against which the performance of an auditor can be measured. Auditing standards contain guidance for the professionals on how they should carry out their professional engagements, enshrined as the basic principles and essential procedures to apply those basic principles that relates to judgment or behavior. Auditing standards

are framed to ensure probity, integrity and quality in the professionals' work, essential for ensuring the confidence of the society in the financial information being reported by the business enterprises.

In India, the Auditing and Assurance Standards Board of the Institute is formulating and issuing high quality standards dealing with auditing, review, other assurance, quality control and related services, which represent a codification of the best practices in the field of auditing in the country and are, therefore, mandatory in nature. The Standards issued by the Board under the authority of the Council are benchmarked with the International Standards on Auditing (ISAs) issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). AASB in 2007 initialed its Clarity Project corresponding to that initiated by IAASB. Pursuant to the said Project the Board has brought in sweeping to the auditing Standards, the way they are written and are to be understood, besides re-numbering and re-categorisation of the same. The Board has issued 16 new/Revised auditing Standards and by 2010 end, the entire suite of new/revised auditing Standards would be in place.

In addition to the Standards, the Board also formulates and issues Guidance Notes, under the authority of the Council. Further, the Board also formulates Technical Guides, Practice Manuals, Studies and Other Papers under its own authority for the guidance of the members. To provide guidance in implementation of Standards on Auditing (SAs) issued under the Clarity Project, the Board is also bringing out Implementation Guide to the Standards issued under the Clarity Project.

The achievements of the Board are:

➤ **Engagement & Quality Control Standards**

Quality Control Standards

- ◆ Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements"

Engagement Standards

- ◆ 33 Standards on Auditing, including 22 Standards under the Clarity Project and 1 General Clarifications (as listed below)
- ◆ 1 Standard on Review Engagements
- ◆ 1 Standard on Assurance Engagements
- ◆ 2 Standards on Related Services
- **Statements on Auditing and Guidance Notes**
 - ◆ 2 Statements (List is given as Annexure-II)
 - ◆ 31 Guidance Notes on auditing issues, as given in the Handbook of Auditing Pronouncements, is enclosed as Annexure-III
- **Industry Specific Guidance Notes**
 - ◆ Audit of Banks (Revised 2009 edition)
 - ◆ Audit of Accounts of Members of Stock Exchanges
 - ◆ Audit of Companies Carrying on General Insurance Business
 - ◆ Audit of Companies Carrying on Life Insurance Business
- **Other Publications (Non – authoritative)**
 - ◆ Handbook of Auditing Pronouncements (2008 Edition)
 - ◆ Background Material on Auditing and Assurance Standards
 - ◆ Technical Guide on Audit in Telecom Industry – Revenue, Fixed Assets and Related Operating Costs
 - ◆ Technical Guide on E-Commerce- Considerations for Audit of Financial Statements
 - ◆ A Study on Basel II and Risk-based Supervision
 - ◆ Implementation Guide to SQC 1
 - ◆ Implementation Guide to Risk-based Audit of Financial Statements

5.3.1 The Year 2008-09

During the year 2008-09, seven meetings of the Auditing and Assurance Standards Board totaling 11 days of full Board deliberation were held. During this year, the Board sped up its process of

Convergence with the International Standards on Auditing (ISAs) issued by International Auditing and Assurance Standards Board. The Board issued the "Convergence with the International Standards of the IAASB-Position Paper and Work Plan". This Paper sets forth the position and policy of the Institute in respect of Convergence with the International Standards issued by the IAASB and the need for continuing the work towards that direction. The Paper further discusses the pertinent issues before AASB in convergence. The Paper also discusses the Work Plan of the Auditing and Assurance Standards Board (AASB) in the context of achieving convergence with the IAASB's Standards. In addition to this, the paper also discusses the ICAI initiatives on the convergence with the IAASB. Further, in the process of the convergence with the IAASB standards, the Board has, during the year, issued twelve (12) Standards on Auditing (SAs) under the Clarity Project, which are as follows:

Revised SA 230, "Audit Documentation"

SA 230 is a revised version of the erstwhile Auditing and Assurance Standard (AAS) 3, "Documentation" issued by the Institute in 1985. The new Standard deals with the auditor's responsibility to prepare audit documentation for an audit of financial statements. SA 230 also deals with the requirements of timely preparation of audit documentation, documentation of the audit procedures performed and audit evidence obtained and assembly of the final audit file. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2009.

Revised SA 250, "Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements"

SA 250 is a revised version of the erstwhile Auditing and Assurance Standard (AAS) 21, "Considerations of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements" issued by the Institute in 2001. The new Standard deals with the auditor's responsibility to consider laws and regulations when performing an audit of financial statements. SA 250 states the effect of laws and regulations, responsibility of management for compliance with laws and regulation, responsibility of the auditor, audit procedures and reporting of identified or suspected non-compliance and documentation requirements. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2009.

Revised SA 260, "Communication with Those Charged with Governance"

SA 260 is a revised version of the erstwhile Auditing and Assurance Standard (AAS) 27, "Communications of Audit Matters with Those Charged with Governance" issued by the Institute in 2003. This Standard deals with the auditor's responsibility to communicate with those charged with governance in relation to an audit of financial statements. SA 260 also describes the requirements regarding those charged with governance, matter to be communicated and documentation. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2009.

Revised SA 500, "Audit Evidence"

Audit evidence is fundamental aspect of an audit on which the final audit opinion and the audit report is based. The quality and effectiveness of an audit is, therefore, to a large extent affected by the adequacy and appropriateness of the auditor's procedures in gathering and evaluating the audit evidence. Though the Council of the Institute had in May 1988 issued a Standard on Audit Evidence, the Revised version of this Standard cleared today contains greater guidance for the auditors on critical aspects of audit evidence such as what constitutes sufficient appropriate audit evidence, information to be used as audit evidence, factors to consider in selecting items for testing, how to respond in case of inconsistency in or doubts over reliability of audit evidence. In other words, the Revised Standard in principles and procedures to be followed by them to obtain and evaluate audit evidence which is sufficient and appropriate for the purpose of their audit. This Revised Standard is effective for audits of all financial statements for periods beginning on or after April 1, 2009.

Revised SA 510, "Initial Audit Engagements- Opening Balances"

SA 510 is a revised version of the erstwhile Auditing and Assurance Standard (AAS) 22, "Initial Engagements - Opening Balances" issued by the Institute in July 2001. This Standard deals with

auditor's responsibility with respect to opening balances when performing initial audit engagements. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010.

Revised SA 530, "Audit Sampling"

SA 530 is a revised version of the erstwhile Auditing and Assurance Standard (AAS) 15, "Audit Sampling" issued by the Institute in April, 1998. This Standard guides auditors while using sampling techniques in their audit assignments, and covers both statistical and non-statistical sampling. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2009.

Revised SA 540, "Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates, and Related Disclosures"

SA 540 is a revised version of the erstwhile Auditing and Assurance Standard (AAS) 18, "Audit of Accounting Estimates" issued by the Institute in April, 2000. This Standard provides timely guidance on audit of fair value and accounting estimates in the current times of market uncertainty and liquidity crunch. Accounting estimate is an approximation of a monetary amount in the absence of precise means of measurement. Risk of material misstatement increases significantly since accounting estimate involves the use of judgment by the management. This Standard provides specific guidance to auditor while verifying the valuation of complex financial instruments which are not traded in active and open market and transactions involving the exchange parties without monetary consideration. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2009.

Revised SA 550, "Related Parties"

SA 550 is a revised version of the erstwhile Auditing and Assurance Standard (AAS) 23, "Related Parties" issued by the Institute in April, 2001. This Standard is aimed to strengthen current auditing practice in this area by emphasizing the need for the auditor to understand related party relationships and transactions in order to identify the risks of material misstatement to which these may give rise, and directing the auditor to focus work effort on the assessed risks of material misstatement, including those due to fraud. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010.

Revised SA 560, "Subsequent events"

SA 560 is a revised version of the erstwhile Auditing and Assurance Standard (AAS) 19, "Subsequent Events" issued by the Institute in 2000. The new Standard deals with the auditor's responsibilities relating to subsequent events in an audit of financial statements. SA 560 also deals with the events occurring between the date of the financial statements and the date of the auditor's report, facts which become known to the auditor after the date of the auditor's report but before the date the financial statements are issued and facts which become known to the auditor after the financial statements have been issued. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2009.

Revised SA 570, "Going Concern"

SA 570 is a revised version of the erstwhile Auditing and Assurance Standard (AAS) 16, "Going Concern" issued by the Institute in 1998. The new Standard is quite detailed in terms of auditor's responsibility in the audit of financial statements with respect to management's use of the going concern assumption in the preparation and presentation of the financial statements. SA 570 requires the auditor to inquire of management as to its knowledge of events or conditions beyond the period of management's assessment that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. SA 570 also states the requirements of risk assessment procedures and related activities, evaluating management's assessment, additional procedures, audit conclusions and reporting, use of going concern assumption etc. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2009.

Revised SA 580, "Written Representations"

The SA 580 is a revised version of the erstwhile Auditing and Assurance Standard (AAS) 11, *Representations by Management* issued by the Institute in 1996. The new Standard is quite detailed in terms of the duties and objectives of the auditors in regard to the acknowledgement by the management that it is fulfilling its responsibility relating to preparation and presentation of financial statements and internal controls, the various forms of management representations, situations where management representations are unreliable or where the management refuses to provide requested representations. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2009.

SA 720, "The Auditor's Responsibility in Relation to Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements"

The responsibility the auditor, in an audit of financial statements, is to express an opinion on the truth and fairness of the financial statements, the basic objective of an audit being to lend credibility to the financial statements. In a number of cases, especially companies, the annual reports or other such documents that contain audited financial statements and audit report thereon, issued to stakeholders, contain a lot of other information which is related/ unrelated to the financial statements. For example, reports by managements/ directors, financial ratios, etc. The Standard is a first of its kind Standard to have been issued by the Institute and requires the auditor to read such other information to identify any material inconsistencies *vis a vis* the audited financial statements since these can undermine the credibility of those financial statements and the audit report thereon. The Standard contains detailed guidance on auditor's procedures where such material inconsistency is identified or in the process of reading such other information, any apparent misstatement of facts come to the attention of the auditor. This Standard is effective for audits of all financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010.

In addition to the above, the Council, at its 288th meeting held from June 18 to 20, 2009 at Mumbai and Aamby Valley city, approved the following Standards on Auditing (SAs) and decided to make these SAs applicable for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010:

Revised SA 210, "Agreeing the Terms of Audit Engagements"

The SA 210 is a revised version of the erstwhile Auditing and Assurance Standard (AAS) 26, *Terms of Audit Engagements* issued by the Institute in 2003. The new Standard deals with the auditor's responsibilities in agreeing the terms of the audit engagement with management and, where appropriate, those charged with governance that includes establishing that certain preconditions for an audit, responsibility for which rests with management and, where appropriate, those charged with governance, are present. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010.

SA 265, "Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management"

Communication is a best way of imparting or interchanging of thoughts and opinions relating to deficiencies come across by the auditor during the course of an audit to the management or those charged with governance. Though the aspects relating to communication of audit matters has been covered by Revised Standard on Auditing (SA) 260, *Communication with Those Charged with Governance*, this Standard specifically deals with the auditor's responsibility to communicate appropriately to those charged with governance and management deficiencies in internal control that the auditor has identified in an audit of financial statements. This Standard is effective for audits of all financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010.

Revised SA 402, "Audit Considerations Relating to an Entity Using a Service Organization"

In the today's era, it is very common for the organisations to outsource some of its operational activities to one or more service organisations to concentrate more on its core activities and optimum utilisation of its available resources. Though the erstwhile Auditing and Assurance Standard (AAS) 24, *Audit Considerations Relating to an Entity Using a Service Organisation* issued by the Institute in August, 2002 covered these aspects, revised Standard provides more elaboration and application guidance on those aspects. The Standard deals with the user auditor's responsibility to obtain sufficient appropriate audit evidence when a user entity uses the services of one or more service organisations. It also provides the linkage with the risk based audit Standards, i.e., SA 315, *Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement Through Understanding the Entity and Its Environment* and SA 330, *The Auditor's Responses to Assessed Risks*. This Standard is effective for audits of all financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010.

Revised SA 610, "Using the Work of Internal Auditors"

The SA 610 is a revised version of the erstwhile Auditing and Assurance Standard (AAS) 7, *Relaying upon the Work of an Internal Auditor* issued by the Institute in January 1989. The new Standard deals with the external auditor's responsibilities regarding the work of internal auditors when the external auditor has determined, in accordance with SA 315, that the internal audit function is likely to be relevant to the audit. This Standard is effective for audits of all financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010.

Revised SA 320, "Materiality in Planning and Performing an Audit"

The SA 320 is a revised version of the erstwhile Auditing and Assurance Standard (AAS) 13, *Audit Materiality* issued by the Institute in January 1977. Whereas erstwhile AAS 13 covers the aspects relating to audit materiality, its relationship with audit risk at the planning stage as well as at the time of performance of audit procedures and evaluation of the misstatement identified during the audit, the new Standard deals only with the auditor's responsibilities to apply concept of materiality in planning and performing an audit of financial statement and there is separate SA for the evaluation of misstatement identified during the audit i.e. SA 450. This Standard is effective for audits of all financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010.

Revised SA 450, "Evaluation of Misstatements Identified during the Audit"

Although there is no separate Standard on Auditing corresponding to SA 450, "Evaluation of Misstatement Identified During the Audit", the some concepts of SA 450 has been covered by the erstwhile AAS 13, *Audit Materiality* issued in January, 1997. This SA deals with the auditor's responsibilities to evaluate the effect of misstatements identified during the audit or uncorrected misstatements, if any, on the financial statements and its link with SA 320, which deals with the auditor's responsibilities to apply the concept of materiality in planning and performing an audit of financial statements. This Standard is effective for audits of all financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010.

Exposure Drafts

The Board also issued the Exposure Drafts of the following Standards on Auditing (SAs) under the Clarity Project for public comments:-

- Revised SA 700, "Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements"
- SA 705, "Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report"
- SA 706, "Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor's Report"

5.3.2 Other Technical Literature

The Board issued the following other technical literature during the year:

- ***Handbook of Auditing Pronouncements (2008 Edition)***
 - Two volumes – I and II
 - Volume I: All Quality Control and Engagement Standards in force as on April 1, 2008.
 - Also includes text of all revised/ new Standards issued under AASB Clarity Project till April 1, 2008.
 - Text of Revised Preface as well as Framework for Assurance Engagements.
 - Text of Statement on Reporting under Section 227(1A) of the Companies Act, 1956 and Statement on CARO 2003.
 - Text of General Clarifications to Standards.
 - Volume II: Text of 32 generic guidance notes on auditing in force as on April 1, 2008.
 - CD of the entire Handbook.
- ***Guidance Note on Audit of Banks-Revised 2009 edition***
 - Thoroughly revised taking impact of all relevant circulars issued by the RBI.
 - Totally been re-written to include the impact of the two risk based Standards, i.e., SA 315 and SA 330.
 - Detailed guidance on the New Capital Adequacy Framework, i.e., Basel-II.
 - Separate chapters on:
 - Special features of bank treasury operations
 - Foreign exchange and derivative transactions
 - Disclosure requirements in financial statements
 - CD of important RBI circulars.
- ***Implementation Guide to SQC 1***
 - Set of illustrative policies that an audit firm may adopt, with or without modification.
 - Annexures provide the illustrative forms, checklists and templates
- ***Implementation Guide to Risk-based Audit of Financial Statements***
 - Explains the basic requirements of the two risk based Standards SA 315 and SA 330
 - Practical and a case study based approach to explain SAs
 - Also discusses the implications of Revised SA 240, "The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements" and Revised SA 300, "Planning an Audit of Financial Statements" on carrying out risk-based audits.
- ***Background Material for Training Programmes***
 - Contains extensive but simple reading material on auditing standards.
 - Divided into five parts:
 - The first part, *Introduction*, gives a brief insight to the readers in to the history and nature of auditing/, importance of auditing standards, framework for assurance engagements, etc.
 - The second part, *Presentations*, contain snap shots of the fundamental principles contained in the Auditing and Assurance Standards along with some notes.
 - The third part of the Background Material contains possible documentation requirements culled out from the various AASs.
 - The fourth part of the Background Material contains case studies and technical posers.
 - The fifth part contains the text of the new Standards on Auditing which have become effective this year.

➤ ***A Study on Basel II and Risk-based Supervision***

- Explains significant principles of the Basel II Framework using graphs, tables and diagrammatic representations.
- Divided into five chapters:
 - An Overview
 - The Three Pillar Structure
 - Credit Risk
 - Operational Risk
 - Implementation of Basel II
 - Implementation approach explained in simplified manner through an Illustrative Standard Framework

➤ ***Technical Guide on Audit in Telecom Industry-Revenue, Fixed Assets and Related Operating Costs***

- Regulatory framework for telecom companies
- Audit approach and procedures for:
 - risk assessment,
 - revenues and receivables
 - fixed assets, etc.
- Extensive glossary of terms
- Appendix - guidelines for obtaining licenses for various telecom services, Adjusted Gross Revenue Computation Sheet and Format of Auditor's Report.

➤ ***Technical Guide on E-Commerce- Considerations for Audit of Financial Statements***

- Commercial activities using connected computers over a public network, such as the internet.
- Assessing effect of e-commerce on the auditor's assessment of the risk for the purpose of forming an opinion on the financial statements.
- Specific matters to consider
- Application of relevant Standards on Auditing (SAs) while performing audit in an e-commerce environment.
- Appendix - Glossary of Terms peculiar to e-commerce environment and text of 'The Information Technology Act, 2000'.

➤ **Projects under progress**

In addition to these, the Board has, during the year also undertaken several other projects and has made significant progress in the some of the projects.

5.3.3 Other Initiatives and Development

➤ ***Interaction with Regulatory Bodies***

The Board periodically interacts with the regulators and other Government institutions such as, Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Ministry of Corporate Affairs (MCA), Insurance Regulatory Development Authority (IRDA) Comptroller and Auditor General of India (C&AG), etc., to cull out the auditing issues.

➤ ***Contribution to the IAASB Activities and Responding to International Developments***

Since the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is a founder member of the International Federation of Accountants (IFAC), the AASB interacts with the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) at various levels. In April 2009, the representatives of the Institute attended the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) National Standard Setters (NSS) meeting at Vancouver and presented their views. The representatives apprised the developments made in India with respect to convergence with the International Standards and the challenges faced in the process.

➤ **Creating Awareness and Capacity Building**

Creating awareness amongst the members on auditing standards is one of the main agenda for the Board during the year 2008-09. In this process, the Board has organized three Conclaves of Auditing Professional at New Delhi, Pune and Kanpur. The topics discussed in these conclaves includes such as, Convergence of Indian Auditing and Assurance Standards with International Auditing Standards, Risk Based Audits- Recent Trends, and how to improve the quality of the firms including implementation of Standard on Quality Control (SQC) 1 within the firm. Further, in order to create awareness, the Board is also planning to revise its existing two publications, "What is an Audit- Understanding an Audit of Financial Statements" and "Background Material on Auditing and Assurance Standards".

➤ **Future Strategy and Work Program**

As the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) has already completed its Clarity Project in March, 2009, the Board will also try to complete its convergence process by April 1, 2010. For this purpose, the Board has already constituted the study group for the Standards on Auditing corresponding to the ISAs issued by IAASB under the Clarity Project, which are yet to be issued by the Board. In addition to this, the Board has also chalked out a detailed timetable for completing the Clarity Project within the timeframe. A Reconciliation of the ISAs issued by the IAASB and Standards issued by the AASB till date has been given hereunder to this report. Further, in setting its Agenda for the next year, the Board will also prepare strategy for creating awareness about auditing standards in India amongst the members. For this purpose, the Board has decided to issue the Implementation Guide to the Standards on Auditing issued under the Clarity Project.

5.4 Research

The Research Committee is one of the oldest Technical Committees of the Institute. The Committee publishes Guidance Notes, Technical Guides, Studies, Monographs, etc., on generally accepted accounting and/or auditing principles and practices designed to enhance the value of the services rendered by the profession. It undertakes approved research projects on current and continuous basis in various areas barring those covered by the functions of any other Committee of the Institute. Through its Sub-Committee, the Shield Panel, the Research Committee conducts the prestigious annual competition for the 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting', with a view to improve the presentation of financial statements.

5.4.1 Achievements of the Committee

During the period, the Committee released the following publications:

Technical Guide on Accounting for Microfinance Institutions

Microfinance sector is a growing industry with many Micro Finance Institutions (MFIs) operating in the country. The publication primarily provides an accounting and financial reporting framework for the presentation of true and fair view of the state of affairs and the operating results of the activities of MFIs in their financial statements. The publication also recommends the formats of financial statements for MFIs and the disclosures of relevant non-financial information therein. The preparers and the auditors of financial statements of MFIs would find this publication useful for addressing the accounting issues involved in the microfinance sector.

Technical Guide on Revenue Recognition for Software

This Technical Guide provides guidance to deal with industry-specific accounting issues relating to revenue recognition of software with a view to bring about establishment of sound accounting practices. Many of today's revenue generating contracts being entered into the software industry are complex and involve considerable uncertainty. A variety of revenue recognition principles are being followed in the Software Industry. The area requires considerable judgment. Recognising the need for establishing uniform and sound accounting practices for revenue recognition of various types of

contracts entered into the Software Industry, the Committee brought out this 'Technical Guide on Revenue Recognition for Software'.

Technical Guide on Share Valuation

The Committee has revised its existing publication titled 'Study on Share Valuation' (Second Edition 1994) in view of developments subsequent to the last edition. The revised publication is titled as 'Technical Guide on Share Valuation'. This publication deals with approaches, rules and principles in share valuation as laid down by law, the statutory guidelines, and the decisions of courts as well as established valuation practices. The Guide concentrates on the practical aspects used by experts for valuing shares. It aims to provide guidance on contemporary issues involved in share valuation.

Technical Guide on Estimation of Future Cash Flows and Discount Rates for the purposes of AS 28, Impairment of Assets

This Technical Guide contains practical implementation guidance for applying the principles of Accounting Standard (AS) 28, 'Impairment of Assets'. The standard ensures that the assets of an enterprise are carried at no more than their recoverable amount. For determination of the recoverable amount of an asset, measurement of 'value in use' is required under AS 28. AS 28 lays down the principles for the measurement of 'value in use' which in turn requires estimation of cash flows and the appropriate discount rates. It was being felt that there are many aspects as regards the measurement of 'value in use' in respect of which guidance is required. Therefore, the Research Committee of the Institute formulated this Technical Guide to deal with such aspects.

5.4.2 Important Projects in Progress

Apart from the projects completed during the year, certain other projects of the Committee are in progress. The Committee has taken up the task of issuing guidance on in the emerging areas such as Accounting for SEZ Development Activities, Accounting in Not-for-Profit Organisations (NPOs)/Non-Governmental Organisations' and Revenue Recognition for Telecommunication Companies. Due to developments in Oil and Gas Industry and amendments in laws, there is a need to revise the existing Guidance Note on Accounting in Oil & Gas Industry. Accordingly, the Committee has also undertaken the project of revision of the Guidance Note. The Committee has also decided to publish the common discrepancies found by it in the evaluation of the Annual Reports and publish those discrepancies in the form of study with a view to apprise the members of the Institute and others concerned about the major non-compliance observed during the review.

5.4.3 ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting

The ICAI, through its Research Committee, has been holding an annual competition for the 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting'. The objective of this competition is to recognise and encourage excellence in the preparation and presentation of financial information with the mission of greater accountability and well-informed decision making. The competition propagates that financial reporting should be committed to the canons of accountability, transparency, integrity, reliability, timeliness and social responsibility. The Competition for the year 2007-08 was held under seven categories based on the functional classification of various industries.

For 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' for the year 2007-08, the Panel of Judges meticulously considered the financial and other information contained in the Annual Reports and Accounts of these enterprises. The Panel this year introduced a new award, i.e., Hall of Fame Award. It decided to give this award to an entity that has been awarded the first prize under the same category continuously in the last five years. A total of thirty awards - one Hall of Fame, seven Gold Shields, eight Silver Shields and fourteen Plaques were distributed at the function as detailed hereunder:

Category		Award	Name of the Entity	Annual Report and Accounts for the year ended
I	Manufacturing and Trading enterprises (including Processing, Mining, Plantations, Oil and Gas enterprises)	Gold Shield	Dr. Reddy's Laboratories Limited	March 31, 2008
		Silver Shield	Tata BP Solar India Limited	March 31, 2008
		Plaque for Commended Annual Report	1. Caim India Limited	December 31, 2007
			2. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited	December 31, 2007
			ITC Limited	March 31, 2008
			3. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited	March 31, 2008
			4. Steel Authority of India Limited	March 31, 2008
II	Banking and Financial Institutions (including NBFCs, Mutual Funds, Unit Trust of India, Investment Bankers, HFCs, etc.)	Gold Shield	ICICI Bank Limited	March 31, 2008
		Silver Shield	1. SBI Capital Markets Limited	March 31, 2008
			2. Shriram Transport Finance Company Limited	March 31, 2008
		Plaque for Commended Annual Report	1. Capital Local Area Bank Limited	March 31, 2008
			2. GRUH Finance Limited	March 31, 2008
			3. Union Bank of India	March 31, 2008
III	Service Sector (including Consultancy, Transport, Stock Exchanges, R&D, Private Hospitals)	Gold Shield	Bombay Stock Exchange Limited	March 31, 2008
		Plaque for Commended Annual Report	KIMS Healthcare Management Limited	March 31, 2008
IV	Insurance Sector	Gold Shield	ICICI Prudential Life Insurance Limited	March 31, 2008
		Silver Shield	ICICI Lombard General Insurance Company Limited	March 31, 2008
V	Information Technology, Communication and Entertainment enterprises	Hall of Fame	Infosys Technologies Limited	March 31, 2008
		Gold Shield	Nucleus Software Exports Limited	March 31, 2008
		Silver Shield	1. Mphasis Limited	March 31, 2008
			2. OnMobile Global Limited	March 31, 2008
		Plaque for Commended Annual Report	1. Persistent Systems Limited	March 31, 2008
			2. Shree Ashtavinayak Cine Vision Limited	March 31, 2008
VI	Infrastructure & Construction Sector (including Power Generation and Supply, Port Trusts, Metro, Roads)	Gold Shield	The Tata Power Company Limited	March 31, 2008
		Silver Shield	NTPC Limited	March 31, 2008
		Plaque for Commended Annual Report	1. Larsen & Toubro Limited	March 31, 2008
			2. Puravankara Projects Limited	March 31, 2008
VII	Others (Section 25 companies, Educational Institutions, Charitable hospitals and other organisations)	Gold Shield	Vidya Dairy	March 31, 2008
		Silver Shield	Swami Vivekananda Youth Movement	March 31, 2008
		Plaque for Commended Annual Report	Financial Management Service Foundation	March 31, 2008

The awardees of the Competition 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' for the year 2007-08 were felicitated at an award function of 'ICAI Awards' organised at Goregaon Sports Club, Mumbai. Hon'ble Shri Ram Naik, Ex-Minister of Petroleum and Natural Gas, was the chief guest at the function. The function was attended by the senior government officials, celebrities, industrialists, chief executives of large public and private enterprises.

5.4.4 Invitation for Research Proposals

Research Committee invites application for Research Projects from members and others for carrying out research in the field of accounting and other affiliated fields for e.g. accounting for chain departmental stores, accounting in health care industry, accounting for electricity generation and distribution companies, accounting in aviation industry, accounting for shipping companies, management control systems, approaches to social cost-benefits analysis in the Indian context, etc.

5.5 Corporate Laws Committee

5.5.1 Schedule VI and prescribing of Saral Schedule VI for small and medium sized companies.

5.5.2 Views and Suggestions on:

- a) Norms on Managerial Remuneration,
- b) Compulsory appointment of Chief Financial Officer in Companies beyond a particular size,
- c) Revision of Schedule XIV of Companies Act,
- d) Functioning of the offices of the Registrar of Companies, study on various aspects of Company Law practices.
- e) Background Material on Valuation
- f) Companies Bill, 2008
- g) Revised Valuation Professionals Bill
- h) LLP Concept Rules

5.5.3 Corporate Affairs Standards on:

- a) Certification under MCA 21
- b) Auditors Appointment, Retirement and Removal
- c) Business Valuation

5.5.4 Conducted the First Batch of Certificate Course on Valuation:

As per the opportunity available under the new Companies Bill 2008 and also with the proposed adaptation of Indian GAAP with IFRS, the Council decided to launch a Certificate Course on Valuation as technical empowerment exercise for the professionals. Accordingly the Committee designed the course curriculum and other modalities of the course and conducted the course at the following locations:

- a) Delhi
- b) Mumbai
- c) Chennai
- d) Kolkata

5.5.5 Conjecture on:

- (a) Knowledge & Procedures Related to Accounting in Liquidation has been prepared and commend the Training Programme for the staff/officals of Office of Official Liquidator, Delhi.
- (b) Training Programme on Valuation for the officials of the Department of Disinvestment, Ministry of Finance.

- (c) The Classes for the Second Batch of the Certificate Course on Valuation at Delhi and Mumbai have been started.

5.5.6 The Classes for the Second Batch of the Certificate Course on Valuation at Delhi and Mumbai have been started.

5.6 Financial Markets and Investors' Protection

The recent financial crisis which swamped all across the world left a deep impact on the markets and investors. Policy makers are devising strategies to restore financial stability and lay ground work for new growth. Despite the global slowdown, the Indian Capital Market is presently riding on positive sentiments. The new Government after the recent elections is conscious of the fact that all round steps have to be taken to put the economy on the track for which action plan is on the anvil. FI's and FII's are watching with interest the stimulus packages and reforms that the government will be offering to the corporate, thereby there is a considerable scope for more investments to flow into the country. On the other hand, recent corporate scandal in the country raised concern regarding the credibility of investor protection and their rights. On the one hand, the market is on a new trajectory path, the investors are watching with subdued optimism. It is therefore a situation of paradigm and paradox for the market as a whole.

Taking a holistic view of the scenario, the Committee evolved a comprehensive action plan envisaging proactive steps highlighting the role and responsibilities of members in the field of capital markets. Simultaneously the Institute as partner in nation building, it is focused on bringing public awareness for empowerment in Investor Education and Protection for which new projects, programmes and publications were chalked out.

PROJECTS

- Introspection on Market Debacles (Early 2008) – A Presentation - The Committee prepared a presentation highlighting the sources and causes of the problem along with the sensitivities where problem lies for consideration by the Ministry of Corporate Affairs.
- Insights on Initial Public Offerings (IPO) – A Research Study - The Ministry of Corporate Affairs mandated the Institute to come out with a Report on the IPO's after the market debacles in the year 2008. A group was formed for the purpose and a summary report was prepared.
- Inculcating Awareness amongst investors—All India Network Project - The Committee under the aegis of Investor Education Protection Fund of the Ministry of Corporate Affairs drew up an elaborate exercise of organizing 50 investor awareness programmes throughout the country during the months of November, December 2008 and in January, 2009.
- Issues related to investor protection—A 13/26 TV Episodes Mass Media Production - The exercise of producing serials on issues relating to investor protection is still under discussion.
- Interface with Regulatory Authorities – SEBI & MCA – Submissions/Suggestions on Policy/Discussion Papers - The Committee participated in various meetings of the SEBI Advisory Committee on Mutual Funds and in SEBI Committee on Standards and Disclosures.

Programmes

- Diamond Jubilee Conference - As a part of Diamond Jubilee Celebrations of the Institute, a Diamond Jubilee National Conference on Financial markets was held on 16th July, 2008 at Ernakulam, attended by 450 members.
- All India Conference on Capital Market – The Road Ahead – Kolkata - A National Conference on Capital Market was held on 19th July, 2008 at Kolkata. This mega conference was attended by around 500 members and eminent national/international experts in the field of capital markets addressed on various topics.
- Workshops on Private Equity - Taking into account the emerging trends in the capital market and professional opportunities for members, the Committee organized two day workshops on the subject at Manesar, near Gurgaon on 5th & 6th April, 2008 attended by 50 members; at

Mumbai on 1st and 2nd August 2008 which was the largest ever conducted programme in the country attended by over 450 persons. Another workshop was held at Chandigarh on 5th and 6th September, 2008 with attendance of 70 persons.

- All India Conference - A National Conference on Capital Market was held on 13th September, 2008 at New Delhi. This conference was attended by 100 members and eminent experts in the field of capital markets who addressed on various topics. The event was organised in association with NIRC of ICAI and Association of National Members of India (ANMI).
- ICAI-ET joint programme on "Sensex ni Sangathe - A joint programme on "Sensex ni Sangathe" (in tune with Sensex) was held on 23rd October, 2008 at Mumbai. This conference was attended by members and eminent experts in the field of capital markets who addressed on various topics. Around 800 members were present.
- Chain Seminars on Currency Futures - With the SEBI permitting trading in currency futures from 29th August, 2008, the MCX SX, ICAI and FEDAI organised a half-day awareness programme on trading through currency futures at various places in the country. Programmes were held at New Delhi, Kolkata, Chennai, Jaipur, Ahmedabad, Indore, Bangalore, Hyderabad, Coimbatore, Cochin and Mumbai during the month of September, 2008
- All India Investor Awareness Programmes - Under the aegis of the Investor Education and Protection Fund of the Ministry of Corporate Affairs of the Government of India, the Institute had organized investor awareness programmes at 50 places during the year 2008-09.
- Certificate Courses - Forex and Treasury Management & Derivatives - The Committee conducted the 1st Batch of the above courses at Mumbai and New Delhi respectively. The Committee is now further proposing to extend these courses to other metros and new batches are likely to start shortly.
- CPE Teleconferencing on Capital Market Reforms - The Committee on Capital Markets and Investors' Protection participated in Teleconferencing on the subject Capital Market Reforms held on 13th September, 2008 organized by the CPE.
- Conferences /Workshops on Emerging Trends in the field of Financial Markets - A joint two days conference was held on 24th & 25th April 2009 at Amritsar hosted by the Amritsar Branch of NIRC. The conference was a value addition to the members in terms of knowing more about the professional opportunities in the field of capital market.
- One day CPE programme on Capital Market at Chennai - The Committee conducted one day CPE programme on Capital Market in Chennai on 28th May, 2009. This conference was attended by 850 members and eminent experts in the field of capital markets who addressed on various topics.

Publication

- Revision of the existing Guidance Note on Certification of Corporate Governance (As stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement) - The revised Guidance Note 2009 was published.
- Literature Materials - The Committee prepared two comprehensive literature materials on Private Equity & IPO and the same were circulated in the various seminars and conferences conducted.
- Committee Glimpses - The Committee came out with its PR kit for the Year 2008-09. It reflects Committee achievements, its past, present and future.

5.7 Expert Opinions

The objective of financial statements is to provide information about the reporting entity's financial performance and financial position that is useful to a wide range of users for ascertaining stewardship of entity's management and for making economic decisions. In order to achieve this objective, financial statements must be transparent, consistent, comprehensive, comparable and reflect the underlying economic reality of the entity and the transactions it undertakes. The Expert Advisory Committee (EAC) contributes to this objective by solving the various difficulties faced by the members of the Institute in the interpretation, implementation and understanding of generally accepted accounting principles while preparing and presenting the financial statements and while reconciling the views of auditors, management, various stakeholders and authorities.

The Committee replies to the queries received in accordance with the Advisory Service Rules framed for this purpose. As per the Rules, the Committee deals with queries relating to accounting and/or auditing principles and allied matters and as a general rule does not answer queries which involve purely legal interpretation of various enactments and matters involving professional misconduct. The Advisory Service Rules can be accessed from the website of the Institute or can be obtained from the Institute's Head Office at New Delhi. It may also be noted that although the Committee has been appointed by the Council, an opinion given or a view expressed by the Committee represents the opinion or the view of the members of the EAC and not the official opinion of the Council of the Institute.

During the period from 01.04.2008 to 31.05.2009, the Committee finalised 60 opinions on wide ranging issues, like accounting for deferred taxes, employee benefit schemes, foreign exchange differences, borrowing costs, valuation of material-in-transit, treatment of expenditure during construction period, etc. The Committee also considered and finalised six opinions on different accounting issues received from the Regulators/ Government authorities. During the period, a joint programme, namely, "Diamond Jubilee National Workshop on Emerging Paradigm for Accounting Professionals" was organised by the Expert Advisory Committee and Committee on Trade Laws and WTO which was hosted by the Lucknow Branch of CIRC of the ICAI, on 24th October, 2008 at Lucknow. The Workshop was inaugurated and addressed by Hon'ble Shri Satish Chandra Mishra, Chairman, UP State Advisory Council and Member, Rajya Sabha. Hon'ble Shri Naresh Agarwal, Former Minister, Govt. of UP, also addressed the audience at the said Programme. The workshop was attended by about 450 members. An Information Brochure of the Committee was also released at the above-said programme. The brochure was sent to about 14,500 enterprises which includes various sectors such as, manufacturing, banking and finance, PSUs, trading, service, IT companies and communications, construction, electricity, insurance, educational institutions, NGOs, port-trusts and chambers of commerce and industry.

The opinions finalised during a year are published as a Compendium of Opinions. With the issuance of the 25th volume of the Compendium during the year, the Compendium of opinions containing opinions finalised by the EAC upto January 2006 has been released for sale. A CD containing all the opinions contained in all the twenty-five volumes of Compendium of Opinions with user-friendly features for easy referencing was also released during the period. It is believed that the CD would be a strong knowledge resource for the profession. The next volumes of the Compendium in the series, containing opinions given by EAC between February 2006 and January 2009, are under compilation and are likely to be released for sale shortly. The Committee also publishes some of the opinions finalised by it in every issue of the Institute's Journal 'The Chartered Accountant'. Recent opinions of the Committee are also available on the website of the Institute.

5.8 Continuing Professional Education

5.8.1 Overview

CPE serves as a means for professionals to maintain and develop their knowledge, skill and competence. Needless to state, the ICAI has always striven for excellence in the standard of professional services rendered by its members and the CPE Committee of the ICAI has continually been taking every possible initiatives to assist the members in maintaining that standard. The Committee adopted several measures to ensure that the members of the ICAI remain continuously updated with respect to developments in existing and emerging disciplines and subject specific areas directly or indirectly related to the profession of Chartered Accountancy and to help impart necessary skills to the members so that knowledge thus garnered by them gets translated into practice.

To enable all the members maintain the expected level of competence in order to improve their performance in their current role, taken new roles, improve career prospects with current employees or in current practice and to support career progression in new employers or to different practices, the requirements of CPE credit hours have been made mandatory for all members irrespective of age or

category (i.e., with COP/ without COP) and CPE credit requirements for members of the ICAI from the calendar year 2008 stood as follows:

- All the members who are holding Certificate of Practice (except those members who are residing abroad), unless exempted, are required to:
 - Complete at least 90 CPE credit hours in each rolling three-year period of which 60 CPE credit hours should be of structured learning.
 - Complete minimum 20 CPE credit hours of structured learning in each year.
- All the members who are not holding Certificate of Practice or are residing abroad (whether holding Certificate of Practice or not), unless exempted, are required to:
 - Complete at least 45 CPE credit hours of structured/unstructured learning in each rolling three-year period
 - Complete minimum 10 CPE credit hours of structured/unstructured learning in each year.
- All the members (above 60 years of age) who are holding Certificate of Practice, unless exempted, are required to:
 - Complete at least 70 CPE credit hours (structured/unstructured) in each rolling three-year period.
 - Complete minimum 10 CPE credit hours of structured/ unstructured in the first year i.e. 2008
 - Complete minimum 20 CPE credit hours of structured/ unstructured in the second and third year i.e. 2009 & 2010.
- All the members (above 60 years of age) who are not holding Certificate of Practice, unless exempted, are required to:
 - Complete at least 35 CPE credit hours (structured/unstructured) in each rolling three-year period.
 - Complete minimum 5 CPE credit hours of structured/ unstructured in the first year i.e. 2008
 - Complete minimum 10 CPE credit hours of structured/ unstructured in the second and third year i.e. 2009 & 2010.

To avail CPE hours for undergoing unstructured learning activities during any calendar year, the members are required to submit a self-declaration form latest by 31st May of the following year to the concerned decentralized office at whose jurisdiction his/her membership falls.

5.8.2 Tele-conferencing Programmes:

Since long, teleconferencing remained one of the cost effective modes to disseminate knowledge. Now a days, the Committee holds one or two such events on topics related and relevant to Chartered Accountancy Profession in collaboration with the Indira Gandhi National Open University (IGNOU), Delhi. The topics so far covered are: Auditing and Assurance Standards, Recent Changes in TDS Provisions, Company Audit, Convergence of Indian Accounting Standards with IFRS, Tax Audit, Recent Developments in Capital Markets, Recent Developments in Service Tax, Information Technology, Peer Review, Insurance & Pension, Wealth Management and Investment Strategies, Statutory Bank Audit, Corporate Governance, Capital Gains & Survey, Search & Seizure, Set off and carry forward losses under the IT act-Practical issues & Appeal procedures before the CIT (Appeals) & ITAT, Legal Compliance aspects relating to Non-Profit Organizations with Special Reference to I.T Act and F.C. R. Act” and “ Art of Preparation of Project Reports with Reference to availing term loan and working Capital.

Taking into consideration the overwhelming responses that have continually been received from the members, the CPE Committee has started making CDs of the Teleconferencing Programmes. The

members could get these CDs on payment of Rs. 50 per unit and by viewing these CDs, members could also claim 2 hours (unstructured) CPE Credit.

5.8.3 E-learning initiative:

The Committee had expanded its wing towards spreading knowledge through E-learning mode and during this year two projects were taken up namely, service tax and IFRS. E-learning course on service-tax was introduced in November 2008 and nearly 50,000 members have so far taken benefit of that facility. Since, 1st April, 2009 onwards all E-learning courses are being conducted by the I.T. Committee of ICAI since that area closely fits into its functional pattern.

5.8.4 In-house Executive Development Programme:

The Committee is committed to impart quality education with a view to hone the skills of officials of and cater to the needs of the business houses on areas of their interest at affordable cost. The Committee conducts about 4 to 5 such events every month at various organizations across the country on topics of contemporary relevance and on IFRS in particular. More than 2000 officials took benefit of such courses to upgrade their knowledge, during the year.

5.8.5 CPE Portal

The Committee took initiative to revamp the portal that was in existence and being maintained by an outsourced agency. To make the system more flexible and user-friendly, that portal is presently being monitored and managed by inhouse officials and members can view their yearly structured/unstructured credit hours, with all associated details and even get the desired output printed with least effort.

5.8.6 Monitoring mechanism of Programme Organising Units (POUs) strengthened:

In order to streamline the functional pattern of POUs as well as proper monitoring of events organized by them and timely updation of attendance, a practice of monthly information system has been introduced. That in turn would facilitate improvement in quality of education imparted and content of the background material developed.

5.8.7 Unstructured Learning Activities (ULA):

As stated elsewhere, members of certain category could avail the benefit of ULA also and following are the areas covered in the Advisory issued in that effect:

- Web-based learning modules (e-learning)
- *e-learning is "instructional content or learning experiences delivered or enabled by electronic technology". Electronic technology encompasses everything from Computer-Based Training (CBT), to compact disks (CDs), to Web-based applications."*
- Self-learning modules and courses (use of audiotapes, videotapes, correspondence courses, computer based learning programmes)
- Reading and individual home study
- Reading and Individual Home Study may constitute reading articles in the Journal, 'The Chartered Accountant' of the Institute, reading technical, professional, financial or business literature
- Group or bilateral discussion on technical issues
- Acting as visiting faculty or guest faculty at the various Universities/ Management Institutions / Institutions of National Importance
- Participation in CPE Teleconferencing Programmes without the supervision of the POU
- Providing solutions to questionnaires / puzzles available on Web/ Professional Journals
- Internal Training Programmes being organised by firms of Chartered Accountants having seven or more partners

The last date for submission of self-declaration form towards availing ULA mode for the calendar year 2008 was 31st May 2009 and response from members remained overwhelming to avoid any default on their part.

5.8.8 CPE Calendar:

As a matter of practice, a list of indicative topics under different broad heads is prepared at the beginning of every financial year and that facilitates maintaining uniformity in coverage and content while holding events at various places across the country. However, these topics are obligatory and to make the list reasonably exhaustive, certain optional topics are separately added to it. The obligatory topics for the year 2009-2010 include the following:

Accounting and Auditing

- 1.. Accounting Standards issued by ICAI
2. Audit, Assurance and Quality Standards issued by ICAI
3. Implementing the Accounting Standards in various Sectors/Industries (Banking Sector, Real Estate Sector, Insurance Industry etc.): Technical & Managerial Issues
4. Implementation issues in Auditing Standards, Expectations, and compliance requirements in general in various sectors/Industries (Banking Sector, Real Estate Sector, Insurance Industry etc.)
5. Pronouncements and other documents of ICAI on Accounting and Auditing
6. Accounting Standards with Sector-wise / Industry-wise practical presentations
7. US & UK GAAPs
8. Internal Audit Standards
9. Peer Review – Systems, Procedure and Documentation for Practice Units
10. Technical Standards under Quality Review
11. Sarbanes Oxley Act
12. Implications of Sarbanes Oxley Act on the Internal Audit
13. Accounting of the Urban Local Bodies
14. Accounts of Co-operative Societies
15. Audit of Small Entities
16. Forensic Accounting and Audit
17. Internal Audit - including Risk Based Internal Audit
18. Internal Audit and Fraud Risk
19. Internal Control – including Risk Based Perspective
20. Providing Assurance on Internal Controls
21. Service Tax Audit
22. VAT Audit
23. Issues related to Non-corporate Enterprises and their Auditors
24. Clause 49 & Role of Internal Audit
25. Compliance Aspects of Accounting Standards and other Reporting and Disclosure Requirements
26. Compliance Aspects of Generally Accepted Accounting Principles in the Preparation and Presentation of Financial Statements
27. Compliance aspects of AAS and other mandatory guidelines issued by ICAI
28. Relationship of Internal Auditor with those charged with Governance
29. Professional Code of Conduct and Business Ethics
30. Sustainability Reporting

Cost & Financial Management

31. Balanced Scorecard
32. Business Process Improvements
33. Capital Budgeting under Globalised Business Environment
34. Financial Forecasting
35. Cost Management
36. Financial Due-Diligence

37. Financial Instruments
38. Financial Modeling
39. Issues in Cross Border Investments
40. Corporate Financial Reporting
41. Restatements of Financial Statements under US GAAPs and IASs

Information Technology

42. Practical Workshop on:
 - a. IS Audit of Banks/ Banking Application
 - b. Using CAAT's/ General Audit Software
 - c. IS Audit of Stock Broker CTCL Facility
 - d. MS-Excel - Tool for Audit
 - e. Network Security Audit/ Review
 - f. Windows XP Security Review
 - g. Windows 2000/ 2003 Security Review
 - h. MS-Excel – Tool for Financial Analysis/ Reporting
 - i. MS-Excel for Financial Management
 - j. Advanced Features & Facilities of MS-Excel
 - k. Data Extraction/ Analysis for Accounting/ Financial Requirements
 - l. Reporting/ Documentation Using MS-Word
 - m. IS Audit/ Review of Core Banking Applications (CBA)
 - n. Information System Audit
43. XBRL Financial Reporting Language
44. Certification of Internal Controls – Clause 49/ Sarbanes Oxley Act
45. Accounting Software Security Audit/ Review & Advanced Facilities/ Features
46. Digital Signatures & e-filing (Income Tax/ MCA21)
47. Understanding ERP (2 Days)
48. ERP Implementation/ Testing/ Maintenance (8/21 Days)
49. Information Technology Act
50. Emerging IT Challenges & Opportunities
51. Emerging Opportunities in BPO/ KPO Sunrise Sectors
52. IT Best Practices – A Review
53. Computer Assisted Performance Evaluation
54. E-Commerce / E-Governance
55. Management Information Systems (MIS)
56. Technology Management
57. Information Systems- Security and Control
58. Internal Audit – Coping with Emerging IT Risks

Taxation

59. Audit under Income Tax Act – Preparation, Presentation and Documentation
60. Depreciation: Accounting, Taxation and Company Law issues
61. Accounting Standards vis-à-vis Taxation
62. Emerging Issues in Indirect Taxation
63. Issues in Business Taxation
64. Issues in International Taxation (including NRI Taxation, DTAA, Transfer Pricing & Taxation in Foreign Countries)
65. Foreign Payments – TDS u/s 195 of the Income Tax Act, 1961
66. Tax Tribunals including National Tax Tribunal – Role of Chartered Accountants
67. Recent Judgment/Judgments on Direct Tax Laws
68. Service Tax – Law and Practice
69. Taxation of Non-Resident Indians – Recent Developments
70. Stay, Tax Recovery and other Related Provisions under the Tax Laws
71. Transfer Pricing
72. Corporate Taxation
73. Fringe Benefit Tax (FBT)

74. Value Added Tax (VAT) – Including State Level VAT
75. Survey, Search and Seizure – Current Developments
76. Desk Review
77. Export Import Trade / Customs Valuation Law – Rules & Compliances
78. Central Sales Tax (CST)
79. Tax Havens
80. Tax Audit u/s 44AB
81. Assessment Procedures
82. Income Tax Assessment
83. Preparation & presentation of Appeals before the CIT & ITAT
84. Reforms of Indian Tax System in the context of GST

Business Management

85. Conflict Management
86. Consumer and Organizational Buying Behavior
87. Contract Management – Practical Issues
88. Competitiveness: Concepts and Challenges
89. Commercial Due Diligence
90. Credit Analysis and Credit Management
91. Evaluation of Supplier Strategy: Valuation Framework
92. Management of Change
93. Managing Creativity
94. Managing Employee Redundancy
95. Implementing ABC in Manufacturing Environment
96. Industrial Relations
97. Value Based Management
98. Total Quality Management
99. Strategic Decision – Making
100. Sustainability Development
101. Motivation Techniques
102. Narrative Reporting
103. Knowledge Management
104. Operations Planning and Control
105. Just-in-time approach (JIT)
106. Performance Management
107. Effective Time Management
108. Quality Audits
109. Value Added Business Controls – The Right Way to Manage Risk
110. Management Audit
111. Decision Making Under Conditions of Risk and Uncertainty
112. Cost Reduction and Cost Control
113. Cost reduction techniques in Resource Mobilization
114. Business Ethics
115. Principles and Topics in Corporate Communications
116. Business Presentations and Audience Analysis
117. Business Sustainability

Corporate Laws

118. Schedule – VI
119. E-forms under MCA – 21
120. Arbitration Act, 1996
121. Valuation Techniques
122. Mergers and Amalgamations
123. Companies (Auditors' Report) Order (CARO)
124. Auditors' Report under the Companies Act – Issues on CARO, Documentation, Reporting and Disclosure Requirements
125. NCLT Law and Practice

126. MCA-21 – Challenges & Opportunities for the Profession
127. Limited Liability Partnership Act 2008
128. EXIM Policy and Procedures
129. Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006
130. Competition Act and Merger and Acquisition

Code of Conduct

131. Code of Ethics of ICAI and relevant emerging issues

Financial and Capital Market

132. Derivatives: Futures and Options
133. Derivatives – Accounting and Taxation
134. OTC Derivatives – A Legal Perspective
135. Sources of Raising Funds
136. Recent Trends in Finance and Capital Market
137. International Finance
138. Role of International Funding Institutes
139. Foreign Direct Investment (FDI) Rules
140. Project Report and Appraisal
141. Project Financing
142. FOREX Management
143. Listing Agreement

Corporate Governance

144. Audit Committee Charter
145. Audit Committee and Independent Directors
146. COSO, COBIT & Enterprise Resource Planning (ERP)
147. Whistle Blower Policy – Framework
148. Enterprise Governance
149. Sustainable Development and Global Reporting Index (GRI)
150. Role of CAs in Corporate Governance
151. Corporate Governance Rating
152. Corporate Governance Audit
153. Global Warming/Climate Change
154. Corporate Social Responsibility (CSR)
155. Carbon Credit
156. Improve Board Effectiveness through Good Governance
157. Impact of Corporate Governance in Global Development
158. Green Business Practices

Insurance and Risk Management

159. Insurance Survey and Loss Assessment
160. Developments in Pension Fund
161. Anti Money Laundering in Insurance Sector
162. Risk Management
163. Valuation of Insurance Companies
164. Third Party Insurance
165. AS-15 and Actuarial Sciences
166. Product Pricing

Public Finance

167. Fiscal Policy and Economic Growth
168. Public Finance and Public Policy: Responsibilities and Limitations of Government
169. Taxation Perspective – A Democratic Approach – Public Finance in India
170. Public Debt and Economic Planning in India
171. Managing Public Fund – critical issues & implications
172. Public Debt in India

173. External Debt and Foreign Reserves
174. Budget – Process in India: Aids & Grants
175. The politics of Public Budgeting: Getting and spending – borrowing & balancing
176. Budget and Ballots in India – Participatory Budgeting from State to Centre
177. Fiscal Prudence and Challenges: A review of Centre and State Linkage
178. Effects of Public Expenditure
179. Indian Federal Finance
180. Taxation in Agriculture Sector
181. Railway Finance
182. Incidence and Effects of Taxation
183. Taxation Accountability and Realization
184. Public Sector Undertakings in India - A Paradigm Shift
185. International Funding Institutions: Role of International Funding Institutions/Changing Role and responsibilities
186. Money Laundering
187. Rural Banking - Growing relevance and Prospect
188. Economic growth in post – liberalization era
189. Delegation to Devolution – A comparative Review of Public Finance in India
190. Tax Governance – A middle income class agency
191. Economic resurgence of State in India: Capacity and Consent
192. Changes in Money Supply: Policy implications and relevance in the Current era

Soft Skills

193. Personality Development
194. Customer Relationship Management
195. Effective representation before Income Tax Authorities
196. Stress Management
197. Presentation and Communication Skills
198. Interpersonal Skills
199. Listening and Reading Skills
200. Personal Finance
201. Economic Slowdown & Financial Crisis

Others

202. Consultancy and Advisory Services
203. Business Advisory Services
204. Right to Information Act
205. Six Sigma
206. Fraud Investigation, Reporting and Prevention
207. Jurisprudence, Interpretation of Law and Evidences Act
208. Money Laundering Risk and Management – including Prevention
209. CA Amendment Act, 2006
210. Merger, Demerger & Networking of CA Firms and Capacity Building
211. Art of Drafting Conveyance Deeds

Other Initiatives of the CPE Committee

- With a view to help companies in implementing IFRS systematically and to meet the deadline of 1st April 2011, nearly half a dozen In-house Executive Development Programmes are being held every month and particularly in large PSUs.
- Organizing Programmes in core areas with special emphasis on Accounting Standards, Auditing Statements, Code of Conduct and Professional Ethics.
- To help members understand the purpose and prospect of mandatory CPE hours, a comprehensive manual in the form of FAQs would be brought out.
- Couples of contemporary publications on topics of today's interest would also be brought out under the banner of CPEC.

- To improve effectiveness of the teleconferencing programmes, CDs on topics taught are now being distributed to all POU's of ICAI.
- In order to make the existing CPE Statement internationally comparable, leading to real value addition through imparting quality education, revision of and amendment to certain of its clauses are contemplated.
- To help those members residing at remote places, approval for formation of various types of POU's such as CPE Chapters and Study Groups would be given.
- Organize training for trainers programmes for CPE resource persons in various regions across the country.

5.9 Professional Development Committee

An Introduction:

The Professional Development Committee was set up in the year 1962 as a non-standing Committee by the Institute of Chartered Accountants of India. The Professional Development Committee is one of the most vibrant Committees of the Institute which has always been making vigorous efforts towards exploring, and making available ample opportunities for the members of the Institute in different sectors of the economy. It determines the professional development needs and identifies issues and other areas, which can impact the profession. In order to achieve this, Committee has been striving to generate more professional opportunities for the members of the Institute by exploring/pursuing new/existing areas where the professional skills of the members could be utilized in a productive and fruitful manner. The Committee has also made considerable efforts to ensure that equitable opportunities are available to all members of the profession. Apart from exploring uncharted territories in the professional development, the Professional Development Committee strives to strengthen the communication process with multitude of users across the different sections of the society and educate them about the role of Chartered Accountants. With a view to enhance skill sets of Chartered Accountants in the existing and new areas, it also organizes seminars, workshops on contemporary areas of interest.

In order to achieve mission, Professional Development Committee took many path breaking initiatives during the year, like holding meeting with different officials in different government departments, regulatory bodies etc. Besides meeting, committee organized seminars and workshops with the objective of improving the skills of the members, keeping them abreast of the new rules & regulations and bringing members and regulators closer to each other.

The major achievements/endeavours of the Professional Development Committee in this reporting period are given below:

- The Multi Purpose Empanelment Form for the year 2009-10 was successfully hosted on website www.meficai.org alongwith a link for "Complaint Centre". This year, highest no. of applications have been received for empanelment in comparison to any other year, without any extension of last date.
- Meeting with the officials of the Ministry of Finance, Reserve Bank of India and Comptroller and Auditor General of India on issue relating to managerial autonomy in the appointment of statutory auditors.
- Meeting with the officials of the Reserve Bank of India on various matters of professional interest including issues relating to bank branch audit/allocation & allotment, issues related to NBFCs, etc.
- Meetings held with the officials of NABARD to discuss various issues of professional interest such as revision of audit fee for Statutory Auditors, training to the auditors and facilitating quality service delivery.
- Meeting with the Office of Comptroller and Auditor General of India on various issues of professional interest.
- A Joint Committee of National Housing Bank (NHB) and ICAI, has been constituted for cooperating and promoting the interest of the Housing Sector by organizing training workshops for Chartered Accountants.

- A Joint Committee of Indian Banks Association (IBA) and ICAI, has been constituted for examining the present position prevalent in various banks in the matter of scope, coverage and reporting requirements for various kinds of audit in vogue in banking sector.
- The Professional Development Committee Knowledge Portal www.pdicai.org continues to provide its services to the members with timely and essential information on practice development and new professional opportunities in different sectors to the members.
- The Portal for CA Networking and consolidation, which is available at the link www.canet.co.in continues with its initiatives to provide a platform to Chartered Accountants to network with the people who share similar ideas, goals and visions and who complement strengths of participants of the Network.
- Besides the above, meetings held with the following associations, authorities with the objective to explore more professional avenues and to focus on the untouched areas in the pre existing avenues.
 - Senior officials of Khadi and Village Industries Commission (KVIC), Mumbai in order to forecast the new domain for CAs.
 - Senior Officials of Central Bureau of Investigation, New Delhi
 - Officials of Bombay Stock Exchange
 - Officials of Forward Markets Commission
 - Executive Director (Finance & Accounts), Life Insurance Corporation of India
 - Senior officials of Financial Intelligence Unit – India
 - Member (Finance) and Senior Officials of National Highways Authority of India
 - Additional Director General of Investigation and Registration, Ministry of Corporate Affairs, Government of India.
 - Various officials of Enforcement Directorate, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India
 - Officials of Central Depository Services (India) Limited of India
 - Officials of Monopolistic and Restrictive Trade Practices Commission of India
 - Officials of Indian Renewable Energy Development Agency Limited
 - Financial Commissioner, Employees State Insurance Corporation
 - Chairman and Managing Director, Punjab & Sind Bank
 - Chairman and Managing Director, Allahabad bank
- As a result of great stride for ensuring equitable professional opportunities and to provide more and more tasks, following Authorities were provided the panels of Chartered Accountants/ firms.
 - The Pay & Accounts Office, Board of Radiation and Isotope Technology, Mumbai
 - The Registrar, Cooperative Societies, Government of Maharashtra
 - The Project Officer, District Rural Development Agency, Puducherry
 - The Assistant General Manager, Food Corporation of India, New Delhi
 - The National Commodity & Derivatives Exchange Limited
 - The Official Liquidator, High Court of Karnataka, Bangalore
 - The Assistant General Manager, Punjab & Sind Bank, New Delhi
 - The Chairman, Public Sector Restructuring and Internal Audit Board, Thiruvananthapuram
 - The Project Officer, Sarva Shiksha Abhiyan Warangal
 - The Chief Executive Officer, UPSE Securities Ltd., Kanpur
 - The Dy. Manager, Oriental Insurance Co. Ltd
 - The Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation, Mumbai
 - The Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation, Kolkata
 - The Chief Commissioner of Income Tax, Kanpur
- In its endeavour to consider ways and means to provide specific assistance in improvement of skill and talent of our members, the Committee organized the following Conferences/Seminars/Workshop/training programmes during the period.

- Series of workshop for the auditors of 'Non Banking Financial Companies (NBFC)' was organized by the Committee at Hyderabad, Trichur, Kolkata, and Chandigarh.
- Training programme on Basel II for Statutory Auditors of Banks hosted by WIRC on 27th – 28th May, 2008 at Mumbai.
- Workshop on Climate Change Mitigation including CER Process..... Professional Opportunities for Chartered Accountants hosted by WIRC of ICAI at Mumbai on 26th July 2008.
- Workshop on Emerging Professional Opportunities at Ahmedabad on 22nd August, 2008.
- Dinner meeting for Chairmen Regional Rural Banks and General Managers of Sponsoring Banks looking after Regional Rural Banks on 26th August, 2008 at New Delhi.
- Capacity Building Programme for Statutory Auditors of Housing Finance Companies (HFCs) jointly with National Housing Bank at Mumbai on 5th September, 2008.
- Meetings were organized on 2nd September and 20th October 2009 with Carbon Credit and CDM Experts at Delhi and Mumbai respectively to improve upon the background material developed for the workshop held on 26th July 2009 at Mumbai.
- Meeting of Chairmen and Auditors of RRBs on 11th September, 2008 to discuss Audit Manual, Prudential Norms of Regional Rural Banks and various other issues pertaining to the Statutory Audit of RRBs.
- Dinner meeting with Director Finance and Independent Directors of PSUs to strengthen relationship with Public Sector Undertakings on 24th September, 2008 at New Delhi.
- Meeting with Director Finance and Statutory Auditors of Public Sector Undertakings to discuss and review the existing directions for conducting audit of PSUs under section 619(3)(a) of the Companies Act 1956 on 17th December 2008 at New Delhi.
- Series of Interactive Workshops for Central Statutory Auditors held at Mumbai, Bangalore, New Delhi, Kolkata.
- Series of Diamond Jubilee Interactive Symposium for Bank Auditors at Ernakulam, Trivendrum, Ghaziabad, Noida.
- Series of Diamond Jubilee National Symposium for Statutory Auditors of Regional Rural Banks" jointly with NABARD at Kolkata, Lucknow, Bhopal and Pimpri-Chinchwad.
- Diamond Jubilee Symposium on Professional Excellence & Enrichment at Bhilai on 15th February, 2009.
- Diamond Jubilee Symposium on Professional Enrichment at Allahabad on 26th April, 2009.
- 2-day programme on IFRS for senior C&AG officials in the O/o C&AG on 1st and 2nd April, 2009.
- Faculty support provided to the O/o of CAG for 4 day training programme (13-16th April, 2009) on New /Revised Accounting standards/Auditing & Assurance Standards for C&AG officials
- Series of workshops for Statutory auditors of PSUs have been held jointly with the office of C&AG at Delhi, Ernakulam, Mumbai, Kolkata Lucknow and Jaipur.
- All India Conference on Professional Development and Enrichment at Coimbatore on 29-30th May, 2009.

5.10 Peer Review Board

The Peer Review mechanism, introduced by ICAI – a leader in this behalf – in the country has been a successful endeavour by the Institute, which has to a large extent achieved its objectives for which it was set up.

The Peer Review Board set up by the Council of the Institute in the year 2002, comprising of Members of the Council and representatives from bodies like the Ministry of Corporate Affairs, C&AG, SEBI, CII & FICCI is moving forward in ensuring that the reviews are carried out as per the best global practices.

In order that there is consistency and uniformity in carrying out reviews by the Reviewers, the Board imparts training to the Reviewers, before assigning them the Practice Units for review. The training

modules specially developed for the purpose as a book titled "Training Modules for Peer Reviewers" is provided as training curriculum for Reviewers and also guidance for the training facilitators on how to conduct reviewers' training.

The Peer Review Process aims to cover all firms of Chartered Accountants (PUs) in a phased manner in three stages. The PUs are selected on random basis, through a specially developed software. PUs covered under Stage I have been selected in 5 phases and those under Stage II have so far been selected for 5 phases. Selection of PUs under Stage III has also been made under phase I thereof. Details of PUs selected, reviews completed and Peer Review Certificates issued will be found elsewhere in this report.

Subsequent to the decision of the Council of ICAI accepting the recommendation of SEBI that for appointment as an auditor of listed companies for accounting periods commencing on or after April 1, 2009 the auditor Firms/Practice Units must have a certificate from the Peer Review Board of the Institute, the Board decided that all the listed companies auditor firms shall be covered under the purview of Peer Review on a fast track basis. Accordingly 1240 firms were selected for their Peer Review exercise and were intimated about their Peer Review.

5.10.1 Initiatives of the Board

- The Board has decided to come out with an e-learning modules for training the Reviewers to enable them to go through these modules at their convenience. An option would also be given to the members either to attend the training programme organized by the Board or go through the e-learning modules. Thereafter a self assessment test would also be developed for the benefit of members.
- The Board is coming out with the menu driven software for audit documentation to improve the quality of documentation. This would facilitate the Practice Units to ensure that they have in place proper systems and procedures for maintaining the quality of attestation services they render to their clients.
- The Board has also decided to organize refresher training programme for Peer Reviewers who are already trained with an objective to update their knowledge & skills on accounting & auditing standards.
- The Board has also finalized the revision of its publications. The Board's publications i.e. Peer Review Manual, Training Module for Peer Reviewers and FAQs will be printed shortly.

5.11 Committee for Members in Industry

5.11.1 Overview

The Committee for Members in Industry is involved in encouraging and enhancing close links between ICAI and the Chartered Accountants working in industries in various capacities so as to provide them, a base of reference in terms of knowledge, expertise, skills and assistance in individual career growth through the development of extensive and intensive relationship with organizations and agencies of the Government, so as to provide the maximum possible exposure to the world of trade, commerce, industry and governance, while simultaneously pursuing the goal of providing the maximum of employment opportunities.

The Committee also provides assistance to members of the Institute in finding appropriate career opportunities in the industry. In this regard, the Committee is engaged in providing placement services to the following categories of members and students of the Institute:

- (i) Newly qualified Chartered Accountants through the campus placement programme
- (ii) Experienced Chartered Accountants – who are presently serving in industries
- (iii) Semi Qualified Accounting Professionals

All the above services are being administered through the Placement Portal www.cmii.icai.org. The ICAI placement portal provides an opportunity to (both qualified as well as semi qualified) and the

industry to interact with the objective of building capacity for international best practice oriented finance and accounting culture in the Indian industry.

5.11.2 Campus Interviews

The Committee organized campus placement programme in the year 2008-2009 and 2009-2010 (upto 2nd July, 2009) for the placements of the members qualified in May 2008 and November, 2008 CA Final Examination.

During 2008-2009

Executive Summary of the Campus Placement Programme held during August- September-2008

- In all 3817 candidates had the opportunity to avail this service.
- The bio-data of these professionals were classified centre-wise and they were given the opportunity to meet 149 interview boards of 77 organisations at sixteen centers.
- Highest salary offered for International posting in the Campus Placement Programme was Rs. 21.00 Lacs per annum.
- Highest salary offered for domestic posting in the Campus Placement Programme was Rs. 10.61 Lacs per annum.
- Around 1000 jobs were offered to the candidates who participated in Campus Placement Programme.
- The average salary offered to the newly qualified Chartered Accountants was about Rs. 6.11 lacs per annum.
- 77 companies participated during the Campus Placement Programme.
- 149 Interview Panels have participated during the Campus Placement Programme.
- IT Software sector (16.16%) was amongst the highest recruiter of all sectors, but sectors like Mining (8.42%), Banking (7.52%), Financial Services (6.40%), Oil & Gas Refining (5.50%) were the major recruiters.
- Nineteen recruiting entities have also joined the Campus Placement Programme for the first time.
- The Committee brought out revised publications on 'Quick Review Questions' & 'How to face an Interview Board' to enable the candidates to prepare for their Interviews.
- The Committee organised Orientation Programme for candidates to sharpen their soft skills and give updates on technical matters.

Special Campus Placement Programmes, July, 2008

Special Campus Placement Programmes was organized for the candidates who had undergone the three months residential programme on Professional Skills Development at NIFM, Faridabad in July 2008.

- Seven organizations participated and 21 jobs were offered
- The maximum salary offered for international posting to two candidates was USD 24000 per annum.
- For the domestic posting to four candidates, the offer was Rs 11 Lacs per annum.

Special Campus Placement Programmes October, 2008

Special Campus Placement Programmes organized for the candidates who had undergone the three months residential Programme at NIFM, Faridabad in October, 2008.

- Five organizations participated and 14 jobs offered
- Maximum salary offered for International posting was USD 24000 per annum to five candidates.
- For the domestic Posting, the offer was Rs 6.5 Lacs per annum to two candidates.

During 2009-2010 (upto 2nd July, 2009)**Executive Summary of the Campus Placement Programme, March-April-2009**

- In all 3842 candidates had the opportunity to avail this service.
- The biodata of these professionals were classified centrewise and they were given an opportunity to meet 95 interview boards of 54 organisations at sixteen centres.
- Highest salary offered for International posting in the Campus Placement Programme was Rs. 23.00 Lacs per annum.
- Highest salary offered for domestic posting in the Campus Placement Programme was Rs. 9 Lacs per annum.
- Around 508 jobs were offered to the candidates who participated in Campus Placement Programme.
- The average salary offered to the candidates was about Rs. 6.06 lacs per annum.
- 54 companies participated during the Campus Placement Programme.
- 95 Interview Panels participated during the Campus Placement Programme.
- Financial Services (29.62%) was amongst the highest recruiter of all sectors, but sectors like Banking (20.00%), Oil & Gas Refining (11.90%), Engineering Procurement and Construction (8.10%), were the major recruiters.
- The Committee brought out two edition of publications "Handbook for newly qualified Chartered Accountants" to enable the candidates to prepare for their Interviews.
- The Committee organised Orientation Programme for candidates to sharpen their soft skills and give updates on Technical matters.

Special Campus Placement Programmes, May 2009

The Committee organized Special Campus Placement Programme on 16th May, 2009 for candidates who had undergone three months Residential Programme on Professional Skills Development at NIFM Faridabad as well as Shri L. N. Mittal Institute of Information Technology, Jaipur.

- Seven organizations participated and 28 jobs were offered
- Maximum salary offered was Rs 5.75 Lacs per annum to four candidates.

Campus Placement Programme exclusively structured for SMEs and SMPs

The Campus Placement Programme exclusively structured for Small and Medium sized Enterprises (SMEs) and Small and Medium Chartered Accountants firms for newly qualified Chartered Accountants qualified in November, 2008 and May, 2008 examinations was held during June at thirteen centres across the country to further improve the penetration of the Campus Placement Programme amongst each and every possible employers of CAs. In all 133 candidates got job offers from 69 organizations.

Questionnaire to all the Members Working In Industry

In order to understand and analyze the expectations of the Members in Industry from the Institute and to encourage them to join the mainstream of the Institute, CMII has hosted a questionnaire on Placement Portal under link <http://www.cmii.icai.org/imgs/question-email1.pdf>

Programmes/Seminars/Conferences organized:

The Committee organized the following programmes/seminars/conferences for the benefit of the members in industry during 2008-09 and 2009-10 (upto 2nd July 2009):

During 2008-09:**CFOs Meet**

S.No.	Place	Date	S.No.	Place	Date
1	Mumbai	22nd April, 2008	2	Chennai	28th December, 2008

Corporate Accountants Meets

S.No.	Place	Date	S.No.	Place	Date
1	Bhilai	22nd June, 2008	5	Pune	26th December, 2008
2	Coimbatore	18th October, 2008	6	Mumbai	29th December, 2008
3	Ernakulam	31st October, 2008	7	Bangalore	9th January, 2009
4	Hyderabad	14th November, 2008			

HR Meets

S.No.	Place	Date
1	Mumbai	11th July, 2008
2	New Delhi	25th July, 2008
3.	Mumbai	24th December, 2008

Industry Specific Programmes

S.No.	Topic	Date and Place
1	Seminar on IFRS	5th to 7th June, 2008 at Mumbai
2	Workshop on Private Equity	1st and 2nd August, 2008 at Mumbai
3	Diamond Jubilee Residential Refresher Workshop	22nd to 24th of August, 2008 at Alleppey
4	Workshop on IFRS	29th and 30th of August, 2008 at Baroda
5	Seminar on Enriching Knowledge and Maintaining Excellence	17th October, 2008 at New Delhi
6	CPE Seminar for Members in Industry	15th of November, 2008 at Hyderabad
7	All India Conference on 'Winds of Change – Challenges to the Profession'	16th to 17th of December, 2008 at Kolkata
8	Diamond Jubilee Conclave of Members in Industry	27th December, 2008 at Pune.
9	Training Programme on 'Real Estate & Construction Industry'	28th December, 2008 at Chennai
10	Seminar on IFRS vs GAAPs	23rd January, 2009 at Mumbai
11	Seminar on Direct Taxes	24th January, 2009 at Mumbai
12	Seminar on Raising of Financial Resources	25th January, 2009 at Mumbai

Corporate Forum

ICAI's Corporate Forum (23rd to 25th January, 2009) was organized in Mumbai comprising of following three concurrent events:

- Career Ascent (23rd to 24th January, 2009): An event to provide Chartered Accountants having one or more year of industry experience with growth and career prospects by way of providing newer job opportunities.
- Three companies namely Nestle India Limited, IBM Daksh & Sharaf Shipping LLC participated and offered jobs to the various members.
- Corporate Conclave (23rd to 25th January, 2009): Three (different) National Conclaves on contemporary topics like IFRSs, Direct Taxes and Raising of Financial Resources were held to enrich the knowledge and enhance the skill set of members.

The numbers of delegates registered were as follows:

IFRS vs. Indian GAAPs	375
Direct Taxes	210
Raising of Financial Resources	165

- ICAI Awards 2008 (25th January, 2009): These awards sought to acknowledge the Chartered Accountants in industry who demonstrated excellence in the way in which they conducted their profession serving as exemplary role models in the industry and who created value to their company's stakeholders on a sustainable basis. The jury to adjudge the nominations for the awards comprised of about two dozen elite dignitaries of the stature of CMDs, Chairman, President, CFOs etc. of the well-known companies and corporations of the country.
- The Jury Meeting took place on 17th January, 2009 at Mumbai, which was Chaired by Hon'ble Shri Suresh Prabhu, Former Union Minister of Power, Heavy Industries and Enterprise and Member of Parliament – Lok Sabha. The ICAI Awards, 2008 function was held on 25th January, 2009 at Goregaon Sports Club, Mumbai inaugurated by Hon'ble Shri Ram Naik, Former Union Minister for Petroleum and Oil & Natural Gases and the awards given away as under:

23

Sr. no	Category	Name of the Award Winner	Designation	Organisation
1	CA Business Achiever-Corporate	CA. Akhil Gupta	Dy Group CEO & MD	Bharti Group
2	CA Business Achiever-Financial Services	CA. Motilal Oswal	Chairman & Managing Director	Motilal Oswal Financial Services Ltd.
3	CA Business Achiever-SME	CA. K. Ullas Kamath	Dy MD	Jyothy Laboratories Limited
4	CFO - Manufacturing	CA. Adesh Gupta	Whole Time Director & CFO	Aditya Birla NUVO Limited
5	CFO-Financial Sector	CA. Keki Mistry	Vice Chairman and MD	HDFC Ltd
6	CFO-Public sector	CA. A.K. Singhal	Director (Finance)	NTPC Limited
7	CFO (Information Technology, Media, Communication and Entertainment)	CA. V. Balakrishnan	CFO	Infosys Technologies Limited
8	CFO-Women	CA. Irawati Dani	Director (Finance)	Western Coalfields Limited
9	CA Professional Achiever-Finance Sector	CA. Bharat Banka	MD & CEO	Aditya Birla Capital Advisors, also President and Head, Group Corporate Finance, Aditya Birla Group.

During 2009-10

- Seminar on Personality Development and Goal Setting for Professionals on 1st June 2009 at Faridabad.
- One Day CPE Conclave for Members in Industry on 5th June 2009 at Hotel Cindrella, Sevoke Road, 2nd Mile, Siliguri.
- Diamond Jubilee Seminar on 9th June 2009 at Ludhiana.

Publications of the Committee

During 2008-09:

The following publications have been released for the benefit of the members in industry. The same were distributed free of cost to the newly qualified Chartered Accountants at the time of orientation programme:

- How to Face an Interview Board
- Quick Review Questions

During 2009-10:

The Committee has brought out two editions of 'Handbook for Newly Qualified Chartered Accountants' for the benefit of newly qualified Chartered Accountants.

Publication-Projects commissioned by the Committee

- The Committee is in process of restarting the publication of e-newsletter 'Corporate Communiqué.
- Committee is in the process to commission the publication on projects as per the following details:

Sr. No	Name of Author	Topics of the Publication
1	CA. Rajay K. Aggarwal	Mergers and Acquisitions: An International Perspective
2	CA. Ravikumar Yanamandra	Customs Valuation
3	CA. Nitesh Shah	Value Added Business Controls - The Right Way to Manage Risk

The Committee is working on the following strategic initiatives:

- Developing CPE Study Circles for Members in Industry.
- To host a full-fledged job portal with the state of the art filtering facilities and online payment facility for recruiting entities.
- National Young CA in service Competition for Young Chartered Accountants.
- Industry-specific Programmes
- CFOs Meets.
- Corporate Accountants meets
- ICAI Corporate Forum - Award Ceremony for the year 2009
- Domestic and international study tours for Members in Industry.
- Sports, Cultural and Social events to showcase the extra curricular activities of members to promote & spread brotherhood among them.

5.12 Committee on Information Technology

5.12.1 Overview

Information Technology has today emerged as the business driver of choice, from a humble role of business enabler. Information Technology has brought revolutionary changes in the way business is being transacted today as enterprises and governments are adopting IT in big to better manage their operations and offer value added services to their clients/ citizens through e-services/ e-governance initiatives - e-Banking/ e-Service/ e-Payments/ e-Governance/ e-Reservations/ e-Procurement/ e-Tender!

IT Enabled Services (ITeS) like Enterprise Resource Planning (ERP)/ Business Process Outsourcing (BPO)/ Knowledge Process Outsourcing (KPO) are growing fast now-a-days with new WTO and the world fast transforming into a global village.

The Council of the Institute has constituted the Committee on Information Technology in the year 2000 to regularly map IT challenges and by converting them to a gainful professional opportunities for the profession through suitable education and development programmes like Post Qualification

Courses/ Conferences/ Seminars/ Practical Workshops; apart from coming out with study guides, resources, e-learning/ computer based training modules.

The first initiative of the Committee was to equip CA's to offer IS Audit/ Systems & Process Audit Assurance (SPA) value added services, which are in increasing demand today, through the Post Qualification Course (PQC) on Information Systems Audit. CA's are increasingly offering these services to their clients, particularly Banks/ Financial Institutions/ Stock Brokers, where there is a statutory requirement.

Considering the demand especially of ISA members, the Committee has started offering Practical Workshops on use of Information Technology to enhance the efficiency and effectiveness of operations, such that CA's can offer better value added services to their clients by use of IT as a tool. The Committee also offers CPE Course on CAAT to provide hands-on practical training on computer assisted audit techniques/ general audit software and has also released CAAT Resources CD.

The Committee has identified ERP Consulting as the next area for the development of the profession considering increasing emerging professional opportunities in this sector and has started offering courses on SAP FA & SAP MA, and Microsoft Dynamics NAV. The Committee has launched Tally Business Assurance Practice (BAP) workshop on 12th July 2008 on remote audit of Tally clients.

The Committee has launched e-Learning/ Computer Based Learning module on "Bank Branch Audit – An Overview" with Continuing Professional Education Committee of the Institute, "Using CAAT/ GAS – An Intro." and "Using MS-Excel as a CAAT/ GAS Tool". The Committee also launched e-learning courses on Service Tax and IFRS. The Committee is actively endeavoring to develop competencies and seek professional opportunities for CA's in the IT area.

The Committee has also started offering Computer Appreciation Course for Senior Members in association with the Continuing Professional Education Committee of the Institute as a part of the Institute initiative to ensure that the profession is IT equipped. Batches of this course are organized in the ITT Centres established at 100 IT centres of the Institute.

The Committee has started "Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection in IT Environment". The course aims to develop investigative skills required to uncover corporate/ business fraud, measure resultant damage, provide litigation support/ outside counsel by applying accounting, auditing principles for the detection of frauds.

The first batch of this Certification Course is started from 17th January 2009 at Mumbai. 25 candidates joined the course.

5.12.2 Initiatives of the Committee on Information Technology:

Project Parivartan (Improving eGovernance in ICAI):

It is the Vision of the President (ICAI), CA. Uttam Prakash Agarwal and its holistic adoption is with the help of Infosys Technologies. The Committee has conceived Project 'Parivartan' with an idea of taking ICAI to a qualitatively new way of working which would bring together both aspiring and existing chartered accountants in the country to come together as a CA pariwar. The goal is to create single tightly integrated system for catering to the entire community of chartered accountants, irrespective of their geographical locations, through the Internet. The initial kick start of Project Parivartan took place on 6th May 2009 in Head office of the Institute where Departmental Heads/ Secretaries to non-standing committees had interaction with Infosys team. As a part of the project, there will be workshops at all 5 regional Head Quarters and also at Bangalore & Jaipur where members & students are invited to participate in the workshops.

Formation of IT Directorate:

During the year the Committee on Information Technology considered the need for a full fledged Information Technology (IT) Directorate to bring all IT activities under one umbrella to enable co-

ordination and optimum use of resources for the developmental activities relating to members & students. The committee felt that IT directorate shall synchronize, standardize, optimize and expedite the processes to bring a unified approach towards all IT initiatives such as VIP, Online Exam & Results Processing, websites & portals, e-Learning, IT education & training to Members & Students including Post Qualification Courses. The committee recommended the creation of IT Directorate to the Executive Committee (EC) and EC at its meeting held on 6th April 2009 approved the creation of IT Directorate and decided to bring it into operation from April 2009.

First National ICAI Webcast on Global Economic Crisis – Changing Role of CA's on 17th April 2009:

The Committee organized the historic First National ICAI Webcast on Global Economic Crisis – Changing Role of CA's on Friday the 17th April 2009. To promote online education and to reach out to more learners in less time, CA. Uttam Prakash Agarwal, the President of the Institute inaugurated Web Casting event. Over 4000 members have registered the webcast, many of whom have visited on multiple occasions. It is another milestone in the history of the Institute. ICAI is the first professional Institute to do it and many others will follow our path. The concept of on-demand learning environment using web will go a long way & ICAI soon will have more such events. ICAI will invite industry leaders to address its members on various topics related to the profession. Such events will not only save travel and costs associated with traditional on-site training but also create unique experience for learners. The impossible is made possible. It created a platform for many of ICAI members residing abroad to view the seminars of the Institute live who are wanting to participate in the seminars of the Institute but not able to do so because of their geographical location.

New Publications of Committee:

The Committee has released two brochures – IT Courses and IT Publications to reach out to the members at large. An information booklet on Post Qualification Course on Information System Audit has been published by the Committee to market ISA course.

The Committee has launched three new Publications (a) "Technical Guide on Systems Audit of Stock Brokers", (b) "Technical Guide on Information Systems Audit" and (c) "Data Analysis for Auditors - Practical Case Studies on Using CAATs" for the benefit of members and to develop the profession in this area.

ISA Meets:

The Committee organized ISA Meet of 3 hours duration at Coimbatore, Bangalore & Tirupati on 29th December 2008, 5th January 2009 & 29th April 2009 respectively. These ISA Meets brought together ISA Members for a brainstorming session on technology trends and to gear-up themselves to face the challenges, apart from getting views and suggestions from the members. It also provides CPE hours to the members participated in the meet.

Auditors Training Programme on Finacle (Core Banking System) at Infosys Campus, Bangalore from 1st to 5th June 2009:

The Committee organized a non residential "Auditors Training Programme on Finacle Core Banking System" with the help of Infosys Technologies at Bangalore from 1st to 5th June 2009. The course aimed at providing hands-on training on the basic use of Finacle and the use of its Audit & Control features.

This programme is specially designed to meet the requirements of Bank Branch Auditors and members who have qualified the Post Qualification Course on Information Systems Audit (ISA).

IT Manager Course for Members in Industry:

It is the Committee's initiative to launch IT Manager Course for members in Industry will suitably equip the Industry members in the IT Field. ISA Post Qualification Course is meant for members in

practice, while Chartered Accountants are increasingly managing the IT Departments of enterprises today.

The Committee at its recent meeting held on 3rd June 2009 decided to offer IT Manager Course to enable members to contribute for adoption of good IT Governance practices and procedures in corporate, banks and financial institutions, while at the same time enhance their professional opportunities in Industry.

Information Technology Summit 2009:

The Committee is organising a series of Technology Summits in Delhi, Pune, Jaipur, Kolkata, Chennai, Hyderabad, Emakulam and Bangalore this year. These Summits provide an opportunity for members to understand various opportunities open to them in the field of Information Systems Audit and other related areas.

Significant International Initiatives:

The MoU between ICAI the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (ICASL) provides a facility to acquire DISA (ICAI) qualification by Sri Lankans. During this year, the Committee conducted the course at Sri Lanka on 11th May 2009. The Secretary of the committee visited Sri Lanka for the inaugural session and had extensive discussions with ICASL team. ICASL team expressed keen interest to extend the scope of the said MoU to cover other courses, practical training and workshops offered by the Committee. They were also keen on the Information Technology Training courses offered by ICAI to its students. The Accounting Technician Course offered by ICAI is another area of interest between both the Institutes.

The Post Qualification Course is popularised in all the 22 foreign chapters of ICAI. Dubai, Abu Dhabi and NewYork Chapters of ICAI have shown interest to conduct ISA Courses for the benefit of members residing abroad.

ISA Question Bank:

During the year the Committee has decided to enhance ISA Question Bank for Online Practice Test and Researched Online Study Materials to enable regular update of Question Bank and provide latest information to the members. Accordingly a D.I.S.A. (ICAI) Question Bank Development Guide was hosted inviting questions from members. An announcement to this effect has also been hosted in the May 2009 issue of The Chartered Accountant.

Revamped Committee Portal:

The Committee has launched its New CIT Portal which is more user friendly & efficient with added features. It is developed in Visual Studio 2008 and is equipped with RSS Facility using which users are able to get the latest updates hosted on the site.

The new portal has online eLearning module on IS Security, Cyber Threats & Review. Members can access the Portal from <http://cit.icai.org>.

Service Tax eLearning Module:

The first e-learning course on Service Tax has been a big success and more then 4500 members have registered for this e-learning course in the last 4 months. On registration a member is provided with an e-learning kit consisting of a Book on Service Tax, video presentation by the author and a Redeem Code.

Launch of e-Learning Course on IFRS-International Financial Reporting Standards:

Committee on Information Technology has launched another e-Leaming Course on “IFRS-International Financial Reporting Standards” on Friday the 3rd July 2009 at Agra International Conference held from July 3rd to 5th 2009 in presence of the President CA. Uttam Prakash Aggarwal.

International Financial Reporting Standards (IFRS) are the accounting standards of the future. Over 110 countries are now using IFRS. The International Accounting Standards Board (IASB) is continuously making amendments to their standards to ensure that a single set of global accounting standards become the norm and everyone talks the same accounting language.

Promotion of XBRL – Financial Reporting Language:

The Institute is spearheading the XBRL initiative in the country to promote greater use of this Financial Reporting Language. ICAI is Indian Jurisdiction for XBRL International. XBRL implementation in India is a good professional opportunity for ICAI members. The committee decided to develop technology tools to make Financial Statements XBRL compliant. The committee decided to organize Seminars & Conferences to promote XBRL in India.

eRoom Study Group for accessing knowledge resources:

During the year the committee has constituted eRoom Study Group at Bangalore to develop an eRoom for members which will facilitate access to all the ICAI knowledge resources such as publications, presentations, seminar materials online under one portal. The group will review existing ICAI online facility and will discuss a strategy to make as much eContent as possible online.

ISACA Study Groups:

Another important initiative of the committee during the year is creation of ISACA study group to educate & develop ISA Members to provide Information Systems Assurance Services using IS Audit Standards, Guidelines and Procedures now available to us under ICAI-ISACA MoU.

5.12.3 Post Qualification Course on Information Systems Audit:

The Post Qualification Course on Information Systems Audit (ISA) continues to be very popular amongst the members. This course has been a unique rallying point for members to develop and grow all over the country. The Committee organized 57 batches of ISA Professional Training were organized at 57 centres and the ISA Eligibility Test was organized at about 150 centres, in the report period. The following table provides the numerical data:

Particulars	Registration	ET Pass
As on April 1, 2008	26,943	19,137
During the Year	1,992	623
As on March 31, 2009	28,935	19,760
During April 1, 2009 to July 20 2009	178	630
Total as on July 20, 2009	29,113	20,390

5.12.4 Registration Statistics of the various courses offered by IT Committee:

Registration for CAAT, SAP ERP Course, Microsoft NAV Dynamics & Certificate Course on Forensic Accounting & Fraud Detection using IT & CAATs as on 20th July, 2009 is as follows:

Sr. No.	Course	Registrations as on 20 th July, 2009
1.	CAAT	3,197
2.	SAP ERP Course	302
3.	Microsoft NAV Dynamics	74
4	FAFD	33

5.12.5 IT Conferences, Seminars, Practical Workshops:

This year, the Committee has organized a series of IT Summits and Workshops as detailed below, with the theme "Technology Summit 2009" in June, July and August 2009 for the benefit of

members:

Sr.	City	Theme	Region	Date
1	Bangalore	Technology Summit 2009	South	26 th -27 th June, 2009
2	Kolkatta	Technology Summit 2009	East	18 th -19 th July, 2009
3	Ernakulam	Techno Link Workshop 2009	South	18 th July, 2009
4	Delhi	Technology Summit 2009	North	August, 2009

In addition, the committee organized following Conferences in association with respective Branches of WIRC of ICAI”

Sr.	City	Theme	Region	Date
1	Pimpri Chinchwad	Diamond Jubilee National IT Conference	West	20 th -21 st June, 2009
2	Baroda	National Diamond Jubilee Convention on Information Technology	West	16 th May, 2009

5.13 Publication Relation Activities Undertaken

The Public Relations Activities in the year 2008-09 took a leap forward as the Institute celebrated Diamond Jubilee Year celebrations which focused on building the brand of the profession domestically and globally. This historic year saw an increased interaction with Media, within the Institute-with its members, branches and regional offices. Some of the important activities undertaken by the PR division include the following:

- The Media interactions increased through one to one interviews, constantly apprising the media of the latest developments regarding the curriculum, profession, introduction of new courses, new guidelines for CAs, visit of foreign delegations, other activities and events etc.
- Promoted the potential & scope of Chartered Accountancy Profession in today's dynamic context by way of articles as well as through interactive meetings/releases issued to the press at national /regional level and through various TV Channels.
- Providing logistic support to various departments within the Institute, to the regional Offices and Branches with a view to develop communication link between the Institute and its offices/related organizations.
- As a part of the PR exercise, organized appropriate coverage in Print and Electronic Media to different Seminars/Programmes/Events /book launches of the Institute, organized by different Committees.
- PR was an intrinsic part of the Diamond Jubilee Celebrations Committee and the jobs related to creative & media publicity were assigned to the section. Diamond Jubilee Logo was created which was integral to all communication pertaining to the celebrations. Specific stationery was designed which would be used along with the logo through out the year.
- The complete communication for the Diamond Jubilee Celebrations – Invites, Brochure, Souvenir, posters, stickers, advertisements, and newsletter cover etc were designed. The same were forwarded to all branches/regional offices to maintain uniformity in the communication.
- For an appropriate coverage of the Diamond Jubilee celebrations, a tie up was established with 3 Electronic channels-CNBC, UTVi, Zee. All the 3 channels have given wide publicity to various activities organized to mark this momentous occasion.
- It was decided to bring out a souvenir on the occasion of Diamond Jubilee Year. Important dignitaries like National political leaders, Chief Ministers of states and heads of International

bodies were contacted & requested to send the messages on this occasion. A special Souvenir compiling all these messages and also from corporate leaders was brought out.

- As a part of many initiatives taken by the Institute, an International Conference titled "Accounting Profession - Shining Bridge Between Global Economies" was organized in Jaipur where in an MoU was signed between ICAI and ICAEW, UK. The Conference was attended by 2400 delegates and 250 delegates from about 40 countries. The whole event was given wide coverage in the media.
- Keeping in mind the need of hour to lend support and closely associate with the society and contribute actively at the grass root levels in social welfare, National Service Scheme (NSS) was launched by the Institute. Hon'ble Mayor of Delhi, Ms. Aarti Mehra launched this project which will include organizing special camps for various developmental tasks of national importance such as mass literacy, environmental enrichment, health, family welfare, child welfare, slum development, welfare of the physically challenged, senior citizens welfare, disaster management, helping NGOs etc. The media covered the entire event.
- Yearly Publication called "Year Book" was brought out by the Public Relation Cell comprising the achievements of the Institute in all the regions along with the achievements of the Committees.
- The 59th Annual Function of the Institute witnessed the launch of new Accounting Software and signing of MoU with CPA Australia. The event was given due coverage in media.
- The Institute organized a 4 day successful "National Leadership and Yog Camp" at Yog Gram, Haridwar. The event was properly covered by media at Haridwar and all other regions through the wide publicity given by the Public Relation Cell.
- CA Curriculum was promoted through structured articles as well as interactive meetings with the press in national as well as regional news papers and TV Channels. The multi faceted growth of the Indian economy has resulted in huge demand for 2nd tier accounting professionals for large, small & medium enterprises. Responding to this demand of the industry, the Institute launched Accounting Technician Course. The function was attended by more than 1500 students and members and was inaugurated by then union Minister of Railways, Shri Lalu Prasad. The whole media- print and electronic covered the function. In order to promote the Accounting Technician Course, advertisements are being released in various publications. Also, UTVi has been made media partner for the events being organized by the Institute. To promote, Accounting Technician course, a commercial prepared by UTVi is being run on the channels.
- The recently concluded International Conference at Agra in July 2009 marked a grand success and at the conference 3 MOUs/ Joint Declarations were signed at the events which were well covered in media.
- The Press and Media continues to be apprised of the emerging developments in the profession through constant interactions and in particular after each of the Council meetings.

5.14 Trade Laws and WTO

The Committee on Trade Laws and WTO was constituted with the mission to establish and assure the expertise and authority of the Institute of Chartered Accountants of India in all matters concerning Laws of Trade including Trade in Goods and Services in particular, and the implementation of international trade regimes including the WTO regime in general, both nationally and internationally and to create and expand a base of expertise in these matters among the membership of the Institute through such ways and means as are considered to be most effective so as to fulfill national stated and unstated aspirations, concerns, and needs in all these regards.

The Committee's composition includes members of the Council of the ICAI, members co-opted to the Committee from various parts of the country and other experts invited from time to time at the deliberations of the Committee.

The Committee on Trade Laws and WTO, since its creation in 2001 has been devoting itself to create awareness, education and prepare the ground work needed to develop professionals having specialised skills in the field of WTO, in the process of implementing continuing initiatives to contribute towards the process of India's economic development.

The Committee has been seeking to evaluate the changes taking place in the new world trade milieu and their ramifications for this prominent sector in order to adequately equip members of the Institute to take advantage of the space created by the new world trading regime. In order that the Indian professionals do not remain insular to the winds of change that have been gathering around us at a mind boggling pace, the Committee has currently embarked upon to provide greater thrust, inter alia, to the pursuance of following :-

- Capability enhancement of Members of the Institute in WTO Regime
- Identification and exploration of means for expanding export of services from Indian professionals
- Creation of professional avenues under WTO
- Dissemination of knowledge through various means
- Provision of level playing field for Indian professionals under WTO Regime by providing technical inputs to the Government for taking up at appropriate level at WTO.

5.14.1 Research Activities

With the basic objective of providing guidance to the Chartered Accountants in practice and in service and others concerned to have an insight in various fields and on issues of relevance to International Trade Laws and WTO, the Committee has released the following publications during the period under report:

- Canadian Advantage-A Research Study on Canadian Business Opportunities
- Introduction to WTO and Opportunities for Chartered Accountants in International Trade Laws and WTO
- Handbook on Foreign Trade Policy and Guide to Export and Import Study on Benefits of Preferential Trade Agreements

The Committee has also undertaken country specific research studies for the following countries. The basic objective of these research studies is to provide guidance to the Chartered Accountants and others concerned on the trade laws/rules applicable in major trading partners for (a) setting-up businesses in such countries; and (b) operating as professional accountants in such countries:

- UAE
- Australia
- Singapore
- France
- Italy

5.14.2 Technical Inputs to Government

- Analyzed the Annual Supplement 2008 of the Foreign Trade Policy 2004-09.
- The Committee has undertaken analysis of trade policies of those WTO Members whose Trade Policy Review shall be due to take place at WTO level during the year 2009 viz., New Zealand, Morocco, Guyana, Zambia, South African Customs Union, Chile, Maldives, Niger/Senegal, El Salvador and Georgia addressing concerns in respect of the Accountancy services for those countries so that the same could be communicated to the Government for addressing them at WTO level.

5.14.3 International Study Tours/ Seminars/ Conferences/ Awareness Programmes/ Workshops

During the period under report, the Committee on Trade Laws & WTO organised the following programs:-

- Seminar on International Trade Laws and Foreign Trade Policy held on 17th May, 2008 at Mumbai jointly with Committee on Economic & Commercial Laws and hosted by the WIRC of the ICAI.
- ICAI International Study Tour to Thailand, Malaysia and Singapore during 10-17 August, 2008 jointly with Bhilai Branch of CIRC of the ICAI. The delegation comprised of 54 participants covering members from all the regions.
- Seminar on Emerging Professional Opportunities under WTO Regime with Special Reference to BPO/KPO on 6th September, 2008 at Kolkata hosted by EIRC of the ICAI.
- Interactive Workshop for the members registered in the ICAI's Post Qualification Course in International Trade Laws and WTO on 10th September, 2008 at ICAI Bhawan, New Delhi and relayed through Videoconferencing to Regional Offices of ICAI at Mumbai, Chennai, Kolkata and Kanpur.
- Diamond Jubilee Seminar on Emerging Paradigm for Accountants on 2nd October 2008 at Agra hosted by Agra Branch of CIRC of the ICAI.
- Diamond Jubilee National Workshop on Emerging Paradigm for Accounting Professionals jointly with the Expert Advisory Committee on 24th October 2008 at Lucknow hosted by Lucknow Branch of CIRC of the ICAI.
- Diamond Jubilee Conference on Emerging Paradigm for Accountants on Tuesday, 30th December 2008 at Coimbatore hosted by Coimbatore Branch of SIRC of the ICAI.
- All India Conference on WTO and Taxation jointly with Direct Taxes Committee on 3rd and 4th January, 2009 at Varanasi hosted by Varanasi Branch of CIRC of ICAI.
- Visit of ICAI Delegation to Hong Kong during 18th – 21st January, 2009
- Meet on Cross Border Integration in WTO Regime on 24th January, 2009 at Mumbai.
- Diamond Jubilee All India Convention on Tax and WTO jointly with Indirect Taxes Committee and Direct Taxes Committee on 30th and 31st January, 2009 at Goa hosted by Goa Branch of WIRC of the ICAI.
- Diamond Jubilee Symposium on Professional Excellence & Enrichment jointly with the Professional Development Committee on 15th February, 2009 at Bhilai hosted by Bhilai Branch of CIRC of the ICAI.
- International R.R.C at Thailand from 4th to 8th May, 2009 hosted by Bhilai Branch of CIRC of the ICAI.
- Interaction with the Trade officials of various Embassies in India on 15th May, 2009 at New Delhi. The interaction was attended by the officials from the Embassies/High Commissions of Germany, Iceland, Belarus, Paraguay, Tunisia, Malawi, Maldives, Sri Lanka and Pakistan. Continuing with the initiative, a meeting was also held with the officials of British High Commission on 26th May, 2009 at New Delhi.
- "Interactive Workshop on GATS - Issues for Accounting" on 26th June, 2009 at New Delhi and relayed through videoconferencing to Regional Offices of the ICAI at Mumbai, Kolkata and Kanpur.

The Committee has also brought out a standard Background Material on International Trade Laws & WTO.

5.14.4 Post Qualification Course in International Trade Laws and World Trade Organisation

The Committee had introduced a Post Qualification Course in International Trade Laws and World Trade Organisation to orient Chartered Accountants towards developing the necessary and desirable capabilities to adapt to and respond to the dynamic and challenging international economic environment. This Course has also been receiving good response from the members.

- After the successful launch of the Post Qualification Course in International Trade Laws & WTO (ITL & WTO) in November 2004, total of 309 Members have been registered in the Course from across the country.
- Two batches of the 30 days Personal Contact Programme (PCP) for the Post Qualification Course in ITL & WTO were successfully conducted during the year 2008-09 at New Delhi. The 1st batch was organised during July – August, 2008. The 2nd batch was organised at New Delhi & relayed through videoconferencing to the Institute's offices at Mumbai, Chennai and Kolkata during December, 2008 to January 2009. Further, phase 1 of the Personal Contact Programme (PCP) for the Post Qualification Course in ITL & WTO has also been successfully completed at New Delhi from 1st July 2009 to 15th July 2009. Eminent faculty consisting of Senior Government Officials in different Ministries/Departments, such as Ministry of Commerce, Ministry of Finance, Directorate General of Safeguards, Directorate General of Foreign Trade, Competition Commission of India, Export Inspection Council of India, Copyright Board, faculty from Indian Institute of Foreign Trade, Indian Institute of Public Administration, University of Delhi, Delhi School of Economics, noted law firms, people from trade and industry, professionals, consultants and other research based organizations in the field of International Trade and WTO made presentations and delivered lectures during the PCPs.
- The syllabus, course structure, study material and the framework of the Post Qualification Course in International Trade Laws and WTO are proposed to be realigned with a view to give a focused outlook to the overall structure of the Course. The scheme is, however, pending for approval by the Government.
- The Committee has been taking efforts to popularize the Course amongst members throughout the country and also to promote the Course in the industry, Government and other potential user-groups to create professional avenues for members so equipped in International Trade Laws and WTO field.
- Interactions were held with various experts in the field of International Trade Laws and WTO on 5th May, 2008 at New Delhi seeking their views with regard to the possible road map for Chartered Accountants in this field.

5.14.5 Web Portal on WTO

The Committee has developed a comprehensive web portal on WTO (<http://wto.icai.org>) to meet the emerging needs of the members. The portal intends to keep the members abreast of latest development in the ever-changing global trading environment.

5.14.6 E-Newsletter

The Committee has introduced an E-newsletter titled 'Gateway to International Trade – E-Communique of the Committee on Trade Laws and WTO' to focus on various issues related to international trade. During the period under report, October, 2008, April, 2009 & July, 2009 issues of the said E-newsletter have been brought out and hosted at the website of the Institute.

5.14.7 Technical Desk on WTO

Technical Desk on WTO for attending technical queries on WTO has been strengthened.

5.14.8 News on WTO

In order to keep the members abreast of latest developments taking place in the field of International Trade and WTO, relevant press/news clippings on WTO are being regularly hosted at the website for information of the members.

5.14.9 Post Qualification Course in International Trade Laws and World Trade Organisation

- Since the launch of the course in November 2004 applications for registration in the course have been coming from all parts of the country. The Region-wise fragmentation of the registration is as follows:-

Region	No. of Members registered till 14/07/2009
Western	79
Southern	55
Eastern	31
Central	52
Northern	92
Total	309

5.14.10 Other Projects/Initiatives under progress

- With the basic objective of providing guidance to the Chartered Accountants in practice and in service and others concerned to have an insight in various fields and on issues of relevance to International Trade Laws and WTO, the Committee has also undertaken research activities in the following fields to bring focused research publications:-
 - International Commercial Arbitration
 - Cross –border Mergers & Acquisitions
 - Country Specific Research Studies for various Countries

5.15 Committee on Insurance and Pension

5.15.1 Developing Professional Opportunities for CAs with DIRM Qualification

- Representation has been sent to IRDA with a request to amend the IRDA Guidelines for Appointment of Statutory Auditors of Insurance Companies for giving weightage to firms of CAs having DIRM Qualified partners or paid chartered accountant(s) while appointing the firms as statutory auditors of insurance companies.
- Representation has been sent to the office of the Comptroller and Auditor General with a request for giving weightage to firms of Chartered Accountants having a DIRM Qualified partner(s) or paid chartered accountants while appointing the firms as divisional auditors of public sector insurance companies.
- DIRM marketing letters were sent to the CMD's of various insurance companies, Third Party Administrators and NCR Based Surveyors and loss assessors with a request to utilize the services of DIRM qualified Chartered Accountants
- Letters were sent to the nominee directors of public sector insurance companies to consider taking appropriate steps so that the information of the members of the Institute could be disseminated amongst the possible users of the services of such DIRM qualified members.

5.15.2 Training and equipping members in insurance and pension sectors by way of a Post Qualification Course

- Three Orientation Courses have been successfully held at Ahmedabad , Chennai and New Delhi on 6th - 11th October ,2008, 16th - 21st March, 2009 and 18th - 23rd May, 2009 respectively for the candidates who have passed the DIRM Technical examination.

5.15.3 DIRM Orientation Course for DIRM Technical Examination passed members of the Institute organized during 18-23, May, 2009 at New Delhi

- Suggested Answers to DIRM Technical Examinations held upto November 2008 are hosted at the Institute's website at http://www.icai.org/post.html?post_id=2432 for the benefit of the DIRM pursuing members of ICAI.
- To popularize the DIRM course amongst the members, the Committee is consistently making efforts and taking up appropriate measures. As a result, the number of registrations have reached upto 3520 till 2nd July, 2009. The region-wise break up is as under:

Region	Registrations
Central	718
Eastern	388
Northern	525
Southern	1140
Western	749

- With a view to enlighten the users of the services of DIRM qualified Chartered Accountants and to the general members and students of the Chartered Accountancy course, the Committee invited DIRM qualified members to share their experiences on how the DIRM course enabled them to develop the domain expertise in the areas of Insurance and Risk Management. The responses received from the members in respect of our above request have been hosted on the website of the institute at http://icai.org/post.html?post_id=3396
- In response to the follow ups made, the Insurance Institute of India has granted exemption from the following papers of the Licentiate, Associate and Fellowship courses to the members of the ICAI.
 1. Paper No. 12 : Insurance Business Environments
 2. Paper No. 21 : Information Technology
 3. Paper No. 26 : Life Assurance Finance
 4. Paper No. 89 : Management Accounting and
 5. Paper No. 99 : Asset Management

In addition to the above, the DIRM qualified members are granted additional exemptions from the following papers of the aforesaid courses:

1. Paper No. 01: Principles of Insurance
2. Paper No. 11: Practice of General Insurance
3. Paper No. 82: Statistics

The Insurance Institute of India has also been requested to grant some more exemptions to the DIRM qualified members.

5.15.4 Updates on Insurance and Pension Sectors

Separate Web Portal of the Committee (<http://www.insuranceicai.org>) is being updated by hosting daily updates on insurance and pension sectors on daily basis (except on Sundays and Holidays) for dissemination of knowledge and awareness amongst members of the Institute.

5.15.5 Developing Domain Expertise amongst CAs in the areas of Insurance and Risk Management and Pension

Publications

- A book entitled "Technical Guide on Review and Certification of Investment Risk Management Systems and Processes of Insurance Companies" has been released. The book provides necessary guidance on the audit of the insurance and risk management systems and processes of insurance companies as per the requirements of the guidelines issued by the IRDA in this regard.
- The revised Study Material for DIRM course have been printed and hosted in the website of the institute at the Hyperlink http://www.icai.org.in/post.html?post_id=959&c_id=51 to provide updated materials to the DIRM course pursuing members. The study material for the DIRM Course has been revised in such a manner that it may be referred by a member other than those pursuing the DIRM Course.

The modules have been named as:

- Principles and Practice of Life Insurance
- Principles and Practice of General Insurance
- Risk Management and Reinsurance
- Business Strategic Planning and Information Technology in Insurance Sector

5.15.6 Programmes on Insurance and Pension sectors conducted by the Committee

- A meeting of the nominee Directors of the Public sector Insurance Companies was held on July 29th 2008 at New Delhi.
- The Committee organized a three day Management Development Programme on Risk Management in Public Sector jointly with Committee on Internal Audit of ICAI in collaboration with The Department of Public Enterprises (Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises), Government of India at New Delhi during 19th - 21st November, 2008. The programme was well attended by 39 delegates.
- A National Symposium on Insurance and Risk Management was organized on 17th January, 2009 at Mumbai. The Chairman, IRDA inaugurated the same.
- In addition to the aforesaid programmes, the Committee provided financial support of Rs. 50000/- p.a. to the Regional Councils and the three largest Branches of each Regional Council and Rs. 20000/- p.a. to the other branches of the Institute. A report of the programmes conducted by the Regional Councils and Branches in response to the request of the Committee is given below:

S. No.	Name of the organizing unit	Date & Place	Topics covered
1.	Calicut Branch of SIRC	26 th July, 2008 at Calicut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risk Management ▪ Insurance Survey & Loss Assessment/Loss of Profit Internal/Divisional Audit of Insurance companies
2.	Hubli Branch of SIRC of ICAI	26 th July, 2008 at Hubli	<ul style="list-style-type: none"> • Insurance and Risk Management

3.	HP Branch of NIRC of ICAI	9 th August, 2008 at Shimla	<ul style="list-style-type: none"> • Anti Money Laundering • New Pension System
4.	Vellore Branch of SIRC of ICAI	9 th August, 2008 at Vellore	<ul style="list-style-type: none"> • Transformation of Insurance & Pension Sectors • Professional opportunities in Insurance and Pension • Risk Management – Perspectives & Issues • Internal Audit of Insurance Companies • Insurance Survey and Loss Assessment
5.	Moradabad Branch of CIRC	30 th August 2008 at Moradabad	<ul style="list-style-type: none"> • Anti Money Laundering in Insurance Sector • Insurance Survey & Loss Assessment • Precaution to be taken during attestation and EDP Audit
6.	Bellary Branch of SIRC	28 th June, 2008 at Bellary	Risk Management in Life Insurance
7.	Aligarh Branch of CIRC	6 th December, 2008 at Aligarh	<ul style="list-style-type: none"> • A paper on Consequential Loss assessment & Computation • Features of Loss of Profits Policy • Development in Pension Sector in India • Insurance Broking
8.	Bareilly Branch of CIRC	6 th December, 2008 at Bareilly	<ul style="list-style-type: none"> • Insurance Survey & Loss Assessment • Arbitration Insurance Broking
9.	Jaipur Branch of CIRC of ICAI	3 rd and 4 th January, 2009 at Jaipur	<ul style="list-style-type: none"> • New Professional Opportunities for CAs in Insurance and Pension sectors • AS-15 (revised) on Employee Benefits with inputs on Actuarial Sciences • Impressing the stakeholders – the Right Approach (Personality Development for Professionals) • Recent Amendments in Income Tax • Tax Implications of Real Estate Investment • TDS – Recent developments • Tax Audit – Recent Amendments
10.	Ahmedabad Branch of WIRC of ICAI	30 th December, 2008 at Ahmedabad	<ul style="list-style-type: none"> • "Insurance Sector Reforms – The Aspirations and Concern • "Accounting Aspects in General Insurance Industry • Insurance relating to Export and Import Transactions – • "Legal Perspectives in General Insurance"
11.	Aurangabad Branch of WIRC of ICAI	27 th December, 2008 at Aurangabad	<ul style="list-style-type: none"> • Topics on Insurance and Pension
12.	Madurai Branch of WIRC of ICAI	31 st January, 2009 at Madurai	<ul style="list-style-type: none"> • Topics on Insurance and Pension
13.	Surat Branch of ICAI	21 st December, 2008 at Surat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Re-Insurance- an opportunity for Chartered Accountants ▪ Opportunities for Chartered Accountants in Insurance Sector

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Audit & Accounts in Insurance ▪ Risk Management
14.	Baroda Branch of ICAI	20th December, 2008 at Baroda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Re-Insurance- an opportunity for Chartered Accountants ▪ Opportunities for Chartered Accountants in Insurance Sector ▪ Audit & Accounts in Insurance ▪ Risk Management
15.	CIRC of ICAI	31st May, 2008 at Kanpur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insurance Survey & Loss Assessment ▪ Insurance Broking ▪ Risk Management - Its Essentials and Process ▪ Third Party Insurance
16.	Saharanpur Branch of CIRC of ICAI	28th May, 2008 at Saharanpur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insurance Survey and Loss Assessment ▪ Insurance Broking ▪ Third Party Insurance ▪ AS-15 on Employee Benefits
17.	Alwar Branch of CIRC of ICAI	1st June, 2008 at Alwar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insurance and Pension sector related topics
18.	Faridabad Branch of NIRC of ICAI	14th June, 2008 at Faridabad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AS-15 (R) on Employee Benefits ▪ Emerging opportunity for CAs in Insurance Sector
19.	Bhopal Branch of CIRC of ICAI	31st May, 2008 at Bhopal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insurance and Risk Management related topics
20.	Gorakhpur Branch of CIRC of ICAI	6th July, 2008 at Gorakhpur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AS-15 (R) on Employee Benefits ▪ Risk Management ▪ Anti Money Laundering
21.	Asansol Branch of EIRC of ICAI	22nd June, 2008 at Asansol	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risk Management ▪ Audit of insurance companies
22.	SIRC of ICAI	29th March, 2009 at Chennai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Approach to Risk Management and Insurance in the emerging Scenario ▪ Recent development in Insurance Business ▪ Statutory, Internal & Concurrent Audit of Insurance Companies ▪ Insurance Broking – Role, Nature, Laws & Regulations and Distinction between Insurance Agency and Insurance Broker ship
23.	Gurgaon Branch of SIRC of ICAI	16th May, 2009 at Gurgaon	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insurance Arbitration ▪ Development in Pension Sector ▪ Insurance Survey and Loss Assessment (Loss of Profit policy) ▪ Emerging insurance market and opportunity for CAs

5.15.7 Programme on AS-15 (Revised) on Employee benefits with inputs on Actuarial Sciences:

The Committee provided a one time financial support of Rs. 20000/- to the regional councils and branches of ICAI for organizing programmes on Accounting Standard-15 (Revised) on Employee Benefits with inputs on Actuarial Science for the benefits of the members of the Institute during the

Council year 2008-09. The status report of the Programmes organized by the Regional Councils and Branches under this special financial support scheme is as under:

- WIRC of ICAI on 21st June, 2008 at Mumbai
- Coimbatore Branch of SIRC of ICAI on 19th July, 2008 at Coimbatore
- NIRC of ICAI on 28th November 2008 at New Delhi.
- Hyderabad Branch of SIRC of ICAI on 7th February, 2009 at Hyderabad.
- Faculty support to the CPE Committee was provided for organizing a CPE Teleconferencing on AS-15 on Employee Benefits [Revised] with inputs on Actuarial Science on 28th January 2009.

5.15.8 Involvement of Insurance Industry in the Technical Endeavours of the Committee

Letters have been sent to CMDs and CEOs of various Insurance Companies to nominate a few experts working in their organisations whose services could be utilized by the Committee as an author/reviewer of the proposed publications of the Committee. A set of the latest publications of the Committee were sent to the CMDs and CEOs for their perusal and keeping the publications in their organisations' Library.

5.15.9 Revision of Honorarium payable to authors

Consequent upon the initiative of the Committee, the Executive Committee at its 474th meeting held on 12th May 2008, decided, inter alia, to revise the Honorarium payable to authors preparing the basic drafts of the publications on behalf of the Committee.

5.15.10 Research activities in the areas of Insurance and Pension

- Letters have been sent to all members, special invitees & insurance companies to get the inputs on taxation issues involved in the Insurance business. The queries so received have been forwarded to the Committee on Direct taxes for their consideration and necessary actions.
- With an endeavor to encourage research in the areas of insurance and risk management by way of providing the financial support through Accounting Research Foundation of the ICAI, the Committee has sent letters, project facilities (guidelines for research proposals) of Accounting Research Foundation of ICAI to possible classes of researchers. In response the Expert Group of ARF has approved a project entitled Reforms in Insurance Sector subject to the eligible cost of Rs. 2.25 lacs and total duration of 12 months.

5.15.11 Technical Support for the Endeavors of the PFRDA

The Committee has been providing technical support to PFRDA with the help of a Technical Group constituted by the Committee for this purpose in the following areas:

- i. Drafting of accounting norms for Pension Fund Managers.
- ii. Designing Reporting formats for receiving and evaluating information being collected from Pension Fund Managers.
- iii. Audit of activities of the fund managers and report on compliance with guidelines and directions issued by the PFRDA/NPS Trust from time to time.

5.16 Committee on Corporate Governance

The Committee on Corporate Governance was constituted in September, 2005 with a view to address the corporate governance related issues confronted by both the Private and Public Sector entities, whether listed or unlisted. Its primary objective is to encourage appropriate level of corporate governance, provide assistance in laying down benchmarks and proactively conduct research about the difficulties/problems being faced by the corporations in view of globalization and to promote corporate governance in enterprises including Public sector.

To uphold professionalism in practice of governance standards, the Committee has been organizing several training programmes/seminars with an aim to provide knowledge in various components of corporate governance including the practical aspects alongwith numerous legal and regulatory requirements. The National Foundation for Corporate Governance (NFCG), set up by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, often sponsored the programmes of the Committee. As part of another major initiative, the Committee has brought out the publication entitled "*Code of Governance for NGOs*" in January, 2009 to help NGOs ensure greater transparency and better internal control.

5.16.1 Programmes organized

During the year, the Committee organized the following programmes:

- An Induction Programme on Independent Directors held at Kolkata in June, 2008 jointly with EIRC, Kolkata.
- A National Seminar on Corporate Governance held at Mumbai in August, 2008, in partnership with the National Foundation for Corporate Governance (NFCG) and hosted by WIRC, Mumbai.
- A National Seminar on Corporate Governance held at Kolkata in September, 2008, in partnership with NFCG and hosted by EIRC, Kolkata.
- A Half-Day Seminar on Corporate Governance held at Kanpur in December, 2008, in partnership with NFCG and hosted by CIRC, Kanpur.
- A National Seminar on Corporate Governance held at Chennai in December, 2008, in partnership with NFCG and hosted by SIRC, Chennai.
- A National Seminar on Corporate Governance held at Hyderabad in March, 2009 in partnership with NFCG and hosted by Hyderabad Branch of SIRC.

5.16.2 Initiatives/Projects in progress

- Interact with regulators on various issues relating to corporate governance.
- Launch Certificate Course on Corporate Governance
- Constitute ICAI Expert Advisory Group in the preparation of ICAI Code on Corporate Governance comprising of renowned experts
- Research – Case Studies on success/failure of Corporate Governance in Indian Corporate World
- Bring out publication on Role and Responsibilities of Independent Directors and Audit Committee
- Develop a Software on Corporate Governance Rating
- Organize Public Awareness Programme on Corporate Social Responsibility
- Organize Workshops on Independent Directors
- Hold National Seminars and one International Conference in partnership with NFCG
- Conduct a sample survey with family owned enterprises on Audit Committee Practices
- Organize Round Table Conference on Audit Committee for Banking and Corporate Sector separately

5.17 Committee for Capacity Building of CA Firms

5.17.1 Overview

The Committee for Capacity Building of CA Firms (CCBCAF) constituted in February 2008, aims at addressing the conceptual and implementation issues regarding the capacity building measures of practicing Chartered accountants and providing comprehensive guidance to them. The Committee also aims at facilitating small and medium firms to scale up their resources, infrastructure and skill set, thereby enabling them to handle larger assignments resulting in growth in profits and market share. To serve the purpose, the Committee regularly reviews the progress of various capacity building measures initiated by the Institute, namely, Networking, Merger, Corporate Form of Practice in context of the current rules and procedures.

5.17.2 Achievements of the Committee (till 31st May, 2009)

- Reviewed the position of the 35 Networks registered with ICAI by sending Feedback Forms to the 112 firms constituting it and thereby, identified the challenges/bottlenecks being faced by them in the functioning of their Networks.
- Facilitated the identification & interaction amongst interested practicing members for Networking, Mergers etc. through CA Networking Portal www.caconnect.co.in
- Ensured availability of updated comprehensive data of the Networks registered in India, on the website of the Institute for easy accessibility by the end users.
- Organised an Interactive Program on Capacity Building of CA firms on 20th April, 2009 at Mumbai. An exhaustive feedback form seeking views of the members on the various capacity building measures of the Institute was collected from the participants of the Interactive Program and a complete analysis was done to identify the difficulties/impediments being faced by practicing Small & Medium Practitioners in consolidation.
- Organised an Interactive Program on Capacity Building of CA firms on 22nd May, 2009 at Hyderabad jointly with Hyderabad Branch.
- Constituted a Study Group for Revision of Guidelines on Network, Merger-Demerger and Corporate Form of Practice in order to identify and eliminate the impediments in the existing Guidelines.

5.17.3 Strategic initiatives of the Committee:

- To organize Workshop/Interactive Programs on Capacity Building in 5 major cities, namely, Kanpur, Delhi, Chennai, Kolkata and Mumbai during June to August 2009 for creating awareness among practicing members on the various Capacity Building initiatives of ICAI and identifying the impediments and challenges being faced by small and medium practitioners in resorting to them.
- To organize a National Networking and Capacity Building Summit on 22nd August, 2009 at Mumbai.
- To revise the Guidelines on Network, Merger-Demerger and Corporate Form of Practice.
- To explore the feasibility of international networking in the CA Networking Portal www.caconnect.co.in and accordingly, customize the site.
- To develop a module to address the conceptual and implementation issues at firm level, and as a comprehensive guide on what, how and why of consolidation and networking.

5.18 Committee on Economic and Commercial Laws

The Committee on Economic and Commercial Laws (CECL) was constituted in February 2008 with the specific objective of focusing more clearly on the emerging professional opportunities in the area of economic and commercial laws and to facilitate legislative process in the area of making/amending economic and commercial laws.

The following are the significant achievements and exercises undertaken by the Committee:-

Certificate Course on Arbitration

The Committee has organised the VI and VII batches of the Certificate Course on Arbitration at New Delhi from 1st – 6th December 2008 and at Mumbai from 17th January to 15th February 2009 respectively.

The Committee has decided to continue to organise the Certificate Course on Arbitration on regular basis at Metros and Non-Metros. The Committee is organizing the Certificate Course on Arbitration at one or two places in the Western and Southern Regions. Efforts are also being made to organise the Course in other Regions/Branches.

Advance Level Workshops

The Advance Level Workshops on Arbitration would be organised mainly for the members who have already undergone the Arbitration Course. The members who have 10 years of practice/post-qualification experience would also be eligible to join the workshops.

Promotion of ICAI Panel of Arbitrators

- The ICAI Panel of Arbitrators hosted on the website of the Institute. A suitable Announcement in this regard was also published in the Journal of the Institute.
- Letters along with the ICAI Panel of Arbitrators were sent to the user bodies namely Hon'ble High Courts, Chambers of Commerce, Stock Exchanges and Arbitral Institutes across the country and globally to utilise the Panel for appointing Chartered Accountants as Arbitrators
- The Committee formed a Sub-Group with a view to promote the ICAI Panel of Arbitrators initially at the National level and thereafter globally.
- The Seminars/ Conferences jointly with various Trade Bodies and Associations would be organised to create awareness about the vital role which Chartered Accountant's can play in Arbitration / Conciliation/ Mediation Proceedings especially with respect to Finance, Accounting and Taxation matters etc.
- The Chairman/Members of the Committee and Sub-Group will meet the Secretaries of Legal Departments of the State Governments along with the Members of the concerned Regional Councils and its Branches to discuss and apprise them about the role of Chartered Accountants which they can play in Arbitration matters.
- The Committee will publish four pages regularly in the Chartered Accountant Journal with regard to Arbitration matters (Statutory Updation, Articles and Case Laws) and other significant achievements to facilitate members update their knowledge.

Publications

- The Committee is taking steps to bring out three new publications and to revise the earlier publications of the Committee.
- A Study on Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976
- Referencer on FEMA (Foreign Exchange Management Act, 1999)

New Publications of the Committee

- A Study on Prevention on Money Laundering Act, 2002
- Handbook on Professional Opportunities in Economic and Commercial Laws
- A study on Drafting, Conveyance, Stamping and Registration of Commercial and other Documents.

Preparation of Background Material

- Steps are being taken to prepare the suitable Background Material on SEZ laws for the workshops for circulation amongst the participants in the Workshops well in advance.

Interaction with various Government Departments/Ministries

- There has been a constant interaction with the officials of the Government Departments/Ministries for the purpose of exploring professional opportunities for the members and the Committee has decided to continue this exercise.

Suggestions/Comments on various Economic and Commercial Laws

- The Committee has submitted its views/suggestions on the housing finance companies/sector to National Housing Bank and on Prevention of Money Laundering (Amendments) Bill 2008 to Parliamentary Standing Committee on Finance.

Preparation of Background Material

Steps are underway to prepare the background material on the following Laws:

- Special Economic Zone and Allied Laws
- Arbitration and Conciliation Act, 1996
- Competition Act, 2002
- Foreign Exchange Management Act, 1999 and Foreign Direct Investment
- Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 and Trust Laws

Workshops Organised

The following Workshops have been organised by the Committee for the benefit of the members:

- Workshop on “Professional opportunities in Foreign Exchange laws” on 12th and 13th September 2008 at Mumbai
- Workshop on “Professional Opportunities in Drafting, Conveyancing, Registration and Stamping of Commercial and Other Documents” on 3rd -4th October, 2008 at Mumbai.
- Workshop on “Professional Opportunities in Economic and Commercial Laws” on 18th -19th October, 2008 at Ahmedabad.
- The Committee is now arranging to hold the Workshops on SEZ and its allied Laws across the Country.

5.19 Committee on Government Accounting

The Committee on Government Accounting was constituted in the year 2008 with the following Terms of Reference:

- To review and on that basis suggest improvements to the existing Government Accounting System.
- Providing awareness of Government Accounting to the society at large and specifically to the stakeholders including inter-alia to employees of the government, C&AG, members of the profession, media, NGOs and to citizens generally.
- To provide training within the Government bodies at Central, State, District level, Local bodies and Gram Panchayat Level.
- To facilitate suitable interface with present day Information Technology and to evolve methods which would enable in use of technology in assisting the accounting reform process.
- Collaboration and coordination with Comptroller & Auditor General of India (CAG), Controller General of Accounts (CGA) and various other Ministries for development of the improvements in the framework of Government Accounting System.
- To assist Central Government and the State Governments in enhancing accountability and transparency in Public service delivery mechanism.
- To suggest to the Central and State Government accounting reforms which would assist in widening the tax base & in better administration of the revenue collection and deployment machinery, assist the process of outcome measurement and improve MIS, reporting and budgetary control mechanisms.
- To encourage the study of and create awareness in regard to government accounting within the profession and to undertake capacity building measures for the profession to enable the profession to assist the government in the process of implementation of government accounting reforms and for this purpose undertake studies, conduct training and awareness programmes, publish background material etc.

5.19.1 Activities undertaken between 1-4-2008 to 31-5-2009

- The status paper on the “existing system of accounting in government and accrual accounting reforms in the government”, is under preparation covering *inter alia* “global experience of government accounting reforms, Indian Scenario, the cash basis of accounting used by the government in India, its limitations, accrual accounting, its benefits for the government, lesson learned from New Zealand experience, key issues involved and preconditions for successful implementation of accrual accounting reforms etc.”
- An article on Government Accounting is under preparation by Shri S. Sathyamoorthy, Former Deputy C&AG, Special Invitee in the Committee for publishing the same in the Institute’s Journal “*The Chartered Accountant*” for information of the members of the profession.
- With a view to initiate the process of accounting reforms, the Chairman of the Committee met senior officials of Government of Goa regarding accounting reforms in Government of Goa and expressed the willingness to undertake a project of accounting reforms for Government of Goa. The overall conclusion was very positive. Thereafter, in a meeting with Shri Digambar Kamath, Hon’ble Chief Minister of Goa, the Chairman of the Committee submitted the proposal letter prepared by ICAI for undertaking the project of accounting reforms. The Committee is following up with the Goa Government for the same.

- Developed and compiled the database of Members/ Chartered Accountants as resource persons who are well conversant with the present Government Accounting System and having experience in assisting the Government at any level i.e. Central State and Local Bodies.
- Meetings were also held with Shri S.M. Kumar, Additional Controller General of Accounts and Ms. Praveen Tripathi, Dy. Comptroller and Auditor General of India regarding ongoing accounting reforms process and agreed to co-ordinate each other for successful implementation of accounting reforms.

5.20 Committee on Management Accounting

5.20.1 Master in Business Finance Certificate Course.

The Committee launched the Master in Business Finance Certificate Course for the Members of ICAI. The course focuses on the topics of contemporary relevance like Treasury and Forex, Management, M&A, Corporate Valuation, Fund Raising – National & International, Theory & Practice of Financial Management. The course curriculum requires the participants to prepare case studies and participate in group discussions.

5.20.2 Management Accounting and Business Finance (Journal)

The Committee published its first issue of the monthly journal 'Management Accounting and Business Finance' to focus on the relevant issues relating to Management Accounting and Financial Management in the present business environment. The journal was circulated among various banks, universities, leading business schools, ministries etc. and most of them have complimented the committee for the initiative.

5.20.3 Final Report of CARRs/CAS

The Government of India, Ministry of Corporate Affairs, has constituted an expert group to review the existing Cost Accounting Record Rules and Cost Audit Report Rules (CARRs). During the course of expert group meetings, views and approach of ICAI vis-à-vis maintenance of Cost Accounting Records were given. It was stressed that the Cost Accounting Records should be maintained based on sound Accounting principles and not on the basis of rules.

The ICAI is also represented by the Committee on Management Accounting on the Cost Accounting Standards Board (CASB) of ICWAI. The CASB has issued exposure drafts of

- CAS-9 : Cost Accounting Standard on Cost of Utilities
- CAS-11 : Cost Accounting Standard on Direct Expenses
- CAS-12 : Cost Accounting Standard on Packing Material Cost

The CASB has also discussed the first draft of following Cost Accounting Standards.

- CAS-10 : Cost Accounting Standard on Administrative Overheads
- CAS-13 : Cost Accounting Standard on Repairs and Maintenance Cost
- CAS-7 : Cost Accounting Standard on Material Cost
- CAS-8 : Cost Accounting Standard on Employee Cost

5.21 Committee on Public Finance

In the year 2008, ICAI constituted a Committee on Public Finance for the first time with the mission to extend professional expertise to the Central, State and local Government in the area of Public Finance. Since its inception the Committee has come a long way creating landmark history of ICAI.

Till date, Committee has interacted with seven Governors, fourteen Chief Ministers, seven Finance Ministers and twenty five Secretaries/Ministers/ Commissioners of the State & Union Territories and offered its helping hands in the betterment of the economy and administration.

To have access with apex planning body of India, Committee organised a Talk Session on 4th December 2008 at ICAI, Delhi in which Prof. Abhijit Sen, Member, Planning Commission, Government of India, introspected upon Capital Expenditure & Revenue Expenditure, Planned & Non-Planned Expenditure, cash receipts and finances of State and Central Government. Similar meetings were also organized with members of Finance Commission.

To create awareness amongst the officials of the Kerala Government on assets management and exploring scope for additional revenue resources, Committee jointly with Centre for Taxation Studies, Government of Kerala, organized a State Summit on "Issues concerning Public Finance" on 27th December 2008 at Ernakulam, Kerala. Appreciating the work of the Committee, KSID has offered proposal for preparing report on its assets, liabilities, computerization and conversion of accounting system into double entry accrual based accounting system of the entire department.

The Committee jointly with Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Govt. of India, organized one day Workshop on IFRS on 28th January, 2009 at New Delhi in which around 50 CEOs, CFOs, senior officials from Finance Department of PSUs and Government Enterprises participated.

The Committee also organized two days training programme on various issues of VAT for the senior officials of the Department of Trade & Taxes on 2nd and 3rd February, 2009 at New Delhi and on Outcome Budget and Accrual Based Accounting System for the officials of Agartala Municipal Council on 15th & 16th May, 2009 at Agartala. The Committee also prepared Report on Convergence of Resources and Revenue Enhancement for the Government of Meghalaya.

The Government of Gujarat has invited the Committee to provide training to their tribal youths in the various accounting packages which in turn would enable them to gain sustainable employment.

The Committee invited to its meetings leading personalities and ministers for sharing their views. CA. K Rahman Khan, Hon'ble Deputy Speaker, Rajya Sabha, Hon'ble Shri Yashwant Sinha, Ex-Finance Minister, Govt. of India, Shri Rupchand Pal, Hon'ble Chairperson, Committee on Public Undertakings & Member, Standing Committee on Finance of the Parliament of India, Late Shri Govind Singh Gurjar, Ex-Governor, Govt. of Puducherry, Dr. Satish C. Jha, Member, Economic Advisory Council to the Prime Minister, Prof. Atul Sarma, Member, Thirteenth Finance Commission participated in the Committee Meetings.

On 26th May, 2009, the Committee conducted its seventh Meeting at ICAI, Delhi. Hon'ble Finance Minister of Government of Delhi, Dr. A. K. Walia addressed as the Chief Guest and appreciated the role of Chartered Accountants in economic development of the country. He also invited Chartered Accountants to contribute in raising revenue resources of Government of Delhi.

On 18th June, 2009, at a meeting conducted at Mumbai with Shri Ashok Chavan, Hon'ble Chief Minister of Maharashtra the Vice-President, ICAI and the Chairman and Vice-Chairman of the Committee met the Chief Minister and discussed the issues related to public finance in the State.

The Committee's endeavour is to create awareness on effective utilization of Public Fund, generation of additional revenue and providing technical inputs to all the concerned persons of Central & State Governments, PSUs, CPSEs, Local Bodies & NGOs for betterment.

5.22 Direct Taxes Committee

During the year 2008-09, two new Committees viz. Direct Taxes Committee and Indirect Taxes Committee were formed in place of erstwhile Fiscal Laws Committee. During the period 1.04.2008 to 31.05.2009, the Committee undertook various activities like representations to the Government, Interaction with CBDT officials, organizing Certificate Courses on International Taxation, revising

the existing publications of the Fiscal Laws Committee, organizing seminars and conferences and so on.

5.22.1 Representations/Suggestions

The Committee made the following representations to the Government:

- Request for extension of time for payment of taxes through electronic mode.
- Suggestions on Authority for Rulings on Central Taxes Bill, 2007 and on the desire of the Parliamentary Standing Committee the view of the Institute was also represented by a personal appearance.
- Suggestions on the "Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill, 2008"
- Representation seeking clarification on the issue whether remittances relating to TDS can be made using the old challan 281 as the new Form No.17 was not uploaded in the payment gateway on Ministry's website.
- Request to CBDT to take appropriate steps at the earliest for timely completion of scrutiny assessment in refund cases also, preferably by setting a cut-off date for completion of such assessments. In the alternative, it was suggested that the condition that refund should be granted only after completion of such assessment may be removed.
- Pre-Budget Memorandum -2009 submitted to the Government.
- A detailed reply relating to the measures taken by ICAI to check malpractices in the field of tax audit was submitted to the Ministry of Corporate Affairs.
- Representation to consider some hardships and practical difficulties likely to arise in the filing of Income tax Returns for A.Y. 2009-10 with respect to the directions given in the CBDT Circular No. 03/2009 dated 21-05-2009 particularly with reference to submission of ITR V
- Representation to consider genuine hardships and practical difficulties faced in getting a Certificate for lower deduction or non-deduction of tax at source

5.22.2 Interaction with CBDT Officials

The Direct Taxes Committee along with NIRC organised a felicitation dinner for Shri R.S.Mathoda, the then Chairman, Central Board of Direct Taxes. Shri Mathoda while stating that the profession of Chartered Accountants is playing very significant role expressed hope that it will continue to do so in future more and more proactively. The Hon'ble President of ICAI responded stating that the ICAI is playing significant role as "Partner in Nation Building" and will continue to do so. He also pointed out specific instances of ICAI having suggested measures for better revenue collections and prevention of leakage thereof.

5.22.3 Certificate course on International Taxation

The Committee organized Certificate Courses on International Taxation at Ahmedabad and Delhi. The Course and the course contents were widely appreciated by the members. With the formation of a separate Committee on International Taxation from 5th February, 2009, this Certificate course has been transferred to the same.

5.22.4 Publications

The Committee formed various study groups all over the country to revise the following existing publications of the Fiscal Laws Committee:

1. Guidance Note on Tax Audit under section 44AB of the Income-tax Act, 1961
2. Taxation of Charitable Trusts and Institutions – A Study
3. Guidance Note on Report under section 115JB of the Income-tax Act, 1961.

5.22.5 Seminars/Conferences

The Committee organized the following Seminars and Conferences during the said period:

- Residential Course on Taxation organised jointly with Indirect Taxes Committee from 5th to 7th June, 2008 at Ramnagar.
- Diamond Jubilee Conference on 18th and 19th July, 2008 at Hyderabad.
- All India Conference on 23rd and 24th October, 2008 at Vishakhapatnam.
- National Diamond Jubilee Conference on Taxation on 15th and 16th October, 2008 at Chinchwadgaon (Pune).
- National Seminar on Taxation on 7th December, 2008 at Kanpur.
- All India Conference on WTO and Taxation on 3rd and 4th January, 2009 at Varanasi.
- Diamond Jubilee All India Tax and WTO Convention on 30th and 31st January, 2009 at Goa.
- A Workshop on Direct Taxes on 25th April, 2009 at Indore.
- Residential Workshop on Direct Taxes & IFRS on 17th and 18th May, 2009 at Trichur.
- A Workshop on Direct Taxes on 16th May, 2009 at Bilaspur.
- National Tax Seminar on Direct Taxes on 30th April, 2009 at Kanpur.
- National Seminar on Direct Taxes on 27th June, 2009 at Raipur.
- Full day Workshop on Direct Taxes on 27th June, 2009 at Salem.

5.23 Indirect Taxes Committee

5.23.1 Presentation to the Parliamentary Standing Committee on Authority for Advance Rulings on Central Taxes Bill, 2007

The Parliamentary Standing Committee on Finance invited suggestions from the Institute on Authority for Advance Rulings on Central Taxes Bill, 2007. A memorandum containing the views of the ICAI was submitted to the Parliamentary Standing Committee on Finance.

Further, the Institute was requested to represent its views by a personal appearance before the Parliamentary Standing Committee on Finance. Accordingly, the President, Chairman, Direct Taxes Committee and the Secretary, ICAI appeared before the Committee on 19th June, 2008 and presented Institute's views. At the time of personal appearance it was suggested that the scope of the matters which can be considered by Authority for Advance Ruling should be expanded by allowing resident assessee also to make reference. With a view to regulate total number of references certain limits can be specified as regards type of issues which can be referred, monetary ceiling, process fees for reference etc. It was also suggested that professionals such as Chartered Accountants & Advocates with experience of certain number of years should also be considered as eligible to be appointed as member of the Authority for Advance Ruling.

5.23.2 Representation to Government:

The Committee made two representations to the Government as follow:

(a) Representation to CBEC

The Indirect Taxes Committee along with Representation Committee of the Institute submitted a representation to the Chairman, Central Board of Excise and Customs, requesting the Government to include chartered accountants for conducting special audit under section 14A and 14AA of the Excise Act, 1944.

(b) Representation to Government of Maharashtra

The Commissioner of Sales Tax, Maharashtra, issued a circular in November, 2008 amending Audit Report in Form No.704 making it applicable to the ongoing audits for the financial year 2007-08. In the newly introduced audit report there were some issues. In this matter the Regional Indirect Taxes Committee at WIRC submitted a representation to State of Maharashtra VAT & CST and also held meetings with the Sales Tax Department. After the representation and meetings held the Sales Tax Department agreed to continue to accept audit reports in old form at the option of dealer and auditor concerned.

5.23.3 Suggestion on technical paper issued by OECD

The OECD invited comments/inputs on the technical paper in respect of applicability of VAT/GST to cross border trade in services and intangibles. The paper sets out fundamental approaches for applying

value added taxes to cross-border supplies of services and intangibles in a business-to-business context. The Committee discussed the technical papers through conference calls and submitted its suggestion on the said technical papers to the OECD.

5.23.4 Training Programmes for Government Officials :

The Committee organised three training programmes for Government Officials during the year 2008-09. These training courses covered the topics on accounting concepts, scrutiny of books of account and other related statements, audit techniques, reconciliation of financial records with indirect tax records, finding out clues from financial records. These training programmes were well appreciated by all the participants and were a grand success.

- (a) Two weeks Training Course on "Use of Financial and Accounting Tools in the area of Indirect Taxes" for the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise) Group "A" Probationers of 59th Batch. The Training Course was held from 16th to 27th June, 2008 at National Academy of Customs, Excise and Narcotics (NACEN), Faridabad. The Training Course was inaugurated by CA. Amarjit Chopra, Council Member and the welcome address was delivered by Ms. Shashi Minz, Additional Director General, NACEN. The valedictory address was delivered by the Chairperson, Indirect Taxes Committee. The Course was well appreciated by all the I.R.S. Probationers and they expressed the desire that such training courses should be extended to at least one month.
- (b) After successfully organising training programmes for 59th batch of I.R.S. Probationers, the Committee organised training programme on "Use of Financial and Accounting Tools in the area of Indirect Taxes" for Superintendents and Inspectors (on the same lines as it was conducted for IRS Probationers) from 18th August to 22nd August, 2008 at NACEN, New Delhi.
- (c) The Regional Indirect Taxes Committee at SIRC organised a Training Programme on Accounting for the Officers of the Commercial Taxes Department, Tamilnadu in September, 2008. The training programme was inaugurated by Shri Thiru. S.N.M. Ubayadullah, Minister of Commercial Taxes, Government of Tamilnadu at ICAI Bhawan, Chennai.

5.23.5 Pre-budget Memorandum, 2009

The Committee submitted Pre-budget Memorandum, 2009 to the Government on the basis of suggestion received from members.

5.23.6 Research Project on GST/VAT

Members outside India desirous of associating with the Research Project were invited to express their interest in undertaking research in various aspects of GST/VAT. A group of 14 members in different countries having specialization in the field of GST / VAT was formed. Among those 14 members, 2 prepared their country specific papers and rest expressed inability/dropped out.

The Project completed and closed with the publication of the paper book containing 2 papers submitted by members and those contributed by other international experts at the International Seminar held on 16th January, 2008—countries covered – UK, Canada, Australia and Brazil.

5.23.7 Residential Course on Taxation

The Committee organized a three days Residential Course on Taxation jointly with Direct Taxes Committee at Ramnagar (Uttarakhand) held from 5th to 7th June, 2008. The topics covered related to practical issues in direct and indirect taxes in the sectors like retail, banking, financial services, hospitality, media and entertainment etc. The Course was attended by members and non-members from the industry and the same was a grand success.

5.23.8 Three Days Basic Level Course on Service Tax

As the area of Indirect Taxes was expanding very fast, the Indirect Taxes Committee thought that this is the right time to encourage our members to practice in the area of Indirect Taxes. As a first steps

in this direction to encourage our members to practice in the field of Indirect Taxes, the Committee decided to organize 3 Days Basic Level Course on Service Tax all over the country.

The first 3 days Basic Level Course on Service Tax was organised from 29th to 31st August, 2008 at Siliguri which was inaugurated by Additional Commissioner, Central Excise and Customs, Siliguri. The Assistant Commissioner Siliguri Division and Assistant Commissioner, Jalpaiguri were also present during the inaugural session. The faculty for the 3 days training course was of the view that there was tremendous interest in the subject and the participants were very keen to learn the subject. All the participants were happy that it was a continuous 3 days course and they could concentrate on the subject and mentioned that this course has added significant value and will enable them to identify opportunities and take up assignments in this field of practice. The course was a grand success.

Thereafter, second batch of the 3 Days Basic Level Course on Service Tax was conducted by Raipur Branch of CIRC in October, 2008. This was also a grand success.

5.23.9 National Conference on Indirect Taxes at Mumbai

The organised a 2 days National Conference on Indirect Taxes at Mumbai on 26th and 27th December, 2008 which was hosted by the WIRC of the ICAI. This conference was attended by 600 members and was a grand success.

The basic objective of the Conference was to discuss and deliberate in detail, with a practical focus on the critical and important issues under various Indirect Taxes laws which impact trade & industry / business decisions and also to generate a thought process on the proposed GST regime in the country.

5.23.10 International Seminar on “GST Architecture in Federal System (with special reference to proposed introduction of GST in India)”

The Committee organized an International Seminar on “GST Architecture in Federal System (with special reference to proposed introduction of GST in India)” on 16th January, 2009 at New Delhi. This programme was hosted by NIRC of ICAI.

This was a taxation policy related program to demonstrate leadership of Institute in this area. The Seminar was attended by the policy makers, officials from State Governments' VAT Department, representatives from ASSOCHAM, FICCI, PHD Chamber of Commerce and Indian Merchant Chambers,

International speakers including Dr. Shome, who is the Chief Economist with HMRC, U.K. and prior to that, was Advisor to Finance Minister had been called specifically for the Seminar.

Shri P.C. Jha, Chairman, CBEC, was chief guest for inaugural function. The Seminar was inaugurated by the President, ICAI and the special address was delivered by the Vice President. The Seminar was well appreciated by all the participants and had a grand success.

5.23.11 Publications

“A Guide to CENVAT Credits” has been published. It is expected to help the members practicing in the area of Indirect Taxes to a great extent.

5.23.12 IDT Net

The IDT net, a networking portal for the members practicing or working in the field of indirect taxes was created and up linked with the website of the Institute. More and more members specializing in the area of indirect taxes are registering with the IDT Net.

5.24 Perspective Planning Committee

Perspective Planning Committee is a non-standing Committee of the ICAI which has been constituted in order to meet the needs of the future so as to be able to present a strong and positive face in the fast

changing world trading environment. In order to meet the needs of the future so as to be able to present a strong and positive face in the fast changing world trading environment, the Perspective Planning Committee considers all the emerging developments nationally and internationally which may have possible bearing on regulated area carved out for the profession and supplement further by suggesting ways and means to promote the role of Chartered Accountancy profession in non-regulated area by flagging issues wherein profession needs to devote attention. The Committee is constituted with the objective as envisaged in the phrase 'he who is not prepared today will be less so tomorrow'.

The Perspective Planning Committee has been formed as a proactive measure to consider the emerging developments nationally and internationally, which may have it possible bearing on regulated area carved out for the profession and supplement further by suggesting ways and means to promote the role of Chartered Accountancy profession in non-regulated areas.

5.24.1 The Action plan as envisaged by the Committee INCLUDES:

- o Enhancing capacity of the profession and greater integration of the profession with global imperatives.
- o Planning for growth in profession while maintaining quality.
- o Positioning the Institute and the profession for a greater role in nation building.
- o Giving impetus to research activities.
- o Creating enabling institutional and organizational framework.

The area of work of the Committee is perpetual in nature as it calls for scanning the developments and brings it to the notice of Committee for discussion and debate. The Committee assesses the developments on case-to-case basis & request association and collaboration by all the Council colleagues and membership in general so that such developments, which have a negative dimension on the profession, are negated through appropriate communication/liaison work and at the same time bolster existing regulatory profile available.

The Committee works primarily as a research and analysis wing and is the brain, eyes and ears of the Council and profession.

In order to keep the Accounting Profession in tune with the developments taking place around the world and provide an interactive platform for Accountants across the globe the Committee organized two All India Diamond Jubilee Conferences in the month of December on the theme(s):-

- **"ICAI@60 – Challenges and Opportunities"** on 13th and 14th December 2008 hosted by Guwahati Branch of EIRC of ICAI and was attended by eminent speakers from the industry and the regulators who shared their words of wisdom with the accounting fraternity. Around 540 members including 95 students attended the Conference.
- **"Emerging Paradigm of Accountancy Profession"** on 24th and 25th December 2008 hosted by Hyderabad Branch of SIRC of the ICAI as part of Diamond Jubilee Year Celebrations of the ICAI. The Conference was a grand success and was attended by around 1800 delegates including members of the profession and other stakeholders.

The Committee in order to study the dynamic changes taking place in the accounting profession be it in industry or in practice conducted survey exercise(s) for which it launched two questionnaire(s) on "Competency Mapping for Accountancy Professionals" and "Changing Profile of Profession in context of member firms". These surveys intends to identify the practitioners and industry perspective on the focused requirements in terms of dexterity/ skill set which a new CA should possess and focusing Chartered Accountants in practice, with regard to their capacity building in relation to the assignments and extended brand image of CA Profession respectively. The Committee received overwhelming responses on the same which were around 10,000 and had came out with its two survey reports on the said theme which interalia helped the Council in bringing out its action plan for the future.

5.24.2 The Committee has so far referred 30 developments arising out of the Committee meetings to various Committees of ICAI on following areas.

- Designing workshop modules/programs for industry
- Ties up with International/ National Premier Institute(s) to have co-branding
- Post Qualification Courses attune to market realities
- Develop our own certification programs of short duration.
- Panel to recast cost accounting standards
- Setting up of National Tax Tribunal Appellate and National Company Law Tribunal Appellate
- IPO timings
- Disclosure of derivative losses and the fall in sensex
- ICWAI Accounting Technician course
- Report of the Advisory Committee on "Improvements to Financial Reporting" to the United State Securities and Exchange
- Report on EU approach to Corporate Governance
- IFAC information paper (June, 2008) on "Approaches to Continuing Professional Development (CPD) measurement"
- Agriculture a new avenue for CAs
- CESR takes steps to Strengthen Market Confidence
- MOU of the 5th three countries' accounting standard setters' meeting.
- Strategic and Operational Plan issued by IFACs international ethics standards board for accountants.
- Survey of ACAs reveals leadership and commercial skills at the core of FD's role
- Announcement of ICAEW regarding audit firm governance working group announced
- Activity Report on challenges to Corporate Reporting by FRRP of UK.
- Launch of CPA Program by Piron Education and ICFAI.
- Emergence of Forensic Auditing as a Professional opportunity area.
- Press release on IT department, Mumbai will conduct 1000 surveys in 3 months.
- Group Pension scheme for Chartered Accountants
- Report of G-20 summit on short/ medium/ long-term impact and remedies of meltdown.
- Vertical based specialization for the CA members through modified certification courses.
- Impact of Dr. Rakesh Mohan Committee report on Financial Sector Reforms
- Impact of Planning Commission report on Financial Sector Assessment
- European Commission decision on third country auditors
- Relaxation of articleship training abroad
- Report of G-20 working group on enhancing sound regulation and strengthening transparency

6. INTERNATIONAL AFFAIRS COMMITTEE

6.1 Recognition of Indian Qualification by other Accounting Bodies

The process of dialogue for evaluation of the Institute's qualification by selected overseas accounting bodies, being a long drawn process interalia involving the evaluation of qualification, training, continuing professional education, disciplinary requirements and involving domestic sensitivities; the results of the process are slow; yet at the same time the Institute is continuing its efforts for early culmination of the process. The Institute had signed Memorandum of Understanding (MoU) with The Institute of Chartered Accountants in England & Wales and the University of Djibouti. Mutual Recognition Agreement (MRA) has been signed with CPA Australia. The Process of qualification recognition is at various stages of discussion with accounting bodies in the Canada, Singapore, Bahrain, Ireland etc.

6.2 Institute's Representation at International Forums

The prominent role played by the Institute is evidenced in form of nomination it enjoys in the governing boards of international accounting bodies namely the International Federation of Accountants (IFAC), Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) and South Asian

Federation of Accountants (SAFA) in addition to their various functional Committees. Its nominees are currently represented on the following:

Committees of IFAC

- As Board Member
- Small and Medium Practices Committee,
- Developing Nations Committee
- IFAC Compliance Advisory Panel

CAPA

- As President
- As Board Member

SAFA

- As Board Member
- Committee on Education, Training & CPD
- Committee on Accounting and Auditing Standards
- Committee on Professional Ethics and Independence
- Committee for Improvement in Transparency, Accountability and Governance
- Committee on Professional Accountants in Business
- Committee on Quality Control
- Small and Medium Practitioners Committee
- Committee on Harmonization of Fiscal and Tariff Regime
- Task Force to review Constitution of SAFA
- President ICAI as Board Member
- Secretary as Permanent Secretary

6.3 MOUs/MRAs

The ICAI signed a Memorandum of Understanding with the *University of Djibouti*, Republic of Djibouti on May 18, 2009 coinciding with the Africa Day Celebrations from 18-19 May 2009 at Mumbai. The MoU was signed for imparting training to Djibouti nationals in sphere of accountancy and working collaboratively for institutionalization of Accountancy Body in Djibouti.

The ICAI signed a Mutual Recognition Agreement with the *Certified Public Accountants, Australia* on February 03, 2009 to recognize the qualification, training of each other and admit the members in good standing by prescribing a bridging mechanism and to increased mobility to professionals at either end.

The ICAI had signed a Memorandum of Understanding with the *Institute of Chartered Accountants in England & Wales* on November 20, 2008 to foster working relations between the two bodies. The MoU provided for mutual Recognition and Examination arrangements for the members of the two largest Institutes of the world.

6.4 Opening up of Chapters Abroad

The ICAI has opened up its 20th Chapter at New York on 24th July '08.

It has also approved formation of its 21st Chapter at Singapore, which is likely to be operationalized soon.

Talks are on for opening up of ICAI Chapter in Ireland & Thailand as well.

6.5 Inbound Delegation

Visit of delegation from AMF France on 2nd April'08

A delegation led by Mr. Hubert Reynier, Managing Director of the Regulatory Policy and International Affairs Division, AMF along with Mr. Patrice Aguesse, Head of Regulation of Financial Disclosures and Corporate Financing, AMF and Mr. Patrick Parent, Deputy Head of Corporate Accounting and Auditing Division, AMF had visited ICAI to interact on the enforcement of accounting standards and auditors oversight in India. Along with Mr. Jitesh Khosla, Joint Secretary, MCA, Ms. Neelam Bhardwaj, General Manager, Division of issues and Listing, SEBI, Mr. Parag Basu, General Manager, Division of issues and Listing, SEBI and Mr. Nitesh Bhati, Manager, Division of issues and Listing, SEBI have also attended the meeting. Information was sought about the terms of reference being signed between AMF and SEBI in February 2008 with an objective to ensure better co-operation and fair and transparent market. Stress was on the common understanding of both economies in relation to the equivalence process with IFRS and IAS.

Visit of Mongolian Accountants for IFRS training on 3rd & 4th April'08

The ICAI and the CPA Mongolia had signed a Memorandum of Discussion on Bilateral Cooperation on 11th September'06, for promoting mutual interest & co-operation between the two institutes and for organizing training program(s) for their Accountants. In pursuance thereof, a two-days training in IFRS was provided by ICAI to their 10 delegates on 3rd & 4th April'08.

Visit of Lord Mayor on 20th-21st April'08

A delegation led by Mr. Alderman David Lewis MA, the Hon Rt. Mayor of the city of London, along with Ian Luder, Sheriff of the city of London, Mr. Martin Hagen, Vice President, ICAEW, Ms. Jane Owen, Director, UK Trade and Investment, Mr. Jeff Glekin, Deputy Head of Mission Mumbai, & Mr. Graham Ward, Chairman, UK side of the Indo UK Accountancy Task Force had visited the ICAI. The meeting focused on fostering bilateral relations between Indian and UK Accounting profession. The delegates sought information on the status of "Limited Liability Partnership Bill", taxation on LLPs, role of Quality Review Board and Rotation of Auditors in Indian context. The ICAI apprised the delegation on the Indian environment in context of the above issues. Further, the current status of on going exercise for MRA between ICAI & ICAEW was discussed.

Visit of delegation from Samara Region, Russia on 2nd May'08

The delegation from the Institute of Professional Accountants Samara Region (SIPA), Russia consisting of Mr. Dmitry Yakovenko, President of the Institute of Professional Accountants of Samara Region; Mr. Yury Bodrov, Member of the Board and Mr. Alexander Shestakov, Assistant to the President visited ICAI. President SIPA gave a brief background about their Institute and desired to utilize the opportunity for the two countries to come together. He informed that they had got support from various countries such as UK, Azerbaijan Republic for the development of Professional Certification Accountants course on IFRS. President ICAI also gave general overview of the accounting profession in India underlining the regulatory framework, accounting standards etc.

SIPA sought assistance from ICAI in the area of Risk Management and Insurance to which ICAI responded that it has developed expertise in these matter and ICAI has a separate Committee and exclusive Post Qualification Courses on the subject.

The possibilities of reciprocal recognition agreement of professional qualification was also discussed in detail, wherein ICAI necessitated the same treatment be given to them as given to CPA America.

Visit of delegation from the Committee of European Securities Regulators on 25th July'08

Mr. Lee Piller and Ms. Marion Bougel from the Committee of European Securities Regulators, had visited the Institute and had visited ICAI. The visit was focused on understanding the Accounting Standards in India and to discuss the issues in Convergence with IFRS in India.

Consultative visit by Kenya Accountants and Secretaries National Examinations Board (KASNEB) on 7th October 2008.

Mr. Lenya Jeremiah M, Examination Officer and Rosemary K A Barasa, Senior Officer Human Resources Management and Administration from Kenya Accountants and Secretaries National Examinations Board (KASNEB) had visited ICAI to consult on the examination matters to be included in their review of the syllabus of ICAI and such other institutions. The review is aimed at ensuring that the examination syllabuses continue to meet market demands and international standards

Visit of delegation from UK's Financial Reporting Council on November 07, 2008

Mr. Paul Boyle, Chief Executive of the UK's FRC had visited ICAI and discussed the role being played by FRC in the regulation of Accountancy profession.

Visit of Mongolian Accountants for IFRS & English training from November 2008 to January 2009.

Subsequent to the visit of Mongolian delegation from the Mongolian Institute of CPAs in April 2008; the ICAI provided English and IFRS training to Mongolian Accountants commencing from 06th November '08 for three months, for which Ambassador of India at Mongolia had requested ICAI. Two more such batches would be undertaken in future.

Visit of Mr. Lyle Handfield, Certified General Accountants Association (CGA) of Canada on 13th April 2009

Mr. Lyle Handfield, Vice-president, International and Corporate Affairs and Mr. Baldev Vice-president, Finance and Administration, Certified General Accountants Association (CGA) of Canada visited ICAI to discuss the bilateral talks between ICAI and CGA Canada for entering into a Mutual Recognition Agreement.

Visit of Delegation from the Canadian Institute of Chartered Accountants from 8th to 10th June 2009

A delegation from the Canadian Institute of Chartered Accountants led by CA Jylan Khalil, Director of CA Qualification along with CA Paule Massicotte, ~~Principal~~ **Principal** of CA Qualification had visited ICAI to discuss in detail, the possibilities of reciprocal recognition agreement of professional qualification between both the Institutes.

Visit of delegation from the American Institute of CPAs June 30, 2009

Mr. Ernie Almonte, Chairman, AICPA visited India from June 30, 2009 to July 04, 2009 to deliver a Keynote Address at the ICAI Diamond Jubilee International Conference in Agra. Coinciding with the visit, meetings with C& AG, CGA, Ministry of Finance and Ministry of Corporate Affairs also took place.

AFRICA DAY CELEBRATIONS

The ICAI and Indo-African Chambers of Commerce and Industry celebrated Africa Day from 18-19 May 2009 at Mumbai. Diplomats from various countries from African Continent congregated to formalize strategy for working towards the growth of the Africa. The diplomats applauded the endeavors of India for development of African continent and expressed confidence for taking forward the productive relationship between India and Africa to new heights.

To mark the augmentation of relationship a Memorandum of Understanding between ICAI and University of Djibouti was signed for imparting training to Djibouti nationals in sphere of accountancy and working collaboratively for institutionalization of Accountancy Body in Djibouti. Hon'ble Shri S C Jamir Governor, Maharashtra, Hon'ble Shri Musalia Mudavadi, Deputy Prime

Minister of Kenya and Shri Jayant Rao Patil, Minister of Home Affairs, Maharashtra Govt. graced the occasion.

Setting up of an International Federation of Accounting Technicians (in line with IFAC)

The ICAI is considering the proposal for setting up International Federation of Accounting Technicians (IFAT) in lines with International Federation of Accountants (IFAC) to promote the profession of Accounting Technician worldwide. The mission of the IFAT is to provide a framework to develop and strengthen the accounting technician profession as a semi-skilled certification through quality accounting education, training, ethical requirements, CPD, disciplinary requirements and professional outreach activities that meet the needs of all the stakeholders worldwide.

Contribution to special groups constituted by the Government of India

The ICAI is actively participating and contributing to special Task Forces, namely Indo UK Accountancy Task Force and Indo UK Task Force on Corporate Affairs constituted under the aegis of the Ministry of Commerce & Industry & the Ministry of Corporate Affairs respectively.

6.6 Conferences

Participation at BRIC Conference

President, ICAI along with the Vice President and Secretary, ICAI addressed the BRIC Forum (Seminar) on 19th May'08 at New York, with a participation of more than 20 senior government officials and leaders of the accountancy profession and regulatory bodies to discuss developments in adopting IFAC's international standards and the challenges. Shri Shankar Narayan, Principal Accountant General (Civil Audit), from the office of Comptroller & Auditor General of India also attended the Big Forum.

Diamond Jubilee International Conference "Chartered Accountancy in Retrospect and Prospect" from July 02-03, 2008

Coinciding with the Diamond Jubilee Celebrations, a two-day Conference on the theme "Chartered Accountancy in Retrospect and Prospect" was held on 2nd and 3rd July, 2008. The Conference was attended by over 1000 members of the Indian Chartered Accountants Community including 50 members from SAFA countries, regulators, and representatives of multi-lateral agencies, International Standards setting bodies, and Accounting bodies from SAARC Region. The ICAI hosted the SAFA Meetings. The Diamond Jubilee Celebrations was inaugurated by the august hands of Hon'ble Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh. Hon'ble Finance Minister of India, Shri P. Chidambaram also joined the Diamond Jubilee Celebrations. Hon'ble Minister of Corporate Affairs, P.C. Gupta and CA. Rahman Khan, Deputy Chairman Rajya Sabha also addressed the audience on 1st July, 2008. The Chief Post Master General had released a Special Cover on this unforgettable occasion.

International Conference on "Accounting Profession - Shining Bridge between Global Economies" was held at Jaipur from 20-22 November 2008

The International Conference on "Accounting Profession- Shining Bridge between Global Economies" was organized by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) from November 20th-22nd, 2008 at Jaipur. The three-day event presented a matchless forum for exchange of ideas amongst renowned accounting experts, international doyens from the field of finance and corporate honchos with the presence of more than 2400 delegates of CA fraternity across the globe. It was a congregation of renowned experts in the area of accounting, auditing and management from International Federation of Accountants (IFAC), Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA), International Accounting Standards Board (IASB) and other international bodies including leaders from Trade and Industry had done the honours in attending the Conference. The Chief Guest Hon'ble Union Minister of Corporate Affairs, Shri Prem Chand Gupta, inaugurated the event. The ICAI hosted the CAPA & SAFA Meetings.

7. OTHER ACTIVITIES

7.1 Human Resource Development

To propel the organization into the next orbit of growth, it is essential for an organization to have sincere, dedicated and competent human resources at its command. Towards this end, the Council not only continued to focus on retaining its high performance work force, but also initiated steps to attract the best and the brightest talent. Recognizing also the fact that training is the backbone for enhancement in the level of competence and personality development, continued emphasis was laid on participation in training programmes, courses organized within and outside the premises of the ICAI.

Aiming at further sharpening the skills and knowledge and also bringing attitudinal changes for providing quality services to members, students and others concerned, various structured training programmes on different topics were organized in the headquarters in Delhi as well as in regional offices.

In its quest to attract the best and the brightest talent, time-scheduled recruitment drives with focus on faculty /academics were successfully undertaken during the last six months of the period under report. The initiatives so undertaken have yielded the desired results in the form of employing 131 more human resources meant for technical/academics and administrative positions in the different areas of the ICAI.

Further, HR Initiatives aiming at grievance redressal, timely counselling, enhanced facility management etc. taken during the period under report include better and quality work environment, weekly departmental meetings, periodic employee counseling, open the month with grievance seeking and hardship mitigating steps.

7.1.1 Constitution of HR & Admin Committee

In order to make available the right kind and number of employees with each one of the Committees of the Council, offices and departments, and to have better administrative procedures of the Institute, the HR & Administration Committee was constituted for the first time in February, 2009. The HR & Admin Committee would aim to: -

1. ensure adequate and qualitative manpower across the Committees of the Council, offices of the Institute at its various locations, regional offices, decentralized offices and branches.
2. constantly analyze requirement of manpower at all levels (Central, Regional & branch levels) based on workload and take steps for recruitment and relocation of personnel.
3. govern and monitor the HR and Administration functions of the Institute.
4. bring about reforms in general administration and personnel management of the Institute.

The first meeting of HR & Admin Committee was held on 25th February 2009 and the Committee has already taken initiatives.

7.1.2 Sub Group of HR & Admin Committee

Sub Group of HR & Admin Committee was constituted on 15th April 2009 in order to take a holistic view of the matters arising from/related to the recommendations of the Sixth Pay Commission for being extended to the employees of the Institute and the financial implications involved-present and foreseeable future.

The first meeting of Sub Group of HR & Admin Committee was held on 10th May 2009.

TRAINING PROGRAMMES - APRIL 2008 ONWARDS

S.No.	Date of Programme	Duration (Days/Hours)	Title	No. of Participants	No. of manhours = (No. of participants X No. of days trained X No. of hours each day)
Head Office					
01.	28.04.08 to 02.05.08	5 days	Orientation Programme for newly joined Management Trainees	50	50 X 5 X 8 = 2000
Kolkata Office					
01.	07.05.08 to 09.05.08 & 12.05.08 to 16.05.08	8 days	Orientation with different departments and personality development	8	8 X 8 X 8 = 512
Kanpur Office					
01.	04.04.08	2 hours	Different Department: Different Roles, by Chairman, CIRC	All Staff	
02.	17.04.08	2 ½ hours	Personal Growth through self exploration, by outside faculty	All staff	
03.	09.04.08 to 12.04.08, 21.04.08 to 25.04.08, 30.04.08 & 12.05.08	15 days	Training Programme for newly joined Management Trainees and Data entry operators	7	15 X 7 X 8 = 840
04.	07.06.08	2 hours	Programme on Different departments: Different Roles (FAQ-CPT-PCC)	All Staff	

7.1.3 Achievements of HR & Admin Committee**Creation of Unique, first of its kind, HR & Admin Committee**

A unique and first of its kind initiative was taken in the year 2009 by forming a new Committee namely, HR & Admin Committee to cater to the specific and specialized needs of the Institute in the area of Human Resources Development. Since its inception, various initiatives were taken and achievements made. To name a few, the following are the significant activities:

Organisational Restructuring

In tune with the modern management concepts, a unique, bold, innovative idea turned into applied Human Engineering was implemented whereby, the Department based functioning of the Institute, was replaced by active, committee based live organization. The results are very encouraging and more importantly tangible and measurable ones. This organizational restructuring has infused a new sense of dynamic, result-oriented, pragmatic, proactive functioning in the Institute.

Creation of Additional Committees

To cope up with the growing needs of the Profession in today's dynamic globalization environment the emerging areas are identified and to protect the interests of the Members and identifying new opportunities, new committees were formed viz.

1. Representation Committee
2. HR & Admin Committee
3. Committee on International Taxation
4. Committee for Small & Medium Practitioners
5. Infrastructure Committee

These additional Committees were formed without any recruitment of additional Human Resources, clearly demonstrates, the unique, creative leadership of the President.

Empowerment of Executives

To nurture and develop young talents, and to infuse new thoughts and innovative ideas, nevertheless to synchronize them with the experienced top management, to create a second line of leadership, a new, bold initiative was taken to place young Chartered Accountants in the position of Secretaries to various committees which has already shown remarkable results.

Manpower Planning

A unique programme for manpower planning taking into consideration various specific needs of various departments and Committees was initiated and accordingly, the action plan has been drawn out to meet the requirement.

Identification and redeployment of surplus manpower

Special emphasis was laid to identify the redundant and surplus manpower available and they have been gainfully reemployed for the benefit of individual in particular and Institute in general.

Selection and Placement

Special recruitment drives were conducted to meet the extra manpower requirements for various Directorate/s and Committee/s.

Right-sizing of Manpower

Lean Management concepts are converted into Action Plans by identifying and pruning unnecessary span of controls in HR as part of cost control leading to better financial management.

Better quality of work life

Initiatives were taken to improve the morale and job satisfaction of officials by positioning them in their functional areas of interest in employment.

Training and Development

Several initiatives were taken to conduct various training programmes during the second quarter and an action plan along with a training calendar is made ready for execution.

Feel good and sense of belongingness

The novel initiative of Dress Code among officials of the Institute has been introduced to create a sense of belongingness apart from feel good attitude, in tune with the modern corporate sector.

New department to cater to Accounting Technician Course

A new department has been created to position and market the Accounting Technician Course through creative public relation management.

Conventional Corporate Communication

Breaking away from the shackles of the conventional pattern, a novel, creative and "keep in touch directly" — a concept was launched by the President, to enable all the officials of the Institute to contact, communicate and implement plans into Action directly with President any day, any time,

24X7 has resulted in expediting approvals, instant decision making result oriented “Efficient, Effective, Enterprising Leadership”.

7.1.4 Administration Area

Procurement of Diesel Generator Set for ITT labs/ branches

In line with the approval of the competent authority of the Institute, till date orders for 68 nos. of DG Sets of various capacities as per the requirement have been placed for different ITT labs set up through branches including one 500 KVA DG set to Centre of Excellence, Hyderabad for uninterrupted back up power. In most of the locations, installation and commissioning work has been completed and DG sets have been put to use. The balance locations is expected to be operational by end of July 2009. Further, it has been proposed to provide DG sets at ITT labs being set up/ to be set up in CPE chapters of the Institute and same is under consideration of the competent authority.

Foundation stone laying ceremony of Centre of Excellence at Jaipur

Foundation stone of the Institute's Centre of Excellence at Jaipur was laid by the then Union Minister of Corporate Affairs in presence of the Chief Guest, the then Chief Minister of Rajasthan on 11.09.2009. The proposed campus will be of residential type and will be spread over a land of 25 acres. The selection of architect has been finalized and selection of contractor is under process.

Inauguration of ICAI National Service Scheme

ICAI National Service Scheme was launched on 27.01.2009 in the presence of Ms Arti Mehra, Mayor of Municipal Corporation of Delhi by inaugurating the plantation/flower bed planted in Jawahar Marg in front of Gandhi Darshan. The maintenance of the plantation is being done by the Institute.

Inauguration of Centre of Excellence, Hyderabad

The premise of Centre of Excellence at Hyderabad (Institutional block) was inaugurated on 31.01.2009 and its residential block was inaugurated on 2.7.2009. The campus has been built over a land of 2.82 acres.

Implementation of uniform dress code for the employees of the Institute

Use of uniform dress code for the employees of the Institute at head office, regional offices and branches has been implemented.

Inauguration of Accountancy Museum

The Accountancy Museum having rare and historic images like oldest balance sheet and documentary evidence of the evolution of accountancy was inaugurated at Institute's premises at C-1, Sector-1, Noida on 2.02.2009. Items like minutes of Indian Accountancy Board, First Annual Report of Council, Institute's own 1st balance sheet etc. have been kept for display. There is no entry fee for visiting the museum. Recognition/ permission has been given by the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India for use the name of the museum as Accountancy Museum of India vide their letter dated 30.04.2009.

Installation of Access control systems

Access control systems at head office has been installed and made operational. The same facility will be implemented in Regional offices also shortly.

Introduction of Policy on Accounting of Consumption of Store Items

With a view to lay down guidelines for proper accounting of consumption of store items received by Departments/ Sections from HO/Other Stores or procured directly by any Department/ Section, a

Policy on Accounting of Consumption of Store Items was put in place. This Policy is required to assure the authorities that the items are used for the purpose they were procured and in line with the broad aims of the organization. This policy is likely to further ensure that organization gets the best output from the funds being spent.

Celebrations of Chartered Accountants Day

The Institute's flag was hosted by the President in the head office of the Institute on this auspicious occasion and the President garlanded the statue of Late G.P. Kapadia, the first President of the Institute.

Inauguration of Administrative block of ICAI Complex at plot no A-29, Sector- 62, Noida.

On the occasion of celebration of CA Day, the Administrative block of ICAI Complex at plot no A-29, Sector-62, Noida was inaugurated by the President, ICAI on 1st July, 2009 in presence of Mr. Ernest A. Almonte, President, American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) and Vice-President, ICAI.

.....THE MARCH IS ON.....

It is not a period to allow the complacency to set in, but to look forward and march on, surpassing every standards already set. We believe, success and excellence is not just an event but a way of life. In this direction, the concerns in the following core functional areas of Human resources will be taken up keeping in view to have a better quality of work life and to create a favourable knowledge management environment:

- Service Rules
- Recruitment Rules
- Transfer Policy
- Purchase Policy
- Weeding out/Disposal Policy

....."EXCEEDING EXPECTATIONS" - HR - ADMIN COMMITTEE."

7.2 Audit Committee

7.2.1 Significant Achievements

- Appointments of Statutory and Internal auditors of Headquarter, Regional Offices and Decentralized Offices and revision of their audit fees.
- Implementation of revised criterion with regard to appointment of statutory and internal auditors of various Branches, Regional Offices, Decentralised Offices and Head Office.
- Procedure for processing payment to observers directly by Examination Department instead of routing through Accounts Department.
- Follow up for updation of Fixed Assets Register at Head Office and its reconciliation.
- Audit of accounts of printer of ICAI Journal and recovery of due amounts.
- Follow up for Reconciliation of Head Office accounts with Regional Councils/Branches.
- Analysis of Branch Accounts and auditor reports for the year ended 31st March, 2008 and 31st March, 2009.
- Review of the reports received from various regions and of the observations of the Internal Auditors made and preparation of Gist for the Audit Committee.
- Review of scope of work of the Internal Auditors including departments/non-standing committees and their reporting structure made to ensure fullness of internal control mechanism and uniform practice.
- Closure of Inoperative Bank accounts at Regional Councils and DCOs.
- Write back of old Library Deposits at Regional Councils.
- Regulating the Investment of Funds and Reviewing the Investment guidelines of the Institute.

- Follow up for convening the Regional Audit Committee meetings every quarter.
- Analysis of stale cheques and its write back.
- Processing of document on Delegation of Powers.
- Discussions held with Statutory & Internal Auditors before finalization of accounts.
- Review of the reports received from various regions and observations of Internal Auditors noted for adherence to the laid down policies of ICAI.
- Preparing of guidelines to strengthen the Internal Control Mechanism.
- Steps are underway to further strengthen the security of the IT system in the context of present day IT environment.

7.2.2 Initiatives

- Appointment of Internal Auditors of the branches and DCOs having membership strength of more than 1000 members introduced.
- To streamline the process of appointment of Auditors and making it more transparent by preparation and maintenance of panel of auditors.
- To further streamline and strengthen the Internal Control Mechanism of ICAI Headquarter, a draft internal control document prepared and circulated to all the user departments/non-standing committees, Regional offices and Decentralized Offices.
- Initiative has been taken to provide training on Accounts module to employees at Branches.
- Physical verification of Fixed Assets is being carried out.
- Process to identify the major departments is being done for the purpose of proper Delegation of Authority.
- Process of issuing guidelines regarding the scope of Audit to all Regional Councils is being carried out.

7.3 Financial Reporting Review Board

The ICAI, continuing with its endeavours to improve the financial reporting practices in the country, has constituted the Financial Reporting Review Board (FRRB). The FRRB reviews the General Purpose Financial Statements of various enterprises and the auditors' report thereon either suo motto or on a reference made to it by any regulatory body(ies) or where serious accounting irregularities have been highlighted by the media reports with a view to determine, to the extent possible:

- a) Compliance with the generally accepted accounting principles in the preparation and presentation of the financial statements;
- b) Compliance with the disclosure requirements prescribed by the regulatory bodies, statutes and rules and regulations relevant to the enterprise; and
- c) Compliance with the reporting obligation of the enterprise as well as the auditors.

As per the Operating Procedures of the FRRB, the Board is assisted by Technical Reviewers and Financial Reporting Review Groups in review of the General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon. The preliminary review of the General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon selected for review is conducted by the Technical Reviewers selected from the panel maintained by the Board. Preliminary review reports of Technical Reviewers on review of the General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon are considered and finalised by Financial Reporting Review Groups before the same are finally examined by the Board.

7.3.1 Review of General Purpose financial statements and auditors' report thereon

Suo Motto

- The General Purpose Financial Statements and auditors' reports thereon relating to the financial year 2007-08 of 100 companies has been selected by the Board during the Council Year 2009-10 and review process of the same have been commenced.

- The General Purpose Financial Statements and auditor's reports thereon relating to the financial year 2006-07 of 54 companies were selected by the Board for review during the Council Year 2008-09 and out of these 54 Companies the Board has considered 26 reports.
- The General Purpose Financial Statements and auditors' reports thereon relating to the financial year 2005-06 of 61 companies were selected by the Board for review during the Council Year 2007-08 and out of these 61 companies, the Board has considered 50 reports.
- The General Purpose Financial Statements and auditors' reports thereon relating to the financial year 2004-05 of 53 companies were selected by the Board for review during the Council Year 2006-07. Out of these 53 companies, 42 reports have been considered by the Board.

The General Purpose Financial Statements relating to the financial years 2004-05, 2005-06 and 2006-07 have become quite old in the present day context, therefore, the Board decided not to continue the review of these old financial statements. Accordingly, the reviews of General Purpose Financial Statements of remaining 50 companies relating to the financial years 2004-05, 2005-06 and 2006-07 were discontinued which was either to be considered by Financial Reporting Review Groups or they were still pending with the Technical Reviewers and in respect of which the reports were not received till that date.

7.3.2 Special Cases

Satyam Computer Services Ltd.

As the gross irregularities in the accounts of Satyam Computer Services Ltd. had been revealed by none other than Chairman of the Company in January 2009. Therefore Financial Reporting Review Board decided to undertake the review of the general purpose financial statements of Satyam Computer Services Ltd. and the auditors' report thereon as a special case.

Considering the seriousness of the matter the following initiatives were taken by the Board.

- Generally the Board reviews the general-purpose financial statements of an enterprise only for a single year. However, considering the gravity of situation, the FRRB decided to review the general purpose financial statements and the auditor's report thereon for the five financial years from financial year 2003-04 to financial year 2007-08.
- Normally such a review is conducted by a Chartered Accountant who is empanelled with FRRB. However, in order to ensure effective review with high standard, the Board decided to appoint a Panel of three Reviewers who are senior, experienced and well reputed members of the Institute.

Accordingly, the Panel of Reviewers has been appointed and they have completed the review of five years' general purpose financial statements of Satyam Computer Services Ltd. Their report is expected to be submitted at the earliest.

Other Special Cases

- Since media has reported serious accounting irregularities in the Financial Statements of Maytas Infra Limited, therefore, the Board has also undertaken the review of the Financial Statements of Maytas Infra Limited.
- As a pro-active measure, 50 enterprises have been selected on random basis wherein the Independent Directors have resigned in the Post- Satyam period for review and review process of the same has been commenced.

7.3.3 Constitution of Financial Reporting Review Groups

The Board constituted sixteen and nine Financial Reporting Review Groups for the Council Years 2008-09 and 2009-10 respectively for consideration and finalisation of the preliminary review reports

submitted by the Technical Reviewers on General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon in the respective years.

7.3.4 Publications

With a view to apprise the members of the ICAI and others concerned about the major non-compliances observed during the review, the Board compiles such non-compliances from time to time and publishes the same in the Journal of the ICAI. Articles on non-compliances under the title 'Enhancing Audit Quality' were published in the Institute's Journal, 'The Chartered Accountant', in the issues of December 2008, January, February, June and July 2009.

In order to enhance the knowledge of preparers of the financial statements and auditors the Board has also decided to publish 'A Study on Compliance of Financial Reporting Requirements' containing pertinent observations of the Board on compliance aspects of various Financial Reporting Requirements in context of the applicable Accounting / Auditing Standards and Guidance Notes as well as relevant Laws and Statutes. This study includes the observations of the Board made during the review of the general purpose financial statements relating to the financial years from 2002-03 to 2006-07.

7.3.5 Conduct of Training Programmes/Workshops

With an objective to augment the strength of number of Technical Reviewers empanelled with the Board and to improve the overall financial reporting review skills of the members and to acquaint them with major non-compliances, the Board organises the One day Seminars/ Training Programmes on regular basis. One Day Seminar on Corporate Disclosure was organized on October 18, 2008 at Coimbatore. One Day Training Programmes were also organised on September 5, 2008 at Kolkata and on June 13, 2009 at Chennai. At present, the Board has empanelled 170 members as Technical Reviewers.

7.4 Internal Audit Standards Board

The traditional internal audit model has been transaction-based and cost-driven. Today, internal audit is undergoing significant changes in migrating from a reactive, historically-focused function to a proactive group that takes a risk based focus. Internal audit function is being looked upon to assume a leadership role in assessing and managing their strategic risks, adding value to the organization and identifying operational improvement opportunity.

Despite being given to work in multi disciplinary internal audit teams, chartered accountants have created a niche of their own in this area. To maintain that niche, it would be necessary for the chartered accountants to periodically assess their knowledge and skill up gradation requirements and undertake such up gradation regularly. The Institute, therefore, sought to provide resources relating to the profession of internal auditing with a view to promote the profession as well as its role in the success of an organisation. Accordingly, the Institute had constituted a non-standing Committee, Committee on Internal Audit on 5th February 2004. The Committee was renamed as "*Internal Audit Standards Board*" in November 2008. The objective of the Board is to review the existing internal practices in India and develop Standards on Internal Audit, Guidance Notes and undertake the research in the field of internal audit.

Standards on Internal Audit

During the period, the Internal Audit Standards Board has issued 13 Standards on Internal Audit in addition to the Framework for Standards on Internal Audit, which are as follows:

Framework for Standards on Internal Audit

The Framework for Standards on Internal Audit provides a frame of reference for the internal audit standards being issued by the Institute. The objective of the Framework is to promote the

professionalism in the internal audit activity. The Framework comprises of four components viz., the Code of Conduct, the Competence Framework, the Body of Standards and the Technical Guidance.

“Reporting”

The purpose of the Standard on Internal Audit (SIA) 4, Reporting is to establish standards on the form and content of the internal auditor's report issued as a result of the internal audit performed by an internal auditor of the systems, processes, controls including the items of financial statements of an entity.

SIA 5, “Sampling”

The Standard on Internal Audit (SIA) 5, Sampling provides guidance regarding the design and selection of an audit sample and also on the use of the audit sampling in the internal audit engagements. This SIA also deals with the evaluation of the sample results.

SIA 6, “Analytical Procedures”

The Standard on Internal Audit (SIA) 6, Analytical Procedures provides guidance regarding the application of analytical procedures during internal audit.

SIA 7, “Quality Assurance in Internal Audit”

The Standard on Internal Audit (SIA) 7, Quality Assurance in Internal Audit establishes standards and provides guidance regarding quality assurance in internal audit. This Standard also provides extensive knowledge about the internal quality reviews, external quality reviews and communicating the results thereof.

SIA 8, “Terms of Internal Audit Engagement”

This Standard on Internal Audit (SIA) 8, Terms of Internal Audit Engagement provides guidance in respect of terms of engagement of the internal audit activity whether carried out in house or by an external agency. This SIA describes the elements of the terms of engagement viz, scope, responsibility, authority, confidentiality, limitations, reporting, compensation and compliance with Standards.

SIA 9, “Communication with Management”

The Standard on Internal Audit (SIA) 9, Communication with Management provides a framework for the internal auditor's communication with management. It identifies some specific matters to be communicated with the management as described in the terms of engagement.

SIA 10, “Internal Audit Evidence”

This Standard explains the concept of sufficient appropriate internal audit evidence, procedures to be performed to obtain internal audit evidence namely, inspection, observation, inquiry and confirmation, computation and analytical review.

SIA 11, “Consideration of Fraud in an Internal Audit”

This Standard provides guidance on the designing and implementation of the internal controls in an entity that would also help the internal audit to assess the risks of frauds. The Standards also establishes the responsibilities of the internal auditor relating to the fraud prevention and detection. The SIA also provides guidance regarding communication and documentation of fraud.

SIA 12, "Internal Control Evaluation"

The Standard extensively deals with aspects such as meaning and inherent limitations of internal controls, control environment, risk assessment, tests of control and communication of weaknesses. The SIA also describes role of the internal auditor in evaluating internal controls.

SIA 13, "Enterprise Risk Management"

The Standard establishes process of enterprise risk management and the role of the internal auditor. This Standard also provides guidance regarding the internal audit plan and information which internal auditor should provide in his report.

SIA 14, "Internal Audit in an Information Technology Environment"

This Standard describes skills and competence needed by the internal auditor to conduct an internal audit in an information technology environment, factors to consider while planning such an internal audit, matters that may affect audit in an IT environment, assessment of risk, audit procedures, review of the IT environment and documentation.

SIA 15, "Knowledge of the Entity and Its Environment"

This Standard also sets out guidelines regarding the application, usage and documentation of knowledge of the entity by the internal auditor.

SIA 16, "Using the Work of an Expert"

The Standard explains situations in which the need for using the work of an expert might arise, factors to consider when deciding whether to use the work of an expert or not, evaluating the skills and competence and objectivity of an expert, procedures for evaluating the work of an expert, references to an expert in the internal auditor's report, etc.

Compendium of Standards on Internal Audit (As on February 3, 2009)

- The Internal Audit Standards Board has codified the best practices for internal audit as Standards on Internal Audit. With a view to provide ease of reference and availability of all the Standards issued till date as well as Framework and the Preface at one place, the Board has issued Compendium of Standards on Internal Audit.

In addition to it, the Board has also issued the Exposure Draft of proposed Standard on Internal Audit, *Consideration of Laws and Regulations in an Internal Audit*. The Board has also undertaken the project to formulate Standard on Internal Audit, *Monitoring Progress*.

7.4.1 Technical Guides:

In addition to bringing out Standards, the Board is also working aggressively on formulating industry specific guidelines on internal audit.

During the period, the Internal Audit Standards Board has issued the following Technical Guides:

Technical Guide on Internal Audit in Telecommunications Industry This Guide has been issued to provide an in-depth understanding of the business culture, systems, and processes in the telecommunications industry. It would help the readers in understanding the various technicalities arising during the internal audit in a telecom company.

Technical Guide on Internal Audit of Stock Brokers

This Guide has been issued by the Board to provide guidance in understanding the intricacies of the stock broking entity and thereby enabling in discharge of onerous responsibilities with utmost efficiency by the internal auditor.

Technical Guide on Internal Audit of Intangible Assets

This Guide highlights the role that the internal audit function can play in efficient and effective management of intangible assets. It covers in details all aspects relevant to internal audit of intangible assets. In addition to it, the Board has also undertaken the projects relating to formulation of Technical Guides on Internal Audit of following industries/ segments:

1. Non-profit Organisations
2. Treasury Functions in Banks
3. Infrastructure
4. Municipalities and Local Bodies
5. Educational Institution
6. IT BPO
7. Software Development
8. Petrochemicals
9. Mining and Extraction- Coal, Iron, Steel and Aluminium Industries
10. Risk Management Process of the Entity, etc

7.4.2 General Guides:

The Board has issued during the year *Guide to Implementing Enterprise Risk Management* which provides guidance on the essentials of implementing an ERM system in an organisation. It provides, in a simple manner, a step by step approach to implementing ERM Framework as also issues that would be faced during implementation. The Board has also issued the *Manual on Concurrent Audit of Banks* that describes almost all critical aspects in concurrent audit of banks.

The Internal Audit Standards Board has issued first of its kind *Manual on Internal Audit* which contains a step by step approach to conduct internal audit, right from appointment to reporting. It also deals with conceptual as well as practical approach to internal audit.

The Board has also brought out *Training Material on Internal Audit* to expand the knowledge base of the members in the field of internal audit. The Training Material is intended to serve as a source material to be used by the participants at the training programme.

Other ongoing projects of the Board are as follows:

- (a) Implementation Guide to SIA 7, *Quality Assurance in Internal Audit*
- (b) Implementation Guide to SIA 4, *Reporting*
- (c) Study on Role of Internal Audit in Achieving Basel II Compliance
- (d) Study on Role of Internal Audit in Quarterly Financial Reporting, Disclosures and Management Certifications
- (e) Study on Role of Internal Audit in the Risk Management Process of the Entity
- (f) Study on Relationship of Internal Auditor with Audit Committee

7.4.3 Conferences and Other Programmes

With a view to create awareness about the latest developments in the field of internal audit, the Board has organised following seminars, conferences, workshops, etc in association with the Regional Councils and their branches:

- (a) Management Development Programme on Risk Management in Public Sector at New Delhi
- (b) Conclave on Internal Audit at New Delhi
- (c) All India Conference on Internal Audit at New Delhi
- (d) National Diamond Jubilee Conference on Internal Audit, *Role of Internal Auditing in the Times of Economic Challenges* at Pune
- (e) Diamond Jubilee All India Conference, *Winds of Change- Challenges to the Profession* at Kolkata
- (f) National Conclave on IFRS and Internal Audit at Bangalore
- (g) Seminar on Internal Audit of Stock Brokers at Mumbai
- (h) Seminar on Internal Audit at Hyderabad
- (i) National Seminar on Internal Audit at Patna

7.4.4 Courses

The Board has started the *Certificate Course on Enterprise Risk Management* on June 6, 2009 at New Delhi. The objectives of starting this course is to impart the necessary technical knowledge and expertise and build upon the skill sets of the members of the Institute, thereby assisting them to play a leading role in various aspects of Enterprise Risk Management and develop it as an area of core competence. The participants of the course are working in areas related to internal audit, enterprise risk management, corporate governance in various sectors of the economy.

Having regard to the professional and personal preoccupations of the participants, the Course is designed as a balanced mix of class room teaching, e-learning as well as self study. The class room teaching would be completed over a 6 week class room time framework with classes being held on six Saturdays.

In due course, the Internal Audit Standards Board will start the Course at Mumbai, Chennai, Kolkata and Hyderabad.

7.4.5 Others

The Board had also decided to issue Brochure "*What is an Internal Audit*" highlighting the evolving needs of modern organisations and the changing role of internal audit function.

7.5 Committee on International Taxation

The Committee on International Taxation was formed for the first time on 5th February, 2009.

7.5.1 Notes/ Matters/ Activities

1. ICAI has become corporate member of International Fiscal Association.
2. Suggestions relating to International Taxation were included in the Pre-Budget Memorandum, 2009 submitted to the Government on 26th May, 2009.
3. First batch of the Certificate Course on International Taxation organized by the Committee in Mumbai.
4. The Second batch of the Certificate Course on International Taxation is currently running in Hyderabad.
5. The Committee is in the process of getting the Study Material for the Certificate Course on International Taxation prepared by experts.
6. Efforts are made to develop e-learning course for the benefit of members in areas other than metropolitan cities.

7.6 Ethical Standards Board

Ethics is the foundation of a civilized society, and is a preliminary requirement of what a civilized person expects from another civilized person. The recent spate of events in the corporate world has highlighted the importance of ethics in business and profession. A business or profession that lacks the compliance of ethics is bound to fail sooner or later.

Every institution, be it political, business or professional, must therefore have a system for compliance of ethical standards to the extent as may be acceptable to the public at large. Accordingly, it is imperative for the members of any profession to comply with the ethics in its letter and spirit.

With this vision, the Ethical Standards Board of the Institute was formed, having primary responsibility to formulate principles of Ethics for its members that are stringent enough to guarantee the confidence building in the public. The mission of the Board is "To work towards evolving a dynamic and contemporary Code of Ethics and ethical behaviour for members while retaining the long cherished ideals of 'excellence, independence, integrity' as also to protect the dignity and interests of the members".

Besides formulating ethical principles for members, the Board also examines and renders advice on ethical issues referred to it. It reviews the 'Code of Ethics' for members from time to time, and publishes the revised editions. The other publications of the Board, namely, 'FAQ on Ethical Issues', 'Guidance Note on Independence of Auditors' and 'Guidance Note on Revision of the Audit Report' are also reviewed and revised from time to time. The Board promotes public awareness and confidence in the integrity, objectivity, competence and professionalism of members. It also examines and deals with the complaints of members against their unjustified removal as auditors of an entity, as per procedure evolved, and takes necessary steps to protect the interest of its members.

7.6.1 Important decisions on various issues

- The Code of Ethics -2009 was released on 4th February, 2009. The revised Code of Ethics for the first time incorporated the International Federation of Accountants (IFAC) Code of Ethics for professional accountants with variances, wherever required, to make it compatible with Indian laws.
- Advertisement Guidelines issued on 14th May, 2008 for the members in practice to allow them to advertise in a restricted way through a write-up.
- Council General Guidelines, 2008 issued on 8th August, 2008 on various issues e.g. Maintenance of Books of Account, Tax Audit Assignments under I.T. Act, 1961, Specified Number of Audit Assignments etc.
- Members in practice are allowed to own agricultural land and carry out agricultural activity under general permission under Appendix (9) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.
- Members of the Council, the Chairman/Vice-Chairman of the Committees of the Council, the Members of the of the Regional Councils and Members of the Managing Committees of Branches may print either their residential address or office address including telephone/fax no. without mentioning the firm's name on the back of the visiting cards.
- Management Consultancy Companies floated by Practicing Chartered Accountants can receive remuneration from an employer based on percentage of the annual CTC of the candidate while providing services relating to recruitment or placement of such candidate as only clauses (6) & (7) of Part I of First Schedule of are applicable to such companies. Individual practicing Chartered Accountants or their firms are not permitted for the same as per the provisions of Clause (10) of part I of the First Schedule of the CA Act.
- Member who is in practice can not use the designation of 'District Governor' in his rotary visiting card along with the word 'Chartered Accountant (In view Section 7 of the Act and Clause (7) of Part I of the First Schedule to the Act).
- It is not permissible for a Member of ICAI who is practicing as an Advocate, to use CA Logo on his professional stationary as the CA Logo is recognized as a symbol of CA Profession in India and it is to promote the brand of Profession of Chartered Accountants.
- Based on an ethical point of view the CA Director of a Company should not participate in board meeting and withdraw himself when the item relating to his client(s) is considered by the Board
- Members from industry as well as from practice can pursue the AMFI (Association of Mutual Funds in India) Course. However, as to the question whether a member can be registered with it so as to take the role of Financial Intermediary, the Board decided that, members from Industry/ otherwise not in practice can obtain the membership by registering them with a mutual fund / Association whereas members in practice can not do so whether holding full time COP or Part time COP.
- Engagement by a member in practice, in the business of buying and selling shares amounts to be 'any business' within the meaning of Clause (11) of Part I of the First Schedule and hence the prior permission of the Council is required.
- It is prohibitive to undertake the assignments of Internal Audit of a client and entry of the transaction for Accounting, simultaneously being violative of the provisions of the 'Guidance Note on Independence of Auditors'
- Concurrent audit and the assignment of Quarterly review of the same entity cannot be taken simultaneously as the concurrent audit being a kind of internal audit and the quarterly review being a kind of Statutory audit undertaken simultaneously are prohibited under the provisions of 'Guidance Note on Independence of Auditors'.

- Publishing a book by a firm containing its history for the purpose of distributing to clients, associates, friends and well wishers and printing of the words 'Celebrating 75 years in the Profession' on special letterheads and envelopes of the firm will lead to solicitation of professional work, hence not permissible as per the provisions of Clause (6) and (7) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949.
- Member is not permitted to use his letterhead containing the name and address of his firm for presenting before the public at large, as it contains a promotional element and leads to solicitation of professional work.

7.6.2 Significant Initiatives by the Board

- Examination of changes required to be made in The Chartered Accountants Act, 1949 due to provisions of Limited Liability Partnership Act, 2008.
- Finalisation of Guidelines/Modalities on Multi Disciplinary Partnerships (MDPs) due to amendments in The Chartered Accountants Act, 1949 and The Chartered Accountants Regulations, 1988.
- Bring awareness among members on Ethics.
- Revision of "FAQ on Ethical Issues".
- Revision of "Guidance Note on Independence of Auditors"

7.7 Vision Committee

Vision Committee of ICAI, established in the year 2007 has completed first of its milestones and issued Pilot Vision Document, 2021 setting out Vision for the profession as a whole, members in service, members in practice, students and the Institute. Following on the recommendation made in this document to work on shorter term time frame of 3 -5 years for developing action plan, the Committee is now in the next stage where it has taken up the task of developing Vision Statements for shorter, reasonably foreseeable period of 3 years coinciding with the Council Term. This will ultimately lead to setting more current and realistic goals after making mid course corrections based on the fast changing economic scenario ultimately leading to achievement of the goals set out for 2021. This Vision Statement once approved by the Council will become the directional document for the leadership of the Council, Council, its committees and all its organs including staff.

In the year 2008-09, the Committee:

- 1) Engaged a Research Agency and conducted in depth research study to identify the key success factors for leadership and success in the third decade of the millennium and finally developed 'Vision Statement 2021' which has been approved by the Council in its 276th Meeting held in February 2008.
- 2) Developed conceptual Discussion Draft for the Committee to formulate the Committee's Business plan for the Vision Document.
- 3) Presented Pilot Vision Document with Restructuring framework to the Council in its 283rd Meeting held in December 2008 which is approved by the Council.

In the year 2009-10, the Committee commenced its work with a open discussion session with Regional and Branch Office Bearers and obtained responses to a Questionnaire developed after considering the findings of the above stated Research Agency. The next step identified by the Committee is to hold Vision Workshops in different regions. These are planned as focus group discussion sessions with specific subjects like potential areas where services of CAs will be required in near future, what are the expectations from members, competency areas, etc as focus of discussion. The participants are past Presidents, Past Central Council Members, Past Regional Council Chairman and Past Regional Council Members and members serving at senior positions in businesses or members who have established businesses. The objective is to obtain their views from different geographies and different levels of development and perspectives considering the diversity of India.

Three Workshops are held so far and three more are planned.

7.8 Committee for Small and Medium Practitioners

Having regard to the large number of Small and Medium Practitioners in this country, the Committee for Small and Medium Practitioners has been constituted for the first time in the year 2009-10 with the main objective to provide adequate training and infrastructure to improve their practice profile and service the clients in a better and efficient manner. The Terms of Reference of the Committee are reproduced below:

“The primary objective of the Committee for Small and Medium Practitioners is to implement an action - oriented framework to empower small and medium practitioners to assimilate and apply in actual real life work situations the technical literature, methodologies and capacity building models formulated, devised and conceptualized by other committees of the Institute of Chartered Accountants of India. The terms of reference of the Committee are as under:

- Developing ways and means to assist Small and Medium Practitioners to manage practice in efficient manner.
- Strengthening networking rules to rejuvenate the practice portfolio of Small and Medium Practitioners
- Assisting Small and Medium Practitioners in identifying new and exclusive areas of practice
- Developing and issue guidance relevant to practice areas of Small and Medium Practitioners
- Empowering Small and Medium Practitioners to apply technical standards in an efficient manner
- Assisting Small and Medium Practitioners in improving their visibility amongst the business community by organizing programme in association with Chambers of Commerce
- Creating awareness amongst Small and Medium Practitioners about the accounting, auditing and ethical standards through workshops, symposia etc.
- Any other matter with the permission of the Council.”

The Committee intends to undertake the in-depth survey of SMPs to identify their needs and work out ways and means to provide adequate support in all areas of professional practice. The Committee intends to strengthen the practice portfolio of SMPs by developing new areas of specialization such as non-company law related certification, valuation, forensic etc. The Committee is also planning to conduct crash courses at branch level for educating the SMPs in new upcoming areas.

7.9 Representation Committee

The Representation Committee was set up for the first time on 5th February, 2009 as a non-standing Committee. Often one has come across situations where members from different Committees on different occasions have been representing the Institute on various issues before various Governments, authorities and regulators, resultantly the same authority/regulator is approached by different set of members from ICAI itself on different occasions and at times on the same issues. In order to address the issue, the President constituted the Representation Committee so that it can take up any issue which comes to its attention for being represented before any Authority/Regulator. This Committee has facilitated bringing of all such issues to be addressed at one place and has provided one point of communication on behalf of the Institute.

Since formation of the Committee, following representations have so far been made:

- Reserve Bank of India, Mumbai opposing autonomy given to banks to appoint auditors.
- Insurance Institute of India, Mumbai seeking exemption in their Licentiate, Associateship and Fellowship papers for members of the ICAI.
- The Department of Commercial Tax, Government of Uttar Pradesh seeking clarifications under Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 and VAT audit provision under the Act and also seeking general extension to obtain and submit the Audit Report till 30th June 2009.

- The Charity Commissioner (Maharashtra State), Mumbai Request for allowing Chartered Accountants to appear in matters pertaining to registration of societies and registration of trusts.
- The Chief Minister of Goa for introduction of Double entry and Accrual Based Accounting System for Goa Government.
- The Controller of Certifying Authorities, Department of Information Technology, Government of India for empanelment of Auditors for auditing infrastructure of Certifying Authorities.
- The Central Board of Direct Taxes seeking clarification regarding new Form No.17.
- The Central Board of Direct Taxes on undue hardship faced by assesseees on account of delay of refund in scrutiny cases in respect of A.Y. 2007-08.
- Andaman & Nicobar Islands Khadi & Village Industries Board asking them to amend their quotation notice for preparation, re-casting and auditing of the Budgetary Resources Account and Consortium Bank Credit Account, and bring the same in line with the Code of Ethics.
- Ministry of Finance, Government of Maharashtra and the Commissioner of Sales Tax (Maharashtra State), Mumbai regarding violation in the matter of VAT & CST Registration Certificate of Dealers in Maharashtra.
- Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India for empowerment of visually challenged Chartered Accountants by mandating their employment in government sector in finance and accounts areas.
- All Chief Ministers suggesting introduction of Double Entry Accrual based Accounting system.
- Reserve Bank of India requesting them to provide updated list of districts to ICAI for Bank Branch Auditors Panel.
- The Law & Judiciary Department, Government of Maharashtra, Mumbai suggesting introduction of Amnesty Scheme and on-line system for compliances/registration of documents with the office of the Registrar of Firms, Maharashtra, Mumbai.
- Central Board of Excise & Customs proposing nomination of Chartered Accountants u/s 14A and 14AA of the Central Excise Act, 1944 for special audit.
- Comptroller & Auditor General of India regarding differential audit fee of Public sector and Private sector.
- The Ministry of Information Technology & Communications Government of India seeking extension of time to submit the Annual Performance Report (APR) to the STPI.
- Chief Finance & Account Officer regarding Audit of schemes under Madhyan Bhojan Pradhikaran.
- The Central Board of Direct Taxes on genuine hardships and practical difficulties faced in getting a Certificate for lower deduction or non-deduction of tax at source.
- The Central Board of Direct Taxes on hardships and practical difficulties likely to arise in the filing of Income tax Returns for A.Y. 2009-10 with respect to the directions given in the CBDT Circular No. 03/2009 dated 21-05-2009.
- Reserve Bank of India regarding Remuneration for Concurrent Audit of Banks.

7.10 Infrastructure Committee

The Infrastructure Committee is a newly constituted Committee approved by the Council at its 286th Meeting held on 7th March 2009. The Terms of Reference of the Committee are as under :

1. Maintenance of the existing land and institutional buildings of the Institute, Regional Councils and its branches, and chapters abroad.
2. Acquiring of land and building for the Centres of Excellence/Regional Councils/Branches across the country and chapters abroad.
3. Laying down of policy guidelines on minimum infrastructure facilities for Regional Councils/Branches/Chapters acquiring new land and institutional buildings.
4. Adding of value to the existing institutional buildings by upgradation and additional infrastructure facilities.
5. Administering and maintenance of original documents in respect of land and institutional buildings under the applicable statutes.
6. Ensuring of adequacy and quality of all capital assets for the Institute, Regional Councils, its branches, Centres of Excellence and Chapters abroad.
7. Analyzing of requirements of capital asset and taking necessary steps.

8. Ensuring of uniformity and standardisation of buildings of the Institute.
9. Any other tasks/function that may be assigned by the Council/President.

The Infrastructure Committee has held two meetings on 25th February 09 and 11th May 09 at New Delhi and considered the various issues pertaining to the infrastructure development for the Institute / Regional Council and its branches / chapters across the Country.

7.10.1 Significant achievements of the Committee are as under.

A. Centre of Excellence

The Institute has acquired land for Centre of Excellence at following places :

Jaipur	Bangalore	Hyderabad
--------	-----------	-----------

B. Institutional Buildings

The Institutional Buildings comprised of Four Buildings viz. Auditorium Block, Research Block, Hostel Block and Administrative Block.

Administrative Block has been completed and inaugurated by the Hon'ble President on 1st July 09. The other three buildings are nearing completion.

C. The Institute has acquired Building for the Pune branch.

D. The Institute has acquired land for following branches :

Kota	Sangli	Jalgaon	Rohtak	Bilaspur
Hubli	Ahmednagar	Mathura	Faridabad	

E. The Institute has commenced construction work for building of the following branches

Vadodara	Nashik	Durgapur	Vijayawada
----------	--------	----------	------------

F. The following proposals for acquisition of land of the branches are under consideration.

Bhilwara	Kottayam	Solapur	Kolhapur	Pimpri Chinchwad	Bellary
----------	----------	---------	----------	------------------	---------

G. The following branches have already started the process of acquisition of land.

Varanasi	Meerut	Bareilly	Allahabad	Moradabad	Bhatinda
----------	--------	----------	-----------	-----------	----------

- The Committee has revised the guidelines regarding Building Grant to the branches and the same have been approved by the Executive Committee.
- The Committee has recommended for amendment in the guidelines regarding recommendation of the proposal for Building Grant and it is under consideration of the Executive Committee.
- The Refurbishment / Renovation of existing building of the Institute 'ICAI Bhawan', 27, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai is in progress.
- The Institute building at A-29, Sector 62, Noida are in the final stage of completion and expected to be functional from July 09. The Building Committee for the branches which have or which do not have their own land / building were advised to acquire land / building for the branches.

- The branches who have not acquired land / building have been advised to start the process of acquisition of land.
- The Committee has a vision to create best Institutional Building Infrastructure for all the Branches of the Institute, develop Centre of Excellence for qualitative practical training in respect of IT, case studies and research, General Management and Communication Skills to the students and members.

7.11 Diamond Jubilee Committee

On 1st July, 2008, the Indian Chartered Accountancy Profession entered its 60th year of existence and coinciding with this occasion, the period started 1st July, 2008 celebrated for the Diamond Jubilee Year celebrations. 1st July is the day which has a special mile stone for the profession with the Chartered Accountants Act having been brought into being by the Parliament of India in 1949.

- As a prelude to start of 60th year and Diamond Jubilee Celebrations, following events were organized at New Delhi —

'Save the Environment Marathon' flagged off by Smt. Sheila Dikshit, Chief Minister of NCT of Delhi on 29th June, 2008

'Bhajan Sandhya by Sharma Sisters', and 'Lifestyle Management using Yoga & Meditation' by Swami Ramdevji Maharaj on 29th June, 2008.

'Health Check-up Camp' and 'Blood Donation Camp' on 30th June, 2008

'Motivation: Key to Success' – A Workshop led by Shri Shiv Khara, on 30th June, 2008 for the benefit of CA students

- 60th Foundation Day of the Institute - Diamond Jubilee Celebrations began with the Flag Hoisting in the premises of the Institute at "ICAI Bhawan", at 7.30 AM on 1st July, 2008.
- The entity to 60th year and start of Diamond Jubilee Celebrations were formally inaugurated by Dr. Manmohan Singh, Hon'ble Prime Minister of India, at New Delhi on 1st July, 2008.

Dignitaries joining the Celebrations, among others, included

Shri Prem Chand Gupta, Hon'ble Union Minister of Corporate Affairs CA. K. Rehman Khan, Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha

- Shri P. Chidambaram the then Hon'ble Finance Minister on 1st July, 2008 released the Special Cover brought out by Department of Posts on the occasion of the Diamond Jubilee
- Smt. Aarti Mehra, Mayor, Municipal Corporation of Delhi, planted a sapling in the Institute's premises at New Delhi on 1st July, 2008 to encourage 'Save Environment' - the initiative of the Institute.
- Live Performance - oriented to Lord Shiva and Maa Durga (Shakti) - by Padmashree Ms. Hema Malini on 1st July, 2008 was organized.
- Diamond Jubilee Conference with the theme "Chartered Accountancy Profession in Retrospect and Prospect" on 2nd and 3rd July, 2008
- Shri Montek Singh Ahluwalia, Hon'ble Deputy Chairman, Planning Commission, Shri Vinod Rai, Comptroller & Auditor General of India, CA. C. Ramachandraiah, Member of Parliament, Shri V.K. Dhali, Acting Chairman, Competition Commission of India, Shri Anurag Goel, Secretary, Ministry of Corporate Affairs, and Shri Dileep Padgaonkar, eminent journalist, among others, addressed delegates at the above Conference.

- "The Accountancy Profession and Economic Development in India" – a book - released by Shri Montek Singh Ahluwalia, at the above Conference.
- Live performance by Ms. Shreya Ghosal, Mr. Toshi Sabri, and other in the evening of 2nd July, 2008.
- July, 2008 Issue of The Chartered Accountant brought out as Special Issue. Special Issue of Newsletter also brought out by Regional Councils and their Branches.
- The Regional Councils and their Branches also organized conferences and programmes in commemoration of the Diamond Jubilee of the Institute. Eminent personalities who graced such programmes included CA. Rameshwar Thakur, His Excellency, the Governor of Karnataka, Dr. A.R. Kidwai, Governor of Haryana, Shri S. Jaipal Reddy, Union Minister for Urban Development, Shri Narendra Modi, Chief Minister of Gujarat, and Shri Shriprakash Jaiswal, Union Minister of State for Home.

Diamond Jubilee Conference held on 2-3 July, 2008 on the theme

"Chartered Accountancy Profession in Retrospect and Prospect" at Convention Hall, The Ashok, Chanakya Puri, New Delhi.

Coinciding with the start of Diamond Jubilee Celebrations effecting 1st July, 2008, the ICAI organised a Diamond Jubilee Conference on the theme "Chartered Accountancy Profession in Retrospect and Prospect" on 2 – 3 July, 2008 at New Delhi. The Conference was attended by 1500 members of the Indian Chartered Accountants Community including 50 members from SAFA countries and addressed by doyens of trade and industry, regulators, representatives of multi-lateral agencies, International Standards setting bodies, and Accounting bodies from SAARC Region.

ICAI National Leadership and Yog Camp, Orientation Programme held from 13th to 16th March, 2009 at Haridwar.

The 4 day 'National Leadership and Yog Camp' organized by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) from 13th-16th March, 2009 for the elected representatives of ICAI at all three tiers- Central Council, Regional Councils and Branches, on yogic exercises was successfully conducted by renowned yoga guru, Swami Ramdev ji Maharaj and Acharya Shri Balkishan ji, Spiritualist & Ayurved Scholar, for benefits like a healthy, disease-free body and a calm & alert mind. The yogic session which started with discourse by Swami Ramdev Ji Maharaj on Yogic life saw participation by over 600 leaders of CA fraternity from all over India. Apart from yogic exercises, yagnas were performed amongst vedic chantings, which was attended by leaders of chartered accountants from all regions. The yogic sessions were followed by National Flag Hoisting, National Anthem and Vande Mataram.

Branch Orientation Programmes of all the regions viz. Western, Southern, Northern, Eastern and Central regions discussed on various issues, chief among them were issues such as raising the standard of education, contribution of branches in strategic decision and policy making process of the Institute, Continuing Professional Development, Forensic Accounting, International Financial Reporting Standards etc. These meetings were widely attended by and were addressed by senior functionaries of the institute. It is noteworthy to mention that 118 branches of ICAI through their 600 plus leaders are part of this brainstorming session. Swami Ramdev ji Maharaj addressed each of the meetings.

The Camp also had site-seeing tour of Rishikesh and Haridwar as part of their professional development programme whereby it was learnt by the leaders of chartered accountancy that how the spirituality in conjunction with yogic exercises can make life stress free and lead to increased efficiency and effectiveness in their professional life besides day to day routine activities.

At the concluding day of Yoga Camp, so rich accolades by Swami Ramdev ji Maharaj to the CA. profession and in promoting the confidence amongst masses. He was of the view that the yoga

exercises and simple living and high thinking which is a path to achieving a bridge between almighty and the humanity is something which everyone should aspire for. He requested the Chartered Accountants to collaborate in the efforts of the Bharat Swabhiman Movement so that the two can provide further direction to the social aspects of governance.

At the occasion, regional representatives of the CA. fraternity from east, west, north, south and central regions, paid their complements to the movement ushered by Swami Ramdev ji Maharaj and offered full support at regional level to the activities of the Bharat Swabhiman Movement.

All India Diamond Jubilee T 20 Cricket Match between Team ICAI and Team IRS (Income Tax) on Saturday the 4th April, 2009 at Ferozeshah Kotla Stadium, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

A T-20 Day & Night Diamond Jubilee Cricket Match under the aegis of Diamond Jubilee Committee was held on 4th April, 2009 at Ferozeshah Kotla. ICAI team won a keenly fought match and defeated Team IRS Income-tax. Earlier a Ceremonial Match between ICAI Council Members and CBDT functionaries also took place. The event was covered live on DD Sports and evoked a good response.

ICAI Diamond Jubilee International Conference on the theme "Winds of Challenges – Global Strategies for Accounting Profession" on 3 – 5 July, 2009 at Agra.

The three day conference had dwelled upon issues of emerging and contemporary significance namely harmonization of International standards, Technology in Financial sector, Bridging expectation gap, financial markets and beyond. The conference had brought the entire ICAI membership to Agra as against a member base of nearly 500, more than ninety percent of conference participation was from all other parts of country and south East Asia and majority of developed countries with over 200 foreign delegates from over 25 countries.

The Conference was attended by renowned personalities like Sir David Tweedie, Chairman, International Accounting Standards Board, Dr. Arnold Shilder, Chairman, International Auditing and Assurance Standards Board, Mr. Ernie Almonte, CPA-Chairman, American Institute of Certified Public Accountants, Ms. Liv Watson, Vice Chairman, XBRL.

The Evening of 3rd had cultural programme on Indian cultural heritage theme performed by Ms. Surabhi Singh-Krishna Theme Kathak Performance, Mr. Surinder Sharma (Renowned Laughter Poet), Mr. Nitin Chopra -Shiva Nritya, UP Based Cultural Folk (Holi/Rasleela/Mayur Nritya), Rajasthan Based Cultural Folk (Kaalbelia/Ghuvur), Punjabi Based Cultural Folk (Gidha and Bhangra)

The Evening of 4th had bollywood cultural programme performed by Mr. Udit Narayan, Monika Thakur and troupe.

5th July, 2009 i.e. last day of the International Conference had witnessed the Agra Go Green Run, a mega initiative to integrate Chartered Accountants and students with people from all walks of life, having concerns of protecting the environment. Celebrities namely Rahul Bose amongst others had participated there at. The run was participated by over 3000 students and members and their families.

ICAI Diamond Jubilee Conference on "Professionalism as a Tool to Economic Growth".

Celebrating Sixty year of historic run and this year as ICAI's Diamond Jubilee Year, ICAI organized a Diamond Jubilee Conference for its members with a theme "Professionalism as a Tool to Economic Growth" at Durbar Hall, Hotel Taj Palace, Sardar Patel Marg, New Delhi on July 11, 2009.

The Conference was inaugurated by CA. K.Rahman Khan, Hon'ble Deputy Chairman of Rajya Sabha. CA. Akhil Gupta, President and Deputy CEO, Bharti Enterprises and CA. Archana Bhutani of KPMG made respective presentations.

A separate webpage of "Diamond Jubilee Celebrations" is available on www.icai.org. The webpage amongst others also outlines ICAI's request to corporates and others to associate themselves in the various initiatives of ICAI Diamond Jubilee Committee.

While each year we have been celebrating 1st July as the CA Day, given the stature of the current year being a landmark year of the Diamond Jubilee, it has been decided to position the ICAI's role in various contemporary & emerging areas as under by associating/organizing events commemorating the ICAI's contribution. The period of July, 2009 to June, 2010 to be dedicated monthwise for different activities. At the outset the Committee dedicated such theme areas for first six months as under:

Activity	Month
Go Green	July, 2009
Educational Initiative and IT Training	August, 2009
Career Counseling	September, 2009
Empowerment	October, 2009
Agriculture	November, 2009
Public Awareness	December, 2009
Sports and Youth Festival	January, 2010

8. OTHER MATTERS

8.1 Annual Function of the ICAI

The 59th Annual Function of the ICAI was held on 4th February, 2009 at New Delhi. Shri Prem Chand Gupta, Hon'ble Union Minister of Corporate Affairs was the Chief Guest. The 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' for the year 2007-08, Prizes and Medals to the meritorious students in the examinations conducted by the ICAI, Shields and Certificates of appreciation to the outstanding Regional Council and Branches of the ICAI, were given away at the said function. The Function was attended by a record number of invitees which included, among others, Senior Government Officers, Members, Students, Officers and Staff of the ICAI. The Chief Guest showered flowers of appreciation on the profession of Chartered Accountants.

8.2 Amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988

- (i) During the year, the Central Government has accorded its final approval for amendments in the following Regulations of the Chartered Accountants Regulations, 1988 :-

Regulation	Amendment	Published
Regulation 3A	List of Members	in the Gazette of India vide Notification No. 1CA(7)/11 6/2008 dated 25 th September, 2008 in the Part III Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 25 th September, 2008.
Regulation 5(1)	Application for Membership	
Regulation 6	Fees	
Regulation 10	Cancellation of a Certificate of Practice	
Regulation 11	Restoration of Certificate of Practice	
Regulations 12, 13, 14, 15, 16 and 17	Only additions after the headings of the concerned Regulations	
Regulation 17 A	Fee and Procedure for investigation of a complaint or information to be followed by the Director (Discipline), Disciplinary Directorate and Procedure for inquiry by the Disciplinary Committee – applicable to a complaint or information received on or after 17.11.2006.	
Regulation 19	Restoration to Membership	
Regulation 53A	Other Professional Bodies	
Regulation 53B	Membership of Professional Bodies for Partnership	
Regulations 82 to 126	Chapter VI – Elections – for deletion	
Regulation 137(9)	Office-bearers and Committees	
Regulation 174A	Committees of the Council	
Regulation 175	Executive Committee	
Regulation 176A	Finance Committee	
Regulation 194	Maintenance of Accounts	
Regulation 197	Comparison of actuals with budget estimates.	

Regulation 28D	Enrolment for Integrated Professional Competence Course and Fees	Published in the Gazette of India vide Notification No. 1CA(7)/123/2008 dated 2 nd December, 2008 in the Part III Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 3 rd December, 2008.
Regulation 28E	Admission to Integrated Professional Competence Examination, Fees and Syllabus	
Regulation 29C	Admission to Final Examination	
Regulation 31(iii)	As per the syllabus specified by the Council from time to time after commencement of enrolment to Integrated Professional Competence Course – for addition.	
Regulation 37C	Requirements for passing Integrated Professional Competence Examination	
Regulation 38C	Requirements for Passing the Final Examination	
Regulation 40	Examination Certificates	
Regulation 45	Admission to Articleship	
Regulation 50	Provided also that a candidate enrolled for the Integrated Professional Competence Course shall be eligible to three years articleship on his passing the Group-I level or Accounting Technician level of the Integrated Professional Competence examination – for addition	

8.3 Central Council Library

Central Council Library is globally connected through Internet, fully computerized & operational. Library material including database of Books, Journals & Articles can be searched through Subject, Author, Title, Topic, Keyword, & Publisher wise, this record is available on Internet Online Services www.icai.org under “know your Institute – Central Council Library”. Reference service is also provided to the Researchers & Scholars from different Universities & CPT Course Students as a special case. Noida Office of the Institute & Vishwas Nagar Students library has also been provided with library facilities by the Central Council Library, along with nucleus Libraries provided to each Directorates of the Institute.

Central Council Library provides Links for various Library-Web services through www.icai.org under “know your Institute – Central Council Library”. The services are self-explanatory. Some of these links such as list of online Journals, E-books, Articles from Chartered Accountants Journals and online database of Books, Journals and Articles in the Library, provide further search in the above online databases. One can even suggest new Books/Journals under “Suggest Books/Journal columns” for consideration by the Institute. One may note that The “Accountants Browser” is an index of important/Professional Articles with archives for last 10 years.

Besides above, Library has installed a number of the Institute’s databases in the Central Council Library premises and at various Departments to facilitate the search for required material by the students, Members, Faculties and the Research Scholars. A New Software –Liberty is acquired connecting the database of Central Council Library with all regional libraries database. Central Council Library is also procuring necessary publication/Books for the following current courses offered by ICAI including a provision of publication/Books for all Committees.

- Certificate Course on Enterprise Risk Management
- Certificate Course on Master in Business Finance
- Certificate Course on Corporate Governance
- Certificate Course on Forensic accounting & Fraud Detection using IT & CAATs
- Certificate Course on Forex and Treasury Management
- Certificate Course on Derivatives
- Certificate Course on Valuation
- Certificate Course on Arbitration

Webservices:-

The Web Services available on www.icai.org are as follows:-

- List of Online Journals
- e-Books Links
- Articles from Chartered Accountant Journal(1951 - 2000)
- Articles from Chartered Accountant Journal(2001 - 2007)
- Central Council Library – A complete Online Search for Database the Books, Journals & Articles in the Central Council Library
- List of Books on WTO available in the Central Council Library
- Accountant's Browser, an Archive of Professional Articles for last 10 years
- Central Council Library - New Delhi - Conference / Seminar
- CDs Available in The Library
- The Chartered Accountant Index July 2002 - June 2007
- List Of Recommended Books
- Library Security Deposit Rules
- Library News and Views
- List of Journals Subscribed by Central Council Library
- Library Services - Membership Form for Members
- Library Services – Membership Form for Students
- Photographs Available In The Library
- Recent Additions – Books added in Central Council Library
- SAFA Books/ Publications Available in the library
- Suggest Books/ Journals

The Online database installed in the Library are as follows:-

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| ➤ Library Software – Liberty | ➤ Excus Online |
| ➤ Electronic membership of IBFD | ➤ E- Jurix |
| ➤ Prowess (CMIE) | ➤ Indlaw.com |
| ➤ CTR Online | ➤ Delnet |
| ➤ ITR Online | ➤ Indiatat.com |
| ➤ Manupatralaw.com | ➤ Taxman |

8.4 Editorial Board

Surging ahead with its mission to keep the ICAI members and other readers of *The Chartered Accountant* journal up-to-date on various subjects, emerging areas, aspects and challenges of the profession in today's age of fast-paced globalisation, the Editorial Board has established many a landmark during the period of this report (1.4.2008 and 31.5. 2009).

A 'Brand Ambassador' of ICAI and the most visible indicator of the Institute's profile for the members, students and external audiences, *The Chartered Accountant* today matches the global standards of professional Journals, be it content quality, in-depth topical coverage, interactive features, international standard layout/design, paper quality, overall look and feel or greater reach. It is increasingly being recognized as one of the most reliable and reader-friendly tools of professional knowledge update, not only for the members but also for allied professionals, institutions and a cross-section of the economic world in India and abroad, if our readers' feedback is any indication.

With ever-widening reach and readership base, the total circulation the Journal stands at more than 1,91,000 today.

Contents and e-Journal:

- ◆ During 1.4.2008 and 31.5.2009, a total of 160 articles on various topics were printed.
 - ◆ Nine new features – 'Industry-Specific', 'International Taxation', 'Global Perspective', 'Career', 'Management', 'Outsourcing', 'Vastu Shastra', 'Know Your Future', 'Health' were introduced in the Journal while it was decided to publish selective extra-ordinary success stories of the ICAI members in various walks of professional life to promote the image of the profession in the society at large. Existing features like 'Legal Update', 'National Update', 'International Update' were further upgraded to keep the members better informed.
- A unique 218-page July 2008 issue was brought out coinciding with ICAI Diamond jubilee year and it elaborately covered the rare glorious moments of ICAI history.

- CEOs/CFO of companies having turnover of at least Rs. 1000 crore, and Chairmen, CEOs, Managing Directors and CFOs of top 500 companies were invited to contribute in the journal to widen and improve upon the coverage of the journal.
- ◆ The online journal, which has been hosted on ICAI website with a unique URL www.ejournal.icai.org, was further upgraded and improvised to make it more dynamic and user-friendly with faster and easier browsing with search facility without any requirement of available specific software. Every issue of the Journal was made available online well in advance. The Journal page and the Editorial Board page on the ICAI website were also comprehensively upgraded and updated.

Layout and Design:

- ◆ The layout-design and font type face of the entire journal were further upgraded to match international standards.
- ◆ The Masthead and basic template of the Cover page were further improved.

Other Initiatives:

- ◆ As part of ICAI brand building initiative, an elaborate exercise was carried out to standardize the newsletters of the Regional Councils and their Branches in terms of cover page, masthead, colour combination, presentation style and coverage, strictly in line with the 'Advisory on Newsletters Published by the Regional Councils and their Branches' (as approved by the Executive Committee) and decisions taken by the Editorial Board.
- ◆ A unique Accountancy Museum of India was established in Noida. The museum, among other things, presents rare and historic images (evidence of the oldest balance sheet in human civilization), and documentary evidences of the evolution of Accountancy in India.
- ◆ For the benefit of CA students at large, it was decided to mandatorily supply the journal to all of them by incorporating the journal charges in their fee structure.
- ◆ The Board mooted an exclusive online version of the journal in line with the online versions of leading national dailies. A mobile version of the journal has also been envisaged.
- ◆ To further improve the overall quality of the Journal, a readership survey was conducted resulting into a very positive feedback from the readers.
- ◆ For added convenience of reading the journal, members were given option to get the copy of their journal at their residential addresses if they so desired.
- ◆ The panel of professional editors was expanded so that the release of ICAI publications may be expedited after professional language editing.

8.5 High Powered Committee

A corporate fraud of huge magnitude came to light, with the revelation by the then Chairman of M/s Satyam Computer Services Ltd. about serious irregularities and mis-statements in the financial statements of the Company running into several years. The then Chairman, in his confessional statement made on 7th January, 2009 owned up responsibility for having fudged the accounts and having shown inflated figures for a number of years.

The entire fiasco raised serious concerns about the efficacy and reliability of the financial statements and reporting, corporate governance, process of audit, the due diligence exercise and role of auditors and vulnerability of shareholders/investors. The Council of the ICAI, deeply concerned with the financial scandal, which has serious ramifications for not only India's corporate sector, but also on the governance system in Indian corporates, felt the need to restore the confidence of the public in the accounting and auditing profession, and hence constituted the High Powered Committee at its 284th meeting held on 12th & 13th January, 2009 at New Delhi to look into the entire gamut of the Satyam fiasco, including helping/co-ordination with the investigation being carried out by various agencies, going into the roots of the problem, effectiveness of the system in place, systemic issues; to identify the root causes including persons involved/associated; and to suggest change(s), wherever required, for the purpose of making appropriate recommendation(s) to the Central Government, SEBI and other Regulators.

The task of the Committee is in progress.

9. MEMBERS

9.1 Membership

During the year ended 31st March, 2009, 8395 new members were enrolled by the ICAI bringing the total membership to 153600 as on 1st April, 2009 inclusive of 2131 members restored under General Amnesty Scheme (that closed on 31st March 2009).

During the year ended 31st March 2009, 3101 associates were admitted as fellows, in comparison to the figure of 2936 in the previous year.

Total Members as on 1.4.2009

Category of Members	Fellow (1)	Associate (2)	Total of Columns (1) and (2)
In Full Time Practice	51298	19064	70362
In Part-time Practice	3081	5230	8311
Not in Practice	9539	65388	74927
	63918	89682	153600

9.2 Chartered Accountants' Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants Benevolent Fund continues to provide financial assistance to needy persons who are or have been members of the Institute and their dependents, for maintenance of the dependents, their educational and medical needs etc. The financial and other particulars of the fund are as follows:

Details of Membership

1. Total Life Members as on 31.03.2008 = 87,029
2. Total Life Members as on 31.03.2009 = 94,480
3. Total Additions of New life Members
(As on 31.03.2009) = 7,451
4. Total Financial Assistance given upto 31.03.2009 = 79

Details of Financial Particulars

	During the year Ended 31.03.2008	During the year Ended 31.03.2009
	Rs.	Rs.
1. Total Assistance provided	1,64,16,000.00	57,00,000.00
2. Administrative Expenses	11,235.00	14,438.00
3. Surplus (Deficit) of the Fund	(72,46,236.00)	32,17,810.00
4. Balance of the Fund	1,66,91,180.00	1,99,08,990.00
5. Balance of Corpus	7,35,97,300.00	8,06,82,800.00

9.3 S.Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

During the year ended 31st March, 2008, 60 scholarships of the value of Rs. 500 each per month are to be given to the students undergoing the Chartered Accountancy course. The number of life membership of the Fund increased from 1527 as on 31st March, 2008 to 1775 as on 31st March, 2009. The balance in the credit of the Fund was Rs. 9,57,181/- as on 31st March, 2009 as against Rs. 10,29,295/- as on 31st March, 2008.

9.4 Chartered Accountants Students Benevolent Fund (CASBF)

The fund was established in August 2008 with the aim and objective to provide financial assistance, scholarships etc. to the students registered with ICAI. To begin with, CASBF has decided to provide scholarship in the form of financial assistance to 100 students of the value of Rs.1000 per month for one year. The balance in the credit of the general fund was Rs 21,44,658/- as on 31st March, 2009.

10. STUDENTS**10.1 Students' Statistics**

The new scheme of education and training named as Integrated Professional Competence Course and Accounting Technician Course was introduced on 1st December, 2008 and registration for the said new courses commenced from 10th December, 2008. The details in respect of students registered during the previous five years from 2004-2005 to 2008-2009 and from 1st April, 2009 to 31st May, 2009 are as indicated below:

Year	Final (old & New)	CPT	PCC	IPCC	ATC (Registered exclusively)
2004-05	11,061	—	—	—	—
2005-06	13,010	—	—	—	—
2006-07	11,838	1,29,110 (from 13/9/2006 onwards)	24,041 (from 13/9/2006 onwards)	—	—
2007-08	19,558	1,42,612	61,186	—	—
2008-09	11,562	1,39,140	33,764	18,318 (from 10/12/2008 onwards)	8 (from 10/12/2008 onwards)
1st April, 2009 to 2nd July, 2009	1,123	34,720	642	754	—
Total	68,152	4,45,582	1,19,633	19,072	8

During the period 1st April, 2009 to 2nd July, 2009 5 students of Professional Education (Course-I) opted for switch over to Common Proficiency Test Course (against 474 students in 2008-2009). The

number of students of Professional Education (Course – II) who switched over to Professional Competence Course during the year 2008-09 is 268 and between 1st April, 2009 to 2nd July, 2009 is 4. The number of students of Professional Education (Course – II) who have switched over to newly launched education and training course i.e. Integrated Professional Competence Course during the year 2008-09 is 104 and between 1st April, 2009 to 2nd July, 2009 is 20.

10.2 Accreditation Scheme

During the year ended 31st March, 2009, the names of 3 more accredited institutions were added for conducting CPT oral coaching classes totaling to 131 (128+3) and 1 more for conducting PCC oral coaching classes totaling to 74 (73+1). The number of accredited institutions for Professional Education (Course - II), remains the same, which is 96 and also there is no change in the number of existing 10 institutions for Final Course.

10.3 Study materials for the new course

After launch of the new scheme of education and training on 10th December, 2008 study materials of Integrated Professional Competence Course (IPCC) and Accounting Technician Course (ATC) English study materials were released. Hindi study materials are under preparation and as per the plan, Hindi study materials of the above courses have been released.

10.4 Suggested answers

The suggested answers for the following examinations held in May, 2008 and November, 2008 examinations were printed and distributed to regions and branches three months in advance of November, 2008 and June, 2009 examinations.

Professional Education Examination – II (PEE-II)

Group – I / Group – II

Professional Competence Course (PCC)

Group – I / Group – II

Final (Old)

Group – I / Group – II

Final (New)

Group – I / Group – II

In order to facilitate and guide the students for better preparedness to face the examination, the Board of Studies hosted suggested answers on the website of the ICAI with download option free of cost.

10.5 Revision Test Papers (RTPs)

The Revision Test Papers (RTPs) for PE-II, PCC and Final were sent to regions and branches well in time to enable the students to prepare for their examinations.

The design, quality and content of the Revision Test Papers (RTPs) and Suggested answers have been thoroughly redesigned and improved for the benefit of the students.

In order to facilitate and guide the students for better preparedness to face the examination, Board of Studies hosted Revision Test Papers on the website of the ICAI with download option free of cost.

Revision Test Papers are published in respect of the following examinations

Professional Education (Course –II) (Group I & II)

Professional Competence Course (Group I & II)

Final (Group I & II)

Final (New) Course (Group I & II)

10.6 Revision of Study Materials

As a part of continuous process of updating the knowledge of students on an annual basis, the contents of various study materials have been updated and appropriate changes have also been incorporated.

10.7 Digest of Select cases

The digest of select cases in Direct and Indirect Taxes 2008 containing choice cases in Direct and Indirect tax laws has been published.

10.8 Supplementary Study Materials in Taxation subjects

Supplementary study material in Direct and Indirect taxes is an annual publication containing amendments made by the Finance Act, 2008 in Direct Taxes and Indirect taxes. The same has been published and forwarded to regions and branches for being distributed among the students.

10.9 Publications of Board of Studies

The publications brought out by the Board of Studies included Study Materials in respect of Common Proficiency Test (CPT), Professional Education (Course-II), Professional Competence Course (PCC), Integrated Professional Competence Course (IPCC), Accounting Technician Course (ATC) and Final Examinations. The Board also brought out Course material on Information Technology Training Programme/Course, suggested Answers for Professional Education (Course-II), Professional Competence Course (PCC) and Final Examinations as well as compilation of Suggested Answers on Professional Examination (Course-II) and Final Examinations. CD of study material pertaining to PCC, IPCC, ATC, Final Course as well as of Self Assessment (CPT) were also released.

10.10 100 Hours Information Technology Training

Presently 131 Information Technology Centres are fully functional and establishment of another 7 labs are in process. As on date a total 3,741 computers were installed in these computer labs for the benefit of the students. These computer labs have the capacity to train 1,25,000 students per annum.

Computer Labs fully functional	131
Labs establishment in Process	7
Number of computers installed	3,741
Number of students trained from February 2008 to May, 2009 in ICAI computer labs	68,909
Annual capacity to train students in ICAI labs	1,25,000

The study material on 100 Hours Information Technology has also been thoroughly revised and updated.

10.11 Course on General Management and Communication Skills – 54 centres 265 Batches and 10870 students trained during 2008-09

During the period from 1st April, 2008 to 31st March, 2009, 265 batches of the 15 days' Course on General Management and Communication Skills were organized by Regional Councils and their Branches at 54 Centres across the country (inclusive of Dubai Centre) and 10870 students participated in these programmes (7851 students participated during 2007-2008).

During the period from 1/4/2009 to 31/5/2009, 10 batches of the 15 days' Course on General Management and Communication Skills were organized by Regional Councils and their Branches at 5 Centres and 426 students participated during this period.

In order to bring uniformity in the course content and methodology of teaching in GMCS classes throughout the country a uniform course content has been prepared. It is in the advanced stage of finalization.

10.12 Orientation Programme for Integrated Professional Competence Course (IPCC) and Accounting Technician Course (ATC)

Students who have registered for Integrated Professional Competence Course (IPCC) and Accounting Technician Course (ATC) have to undergo mandatory Orientation Programme for 7 days spanning 35 Hours. The objective of this Orientation Programme is to give exposure to freshly qualified Common Proficiency Test (CPT) students in areas like Communication Skills, Presentation Skills, Office Procedures and General Commercial Knowledge. A comprehensive study material covering the course content for the Orientation Programme has been prepared and distributed to the Regions and Branches for organizing such courses. Orientation Programmes have already been commenced by Regions and Branches.

10.13 Increase in number of Scholarships during the year 2008-09 – Total Scholarships 220

The number of merit scholarships has been increased from 12 to 60, merit cum need based scholarships from 12 to 60 and need based scholarships from 20 to 100.

10.14 Integrated Professional Competence Course including Accounting Technician Course launched in December, 2008

The ICAI launched the Integrated Professional Competence Course (IPCC) which includes Accounting Technician Course (ATC). In other words students can either pursue full fledged chartered accountancy course through IPCC or alternatively they can pursue Accounting Technician Course and get a mid-level accounting qualification from the ICAI.

10.15 Students' Newsletter

The monthly C.A. students' newsletter – '*The Chartered Accountant Student*' containing articles on topics relevant to the students, academic updates, important announcements, continued to be popular and proved useful to the students' community as well as members of the Institute.

10.16 Best Article Award

1st Prize Award of Rs.2,000 was awarded to Mr. Rahul Kumar Bajaj for his article on "Concern for - Going Concern" published in September, 2007 issue of Students' Newsletter and 2nd Prize Award was awarded to Mr. Gururaj S for his article on "Towards Greener Tomorrow – Understanding Carbon Credit" published in July, 2007 issue of the Students' Newsletter – The Chartered Accountant Student.

10.17 Students Exchange Programme – 25 students from abroad covering four countries

6 students of the Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN), 9 Students of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (ICASL), 1 student of Chartered Accountants of Pakistan and 9 students of Chartered Accountants of Bangladesh came to India and participated in SAFA students exchange programme in Nagpur on 10th-11th July, 2008.

10.18 Recognition of CA Course for Ph.D. Programme

Due to constant follow up with various Universities, the Board of Studies has been successful in obtaining recognition for CA Course from 80 Universities besides the 4 Indian Institutes of Management and the Association of Indian Universities for the purpose of Ph.D. /Fellow Programme.

10.19 One Day Seminars – 33 programmes

During the year, 33 One day seminars were organized by 20 branches.

10.20 Elocution Contests – 60 programmes

Branch Level Elocution Contests were organized by 54 Branches including 5 Regional Councils which conducted Branch Level Elocution Contests. Apart from this 5 Regional level competitions and one All India Elocution contest were organized.

Final Elocution Contests was held at Jaipur on 5th January, 2009.

10.21 Quiz Contests – 60 programme

Branch Level Quiz Contests were organized by 54 Branches including 5 Regional Councils which conducted Branch Level Quiz Contests. Apart from this 5 Regional level competitions and one All India Quiz contest were organized.

Final Quiz Contests was held at Jaipur on 5th January 2009.

10.22 Regional/ State Level Lecture Meetings – 21 meetings

During the period from 1st April, 2008 to 31st May, 2009, 21 Lecture Meeting/ Half Day Seminar were organised at 15 branches and 1 crash course was held at a branch.

10.23 All India CA Students' Conference – All India conference

The 21st All India CA Students' Conference was organized on 10th and 11th July, 2008 in Nagpur.

10.24 National Convention of CA Students – 5 National conventions

During the year 5 National Conventions were organized. The 5th National Convention was organized on 9th and 10th June, 2008 in Jaipur. 6th National Convention was organized on 23rd and 24th August, 2008 in Kolkata. 7th National Convention was on 1st and 2nd December, 2008 at New Delhi. 8th National Convention was organized at Ernakulam on 5th and 6th December, 2008 and 9th National Convention was held at Rajkot on 1st and 2nd January, 2009.

10.25 Regional/ Sub-Regional/ State Level Conferences – 7 conferences

Two-day Regional/Sub-Regional/State Level Conferences were held at Baroda on 6th and 7th June, 2008, on 11th and 12th July, 2008 at Vasai, on 13th and 14th December, 2008 at Surat, on 17th and 18th December, 2008 at Chennai, 3rd and 4th January, 2009 at Banagalore, on 9th and 10th January, 2009 at Bhubaneswar and 10th and 11th January, 2009 at Coimbatore.

10.26 Joint Seminars with Universities – 3 joint seminars

During the year 3 Joint Seminars with the coordination of various Universities were held.

10.27 Career Counseling Programmes – 80 programmes

Career Counseling Programme being organized in Regional Headquarters and branches to popularize the CA course and also to help students for getting their academic queries in various subjects of the curriculum duly clarified. During the period from 1st April, 2008 to 31st March, 2009, 80 Career Counseling Programmes were organized at different locations throughout the country. 16 Career Counseling Programmes for interacting with the students community were organized at different branches in India during the period from 1st April, 2009 to 31st May, 2009.

10.28 Three Months' (12 weeks) Residential Programme on Professional Skills Development – 7 batches

A three months' residential programme on Professional Skills Development (General Management, Personality Development and Communication Skills) has been initiated for the benefit of CA students and newly qualified Chartered Accountants. The programme is helping the CA students and newly qualified CAs in imbibing the professional skills required for effective functioning in business organisations and profession. Different batches of the programme organized are as follows:

First batch at National Institute of Financial Management (NIFM), Faridabad: April 28, 2008 to July 18, 2008 – 55 Students participated in the programme.

Second batch at NIFM, Faridabad: 11th August, 2008 to October 31st, 2008 – 52 Students participated in the programme.

Third and Fourth batches at L N Mittal Institute of Information Technology, Jaipur: December 02, 2008 to March 01, 2009 – 100 Students participated in the programme.

Fifth batch NIFM Faridabad: Started on February 04, 2009 to April 28, 2009 – 50 Students participated in the programme.

Sixth batch, Indian Institute of Management, Indore: Started on April 13, 2009 and concluded on July 14, 2009 – 60 Students participated in the programme.

Seventh batch, NIFM Faridabad: Started on July 06, 2009 – 53 Students are participating in the programme.

10.29 Gyan Darshan Programme for students of CPT, PCC and Final – Total lectures 190

For the benefit of students pursuing Common Proficiency Test, Professional Competence Course and Final students, lectures by experts were arranged during the year through Gyandarshan Channel in collaboration with Indira Gandhi National Open University (IGNOU), New Delhi. The number of such lectures held is given below:

Common Proficiency Test (CPT) lectures:	110
Professional Competence Course (PCC) lectures:	40
Final lectures:	40

Students from various parts of the country interacted with the faculty through the systems provided by ISRO. These lectures were conducted during the year and up to 1st May, 2009.

10.30 Memorandum of Understanding with Bharathiar University

A Memorandum of Understanding between the ICAI and the Bharathiar University, Coimbatore has been signed on 4th December, 2008 in Coimbatore.

As per the MOU, CA students as well as qualified Chartered Accountants will have the opportunity to pursue B.Com., M.Com., BBA., and MBA degrees of the Bharathiar University.

They would be given exemptions in respect of papers covered by the CA curriculum and they have to appear and pass only in few papers to get these degrees.

Provision has also been made in the MOU to enable chartered accountants to acquire Ph.D.

10.31 Memorandum of Understanding with the Institute of Chartered Accountants of India and Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar

The ICAI has signed a Memorandum of Understanding with the Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar whereby CA students as well as chartered accountants would be able to obtain the degrees of BBA, MBA and Ph.D. subject to the condition in the MOU.

10.32 Toll free numbers for answering students' queries

A toll free number 1800-200-2501 has been installed in the Board of Studies, Noida. Dedicated officers are answering the queries of students. The academic queries are being answered by faculty members.

10.33 Students' Counselors

Student counselors have been appointed in the offices of the Institute at Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai and Jaipur. They are guiding the students on various aspects of the chartered accountancy course.

10.34 Convocations in coordination with M&S Section

Sl.No.	Date	Place of convocation	Sl.No.	Date	Place of convocation
1	November 9, 2008	Mumbai	7	June 7, 2009	New Delhi
2	November 16, 2008	Delhi	8	June 21, 2009	Chennai
3	November 30, 2008	Chennai	9	June 28, 2009	Kolkata
4	December 7, 2008	Kolkata	10	July 2, 2009	Hyderabad
5	December 28, 2008	Jaipur	11	July 11, 2009	Jaipur
6	May 31, 2009	Mumbai			

10.35 Faculty Development Programme – Alleppy, Kerala

A faculty development programme was organized in Alleppy, Kerala. The objective of this programme was to improve the teaching methodology of faculty members imparting professional education to chartered accountancy students. Eminent experts in presentation and communication skills and teaching methodology acted as resource persons in this programme which was attended by more than 50 faculty members from all over the country.

10.36 Training to trainers of IT students

In order to equip the faculty members in Information Technology who are imparting training the CA students, the Board of Studies has organized a trainers training programme wherein eminent experts in the Information Technology fields imparted training to the IT faculty.

10.37 National Sports Competition

To commemorate the Institute's Diamond Jubilee year celebrations Sports Competitions were conducted at the branch (25 branches) and regional levels (5 regions). For participating at the national level competition more than 100 students have been selected at the regional level. The National Level Competition would be organized in the later part of the year 2009.

10.38 Youth Festival

As part of the Institute's Diamond Jubilee year celebrations competitions under the aegis of Youth Festival were conducted in various cultural events such as Light music, vocal music, Duet singing - vocal, Instrumental music, Mono acting, Anthakshari and Comedy show by 25 branches.

10.39 National school level debate competition

As part of the Diamond Jubilee celebrations a national school level debate competition was commenced. Competitions were held at the branch and regional level. 65 branches have conducted the competitions in coordination with schools located in different part of the country wherein 12,330 students participated. The national level competition is proposed to be organized in the later part of the year 2009.

10.40 Celebration of Teachers' Day

The teachers' day was celebrated in a grand manner in the Board of Studies, Noida on September 5, 2008. Faculty members were given a gift and a special certificate from the President, ICAI.

10.41 100 Hours IT training and GMCS at a glance**a. 100 Hours IT training**

Computer Labs fully functional	131
Labs establishment in Process	7
Number of computers installed	3,741
Number of students trained from February 2008 to May, 2009 in ICAI computer labs	68,909
Annual capacity to train students in ICAI labs	1,25,000

b. GMCS classes

No. of Centres	No. of batches	No. of students trained
54	265	10,870

11. REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES**11.1 Branches of Chartered Accountants Students' Association**

With a view to actively involving students of the Chartered Accountancy Course in the development of spirit of fellow-feeling and promotion of social, cultural, academic and intellectual development etc., the Council of the Institute has always been encouraging students to set up branches of Chartered Accountants Students' Association. In this process, so far 42 branches of Students' Association have already been set up.

11.2 REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES

The Institute has five Regional Councils, namely Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively.

11.3 The total number of branches of Regional Councils is 119.

11.4 Currently, there are 21 Chapters of the Institute outside India.

11.5 Currently, there are 30 Reference libraries all over India

11.6 Branch Building

During the period under Report, a number of branches of Regional Councils continued to evince interest in having their own premises. In all, 64 branches have their own premises.

11.7 Rotating Shield

The Institute awards each year Rotating Shield to the Best Regional Council. The award is given on the basis of overall performance. Similarly, a separate Rotating Shield is awarded to the Best Branch each year. The award is given on the basis of established norms. Rotating Shields to the Best C.A. Students' Association on all India basis and Best Branch of Students' Association on Regional Basis have been instituted from the year 1999. For the year 2008 these Shields were awarded at the Annual Function held on 4th February, 2009 to the following winners:-

- Best Regional Council-Northern India Regional Council
- Highly Commendable Performance shield for the year 2008- Western India Regional Council and Southern India Regional Councils (jointly)
- Appreciation Certificates for the year 2008- Eastern India Regional Council and Central India Regional Council
- Best Branch of Regional Council
 - Small Size Branch Category – Pimpri Chinchwad Branch of WIRC
 - Medium Size Branch Category – Vasai Branch of WIRC
 - Big Branch Category- Ernakulam Branch of SIRC and Nagpur Branch of WIRC (Jointly)
- Best Branch of Students' Association
 - Western Region - Nagpur & Surat Branch of WICASA (Jointly)
 - Southern Region - Ernakulam & Trivandrum Branch of SICASA (Jointly)
 - Eastern Region – Guwahati Branch of EICASA
 - Central Region- Indore Branch & Jaipur Branch of CICASA (Jointly)

- Considering their performance, the following branches were separately awarded Highly Commended Performance Shield :-
- Small Size Branch Category -**
- Bhilai Branch of CIRC
 - Tuticorin Branch of SIRC
 - Hubli Branch of SIRC
 - Siliguri Branch of EIRC
- Medium Size Branch Category:**
- Salem Branch of SIRC
 - Aurangabad Branch of WIRC
- Big Branch Category**
- Coimbatore Branch of SIRC and Indore Branch of CIRC (Jointly)
- Considering their performance, the following branches were separately awarded Certificates for Highly Commended Performance :-
- Small Size Branches-** Tirupur Branch of SIRC and Jamnagar Branch of WIRC (jointly)
Medium Size Branches- Guwahati Branch of EIRC and Goa Branch of WIRC (jointly)
- The Secretary WIRC, was Awarded Shield for Excellent Performance.**

11.8 Decentralised Offices

Recognising the value of expeditious and personalised service which are achievable through the process of decentralisation, the Council of the Institute has already set up five decentralised Offices at Bangalore, Hyderabad in Southern Region, Ahmedabad, Pune in Western Region and Jaipur in Central Region besides the decentralised offices already functioning from Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi. Considering the increasing volume of work/activities at the regional level eight more decentralised offices have been set up at Nagpur, Surat, Vadodara and Thane (Western Region), Ernakulam and Coimbatore (Southern Region), Indore (Central Region) and Chandigarh (Northern Region).

12. FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as on 31st March, 2009 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date as approved by the Council are enclosed.

13 APPRECIATION

- 13.1 The Council is grateful to members of the profession who functioned as co-opted members on its Committees, persons nominated on the Boards/Committees constituted under the Chartered Accountants Act, 2006 and to the non-members who assisted the Council during the year 2008 - 2009 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.
- 13.2 The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 2008 - 2009.
- 13.3. The Council wishes to place on records its heartfelt gratitude to Dr. Manmohan Singh, Hon'ble Prime Minister, CA. K. Rahman Khan, Hon'ble Deputy Chairman of Rajya Sabha, CA. Rameshwar Thakur, Hon'ble Governor of Karnataka, Shri P. Chidambaram, [the then] Hon'ble Union Minister of Finance, Shri Lalu Prasad, [the then] Hon'ble Union Minister of Railways, Shri Prem Chand Gupta, [the then] Hon'ble Union Minister of Corporate Affairs, Smt. Shiela Dikshit, Chief Minister of Delhi, Shri Sriprakash Jaiswal, Hon'ble Minister of State for Home, Dr. Montek Singh Ahluwalia, Deputy Chairman, Planning Commission, Shri Vinod Rai, CAG of India, Ms. Aarti Mehra, Mayor, Municipal Corporation of Delhi, Shri Anurag Goel, Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Swami Ram Dev and other dignitaries who were kind enough to grace the various programmes of the ICAI. The Council also

desires to place on record its sincere appreciation to the various functionaries at State level who graced programmes organized by the organs of the ICAI.

13.4 The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/being initiated by them, pursuant to such initiatives.

13.5 The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2008 - 2009 by all officers and staff of the ICAI.

MEMBERS
(From 1st April, 1999)
TABLE I

Year (As on)		Western Region	Southern Region	Eastern Region	Central Region	Northern Region	TOTAL
1 st April, 1999	Associate	17935	12515	5562	4875	8001	48888
	Fellow	12038	9942	4779	5345	9374	41478
	Total	29968	22457	10341	10220	17375	90366
1 st April, 2000	Associate	17771	13023	5807	5057	8411	50069
	Fellow	12200	10369	4941	5617	9784	42911
	Total	29971	23392	10748	10674	18195	92980
1 st April, 2001	Associate	19243	12915	5732	5215	8498	51603
	Fellow	12868	10749	5077	5995	10100	44789
	Total	32111	23664	10809	11210	18598	96392
1 st April, 2002	Associate	20771	13456	5872	5493	9074	54666
	Fellow	13540	11248	5296	6400	10580	47064
	Total	34311	24704	11168	11893	19654	101730
1 st April, 2003	Associate	23194	14446	6374	6318	10287	60619
	Fellow	14279	11742	5572	6909	11135	49637
	Total	37473	26188	11946	13227	21422	110256
1 st April, 2004	Associate	24515	14943	6515	6714	10697	63384
	Fellow	15091	12377	5836	7557	11846	52707
	Total	39606	27320	12351	14271	22543	116091
1 st April, 2005	Associate	26351	15724	6785	7552	11640	68052
	Fellow	15834	12969	6146	8207	12338	55494
	Total	42185	28693	12931	15759	23978	123546
1 st April, 2006	Associate	28528	16700	7172	8480	12898	73778
	Fellow	16385	13358	6313	8539	12573	57168
	Total	44913	30058	13485	17019	25471	130946
1 st April, 2007	Associate	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	Fellow	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	Total	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1 st April, 2008	Associate	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	Fellow	17646	14034	6738	9472	13398	61288
	Total	50010	33237	14677	19517	28040	145481
1 st April, 2009	Associate	34294	20666	8193	10578	15951	89682
	Fellow	18442	14516	7002	10007	13951	63918
	Total	52736	35182	15195	20585	29902	153600

MEMBERS
(From 1st April, 1950)

TABLE II

	Associate	Fellow	Total
As on 1 st April, 1950	1,120	569	1,689
As on 1 st April, 1951	1,285	672	1,957
As on 1 st April, 1961	4,059	1,590	5,649
As on 1 st April, 1971	7,901	3,326	11,227
As on 1 st April, 1981	16,796	8,642	25,438
As on 1 st April, 1991	36,862	22,136	58,998
As on 1 st April, 2001	51,603	44,789	96,392
As on 1 st April, 2002	54,666	47,064	1,01,730
As on 1 st April, 2003	60,619	49,637	1,10,256
As on 1 st April, 2004	63,384	52,707	1,16,091
As on 1 st April, 2005	68,052	55,494	1,23,546
As on 1 st April, 2006	73,778	57,168	1,30,946
As on 1 st April, 2007	81,049	58,792	1,39,841
As on 1 st April, 2008	84,193	61,288	1,45,481
As on 1 st April, 2009	89,682	63,918	1,53,600

STUDENTS GROWTH PROFILE
(From 31st March, 1997)

Course → During the year ↓	Foundation / PE (Course-I)	Inter- mediate/PE (Course-II)	Final	CPT#	PCC##	IPCC	ATC	Total
1996-97	28,209	21,354	9,275	-	-	-	-	58,838
1997-98	37,052	24,652	9,394	-	-	-	-	71,098
1998-99	43,809	28,253	12,227	-	-	-	-	84,289
1999-00	44,180	27,508	10,787	-	-	-	-	82,475
2000-01	35,999	23,405	9,026	-	-	-	-	68,430
2001-02	34,215*	29,403**	11,524	-	-	-	-	75,142
2002-03	35,524	33,283	11,102	-	-	-	-	79,909
2003-04	38,188	34,232	11,390	-	-	-	-	83,810
2004-05	39,000	34,190	11,061	-	-	-	-	84,251
2005-06	38,901	39,467	13,010	-	-	-	-	91,378
2006-07	45,617	32,339	11,838	1,29,110	24,041	-	-	2,42,945
2007-08	-	-	19,558	1,42,612	61,186	-	-	2,23,356
2008-09	-	-	11,562	1,39,140	33,764	18,318***	8***	2,02,792

- * includes PE(Course I) students registration from 1.10.2001 to 31.3.2002 : 5006
 ** includes PE(Course II) students registration from 1.10.2001 to 31.3.2002 : 11848
 *** from 10th December, 2008 to 31st March, 2009
 # CPT from 13th September, 2006
 ## PCC from 13th September, 2006

COMPOSITION OF THE COUNCIL (2009 – 2010)

	Members of the Council (2009-10)	
President CA. Uttam Prakash Agarwal	Elected Members CA. Abhijit Bandyopadhyay CA. Akshay Kumar Gupta CA. Amarjit Chopra CA. Anuj Goyal CA. Atul Chunilal Bheda CA. Bhavna Doshi CA. Charanjot Singh Nanda CA. G. Ramaswamy CA. Harinderjit Singh CA. J. Venkateswarlu CA. Jayant Gokhale CA. Jaydeep Narendra Shah CA. K. Raghu CA. K.P. Khandelwal CA. Mahesh P. Sarda CA. Manoj Fadnis CA. Pankaj Inderchand Jain CA. Preeti Pradip Mahatme CA. Rajkumar S. Adukia CA. S. Gopalakrishnan CA. S. Santhanakrishnan CA. Sanjeev Maheshwari CA. Shanti Lal Daga CA. Subodh Kumar Agrawal CA. Sunil H. Talati CA. Uttam Prakash Agarwal CA. V. Murali CA. V.C. James CA. Ved Jain CA. Vijay Garg CA. Vijay Kumar Gupta CA. Vinod Jain	Kolkata Kanpur New Delhi Ghaziabad Mumbai Mumbai New Delhi Coimbatore New Delhi Hyderabad Mumbai Nagpur Bangalore Kolkata Jamnagar Indore Mumbai Goa Mumbai Hyderabad Chennai Mumbai Hyderabad Kolkata Ahmedabad Mumbai Chennai Kochi New Delhi Jaipur Faridabad New Delhi
Vice-President CA. Amarjit Chopra		
Period 5 th February, 2009 onwards		
Secretary Shri T. Karthikeyan		
Auditors CA. Gurmeet S. Grewal CA. Pramod Jain	Nominated Members Shri Anil K. Agarwal Shri K.P. Sasidharan Shri K.R. Maheshwari Shri Krishna Kant Shri Manoj K. Sarkar Shri O.P. Vaish Shri R. Sekar Smt. Renuka Kumar	New Delhi New Delhi Jaipur New Delhi Kolkata New Delhi Gurgaon New Delhi

COMPOSITION OF THE COUNCIL (2008 – 2009)

President: CA. Ved Jain		Members of the Council (2008-09)	
Vice-President CA. Uttam Prakash Agarwal		Elected Members	
Period Upt 4 th February, 2009		CA. Abhijit Bandyopadhyay	Kolkata
Secretary Dr. Ashok Haldia (till 12 th August, 2008)		CA. Akshay Kumar Gupta	Kanpur
Shri T. Karthikeyan (12 th August, 2008 onwards)		CA. Amarjit Chopra	New Delhi
Auditors CA. Gurmeet S. Grewal CA. Pramod Jain		CA. Anuj Goyal	Ghaziabad
		CA. Atul Chunilal Bheda	Mumbai
		CA. Bhavna Doshi	Mumbai
		CA. Charanjot Singh Nanda	New Delhi
		CA. G. Ramaswamy	Coimbatore
		CA. Harinderjit Singh	New Delhi
		CA. J. Venkateswarlu	Hyderabad
		CA. Jayant Gokhale	Mumbai
		CA. Jaydeep Narendra Shah	Nagpur
		CA. K. Raghu	Bangalore
		CA. K.P. Khandelwal	Kolkata
		CA. Mahesh P. Sarda	Jamnagar
		CA. Manoj Fadnis	Indore
		CA. Pankaj Inderchand Jain	Mumbai
		CA. Preeti Pradip Mahatme	Goa
		CA. Rajkumar S. Adukia	Mumbai
		CA. S. Gopalakrishnan	Hyderabad
		CA. S. Santhanakrishnan	Chennai
		CA. Sanjeev Maheshwari	Mumbai
		CA. Shanti Lal Daga	Hyderabad
		CA. Subodh Kumar Agrawal	Kolkata
		CA. Sunil H. Talati	Ahmedabad
		CA. Uttam Prakash Agarwal	Mumbai
		CA. V. Murali	Chennai
		CA. V.C. James	Kochi
		CA. Ved Jain	New Delhi
		CA. Vijay Garg	Jaipur
		CA. Vijay Kumar Gupta	Faridabad
		CA. Vinod Jain	New Delhi
		Nominated Members	
		Shri A.K. Awasthi	New Delhi
		Shri Anil K. Agarwal	New Delhi
		Shri Jitesh Khosla	New Delhi
		Shri K.R. Maheshwari	Jaipur
		Shri Manoj K. Sarkar	Kolkata
		Shri O.P. Vaish	New Delhi
		Dr. Pritam Singh	Gurgaon
		Shri R. Sekar	New Delhi

AUDITOR'S REPORT

1. We have audited the attached Balance Sheet of The Institute of Chartered Accountants of India as at 31st March, 2009 and also the annexed Income and Expenditure Account and the Cash Flow Statement for the year ended on that date. The accounts of the Institute's Decentralized Offices, Computer Centers, Regional Councils and their Branches audited by other auditors and that their reports have been incorporated and duly considered while preparing our report. These financial statements are the responsibility of the management of the Institute. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted the audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. We further report that :-
 - a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - b) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;
 - c) In our opinion, proper books of account are maintained in conformity with the requirements of the Chartered Accountants Act, 1949;
 - d) In our opinion the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Cash Flow Statement comply with relevant Accounting Standards.
 - e) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the statements together with the schedules attached and read with the Accounting Policies and Notes Forming Part of Accounts give a true and fair view in conformity with the Accounting Principles generally accepted in India:
 - i) In the case of Balance Sheet, of the state of the Institute's affairs, as at 31st March, 2009;
 - ii) In the case of Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date; and
 - iii) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

SA/-
CA. PRAMOD JAIN
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-90358

Place : New Delhi

Date : 29/9/2009

SA/-
CA. GURMEET S. GREWAL
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-82918

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2009

	Schedule	Amount As At 31/03/2009	Rs. in Lacs Amount As At 31/03/2008
SOURCES OF FUNDS:			
Reserves and Surplus	I	24696.60	17650.62
Earmarked Funds	II	9152.98	6968.39
TOTAL		34049.58	24619.01
APPLICATION OF FUNDS:			
Fixed Assets:			
Gross Block	III	15747.23	12325.29
Less: Depreciation and Amortisation		5275.28	4247.17
Net Block		10471.95	8078.12
Capital Work in progress (including capital advances)		4324.02	1888.06
Investments:			
Earmarked Fund Investments	IV	9152.98	6968.39
Employee Benefit Investments		2208.13	1631.58
Other Investments		10290.74	9322.86
Current Assets, Loans & Advances :			
Inventories	V	679.84	718.52
Cash & Bank Balances	VI	4072.47	1387.13
Loans & Advances	VII	2507.16	1647.58
Interest Accrued on Investments		2719.41	2113.91
Sub - Total		9978.88	5867.14
Less: Current Liabilities & Provisions			
Current Liabilities	VIII	10102.19	7422.03
Provision for Employee Benefits		2272.93	1715.11
Sub - Total		12375.12	9137.14
Net Current Assets (Liabilities)		(2396.24)	(3270.00)
TOTAL		34049.58	24619.01
Statement of significant accounting policies			
Notes forming part of Accounts.			
Schedules referred to above form an Integral Part of the Balance Sheet.			
CA. RAVI PRAKASH MITTAL ASSISTANT SECRETARY	CA. T. KARTHIKEYAN SECRETARY	CA. AMARJIT CHOPRA VICE PRESIDENT	CA. UTTAM PRAKASH AGARWAL PRESIDENT

As per our Report of even date attached

CA. PRAMOD JAIN
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER- 90358

CA. GURMEET S GREWAL
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER- 82918

Place : New Delhi

Date: 29/9/2009

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2009**

		Amount Year ended 31/03/2009	Rs. in Lacs Amount Year ended 31/03/2008
INCOME			
Fees	IX	20770.19	13943.23
Seminars		2454.68	1634.12
Other Income	X	2485.32	2880.37
Prior Period Income		25.16	9.88
TOTAL		25735.35	18467.60
EXPENDITURE			
Salaries & Allowances		3490.27	2201.45
Printing & Stationery		3041.53	2777.57
Seminar Expenses		2528.17	1684.78
Other Operating Expenses	XI	7502.56	5728.55
Depreciation and Amortisation		1057.91	706.81
Prior Period Expenses		59.87	24.00
TOTAL		17680.31	13123.16
NET SURPLUS		8055.04	5344.44
Appropriation to Funds / Reserves :			
Education Fund [Policy No. III (c)]	XII	2711.67	1738.50
Employees Benevolent Fund [Policy No. III (d)]	XII	21.69	10.83
General Reserve		5321.68	3595.11
TOTAL		8055.04	5344.44

Statement of significant accounting policies

XII

Notes forming part of Accounts.

XIII

Schedules referred to above form an Integral Part of the Income and Expenditure Account

Sd/-
CA. RAVI PRAKASH MITTAL
ASSISTANT SECRETARY

Sd/-
T. KARTHIKEYAN
SECRETARY

Sd/-
CA. AMARJIT CHOPRA
VICE PRESIDENT

Sd/-
CA. UTTAM PRAKASH AGARWAL
PRESIDENT

As per our Report of even date attached

Sd/-
CA. PRAMOD JAIN
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-90358

Sd/-
CA. GURMEET S GREWAL
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-82918

Place: New Delhi

Date : 29/9/2009

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
CASH FLOW STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2009

	(Amount Rupees in Lacs)	
	2008-2009	2007-2008
A. Cash flows from operating activities		
Net Surplus	8055.04	5344.44
Adjustments for:		
Depreciation and Amortisation	1057.91	706.81
Interest on investments	(1216.82)	(1085.69)
	(158.91)	(378.88)
Operating surplus before working capital changes	7896.13	4965.56
(Increase)/Decrease in Inventories	38.68	(333.04)
(Increase)/Decrease in Interest accrued on Investments	(605.50)	(864.56)
(Increase)/Decrease in Loans & advances	(859.58)	(237.51)
Increase/(Decrease) in Current Liabilities	2680.17	2248.94
Increase/(Decrease) in Provision of Employee Benefits	557.82	(116.06)
	1811.59	697.77
Net cash from operating activities	9707.72	5663.33
B. Cash flows from investing activities		
Acquisition of Fixed Assets including Capital Work In Progress (Net)	(5887.70)	(3136.06)
Acquisition of Investments	(3727.02)	(4291.75)
Interest on investments	1216.82	1085.69
Income from Earmarked Funds investments (Net of payments)	547.89	466.11
Transitional Provision	0.00	(295.13)
Capital Receipts	827.63	381.57
Net Cash from Investing Activities	(7022.38)	(5789.57)
Net Increase/Decrease in cash and cash equivalents	2685.34	(126.24)
Cash and Cash equivalents at the beginning of year	1387.13	1513.37
Cash and Cash equivalents at the end of year-Refer Schedule No-VI	4072.47	1367.13

Note:

1. The above Cash Flow Statement has been derived using the Indirect method prescribed in AS-3 issued by The ICAI.

2. Enclosed Schedules I to XIII form an Integral Part of the Cashflow Statement

Sd/-
CA. RAVI PRAKASH MITTAL
ASSISTANT SECRETARY

Sd/-
T. KARTHIKEYAN
SECRETARY

Sd/-
CA. AMARJIT CHOPRA
VICE PRESIDENT

Sd/-
CA. UTTAM PRAKASH AGARWAL
PRESIDENT

As per our Report of even date attached

Sd/-
CA. PRAMOD JAIN
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-90358

Sd/-
CA. GURMEET S GREWAL
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-82918

Place: New Delhi

Date : 29/9/2009

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE I

RESERVES AND SURPLUS

Rs. in Lacs

	EDUCATION		INFRASTRUCTURE		GENERAL		OTHERS *		TOTAL	
	Amount As At	31/03/2008	Amount As At	31/03/2008	Amount As At	31/03/2009	Amount As At	31/03/2008	Amount As At	31/03/2008
Opening Balance	6,353.52	5,529.35	1,663.84	1,465.90	9,435.47	6,275.81	197.79	158.43	17,650.82	13,427.49
Appropriation from Income & Expenditure A/C	-	-	-	-	5,321.68	3,595.11	-	-	5,321.68	3,595.11
Transitional Provision	-	-	-	-	-	(295.13)	-	-	-	(295.13)
Transfer from/(to) General Reserve/Infrastructure Reserve and Other Reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfers from/(to) Earmarked Funds	1,710.67	824.17	83.91	35.49	(147.37)	(71.55)	63.46	36.06	0.00	-
Admission Fees & allocated Entrance Fees	-	-	8.89	30.39	(192.87)	(68.77)	(13.92)	(0.06)	1,514.07	785.73
Donation received for Buildings	-	-	103.49	21.18	-	-	-	-	103.49	21.18
Net (Depletion)/Additions	-	-	299.98	110.88	-	-	-	-	299.98	110.88
	-	-	-	-	-	-	6.76	5.36	6.76	5.36
Total	8,064.49	6,353.52	2,161.11	1,663.84	14,416.91	9,435.47	254.09	197.79	24,896.60	17,650.82

*Note: Other Reserves are Reserves such as Library Reserves and Class Room Training Reserves as appearing in the books of Regional Councils and Branches

SCHEDULE II
REMARKED FUNDS

REMARKED FUNDS	Opening Balances	Appropriation from Income & Expenditure Account	Transfer from/(to) Reserves and Surplus	Contribution received/Additional during the year	Income during the year	Payments during the year	Adjustments	Total
	Amount As At 01.04.2009	Amount As At 2009-09	Amount As At 2009-09	Amount As At 2009-09	Amount As At 2009-09	Amount As At 2009-09	Amount As At 2009-09	Amount As At 31.03.2009
	01.04.2009	01.04.2007	2009-09	2007-09	2007-09	2008-09	2007-09	31.03.2009
RESEARCH FUNDS	981.31	730.99	-	51.23	177.66	87.90	72.66	1,140.44
ACCOUNTING RESEARCH BUILDING FUND	358.26	325.77	-	-	-	36.51	32.49	394.77
EDUCATION FUND	4,668.62	3,413.78	1,738.50	-	-	475.73	340.51	6,145.05
MEDALS AND PRIZES FUNDS	137.07	126.64	-	0.13	5.40	9.64	11.03	151.10
STUDENTS SCHOLARSHIP FUNDS	41.91	38.46	-	27.95	0.55	4.27	3.84	73.28
EMPLOYEES BENEVOLENT FUND	128.45	106.92	10.83	-	-	12.27	10.65	153.12
OTHER FUNDS (REGIONAL COUNCILS AND BRANCHES)	660.77	552.07	-	328.11	60.54	40.31	22.04	1,095.22
TOTAL	6,948.30	5,204.53	1,749.33	417.42	244.15	876.63	493.22	9,152.98

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE III

FIXED ASSETS

Rs. In Lacs

ASSETS	G R O S S B L O C K			DEPRECIATION AND AMDRTISATION				N E T B L O C K		
	Cost as at 1.4.2008	Additions during the year	Adjustments /Transfers / Sale	Cost as at 31.3.2009	Upto 1.4.2008	For the year	Adjustments Transfers/ /Sale	Upto 31.3.2009	W.D.V as on 31.3.2009	W.D.V as on 31.3.2008
A.Tangible Assets:										
1.Land - Free Hold	689.94	629.39	(0.95)	1,318.38	-	-	-	-	1,318.38	689.94
2.Land -Lease Hold	3,181.81	70.50	-	3,252.31	138.80	40.23	-	179.03	3,073.28	3,043.01
3.Buildings	2,830.07	1,052.95	-	3,883.02	688.44	102.91	-	791.35	3,091.67	2,141.63
4.Electric Installations & Fittings	366.83	153.30	(3.67)	516.46	150.76	28.86	(0.27)	179.35	337.11	216.07
5.Computers	2,060.73	741.52	(42.20)	2,760.05	1,469.34	548.32	(16.15)	2,001.51	758.54	591.39
6.Air Conditioners	472.66	71.48	(1.09)	543.05	210.47	45.29	(0.07)	255.69	287.36	262.19
7.Furniture & Fixtures	1,106.22	309.81	(11.09)	1,404.94	385.87	87.89	(8.69)	465.07	939.87	720.35
8.Lifts	108.40	5.02	-	113.42	49.50	6.17	-	55.67	57.75	58.90
9.Office Equipments	554.32	311.20	(16.63)	848.89	277.21	55.97	(4.62)	328.56	520.33	277.11
10.Vehicles	45.80	21.21	(0.12)	66.89	28.02	4.28	-	32.30	34.59	17.78
11.Library Books	441.57	59.97	-	501.54	441.57	59.97	-	501.54	-	-
B.Intangible Assets:										
Software	466.94	71.34	-	538.28	407.19	78.02	-	485.21	53.07	59.75
TOTAL	12,325.29	3,497.69	(75.75)	15,747.23	4,247.17	1,057.91	(29.80)	5,275.28	10,471.95	8,078.12
Previous Year Figures	10,676.96	1,671.79	(23.46)	12,325.29	3,554.08	706.81	(13.72)	4,247.17	8,078.12	-

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE IV

INVESTMENTS

	Amount As At 31/03/2009	Rs. in Lacs Amount As At 31/03/2008
<u>A. LONG TERM INVESTMENTS (AT COST)</u>		
<u>Bonds</u>		
(I) Government of India-8% (taxable) Bonds-2003	4750.00	4750.00
<u>Others</u>		
(II) Fixed Deposits with Scheduled Banks	3800.00	4991.37
<u>B. CURRENT INVESTMENTS</u>		
<u>Others</u>		
Fixed Deposits with Scheduled Banks	13099.85	8181.46
Total Investments	21649.85	17922.83
ALLOCATED TO:-		
Earmarked Fund Investments	9152.98	6968.39
Employee Benefit Investments	2206.13	1631.58
Other Investments	10290.74	9322.86
Total	21649.85	17922.83

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE V

INVENTORIES

	Amount As At 31/03/2009	Rs. in Lacs Amount As At 31/03/2008
Publications and Study Materials	647.03	689.14
Paper for Study Materials & Publications	0.96	2.34
Consumables Stores	31.85	27.04
Total	679.84	718.52

SCHEDULE VI

CASH AND BANK BALANCES

	Amount As At 31/03/2009	Rs. in Lacs Amount As At 31/03/2008
Cash in Hand	25.38	9.64
Cash at Bank	4047.09	1377.49
Total	4072.47	1387.13

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE VII

LOANS & ADVANCES (Considered Good)

	Amount As At 31/03/2009	Rs. in Lacs Amount As At 31/03/2008
Loans and Advances-Staff	612.76	251.51
Interest Recoverable from Staff Loans	111.25	105.47
Security Deposits	340.65	64.16
ICAI Accounting Research Foundation	210.50	565.20
Accounts Receivables	394.77	231.26
Other - Advances & Pre-payments	837.23	429.98
Total	2507.16	1647.58

SCHEDULE VIII

CURRENT LIABILITIES

	Amount As At 31/03/2009	Rs. in Lacs Amount As At 31/03/2008
Fees Received in Advance		
Examination Fees	701.81	870.54
Journal Subscription	50.39	73.80
Membership Fee	513.78	422.93
Education Fee	5013.33	3887.95
Post Qualification Courses (PQC)	110.15	108.28
Certificate Courses	17.50	0.00
Seminar Fees & Other Collections	730.02	656.12
Creditors for Expenses	2,180.97	929.11
Other Liabilities	784.24	473.30
Total	10102.19	7422.03

353848/09-32

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**SCHEDULE IX****FEES**

	Amount Year ended 31/03/2009	Rs. in Lacs Amount Year ended 31/03/2008
Education	13747.17	8030.82
Examination	2942.93	3317.35
Membership	3001.48	1480.78
Students' Registration	270.88	427.76
Entrance	28.52	7.65
Students' Association	250.89	372.10
Post Qualification Courses (PQC)	176.11	194.60
Certificate Courses	352.21	112.17
Total	20770.19	13943.23